

Union Budget (2025-2026) ? Demands For Grants, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare- Laid

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 3, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

अब सभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 1 और 2 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जायेगा ।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं । इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी । यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वे उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दे दें ।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है । इसलिए मैं सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि समय कम है क्योंकि पांच बजे माननीय मंत्री जी का जवाब होगा और छः बजे गिलोटिन है । इसलिए सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी बात संक्षिप्त में रखें । एक बार जो बात कही जा चुकी है, उसी बात को उसी दल के दूसरे माननीय सदस्य दोहराने की कोशिश न करें । सदन के पटल पर किसानों से संबंधित सभी बातें आ जाएं, ऐसा हम प्रयास करेंगे तो उचित रहेगा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि कार्य-सूची के दूसरे स्तंभ में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2 के सामने प्रविष्ट मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान पर किए जाने वाले खर्चों को चुकाने के निमित्त, आवश्यक धनराशियों को पूरा करने के लिए, संबंधित धनराशियां, जो कार्य-सूची के तीसरे स्तंभ में दिखाई गई राजस्व रेखा

और पूंजी लेखा की रकमों से अधिक न हों, भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को प्रदान की जाएं ।?

Demands for Grants of Union Budget for 2025-2026 submitted to the vote of Lak Sabha

शीर्षक	No. and Title of the Demand	Amount of Demand for Grants submitted to the Vote of the House
	1 Revenue Rs.	2 Capital Rs.

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

1-Department of Agriculture and Farmers Welfare	235044,56,00,000	87,87,00,000
2-Department of Agricultural Research and Education	10462,06,00,000	4,33,00,000

श्री धमेन्द्र यादव ।

? (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, every time it is postponed. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Yes, it is postponed. ? (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, at least an assurance may be given by the hon. Speaker. ? (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी । माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि इस बजट में देश की सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत की आबादी का जीवन खेती और किसानों पर निर्भर है, उस मंत्रालय की चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने पार्टी की ओर से किसानों के मुद्दों पर अपनी बात कहने का यहां अवसर दिया ।

अध्यक्ष जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है । जब भारत की आत्मा गांवों में बसती है तो गांवों की तरक्की और खुशहाली के बिना देश की तरक्की संभव नहीं है । श्रद्धेय नेता जी ने हमेशा कहा कि भारत की तरक्की और विकास का रास्ता अगर कहीं से निकलता है तो खेतों और खलिहानों से निकलता है । अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े-बड़े विद्वान इस सदन में मौजूद हैं । श्रद्धेय नेता जी ने हमेशा कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है तो इसके लिए किसानों को आप संपन्न कर देंगे तो बाजारों की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी ।

अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी द्वारा जब बजट पेश किया गया तो लगातार यह कहा गया कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है । 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट है, लेकिन उन बजट पत्रावलियों को जब देखा गया और उस पत्रावली में जब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट को देखा गया तो बड़ी निराशा हुई ।

केवल 2.7 प्रतिशत बजट का हिस्सा इस मंत्रालय को दिया गया । जो पिछले समय में बजट मिला था, उसमें भी 2.8 परसेंट की कमी कर दी गई थी । अतः मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोग या एनडीए की सरकार किसानों के लिए भाषण चाहे जितने दे, लेकिन ये दिल में किसानों के लिए नफरत लेकर बैठे हुए हैं । अगर नफरत लिए न बैठे होते, तो इतने बड़े बजट में किसानों के लिए बजट कटौती क्यों की जाती?

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2014 के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प का जिक्र करना चाहूंगा । वर्ष 2014 में जो संकल्प-पत्र जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके पास आज कागज बहुत हैं, लेकिन बोलना संक्षिप्त में है ।

श्री धर्मेन्द्र यादव : जी सर ।

माननीय अध्यक्ष : आपको संक्षिप्त में बोलना है ।

? (व्यवधान)

13.46 hrs

(Shri Dilip Saikia in the Chair)

श्री धर्मेन्द्र यादव : सर, आप जो मौका देंगे, उसमें आपकी उदारता रहेगी । वर्ष 2014 के संकल्प-पत्र में कहा गया कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश के अनुरूप, जो किसानों की लागत है, जिसके बारे में सदैव नेता जी कहते थे और उसी बात को स्वामीनाथन जी ने भी कहा कि किसान की अपनी मेहनत, अपने परिवार की मेहनत, उनके पशुओं की मेहनत, खेती की जो वैल्यू है, उसका मार्केट में ब्याज होना चाहिए । सारी की सारी चीजों को अगर मिला लें, तो जो स्वामीनाथन जी ने सी-2 का फार्मूला दिया, सी-2 + 50 परसेंट, यानी लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य ।

माननीय मंत्री जी, वर्ष 2014 में आपके चुनावी घोषणा-पत्र का वायदा है, लेकिन आज वर्ष 2014 से वर्ष 2025 आ गया है, लेकिन अभी तक सरकार का यह संकल्प पूरा नहीं हुआ है । 12वां बजट भी पेश हो गया, 11 साल आपने पूरे कर दिए, भाषण आपके बहुत लंबे हैं, लेकिन सच्चाई से आप बहुत दूर हैं । उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2016 में घोषणा की कि वर्ष 2022 में आने वाले अमृतकाल में जब भारत प्रवेश करेगा, तो उस प्रवेश के समय किसानों की आमदनी को हम दो गुना कर देंगे । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ ।

माननीय कृषि मंत्री जी, आप बहुत अनुभवी हैं । आप लंबे समय तक एक बड़े प्रान्त के मुख्य मंत्री रहे हैं । किसानों के इस्तेमाल की सारी चीजों का मूल्य आपने बढ़ा दिया । आपने खाद का दाम लगातार बढ़ाया, बिजली में आपने कोई सब्सिडी नहीं दी, कीटनाशकों का दाम बढ़ा दिया गया । किसान के इस्तेमाल वाले डीजल के दाम बढ़ गए । ट्रैक्टर, थ्रेसर से लेकर जितनी भी चीजें खेती में किसानों द्वारा इस्तेमाल होती हैं, इन सारी चीजों का दाम बढ़ा दिया, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य देने की आपने जरूरत नहीं समझी । जहां आपने दो गुनी आमदनी का वायदा किया था, जहां आपने सी-2 + 50 परसेंट का वायदा किया था, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि देश के

किसानों की हालत यह है कि अगर वे कर्ज न लें, तो लागत के बराबर भी मार्केट में कहीं मूल्य नहीं है। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि यदि किसानों की आमदनी बढ़ानी है, तो 43 हजार मंडियों की देश में जरूरत है, लेकिन उन मंडियों की देश में स्थिति केवल 7 हजार की है।

माननीय मंत्री जी, कृपया जवाब दे दीजिएगा। जब से एनडीए की सरकार आई है, इन 11 सालों में प्राइवेट सेक्टर्स ने तो मंडियां बढ़ा लीं, साइलोज़ बना लिए, प्राइवेट खरीदारी का इंतजाम तो है, लेकिन आपने कहीं भी सरकारी मंडियां बढ़ाने का काम किया हो, तो उसका डेटा दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मंत्री रहते हुए, विशेषकर बुंदेलखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों मंडियां बढ़ाई थीं, उन मंडियों को नहीं बढ़ाया। और तो और कन्नौज में आलू की, मैनपुर में अनाज की एक बहुत बढ़िया मंडी एक्सप्रेस वे के पास तैयार की थी, जिससे किसान अपनी फसलों को सीधे देश के किसी भी कोने में पहुंचा सकें।

मंत्री जी, आप जानकारी जुटा लीजिएगा, उन मंडियों को भी आपकी सरकार ने नहीं बनाया। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जब सत्तापक्ष की तरफ से कोई खड़ा होता है, तो डबल इंजन की बातें करता है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन का क्या हुआ? माननीय अखिलेश जी के सारे कामों को रोक दिया गया। किसानों की यह हालत है? बेचारे किसान क्या करें? वे कर्ज ले रहे हैं। साहूकारों से उन्हें मुंहमांगे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकार से भी कोई राहत नहीं है।

क्या यह मामूली बात है? आपके 10 सालों के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष 10 हजार से ज्यादा और अब तक देश के एक लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश के तमाम संविदाकर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। अगर देश के किसान अपना हक, अधिकार मांगने आते हैं, चूंकि आपने तीन काले कानून बनाए थे। कृषि मंत्री जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप अपने जवाब में बताइएगा। हम विपक्ष के सभी सदस्य कह रहे थे कि ये तीन काले कानून हैं और आप उन काले कानूनों को नहीं मान रहे थे। किसानों ने दिल्ली में कई महीनों तक सर्दी, गर्मी, बरसात, सारे मौसम झेलकर आंदोलन किए, उसमें 750 किसान शहीद हुए, लेकिन उन शहीद किसानों को आज तक आपकी सरकारी की तरफ से, जहां आज देश की पांचवीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी होने वाली है, वहां एक परिवार को भी आपने मुआवजा नहीं दिया

। क्या यह आपकी सरकार है? वह डंका किन्हीं बड़े-बड़े लोगों के लिए बज रहा होगा, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए डंका बज रहा होगा, लेकिन देश के किसानों की जो बर्बादी है, वह छिपी हुई नहीं है ।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर आपने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्जा माफ किया है । 16 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्जा देश के बैंकों ने बड़े-बड़े पूंजीपतियों का, जिनमें चुनिंदा पूंजीपति होंगे, मैं किसी का नाम कोट नहीं करूंगा, उनके बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन वहीं अगर किसानों के कर्ज की माफी की बात आती है तो सरकार एकदम चुप बैठ जाती है । क्या यही आपका किसानों के प्रति प्रेम है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपने देश के किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, देश के सर्वोच्च सदन से कहना चाहता हूँ कि आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि आपने कैसी सरकार चुन ली है? आप प्रधान मंत्री जी के नाम पर कितनी ही झूठी बातों पर लोगों को विश्वास करवाएंगे? ? (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों को कितना दिया है? ? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : कितना दिया है? आप सुन लीजिए, जितना दिया है उससे ज्यादा आपने यूरिया की बोरी 50 से 40 कर दी, उसमें काट लिया है । उससे ज्यादा आपने जीएसटी में वसूल लिया है । ? (व्यवधान) आप बताइए ट्रैक्टर पर कितना जीएसटी है? यूरिया पर कितना जीएसटी है? कीटनाशकों पर कितना जीएसटी है? जीएसटी के माध्यम से आपने वसूल लिया है । आप किसानों को एक हाथ से एक रुपये देते हैं और दूसरे हाथ से 10 रुपये खींच लेते हैं । देश के किसान सुन रहे हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज किसान मजबूर है । मुझे अहसास है । मेरे पिताजी आज भी खेती, किसानों में रहते हैं, आज भी गौशाला में रहते हैं । मुझे किसानों के दर्द का अहसास है । किसानों की यह हालत थी कि पहले जब कभी भी अगर हम किसान परिवार से कह देते थे कि आप गांव छोड़ दीजिए, जमीन छोड़ दीजिए, शहर में चलकर बस जाइए, नौकरी कर लीजिए तो वे पहले तैयार नहीं होते थे, लेकिन आज किसान इतना मजबूर हो गया है कि खेती छोड़कर, वह शहरों में रिक्शा चलाने के लिए तैयार है । वह शहरों में मजदूरी करने के लिए तैयार है । वह कोई भी काम करने के लिए तैयार है । अब किसानों ने

समझ लिया है कि उनका और उनके बच्चों का भविष्य खेती में नहीं रहा। देश में बहुत से सर्वे हुए। जब किसानों से पूछा गया कि क्या आप खेती करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो मेजोरिटी के किसानों ने कह दिया कि हम खेती नहीं करना चाहते हैं। यह हालत है। देश के 50 फीसदी से ज्यादा किसान आज भी हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं।

इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि यह सरकार हो, चाहे इनके प्रांतों की सरकार हो और प्रांतों में भी, विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए कहूंगा, इन्होंने किसानों को रोजगार नहीं दिया। माननीय मंत्री जी, हाँ, एक रोजगार आपकी सरकार ने किसानों को दे दिया है और किसान परिवार के सभी लोगों को दे दिया है। चाहे दो डिग्री टेम्परेचर हो, तीन डिग्री टेम्परेचर हो, कोहरा हो, तूफान हो, बारिश हो, मूसलाधार बरसात चल रही हो या गर्मी में 50 डिग्री की तपन हो, हर परिस्थिति में किसान परिवार की महिलाओं को, किसान परिवार के बच्चों को, स्वयं किसानों को पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। आपने किसानों की यह हालत कर दी है। कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि किसानों की दुर्दशा आप सब लोग सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि यह किसान समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है। यह बहुत जज्बाती समाज है। यह सरकारी की गलत नीतियों का जमकर विरोध करता है। इसलिए सरकार चाहती है कि किसान कर्ज में उलझे रहें, किसान अपनी समस्याओं में डूबे रहें, किसानों में सम्पन्नता न आ जाए। अगर किसानों में सम्पन्नता आएगी तो उनके परिवार नौकरी से लेकर सम्मान, स्वाभिमान का जीवन जीएंगे। यह सरकार पूरी तरह से चाहती है कि कैसे भी किसान बर्बाद हो जाएं।

सभापति जी, अभी पूरे देश ने देखा है कि अमेरिका से जंजीर में बंध कर नौजवान यहां आए हैं। वे कहां के नौजवान थे, वे वहां के थे जिनको हम देश में संपन्न प्रांत मानते हैं। वे पंजाब, गुजरात और हरियाणा के नौजवान थे। वे सारे नौजवान किसान परिवारों के थे जो खेत बेचकर, कर्ज लेकर, अपने परिवार के बुजुर्गों की परेशानी देखकर, जमीनें गिरवी रखकर, विदेश में गए।? (व्यवधान) इनको शांत रहने दीजिए। ये जानते हैं कि किसान क्या करेंगे? यह हर एक विषय में केवल बोलना जानते हैं बाकी कुछ नहीं है।

सभापति जी, आपने किसान परिवारों के नौजवानों की यह हालत कर दी है। पांच साल प्रचंड बहुमत की सरकार।? (व्यवधान) अभी आपका नंबर आएगा। सत्ता पक्ष की तरफ से जो खड़ा हुआ, उसने कहा कि प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन की

सरकार । पांच साल डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद, आपने वर्ष 2019 के संकल्प पत्र में कहा था कि कृषि ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ का निवेश करेंगे । यह आपके वर्ष 2019 के संकल्प पत्र में है । आपने वर्ष 2014 से 2019 तक सरकार चलाई है । आपने ही वर्ष 2019 से 2024 तक सरकार चलाई है और आपका वर्ष 2019 का यह वादा है कि हम कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो माननीय कृषि मंत्री जी अपने जवाब में बता दें कि आखिर आपकी यह प्रतिबद्धता कहां चली गई है? माननीय मंत्री जी उसके साथ यह भी बता दें कि आखिर आपने वर्ष 2022 जो कि आजादी के अमृत काल का प्रवेश साल था, आपने उसमें दोगुनी आमदनी का वादा किया था । आज हम वर्ष 2025 में यहां बैठे हैं और अमृत काल के भी तीन साल गुजर गए हैं । माननीय मंत्री जी देश के एक किसान का नाम अपने जवाब में बता दीजिए कि इस किसान की पहले आमदनी इतनी थी और आज उनकी आमदनी इतनी हो गई है । मैं यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ।? (व्यवधान) माननीय मंत्री जी यह बताएं कि इन्होंने किन किसानों की आमदनी वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक डबल कर दी है । हम यह सवाल वर्ष 2025 में कर रहे हैं । किसानों की सारी जरूरत की चीजें महंगी हो गई हैं । उन पर टैक्स बढ़ेगा और जब किसानों की फसलें मंडियों में जाएंगी तो मंडियां नहीं चलेंगी । वे कम हैं और जो मंडियां हैं, वे नहीं चलेंगी । जो मंडियां चलती हैं, उनमें बहुत सारे दलाल लोग बैठे हैं । अगर किसान सीधे मंडी में फसल देना चाहेंगे तो वे नहीं दे सकते हैं । अगर दलालों के माध्यम से उपज मंडी में जाएगी तो वह वहां जाएंगी । आपने एमएसपी की घोषणा की है । हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन मंत्री जी आप के पास डेटा होगा । आखिर उस एमएसपी का लाभ कितने लोग ले रहे हैं? क्या उस एमएसपी के आकलन के समय आपने कहीं भी किसानों की लागत का आकलन किया था? स्वामीनाथन जी ने जो रास्ता दिखाया था, क्या आप उस रास्ते पर कभी चले थे? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं ।

सभापति जी, किसानों के बारे में जितनी बात कह दें, लेकिन आप सोचिए कि आलू का किसान कर्ज में डूबा है लेकिन चिप्स के उद्योगपति जितने में उसे खरीदता है, उससे सैकड़ों गुना मुनाफा कमा रहे हैं । आप इसके बारे में बताइए कि क्या यह सच्चाई नहीं है? हमारा तो कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद और अब तो बदायूं में भी बहुत आलू होने लगा है । आलू के किसान परेशान हैं और चिप्स वाले पैसे कमा रहे हैं । धान

के किसान परेशान हैं लेकिन उससे प्रोडक्ट्स बनाने वाले पैसे कमा रहे हैं । गेहूं के किसान परेशान हैं, मक्का के किसान परेशान हैं लेकिन पॉपकॉर्न बेचने वाले लोग कहां तक पहुंचे रहे हैं, नमकीन बनाने वाली कंपनियां कहां तक चली जा रही हैं? आपकी किसानों के लिए जो नीतियां और कार्यक्रम हैं, आखिर वे किन के लिए हैं? किसानों को केवल एक बहाना, झुनझुना दिखाया जा रहा है । आज यहां बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है ।

सभापति जी, मैं इस चर्चा के माध्यम से देश के किसानों से कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग की हर हालत में किसानों की उपज और किसानों की जमीनों पर नीयत है । सरकारी बैंक्स प्राइवेट की जा रही हैं । उन प्राइवेट बैंकों से किसानों को कर्ज देने से उनका भविष्य यह होने जा रहा है कि किसानों की जमीनें भी कुछ चुनिंदा बैंक्स एवं उद्योगपतियों के हाथों में होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ।

सभापति जी, किसानों के तमाम आंदोलन चले हैं । वे विशेष कर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले हैं ।

14.00 hrs

माननीय सभापति जी, मैं माननीय अखिलेश यादव जी और अपनी पार्टी की ओर से न केवल समर्थन करता हूं, न केवल उनकी मांग का साथ देता हूं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि एमएसपी और गारंटी की बात, जो स्वामीनाथन जी ने कही थी, जिस मांग को लेकर अलग-अलग तरीके से किसान आंदोलन हो रहे हैं, एमएसपी लागू कीजिए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से इसे लागू कीजिए । हम जानते हैं कि उसमें भी किसानों को गुमराह कर देंगे । ? (व्यवधान) देखिए, आपने किसानों का बजट डाउन कर दिया, देश का बजट बढ़ रहा है तो फिर मंत्री जी, किसानों का बजट क्यों कम कर दिया? मंत्री जी किसानों को नहीं चाहते हैं या सरकार में बैठे लोग मंत्री को नहीं चाहते हैं? यह तो यही लोग जानें, लेकिन किसानों की कर्ज माफी होनी चाहिए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : स्वामीनाथ आयोग की रिपोर्ट कब आई? यह आयोग कब बना? किसने बनाया? कितने साल हो गए हैं? इनके बारे में भी सबको बता दीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : आदरणीय श्रद्धेय नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग उस समय कृषि मंत्री जी से भी मिले थे । वर्ष 2014 में तो आपने सब कुछ बदलने का वादा किया था । वादा तो आपका था । ? (व्यवधान) यह वादा तो आपका था । ? (व्यवधान) यह वादा किसका था? ? (व्यवधान) और क्या कहते थे? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, श्रद्धेय नेता माननीय अखिलेश जी ने जो संस्कार दिए उसके अनुसार हमने जीवन में कभी किसी व्यक्ति का नाम लेकर टिप्पणी नहीं की और न ही करेंगे । ? (व्यवधान) लेकिन एक बात कोट कर रहे हैं ।? (व्यवधान) आप ही लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी है । मैं नहीं कहता, यह बीजेपी के लोग कहते हैं । ? (व्यवधान) आखिर प्रधान मंत्री जी की गारंटी किसानों के लिए कहां चली गई? आप इधर की बात कर रहे हैं, उधर की कर रहे हैं । ? (व्यवधान) अरे, हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो, तभी हम लोग इधर आ गए, लेकिन आपने क्या किया? ? (व्यवधान) आपने क्या कर दिया? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, अब गन्ना के किसानों का सवाल आता है । देश में गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश बन चुका है और हमने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है । हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, तब पांच साल के कार्यकाल में 90 रुपये गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया था । अब डबल इंजन की सरकार है, हर चुनाव में माननीय प्रधान मंत्री जी सहित इधर से पूरे के पूरे लोग गए, प्रचार में, प्रसार में, वादों में, भाषणों में गए । ? (व्यवधान) आठ साल में तीस रुपये ही बढ़ाए । वर्ष 2017 में दस रुपये बढ़ाए और वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव के आते-आते बीस रुपये और बढ़ा दिए । इस तरह से आठ साल में गन्ने का समर्थन मूल्य केवल 30 रुपये बढ़ाया । समर्थन मूल्य बढ़ाना तो एक बात है, वादे किए और भाषण दिए कि 15 दिनों में गन्ने के मूल्य का भुगतान करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे । ? (व्यवधान) यह भाषण है, वादे हैं, घोषणा पत्र है । ? (व्यवधान) ब्याज तो छोड़िए, किसानों को मूल्य सालों साल से नहीं मिल रहा है । ? (व्यवधान) अरे, जब खजाना तुम तक पहुंच गया तो भुगतान कौन करेगा? यह कौन सी बात होती है? वित्तीय वर्ष खत्म हो गया था । ? (व्यवधान) 15 मार्च को जब कार्यकाल खत्म हुआ तो भुगतान कौन करेगा? भुगतान किया तो क्या कोई अहसान किया? ? (व्यवधान) क्या किसी और का भुगतान किया? किसानों का गन्ना था, आपने उसका भुगतान कर दिया ।? (व्यवधान)

विशेषकर उत्तर प्रदेश और कई प्रांत के साथियों से बात हुई, किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत छुट्टा जानवरों की है । किसानों की उपज जब तक बाजार में बिक नहीं जाती है, पूरा परिवार सर्दी, गर्मी, बरसात, लू और बारिश की परिस्थिति में खेतों में पड़ा रहता है । उनका जीवन नरक हो गया है । मेरी आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी और सरकार से प्रार्थना है कि एक स्थायी ढंग से इंतजाम कीजिए । आप प्रधान मंत्री जी के चुनावी भाषण सुनिए, पता नहीं सरकार में बैठे लोग कैसे हैं कि माननीय प्रधान मंत्री जी की भी नहीं सुनना चाहते?? (व्यवधान)

आप लोग प्रधान मंत्री जी की भी बात नहीं सुनना चाहते । ? (व्यवधान) केवल धर्म के नाम पर, मंदिर, मस्जिद, हिन्दू, मुसलमान, नफरत फैला कर, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से जनता का विश्वास जीत लोगे तो देश का जनमानस, देश का किसान जाग चुका है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बेरोजगारी का आलम पूरा देश जानता है । आज भी खेती का क्षेत्र ऐसा है, जो 60 फीसदी से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है । आखिर रोजगार देने वालों को, कृषि मंत्री जी अगर आप मानते हैं कि 60 फीसदी रोजगार मिल रहा है तो आप 30 परसेंट ही बजट ले आते । आपने कृषि अनुसंधान का बजट कम कर दिया । कृषि का बजट आपने कम कर दिया, जीएसटी आपने बढ़ा दी । तमाम किसानों के सामने जो चुनौतियां हैं, कहीं मंडी की चेन बन नहीं रही है, कोल्ड स्टोरेज की चेन बन नहीं रही है, मार्केट कहीं बन नहीं रही है, कहीं सिंचाई का इंतजाम नहीं है तो ऐसी तमाम चीजें हैं, जिन पर मंत्री जी को, सरकार को सोचना चाहिए । अगर नहीं सोचेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के किसान, किसान परिवार के नौजवान बहुत जागरूक हैं और आने वाले समय में अपने-अपने तरीके से लोग आपको जवाब देंगे ।

मैं किसानों की तरफ से एक बात कहते हुए अपनी बात को करूंगा, क्योंकि हम आपकी घंटी बार-बार नहीं सुनना चाहते । हमारे और भी साथी पीछे बोलने वाले हैं । बीजेपी के लोगों को लगता है कि किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है । सच्चाई यह है कि कृषि विकास दर, कर्ज, आत्महत्याएं, ब्याज, मंडी, जीएसटी और उनके ऊपर मुकदमों से लेकर, आप सोचो कि पंजाब के किसान चलते हैं तो हरियाणा सरकार रोक देती है । कोई मामूली बात है । अंतर्राज्यीय सीमा है, कोई देश की सीमा तो है नहीं । अंतर्राज्यीय सीमाओं में लोग उनको रोक रहे हैं । यहां 750 लोग मर गये, उस पर कोई कार्रवाई नहीं । उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया । इसलिए मैं किसानों का

समर्थन करते हुए अपनी पार्टी की ओर से केवल एक बात कहूंगा । ये हर हाल में किसानों को गुमराह कर रहे हैं । मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं । उसे बताने का मेरे पास टाइम नहीं है । ये गुमराह करते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो सरकार के खजाने पर इतना बोझ आएगा । उससे ज्यादा बड़ा बोझ भी नहीं आना है । अगर सरकार करना चाहे तो ज्यादा बड़ा बोझ नहीं आएगा । इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि किसानों का कर्ज माफ कर दो । भविष्य में उन पर कर्ज न चढ़े, उसके लिए उनकी लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य कर दो तो किसानों का भी लाभकारी सौदा हो जाएगा । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका धन्यवाद ।

माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी ।

श्री धर्मेन्द्र यादव : सभापति जी, बस एक बात कहते हुए, एक लाइन कहूंगा । ? (व्यवधान) गोंडा के अदम गोंडवी साहब एकदम गांव में बैठे हुए कवि रहे हैं । इस सरकार के लिए उनकी कही हुई एक कविता बड़ी फिट बैठ रही है?

?तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है

मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है

तुम्हारी मेज़ चांदी की तुम्हारे जाम सोने के

लेकिन किसान के घर में आज भी फूटी रक्काबी है ।?

माननीय सभापति : ठीक है । श्री जय प्रकाश जी ।

श्री धर्मेन्द्र यादव : माननीय मंत्री जी, किसानों की हालत यह है । इसलिए ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : जय प्रकाश जी, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है ।

? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : सभापति जी, बस एक मिनट दीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : जय प्रकाश जी, आप अपनी बात शुरू कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद । ? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : सभापति जी, मुझे कनक्लूड तो करने दीजिए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : जय प्रकाश जी, आप अपनी बात शुरू कीजिए । आपका समय शुरू हो गया है ।

श्री जय प्रकाश : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : जय प्रकाश जी, एक मिनट रुकिये । माननीय यादव जी, आपका यहां करीब 24 मिनट का भाषण हुआ है । आपकी पार्टी के और भी वक्ता हैं तथा आपका समय खत्म हो गया है । दूसरा, जब मंत्री जी रिप्लाय देंगे तो उस समय आप जरूर उपस्थित रहियेगा । क्योंकि लोग बोल कर चले जाते हैं इसलिए आप जरूर उपस्थित रहियेगा । यह मेरा निवेदन है ।

? (व्यवधान)

CUT MOTIONS

TOKEN

**THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
FARMERS WELFARE (PAGE 1) BE
REDUCED BY RS. 100.**

1

SHRI SUDHAKAR SINGH (BUXAR): I beg to Move:

Need to implement Swaminathan Formula for MSP
whereby the government must ensure that Minimum
Support Price (MSP) is legally guaranteed and

calculated as per the C2+50% formula to provide fair compensation to farmers and protect them from market fluctuations. (1)

Need to expand and strengthen Agricultural Cold Storage and Processing Units in Bihar to reduce post-harvest losses and increase farmers' incomes. (2)

Need to have comprehensive crop insurance and disaster relief reforms in Bihar where the farmers frequently suffer crop losses due to floods, droughts and erratic weather patterns. (3)

Need to impose a complete ban on gene editing in crops to protect farmers' rights, biodiversity and traditional seed sovereignty. (4)

Need to address and implement all demands of Sanyukta Kisan Morcha including legal guarantee for MSP, withdrawal of cases against protesting farmers and compensation for the families of deceased farmers. (5)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद को कानूनी दायरे में लाए जाने की आवश्यकता ।(6)

नागौर जिले में मूंग से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केन्द्र की स्वीकृति की आवश्यकता ।(7)

नागौर और डीडवाना-कुचामन जिलों में एक नए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता ।(8)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खड़ी फसलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता ।(9)

नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान के किसानों के फसल बीमा योजना के तहत लंबित दावों के निराकरण की

आवश्यकता ।(10)

***m10 SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** I beg to Move:

Need to provide funds to start a special programme for promoting organic farming. (11)

Need to provide more funds for providing minimum support price for agricultural products. (12)

Need to provide funds for formulating a special scheme for providing good quality seeds to the farmers. (13)

Need to provide sufficient funds for giving fertiliser subsidy to the farmers. (14)

Need to provide funds for establishing a marketing system for ensuring good price of agricultural products. (15)

Need to provide funds for promotion of coconut and paddy cultivation. (16)

Need to provide funds for establishing training institute for farmers for creating awareness regarding new technology and modern farming. (17)

Need to provide funds for formulating a scheme for increasing the yield of agricultural produce in Kerala. (18)

Need to provide special funds for compensating farmers for loss sustained due to wild animal attack. (19)

***m11 PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD (MUMBAI NORTH-CENTRAL):** I beg to Move:

Need to annihilate farmer suicides in the country by addressing the root causes such as indebtedness,

crop failure and lack of support system. (32)

Need for legalizing the Minimum Support Price (MSP) for agricultural produce to provide farmers with a guaranteed price for their crops and protect them from market fluctuations. (33)

Need for adequate and prompt compensation to farmers for crop losses due to natural calamities by having more efficient and farmer-friendly mechanism for assessing and disbursing compensation. (34)

Need to mitigate impact of export bans on agricultural commodities, such as onions which lead to price crashes and losses for farmers. (35)

Need for improved access to affordable credit and financial services for farmers, particularly small and marginal farmers to enable them to invest in inputs, technology and infrastructure. (36)

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दिए जाने की आवश्यकता ।(37)

SHRI RAJEEV RAI (GHOSI): I beg to Move:

Need to establish a Farmers and Agricultural Labourers Commission to undertake measures for holistic development of farming communities. (38)

Need to provide insurance scheme for farmers and agricultural labourers dying in harness or getting injured while engaged in agricultural works. (39)

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): I beg to Move:

Need to provide legal guarantee for Minimum Support Price (MSP) of agricultural produce, as demanded by various farmer unions. (40)

Need to revise the policy and procedure of assessing damages for crop insurance on an individual farmer's basis, instead of Firka or Taluka or Block level basis. (41)

Need to consider damages caused to agricultural crops by peacocks, wild boars, elephants and other wild animals for paying compensation under the crop insurance policies. (42)

Need to increase budgetary allocation for National Project on promotion of organic farming. (43)

Need to increase budgetary allocation on capital outlay for soil and water conservation. (44)

Need to ensure production and timely distribution of climate resilient high yielding seeds to farmers. (45)

Need to devise plan for boosting domestic oilseed production to achieve self-reliance in edible oils in near future. (46)

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): I beg to Move:

Need to allocate more funds for proper implementation of Minimum Support Price (MSP) for farmers to ensure fair remuneration and price stability. (47)

Need to allocate more funds to improve access to credit and crop insurance for small and marginal farmers to enhance financial security and resilience against crop failures. (48)

Need to allocate more funds to promote sustainable and organic farming practices and to encourage environment-friendly agricultural methods and also to reduce chemical dependency. (49)

Need to allocate more funds to ensure timely distribution of quality seeds and fertilisers to improve crop yields and productivity. (50)

Need to allocate more funds to strengthen Farmer Producer Organizations (FPOs) for better market access and collective bargaining power. (51)

Need to allocate more funds to improve post-harvest storage and cold chain infrastructure to reduce agricultural wastage and increase profitability for farmers. (52)

Need to allocate more funds to ensure timely and efficient disbursement of PM-KISAN payments to all eligible farmers particularly from Sangli. (53)

श्री राजकुमार रोट (बांसवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

राजस्थान के डूंगरपुर में आदिवासी बहुल बांसवाड़ा क्षेत्र में छोटे भूमिधारक किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी की आवश्यकता ।
(65)

बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (राजस्थान) के डूंगरपुर जिले में प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना से जोड़ने की आवश्यकता ।(66)

किसानों द्वारा उत्पादित सभी फसलों पर एमएसपी के कार्यान्वयन की आवश्यकता ।(67)

बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डूंगरपुर जिले (राजस्थान) के किसानों को ऋण प्रक्रिया को सरल बनाकर अधिक ऋण देने की आवश्यकता ।(68)

विशेष रूप से बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के झुंगरपुर जिले (राजस्थान) में किसानों द्वारा कृषि उपकरणों पर लिए गए ऋण को माफ करने की आवश्यकता ।(69)

बांसवाड़ा के झुंगरपुर जिले के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की आवश्यकता क्योंकि मिट्टी परीक्षण के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी नहीं किए गए हैं ।(70)

श्री अमरा राम (सीकर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पादों के एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता । (75)

सभी कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की आवश्यकता ।(76)

कृषि उपज के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के लिए निधि बढ़ाने की आवश्यकता ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को भरपूर फसलों के दौरान पर्याप्त लाभ मिले ।(77)

टमाटर और अन्य सब्जियों को बाजार हस्तक्षेप स्कीम के तहत शामिल करने की आवश्यकता ताकि किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके ।(78)

तिलहन और दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष पैकेज देने की आवश्यकता । (79)

पीपीपी मॉडल के तहत कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) को बड़ी कंपनियों को सौंपने के कारण होने वाले नुकसान को रोकने की आवश्यकता । (80)

हमारे किसानों को कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित उच्च गुणवत्ता और किफायती बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता ।(81)

कृषि तालाबों, ग्रीनहाउस और इसी तरह की अन्य परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए निधि बढ़ाने की आवश्यकता । (82)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनके फसल नुकसान की भरपाई सैटेलाइट इमेजिंग विधि के बजाय फसल कटाई विधि के आधार पर करने की आवश्यकता ।

(83)

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

किसानों को बिजली सब्सिडी देने के लिए विशेष फंड बनाने की आवश्यकता । (84)

बीजों पर सब्सिडी देने और किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता । (85)

किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये करने की आवश्यकता । (86)

चीनी मिलों के लिए नीति बनाने की आवश्यकता ताकि गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर समय पर भुगतान मिल सके ।

(87)

एमएसपी के लिए कानूनी प्रावधान बनाए जाने की आवश्यकता ताकि गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके ।

(88)

किसान सम्मान निधि के पारदर्शी वितरण और यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि भूमि रिकॉर्ड रखने वाले सभी किसानों को किसान सम्मान निधि मिले । (89)

मध्यम और छोटे किसानों के लिए ऋण माफी के लिए नीति बनाए जाने की आवश्यकता । (90)

2025 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नया किसान आयोग बनाए जाने की आवश्यकता । (91)

TOKEN

कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 7) में 100 रुपए कम किए जाएं ।

2

श्री राजेश रंजन (पूर्णिमा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

बिहार के कोशी-सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया मंडल में कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता । (92)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

नागौर में केन्द्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय की स्वीकृति की आवश्यकता । (95)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to Move:

Need to provide funds for establishment of National level agricultural institute at Kollam. (96)

PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD (MUMBAI NORTH-CENTRAL): I beg to Move:

कृषि क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक व्यापक और मानकीकृत प्रणाली शुरू करके शिक्षा और प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता । (100)

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI):

Need to allocate more funds to strengthen agricultural research and education facilities in Sangli to promote innovation, best practices and knowledge-sharing among farmers. (101)

Need to allocate more funds to develop climate-resilient crop varieties through advanced agricultural research to mitigate the impact of climate change on farming. (102)

Need to allocate more funds to establish agricultural innovation hubs in collaboration with universities and research institutions to promote farmer-led innovations and knowledge dissemination. (103)

Need to allocate more funds to enhance digital and AI-driven agricultural extension services to provide farmers with real-time data, weather forecasts and best practices for improving productivity. (104)

Need to allocate more funds to set up a specialized research center in Sangli focused on improving the yield and disease resistance turmeric and grapes to boost farmer incomes and exports. (105)

SHRI SUDHAKAR SINGH (BUXAR): I beg to Move:

Need to establish dedicated Centre of Excellence for vegetables in Buxar to promote advanced research, seed development and high-yield vegetable farming for farmers in Bihar. (106)

Need to set up a full-fledged Indian Council of Agricultural Research (ICAR) research institution in Buxar to focus on regional agricultural challenges, promote scientific innovation and support farmers with better techniques and resources. (107)

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आरसीएम कॉलेज, धामपुर को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता । (110)

उत्तर प्रदेश के नगीना में अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता । (111)

उत्तर प्रदेश के नगीना में गेहूं, चावल और गन्ने के लिए नए और अलग-अलग अनुसंधान केंद्र खोले जाने की आवश्यकता । (112)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को रिटन स्पीचेज़ देनी हैं, वे टेबल पर तुरंत अपनी स्पीच दे सकते हैं । Hon. Members, those who want to lay their written speeches on the Table, can do so. It will be treated as part of the proceedings.

Hon. Member, please start.

श्री जय प्रकाश (हिसार) : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । भारत एक कृषि प्रधान देश है । कृषि प्रधान देश होने के साथ ही, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के रोज़गार कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए एमएसपी के बारे में बहुत चर्चाएं की जा रही हैं । उधर की सरकार की तरफ से भी मैसेज आया, हरियाणा प्रदेश की सरकार का चुनाव हो रहा था, इन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में 24 फसलों के लिए एमएसपी दिया है । मैं आपके माध्यम से, सबसे पहले माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या एमएसपी अभी शुरू हुआ है या यह वर्ष 2014 से पहले भी था क्योंकि वर्ष 2014 से पहले के बारे में लोग बात नहीं करते हैं । मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मुझे याद है, देश की आज़ादी के समय में, कांस्टिट्यूेंट असेम्बली में भी एमएसपी का मुद्दा उठाया गया था और स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी ने इस मुद्दे को उठाया था । उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि देश के विकास के लिए कृषि के उत्पादन का मूल्य देना अति आवश्यक है, तो तब से यह इश्यू चल रहा था । माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, जब देश ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से भीख का कटोरा लेकर दूसरे देशों में गेहूँ और दूसरे अनाजों की भीख मांगता था, आज भारतवर्ष में ग्रीन रिवोल्यूशन की जो क्रांति आयी है, तो यह कांग्रेस पार्टी की देन है । मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है ।

अब बात आती है एमएसपी की । मेरे साथी अनुराग जी अभी यहाँ पर नहीं हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में धान की एमएसपी 1310 रुपए थी, गेहूँ की एमएसपी 1,400 रुपए थी । वर्ष 2024 में धान की एमएसपी 2320 रुपए थी और गेहूँ की एमएसपी 2450 रुपए थी । दस वर्षों में एक हजार रुपए की वृद्धि हुई । एक दिन चर्चा चल रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज डीएपी के भाव में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे, तो वे अपने जवाब में बताएंगे । आज डीएपी का भाव 1600 रुपए है । यूपीए सरकार के समय में इसका भाव 900 रुपए था । यूरिया का भाव 265 रुपए था । आज यूरिया का भाव 300 रुपए से ज्यादा है ।

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने दस वर्षों में एक सौ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से एक हजार रुपए की वृद्धि कर दी, लेकिन जिस तरीके से यूरिया के भाव और कीटनाशक दवाइयों के भाव में बढ़ोतरी हुई है, जो कीटनाशक दवाई 200 रुपए में आता था, आज वह 850 रुपए का है। जो बीज 50 रुपए किलो मिलता था, आज दस वर्षों में वह 150 रुपए किलो हो चुका है। यानी किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली चीजों के दाम में वृद्धि की जा रही है और किसान की फसलों का एमएसपी घटता जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हरियाणा में हमारी सरकार बना दो हम 3,100 रुपए का भाव दे देंगे। लेकिन आज हरियाणा में तो 2,300 रुपए भी नहीं मिल रहा है।

सर, कुल 1,600 रुपए प्रति किंटल के हिसाब से धान की फसल हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कौड़ियों के भाव पर खरीदी गई। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि या तो इसकी जाँच कराओ, अगर हरियाणा और पंजाब में धान 10 परसेंट धान भी एमएसपी पर बिका हो, तो मुझे दण्डित कर देना वरना जिन लोगों ने ये पैसे लिये हैं, चूंकि किसानों के खाते में पूरे पैसे भेजे गए और यह कहा गया कि फसल में मॉइस्चर ज्यादा है, ज्यादा ब्रोकेन है, इसलिए किसानों को कम पैसे दिए गए। यह लूट है।

मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, याद होगा कि यूपीए सरकार में आपने स्वामीनाथन कमीशन का इश्यू उठाया था, स्वामीनाथन कमीशन की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी के लोग अर्धनंगा होकर सड़कों पर घूम रहे थे और जब उनकी सरकार आई तो वह ? * बैठ गए। मैं उस समय विधान सभा का सदस्य था। आज वे इस हाउस के सदस्य हैं, हमारे कृषि मंत्री जी बोल रहे थे, मैंने कहा कि धनखड़ साहब याद करो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए आपने चुनाव-घोषणा पत्र में कहा था, यह क्यों नहीं लागू हुई?

HON. CHAIRPERSON : The words ... * should be deleted.

श्री जय प्रकाश: इस दौरान, स्वामीनाथन कमीशन के जो मद थे, उनको पूरा करने के लिए यूपीए सरकार में डॉ. मनमोहन सिंह जी ने एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स बनायी थी, उसमें चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, मायावती जी थीं। उस

वक्त माननीय नरेन्द्र मोदी जी भी उसमें थे । यह आपको भी याद होगा । उस वक्त यह फैसला हुआ था ।

आज आप जो किसान के कर्ज की बात करते हैं, किसानों के 60 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफ हुए, तो वह यूपीए सरकार में हुआ ।

आपने चंद परिवारों के, साहूकारों के, धन्ना सेठों के 17 लाख करोड़ रुपए माफ करने का काम किया । ? (व्यवधान) इस देश के लोग यह चाहते हैं कि खून और पसीने की कमाई से सूखी धरती का सीना सींचकर इस देश में वे अन्न पैदा करें । हमारे अन्न का लाभ चंद लोग उठाएं, धन्ना सेठ उठाएं, मैं इसका विरोध करता हूं ।

मंत्री जी, अनुराग जी चले गए हैं, कल ही मैंने पढ़ा है कि आज हिमाचल प्रदेश का किसान बड़ा दुखी है । अमेरिका के वॉशिंगटन से जो सेब आएगा, अगर उसकी एक्साइज ड्यूटी आपने कम कर दी, तो हमारा सेब डूब जाएगा । इसलिए, मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि किसान के खेतों में जो भी फसलें पैदा होती हैं, उनका भाव ज्यादा से ज्यादा दिलाने का काम करें ।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं । हमारे साथी मंडियों की बात कर रहे थे । आपने एक सर्कुलर और निकाल दिया है । 25 नवंबर, 2024 को कृषि विपणन पर जो चिट्ठी निकाली गई है, वह किसानों के लिए काला संदेश है, काला वॉरंट है । इस देश में विपणन का सिस्टम, जैसा कि मैंने आपकी चिट्ठी में मैंने पढ़ा है, यदि उसको लागू कर दिया गया, तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा ।

आप किसान निधि की बात करते हैं । वर्ष 2019 से लेकर आज तक किसानों को छः हजार रुपए मिलते हैं । अब डीजल के दामों पर आते हैं । डीजल का दाम वर्ष 2004 में 22 रुपए था । अब मैं जो बताना चाहता हूं, उससे बीजेपी के साथियों को तकलीफ होगी । मंत्री जी, वर्ष 2004 में डीजल 22 रुपए का था और आज डीजल की कीमत 100 रुपए है । कितना बढ़ा? एक ड्रम में सात हजार से ज्यादा रुपए बढ़ गए । यह बात आप लोगों को बताओ । आप किसानों को एक साल में छः हजार रुपए देते हो और एक ड्रम के किसानों से सात हजार रुपए लेते हो । आप किसान के सबसे बड़े विरोधी हो । किसान की सबसे बड़ी विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार है । इसने किसानों से तेल का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2014-15 में 29,289 करोड़ रुपए, डीजल

42,880 करोड़, वर्ष 2015-16 में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सर, वर्ष 2019-20 में 2,30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इन लोगों को डीजल से हुआ । यदि ये किसान का कर्जा माफ कर देते, पूरे देश के किसान पर 2,00,000 करोड़ रुपए कर्जा नहीं है, तो मंत्री जी, आप इस देश के किसान का कर्जा माफ कीजिए । किसानों को जो डीजल आपने इतना महंगा बेचा है, कूड सस्ता था, उसका जो प्रॉफिट आपने कमाया है, वही यदि किसान को दे दें, तो इस देश का किसान इस कर्जे से बच जाएगा । आज हजारों-हजार किसान आए साल आत्महत्या करने पर विवश हैं, उनकी भी जान बच जाएगी ।

सभापति महोदय, अब सिंचाई की बात आती है । खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई चाहिए है । सिंचाई के लिए इस सरकार ने क्या किया? यह सरकार कानून का राज नहीं मानती है, यह कानून को नहीं मानती है । अगर कानून को केंद्र सरकार मानती तो, मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर के लिए कहा है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर खुदवाने के लिए कहा था । क्या आपने आज तक खुदवाई?

वॉटर रिसोर्सेज़ मिनिस्टर यहां से चले गए हैं । मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था । हमारा एसवाईएल का मामला पेंडिंग है । लखवार और व्यासी दो डैम थे, वे यूपीए सरकार के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में शुरू हुए थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार थी । हमने उस पर पैसा खर्च किया था । आज यह बताइए कि उस वक्त से लेकर आज तक आपने लखवार-व्यासी डैम के ऊपर काम क्यों नहीं शुरू कराया? ताकि किसानों को नैचुरल रिसोर्सेज़ से सस्ता पानी न मिल जाए, उसकी उपज के दाम न बढ़ जाएं । किसान को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया ।

सभापति महोदय, जहां तक हमारे साथी कहते हैं, खेती के ऊपर जीएसटी 12 परसेंट है । मंत्री जी, आप भी इस बात को मानोगे? खेती पर जीएसटी 12 परसेंट है और सोने के ऊपर आपने कितनी जीएसटी लगाई? तीन परसेंट । किसान की उपज के ऊपर आपने 12 परसेंट जीएसटी लगाई है, आप किसान को कहां तक मारोगे? जब इस देश का किसान धरना देता है, आप उस मीटिंग में गए थे, दल्लेवाल साहब को गिरफ्तार करा के आ गए? लाठियों से किसानों को पीटा गया ।

सर, आजादी के बाद यदि इस देश में, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसान के लिए ऐसा राज है, जैसा अंग्रेजों का राज था । या तो अंग्रेजों के राज में लाठियां

पड़ती थीं या आज भारतीय जनता पार्टी के राज में लाठियां पड़ रही हैं । 730 किसानों को ज्यादाती दी, उसके बाद आप फिर दोबारा से वही कानून लाना चाहते हैं ।

हम इसका विरोध करेंगे । मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे काले वारंट जारी मत करो, जिससे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए । आपने मनरेगा की बात कही थी । मैं एक राय देना चाहता हूँ कि मनरेगा को खेती के साथ जोड़ दिया जाए । मंत्री जी, आप मनरेगा के ऊपर वाहवाही लूट रहे हो । आपने इसे कब चालू किया था? इसे कांग्रेस पार्टी ने चालू किया था । इसे यूपीए सरकार ने चालू किया था । डॉ. मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे । पूरी दुनिया में यदि सबसे बड़ा रोजगार का एक सिस्टम अडॉप्ट किया था, तो वह यूपीए सरकार ने किया था । भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि किसान की भलाई के लिए आपने क्या किया है? आपने किसान कल्याण महकमा, किसान कल्याण विभाग लिख तो दिया, लेकिन आपने किसान के कल्याण के लिए क्या किया है? आपने किसान के कल्याण के लिए यह काम किया है, आपने एमएसपी दिया नहीं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की । जब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स की बात आयी थी, तो उस वक्त क्या हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ कि तीन लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म, आपको याद होगा, नेशनलाइज्ड बैंक 12 परसेंट पर लोन देते थे, यूपीए सरकार ने उसे चार परसेंट किया था । उस समय हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने आज से 11-12 वर्ष पहले उसे माफ कर दिया था । अगर लोन माफ न हुआ हो तो माननीय सांसद धर्मबीर सिंह जी बता देंगे । भाई आप बता देना कि हमने हरियाणा में माफ किया था या नहीं । मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान के खेत की उपज को बढ़ाने के लिए जो कल-पुर्जे लगाये जाते हैं, उन पर बहुत भारी टैक्स है और सोने के ऊपर तीन परसेंट टैक्स है । आप एमएसपी को कानून की गारंटी क्यों नहीं बनाते हो? ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह लूट का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के धन्ना सेठों के लिए दिया है । मंत्री जी मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप घड़ी मत देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा ही बोलूँगा । एक बात प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना की आयी थी । मंत्री जी ने उस दिन प्रश्नकाल में बहुत विस्तार से बताया था । मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में बहुत बड़ी लूट हो रही है । हमने जब इसे शुरू किया, पहली बात तो मैं सदन को बताना चाहता हूँ और मंत्री जी को अपने जवाब में बताना चाहिए कि किसान कृषि बीमा योजना किसके राज में शुरू हुई ।

महोदय, यह योजना कांग्रेस के राज में शुरू हुई थी । कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के 115 में से 100 मद उसी वक्त लागू करने का प्रयास किया था । एक काम हमसे अधूरा रहा था कि एमएसपी की कीमत कैसे निर्धारित करें । आपने अपने इन 11 सालों में भी C2 प्लस 50 प्रतिशत का फॉर्मूला लागू करने का काम नहीं किया है । बाकी जो ब्याज की माफी की बात थी, इंटरेस्ट की माफी की बात थी, इसे कांग्रेस पार्टी ने किया है । भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के चंद धन्ना सेठों का भला तो किया, लेकिन किसान का कोई भला नहीं किया । यह तो किसान को... * है । आपको याद होगा कि कांग्रेस, यूपीए की सरकार से पहले बहुत सस्ते भाव से जमीन एक्वायर की जाती थी और लैंड एक्कीजिशन की लड़ाई माननीय राहुल गाँधी जी ने भट्टा-पारसौल से लड़ी । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल जी और उनके साथियों को गिरफ्तार किया । राहुल क्या कह रहे थे? राहुल जी केवल एक बात कह रहे थे कि जिस तरीके से हरियाणा में एक लैंड एक्कीजिशन एक्ट बनाया हुआ है, वह पूरे देश में लागू हो । उत्तर प्रदेश में उसे लागू नहीं किया । पूरे भारतवर्ष में हमारी यूपीए सरकार ने उसे लागू किया और आपने आकर के उस लैंड एक्कीजिशन एक्ट को भी बदल दिया । आपने उसमें दो गलत धाराएँ जोड़ दीं । किसान की जमीन...* का काम किसी ने किया है, तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है । मैं मंत्री जी से नरेगा के लिए कहना चाहूँगा और विशेष तौर से एमएसपी के लिए कहना चाहूँगा कि इसे कानून की गारंटी का दर्जा दे दो ।? (व्यवधान)

महोदय, आप भी मानोगे कि किसानों को एमएसपी के कानून की गारंटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए ।? (व्यवधान) आप बता दीजिए ।? (व्यवधान) मंत्री जी, आप बताइए ।? (व्यवधान) मिलनी चाहिए ।? (व्यवधान) अगर एमएसपी को कानून की गारंटी दोगे तो इस देश का किसान बचेगा । तब हम मानेंगे और अगर एमएसपी को कानून की गारंटी नहीं दी तो आप किसानों के सबसे बड़े शत्रु हो । यदि आज इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो हम किसानों को लाभकारी मूल्य देते । आपने तो जनता को भ्रमित करने का काम किया है ।

सभापति जी, माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि वर्ष 2022 में हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे । आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? वर्ष 2022 की ग्रोथ रेट 4.7 थी जो वर्ष 2024 में घटकर 1.4 ग्रोथ रेट हो गई । किसान की आय घटने की वजह से किसानों के बेटे खेती से मुहं मोड़ रहे हैं लेकिन उनके पास

रोजगार भी नहीं हैं । मोदी जी ने वायदा किया था कि दो करोड़ लोगों को सालाना रोजगार दूंगा, यदि किसान के बेटों को रोजगार मिल जाता तो वे डंकी रूट के माध्यम से विदेशों में क्यों जाते? मैं नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि देश की रीढ़ की हड्डी किसान हैं, किसान और किसानों को बचाना है तो स्वामीनाथन कमीशन के जो मद बचे हैं, क्योंकि हमने तो बहुत मद लागू कर दिए थे लेकिन जो मद आपके बचे हैं जैसे सी-2 प्लस 50 परसेंट का फार्मूला, आप उसे लागू करवाओ । स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाकर इस देश को अन्नदाता बनाकर सारी दुनिया में अन्न भेजा था ।

महोदय, मेरा एक सुझाव है । पहले एफसीआई के गोदाम खुली बोली में दिए जाते थे लेकिन आज एक ही व्यक्ति को पूरे भारत वर्ष के भंडारण का काम दिया जा रहा है । मैं इसकी निंदा करता हूँ । मंडियों को बंद करने की जो चिट्ठी आपने लिखी है, उसे वापस मंगवा लो वरना देश का किसान और मजदूर सड़कों पर आकर आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने में विवश हो जाएगा । आप पहले ही 730 किसानों की शहादत आप ले चुके हैं । आप तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक निकले हैं । अंग्रेजों के राज में हमारे पूर्वज सोचते थे कि हमें कैसे भी हो देश आजाद कराना है लेकिन आज आजादी के बाद भी एक ऐसा राज देश के लोग ले आए कि किसानों को शहादत देनी पड़ी । मैं निवेदन करूंगा कि केवल 2.5 परसेंट बढ़ाया है । कृषि मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिए कृषि को मजबूत करेंगे लेकिन इतनी-सी बजट में बढ़ोतरी करके कैसे कृषि को मजबूत कर सकते हैं । मैं इसकी निंदा करता हूँ ।

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : आज बजट पर बहस हो रही है, मगर कृषि मंत्रालय का बजट देखकर लगता है कि सरकार ने किसानों को "बजटीय सूखा" देने का फैसला कर लिया है । पिछले साल के 1.31 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार 2.5 परसेंट की कटौती करके इसे 1.27 लाख करोड़ तक सीमित कर दिया । यानी, पूरे केंद्रीय बजट का महज 2.7 परसेंट । सभापति जी, ये आँकड़े नहीं, किसानों के साथ सरकार के प्रेम का सटीक गणित है । देश की 46% आबादी कृषि पर निर्भर है, मगर सरकार की नजर में ये आधी आबादी सिर्फ 2.7 परसेंट की हकदार है । क्या यही है वह "सबका साथ, सबका विकास", जिसका ढोल सत्ता पक्ष हर चुनाव में पीट जाता है? क्या सब में किसान शामिल नहीं हैं ।

सरकार ने इस बजट में उच्च उपज वाले बीज, बागवानी और दलहन के नाम पर पटाखे छोड़े हैं, मगर ज़मीन पर किसानों की हालत देखिए 2022 में 12,290 किसानों और मजदूरों ने आत्महत्या की। ये सिर्फ आँकड़े नहीं, सरकार की नीतियों का क्रूर रिपोर्ट कार्ड है। किसान MSP के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उर्वरकों की कमी से जूझ रहे हैं, ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल रहा, मगर सरकार को तो डबल इनकम का खेल खेलने में मजा आ रहा है। 2019 में वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 2025 आने वाला है, मगर आय तो छोड़िए, किसानों के लिए अगर डबल हुए हैं तो वह है, डबल बकाया, डबल आत्महत्या और डबल सरकारी बेरुखी।

मुझे आज अपने संसदीय क्षेत्र के सहारनपुर के किसान सरदार वेदप्रकाश जी के बारे में बताना है, जिन्होंने प्रशासन की लापरवाही से तंग आकर आत्मदाह कर लिया। उनकी ज़मीन का विवाद एक दशक से लटका था। ज़रा सोचिए, जिस सरकार को डिजिटल इंडिया पर इतना नाज़ है, उसके अधिकारी एक किसान की गुहार सुनने के लिए ऑफलाइन क्यों हो जाते हैं।

किसान की समस्या को क्यों नहीं हल कर पाते हैं। जब उस किसान की कहीं सुनवाई नहीं हुई और प्रशासन उसकी जमीन को कुर्क करने पहुंचता है तो उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। इसके अलावा ग्राम कलसी में भी किसान धरनारत है, यहां सरकार ने उनकी जमीन तो हाईवे के निर्माण के लिए ली, लेकिन उन्हें श्रेणी के जाल में उलझा कर उन्हें मुआवजे से वंचित कर दिया है। शामली का मामला भी किसानों की बदहाली का आईना है। NHAI ने किसानों की ज़मीन तो ले ली मगर मुआवजा देने में सरकार ने इतने पेच लगा दिए कि उन्हें बाजार की दर से भी कम मुआवजा मिल रहा है और किसानों से ग्राम भाजू के करीब कट का वादा सरकार के अधिकारियों ने किया था लेकिन उसे भी सरकार पूरा नहीं कर रही है इस मांग को पूरा करने के लिए धरने पर बैठे एक किसान की ठंड से मौत हो गई। क्या यही है अच्छे दिन का सपना? क्या सरकार को लगता है कि किसानों के साथ फुटबॉल-फुटबॉल खेलने से उनकी समस्याएँ हल हो जाएंगी। किसान अब लंबे समय तक मूर्ख बनने वाला नहीं है। उसकी समस्याओं का वाजिब हल ढूंढ के ही देना पड़ेगा।

GST पर बात करना भी ज़रूरी है । ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसे कृषि उपकरणों पर 12 परसेंट टैक्स सरकार को लगता है कि किसान अमेज़न प्राइम से खेती का सामान मँगवाते हैं? ये टैक्स छोटे किसानों के लिए कर्ज़ का बोनस है । अगर सरकार को सच में किसानों की फिक्र है, तो GST की बजाय किसान-फ्रेंडली टैक्स स्लैब क्यों नहीं बनाते?

उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो गन्ना किसानों की तकलीफें अंतहीन हैं । FRP अभी तक घोषित नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस वर्ष गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया है मेरे जनपद शामली में चीनी मिलों ने 103 करोड़ रुपए का भुगतान रोक रखा है । थानाभवन की मिल पर किसान धरनादे रहे हैं । आज वहां के किसानों ने जिला प्रशासन को ऑफर दिया है कि हम अपनी संपत्ति के सारे कागज आपको दे रहे हैं तो डीएम साहब इसे बेचकर ही आप हमें पैसा दे दीजिए । 42 रुपए प्रति किलो बिक रही है । जब समाजवादी सरकार में चीनी 36 रुपये किलो थी, जब भी गन्ने का रेट इतना ही था, जितना आज है । सरकार कहती है किसान अन्नदाता हैं, मगर अन्नदाता को अपना हक पाने के लिए भीख माँगनी पड़ रही है । DAP और यूरिया की कमी ने तो किसानों की बुवाई को लॉटरी बना दिया । किसान को पता ही नहीं कि मैंने बीज तो बो दिया है, परंतु वक्त पर मुझे खाद और दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी । उत्तर प्रदेश में खाद और दवाई का समय पर मिलना ऐसा है, जैसे लॉटरी लग गई हो । लगता है, सरकार का फर्टिलाइज़र मिशन असल में मिशन अधूरा है ।

सरकार ने PM-KISAN की राशि बढ़ाने की सिफारिश को भी नज़रअंदाज़ किया है । संसदीय समिति ने 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करने को कहा था, मगर सरकार को लगता है कि किसान खुशहाली के लिए छोटे सिक्के से ही काम चला लेंगे । और तो और, कृषि श्रमिकों को विभाग के नाम में शामिल करने का सुझाव भी धूल खा रहा है । शायद सरकार को लगता है कि नाम बदलने से कृषि श्रमिकों की मजदूरी ऑटो-इंप्रूव हो जाएगी ।

हमारी माँगें स्पष्ट हैं ।

1. MSP कानूनी बनाएँ, नहीं तो किसानों के आंसू राष्ट्रीय नदी बन जाएँगे ।
2. गन्ने का FRP तुरंत घोषित करें वरना चीनी मिलों का मीठा धंधा किसानों का कड़वा सच बन जाएगा ।

3. कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि श्रमिक जोड़ें शायद तब सरकार को याद आए कि खेतों में सिर्फ मालिक ही नहीं, मजदूर भी पसीना बहाते हैं ।
4. GST घटाएँ ट्रैक्टर पर टैक्स नहीं, सपोर्ट लगाएँ ।
5. भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता नहीं तो किसान जमीन से ज्यादा कोर्ट-कचहरी में उगाएँगे ।

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): In 2025-26, Rs 1,37,757 crore has been allocated to the Ministry (2.7% of the union budget). The allocation towards the Ministry is estimated to decrease by 2.5% over the revised estimates of 2024-25. According to the revised estimates of 2024-25, the expenditure of the Ministry has increased by 6.8% over the budget estimate. The inflation is much higher and the increase in the cost is still going high. This means the budget allocation for 2025-26 literally reduced. But the Finance Minister juggles with just numbers. this is a government which professes so much about the welfare of Farmer has totally ignored about their peace and prosperity. It is unfortunate that the union budget is silent about the need to implement the recommendations of the Dr. M.S. Swaminathan Committee for the welfare of farming community and the need to provide remunerative prices to farmers for their agriculture produce in order to save them from abject poverty and miserable conditions, leading to suicides.

Out of the total allocation to the Ministry, 92% is estimated to be spent by the Department of Agriculture and Farmers' Welfare while the remaining is estimated to be spent by the Department of Agricultural Research and Education.

The Department of Agriculture and Farmers' Welfare spends 77% of its budget on three major schemes: PM-Kisan Samman Nidhi (direct cash transfer of Rs 6,000 per year per farmer family). Modified Interest Subvention Scheme, and Crop Insurance Scheme.

The Economic Survey (2023-24) also noted that several issues affect the growth in the agriculture sector. These include:

Fragmented land holdings.

Low productivity of agriculture,

Insufficient access to quality inputs,

Inadequate access to marketing infrastructure,

High Dependency on rains and poor irrigation infrastructure,

Lack of farm mechanisation, and

Poor access to farm investment mechanism

It is indeed a great achievement of the farmers of the country whose untiring hard labour has showed the world that farmers feed the people of all walks of life. It's true that many countries have experienced scarcity of food grains and faced starvation during the Corona crisis. But we in India have ensured that nobody remained hungry during the worst pandemic in 100 years. The credit goes to our Farmers and sons of the soil.

Uzhudhuntu Vaazhvaare Vaazhvaarmar Rellaam

Thozhudhuntu Pinsel Pavar

Which means, they alone live who live by agriculture; all others lead a cringing, dependent life.

I would like to give maximum credit to the small farmers of the country for this consistent success and strengthening the agriculture sector. Under the PM-Kisan Samman Nidhi, I would like to suggest that the Government should increase this to Rs. 12,000 per annum and also include the landless agricultural workers who are the backbone of the country.

It is very unfortunate that the incidence of death by suicide by farmers and farm workers is on the rise. More than one lakh farmers have committed suicide in the last 10 years. According to the report of National Crime Records Bureau 30 farmers die every day by committing suicide in spite of the tall claims of farm loan disposals by the Government. A country cannot be considered a developed one, when the Sons of the soil, farmers live in utter distress and penury.

In Tamil Nadu our Beloved leader Dr. Kalaignar. M. Karunanidhi has announced free electricity for the farmer's in the year 1989. It still continues in Tamil Nadu under the dynamic leadership of Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Thalapathy M.K. Stalin. The union Government should follow the footsteps of Tamil Nadu. The Union Government should waive off all farm loans provided to Farmers from all Banks including all Co-operative banks in the country and MSP should be implemented.

India is a global agricultural powerhouse, leading in milk, pulses, and spices production, and also ranks second in rice, wheat, cotton, sugarcane, and other key crops, with a large portion of its land cultivated, though much of it is rain-fed.

India has a total geographical area of 328.7 million hectares, with around 54.8% used for agricultural land. About 141 million hectares is the reported net sown area, and 219.158 million hectares is the gross cropped area. The net irrigated area during 2021-22 was 77.9 million hectares, with tube wells being the primary source of irrigation. Around 63% of the cultivated land is rainfed (roughly 125 million hectares), while 37% is irrigated (70 million hectares).

India is the world's largest producer of milk, pulses, and spices, and second-largest producer of rice, wheat, cotton, sugarcane, farmed fish, sheep & goat meat, fruit, vegetables, and tea.

According to 2022-23 Agriculture data, India's foodgrain production had touched 330.5 million metric tons and horticulture output hit a record 351.92 million tons.

India's agricultural exports have seen significant growth, increasing from USD 22.70 billion in 2013-14 to USD 48.15 billion in 2023-24.

Leading agricultural exports include marine products, basmati and non-basmati rice, spices, buffalo meat, sugar, and miscellaneous processed items. The USA, China, UAE, and Saudi Arabia are major importers of India's agricultural products.

Marine products exports were valued at over 610 billion Indian rupees in FY24. In April-July 2024, the overall value of agricultural exports stood at US\$ 15.76 billion. During FY24, India exported 19,678 metric tonnes of floriculture products, earning Rs.717.83 crore (USD 86.63 million). India is also a leading exporter of fresh grapes, shipping 343,982.34 MT worth Rs.3,460.70 crore (USD 417.07 million) globally in 2023-24. But the farmers and farm workers agro based people are penalized by the union Government. They suffer silently in penury and agony.

Agriculture employs more than 50% of the Indian workforce. The economic contribution of agriculture to India's GDP is steadily declining with the country's broad-based economic growth. Rice and wheat are major food grains, accounting for a large portion of the total food grain production. Sugarcane, cotton, groundnuts, and fruits and vegetables are also significant crops. India is a leading producer of milk, with a large cattle population, and is also a significant exporter of beef and veal.

Taking the average household size of marginal farmers to be 5.7, the annual per capita income from crop cultivation is extremely low at Rs. 4308, and the monthly per capita income at Rs. 359. This is way below

the poverty line set by the Ranganathan Committee report (2014) at Rs. 972 per month per capita, i.e., Rs. 11,664 per capita annually. As expected, the per capita income increases with an increase in landholding size. The per capita income earned from crop production is higher at Rs 71670, for the farmers with large landholding sizes which is 14.5 times more than the marginal farmers. The per capita income share from crop production as a proportion to the per capita income from all sources also increases with the increase in land holding size which suggests that in the case of marginal and small farmers income from crop produces not being a viable option these farmers largely depend on wage labour for their sustenance.

In India, the average income of agricultural households from farming has been growing, albeit at a slow pace. This may be explained by a much higher increase in the input cost that barely corresponds with an increase in the price of output. Natural calamities, erratic rainfall and temperature further add to farmers' woes.

Farmers have no other option but to resort to other sources viz. livestock, wage labour and non-farm business for their sustenance and risk mitigation. The situation is quite vulnerable for the marginal (less <1 hectare) and small farmers (1-2 hectare of land) as their income is way behind that of the medium and large farmers. Nearly 86% of the land holdings in India are about two hectares, of which a sizeable number constitutes less than one hectare.

In India, the average income of agricultural households from farming has been growing, albeit at a slow pace. This may be explained by a much higher increase in the input cost that barely corresponds with an increase in the price of output. Natural calamities, erratic rainfall and temperature further add to farmers' woes.

Farmers have no other option but to resort to other sources viz. livestock, wage labour and non-farm business for their sustenance and risk mitigation. The situation is quite vulnerable for the marginal (less <1 hectare) and small farmers (1-2 hectare of land) as their income is way behind that of the medium and large farmers. Nearly 86% of the land holdings in India are about two hectares, of which a sizeable number constitutes less than one hectare.

Equally important is to bring higher efficiency in the existing marketing channels, including government procurement centres, the opening up of FPOs, cooperatives and other value chains so that farmers are able to get remunerative prices for their produce.

As mentioned above, poor farmers cannot remain dependent only on farming as a source of livelihood to meet their consumption and other expenditures.

Livestock appears to be the preferred activity, perhaps at the cost of farming. Extending credit, livestock insurance and extension services can help farmers and, also their women to take advantage of the growing opportunities in the dairy sector. Higher public investment is required in research on productivity enhancing technology with due consideration of mitigating greenhouse gas emissions, opening of veterinary clinics/hospitals, vaccination set-up centres and automation systems. Continued efforts are needed to train the rural youth to increase employment intensity in rural manufacturing and tertiary sectors, especially in agro and food processing. Strengthening small-scale rural industries with adequate financial incentive structures can also be helpful to absorb labour.

The marginal farmers may not be efficient in the use of inputs and hence require considerable handholding of the government. Though some of

the sampled marginal farmers are aware of government facilities for the purchase of inputs, sale of produce to procurement centres/agencies and scheme of direct cash transfers, the level of utilization of these facilities/programmes by them is very low. It is important to increase awareness about the flagship programmes.

Government may initiate a differential income support scheme for marginal farmers that provides them higher support. Such a targeting is possible using the database of PM Kisan and JAM trinity.

A faster updation of land records by each state can be useful in better targeting of direct support. Government should issue a farmer card to women farmers and labourers to enable them to avail the benefits under various schemes.

The pace of public investment in canal irrigation, research, extension, and rural infrastructure should be continued to incentivize farmers to make investments. Due to increasing migration of male members in the family, women tend to look after farming. Investment support for machinery/farm implements and opening of app based custom hiring centres can improve mechanization and enable them to grow diverse crops, augment yield and generate surplus.

In a vast country like our India, while some places are severely affected by scarcity of rainfall and drought, some places are affected by excess rainfall and flooding. While parts of Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan are affected by severe drought due to shortage of rainfall during the crop seasons, the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and west Bengal are affected severely by cyclones and floods. In both the instances the farmers are most affected as their crops are damaged completely. Hence the Farmers are in the clutches of either a severe flood or drought. This is a very bad situation for farmers of this

country. It not only affects their crops but also make them suffer most to repay their loans resulting in the suicides of farmers in the country.

Agriculture and agro based industries are the back bone of our country. Farmers and Agro-based allied workers constitute about 60% of our total population. Braving most difficult problems our farmers continue to toil hard to fulfill our farm needs. Their service and sacrifices has to be appreciated appropriately for them to engage continuously practice agriculture. Farmers need to be encouraged with financial support as well as ensuring them with adequate supply of seeds. fertilizers, insecticides & pesticides farm equipments etc.

Farmers should be encouraged with good reasonable Minimum Support Price (MSP) for their produce. There are hundreds of crops raised by our farmers, but MSP is not fixed for all the farm produce. The government needs to pay more focus and attention in this area.

The Government should also instill confidence in their minds by effecting good procurement policies. Without these two vital actions farmers will be reluctant to take up agriculture and will affect our agrarian economy and agriculture will decline fast. As a result we will be dependent on imported goods from foreign countries, which again increase the price.

More than 55% of Indians make a living from farming, with agriculture being the largest source of livelihoods in the country. In 2024, agriculture accounted for 23% of India's GDP and employed 62% of the country's total workforce.

A large proportion of farmers in India are small and marginal farmers, with around 86% having less than one hectare of land. A significant portion of India's population lives in rural areas, with 65% of the country's

population living in rural areas. About two-thirds of India's population depends on agriculture.

At the moment the road to recovery is dim. The union government which pluck and sucks majority of the revenue generated from the productive States and caters according to their agenda, especially to their Vote bank states like UP, Bihar, Madhya Pradesh, Assam and other North eastern states. The Government attitude of robbing Peter to pay Paul must be stopped. Otherwise there will be unrest in the country in as far as the revenue sharing.

Once upon a time, the mind voice of the people of southern States like Tamil

Nadu, Kerala, Telangana, Karnataka was

Vadakku Vazhkirathu Therku Theikirathu

now their mind voice changed to

Vadakil Vennai therki Sunnambu

The Union Government must bring in a comprehensive policy to encourage productive States and ensure adequate support to States like Tamil Nadu.

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): Agriculture is the backbone of our nation, and the sweat and toil of our farmers sustain not just our economy but the very lives of our people. Yet, they continue to face numerous challenges that demand urgent intervention from this Government.

Fair Prices and Market Reforms: One of the major challenges our farmers face is the issue of fair pricing. While they put in immense effort in cultivating crops, the returns they receive are often insufficient. The implementation of Minimum Support Price (MSP) for all major crops

needs to be strengthened, and procurement mechanisms must be streamlined to ensure farmers get fair compensation for their produce. The delay in payments under procurement schemes must also be addressed to protect their financial security.

Irrigation and Water Conservation: Water scarcity remains a persistent issue in Nashik and many other parts of India. There is a dire need to expand irrigation facilities and promote sustainable water management techniques, such as micro-irrigation, watershed management, and efficient canal systems.

Crop Insurance and Financial Assistance: the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has been a significant step in securing farmers against losses. However, there have been grievances regarding delays in insurance claim settlements and discrepancies in the compensation for our farmers. Special schemes should be designed to provide timely financial support with lower interest rates, reducing their dependency on informal lenders who exploit them.

Strengthening Farmer Producer Organizations (FPOs): Farmer Producer Organizations (FPOs) have been instrumental in improving the bargaining power of small farmers. However, they need greater financial support, skill development programs, and market linkages.

Control Over Prices of Pesticides, Seeds, and Fertilizers: Another major concern is the increasing prices of essential agricultural inputs such as pesticides, seeds, and fertilizers, which are often dictated by private companies. These rising costs put an additional financial burden on our farmers, reducing their profitability. Additionally, strict monitoring should be in place to prevent hoarding and artificial price hikes by companies.

Problem of Farmers in my Constituency: Additionally, I would like to bring to the attention of this House the urgent need to remove the 20% export

duty on onions to address falling domestic prices, surplus production, and rising global competition. Onion prices have dropped to 15-20 per kg due to peak arrivals from Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, and Bihar, with further declines expected.

Competing nations like Pakistan and China are offering onions at \$125 per ton cheaper, capturing markets in Far East Asia and the Gulf nations, which have traditionally been dominated by Indian exporters. Even Bangladesh has reduced imports from India, and the continuation of the export duty since December 2024 has further weakened India's position, impacting farmers and exporters.

Our farmers are the lifeline of this country, and we must ensure their well-being. I urge the Government to address these concerns with the urgency they deserve. A prosperous farmer leads to a prosperous nation. We must stand together to protect their interests and provide them with the dignity, security, and respect they rightfully deserve.

प्र. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : मैं आज हमारे किसानों की बात करूंगी-जो भारत की रीढ़ हैं ।

जवाहरलाल नेहरू जी ने 1948 में कहा था, "सब कुछ इंतज़ार कर सकता है, लेकिन खेती नहीं ।" ये एक वादा था कि खेती को पहले रखा जाएगा । लेकिन 2025 में, हमारे किसान इंतज़ार कर रहे हैं-मदद का, उम्मीद का, और एक ऐसी सरकार का जो सचमुच उनकी परवाह करे ।

#लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, 'जय जवान, जय किसान,' कि किसान सैनिक जितने ही ज़रूरी हैं । मगर आज ये सरकार उन्हें भूले हुए नायकों की तरह छोड़ रही है ।

इस साल के बजट में खेती को 1,37,757 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है-कुल बजट का सिर्फ 2.7% । पिछले साल से 2.5% कम । हमारे देश के लगभग आधे

लोग-46%-खेती करते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3.8% बढ़ती है । इतना धीमा क्यों? क्योंकि बुनियाद ही टूटी "हुई" है ।

पानी? बड़ी चिंता । आधे खेत (44%) बारिश पर निर्भर । 2017 की रिपोर्ट ने चेताया कि समंदर ऊपर आ रहा है, तटीय ज़मीन नमकीन हो रही है, पीने का पानी गायब । सुझाव था-मैंग्रोव लगाओ, मछली-चावल की खेती शुरू करो । यहाँ क्या हुआ? Rashtriya Krishi Vikas Yojana को 8,500 करोड़-42% बढ़ा लेकिन कोई साफ योजना नहीं है । पंजाब में पानी खत्म हो रहा है, क्योंकि MSP के चक्कर में पानी पीने वाली फसलें बोई जा रही हैं । इंदिरा गांधी ने कहा था, "अगर खेती हारी, तो सब हारेगा ।" हम उसी रास्ते पर हैं ।

खाद और कीटनाशक? यह एक नुकसान का जाल बन चुका है । 2016 की रिपोर्ट कहती है, हम ज्यादा नाइट्रोजन डालते हैं-6.7:2.4:1 के अनुपात में, जबकि चाहिए 4:2:1 के अनुपात में ।

यूरिया सस्ता है, जबकि बाकी fertilizer महंगे हैं । किसान ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिट्टी खराब होती है । सरकार 1,67,887 करोड़ रुपये की subsidy देती है, लेकिन फिर भी 31% fertilizer बाहर से मंगाना पड़ता है । DAP का 50-60% और MOP का 100% import किया जाता है ।

Pesticide का इस्तेमाल 2010 में 55,540 टन था, जो 2015 में बढ़कर 57,353 टन हो गया । इस दौरान import 43% बढ़ गया । यह सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन इसे रोकने के लिए न तो सही rules हैं और न ही study के लिए पर्याप्त पैसे दिए जा रहे हैं ।

बर्बादी? दिल तोड़ने वाली । 2020-21 में 69 मिलियन टन अनाज, 1.5 लाख करोड़ रुपये का, सड़ गया । 2017 की रिपोर्ट कहती है कि हर साल 92,651 करोड़ रुपये के फल और सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की कमी है । 2008 से अब तक 102 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, लेकिन 134 अभी भी अधूरे पड़े हैं । इस साल 584 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जो पिछले साल जितना ही है । इससे फसल नहीं बचेगी । अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, 'किसान की फसल सड़े नहीं, जब देश भूखा हो ।' लेकिन सड़ रही है ।

मशीनें? अब भी दूर की बात । 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 47% खेती में मशीनों का उपयोग हो रहा है, जबकि चीन में 60% और ब्राजील में 75% है । 86% किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम ज़मीन है, जिससे वे खुद मशीनें खरीद नहीं सकते । 37,097 किराए के केंद्र हैं, जो 100-200 किसानों को मदद देते हैं, लेकिन हर गांव तक नहीं पहुँचे हैं । सस्ते औज़ार और योजना चाहिए, जिससे 25 साल में 75% मशीनीकरण हो सके । लेकिन बजट में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, मेरा अपना राज्य । यहाँ का किसान हर दिन संघर्ष कर रहा है-सूखे से, कर्ज से और सरकार की बेरुखी से । विदर्भ में बीटी कॉटन ने बड़े सपने दिखाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 7,992 किसानों ने आत्महत्या कर ली । मराठवाड़ा में 40% खेतों में पानी नहीं है ।

गन्ना यहाँ की शान है, देश के 13% चीनी उत्पादन में योगदान देता है, लेकिन पानी की कमी और MSP की गड़बड़ ने इसे बोझ बना दिया है ।

2023 की रिपोर्ट बताती है कि लंपी स्किन बीमारी ने हजारों गायों को मारा, जिससे किसानों की कमाई भी खत्म हो गई । राज्य सरकार ने थोड़ा पैसा दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है । कोल्ड स्टोरेज की समस्या भी बनी हुई है । 2017 की रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में फल और सब्जियां बर्बाद हो रही हैं क्योंकि स्टोरेज की अवस्था नहीं है । यहाँ का किसान मेहनत करता है, लेकिन फायदा चीनी मिलों और बड़ी कंपनियों को होता है । सरकार महाराष्ट्र को भूल चुकी है, और यहाँ के किसानों का दर्द सबसे ज्यादा है ।

फल, सब्जियों? एक बहा मौका बर्बाद हो रहा है । 2023 की रिपोर्ट बताती है कि हम फल और सब्जियों के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन राजस्थान में प्रति हेक्टेयर 2.79 टन और पंजाब में 18.4 टन उत्पादन हो रहा है । आपात और निर्यात में 890 करोड़ रुपये का अंतर है । झींगा 90% बाहर से आ रहा है-हम खुद इसे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे?

पैसा और बीमा? सिर्फ जाल और झूठ । किसानों पर कर्ज 24.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है, लेकिन 43% छोटे किसान सूदखोरों से कर्ज लेते हैं-शादी के लिए, खेती के लिए नहीं । बीमा के लिए 12,242 करोड़ रुपये मिले, जो 23% कम है । सिर्फ

10% किसान बीमा का फायदा * उठाते हैं, जबकि 39% किसानों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा था, "किसान की सुरक्षा, देश की सुरक्षा।" लेकिन अब वह सुरक्षा कहीं नहीं दिखती।

मोदी जी कहते हैं, "बीज से बाजार तक, किसान को ताकत देनी है।" लेकिन ताकत कहाँ? शोध के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा। 2014 की रिपोर्ट कहती है कि ICAR की बैठकें हर साल नहीं, बल्कि दो साल में एक बार हो रही हैं। 2017 में कहा गया था कि हमें मौसम के अनुसार नई फसलें चाहिए, लेकिन उसके लिए बजट कहाँ है? मोदी का "आधुनिक सपना सुनने में अच्छा लगता है-नई योजनाएँ, असम में यूरिया प्लांट-लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, फसलें कम हो रही हैं, और निराशा बढ़ रही है। ये सिर्फ बातें हैं, ट्रैक्टर नहीं।

यह सरकार भारत को नुकसान पहुँचा रही है। किसान सशक्त नहीं, बल्कि उपेक्षित हैं। नेहरू का वादा धूल में मिल गया, शास्त्री की आवाज़ अनसुनी हो गई, सिंह की चेतावनी दबी रह गई, और मोदी के वादे खोखले साबित हो रहे हैं।

झूठ की तालियां बंद करें, किसानों की मदद शुरू करें।

SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL): On behalf of CPI (M) I express my views in Demands for Grants in agriculture and farmer welfare 2025-2026.

Farmers are the backbone of India infact they are our *Annadatas*. Agriculture is the largest livelihood provider in India with an estimated 93.09 million households as agricultural and 90 and 150 million Indians are farmers.

But in 2025-2026 Rs. 1,37,757 crores have been allocated to the ministry This is simply 2.7% of the union budget.

Out of total allocation to the ministry 92% is estimated to spent by to (1,27,290 cores) dept of agriculture and farmers welfare and to rest 8% to be agriculture research and education this equation is improper.

In 1,27,290 crores 77% i.e. 98,013 crores spends for Three schemes.

(i) PM Kisan (ii) Crop insurance (iii) Crop loan interest subvention.

The small and marginal farmers are facing challenges to get these benefits.

To generate income and create employment opportunities for small and marginal farmer's union govt launched a scheme called formation and promotion of new farmers producers organisations. This scheme was totally failure scheme nothing has been done by this.

Out of the total income of an agricultural house hold, 54% was income from wages, only 22% from production yield and 17% from farming animals in Tamilnadu. Indian average is 40: 37:15. Agricultural income of 10 states are below the average.

Access to quality of seeds is measured by the seed replacement rate (SRR) It is a measure of total cropped area which is covered with certified seeds. Niti Aayog had noted that to SRR is India remains low due to a demand supply mismatch and low production. Out of the Total availability of seeds 26% was supplied by the public sector as compared to the 74% distribution but ion through private distributers. Public sector seed production to be raised to 50% so that the price of seed will be in the control.

In India about half of to agricultural area under crops is completely dependent on rainfall.

Climate change which affects the rainfall some time is may be high. Some time it may very low. We cannot store the rain water while rainfall is high. We need more reservoirs. Constructing dams and reservoirs are not done in recent periods. But it is very essential for the irrigation. We

have to allocate funds for construction dams and reservoirs as well as for micro irrigation system.

Agricultural loan waving scheme is now needed. Because as per NCRB Report 1,17,000 farmers committed suicide in the past 10 years. So please give provision of funds for waiving of loans to the small and marginal farmers.

Please implement Dr. MS Swaminathan Committee recommendations on MSP in C2+50 formula. That only give benefits in the farmer's income.

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद): आज हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2025 के बजट पर अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह बजट हमारे देश के कृषि एवं किसान कल्याण और प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं माननीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान का हार्दिक धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की हृदय से सराहना करना चाहता हूँ। उनकी तीसरी पारी की शुरुआत में ही किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पदभार संभालते ही उनका पहला निर्णय पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करना था, इस योजना के लिए 2025-26 में 63,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष के बराबर है, लेकिन इसका प्रभाव किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है। हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं। अब तक 11.8 करोड़ से अधिक किसानों को 3.24 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। हाल ही में 17वीं किस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये मिले। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक वरदान है, जो खेती की छोटी-छोटी जरूरतों जैसे बीज, खाद, और औजारों के लिए संघर्ष करते हैं। यह उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकट से उबारती है। मैं इस योजना को हमारे अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर मानता हूँ और इसके लिए सरकार को साधुवाद देता हूँ।

मोदी 3.0 सरकार हमारे अन्नदाताओं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। यह पहल न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, बढ़ती लागत, और बाजार की अनिश्चितता से निपटने का बल भी देती है।

विशेष रूप से कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा करना चाहता हूँ। यह बजट हमारे देश के अन्नदाताओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि 75% से अधिक आबादी की आजीविका का आधार भी हैं।

वर्ष 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1,37,757 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो केंद्रीय बजट का 2.7% है। यह राशि भले ही 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 2.5% कम हो, लेकिन यह किसी भी तरह से सरकार की प्राथमिकता में कमी को नहीं दर्शाता। पिछले वर्ष, यानी 2024-25 में, मंत्रालय का व्यय बजट अनुमान से 6.8% अधिक रहा, जो यह साबित करता है कि जरूरत पड़ने पर सरकार संसाधन जुटाने में कभी पीछे नहीं हटती। इस बजट में दो विभागों का स्पष्ट विभाजन है:

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग:

इसे 1,27,290 करोड़ रुपये मिले हैं, जो कुल आवंटन का 92% है। यह विभाग नीतियों को लागू करने, किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने और बीज, उर्वरक जैसे इनपुट्स के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के लिए 10,466 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले वर्ष से 3.1% अधिक है। यह विभाग भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और शिक्षा को मजबूत करता है।

यह संतुलन दर्शाता है कि सरकार तात्कालिक राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक विकास पर भी ध्यान दे रही है। यह बजट हमारे अन्नदाताओं के लिए एक मजबूत ढाल और भविष्य की राह का प्रतीक है।

हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रमुख योजनाएँ:

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अपने बजट का 77% हिस्सा तीन प्रमुख योजनाओं पर खर्च करता है, जो हमारे किसानों की रीढ़ हैं। मैं इन पर विस्तार से प्रकाश डालना चाहता हूँ:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

योजना के लिए 2025-26 में 63,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों के समान है, लेकिन इसका प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं। अब तक 11.8 करोड़ से अधिक किसानों को 3.24 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सहायता दी जा चुकी है। हाल ही में 17वीं किस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये मिले। यह पहल हमारे उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान है, जो खेती में छोटी-छोटी जरूरतों जैसे बीज, खाद, और औजारों के लिए संघर्ष करते हैं। यह योजना सूखे, बाढ़, या बाजार की अनिश्चितता के समय उन्हें आर्थिक संकट से उबारती है। यह हमारे अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, और मैं इसके लिए सरकार को साधुवाद देता हूँ।

मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MISS)

इसके लिए 22,600 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह योजना किसानों को 3% की रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण देती है। इस बजट में एक बड़ी घोषणा यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव हमारे उन मेहनती किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो आधुनिक तकनीक अपनाना चाहते हैं, ड्रोन का उपयोग करना चाहते हैं, या बड़े पैमाने पर खेती में निवेश करना चाहते हैं। पिछले दो वर्षों में बैंक ऋण में तीन गुना वृद्धि हुई है, और यह योजना उस गति को और तेज करेगी। यह खेती की लागत को कम करेगी, उत्पादकता को बढ़ाएगी, और हमारे किसानों का लाभ दोगुना करने का सपना साकार करेगी।

फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए 12,242 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले वर्ष के 15,864 करोड़ रुपये से 23% कम है। लेकिन यह कमी प्रभाव को कम नहीं करती। यह योजना 4 करोड़ से अधिक किसानों को प्राकृतिक आपदाओं - सूखा, बाढ़,

ओलावृष्टि, और कीटों से होने वाले नुकसान से बचाती है। सरकार प्रीमियम का बड़ा हिस्सा वहन करती है, ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। यह एक सुरक्षा कवच है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे अन्नदाताओं की मेहनत कभी बेकार न जाए। यह उन्हें नई फसलों और तकनीकों को आजमाने का हौसला देता है, ताकि वे खेती को और लाभकारी बना सकें।

अन्य योजनाएँ जो आधार को मजबूत करती हैं :

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY): 8,500 करोड़ रुपये, यानी 42% की वृद्धि। यह योजना राज्यों को गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, और मिट्टी परीक्षण जैसी सुविधाएँ शुरू करने की आजादी देती है, जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करती है।

कृषिउन्नति योजना: 8,000 करोड़ रुपये, 13% की बढ़ोतरी के साथ। यह फसल उत्पादकता और जैविक खेती को बढ़ावा देती है, जिससे पर्यावरण और किसानों दोनों को लाभ होता है।

PM-आशा: 6,941 करोड़ रुपये, 8% की वृद्धि। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत तिलहन और दालों की खरीद सुनिश्चित करती है, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिले।

बजट की नई पहल: भविष्य की नींव

यह बजट सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा नहीं करता, बल्कि आने वाले कल के लिए भी मजबूत नींव रखता है। मैं इसकी प्रमुख घोषणाओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ:

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

योजना 100 जिलों में शुरू होगी, जहाँ उत्पादकता कम है, फसल तीव्रता मध्यम है, और ऋण की पहुँच सीमित है। यह 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाएगी। इसमें सिंचाई, बेहतर बीज, और बाजार सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। यह उन क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाएगी जो अब तक पीछे छूट गए थे। यह ग्रामीण भारत को सशक्त करने और असमानता को दूर करने का एक सुनहरा अवसर है।

राष्ट्रीय उच्च उत्पादकता बीज मिशन

100 करोड़ रुपये के साथ यह मिशन 100 से अधिक जलवायु-अनुकूल और कीट-प्रतिरोधी बीज विकसित करेगा । यह मौसम की अनिश्चितता और कीटों से होने वाले नुकसान से हमारे किसानों को बचाएगा । यह न केवल उत्पादन बढ़ाएगा, बल्कि खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाएगा । यह हमारे अन्नदाताओं को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने का एक क्रांतिकारी कदम है ।

बागवानी पर जोर

500 करोड़ रुपये के साथ फल और सब्जियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू होगा । इसमें किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और सहकारी समितियाँ किसानों को संगठित करेंगी, उनकी मोलभाव की शक्ति बढ़ाएँगी । यह उच्च मूल्य वाली फसलों से आय बढ़ाएगा और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा । यह न केवल आर्थिक लाभ देगा, बल्कि पोषण सुरक्षा को भी मजबूत करेगा ।

दालों में आत्मनिर्भरता

1,000 करोड़ रुपये के साथ 6 साल का यह मिशन तुअर, उड़द, और मसूर की खरीद और उत्पादन पर केंद्रित है । यह आयात पर हमारी निर्भरता को कम करेगा और घरेलू दाल उत्पादन को बढ़ावा देगा । यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसानों की आय को भी मजबूत करेगा । यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है ।

गुजरात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है, और इस बजट में इसे विशेष महत्व दिया गया है । राज्य के लिए 25,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । इसमें शामिल हैं:

स्मार्ट खेती: आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ ।

बाजार सुविधाएँ: बेहतर लॉजिस्टिक्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर से किसानों की उपज को बाजार तक पहुँचाने में आसानी होगी ।

औद्योगिक विकास: नए औद्योगिक कॉरिडोर से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।

पर्यटन और संस्कृति: ऐतिहासिक स्थलों के विकास से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ।

दाहोद, जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस बजट में विशेष प्राथमिकता प्राप्त कर रहा है। इसके विकास को गति देने के लिए कई योजनाएँ बनाई गई हैं।

कृषि विकास

150 करोड़ रुपये जैविक खेती और मिट्टी संरक्षण के लिए आवंटित किए गए हैं।

किसानों को उन्नत तकनीकों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार तक उत्पादों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निर्यात सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।

सिंचाई सुविधाएँ

80 करोड़ रुपये सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के विकास पर खर्च किए जाएंगे।

यह योजना पानी की बचत में मदद करेगी और क्षेत्र को सूखे की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी।

पशुपालन

50 करोड़ रुपये दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए आवंटित किए गए हैं।

इससे ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

उन्नत पशुपालन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

कनेक्टिविटी

PM गति शक्ति योजना के तहत 200 करोड़ रुपये सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए।

45 करोड़ रुपये एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को भी सहायता मिलेगी।

वनबंधु कल्याण योजना

30,000 करोड़ रुपये शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किए गए हैं ।

इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों का समग्र उत्थान करना है ।

बेहतर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे ।

यह योजनाएँ दाहोद के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध होंगी । माननीय सभापति, यह बजट हमारे अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने, कृषि को आत्मनिर्भर बनाने, और ग्रामीण भारत को सशक्त करने का एक स्वर्णिम अवसर है । यह सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव है । मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस संतुलित और प्रगतिशील बजट के लिए धन्यवाद देता हूँ । मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके नेतृत्व के लिए सलाम करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में यह देश नई ऊँचाइयों को छू रहा है ।

मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करता हूँ और इस सम्मानित सदन से विनम्र आग्रह करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए । यह बजट हमारे किसानों, हमारे गाँवों, और हमारे देश के लिए एक नई सुबह की शुरुआत है ।

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ₹1.37 लाख करोड़ की अनुदान मांगों का समर्थन करती हूँ । यह बजट मात्र एक संख्या नहीं है, यह हमारे देश के अन्नदाताओं- विशेषकर महिला किसानों के सम्मान, सशक्तिकरण और समृद्धि की दिशा में सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक है । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने यह साबित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत इंजन "कृषि" है ।

2008-09 में जहाँ कृषि बजट ₹11,915 करोड़ था, वह अब 2024-25 में बढ़कर ₹1,22,528 करोड़ और 2025-26 में ₹1,27,290 करोड़ तक पहुँच चुका है । यह सिर्फ आंकड़ों में उछाल नहीं, बल्कि नीति में उस बदलाव का संकेत है जो किसान को विकास के केंद्र में रखता है । खाद्यान्न उत्पादन 204.6 मिलियन टन (2004-05) से बढ़कर अब 332.3 मिलियन टन (2023-24 अनुमानित) हो गया है । साथ ही धान और गेहूँ जैसे मुख्य फसलों के MSP में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है । धान के लिए ₹850 से ₹2,300 और गेहूँ के लिए ₹1,080 से ₹2,425 प्रति क्विंटल तक ।

सरकार की किसान-हितैषी योजनाओं जैसे PM-KISAN (रु 3.46 लाख करोड़), PM फसल बीमा योजना (₹1.65 लाख करोड़), e-NAM (1400+ मंडियों), और Agricultural Infrastructure Fund (₹52,738 करोड़) के तहत किए गए प्रावधानों से न केवल किसान को सुरक्षा मिली है बल्कि बाजार तक सीधी पहुंच भी मिली है। KCC की सीमा 23 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई है, जिससे लाखों किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मिल रहा है। साथ ही PLI स्कीम के तहत कृषि क्षेत्र में ₹8,910 करोड़ का निवेश और ₹1,084 करोड़ की प्रोत्साहन राशि छोटे किसानों के लिए नवाचार और उद्यमिता का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

सरकार द्वारा "Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana", "Mission for Aatmanirbharta in Pulses", "National Mission on High Yielding Seeds", और "Mission for Cotton Productivity" जैसी योजनाएं भारत के कृषि भविष्य को आधुनिक, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बना रही हैं। मैं विशेष रूप से इस बात की सराहना करती हूँ कि सरकार ने बिहार में मखाना किसानों के लिए "मखाना बोर्ड" की स्थापना की है। मैं आग्रह करती हूँ कि मखाना को MSP के दायरे में लाया जाए ताकि छोटे और सीमांत किसानों को लाभमिल सके, विशेषकर महिला किसानों को जो इस पारंपरिक फसल से जुड़ी हुई हैं।

साथ ही मैं सरकार का ध्यान देश के प्रतिष्ठित कृषि संस्थान डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसे "Institute of National Importance" का दर्जा प्राप्त है। यह संस्थान न केवल बिहार बल्कि पूरे पूर्वी भारत के किसानों को आधुनिक तकनीक, जलवायु-संवेदनशील खेती, जैविक कृषि और कृषि स्टार्टअप्स से जोड़ने की क्षमता रखता है। मेरी मांग है कि इस विश्वविद्यालय को एक विशेष पैकेज के अंतर्गत उन्नत आधारभूत संरचना, रिसर्च ग्रांट्स और ग्लोबल पार्टनरशिप्स की सुविधा दी जाए ताकि यह संस्थान "Centre of Excellence" बन सके।

यह बजट एक विजन डॉक्यूमेंट है यह उस आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है जिसमें किसान केवल एक उत्पादक नहीं, बल्कि एक उद्यमी, एक नवप्रवर्तनकर्ता और एक सशक्त नागरिक के रूप में देखा जा रहा है। यह बजट महिला किसानों की भागीदारी को भी नए स्तर पर ले जाने का अवसर है।

श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) : मुझे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर देने के धन्यवाद । सर्वप्रथम, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई दूंगा कि आज उनके नेतृत्व में 1 लाख 37 हजार करोड़ का कृषि बजट आवंटित किया गया है, जिससे इस देश के किसान को लाभ मिलेगा ।

माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा किसानों को प्राथमिकता देने की बात की और फिर मान्यनीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अंग होगा- farmers making our country the food basket of the world और इस विकसित भारत की यात्रा में, पहला engine कृषि होगा ।

मैं केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि से संबंधित घोषणाओं का स्वागत करता हूँ और कृषि मंत्रालय के लिए प्रस्तावित 1 लाख 37 हजार करोड़ की अनुदान मांग का पूर्ण समर्थन करता हूँ । इस बजट में बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा हुई है-

Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana यह योजना 100 low-productivity जिलों में लागू होगी और इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा । मैं आग्रह करता हूँ कि कुरुक्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाए ।

दल्हनों में आत्मनिर्भरता मिशन-₹1,000 करोड़ के बजट के साथ toor, urad और masoor दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा । NAFED और NCCF किसानों से अगले 4 वर्षों तक pulses की पूरी उपज खरीदेंगे ।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम -₹500 करोड़ की योजना से horticulture farmers को बेहतर मूल्य, प्रोसेसिंग और सप्लाय चेन की सुविधाएँ मिलेंगी ।

पंच वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन- 500 करोड़ रुपये के साथ extra-long staple cotton varieties को बढ़ावा दिया जाएगा ।

National Mission on High-Yielding Seeds 100 करोड़ रुपये की इस योजना से 100+ climate-resilient seed varieties का विकास होगा ।

Rural Prosperity and Resilience Programme-Skilling, investment और technology adoption पर जोर देकर किसानों की आजीविका को मजबूत किया जाएगा ।

इस देश में हमारे किसान एक unifying force भी है, जिसकी ज़िम्मेदारी सरकार की भी है और विपक्ष की भी, हम सभी किसानों के हित के लिए प्रयासरत है और इसमें वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन किसानों का हित और विकास हम सबकी प्राथमिकता है क्योंकि इस किसान की उपज ही हम सब खाते हैं. मैं धरने पर बैठे किसान भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि सरकार आपके साथ है, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है आपके विकास और प्रगति के लिए ।

जब किसान यह नहीं सोचता कि उसकी फसल भाजपा वाले को जा रही या कांग्रेस वाले को, तो उसके विकास के संबंध में हमारी भी एक आम सहमति होनी चाहिए की किस प्रकार हम extreme prioritization की strategy के साथ उन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिससे कृषि को एक मुनाफे का काम बनाया जा सके ।

किसान का बेटा होना मेरे लिए सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि मेरा गौरव है । मेरे पिता, स्वर्गीय ओ.पी. जिंदल जी ने मुझे बचपन में ही सिखाया कि जो खेतों में मेहनत करता है, वही असली भारत का निर्माण करता है ।

मैं आज जहाँ भी हूँ, उसके पीछे खेतों में बहाया हुआ पसीना और संघर्ष की सीख है । चाहे उद्योग हो या राजनीति, मैंने अपने पिता से सीखा कि हर काम को उसी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए, जैसे एक किसान अपने खेत में करता है ।

मेरे पिताजी ने खेतों में खुद हल चलाया, मिट्टी में पसीना बहाया और हमें यह सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और आज भी जब मैं किसान भाइयों से मिलता हूँ, तो उनकी मेहनत और संघर्ष में खुद को देखता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी मिट्टी का हिस्सा हूँ ।

मैं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की धरती से आता हूँ जो श्रीमद् भगवद् गीता की भूमि है और भगवद् गीता के अध्याय 3, श्लोक 14 में यह कहा गया है कि,

"अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।"

अर्थात् सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है ।

यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कृषि ही जीवन का आधार है और किसान की मेहनत से ही संपूर्ण सृष्टि का पोषण संभव है । अगर खेतों में हरियाली है, तो देश में समृद्धि है । जब किसान अपने पसीने से धरती को सौचता है, तो वह केवल अन्न नहीं उगाता, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नींव को भी मजबूत करता है ।

हमें किसानों को एक उद्यमी' की तरह देखना होगा - जो innovation करता है, risk लेता है, और अपनी मेहनत से नए अवसरों का निर्माण करता है । किसान सिर्फ खेतों में मजदूरी करने वाला नहीं है, बल्कि एक कुशल प्रबंधक, एक उद्यमी और एक अर्थव्यवस्था का निर्माता है । अब समय आ गया है कि किसान को सिर्फ खेती तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का नेतृत्व करने वाला Agri-Entrepreneur (Agripreneur) बनाया जाए ।

जिस तरह सृष्टि पाँच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है, और जिस तरह हमारे हाथ की पाँच उंगलियों मिलकर एक मजबूत मुट्ठी बनाती हैं, उसी तरह कृषि भी पाँच स्तंभों पर टिकी हुई है-Production, Processing, Distribution, Retail और Consumer. अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर होता है, तो किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता ।

मैं अपनी बात इन पांच स्तम्भों और इनसे सम्बंधित चुनौतियों पर रखना चाहूंगा-

सबसे पहला स्तंभ है Production यानी उत्पादन

अगर हमे extreme prioritization theory को समझना है तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है खेती की प्रक्रिया को समझना ।

खेती की प्रक्रिया जुताई से शुरू होती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है । फिर बीज बोए जाते हैं, सिंचाई और खाद दी जाती है, और अंत में फसल कटाई, भंडारण और बिक्री के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचती है ।

किसान हर कदम पर वही input लगाता है जिसकी आवश्यकता होती है, जिससे एक अच्छी फसल तैयार होती है । इसी तरह, हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कृषि मंत्रालय के बजट को 2008-09 में 12 हज़ार करोड़ से बढ़ाकर 2025-26 में

₹1,37,290 करोड़ किया, जिससे Food grain production 204.6 मिलियन टन (2004-05) से बढ़कर 332.3 मिलियन टन (2023-24) तक पहुँचा ।

आज कई किसान सिर्फ अपनी भूमि के प्रति गहरे लगाव के कारण खेती कर रहे हैं, न कि लाभ या लागत को देखते हुए । उनके लिए खेती सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आत्मसम्मान का प्रतीक है । आज अगर किसी किसान की ज़मीन की कीमत 25 लाख रुपये है तो वो खेती से इसका 10 प्रतिशत भी नहीं कमा पा रहा है । जो कि वो ब्याज से कमा पाता ।

2019 के NSSO data के अनुसार एक किसान की monthly average income खेती से 10,218 रूपये है यानी दिन के 340 रूपये यानी न्यूनतम वेतन का भी 40 प्रतिशत, एक दिहाड़ी मजदूर की कमाई, एक जमीन के मालिक से ज़्यादा है, जो एक चिंता का विषय है और इस पर हमारी सरकार काम कर रही है और मैं मांग करता हूँ की इस data को update किया जाए जिससे हमारी योजनाओं का वास्तविक लाभ सबको पता चले ।

हमें यह भी समझना होगा कि बढ़ती जनसंख्या और Climate Change जैसी चुनौतियों को देखते हुए हमें Quality और Quantity दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा । हमें सिंचाई में भी बदलाव करने होंगे क्योंकि आज हम rainwater harvesting और water conservation की कमी के कारण भूजल पर निर्भर है जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे कई जिले आज red zone में है और water table deplete होता जा रहा है ।

Economic Survey 2024-25 के अनुसार, भारत को Cereals के Overproduction से हटकर Pulses, Edible Oil और High-Value Crops पर ध्यान देना चाहिए ।

लेकिन किसानों को आत्मनिर्भर और Profitable बनाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है । प्रधानमंत्री जी ने भी प्राकृतिक खेती का समर्थन किया है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है । उदाहरण के लिए, कृषि विज्ञान केंद्रों में अधिकांश भूमि पर अभी भी Chemical Fertilizer आधारित खेती हो रही है, जबकि प्राकृतिक खेती को सीमित स्थान दिया गया है ।

आज हानिकारक फर्टिलाइज़र खुले आम बाजार में बिक रहा है और जिस प्रकार high dose वाली दवाइयों के लिए डॉक्टर का परचा लगता है वैसे ही केमिकल के प्रयोग के

लिए भी कृषि विज्ञान केंद्रों को शोध करके यह बताना चाहिए की किस प्रकार के fertilizer का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को अपनी पूरी भूमि पर Natural Farming करने का निर्देश दिया जाए और उन्हें Artificial Intelligence जैसी नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

इसके अलावा, Natural Farming आधारित फसलों को MSP पर 25 से 50% अधिक मूल्य देने और PM-KISAN के तहत विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग करता हूँ, क्योंकि प्रारंभिक चरणों में Natural Farming की Yield कम होती है और किसानों को hand holding की आवश्यकता है ।

कृषि श्रमिकों की कमी को देखते हुए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्राकृतिक खेती से सम्बंधित कार्यों को मनरेगा में शामिल किया जाए, और उसमें जो भी श्रमिक काम करता है उसको अधिक भत्ता दिया जाए और इसमें वित्तीय योगदान, सरकार और किसान, दोनों द्वारा किया जाए । इस निर्णय से ना सिर्फ श्रमिकों को बेहतर आय मिलेगी बल्कि हमारे देश में प्राकृतिक खेती कर के लिए श्रमिकों को भी प्रशिक्षण मिलेगा । हम किसान के साथ श्रमिकों की भी आय दोगुनी कर सकते हैं अगर हम इस प्रकार की नीतियों को तत्काल लागू करें ।

दूसरा स्तंभ है Storage यानी भंडारण

भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारी कृषि योग्य भूमि सीमित है । भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% (16 करोड़ हेक्टेयर) हिस्सा है, जबकि हमारी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 18% (140 करोड़) है ।

हमें कम भूमि में अधिक उत्पादन करना होता है ताकि दुनिया की 18% आबादी का पेट भरा जा सके । यह हमारे किसानों की मेहनत और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता का प्रमाण है । इस चुनौती के साथ-साथ हमें भंडारण (Storage) और सप्लाई चेन (Supply Chain) से जुड़ी गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है ।

Food and Agricultural Organization (FAO) के अनुसार, भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 311 MMT है, लेकिन हमारी Total Storage Capacity केवल 145 MMT है,

जिससे 166 MMT का भारी Storage Shortage बना हुआ है ।

जहाँ दुनिया के अन्य देशों में 131% Surplus Storage Capacity है, वहीं भारत में 47% की कमी है । इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है, क्योंकि वे अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते और मजबूरी में उसे कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होते हैं ।

NABCONS के 2022 के All India Post-Harvest Loss Survey के अनुसार, भारत को हर साल ₹1.53 लाख करोड़ (\$18.5 billion) का खाद्य नुकसान होता है । इसमें 12.5 MMT अनाज, 2.11 MMT तिलहन और 1.37 MMT दालों की बर्बादी शामिल है ।

इतना ही नहीं, भारत में poor cold chain infrastructure के कारण हर साल 49.9 MMT फल और सब्जियाँ खराब हो जाती हैं । इस वजह से किसानों की उपज की कीमत गिर जाती है और उनकी आय पर नकारात्मक असर पड़ता है ।

अगर हम Storage और Supply Chain को मजबूत करें, तो यह नुकसान रोका जा सकता है और किसानों की कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है । इसी दिशा में गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 'World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector' लाया गया है, जो भारत के कृषि क्षेत्र को और मजबूत करेगा और किसानों को सुरक्षित भंडारण सुविधा उपलब्ध कराएगा ।

अब Post-Harvest Losses को कम करने और छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार को Solar-Powered Cold Storage Facilities स्थापित करने पर भी जोर देना चाहिए । आज अधिकांश किसान अपनी उपज को तुरंत बेचने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं होती । यदि Farm-Level Cold Storage Units उपलब्ध हों, तो वे अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और बाद में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं ।

इस योजना को NAFED, National Cooperative Consumers' Federation (NCCF), Central Warehousing Corporation और Farmer Producer Organizations (FPOs) के माध्यम से लागू किया जा सकता है । इसके लिए

Agriculture Infrastructure Fund (AIF) और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से फंडिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

तीसरा स्तंभ है Transportation यानी परिवहन

आज हम Technology और Innovation के युग में जी रहे हैं, जहाँ हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है । Amazon, Blinkit, Uber जैसी सुविधाओं के माध्यम से देश के किसी भी कोने से सामान मंगवाया जा सकता है । कुरुक्षेत्र का व्यापारी आज Amazon और Flipkart के जरिए कोहिमा और गुवाहाटी तक अपना सामान बेच सकता है । लेकिन सवाल यह है कि जब Zomato से दिल्ली में बैठा व्यक्ति कोलकाता के किसी रेस्तरां से खाना मंगवा सकता है, तो नागपुर के संतरे या भुसावल के केले सीधे घर तक क्यों नहीं आ सकते?

हमें किसानों के लिए भी ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जहाँ वे अपनी उपज को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकें । यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि व्यावहारिक समाधान हो सकता है अगर हम Technology, Storage और Logistics को मजबूत करें ।

भारत कृषि उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन हमारा वैश्विक कृषि निर्यात मात्र 2.4% है । इसका सबसे बड़ा कारण कमज़ोर Storage, Transportation और Processing Infrastructure है । हर साल भारत में ₹1,52,790 करोड़ की फसल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ठीक से Cold Storage और Logistics उपलब्ध नहीं है । भारत में 86% किसान छोटे और सीमांत (Small & Marginal Farmers - SMF) हैं, जिनके पास जमीन कम होने के कारण उन्हें अपनी फसों का सही दाम नहीं मिल पाता ।

Post-Harvest Losses के कारण किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है । फल-सब्जियों में ₹57,000 करोड़ का नुकसान होता है, जिसमें केले (₹5,777 करोड़), आम (₹10,581 करोड़), टमाटर (₹5,921 करोड़), और प्याज (₹5,156 करोड़) शामिल हैं । अगर Storage और Supply Chain को मजबूत किया जाए, तो यह नुकसान किसानों की कमाई में बदला जा सकता है ।

भारतीय रेलवे खाद्यान्न ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन है । Food Corporation of India (FCI) अपने 90% खाद्यान्न रेलवे से ही भेजता है, लेकिन 97% फल और सब्जियाँ सड़क मार्ग से जाती हैं, जिससे Transit Losses बढ़ते हैं ।

Kisan Rail ने इस समस्या को हल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है । उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र के Nashik के अंगूर किसानों ने Kisan Rail से 22,000 किंटल अंगूर भेजे और प्रति किंटल ₹5,000 का लाभ कमाया । यह साबित करता है कि Rail-based Cold Storage Wagons और Dedicated Agriculture Corridors के ज़रिए किसान अपनी उपज को बिना नुकसान के देशभर में भेज सकते हैं ।

अगर भारत में Dedicated Freight Corridor, Defence Corridor और Economic Corridor हो सकते हैं, तो एक Agriculture Corridor क्यों नहीं? आज ज़रूरत है कि हम Dedicated Agriculture Growth Corridor विकसित करें, जिसमें खेतों से Cold Storage, Food Processing Centers, मंडियों व उपभोक्ताओं तक एक तेज़, सुरक्षित और किफायती सप्लाई चेन बनाई जाए ।

यदि हम इन सुधारों को लागू करें, तो भारत का किसान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकता है । जहाँ पहले किसान अपनी उपज के सही दाम के लिए संघर्ष करता था, वहीं Technology से उसे सीधे ग्राहक तक पहुँचाने का अवसर मिल सकता है ।

पहले Post-Harvest Losses किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला देते थे, वहीं अब Cold Storage और Rail Connectivity इसे रोक सकती है । Technology और Artificial Intelligence के माध्यम से हमें Digital Platforms का प्रयोग करते हुए किसान को खुद अपनी कीमत तय करने योग्य बनाना होगा ।

आज हमें समर्पित कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इनोवेशन की आवश्यकता है, ताकि भारत के किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, बल्कि Agripreneur बनकर Global Market में अपनी पहचान बना सकें ।

चौथा स्तंभ है Retail मानी खुदरा विक्री

हरित क्रांति के बाद से सभी सरकारों ने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया । लेकिन यह एक विडंबना है कि उत्पादन तो बढ़ा, मगर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूत बाजार उपलब्ध नहीं कराए गए । हमारे प्रधानमंत्री जी जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसने आत्मनिर्भर किसान भी शामिल है और किसान आत्मनिर्भर तभी होगा जब उसको barrier free बाजार मिलेगा जिससे वो अपनी उपज का बेहतर सूल्य प्राप्त कर सके ।

आज भी किसान के पास अपनी फसल बेचने के बेहद सीमित विकल्प हैं और समस्या यह है कि इन सभी विकल्पों में कीमत लय करने का अधिकार खरीदार के पास होता है, जबकि अन्य उद्योगों में यह अधिकार विक्रेता के पास होता है ।

इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की जरूरत है । सबसे पहले, Inter-State Trade पर Mandi Fees हटाई जाए । एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए गए कृषि उत्पादों पर अलग से मंडी टैक्स लगाना double taxation के समान है और single national market के विचार के खिलाफ जाता है । इसका समाधान -way bill की अनिवार्य बनाकर केवल उन्हीं व्यापारियों को टैक्स छूट देने में है, जो इसे प्रस्तुत करें ।

दूसरा, हमें अपनी कृषि निर्यात नीति में clarity और continuity लानी होगी और export ban को कम करना होगा क्योंकि इसके कारण किसानों को distress sale करना पड़ता है.

तीसरा, Mandis में Auction System और Minimum Reserve Price (MRP) लागू किया जाए । NITI Aayog के 'New India @75' डॉक्यूमेंट में सुझाया गया है कि MRP को auction का starting point बनाया जाए, जिससे किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिले और traders को quality आधारित मूल्य तय करने के लिए प्रेरित किया जाए ।

चौथा, GST और Taxation Reforms को लागू किया जाए । खाद, बीज, कृषि उपकरण और दवाओं पर GST में छूट देने से किसानों की input cost कम होगी ।

पांचवा, Farmers' Education और Skilling के लिए Budget Allocation किया जाए । किसानों को modern agriculture techniques सिखाने और उन्हें technology से जोड़ने के लिए विशेष बजट का आवंटन किया जाना चाहिए । इससे न केवल उनकी उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम भी होंगे ।

छठा, Smart Cities की तरह 'Smart Villages' का विकास किया जाए । केवल शहरी विकास पर ध्यान देने के बजाय, गांवों को smart villages में बदलने की योजना बनाई जानी चाहिए, जिससे technology, sustainability और सामुदायिक विकास को बढ़ावा मिल सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सके ।

अब समय आ गया है कि Barrier-Free Trade को प्राथमिकता दी जाए। कृषि सुधारों को केवल factor-market reforms तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि marketing reforms को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।

एक uniform pan-India framework के तहत barrier-free trade सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध हो सके। भारत के किसान सिर्फ उत्पादन के ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता के भी हकदार हैं। यह समय है कि कृषि बाजार को मुक्त करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए!

पाँचवा स्तंभ है Consumer यानी उपभोक्ता

एक बहुत बड़ा मुद्दा सिर्फ भारत ही नहीं विश्व में है कि आज हम किस प्रकार का खाना खा रहे हैं।

हमारा देश कृषि प्रधान है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे नागरिक क्या खा रहे हैं? भोजन हमें पोषण देने का माध्यम होना चाहिए, न कि चिंता और बीमारियों का कारण। आज भारतीय उपभोक्ता के भोजन में ज़हर घुल चुका है-रसायन, पेस्टिसाइड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की भरमार है।

यह केवल एक स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी गहरा असर डाल रहा है। आज ICMR और कई शोध यह साबित कर चुके हैं कि हमारे भोजन में मौजूद रसायनों और कैंसर के बीच सीधा संबंध है। Organophosphates, Carbamates, और Glyphosate जैसे पेस्टिसाइड Tomatoes, Spinach, Grapes, और अन्य खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जिससे Breast, Prostate और Stomach Cancer जैसी घातक बीमारियाँ बढ़ रही हैं।

2022 में Journal of Environmental Science and Health में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय बाज़ार में बिकने वाले 40% खाद्य पदार्थों में FSSAI द्वारा तय Maximum Residue Limit (MRL) से अधिक पेस्टिसाइड मिले।

आज हम अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। जब हमारे किसान chemical farming पर निर्भर हैं, तो उपभोक्ता को सुरक्षित और पोषक आहार कैसे मिलेगा? आज हमें

Natural Farming को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि हम अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य दे सकें ।

पेस्टिसाइड ही नहीं, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड भी एक बड़ा खतरा बन चुका है । Economic Survey 2024-25 में यह स्पष्ट किया गया है कि Ultra-Processed Foods (UPFS) स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, और इन्हें नियंत्रित करने की सख्त जरूरत है । भारत में ₹2,500 अरब का यह उद्योग हृदय रोग, कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा दे रहा है ।

आज, हमारी जीवनशैली और भोजन की खराब गुणवत्ता के कारण भारत में 56.4% बीमारियाँ Unhealthy Diets की वजह से हैं । National Family Health Survey (NFHS-5) के अनुसार, 24% भारतीय महिलाएँ और 22.9% पुरुष मोटापे का शिकार हो चुके हैं, जबकि Diabetes की दर 9.3% तक पहुँच गई है ।

आज हमें जापान से सीखने की जरूरत है, जहाँ संतुलित आहार और बेहतर नीतियों के कारण Obesity केवल 4.5% है । भारत को भी Nutritional Education, Stricter Food Regulations और Preventive Healthcare को प्राथमिकता देनी होगी । Economic Survey ने सुझाव दिया है कि Front-of-the-Pack Labeling जैसे सख्त नियम लागू किए जाएँ, ताकि लोग यह जान सकें कि वे क्या खा रहे हैं ।

हमारी सरकार को Natural और Nutritional Farming को बढ़ावा देना होगा । जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है- "हम छोटे-छोटे बदलाव लाकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं । हमें जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा, ताकि बाजार में मिलने वाला हर उत्पाद पोषक और सुरक्षित हो ।

अगर हम अपने नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन नहीं देंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था और समाज का कोई भी विकास अधूरा रहेगा । इसलिए, यह वक्त है कि हम अपने भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें, पेस्टिसाइड मुक्त और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के बिना एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें । यही सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का रास्ता होगा ।

भारत में कृषि और डेयरी सेक्टर केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं । लेकिन कम दूध उत्पादन एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान AI-

powered sensors और Smart Collars के जरिए किया जा सकता है। ये पशुओं की सेहत, दूध उत्पादन और पोषण स्तर की रीयल-टाइम निगरानी कर सकते हैं, जिससे बीमारियों जल्दी पहचानी जाएंगी और Cattle Health Expenses 50% तक कम हो सकते हैं।

इसके अलावा, Sex Sorted Semen Technique को बढ़ावा देकर Female Calf Population को बढ़ाना जरूरी है, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी।

सही Breeding चाहे पशुओं की हो या इंसानों की, उनके स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। Genetic Breeding Techniques, AI, और Smart Sensors से डेयरी सेक्टर में क्रांति लाई जा सकती है। हमें स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर भारत को डेयरी उत्पादन में वैश्विक लीडर बनाना होगा। AI, Sex Sorted Semen, और Smart Monitoring Systems भारतीय डेयरी सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर भारत दुनिया की Dairy Powerhouse बन सकता है।

इन पांच स्तम्भों को अगर हम मज़बूत करेंगे, तभी हमारा किसान मजबूत होगा और जैसे हम entrepreneur और हमारे start up पर गर्व करते हैं वैसे ही हम हमारे agripreneur पर गर्व करेंगे और हमारी सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कृषि के क्षेत्र में विकसित होगा।

भारत के किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि कृषि विशेषज्ञ हैं। अगर हमारे इंजीनियर, डॉक्टर और ।। प्रोफेशनल विदेश जाकर देश के लिए विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं, तो किसान क्यों नहीं? Multinational Farmers को बढ़ावा देने के लिए हमें दूतावासों के माध्यम से ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, तंजानिया, मलावी और ऑस्ट्रेलिया में कृषि भूमि की पहचान, 'Global Farmer Export Mission' की शुरुआत, भारतीय कृषि कंपनियों को प्रोत्साहन, और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना होगा।

इससे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और भारत एक Agriculture Superpower बनेगा। अब समय आ गया है कि "Grown by India" को वैश्विक पहचान मिले।

आज जब सरकार प्राकृतिक खेती, कृषि नवाचार, और डिजिटल कृषि को बढ़ावा दे रही है, तब यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने किसानों को और अधिक सशक्त बनाएं। आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों और सिंचाई सुविधाओं के साथ, किसान नए भारत की तस्वीर गढ़ रहे हैं।

एक सैनिक सरहद पर देश की रक्षा करता है, एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नवाचार करता है, लेकिन यह किसान ही है जो अपने खून-पसीने से अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरता है। उसका श्रम सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर शहर, हर गांव और हर थाली तक पहुँचता है।

इसलिए उस किसान को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि मिलनी चाहिए, जो अपने पसीने से धरती को सींचता है, जो सूरज निकलने से पहले खेतों में उतरता है और रात होने तक अपनी मेहनत जारी रखता है।

हमारी सरकार ने किसान को सिर्फ 'अन्नदाता' नहीं, बल्कि 'राष्ट्र निर्माता' के रूप में देखा है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि किसान को वो सभी संसाधन, तकनीक और आर्थिक सहारा मिले, जिसके वो हकदार है।

अंत में इस देश के किसान के सम्मान में चार पंक्तिया के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा-

बड़े-बड़े ताजों से ऊँचा जिसका मान है,
धरती जिसकी माँ, मेहनत जिसकी पहचान है।
तपते हुए सूरज में जो फसल उगाता है,
उस किसान से ही आत्मनिर्भर हमारा हिंदुस्तान है।

श्री श्रीरंग आप्पा चंद्र बारणे (मावल) : मैं कृषि मंत्रालय के 2025-26 के लिए प्रस्तावित अनुपूरक मांगों का अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इसका समर्थन करता हूँ और स्वागत करता हूँ।

महोदय हमारा देश भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रामीण जीवन का आधार है और देश की लगभग आधी आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत भी है।

इस इस बजट का अवलोकन किया जाय तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए ₹1,37,757 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो कुल केंद्रीय बजट का 2.7% है। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान में 6.8% की वृद्धि की गई थी ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जैसी योजनाओं की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर और किसानों के प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई गई हैं और निश्चितरूप से हमारे किसानों को इसका लाभ भी मिल रहा है इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) हमारी सरकार की एक प्रमुख योजना है, इस योजना को 1 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है जो ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ सभी भूमिधारक किसान परिवारों को दिया जाता है, चाहे उनके पास कितनी भी भूमि हो।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक संशोधित ब्याज अनुदान योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस योजना को 2023-24 से 2025-26 तक विस्तारित किया है और इसके लिए ₹34,856 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

इस योजना से किसानों के लिए रियायती दरों पर कर्ज की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। और किसानों को 7% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही साथ यदि किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, तो उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाती है।

जबकि सभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जुड़े किसान और कृषि गतिविधियों में शामिल सभी किसानों को इसका लाभ दिया जाता है और अब इस योजना के तहत कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, और अन्य संबद्ध क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

और यह योजना व्यक्तिगत किसानों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), कृषक उत्पादक संगठनों (FPOS) और सहकारी समितियों को लाभान्वित करती है ।

बजट 2025-26 में किसानों के लिए कुछ नई योजनाएँ की घोषणा की गई है जो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है ।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में राज्यों की भागीदारी से 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधता लाने, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाने, भंडारण सुविधाओं में सुधार और ऋण उपलब्धता बढ़ाने पर केंद्रित है । इस कार्यक्रम से लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है ।

राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का उद्देश्य अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, उच्च पैदावार वाले बीजों का विकास और प्रसार करना है । इसके तहत 100 से अधिक नई किस्मों के बीजों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर उन्नत बीज मिल सकें। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से भारत ने चना और मूंग के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की है, लेकिन अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है । इस मिशन के तहत तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेंगी, जिससे दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा ।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम के उद्देश से सब्जियों और फलों के उत्पादन, प्रभावी आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा । इससे बागवानी क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि होगी ।

माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार, देश के किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है । मैं ऐसे किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ ।

हमारी कृषि उपज अब भी वैश्विक मानकों से पीछे है । उत्तम गुणवत्ता के बीज, आधुनिक उपकरण और सिंचाई व्यवस्था में सुधार अत्यंत आवश्यक है । भारत एक कृषि प्रधान

देश है. जहां करोड़ों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं । लेकिन वर्तमान समय में कृषि उत्पादकता में कमी, भूमि का विखंडन और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर संकट हमारी कृषि व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं । यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो देश की खाद्य संप्रभुता संकट में पड़ सकती है ।

भूमि विखंडन के प्रभाव हमारी कृषि और समाज पर पड़ रहा है जब जबकि परिवार बढ़ रहे हैं तो पारिवारिक विरासत के चलते कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटने से उत्पादकता प्रभावित हो रही है। और शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि का नाश हो रहा है । छोटे किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग करना कठिन हो जाता है । है । बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करना संभव नहीं रह जाता । सिंचाई, खाद और मशीनरी का कुशल उपयोग नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है । इसके लिए सरकार को निति बनानी चाहिए और भूमि विखंडन को रोका जाना चाहिए

किसानों की वित्तीय स्थिति और आत्महत्याएँ हमारे किसान राष्ट्र की रीढ़ हैं, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर बनी हुई है । 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार, एक औसत कृषि परिवार की मासिक आय मात्र ₹10.218 थी, जो कई परिवारों के लिए अपर्याप्त है । कुछ राज्यों में, जैसे झारखंड में यह ₹4,895 थी, जबकि मेघालय में ₹29,348 । यह क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है ।

कर्ज, फसल की विफलता और बाजार में उचित मूल्य न मिलने के कारण किसानों की आत्महत्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है । सरकार की विभिन्न योजनाएँ इस संकट को हल करने में प्रयासरत हैं. लेकिन यह भी आवश्यक है कि किसानों को अधिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सरकारी सहायता न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है, है, लेकिन वर्तमान में यह केवल 22 फसलों पर लागू है । 2023-24 में, में, सरकार ने 43% धान और 25% गेहूँ की खरीद की, लेकिन अन्य फसलें बाजार की अनियमितताओं के अधीन रहीं । सभी फसलों के लिए MSP को कानूनी रूप से अनिवार्य करने की माँग बढ़ रही है, जिससे किसानों को न्यायसंगत मूल्य सुनिश्चित हो सके ।

हमारे देश की कृषि, अर्थव्यवस्था की नींव है, और इसे सशक्त किए बिना राष्ट्रीय समृद्धि की कल्पना करना असंभव है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर किसान को उचित संसाधन, मूल्य और सम्मान मिले। हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों को सशक्त बनाने के लिए एकजुट हों और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखें।

इसी के साथ मैं पुनः कृषि मंत्रालय के 2025-26 के लिए प्रस्तावित अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद।

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): I would like to express my views on the supplementary demand for grants for the Ministry of Agriculture.

First, I would like to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, for his vision, which has changed the country in the last ten years. All ministries are developing the country like never before. And now, even Akola, Maharashtra, is witnessing development with our double-engine government.

I would like to thank our Honorable Minister of Agriculture for allocating additional funds for various schemes and programs aimed at ensuring agricultural development and farmers' welfare.

The focus of our minister to provide support to farmers through schemes like the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) and the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is commendable. Under PM-KISAN, ₹ 75,000 crores have been allocated to provide financial assistance of ₹6,000 per year to eligible farmers, benefiting over 14 crore farmers across the country.

Our ministry's emphasis on improving agricultural infrastructure and promoting farmers' welfare through initiatives like the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) is laudable. Under RKVY, ₹10,000 crores have

been allocated to promote agricultural research and development, and to improve agricultural productivity and quality.

The budget allocation for Agriculture in 2025-26 is ₹1,32,513 crores, which is higher than the previous year's allocation. This allocation is divided between the following departments:

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare: ₹94,044 crores

Department of Agricultural Research and Education: ₹8,500 crores

Department of Animal Husbandry and Dairying: ₹4,300 crores

I would like to appreciate the government's efforts in:

Increasing the Minimum Support Price (MSP) to 3-7% for crops, benefiting farmers and ensuring fair prices for their produce.

Implementing the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), which aims to improve irrigation facilities and promote water conservation in the agricultural sector.

Promoting organic farming and reducing the use of chemical fertilizers through initiatives like the Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY).

Strengthening the agricultural research and development ecosystem through initiatives like the National Agricultural Research System (NARS).

I would like to make a request to our Honorable Minister for my constituency of Akola, Maharashtra. Sir, Akola is a major agricultural hub, and we are hoping to become the number one agricultural district in Maharashtra with your help.

The following projects require immediate attention:

1. Akola Irrigation Project: This project has the potential to irrigate 50,000 hectares of land, benefiting farmers in Akola and surrounding districts.
2. Watershed Development Project: This project aims to improve water conservation and reduce soil erosion in Akola, benefiting farmers and the environment. The estimated cost of the project is ₹200 crores.
3. Agricultural Research and Development Center: Establishing a research center in Akola will provide farmers with access to cutting-edge technology and expertise, improving agricultural productivity and quality.
4. Farmers' Welfare Scheme: Implementing a comprehensive welfare scheme for farmers in Akola will provide them with financial support, insurance, and other benefits.
5. Agricultural Infrastructure Development Fund: Allocating funds for agricultural infrastructure development in Akola will improve storage facilities, markets, and other infrastructure, benefiting farmers and the agricultural economy.

To conclude my speech, I must again thank our Honorable Minister for the great work being done in the Agriculture Ministry and also request our Honorable Minister to please look into the demands of the people of my Akola constituency.

SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH ALIAS PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD):.

For Kharif Season 2024-25, Soybeans were purchased from the farmers under the Government's by guarantee Nafed and NCCF, for which the farmers registered online. Regarding extending the deadline for buying soybeans from the farmers, I met the Hon'ble Minister of Agriculture on 04/02/2025 and requested to extend the deadline till March 31. 44013 farmers of my Lok Sabha constituency had registered to sell soybeans with guaranteed price, out of which 15749 farmers could

sell soybeans out of the remaining registered 28, 264 farmers. The purchase was not made due to the expiry of the extended period. In the early days, due to technical problems in the government's website, purchases were stopped for many days. Due to the fact that the purchase center did not have the sacks available, so the soybeans of the farmers could not be purchased in large quantities. The difference between the value of soybeans in the current market and the base price of the government should be credited to the farmers? account in the form of subsidy to all the registered farmers. In reference to the cancellation of the circular dated 30th April 2024 regarding Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, I met the hon. Minister of Agriculture and requested him to cancel the unjust circular of 30th April, but no action has been taken in this regard yet. Due to this circular, 32 revenue boards out of 52 revenue boards in the Dharashiv district, were excluded due to receipt of advance notices. For last year's insurance of Rs 297 crores, 25 per cent more advance notices were served to 57 out of 57 revenue boards this year, and government circular of April 30 came into effect. If the circular is cancelled, the farmers would have got an insurance of Rs. 25 thousand 678 per hectare, as this circular is causing great injustice to the farmers. So, the said circular should be cancelled immediately. The insurance rights of farmers should be restored and the reimbursement should be credited to farmers? accounts.

All the farmers whose land has been transferred after the death of their father through inheritance after the year 2019 or who have become farmers after purchase should be included in the Pradhan Mantri Krishi Samman Yojana and the remuneration given under this scheme should be increased and credited directly to the account of the farmers. Thank you.

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : मैं केन्द्रीय बजट 2025-26 के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संबंधी अनुदान के मांगों को सभा पटल पर रखती हूँ । बनासकांठा जिला की जो एरिया नर्मदा केनाल एरिया में नहीं है उस एरिया में अन्डर ग्राउंड पाइप लाइन से सिचाई हेतु सभी गांवी तक पहुंचने से यहाँ के किसानों को काफी मदद मिलेगी तथा ज्यादा तक धनेरा, दाँता, पालनपुर और दियोदर में सिचाई हेतु पानी की भारी कमी को पूरा किया जा सकेगा तथा यहाँ पर बारिस का पानी रोकने के लिए चेक डेम बनाने की अत्यंत आवश्यक है । गुजरात राज्य मे सबसे ज्यादा गौशाला मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिला से है और जो किसान गौ पालन करना चाहते है उन्हे प्रति गाय प्रति दिन का 100 रुपये की धनराशि मुहैया कराया जाय । मेरे संसदीय क्षेत्र में काफी किसान ऑर्गेनिक खेती करते है उन किसानों को एम एस पी नहीं मिलती इसलिए मैं सरकार से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पर एम एस पी की मांग करती हूँ । अब ज्यादातर समस्या आता है कि जो प्रोडक्शन है वह ऑर्गेनिक है या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करना अत्यंत कठिन होती है, इस लिए मेरी सरकार से मांग है कि प्रत्येक तलुका में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब की स्थापना किया जाय । महोदय सभी कृषि विश्वविद्यालयों में स्टाफ की कमी है उसकी पूर्ति की जाय । किसानों को काम ब्याज में लोन मुहैया कराया जाय जिससे किसानों को खेती करने में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े लथा साथ ही साथ किसानों की संपत्ति को जी एस टी के दायरे से बाहर किया जाय । मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा समेत सम्पूर्ण गुजरात में किसानों को उनके द्वारा उगाए आए आलू को कोल्ड स्टोर में रखने की समस्या बनी हुई है, क्यों कि जितने भी कोल्ड स्टोर है सारे प्राइवेट है और उन्हे बड़ी कंपनियों द्वारा पूरा का पूरा बुक कर दिया जाता है तथा किसानों द्वारा पूछे जाने पर पता चलता है कि पूरा कोल्ड स्टोरेज फूल है इससे किसान को उनके आलू खराब होने के डर से आलू कम मूल्य में बेचना पड़ता है जो कि बड़ी कंपनिओ द्वारा लेकर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है और फिर उसी आलू को दो से तीन महीने बाद दोगुना भाव में बेचा जाता है । मेरी सरकार से मांग है कि अधिकतम सरकारी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाय जिससे किसानों को अपने आलू तथा अन्य सब्जियों रखने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और ना ही मजबूर होकर उनके सब्जियों को सस्ते दर में बेचना पड़े । आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु सभी मांगों की पूर्ति करेंगे ।

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं 2025-26 के केंद्रीय बजट में कृषि और किसान कल्याण विभाग की अनुदान की मांग पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। यह बजट केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाताओं के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के किसान केवल अन्न उपजाने वाले नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ भी हैं। उनकी मेहनत से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले एक दशक में किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। यह बजट उसी यात्रा का अगला पड़ाव है, जो हमारे कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ 60% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपिछलेप से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में, कृषि और किसान कल्याण बजट का महत्व और भी बढ़ जाता है। केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, उनकी आय दोगुनी करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है।

इस वर्ष का 2025-26 कृषि बजट इस दिशा में एक मजबूत कदम है। इस बार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को ₹1.50 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹1.35 लाख करोड़ की तुलना में 11% अधिक है। यह बजट कृषि क्षेत्र के सतत विकास, आधुनिक तकनीक के समावेश, फसल बीमा, सिंचाई योजनाओं और किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देने के लिए उपयोग किया जाएगा।

पिछले तीन वर्षों में कृषि एवं किसान कल्याण बजट में लगातार वृद्धि हुई है। 2023-24 में यह बजट ₹1.25 लाख करोड़ था, जिसमें 8% की वृद्धि हुई। इसके बाद 2024-25 में इसे बढ़ाकर ₹1.35 लाख करोड़ किया गया, जिससे 10% की वृद्धि हुई। वहीं, 2025-26 के बजट में इसे और बढ़ाकर ₹1.50 लाख करोड़ कर दिया गया, जो 11% की वृद्धि को दर्शाता है। यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता दे रही है।

इस बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और ई-नाम जैसी योजनाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है। सरकार द्वारा आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में "सबका साथ, सबका विकास" के मंत्र के साथ, सरकार ने किसानों की समृद्धि को केंद्र में रखा है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत का हर किसान आत्मनिर्भर बने और उसकी आय दोगुनी हो। पिछले 10 वर्षों में, मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक योजनाएँ लागू की हैं, जिन्होंने कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है।

पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की हैं। पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे अब तक ₹2.5 लाख करोड़ से अधिक वितरित किए जा चुके हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता और सही खादों की जानकारी दी गई है, जिससे उर्वरकों के अधिक उपयोग में कमी आई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने में मदद की है, जिसमें अब तक ₹40,000 करोड़ से अधिक दावों का भुगतान किया गया है।

ई-नाम (e-NAM) पोर्टल के तहत 1,000 से अधिक मंडियों का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिली है और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है।

नीलगाय और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई राज्यों में फेंसिंग और अन्य उपायों के लिए बजट आवंटित किया है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत "हर खेत को पानी" उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिससे सिंचाई सुविधाओं में सुधार हुआ है।

मैं पालघर जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के किसानों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक जल शक्ति अभियान के तहत पालघर के कई गाँवों में माइक्रो इरीगेशन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे किसानों को जल संरक्षण में मदद मिली है। कृषि उपज विपणन समिति (APMC) को डिजिटल किया गया है, जिससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिल रहा है। साथ ही, आदिवासी किसानों को बांस और औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है।

आगे की जरूरतों की बात करें तो पालघर के तटीय क्षेत्र में मरीन फिशरीज और इनलैंड फिशरीज को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि मछलीपालन और पशुपालन को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा, फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना जरूरी है, जिससे किसानों को उनकी उपज का अधिकतम लाभ मिल सके। आदिवासी किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए विशेष पैकेज लाने की आवश्यकता है। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खेतों की फेंसिंग और संरक्षण योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह, पालघर में एक एग्रो-प्रोसेसिंग पार्क विकसित करने की जरूरत है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इसके अलावा, सूखे की समस्या को दूर करने के लिए टपक सिंचाई और जल संरक्षण योजनाओं का विस्तार आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट भारत के किसानों की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मैं मोदी सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों का समर्थन करता हूँ और कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए अनुदान मांग को पूर्ण रूप से अनुमोदित करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मनीष जायसवाल (हजारीबाग) : इस बार 2025-2026 केंद्रीय बजट में हमारे अन्नदाता किसान पर विशेष ध्यान दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कृषि क्षेत्र को विकास का प्रथम इंजन बताया है और कृषि एवं किसान कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा की गई है। महोदय यह बड़ी खुशी की बात है कि इस सेक्टर के लिए कृषि मंत्रालय के लिए कुल 1,37,757 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जिनमें कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 1,27,290

करोड़ और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए 10,466 करोड़ का आवंटन किया गया है ।

हमारी सरकार के द्वारा लगातार किए गए प्रयासों से कृषि क्षेत्र में विकास दर मजबूत बनी हुई है जोकि पूर्व में कांग्रेस की सरकार जब तक सत्ता में रही परंतु इनके कार्यकाल में कृषि विकास में अस्थिरता बनी रही । वर्ष 2005-2006 में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की विकास दर 5.8 फीसदी थी लेकिन 2008-2009 में इसमें गिरावट दर्ज की गई 2009-10 में 0.4% तथा 2014-15 में -0.2% तक रही । जिससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी कृषि सुधारों में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है । आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि का है ।

कृषि एवं किसान कल्याण के लिए बजट में की गई प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:-

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है इससे देश के हमारे सभी किसान भाईयों को बहुत लाभ मिलेगा । और निश्चित रूप से खाद्यान उत्पादकता में भी वृद्धि होगी ।

हमारी सरकार देश में सबसे कम उत्पादकता वाले 100 से अधिक जिलों में फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू करने जा रही है । 1.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को इससे लाभ मिलेगा ।

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।

ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है ।

उच्च पैदावार वाले बीजों पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा जिसके तहत 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और इस मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ।

भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा । इससे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को आनुवंशिक

संसाधनों के संरक्षण में सहायता मिलेगी

कपास उत्पादकता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, पांच वर्षीय कपास अभियान की घोषणा वित्त मंत्री जी के द्वारा की गई है जो सराहनीय है । कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में 5 साल के लिए कपास मिशन की घोषणा की गई है । इस मिशन से देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा ।

इसके अलावा-

फलों और सब्जियों के उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी कीमतों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा । जिसके लिए 500 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं ।

दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष की अवधि के लिए नया मिशन शुरू किया जाएगा । मिशन का लक्ष्य तुअर, उड़द और मसूर की खरीद के माध्यम से दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता पैदा करना होगा । इस योजना के लिए 1000 करोड़ का आवंटन किया गया है ।

पूर्वोत्तर राज्यों में खाद की कमी दूर करने के लिए असम में 12.7 लाख टन की वार्षिक क्षमता का यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा । इसके साथ-साथ पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया प्लांट्स को फिर से शुरू किया गया है जो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया है ।

अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप पर मछली पालन के लिए नए अनुकूल फ्रेमवर्क पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

2014 से पूर्व जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे किसान भूखे मर रहे थे । बारिश और ओलावृष्टि के कारण इनकी फसल बर्बाद हो जाती थी परंतु महोदय यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने इस देश के अन्नदाता के लिए उचित मुआवजा देकर उनका दुख कम करने का काम कर रही है । इसके तहत किसानों की 100 प्रतिशत खराब फसल होने पर सरकार की ओर से प्रति एकड़ 15 हजार रूपए, 25 से 50 प्रतिशत फसल नुकसान पर 9,000 रूपए प्रति एकड़ मुआवजा, 51 से 75 प्रतिशत फसल नुकसान पर किसानों को 12,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। जो प्रशंसनीय है।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में किसानों को कम लागत पर डीएपी खाद उपलब्ध कराने के लिए 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक एक विशेष पैकेज को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके तहत किसानों को डीएपी पर मौजूदा एनबीएस योजना के अलावा 3,500 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): I would firstly like to express our sincere commendation to the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare for the outstanding achievements it has made under the able stewardship of Hon. PM Shri Narendra Modi Ji. I seek to address to you a few matters of immense public importance that pertain with the long-term policy goals of the Ministry.

Employing over 60% of the Indian population, Agriculture still remains a key facet of the Indian Economy and Society. While the contribution of Agriculture to our economy may have declined post-liberalisation due the phenomenal rise of our industry and services sector, maintaining food security and ensuring farmers' welfare is extremely important if we are to ensure equitable and all round growth. As per-hectare yields dwindle and more people gravitate towards other "aspirational" white collar jobs due to their lucrative nature, it is important that we as a country do not ignore what constitutes the base of our economy. Food is the most basic need of mankind. We may establish all the great bridges and railway lines, make the loftiest of malls in our lively urban centres, develop the most modern of missile systems in our indigenous defence labs, send the most modern satellites on unprecedented explorations, we are doing that and we should do that, however we must surely not forget our most prime of requirements, which is adequate food. Under this government, our country has taken major strides in ensuring food security for the most

marginalized sections of the society, even during an unprecedented tragedy such as COVID-19, which hugely impacted the world, in some cases beyond repair.

Since the last 6 years, Agriculture has been growing at a 5% which is considered to be outstanding, by its standards. High-value sectors like Horticulture, Livestock and Fisheries have become key drivers of the overall economic growth of the nation. In the allied sector, the Fisheries sector has shown a phenomenal CAGR of 8.7%, followed by an 8% CAGR in the livestock sector. India currently ranks 2nd largest globally in fish production. Our total fish production has almost doubled as compared to FY14 and our seafood exports have risen by almost 1.5 times in the last 5 years. Kharif Foodgrain production is expected to reach 1647.05 LMT, an increase of 89.37 LMT from the previous year. This house shall be delighted to note that according to the Economic Survey 2024-25, the coverage of area under irrigation has increased between FY16 and FY21 FROM 49.3% to 55.3% of the Gross Cropped Area (GCA), while irrigation intensity has risen from 144.2% to 154.5% which is a laudable achievement. Our overall foodgrain production has risen by about 10% in the last 3 years. It must be noted that all of this has been achieved in a world where, besides geopolitical uncertainties, there has also been a consistent rise in adverse ecological mishaps. According to the Economic Survey 2024-25, our country has been seeing an increase in the frequency of dry spells during the summer monsoon which have been 27% more common the 30 year period from 1981-2011 as compared to 1951-1980. In Central India, the frequency of extreme daily rainfall events (exceeding 150 mm) has increased by about 75% from 1950 to 2015.

As we discuss the workings of this Ministry, I would especially like to highlight the initiatives by the Ministry that have greatly benefited farmers across the country. Some of the most notable achievements include:

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Was Launched in 2019, this direct income support scheme has provided financial assistance of ₹6,000 annually to small and marginal farmers. This initiative has provided crucial support to millions of farmers, especially during times of distress. As of 31st October 2024, 23.61 lakh farmers have been enrolled under the PM Kisan Maandhan. As of August 2024, Rs 3.24 lakh crore have been transferred to about 12.85 crore beneficiaries.

PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) crop insurance scheme, aimed at providing financial protection to farmers against crop losses due to natural calamities, has been a game-changer. The scheme has provided timely support to farmers facing the aftermath of floods, droughts, and other natural disasters. With 56.96 crore applications insured since its inception in 2016-17, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has demonstrated substantial impact, paying out Rs 1,54,469 crore in claims. This remarkable reach and financial assistance highlight the scheme's vital role in supporting farmers during challenging times. By offering a comprehensive and accessible insurance product, PMFBY empowers farmers, improves agricultural practices, and contributes to the overall growth and stability of the Indian agricultural sector.

National Agriculture Market (e-NAM) digital platform has provided farmers with greater access to markets, reducing middlemen and ensuring better prices for their produce. Rajasthan, particularly Jaipur, has seen a positive impact from e-NAM, with enhanced access to national markets for its farmers. According to the Economic Survey, As of

31st October 2024, over 1.78 crore farmers and 2.62 lakh traders have registered on the e-NAM portal. As of March 2023, a total of 1,361 mandis were also integrated with the e-NAM platform. 91 According to the Economic Survey (2023-24), farmers surveyed reported receiving higher prices for their produce after implementation of the scheme. About 54% also preferred transacting through e-NAM portals over the traditional market due to transparent procedures and other benefits. The Standing Committee on Agriculture (2019) recommended that the government expand the coverage of the e-NAM scheme in states where APMC markets are non-existent. The Committee also recommended that the government undertake training programmes to enhance digital literacy among farmers and improve their participation in the scheme.

The government has implemented extensive soil health management schemes, and the Soil Health Card Scheme, which helps farmers understand the condition of their soil, leading to more efficient use of fertilizers. This has helped improve crop yields and reduce the overuse of fertilizers, thus protecting the environment. Fertiliser subsidy is estimated to constitute 3.3% of the total budget of the Union government in 2025-26. Given India's import dependence in the domain, the government has ensured timely interventions during times of crisis in the fertiliser market in order to shield the farmer of any such ill-effects, a good example of the same came in April 2024, when the Cabinet approved a one-time special package on Di- Ammonium Phosphate (DAP) fertiliser (a grade of P&K fertiliser) beyond the Nutrient Based Subsidy (NBS) scheme which was extended in January 2025 in order to contain the surging prices of DAP.

The Union Budget 2025-26 reiterated the importance ascribed by the Modi Government to Agriculture. This budget describes Agriculture as the 1st Engine of development. The Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana has been launched in partnership with the states, covering 100

districts with low productivity, moderate crop intensity and below-average credit parameters, to benefit 1.7 crore farmers. The Government is also launching a 6-year "Mission for Atma Nirbharta in Pulses" with focus on Tur, Urad and Masoor. A National Mission on High Yielding Seeds is also being launched aiming at strengthening the research ecosystem, targeted development and propagation of seeds with high yield, and commercial availability of more than 100 seed varieties. A 5-year mission has been announced to facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming, and to promote extra-long staple cotton varieties. This mission shall also help address the issue of rising cotton imports in the country and pave the way for enhanced exports of cotton. By enhancing the loan limit under the Modified Interest Subvention Scheme from ₹ 3 lakh to ₹ 5 lakh, for loans taken through the KCC, the Government has ensured greater access to credit for the farmer.

While the Ministry's efforts have had a far-reaching impact, it is important to recognize the specific challenges faced by farmers in Rajasthan, my home state, which is unique due to its geographical and climatic conditions:

Rajasthan is one of the driest states in India, and water scarcity is a major concern for our farmers. The state is highly susceptible to droughts, which impact agriculture, livelihoods, and drinking water availability. The per-capita water availability in Rajasthan is even lesser and considered to be about 780 cubic metres. The state's dependence on rainfall is highly unreliable, and thus, solutions for water conservation and management are critical. Many areas in the state are dependent on rain-fed agriculture, and this unpredictability often leads to crop failure. This, compounded by the fact that water quality in the state is deeply affected due to presence of substances like uranium, makes the existing

water resources sparsely employable. In states like Punjab, over extraction of groundwater resources is directly proportional to the electricity subsidies provided to farmers which removes any disincentives to conserve electricity.

This leads to depletion of state finances and water resources at the same time. This strategy, adopted by a few states, deserves a hard reconsideration if we are to effectively deal with the issue of water scarcity and ensure sustainable development for our people. In order to effectively deal with the issue, since the FY16 fiscal year, the government has been implementing the Per Drop More Crop (PDMC) initiative, a component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY), to promote water efficiency. From FY16 to FY25 (end of Dec. 2024), ₹ 21968.75 crore was released to states for implementation of PDMC Scheme and an area of 95.58 lakh ha has been covered under which is about 104.67 per cent higher as compared to the Pre- PDMC period.

While schemes like PM-KISAN and PMFBY are beneficial, water availability continues to be a fundamental issue affecting productivity.

In 2022-23, 42% of the total cropped area was cultivated with water intensive crops such as paddy, wheat, and sugarcane. In Rajasthan, the agricultural economy is still heavily dependent on wheat and mustard crops, leaving farmers vulnerable to market fluctuations. The lack of diversification into high-value crops or modern agricultural practices limits the income potential of many farmers.

Under the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evan Utthaan Mahabhiyan Yojana (PM-KUSUM), the central government offers subsidies of up to 30% or 50% of the total cost for installation of solar agricultural pumps. As of March 2021, five states are offering free electricity to farmers with other states offering electricity to farmers at

subsidised rates. These states include Andhra Pradesh, Karnataka, Punjab, Tamil Nadu, and Telangana. In 2018, NABARD had noted that in certain states such as Andhra Pradesh, Punjab, Haryana and Tamil Nadu, access to highly subsidised or free canal water has led to over-irrigation of crops. This has led to wasteful use of water and energy needs in certain regions along with deprivation of the same in certain other regions.

As the Economic Survey of 2021-22 also rightly pointed out, there is an urgent need for crop diversification in view of the severe water stress in areas where paddy, wheat and sugarcane are grown. This is not just because of the water-intensive nature of such crops but also because of a consistent change in social attitudes. Between 2011-12 and 2023-24, there has been a decrease in the share of monthly per capita consumption expenditure (MPCE) spent on food items in both rural and urban areas. The share of cereals in total MPCE for rural areas decreased from 10.8% in 2011-12 to 5% in 2023-24 while that for urban areas decreased from 6.7% to 3.8% in the same period. On the other hand, the share of food items like milk and milk products and fruits have increased in the total MPCE. A greater procurement of wheat and paddy by the Government implies a greater share of the same being distributed under Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Anna Yojana (PMGKAY). This makes a large share of the grain distributed under PDS, vulnerable to black marketing or being wasted. Given that for a large part of the country, a bare minimum has been ensured with the PMGKAY, it is also our responsibility to ensure that nutritious food is available to all people and there is considerable incentive to the farmer to give up the cultivation of water intensive crops, especially in states like Rajasthan and Punjab. With the gradual overuse of pesticides, limited use of modern technologies and modern farming equipment, many farmers across the

country, as in Rajasthan, are facing the problem of low yields. This gap affects their income levels and increases their vulnerability to external shocks like drought or pest outbreaks. According to the Food and Agriculture Organisation (FAO), India ranks among the top countries in terms of acreage under cultivation of cereals, rice, and pulses. However, our output per hectare in India is much lower than the global average, especially for crops like wheat, maize and paddy which constitute most of our cultivation. Low agricultural yields translate into low and insecure incomes for farmers and large tracts of agricultural land being locked into low-value agriculture.

In order to improve output yield concerted attempts must be made by reducing staple crop area under cultivation, diversifying crops under cultivation and improving resource use efficiency.

In Rajasthan, many farmers have small, fragmented land holdings, making it difficult to adopt modern agricultural practices or to achieve economies of scale. This affects productivity and makes it difficult for farmers to access financing or take part in large-scale farming ventures. In 2006, the National Commission on Farmers' (Chaired by Shri. M.S. Swaminathan) noted that fragmented and scattered operational holdings are a major challenge to agricultural productivity. In 2015-16, 86% of the total operational holdings in the country were less than two hectares. Small scale farmers face a profound lack of access to credit, logistics, markets and technology. The Committee on Doubling Farmers Income (DFI) noted that land fragmentation is also associated with the division of land and sharing the parcels among inheritors. One of the solutions recommended by the DFI Committee has been to aggregate farmers and promote land pooling to target fragmentation of land holdings. Structures such as Farmer Producer Organisations (FPOs) and Self-Help Groups (SHGs) offer farmers the advantages of larger economies of scale

throughout the agriculture value chain. Collectivization leads to higher collective output, increased land productivity, and higher bargaining power for each farmer-member.

The government launched the Formation and Promotion of 10,000 FPOS scheme in 2020 with a total outlay of Rs 6,865 crore. The scheme aims to enhance agricultural productivity through efficient, cost-effective, and sustainable resource usage. As of August 2024, 8,875 FPOs and 19.7 lakh shareholder farmers have been registered across the country. In 2025-26, the government has allocated Rs 584 crore to the FPO scheme, which is similar to the revised estimate of 2024-25. Under the scheme, FPOs are provided financial assistance of up to Rs 18 lakh per FPO for a period of three years.

For horticultural commodities, if there is a 10% increase in production or 10% fall in prices in comparison to last year's normal prices then the Market Intervention Scheme (MIS) is implemented. In the scheme, there is provision for procurement of 20% of total production on cost of cultivation finalized by Government of India.

As per scheme, the loss up to the extent of 25% of procurement cost is to be shared proportionately by Central and State Government. It is to mention that if the proper price is not realized by the farmer, then the actual loss incurred is much greater than the 25% limit. The probable reasons of this may be:

The horticultural commodities viz. garlic and onion are perishable in nature and these commodities could not be stored for longer duration.

The Government of India does not announce the MSP for horticultural commodities while the price of agricultural commodities, which fall under

MSP, have been raised 1.5 times in previous years. However, no amendments are made in MSP for the horticultural commodities.

Therefore, following amendments are proposed in Market Intervention Scheme:

In place of procurement cost, the calculation should be done on the net loss incurred by purchase & sale of commodities.

The loss up to the extent of 50% to be shared proportionately between Central and State Government.

Pulses can be a better source of protein as compared to cereals and can help improve nutrition intake for NFSA beneficiaries. Under the first phase of the PMGKAY between April to June 2020, the central government distributed one kg of pulses per household per month free of cost for NFSA beneficiaries. Between 2013-14 and 2023-24, the domestic production of pulses has increased at an annual rate of 2.3%, similar to the increase in the total production of foodgrains. However, the production of pulses has been characterised by significant variability. For instance, in 2016-17, production of pulses increased by 42% over 2015-16, but in 2018-19, it decreased by 13% over 2017-18. Moreover, India continues to be import dependent for meeting its domestic needs for consumption of pulses. India's import dependency for pulses in 2020-21 was 9% which is estimated to decrease to 3.6% by 2030-31. In 2023-24, India's production of pulses decreased by 7% to 242 lakh tonnes compared to 2022-23 while imports almost doubled to 47 lakh tonnes. Share of pulses has also declined in the Monthly Per Capita Expenditure in 2011-12 (2.9%) to 2023-24 (2.0%), In order to address the aforementioned issues, the Government has announced the Mission for Atma Nirbharta in Pulses where NAFED will regularly and readily procure

3 pulses. This is a step in the right direction so as pay heed to a significant issue.

while Rajasthan faces its unique set of challenges, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has made significant progress in transforming the agricultural landscape. However, we must continue to focus on water conservation, technological innovation, crop diversification, and ensuring equitable benefits for all farmers.

The Union Budget 2025-26 ticks most of the boxes. It doesn't shrug, core issues in the sector, under the rug but actively addresses them. There is scope for improvement, as there always is. But the fact that we're moving in the right direction, assures me that the sector shall hugely contribute to our collective endeavor of Viksit Bharat by 2047.

Thank you.

श्री धर्मबीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : मैं विशेष रूप से हरियाणा राज्य की आवश्यकताओं और विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं ।

2014 के बाद से हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं । 2014 के बजट और 2025-26 के बजट की तुलना की जाए तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है । भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को मिलने वाले बजट की तुलना दी गई है. जिससे यह पता चलता है कि पिछले एक दशक में किन क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है ।

मुख्य मंत्रालय और उनके बजट आवंटन

विभाग/मंत्रालय	2014-15 (₹ करोड़)	2025-26 ₹ करोड़)	वृद्धि (₹ करोड़)	(वृद्धि (%))
वित्त मंत्रालय	12,90,000	19,39,001	+6,49,001	50.3%
रक्षा मंत्रालय	2,29,000	6,81,210	+4,52,210	197.5%
सड़क परिवहन और राजमार्ग	37,880	2,87,333	+2,49,453	658.5%

मंत्रालय				
रेलवे मंत्रालय	65,445	2,55,445	+1,90,000	290.3%
गृह मंत्रालय	63,000	2,33,210	+1,70,210	270.2%
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	1,15,000	2,15,767	+1,00,767	87.6%
ग्रामीण विकास मंत्रालय	82,202	1,90,405	+1,08,203	131.6%
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	70,586	1,61,965	+91,379	129.5%
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	22,309	1,37,756	+1,15,447	517.4%
शिक्षा मंत्रालय	82,771	1,28,650	+45,879	55.4%
जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन)	13,726	99,502	+85,776	625.0%

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	33,725	99,858	+66,133	196.0%

2014 में कृषि बजट सीमित था और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ भी सीमित रूप से मिल रहा था । लेकिन 2025-26 के बजट में किसानों के लिए हमारी सरकार रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की है । विभिन्न फसलों के लिए नए एमएसपी इस प्रकार हैं:

फसल	एमएसपी 2025-26 (₹ प्रति क्विंटल)	एमएसपी 2024-25 (₹ प्रति क्विंटल)	वृद्धि (₹ प्रति क्विंटल)
गेहूं	2,425	2,275	150
जौ	1,980	850	130
चना	5,650	5,440	210
मसूर	6,700	6,425	275
सरसों	5,950	5,650	300
कुसुम	5,940	5,800	140

देश की आज़ादी के बाद से हरित क्रांति" के नाम पर हमारी सेहत और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । अधिक उत्पादन की होड़ में किसान रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है, बल्कि मानव जीवन पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ रहा है । आज स्थिति यह है कि सब्जियां, अनाज, फल-हर खाद्य पदार्थ में रसायनों का जहर मिला हुआ है । इसके कारण गाँवों से लेकर शहरों तक कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ तेजी से फैल रही हैं ।

रासायनिक खेती के कारण मिट्टी की ताकत इतनी घट चुकी है कि बिना खाद डाले कोई फसल उग ही नहीं सकती । आज़ादी के 70 वर्षों तक इस समस्या पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए "मृदा स्वास्थ्य कार्ड" योजना की शुरुआत की, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता का आकलन कर यह समझा जा सके कि किस क्षेत्र में कौन-सी फसल उगाना उचित होगा । लेकिन केवल मिट्टी की जाँच ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें सुधार के लिए रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों को बढ़ावा देना अनिवार्य है । जैविक खेती से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी ।

वर्तमान में सरकार रासायनिक खादों के लिए लगभग दो लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आबंटित करती है, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मात्र ७० हजार करोड़ रुपये की सहायता दी जाती है । यह असंतुलन दर्शाता है कि हमारी प्राथमिकता अभी भी रासायनिक खेती की और अधिक की हुई है ।

सरकार को जैविक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान करनी चाहिए । इसके लिए कृषि बजट का एक निश्चित हिस्सा चरणबद्ध तरीके से जैविक खेती के लिए आबंटित किया जाए ।

पहले वर्ष 15 %

दूसरे वर्ष 10 %

तीसरे वर्ष 15 %

इसी क्रम में बढ़ाते हुए इसे 50% तक ले जाया जाए ।

इस रणनीति से किसान स्वाभाविक रूप से रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे। इससे कृषि की गुणवत्ता में सुधार होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, और आम जनता को शुद्ध: स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी।

अगर सरकार यह कदम उठाती है, तो भारत में जैविक खेती को नया आयाम मिलेगा और हम एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सफल होंगे।

हरियाणा में कृषि अनुसंधान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जा रही है लेकिन इसमें एक कमी है कि किसानों की अभी तक पूरी फसल की खरीद नहीं की जा रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एमएसपी पर किसान का दाना खरीदा जाए और इस पर खरीद की समय सीमा भी हटाई जाए। ताकि किसान अपनी फसल को जरूरत के हिसाब से सही दाम पर बेच सके। जब जरूरत हो तब बेच सके।

सूक्ष्म सिंचाई योजना का विस्तार: जल संरक्षण और कृषि सुधार की दिशा में आवश्यक कदम

पानी की बढ़ती कमी और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई) को व्यापक रूप से अपनाना बेहद जरूरी है। सामान्य सिंचाई की तुलना में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई लगभग 10 गुना तक पानी की बचत कर सकती है।

यह सर्वविदित है कि यदि भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण पानी की कमी होगी।

हालांकि सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी देती है, लेकिन इसमें एक किसानों को केवल चुनिंदा कंपनियों से पाइपलाइन और अन्य उपकरण खरीदने होंगे। वे कंपनियां महंगे उत्पाद बेचती हैं, जिससे सब्सिडी मिलने के बावजूद किसान को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। कई मामलों में बिना सब्सिडी के खुले बाजार से खरीदने पर किसान को यह उपकरण सस्ते मिल सकते हैं। यह नीति पिछली सरकारों से चली आ रही है। और अब इसमें बदलाव की आवश्यकता है।

समाधान और सुझाव:

- ✓ किसानों को यह स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपनी पसंद की कंपनी या खुले बाजार से पाइपलाइन सिंचाई अन्य और खरीद सकें ।
- ✓ सब्सिडी सीधे किसान के खाते में दी जाए, न कि चुनिंदा कंपनियों को इससे किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे और वे कम लागत में बेहतर समाधान नगे ।
- ✓ सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार जागरूकता अभियान बताए, जिससे अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें ।

सरकार को कम पानी और कम खाद में उगाई जाने कली फसलों को प्रोत्साहित करना चाहिए । इसके लिए इन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) इस प्रकार बढ़ाया जाए ।

सरसों और चना ₹10,000 प्रति किंटल, बाजरा - 25,000 प्रति किंटल ।

* मिलट के किसानों जो बाजरा, दाल, तिलहन, आदि की खेती करने वाले किसानों को मनरेगा में शामिल किया जाए ।

इन फसलों को बढ़ावा देने से कम पानी की खपत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और जल संकट की समस्या कम होगी ।

सरकार को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के नियमों को सरल बनाना होगा और किसानों को स्वतंत्रता देनी होगी कि वे अपनी जरूरत के अनुसार कहीं से भी उपकरण खरीद सकें । साथ ही कम पानी वाली फसलों को अधिक एमएसपी देकर प्रोत्साहित करना चाहिए । इससे जल संरक्षण, किसानों की आय वृद्धि और देश की खाद्य सुरक्षा तीनों उद्देश्यों की पूर्ति होगी ।

*सरकार का बजट 50.65 लाख करोड़ रुपये है । वर्तमान में हर राजनीतिक दल चुनावों के दौरान मुक्त सुविधा देने की घोषणाएं करता है, जिसे आमतौर पर गुफा की रेवड़ी कहा जाता है । इस योजना में सरकार का बड़ा बजट खर्च होता है, और इसका सबसे अधिक प्रभाव बेरोजगार सबके ऊपर पड़ता है । हमारी सरकार इन मुफ्त योजनाओं को नियंत्रित करने और लोगों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है । मेरा सुझाव है कि यदि

इस बजट का केवल 2% हिस्सा नदियों को जोड़ने की परियोजना में लगाया जाए और इसे मनरेगा से जोड़ा जाए तो इससे इंजीनियरों से लेकर मजदूरों तक हर वर्ग के लोगों को रोजगार मिलेगा। जब लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा तो वे मुफ्त की योजनाओं पर निर्भर नहीं रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने 2014 में नेपाल के साथ नदियों को जोड़ने के लिए एक समझौता किया था जिसके तहत शारदा-यमुना लिंक परियोजना बनाई जानी थी। इससे हरियाणा और राजस्थान दोनों को लाभ मिलना था लेकिन अभी तक इस परियोजना पर कार्य नहीं हुआ है। देश में कई अन्य नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है। यदि इस सुझाव को लागू किया जाए तो नदियों के जुड़ने से न केवल जल संकट दूर होगा, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

* रेणुका, लखुवार व किसान बांध के काम को जल्द पूरा कराया जाए ताकि इसका पानी हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सहित राजस्थान आदि राज्यों को मिल सके।

* मेरे संसदीय क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा राजस्थान बोर्डर से सटा हुआ है और पानी की भारी किल्लत है! सरकार ने मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला महेंद्रगढ़ को 9 खण्डों में (नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली, कनीना, महेंद्रगढ़, सतनाली, निजामपुर, और सिंहमा) इनमें तीन ब्लॉक सतनाली, निजामपुर और सिंहमा डार्क जोन में है^a लेकिन इन्हें अटल भूजल योजना में शामिल नहीं किया गया है! महोदय! इन्हें अटल भूजल योजना में शामिल कराया जाए इसी प्रकार भिवानी जिला के तोशाम, भिवानी, बवानी खेड़ा, सिवानी, लोहारू खंड डार्क जोन में है लेकिन इन्हें अटल भूजल में शामिल नहीं किया हुआ है। दादरी जिले के दादरी, झुक्षु, बाढ़डा और बौंद कलां खंड भी अटल भूजल में शामिल किए।

* मानसरोवर योजना के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र के बचे हुए गाँवों को शामिल किया जाए। इससे तालाबों/जोहड़ों को जीवित किया जाए ताकि जमीनी स्तर का पानी ऊपर उठ सके।

सरकार ने किसानों के हित में एफपीओ (कृषि उत्पादक संगठन), ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से कई सराहनीय कदम उठाए हैं। ये योजनाएँ आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने और किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में मदद कर रही हैं। ड्रोन

तकनीक विशेष रूप से फसलों पर कीटनाशक एवं उर्वरक छिड़काव में सहायक सिद्ध हो रही है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है ।

हालांकि, ड्रोन योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधार आवश्यक हैं ।

ड्रोन योजना में सुधार हेतु सुझाव:

वर्तमान में किसानों को सिर्फ एक बैटरी दी जाती है, जिससे लगातार कार्य करने में कठिनाई होती है । यदि अतिरिक्त दो बैटरियों दी जाएँ, तो किसान बिना रुकावट लंबे समय तक ड्रोन का उपयोग कर सकेंगे ।

चूंकि ड्रोन भारी और बड़े आकार के होते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं होता । सरकार को 1-2 लाख रुपए तक का एक वाहन (छोटा पिकअप या लोडिंग वाहन) देने का प्रावधान करना चाहिए, ताकि किसान ड्रोन को सुगमता से परिवहन कर सकें ।

■ ड्रोन से दवा छिड़काव पर मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई जाए ?

वर्तमान में 100 रुपये किसान को और 300 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं ।

इसे बढ़ाकर 150 रुपये किसान को और 450 रुपये सरकार द्वारा देने का प्रावधान किया जाए, ताकि अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें और ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़े ।

सौर ऊर्जा न केवल कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना सकती है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और विजली की लागत कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है । सरकार पहले भी सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी देती रही है, लेकिन हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा इस पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती की गई है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है ।

■ बेकार या अनुपयोगी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की सुविधा दी जाए - ऐसी निचली भूमि (लो-लाइन एरिया), ऊबड़-खाबड़ जमीन या सामूहिक/एकल स्वामित्व वाली जमीन पर सोलर

प्लांट लगाने की अनुमति और सरकारी सहायता दी जाए, जिससे किसान अपनी बेकार पड़ी जमीन का उपयोग कर सकें ।

■ हरियाणा सरकार द्वारा सोलर सब्सिडी को पूर्व स्तर पर बहाल किया जाए- पहले सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए उचित सब्सिडी प्रदान करती थी, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है । इसे फिर से पहले जितना किया जाए, ताकि अधिक किसान इस योजना से जुड़ सकें ।

2014 से पहले हरियाणा में औद्योगीकरण को उतना बल नहीं मिला था, लेकिन 2014 के बाद से विशेष औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए गए हैं । 'मेक इन हरियाणा' और 'स्टार्टअप इंडिया' योजनाओं के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और सोनीपत में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं । स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में 3 गुना अधिक आवंटन किया है ।

* मेरे संसदीय क्षेत्र में जमीन बहुत सस्ते रेट पर उपलब्ध है, रेल और रोड कि कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई । करीब 7 राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे संसदीय क्षेत्र से निकल रहे हैं । पंजाब से लेकर मुंबई तक आसानी से सफर होता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि रोजगार हेतु कुछ उद्योग मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थापित किए जाए ।

छोटे और मझोले उद्योगों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए ।

औद्योगिक क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का और विस्तार किया जाए ।

2014 के मुकाबले 2025-26 में शिक्षा बजट को दोगुना किया गया है । नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को लागू किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, और कौशल विकास के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं ।

* मेरे संसदीय क्षेत्र में एक हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय पाली जो महेन्द्रगढ़ जिले में है दूसरा भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यह राज्य स्तर की, मेरा निवेदन है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को शिक्षा का हब बनाया जाए जहां मेडिकल की शिक्षा से लेकर स्कूल की शिक्षा तक व रिसर्च सेंटर भी बनाया जाए ताकि दिल्ली की पढ़ाई वाली भीड़ कम हो ।

* हरियाणा के हर जिले में एक उच्च स्तरीय कौशल विकास केंद्र खोला जाए ।

* सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए ।

2014 में सरकारी अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक थी, लेकिन 2025-26 में हर जिले में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं । आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिली है । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर टेलीमेडिसिन सेवाओं को मजबूत किया गया है ।

* हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जाए ।

* ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए ।

* एम्स के तर्ज पर हर जिले में हॉस्पिटल खोले जाए । डॉक्टर की कमी को दूर किया जाए ।

2014 में बिजली और जल आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, लेकिन अब 2025-26 में हर गाँव और हर घर तक 24 घंटे बिजली और स्वच्छ पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था की गई है । हर घर जल' योजना के अंतर्गत 90% से अधिक घरों में पाइपलाइन जल आपूर्ति की सुविधा पहुँची है ।

* बिजली दरों में छूट दी जाए और ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की जाए ।

* जल संरक्षण योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए ।

2014 में हरियाणा में सड़क और रेलवे नेटवर्क का विकास अपेक्षाकृत धीमा था । लेकिन 2014 के बाद एक्सप्रेसवे, नए रेलवे कॉरिडोर, और मेट्रो विस्तार योजनाओं पर भारी निवेश किया गया है । मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे व सड़कों के जाल

* ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण तेजी से किया गया जो बचे हैं उन्हें और तेजी से करवाया जाए ।

* मेट्रो नेटवर्क को और विस्तार दिया जाए । मेरी मांग है कि दिल्ली से एम्स बाड़सा तक किया जा रहा है इसे झज्जर तक किया जाए ताकि इसका फायदा हरियाणा के साथ साथ राजस्थान तक के निवासी भी ले सकें और दिल्ली एनसीआर को ट्रैफिक जाम से कुछ राहत मिल सके ।

* कुछ नए राष्ट्रीय राजमार्ग व बाई पास माननीय मंत्री को दिये हुए है उन्हें जल्द बनवाया जाए ।

2014 के बाद स्टार्टअप, स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं के कारण देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है । नई औद्योगिक नीतियों के कारण बड़े उद्योगों ने निवेश बढ़ाया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं ।

* हर जिले में, रोजगार मेले आयोजित किए जाएँ ।

* स्वरोजगार के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ।

* मेरा संसदीय क्षेत्र सड़क व रेल के माध्यम से देश भर के बड़े महानगरों से जुड़ गया है, मेरा निवेदन है कि कुछ उद्योग यहाँ स्थापित किये जाए क्योंकि दिल्ली एनसीआर के मुकाबले यहाँ जमीन बहुत सस्ती है.

2014 से लेकर 2025 तक रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए हैं । "सभी के लिए तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेलवे" के लक्ष्य के साथ, देशभर में रेलवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, और हमारा भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा । 2014 से पहले रेलवे के विकास की गति धीमी थी, लेकिन 2014 के बाद रेलवे बजट में हरियाणा को रिकॉर्ड तोड़ निवेश मिला । भिवानी लोकसभा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की गई:

* भिवानी-महेंद्रगढ़ के कई रेलवे स्टेशन का आधुनिकरण और अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होना ।

* भिवानी-लोहारू-रेवाड़ी रेलखंड का विद्युतीकरण और दोहरीकरण ।

* नई ट्रेनों की सौगात, जिससे दिल्ली, जयपुर, हिसार और चंडीगढ़ तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ी ।

* रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम हुई ।

* मालवाहक कॉरिडोर का विस्तार, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ हुआ ।

यह बजट न केवल विकास की नई ऊँचाइयों छू रहा है, बल्कि हरियाणा के रेलवे नेटवर्क को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है । मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूँ और आगे भी इसी गति से विकास की अपेक्षा करता हूँ ।

नई रेल परियोजनाएँ और ट्रेनों की माँग:

- * भिवानी से जयपुर के लिए नई इंटरसिटी ट्रेन ।

- * दिल्ली से भिवानी व चंडीगढ़ से जयपुर के लिए भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के रास्ते

से वंदे भारत ट्रेन सेवा चालु करवाई जाए.

- * महेंद्रगढ़ से हिसार और सिरसा तक सीधी रेल कनेक्टिविटी ।

- * महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ के लिए सुपरफास्ट ट्रेन ।

- * मैंने माननीय रेल मंत्री जी को अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों के ठहराव हेतु पत्र दिया हुआ है निवेदन है उन सबको भी पूरा किया जाए ।

- * सिवानी स्टेशन के LC-29 पर ROB बनवाया जाए जिस पर मोटरसाइकिल आदि भी गुजर सकें,

- * अटेली स्टेशन पर चंडीगढ़ बांद्रा ट्रेन 22451/52 या टनकपुर दौराई टनकपुर ट्रेन संख्यां 05097/98 में से कम से कम किसी एक ट्रेन का ठहराव अटेली स्टेशन कर करवाया जाए. यह बहुत पुरानी मांग है.

2014 और 2025-26 के बजट की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में व्यापक प्रगति की है । हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार ने न केवल अनुदान बढ़ाया है, बल्कि योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रभावी तरीके से किया है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन योजनाओं को और अधिक सशक्त किया जाए ताकि हम आत्मनिर्भर हरियाणा और सशक्त भारत की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकें ।

मैं सभी माननीय सांसदों से प्रार्थना करता हूँ कि हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करें कि नदियों के पानी का विषय राज्यों का ना होकर केन्द्रीय अधिकार होना चाहिये । जिस वजह से आप के प्रदेशों में टकराव न हो तथा सभी को शुद्ध पानी मिल सके

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I thank to you for giving me an opportunity to participate in the discussion on Demands for Grants 2025-26 pertaining to Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare and its working. In 2025-26, Rs 1,37,757 crore has been allocated to the Ministry (2.7% of the union budget). The allocation towards the Ministry is estimated to decrease by 2.5% over the revised estimates of 2024-25. According to the revised estimates of 2024-25, the expenditure of the Ministry has increased by 6.8% over the budget estimate.

The Union Budget 2025-26, is comprehensively biased as the budget grossly ignores the needs of Tamil Nadu and betrayed the expectations of the people, therefore, the union budget is completely anti-poor, anti-women, anti-youth and anti-farmer. The Union Budget is prejudiced as it completely ignored the demands of Tamil Nadu, despite the fact the economic survey, ranking of higher Education Institutions and the NITI Aayog Reports praised the State's activities. Needless to say, reduction in central funding increase the financial burden on the State Government.

I strongly demand from the Union Government for effective implementation of PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana in Tamil Nadu to cover all districts in the State comprising of maximum number of farmers to enhance productivity, crop intensity, and ensuring high credit access. Proper utilization of earmarked fund to the tune of Rs. 100.00 crore in 2025-26 under National Mission on High Yielding Seeds must focus on ensuring commercial availability of maximum number of seed varieties, development and propagation of climate and pest resilient high yielding seeds, and strengthening research on high yielding seed varieties. I further demand that Farmers of Tamil Nadu must be benefited with loan limit under the Modified Interest Subvention Scheme to be increased from three lakh rupees to five lakh rupees. Keeping in view the fact there will be focus on Horticulture entailing a comprehensive programme for

the promotion of production, efficient supply, processing, and remunerative prices for fruits and vegetables, the scheme benefit the people of Tamil Nadu in particular. Adequate fund out of the total allocation of Rs. 500.00 crore under the programme for 2025-26 be earmarked for the State of Tamil Nadu so that there is maximum number of formation and participation of Farmer Producer Organisations and Cooperatives across the State.

Self-sufficiency in pulses: A new Mission for Aatmanirbharta in Pulses will be launched for a period of six years. The Mission will aim at achieving self-sufficiency in pulses production through procurement of Tur, Urad, and Masoor. An allocation of Rs 1,000 crore has been made for this scheme for 2025-26.

A new urea plant may be established in Tiruvannamalai constituency with adequate infrastructure for production of sufficient quantum of urea to fulfil the needs of the nearby States. There is an urgent need for promotion of agro based industries in the State to promote export to global markets and exploring employment generation in the agro based industry sector. I also urge the Government to set up R&D Centre at Tiruvannamalai Parliamentary Constituency.

I humbly appeal to the Finance Minister to earmark sufficient fund to build marketing and cooperative infrastructure for commercial production of agricultural items in Tamil Nadu in general and my constituency Tiruvannamalai in particular for enhancing farmer's income and for enhancing the contribution of State Agriculture Sector in the GDP of the country.

Thank you.

श्री उमेशभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। जब

भारत ने **1947** में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, तो कृषि पर निर्भर जनसंख्या का हिस्सा **75%** था । **आज**, यह अनुपात लगभग **43%** तक गिर गया है । जब हम देश के **G.D.P. में कृषि के हिस्से** के बारे में बात करते हैं, तो यह **1947 में 50%** से अधिक था । हालांकि, **आज** यह हिस्सा केवल **17-18%** है । वर्तमान सरकार ने पिछले दस वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपाय शामिल हैं । हालांकि, कई नीतियों ने ज़मीन पर इच्छित प्रभाव नहीं डाला है, जिसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र दमण और दीव भी शामिल हैं ।

दमन और दीव न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मत्स्य पालन क्षेत्र, सांस्कृतिक समृद्धि, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक संभावनाओं और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर रणनीतिक भू-राजनीतिक स्थिति के कारण भी महत्वपूर्ण हैं ।

दमन और दीव में कृषि को बेहतर करने के लिए, जहां छोटी जोत वाली भूमि में अपार संभावनाएं हैं, उत्पादकता बढ़ाने और नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं । लेकिन इस वर्ष के बजट और पिछले वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कई योजनाओं के बावजूद, जमीनी हकीकत एकदम अलग तस्वीर प्रस्तुत करती है । मैं केंद्र सरकार, विशेष रूप से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करें कि इस वर्ष के बजट और पिछले वर्षों में घोषित योजनाएं देश के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों या बड़े शहरों और कस्बों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित न रहें ।

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) ग्रामीण स्तर पर **महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सेवाओं** और **प्रौद्योगिकी सक्षम हस्तक्षेपों** के फैलाव और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । वर्तमान में, **728 KVKs** देश में कृषि विशेषज्ञों को सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें कृषि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं । दमन में कोई कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) नहीं है । नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों से संबंधित जानकारी के प्रसार को सुनिश्चित करने और स्थानीय किसानों को सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति और बुनियादी ढांचे के साथ एक अत्याधुनिक केवीके को दमन में जल्द से जल्द स्थापित किया जाए, ताकि यह राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान दे सके ।

वर्तमान में, समय पर इनपुट और मार्गदर्शन की कमी के कारण किसान निराश महसूस कर रहे हैं और एक केवीके की स्थापना उन्हें बहुत राहत और सहायता प्रदान करेगी ।

किसानों से छीनी गई कृषि भूमि की वापसी- 1961 तक पुर्तगाली शासन के दौरान, दीव में कई व्यक्तियों के पास बड़ी कृषि भूमि थी, जो अच्छी आय उत्पन्न करती थी । हालांकि, स्वतंत्रता के बाद, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि सरकार द्वारा जब्त कर ली गई । इसके परिणामस्वरूप, दीव के कृषि क्षेत्र में निजी व्यक्तियों की हिस्सेदारी बड़े रूप से कम हो गई । आज, दीव की जनसंख्या का केवल एक छोटा प्रतिशत ही कृषि को आर्थिक गतिविधि के रूप में अपनाता है, जबकि अधिकांश लोग विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में लगे हैं । दीव जैसे जिलों में, जहां कृषि करने वाली जनसंख्या का हिस्सा कम है, सरकार को कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तंत्र तैयार करना चाहिए, जो मूल्य सृजन/वृद्धि में मदद करे ।

सभी किसानों के लिए मुफ्त प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना- प्रत्येक किसान को 5 लाख रुपये की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मुफ्त प्रदान की जा सकती है और इसके लिए लगने वाली 45-50 रुपये की प्रीमियम लागत सरकार द्वारा वहन की जा सकती है । यह छोटा सांकेतिक कदम और सामाजिक सुरक्षा जाल किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में काफी मददगार होगा ।

मई 2021 में, चक्रवात तौकते ने भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित किया, जिसमें दीव सहित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हुए । दीव में बड़ी संख्या में नारियल के पेड़ उखड़ गए । तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, इन पेड़ों के मालिकों को दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रशासन से वित्तीय मुआवजा नहीं मिला है । बहुत निराशा की बात है कि केंद्र शासित प्रशासन ने सभी प्रभावित किसानों को नारियल के पौधे देने की पेशकश की, जो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था । यह उल्लेख करना उचित होगा कि एक नारियल का पेड़ अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में कम से कम छह से सात साल लेता है । दीव के केंद्र शासित प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों ने किसानों को गरीबी की स्थिति में छोड़ दिया है । यह अनुरोध किया जाता है कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द पर्याप्त और समय पर मुआवजा प्रदान किया जाए ।

कृषि के लिए समर्पित डीजल, गैस या सौर आधारित जनरेटर सेट की कमी के कारण, व्यावसायिक खेती तेज गति से शुरू नहीं हो सकी है। मैं विनम्रतापूर्वक मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखें और क्षेत्र के किसानों की जायज लंबित मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

दमन और दीव में **कृषि औद्योगिक पार्कों** को लागू करने से **आर्थिक विविधीकरण**, **ग्रामीण विकास और कृषि मूल्य वृद्धि** में योगदान हो सकता है। शुरुआत में, दमन और दीव में मूल्य वृद्धि की उच्च संभावना वाले फसलों या कृषि उत्पादों, जैसे नारियल आधारित उत्पादों या मत्स्य पालन, की पहचान की जा सकती है। पार्क के लिए उपयुक्त भूमि का चयन किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम हो। भूमि अधिग्रहण जैसी चुनौतियों को पारदर्शी नीतियों और हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए किसानों, स्थानीय उद्योगों, सरकारी अधिकारियों और निजी निवेशकों को शामिल करना आवश्यक है।

सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्यों के साथ साझेदारी में 'प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू करेगी ताकि मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों का समन्वय किया जा सके। सरकार के अनुसार, यह कार्यक्रम जिसका **लक्ष्य 1.7 करोड़ किसानों** की मदद करना है, **100 जिलों** को कवर करेगा जिनकी उत्पादकता कम है, फसल की तीव्रता मध्यम है और credit मानदंड औसत से नीचे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस योजना के तहत दमन और दीव जिलों को जोड़ने पर विचार करें।

सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय **'Rural Prosperity and Resilience'** कार्यक्रम शुरू करने की योजना की घोषणा की है। यह कृषि में कम रोजगार को कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर संबोधित करेगा। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाए ताकि इस योजना का दायरा छोटे जिलों तक भी विस्तारित किया जा सके ताकि छोटे मछुआरों को भी इसके लाभ मिल सकें।

मैं सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना की ऋण सीमा को **₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख** करने के निर्णय का स्वागत करता हूँ। यह कदम 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और दुग्ध उत्पादकों की मदद करने के लिए है जो इस योजना से

लाभान्वित होते हैं। यह कदम किसानों की बदलती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, KCC से संबंधित कुछ संरचनात्मक समस्याएँ हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के ऋणों के लिए N.P.A. की Outstanding राशि **दिसंबर 2024** के अंत तक **97,543 करोड़** रुपये तक बढ़ गई है, जबकि मार्च 2021 के अंत में यह 68,547 करोड़ रुपये थी, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार। यह प्रवृत्ति विभिन्न चुनौतियों से प्रभावित है, जिसके कारण वर्षों में एनपीए बढ़े हैं। ये **प्राकृतिक आपदाओं, कीट आक्रमणों और बीमारियों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं** के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा, **बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न अस्थिरता** भी किसानों के लिए नए रिटर्न निर्धारित करने में भूमिका निभाती है। वर्षों में खराब ऋणों के संचय में योगदान देने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह इस समस्या के समाधान के लिए एक समग्र ढांचा विकसित करे।

वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि कृषि हमारे देश की प्रगति का पहला इंजन है। केवल मौखिक सेवा से काम नहीं चलेगा। प्रगति के पहले इंजन को प्रथम श्रेणी का व्यवहार, पर्याप्त से अधिक बजटीय आवंटन और सर्वोच्च प्राथमिकता की आवश्यकता है। कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि के बिना, भारत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल नहीं कर सकता। नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) 2021-22, जो अक्टूबर 2024 में प्रकाशित हुआ, दर्शाता है कि परिवारों की औसत मासिक आय 2016-17 में 8,059 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 12,698 रुपये हो गई। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि ग्रामीण परिवारों का औसत मासिक व्यय 2016-17 में 6,646 रुपये से बढ़कर 2021-22 में 11,262 रुपये हो गया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्रामीण परिवारों का मासिक व्यय मासिक आय की वृद्धि से अधिक रहा। ग्रामीण परिवारों में बकाया कर्ज की सूचना देने वाले परिवारों का अनुपात 2016-17 में 47.4 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 52.0 प्रतिशत हो गया, जो एक और चिंताजनक संकेत है। इस सर्वेक्षण में एक और महत्वपूर्ण पहलू उजागर हुआ कि औसत भूमि जोत का आकार 2016-17 में 1.08 हेक्टेयर से घटकर 2021-22 में 0.74 हेक्टेयर हो गया। इन सभी चिंताजनक संकेतों को तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि कृषि क्षेत्र में गिरावट को रोका जा सके।

धन्यवाद

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : मुझे कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद । यह बजट देश के कृषि क्षेत्र के सामने मौजूद अनेक चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है ।

28 फरवरी 2016 को, प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी । लेकिन यह भी भाजपा सरकार के अनगिनत असफल वादों में से एक साबित हुआ । मार्च 2022 में, कृषि पर स्थायी समिति की 37वीं रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि - "विभाग किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य से काफी दूर है । बल्कि, कुछ राज्यों में तो किसानों की आय वास्तव में कम हो गई है । " वर्ष 2025-26 में, कृषि मंत्रालय को केवल रु 1.38 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2.5% की कमी है । जब मंत्रालय अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा है, तो बजट में कटौती क्यों की जा रही है? इस सरकार ने बार-बार कृषि क्षेत्र के फंड में कटौती की है, जबकि यह क्षेत्र देश के 46% श्रमिकों को रोजगार देता है । इससे सरकार का किसान-विरोधी रवैया स्पष्ट रूप से उजागर होता है । हम मांग करते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की जाए ।

सरकार अपनी प्रमुख योजना पीएम-किसान (पीएम-किसान) को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है । लेकिन क्या इस योजना का वास्तव में किसानों को लाभ मिला है? 2021 की कैग ऑडिट रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि योजना के गलत क्रियान्वयन के कारण कई लाभार्थी इससे वंचित रह गए । कुल स्वयं-पंजीकृत किसानों में से 34%-यानी एक-तिहाई का सत्यापन लंबित था, जिससे वे इस योजना का लाभ नहीं ले सके । बार-बार उठाई जाने वाली प्रमुख मांगों में से एक है-इस योजना में भूमिहीन और बटाईदार किसानों को शामिल करना । अंतिम कृषि जनगणना के अनुसार, देश में ऐसे भूमिहीन किसानों की संख्या लगभग 5,31,000 थी, और अब यह संख्या और बढ़ चुकी होगी । गरीब किसान अभी भी इस वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मैं मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि वह इस विषय पर गंभीरता से विचार करे ।

एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना । लेकिन किसानों को किए गए बीमा दावों के भुगतान में लगातार गिरावट आ रही है- 2017-18 में रु 29,000 करोड़ के दावे किसानों को चुकाए गए थे, 2021 में यह घटकर रु 20,500 करोड़ रह गया । 2022-23

मैं यह और कम होकर मात्र रु 16,400 करोड़ रह गया । इसके अलावा, यह योजना दावों के विलंबित भुगतान के लिए भी बदनाम है । रु में, कृषि पर स्थायी समिति ने बीमा कंपनियों के लिए दावों के निपटान की समय-सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी । इस पर अब तक क्या प्रगति हुई है? सच्चाई यह है कि सरकार लगातार इस बीमा योजना के बजटीय आवंटन में कटौती कर रही है । 2025-26 के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए मात्र 12,242 करोड़ आवंटित किए हैं, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 23% कम है । यह 2018-19 के बाद से इस योजना के लिए सबसे कम बजट आवंटन है । इस सरकार ने गरीब किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था । अब समय आ गया है कि आप अपना यह वादा पूरा करें ।

मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ । महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और यह राष्ट्रीय जीडीपी में सभी राज्यों में सबसे अधिक योगदान देता है । लेकिन, आपके बजट में महाराष्ट्र के लिए कोई स्थान नहीं था । उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा लंबे समय से सूखा जैसी परिस्थितियों के कारण कृषि संकट से जूझ रहे हैं । 2018 में, नाबार्ड ने महाराष्ट्र में जल संसाधनों की उपलब्धता को 'संकटग्रस्त' और 'अत्यधिक संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया था । राज्य का अधिकांश कृषि क्षेत्र वर्षा जल पर निर्भर है । जलवायु परिवर्तन और बारिश की बढ़ती अनिश्चितता के कारण गरीब किसान सबसे अधिक पीड़ित हैं । आज भी, महाराष्ट्र में कुल बोए गए क्षेत्र का केवल 18% सिंचित है, जो कि राष्ट्रीय औसत 50% से कहीं कम है । इतनी बड़ी-बड़ी घोषणाओं, तमाम योजनाओं और 'डबल इंजन सरकार' के बावजूद, राज्य में सिंचाई सुविधाएं अपने सबसे निचले स्तर पर क्यों हैं? बार-बार सूखा प्रभावित किसानों के लिए राहत की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं की दर सबसे अधिक है । सरकार ने अब तक इस गंभीर मुद्दे को अनदेखा क्यों किया है? सरकार महाराष्ट्र में जल उपलब्धता और सिंचाई सुधारने के लिए कोई ठोस प्रयास कब करेगी?

मेरा निर्वाचन क्षेत्र प्याज उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन प्याज उत्पादक किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं । हालांकि प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन मौजूदा 20% निर्यात शुल्क किसानों को भारी नुकसान पहुँचा रहा है । मैं मांग करती हूँ कि इस निर्यात शुल्क को तुरंत हटाया जाए । इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ (महाराष्ट्र स्टेट अनियन ग्राउंड्स एसोसिएशन) और किसानों ने लंबे

समय से नेफेड द्वारा बिचौलियों के माध्यम से प्याज की खरीद करने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है । मैं इस मुद्दे की तत्काल जांच की मांग करती हूँ और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई किए जाने की भी मांग करती हूँ । साथ ही, मैं यह भी मांग करती हूँ कि सोयाबीन, दलहन, प्याज और अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों के साथ परामर्श कर तय किया जाए, ताकि उनकी कड़ी मेहनत का उचित वित्तीय मुआवजा मिल सके ।

किसानों की पीड़ा और दुर्दशा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । खेती के प्रत्येक चरण में उन्हें कोई राहत नहीं मिलती । जब किसान अपनी फसल उगाता है, तो उसे कृषि उपकरणों और कीटनाशकों पर भारी जीएसटी चुकाना पड़ता है । जब वह अपनी फसल बेचने जाता है, तो उसे निकटतम एपीएमसी मंडी तक पहुंचने के लिए मीलों की यात्रा करनी पड़ती है । 2019 में, कृषि पर स्थायी समिति ने कहा था कि देश में 41,000 बाजारों की जरूरत है, लेकिन मार्च 2023 तक केवल 7,085 एपीएमसी मंडियां संचालित थीं, जो आवश्यक संख्या का 20% भी नहीं है । जो सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करती है, मुझे यह पूछना है-किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? इसके बाद जब गरीब किसान अपनी फसल बेचने की कोशिश करता है, तो सरकार या तो उसकी फसल खरीदती ही नहीं, और अगर खरीदती भी है, तो उसे उसके श्रम का पूरा भुगतान तक नहीं करती ।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा था- "देश केवल उसकी मिट्टी नहीं, बल्कि उसके लोग भी हैं ।" लेकिन सच्चाई यह है कि इस सरकार ने खुद ही भारतीयों को विफल कर दिया है । अगर हमारी बात नहीं सुननी, तो कम से कम उस अन्नदाता की तो सुनिए, जो धूप में, गर्मी में, बारिश में मेहनत करके वह अन्न उगाता है, जिसे हम सब खाते हैं । धन्यवाद । जय हिंद! जय महाराष्ट्र!

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND):

The field workers of the department should identify the genuine farmers for allotment of farm tools.

The farmers are facing problems to avail the farm loans. Some banking institutions should be identified specifically by the Ministry as designated

Loan Banking Institutions.

Gradually, the farmers are losing interest to cultivate because of lack of proper facilities and this should be recognized by both the Centre and the States.

There should be an exchange programme for farmers for educational or to acquaint them with the different means of productions. The Ministry should adopt policies state wise to conduct exchange tour programmes for the respected farmers.

Rejuvenation for farmers is the need of hour. There is a need to bring a positive policy where country farmers will have dignity as farmers of India.

डॉ. नामदेव किरसान (गड़चिरोली-चिमुर) : भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है । भारत की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा कृषि में लगा हुआ है. जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18% का योगदान देता है । किसान कई समस्याओं से त्रस्त हैं । ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान के जीवन को प्रभावित करते हैं । इनपुट की खरीद से लेकर विपणन और कटाई के बाद की गतिविधियों तक, किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । हालाँकि, किसानों की समस्याओं पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

भारतीय कृषि में मुख्य रूप से छोटे और खंडित भूमि जोत का प्रभुत्व है । इससे किसान कम सक्षम बनते हैं । 2015-16 में 10वीं कृषि जनगणना के अनुसार, भारत की कुल परिचालन भूमि जोत 146.45 मिलियन हेक्टेयर थी और कुल संचालित क्षेत्र 157.82 मिलियन हेक्टेयर था । उनमें से, सीमांत और छोटे परिचालन जोत (0-2 हेक्टेयर) कुल परिचालन जोत का 86.2% हिस्सा बनाते हैं । भूमि के इस विखंडन के कारण, किसान पर्याप्त आय नहीं कमा पाते हैं । इसका कारण मशीनीकरण में कठिनाई, मोनोकॉपिंग और उत्पादों जैसे सामान्य कृषि पद्धतियों का अभ्यास करना है जिससे भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आती है । इससे उत्पादन लागत अधिक और उत्पादकता कम होती है । इस समस्या का मूल कारण उत्तराधिकार कानून के कारण शुरू हुआ ।

कृषि विपणन में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं में परिवहन लागत, अपर्याप्त बाजार अवसंरचना, मूल्य में उतार-चढ़ाव, उचित बाजार जानकारी का अभाव और स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों का शोषण शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधाओं की कमी फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों के लिए एक सीमित कारक रही है। भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण हर साल लगभग 16% फल और सब्जियाँ, 10% तिलहन, 9% दालें और 6% अनाज बर्बाद हो जाते हैं। चूँकि अधिकांश कृषि उपज जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए किसान फसल कटाई के तुरंत बाद कम कीमत पर भी उपज बेचने के लिए परेशान होते हैं। इससे उन्हें बहुत कम आय होती है। अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण किसानों के लिए ऑफ-सीजन के दौरान लोगों की माँगों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है।

कृषि क्षेत्र में, वित्तीय संस्थागत स्रोतों से समय पर, पर्याप्त और कम लागत वाले ऋण की उपलब्धता और पहुँच अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर सीमांत और छोटे किसानों के लिए। अन्य सभी इनपुट के साथ, पूंजी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनपुट में से एक है। ऋण तक पहुँच कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। पूंजी की कमी का सामना करने वाले किसान अपनी उत्पादन गतिविधियों में बेहतर तकनीकों, मशीनरी और उपकरणों में निवेश न करके कम इनपुट का उपयोग करेंगे, जबकि अन्य के पास ऐसी कोई बाधा नहीं है। इससे न केवल उत्पादकता बल्कि उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

भारत में 80% पानी की खपत कृषि में सिंचाई के लिए होती है। भूजल स्तर में कमी कृषि को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अच्छी सिंचाई किसानों को समय पर कृषि कार्य करने में मदद करती है। हाल के दिनों में भूजल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा सकती है क्योंकि इसका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है क्योंकि 65% सिंचाई भूजल स्रोतों का उपयोग करती है। भारत में, सिंचाई सुविधाएँ सीमित हैं, और अधिकांश किसान अभी भी वर्षा पर निर्भर हैं। वर्षा आधारित कृषि हमारे देश में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 51% है और कुल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा है। सिंचाई वाले क्षेत्रों में, किसान मुख्य रूप से बाढ़ सिंचाई विधियों का पालन करते हैं। भले ही आजकल सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का महत्व बढ़ रहा है, लेकिन इसके अधिकांश अपनाने वाले बड़े किसान हैं। गरीब किसान इसे वहन करने में असमर्थ हैं। वर्ष 2021 में बोए गए कुल क्षेत्रफल में से, शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 68.38 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से सूक्ष्म

सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र केवल 12.90 मिलियन हेक्टेयर है, जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का केवल 18.8% है ।

फसल बीमा योजनाओं के संबंध में किसानों के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं में बीमा योजनाओं के बारे में उचित जागरूकता का अभाव, फसल हानि के कारण होने वाले नुकसान का मूल्यांकन, बीमा योजनाओं का अपर्याप्त कवरेज तथा दावों का भुगतान न होना/विलंबित निपटान शामिल हैं ।

जलवायु परिवर्तन से मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जैसे कि सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि । ये परिवर्तन मिट्टी की उर्वरता, फसल की पैदावार और पशुधन उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में कमी आ सकती है ।

मूल्य अस्थिरता किसानों की आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, खासकर छोटे किसान जो बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं । मूल्य अस्थिरता किसानों के लिए आय अस्थिरता का कारण बन सकती है क्योंकि कीमतों में अचानक गिरावट उनकी आय और मुनाफे को कम कर सकती है । इससे किसानों के लिए अपने खेतों में योजना बनाना और निवेश करना मुश्किल हो सकता है, जिससे गरीबी और कम उत्पादकता का दुष्चक्र शुरू हो सकता है । यह स्थिति किसानों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है क्योंकि उन्हें भविष्य में अपनी उपज के लिए मिलने वाली कीमतों के बारे में निश्चित नहीं है । इससे किसानों के लिए यह निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें कौन सी फसल उगानी है, कितना उत्पादन करना है और अपनी उपज कब बेचनी है ।

भारतीय किसान समुदाय में मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, जो कृषि में उपरोक्त सभी चुनौतियों का सामना करते हैं । किसानों को कृषि में प्रकृति की गतिविधियों से लेकर जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव, जैव विविधता की हानि, जल संसाधन की कमी, पूंजी की कमी, श्रम और अन्य इनपुट आदि सहित मानव निर्मित गतिविधियों तक कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इन समस्याओं का मुख्य कारण उचित जागरूकता की कमी, आधुनिक तकनीकों को कम अपनाना, पूंजी की कमी या किसानों और सरकारी संस्थानों के बीच की खाई है । इन समस्याओं को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमान कृषि पद्धतियों का पालन करके,

संसाधनों के सतत उपयोग और ग्रामीण किसानों, सरकार और वित्तीय संस्थानों के बीच की खाई को पाटकर कुछ हद तक कम किया जा सकता है ।

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Respected Speaker Sir, I thank you very much for allowing me to make a submission on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The people of Kerala's main meal is rice and to meet this needs increased cultivation is required in proportion to the growing population of the State. But what we are witnessing is a declining trend in rice cultivation and production. This is the phenomenon across the State. While the production of rice in wetland fell by 10.5% in 2023-24 compared to 2022-23, productivity and the area under cultivation fell by 4.9% and 5.9% respectively. When it comes to rice cultivation in the State of Kerala, the title of rice bowl of Kerala is with the district of Palakkad, as rice cultivation is being carried out in many thousands of hectares of land in the district. However, Palakkad recorded the biggest production decline in the wetland category, say about 23%. The paddy farmers are forced to quit farming due to many factors. One of the reasons is cost escalation in all input materials used for farming as well as labour charges. Palakkad is the district which is on top among the districts in Kerala that has shown declining trend in farming. Another reason for showing less interest in farming is because of delay in procuring their hard-earned produce and sometimes paddy remained open in the field itself for a number of days, getting damaged due to rain, etc. The wild animals damaging their standing crops is also a matter of concern, leading to financial losses. The price that they are getting for their produce is also not in proportion to the cost involved. Another and vital issue the farmers are facing is pertaining to climatic conditions - unexpected rains and no rains. Palakkad is not only a rice bowl of Kerala, but also producing many agricultural produces. I have been demanding to provide a special

package for the farmers of Palakkad in this august house from time to time, say from the day one I became a Member of Parliament from Palakkad parliamentary constituency way back in the year 2019, and I demand the same again here in the interest of farmers belonging to Palakkad district. The farmers of Palakkad not only produce paddy, but other agricultural produces because the soil of Palakkad is such that it suits for all agricultural activities. That is also one of the reasons why I demand for a special agricultural package for the farmers in Palakkad district, so that farmers can undertake cultivation in expanded areas.

The Government with much fanfare announced way back in the year 2016 to double farmers income by 2022. Now we are in the midst of year 2025, we have not seen any positive steps to increase the farmer's income to double and whereas the ground reality is that the farmers were not able to even recover the amount they spent on farming. In many cases reported across the country the farmers were forced to throw their hard-earned produce on the roads as a mark of protest for not able to realize the cost of production and make repayment of bank loan took by them for cultivation.

The legally guaranteed minimum support price for crops is the long standing demand of framers across the country. The historic farmers strike near Delhi border was also for the said cause. It is no doubt that the legally guaranteed minimum support price for crops will address the burning issue of farmers suicides in the country. Sir, during the last ten years the country witnessed a whopping number of farmers suicides, it has been reported by the National Crime Record Bureau at 1,12,000. The rapid increase in suicide rates amongst farmers is importantly also contributable to poor government policy towards the agricultural sector. The amount given under the PM KISAN scheme needs to be increased from Rs. 6,000 to Rs.12,000 per annum as the current amount given by

the government is not sufficient for the purposes the scheme introduced and such seasonal incentives may be extended to tenant farmers and farm labourers as well. The Government should also introduce a comprehensive crop insurance plan for small holding farmers.

The low budget allocations for key agriculture schemes are also a cause of concern. The farmers in the country are struggling with the cost of urea and its timely non-availability. The reduction in the allocation for the fertilizers is likely to impact fertilizer subsidy. It is the need of the hour to produce more yield in lesser areas. To achieve this our farmers should get quality seeds and fertilizers and the most critical factor for farming is good seeds. Good quality seeds can boost production by 20%. Therefore, the Government should study the recommendations of the recently concluded National Seed Congress.

With this I conclude and oppose many aspects of the budget allocations.

Thank you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I would like to highlight the urgent need for policy and governance interventions to safeguard India's agriculture sector, which remains the backbone of our economy. Despite its fundamental role in ensuring food security and rural employment, agriculture is in a deep crisis due to policy neglect, rising costs, climate vulnerabilities, and unfair market conditions. Farmers continue to struggle with inadequate financial support, exploitative trade practices, and the looming threat of climate change. This discussion on the Demands for Grants is not just about financial allocations it is about the survival and dignity of our farmers.

One of the biggest betrayals of this government has been its failure to enact a legal guarantee for Minimum Support Price (MSP). Farmers

fought historic protests demanding fair prices, yet the government has not honored its commitment. Procurement mechanisms remain weak, forcing many farmers to sell their produce at prices lower than the declared MSP. The increasing corporate control over agriculture is another alarming trend, where large agribusinesses dictate terms to small and marginal farmers, pushing them into deeper distress. Institutional loans have become increasingly inaccessible, leading to a surge in farmer indebtedness. The government must prioritize interest-free loans through cooperative banks to support small farmers and prevent their exploitation by private moneylenders. A National Paddy Board must be established, with its headquarters in Kuttanad, to ensure scientific planning, fair pricing, and sustainability for paddy cultivation nationwide.

Meanwhile, reckless import policies have worsened the situation by allowing cheap, foreign produce to flood the domestic market. Rubber, coconut oil, wheat, and pulses are being imported at lower tariffs, causing price crashes and endangering the livelihoods of Indian farmers. The Centre must revise import tariffs and implement stricter trade policies to protect domestic agriculture.

Climate change has further exacerbated agrarian distress. Increased frequency and intensity of extreme weather events like droughts, floods, and storms. These changes can affect soil fertility, crop yields and livestock production, leading to reduced productivity and income for farmers. Farmers may need to invest more in pest and disease management practices, which can increase their costs and reduce their profits. India urgently needs a National Climate Resilient Agriculture Policy that integrates better irrigation, climate-resistant seed varieties, and comprehensive crop insurance.

Unpredictable rainfall affects several agricultural operations and unexpected rainfall during harvest will lead to total crop loss. Heavy rains that result in flooding can be detrimental to crops and soil. In India, around 33.9 million hectares of cropped area have been damaged due to hydro-meteorological calamities including heavy rainfall and floods between 2015-16 and 2021-22.

Kerala's farmers face unique challenges that demand urgent central intervention. Paddy cultivation is declining due to rising labour and input costs, while procurement delays discourage many from continuing production. Farmers in Kuttanad, the "Rice Bowl of Kerala," struggle due to inadequate storage facilities and delayed payments. The rubber sector, a major source of income for Kerala's farmers, is also in crisis. Prices have plummeted due to cheap imports, lack of procurement support, and the absence of a price stabilization mechanism. The government must increase import duties on rubber and implement a Rubber Price Stabilization Fund to ensure fair pricing for farmers. Similarly, coconut farmers suffer due to price fluctuations and unregulated palm oil imports. The Centre must provide an MSP for coconuts and direct financial assistance for pest control and replanting. A Special Agricultural Zone must be declared for Kuttanad, recognizing its unique landscape and integrating it into the Global Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS). A dedicated governance agency must be established to ensure holistic planning and policy implementation. MSP must be aligned with the actual cost of production in Kerala, and Farmer Producer Organizations (FPOs) and cooperatives must be strengthened to enhance collective farming, procurement, and market linkages. Government to support FPOs by giving special concessions in procedural issues, GST, etc. This reduces the returns to farmers whose margins are relatively low to begin with.

Infrastructure for water management and climate adaptation must be prioritized by strengthening bunds, flood management systems, and drainage networks. Floating solar and wind energy projects should be promoted as part of an integrated renewable energy strategy. Organic farming should be encouraged with certification support, and climate-resilient crop varieties must be developed. Community-led water conservation and rainwater harvesting must be expanded, while biodiversity conservation efforts should be strengthened through sustainable practices.

Skill development and digital transformation must be integrated into agricultural reforms. Innovative skill training and incubation programs should be developed to support agri-preneurship. AI and IOT-based smart farming solutions must be implemented to enhance productivity and efficiency. Women and youth must be encouraged to participate in agribusiness through dedicated support for startups, cooperatives, and leadership roles. Holistic rural development initiatives must also be prioritized, including village-level multi-purpose centers that integrate education, banking, markets, and healthcare. Strengthening livestock and dairy farming with local breeds, implementing drinking water and rainwater harvesting systems, and ensuring soil health monitoring will further contribute to sustainable agricultural growth. Government to bring-in subsidy scheme similar to DEDS for the benefit of allied farmers, as well as to increase the GDP growth.

Crop diversification must be promoted through the introduction of short-duration, high- yielding, flood-resistant rice varieties in Kuttanad. Traditional Pokkali farming should be revitalized to harness its saline-resistant properties. Agroforestry must be encouraged to improve resilience and productivity, while inland fisheries, dairy, and poultry sectors should be strengthened. Additionally, value addition centers with

climate-smart infrastructure must be set up at the local level to improve processing and storage. Strengthening rural cold storage and supply chain infrastructure is essential to minimize post-harvest losses. The promotion of coconut-based value-added industries and the implementation of integrated pest and disease management techniques will help stabilize farm incomes.

Focusing on Mavelikkara Lok Sabha Constituency, several agriculture-related issues need immediate attention. Kuttanad farmers continue to face procurement delays and financial distress due to erratic government policies. A dedicated procurement center must be established in Mavelikkara to ensure timely payments. The absence of cold storage and food processing units exacerbates post-harvest losses, particularly for paddy and plantation crops. The Centre must allocate funds for a modern agro-processing facility in Mavelikkara to reduce losses and create employment.

Additionally, the Government must address the neglect of agricultural infrastructure, particularly irrigation and soil conservation measures, which are crucial for Kerala's farming community.

Given these challenges, I demand immediate action from the Union Government. First, a legal MSP guarantee must be enacted to ensure fair prices for farmers. Second, the budget allocation for agriculture must be increased to strengthen rural infrastructure under RIDF through NABARD and farm support programs. Third, crop insurance and disaster relief funds must be enhanced to protect farmers from climate-related losses. Fourth, a special financial package for Kerala's agricultural sector must be implemented, particularly for rubber, coconut, and paddy farmers. Fifth, agricultural credit through cooperative banks must be boosted to ensure easy access to loans for small farmers. Sixth, import tariffs must be revised to prevent cheap foreign produce from flooding

Indian markets. Seventh, cold storage and food processing units must be set up in Kerala to support value-added agriculture.

The fate of Indian agriculture is at stake. Farmers are the backbone of our nation, yet they are being systematically weakened by flawed policies, poor financial support, and corporate interests. It is time to move beyond rhetoric and take decisive action. The government must allocate adequate funds and prioritize farmer welfare over corporate profits. The farmers of India, Kerala, and Mavelikkara are watching - and they demand justice. It is our responsibility to ensure that their voices are heard and their demands met.

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 2025-26 की अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद । यह बजट हमारे देश के किसानों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं इसे सरकार के पक्ष में आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूँ ।

इस मंत्रालय को 1,37,757 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, मंत्रालय के व्यय में बजट अनुमान की तुलना में 6-8% की वृद्धि हुई है ।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 2025-26 के बजट में 1,25,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है । श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनके सहयोगी राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने किसानों के हित में इस बजट में अनेक कल्याणकारी कदम उठाए हैं । जैसे कि :-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल की खराबी के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

इन योजनाओं से किसानों को अपनी आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी, और वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम होंगे ।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे । इस बजट से लगभग 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे ।

पीएम धन धान्य कृषि योजना राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू की जाएगी और अनुमान है कि इसमें 1.7 करोड़ किसान शामिल होंगे । यह योजना कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण पहुंच वाले 100 जिलों को लक्षित करेगी । इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है ।

उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित करना, जलवायु और कीटों के प्रति प्रतिरोधी उच्च उपज देने वाले बीजों का विकास और प्रसार, और उच्च उपज देने वाले बीजों की किस्मों पर अनुसंधान को मजबूत करना । इस मिशन के तहत 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण सीमा में वृद्धि की गई है । संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाएगी ।

इस बजट में बागवानी पर विशेष ध्यान दिया गया है । फलों और सब्जियों के उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी कीमतों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा । इस कार्यक्रम के लिए 2025-26 के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । इसका लक्ष्य राज्यों में किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों का गठन और भागीदारी करना है ।

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल की अवधि के लिए एक नया मिशन शुरू किया जाएगा । इस मिशन का उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर की खरीद के माध्यम से दालों

के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है । इस योजना के लिए 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।

देश के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु असम में 12.7 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है ।

मेरा संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर, जो एक अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जहां 70-80 प्रतिशत खेती होती है, जिनमें गन्ना, गेहूं, धान और आलू की प्रमुख है और फलों में आम व अमरूद की भी काफी उपज है ।

मुझे क्षेत्र में भ्रमण के दौरान विगत काफी समय से स्थानीय लोग शाहजहांपुर जनपद में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कराए जाने हेतु अनुरोध कर रहे हैं । यह सही है कि यहां पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने से युवाओं को कृषि की बारीकियां मालूम हो सकेगी और वे कौशल युक्त बन सकेंगे और साथ ही चूंकि, बरेली मंडल में कहीं भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए शाहजहांपुर के निकटवर्ती कृषि प्रधान जिलों को भी इसका भरपूर लाभ मिल सकेगा ।

अतः मेरा अनुरोध है कि वह शाहजहांपुर जनपद के पुवायां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खुटार, जो गन्ना एवं धान की बंपर उपज के लिए पहचाने जाते हैं, में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए

मेरे संसदीय क्षेत्र में पुवायां तहसील उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली तहसील है । यहां पर धान, गेहूं, गन्ना की भरपूर मात्रा में खेती होती है ।

मेरे क्षेत्र में गन्ना शोध केन्द्र भी स्थापित है, जो गन्ने की नई-नई प्रजातियों पर रिसर्च करता है । उत्तर भारत में गन्ना खेती को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से गन्ने पर शोध हेतु वर्ष 1912 में शाहजहांपुर में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 1976 में एक स्वशासी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के नाम से पुनर्गठित किया गया ।

यह संस्था देश के गन्ना कृषकों एवं चीनी उद्योग के उत्तरोत्तर विकास हेतु निरंतर सतत प्रयासशील है । शोध परिषद का मुख्य उद्देश्य गन्ना खेती के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं सुझाव देना, क्षेत्रीय अनुकूलता के अनुरूप अधिक उपज व शर्करा युक्त रोग-रोधी नवीन गन्ना किस्मों का विकास करना, प्रशिक्षण के माध्यम से गन्ना कृषकों एवं गन्ना

उद्योग से जुड़े कर्मियों को गन्ना खेती के नवीन आयामों व विधाओं से परिचित/प्रशिक्षित कराना है ।

शोध परिषद द्वारा वर्ष 1912 से अब तक गन्ने की कुल 237 किस्मों का विकास कर देश के चीनी उद्योग के उत्थान में अहम योगदान दिया गया है । विभिन्न क्षेत्रीय जलवायु दशाओं में और कृषकों के लिए उपयोगी पाई गई हैं । गन्ना खेती न केवल चीनी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल के वर्षों में सरकार द्वारा इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रोत्साहित करने की योजना के दृष्टिकोण से पेट्रोल के साथ मिलाने हेतु इथेनॉल उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण फसल है ।

उल्लेखनीय है कि 2022-23 में देश में 153 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन संभव हो सका, जो वर्ष 2016-17 में मात्र 42 करोड़ लीटर था । इथेनॉल न केवल हरित धन के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह कच्चे तेल के आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत कर रहा है ।

नई गन्ना किस्मों के बीज गन्ने का उत्पादन व वितरण करने वाले सक्रिय कृषकों का पंजीकरण भी अब शोध परिषद में किया जा रहा है, जिससे अन्य गन्ना कृषकों को प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता उपयुक्त मूल्य पर स्थानीय स्तर पर सुलभ हो रही है । नयी किस्मों के मिनी सीड कट के पारदर्शी वितरण हेतु मिनी सीड कट की ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है ।

ड्रिप सिंचाई और वैकल्पिक नाली में सिंचाई से लगभग 40-60: सिंचाई के पानी की बचत होती है, जिससे भूजल के दोहन में कमी आएगी । इससे लागत में भी कमी संभव होगी तथा गन्ना और चीनी की उत्पादकता में भी आवश्यक वृद्धि होगी । ड्रिप सिंचाई से न केवल पानी की बचत होती है, बल्कि इससे उपज में भी 20-25% की वृद्धि होती है ।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित उ०प्र० गन्ना शोध केन्द्र को केन्द्र सरकार और अधिक प्रभावी एवं उच्चकृत/आधुनिकतम किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए ।

हमारे देश में बांस एक महत्वपूर्ण फसल है तथा भारत दुनिया में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है । बांस का पौधा तेजी से बढ़ता है और इसकी खेती से किसानों को अच्छी आमदनी भी होती है ।

हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में कृषि मंत्रालय ने किसानों की खेती कमाई के एक अच्छे विकल्प को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018-19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों में बांस की खेती का रूझान पैदा हुआ है और आज वे तेजी से दोबारा बांस की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। बाँस अपनी तेज पैदावार व विकास दर और प्रचुरता के कारण इथेनॉल तथा जैव-ऊर्जा उत्पादन के लिये एक विश्वसनीय स्रोत है, जिसकी वजह से बांस की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है।

मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर से गंगा, बहगुल, खन्नौत, गर्रा, रामगंगा एवं बड़ी गंगा ढाईघाट नदी होकर गुजरती है।

इन नदियों के आसपास बांस की खेती की प्रबल संभावनाएं हैं

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत बांस की खेती को बढ़ावा दिए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए।

अंत में, मैं पुनः 2025-26 की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कृषि मंत्रालय का यह बजट हमारे देश के किसानों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट किसानों को अपनी आय में वृद्धि करने में मदद करेगा, और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और उनके सहयोगी राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी तथा श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों का पूरजोर समर्थन करता हूँ।

SHRI TANGELLA UDAY SRINIVAS (KAKINADA): Today I express my views not just as a representative of my people but as a voice for millions of farmers who toil under the sun, braving uncertainty to ensure that India never sleeps on an empty stomach. From the fertile plains of Punjab to the lush coastal fields of Andhra Pradesh, our farmers are not just cultivators of crops, they are the very heartbeat of this nation.

Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, this government has demonstrated an unwavering commitment to agriculture. The budget for the Ministry of Agriculture has been increased to ₹1,27,290 crore—an increase of nearly ₹5,000 crore. This is not just a financial allocation—it is a promise, a commitment to modernization, sustainability, and the welfare of those who work the land.

Several landmark initiatives stand as a testament to this commitment. The PM-KISAN scheme, which has been a lifeline for small and marginal farmers, has been allocated ₹63,500 crore, ensuring financial stability for over 11 crore farmers across the country. The Rashtriya Krishi Vikas Yojana has received an enhanced allocation of ₹8,500 crore, reinforcing efforts to improve soil health, optimize fertilizer use, and strengthen agricultural infrastructure. Recognizing the importance of sustainable farming, the National Mission on Natural Farming has been allocated ₹616 crore to encourage eco-friendly, chemical-free agricultural practices. In a significant step towards modernization, the Namo Drone Didi scheme has been expanded to ₹676 crore, empowering women self-help groups with drone technology to make farming more efficient and precise.

These initiatives reflect a strong intent, but for policies and budgets to make a real impact, they must reach the farmers who need them most. And for that, I turn my attention to my home state, Andhra Pradesh.

Here, tenant farmers form the backbone of agriculture, accounting for over 50% of the workforce. In coastal regions like Kakinada, nearly 65-80% of paddy farmers cultivate leased land. Yet, despite their contribution, these farmers have been systematically excluded from crucial welfare schemes such as PM-KISAN, denied access to bank credit, and left without input subsidies. This exclusion has forced them

into the grasp of informal moneylenders, trapping them in cycles of debt that often end in tragedy.

Under the previous YSRCP regime, tenant farmers in Andhra Pradesh suffered immensely. The state ranked second in farmer suicides, with tenant farmers being the most vulnerable. Neglect and indifference toward their plight, coupled with divisive policies, shattered the livelihoods of thousands of families. Instead of providing relief, the government chose to look the other way as these farmers were pushed to the brink.

In this dark period, our Deputy Chief Minister, Pawan Kalyan, emerged as a beacon of hope. Using his personal funds, he provided direct financial compensation to over 500 families of tenant farmers who had tragically taken their own lives. Through his Kooli Rythu Bharosa Vatra, he actively engaged with struggling farmers, listened to their grievances, and fought for their rights at the highest levels. He inspired all of us, as representatives, to extend our support, reinforcing the idea that governance is not about power but about responsibility.

With the NDA alliance now leading Andhra Pradesh, we are committed to reversing these Injustices. Recognizing the urgent need to protect tenant farmers, the state government has introduced the Andhra Pradesh Land Cultivators Rights Act-2024. This landmark legislation ensures that tenant farmers receive Crop Cultivator Rights Cards within just 15 days, allowing them access to bank loans, input subsidies, crop insurance, and cash transfer schemes,

However, while Andhra Pradesh is taking bold steps in the right direction, the Central Government must step in to ensure that schemes like PM-KISAN extend to tenant farmers nationwide. This is not just about policy; this is about justice.

Additionally, to support tenant farmers at a national level, I urge the Central Government to create a Tenant Farmers Development Fund with an initial allocation of ₹10,000 crore. This fund will ensure that registered tenant farmers under state-recognized frameworks like Andhra Pradesh's CCRC system receive PM-KISAN benefits, providing them with much-needed financial stability. It will enable access to subsidized credit through Kisan Credit Cards, preventing tenant farmers from being forced into the exploitative hands of private moneylenders. It will also ensure their inclusion in crop insurance schemes, reducing their vulnerability to climate shocks and crop failures. Furthermore, the fund will promote mechanization and modern agricultural techniques, helping smallholder tenant farmers improve productivity and increase their incomes.

This initiative has the potential to transform the lives of over 2 crore tenant farmers across India, ensuring they receive the same benefits and protections as landowning farmers.

Our tenant farmers are the silent backbone of Indian agriculture. Their exclusion from financial support is a grave injustice, one that we must correct without further delay. By establishing a Tenant Farmers Development Fund, we can give them the security, dignity, and financial stability they rightfully deserve.

Let us take this bold step together. Let us create a future where every farmer-landowning or tenant-stands strong, secure, and prosperous. Let us build an Atmanirbhar Bharat where no farmer is left behind.

Thank you!

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY (NELLORE): Thank you for this opportunity to place my views on the Demands pertaining to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

We are being an agrarian nation, farmer being the backbone of agriculture and, as Dr. Abdul Kalam said, India having core competence in agriculture, we have to put every single effort to push our agriculture production, productivity and welfare of our farming community.

This discussion on Demands under the control of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare gives us another opportunity to present our views before the hon. Minister for overall development and growth of our agriculture, allied sectors and farmers.

There is no doubt that the Ministry has got 2.7% of the Union Budget, but it has got 2.5% less than what it got at RE last year. For 2025-26, Ministry has got Rs. 1.37 lakh crores when compared to Rs. 1.41 lakh crores at RE of 2024-25. But, if you look at it closely, five schemes of the Ministry - PM-KISAN, Crop Insurance, Modified Interest Subvention Scheme, RKVY and PM-AASHA - take away Rs. 1,13,783 crores and the Ministry left with just Rs. 24,000 crores. So, first question is how hon. Minister, who is former CM, is going to manage with this meager amount. Secondly, how hon. Minister is going adjust the new schemes announced in the Budget, such as PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana, National Mission on High Yielding Seeds, Enhanced credit limit under Kisan Credit Card, Focus on Horticulture, new Urea Plant in Assam and Self-Sufficiency in Pulses, and allocate resources.

The second point I wish to make is relating to the Ministry's one of the Flagship Schemes - PM-KISAN. I thank the hon. PM on behalf of the farming community for releasing 19th Installment of PM-KISAN exactly one month ago and so far GOI spent more than Rs. 3.6 lakh crores. Sir, it is welcome that FM has allocated Rs. 63,500 crores to PM-KISAN for 2025-26. But, Sir, PM-KISAN and other schemes helping only agriculture landowners and not tenant farmers who constitute 17.3% as per NSO's

latest figures and AP has highest (42.4%) tenant farmers, followed by Odisha (39%) and West Bengal (29.5%).

Secondly, GOI is giving PM-KISAN to only 9.8 crore farmers against the original estimation of 14.5 crore farmers in 2019. It means, 5 crore left out are tenant farmers and more than 2 crore tenant farmers are from AP alone. So, I appeal to the hon. Minister to consider extending PM-KISAN to these 5 crore left out tenant farmers which will go a long way in doing justice to the entire farming community.

The next point I wish to touch upon is relating to the growth in agriculture. It is unfortunate that in spite of we are being an agrarian country, agriculture providing employment to more than 50% of people and providing nearly 20% value addition, the growth is not even 50% of rest of the economy. We had grown a little over 5% in 2019-20, but never touched this since then. What are the reasons? What are the reasons that we have not been able to increase productivity of our major crops even to the level of world average is an important aspect that we need to introspect and take corrective measures. Our productivity of paddy is only 60% of world's highest; productivity of wheat is just 40% and maize is only 1/3rd, So, I feel, there is a need to bring structural, technological, targeted utilization of resources, diversification and other measures to push our productivity.

Farmer's income is one area where we are not able to achieve what we intend to. We have Committees and Commissions to push farmers income and the latest one being Doubling Farmers' Income in 2016. But, still, we are not able to double this income. I personally feel that Dr. Swaminathan Commission's recommendations have to be implemented in its spirit only then we can see that farmers' get better income.

Before touching a few other issues, I wish to say about my State - Andhra Pradesh - briefly and request the hon. Minister to help AP, as it is leader in many agri products, so that it becomes a growth engine for Agriculture Ministry:

Eluru district in Andhra Pradesh is leader in producing Cocoa in the country. But, there is frequent fluctuation in the Cocoa prices in the international market and hence farmers in AP are facing problems. So, there is a need to help them whenever there is fall in prices and also extend them every help, right from financial assistance to use of technology, quality, etc.

Andhra Pradesh, with more than 1 lakh hectares, has the highest land under organic farming in the country. So, organic farmers have to be extended every help. There is also need to take steps by the Government for need-based capacity building programme for State extension agencies, agriculture universities, farmers for further pushing organic farming, awareness, etc., in AP. Secondly, Ministry should consider addl. help to States like AP which are performing well in organic farming.

India is world leader in banana production and Andhra Pradesh with nearly 65-70 lakh tonnes is leading producer in the country. But, the unfortunate part is that there is no specific and specialized programme for banana cultivation in the country, except common programmes like Mission for Integrated Development of Horticulture, etc. So, I request for consideration of the hon. Minister for creating a separate and focussed programme for bananas.

Again, AP is producing 90% of palm oil production in the country. There is no doubt that there is National Mission on Edible Oil - Oil Palm helping to some extent. All I suggest to the hon. Agriculture Minister is to make

district as a unit and implement it effectively, so that we can produce more, reduce our dependence on countries like Malaysia and save foreign exchange.

There is a demand for setting up of Central Agricultural University in Andhra Pradesh. Sir, this issue has also come up for discussion before the High Level Committee constituted by Home Ministry with officials from GoAP. I would be delighted, people of AP would be delighted and, more particularly, farmers of AP would be delighted if GOI sets up one Central Agricultural University in AP since the ultimate beneficiaries are none other than farmers.

The next point is about heavy dependence on rain by farmers in the country. More than 50% of net irrigated area is dependent on rainfall. When Vajpayeeji was Prime Minister, he constituted a Task Force on Micro-Irrigation headed by our hon. APCM, Shri Chandrababu Naidu garu, and the Task Force submitted its Report in February, 2004. No doubt, we are implementing More Crop Per Drop and other schemes. But, so far, we have not been able to cover even one lakh hectares and beneficiaries are just 48 lakh farmers out of 14.5 crore farmers - it is an estimation made in 2019 under PM-KISAN. So, there is need for transformational change in the approach towards micro-irrigation.

While I compliment the Government for bringing down subsidy on fertilizers and Urea since 2022-23, but still Government is spending Rs. 1.68 lakh crores next year on these subsidies. Total fertilizer subsidy is estimated to be 3.3% of the country's total Budget. It is huge and I wish that the hon. Minister to focus more on this and see that we bring down imports, push production of Urea and other fertilizers and encourage organic farming in the country.

One issue I wish to bring to the hon. Minister which I read is that Pakistan is illegally cultivating Indian Agricultural Research Institute's improved basmati rice varieties in Multan, Bahawalnagar and Hafizabad. It was also reported that there is also seed piracy by Pakistan. The Indian basmati are protected varieties, but still they are illegally producing them. I am sure, this will impact our Basmati rice exports. So, I request the hon. Minister to take necessary steps.

Finally hon. Minister is also aware of this - I would say that 18% GST on implements and equipment used for agriculture is burdening farmers. And, there have been demands to take this issue before the GST Council and convince it to bring this rate down to 0%. I would say that this is the responsibility of the hon. Agriculture Minister and, I am sure, he would do this for the farming community. So, these are some of the issues which I wish to touch and appeal to the hon. Agriculture Minister to ponder over them carefully and meticulously and take appropriate measure to see that next time when we discuss Demands of Agriculture Ministry in this House or Working of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in the Upper House there would be substantial improvement in whatever I and other Members have mentioned in the House for welfare and wellbeing of our farming community.

With these observations, I support the Demands of the Ministry.

Thank you.

श्री अरुण भारती (जमुई) : सबसे पहले, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए ऐतिहासिक रु 1,37,756.55 करोड़ के बजट का प्रावधान किया । यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत के किसानों के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

- यह बजट किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । मैं बिहार का प्रतिनिधित्व

करता हूँ, एक ऐसा राज्य जिसकी मिट्टी ने सदियों से भारत की कृषि संपदा को समृद्ध किया है। बिहार के किसान मेहनतकश हैं, संघर्षशील हैं, लेकिन कांग्रेस और राजद की सरकारों ने उन्हें हमेशा हाशिए पर रखा। उन्हें न संसाधन मिले, न उचित मूल्य, और न ही उनकी मेहनत का सम्मान। लेकिन आज एनडीए सरकार के नेतृत्व में किसानों का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है।

- हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, जिससे देश में खाद्यान्न उत्पादन 2004-05 में 204.6 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 332.3 मिलियन टन हो गया है। यह दिखाता है कि कैसे सरकार की योजनाओं ने कृषि उत्पादन को नए आयाम दिए हैं। एमएसपी में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। 2008-09 में जहां धान का एमएसपी 2850 प्रति क्विंटल था, वहीं आज यह बढ़कर रु 2,300 प्रति क्विंटल हो गया है।
- इसी तरह, गेहूँ का एमएसपी रु 2,425 प्रति क्विंटल किया गया है। पीएम-किसान योजना के तहत रु 3.46 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिली। पीएम फसल बीमा योजना से रु 1.65 लाख करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया गया, जिससे उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में मदद मिली।
- ए-नम (इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) के माध्यम से 1,400+ मंडियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, जिससे किसानों को अपनी फसल के लिए उचित मूल्य मिलने लगा। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत रु 52,738 करोड़ से अधिक की राशि 87,500+ परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएँ विकसित हो रही हैं।
- बिहार के किसानों की उन्नति के लिए एनडीए सरकार ने कई विशेष योजनाएँ शुरू की हैं। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जा रही है, जिससे उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कोसी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ लाई जा रही हैं, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जमुई को भी इसमें शामिल किया जाए।
- जब मोदी सरकार किसानों के लिए ऐतिहासिक काम कर रही थी, तब चिराग पासवान जी ने बतौर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत किया, जिससे

किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने लगा। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार हुआ, जिससे मखाना, लिची, मक्का, और आम को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पहचान दिलाने का कार्य हुआ। छोटे किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ा गया, जिससे अब वे सीधे खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों से जुड़कर अपनी उपज का अधिक मूल्य पा रहे हैं।

- लेकिन कांग्रेस और राजद की सरकारों ने हमेशा किसानों को धोखा दिया। उन्होंने किसानों को कर्जदार बनाया, उनकी ज़मीन हड़प ली, और कृषि को बिचौलियों के हवाले कर दिया। कांग्रेस शासन में एमएसपी सिर्फ एक चुनावी नारा बना रहा, लेकिन कभी किसानों को उसका पूरा लाभ नहीं मिला। बिहार में सिंचाई व्यवस्था चरमरा गई, नहरें सुखा दी गई, मंडियां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई और खाद-बीज तक किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए। किसानों को ऋण में डुबो दिया गया, एमएसपी का लाभ नहीं मिला, और उन्हें बेबस और लाचार छोड़ दिया गया।
- लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आज किसान सिर्फ ज़मीन जोतने वाला मजदूर नहीं, बल्कि एग्री-एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है। डिजिटल कृषि क्रांति के माध्यम से अब किसान मोबाइल से अपनी फसल का मूल्य तय कर सकता है, ई-नाम के माध्यम से सीधा व्यापारी से जुड़ सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी मिल रहा है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया है।
- आज हम एक नए कृषि युग की शुरुआत देख रहे हैं, जहाँ किसान को सम्मान, समर्थन और समृद्धि मिल रही है। एनडीए सरकार ने कृषि को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक सशक्त आर्थिक इंजन बना दिया है। आज भारत 'फूड बास्केट ऑफ़ द वर्ल्ड' बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह समय है जब किसान को सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा जाए। एनडीए सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, और आने वाले वर्षों में हम उन्हें वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए और बड़े कदम उठाएंगे।
- भारत अब कृषि क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य सिर्फ आत्मनिर्भर भारत नहीं, बल्कि वैश्विक कृषि शक्ति (ग्लोबल एग्रिकल्चरल पावरहाउस) बनना है। इस नए भारत में, किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, बल्कि दुनिया को अन्न देने वाला वैश्विक खिलाड़ी बनेगा। एनडीए सरकार किसानों की हर जरूरत को

समझती है और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है । जय हिन्द!

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Namaskar Sir! I would like to thank you for giving me an opportunity to speak on the very important Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. ? (Interruptions)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, please sit down.

? (Interruptions)

श्री दुष्यंत सिंह : महोदय, खेती हमारे खून में है और 90 परसेंट लोग खेत-खलिहान से निकलकर आते हैं । लोगों ने प्रधान मंत्री जी को मौका दिया है कि तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएं । लोगों ने मोदी जी पर अपना अटूट विश्वास दिखाया है । मोदी जी ने अपने दस साल के शासन में बहुत अच्छे काम किए हैं और इस 11वें साल में उनके नेतृत्व में बनी सरकार में कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मुझे चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है । आज वर्तमान में कृषि बजट Rs. 1,37,757 crores, which constitutes about 2.7 per cent of the Union Budget. हमने 1, 27, 290 करोड़ रुपये कृषि विभाग में किसानों की वेलफेयर के लिए दिए हैं । हमने सोचा है कि कृषि क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट का भी हम काम करें । 10, 466 करोड़ रुपये एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए दिए गए हैं । मैं जरूर कहूंगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कृषि में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसानों की आय बढ़ाई जाए । इसके लिए इनवेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर किया है ।

उन्होंने किसानों के लिए मार्केट्स बनाने ?डिलीवरी ऑफ क्रेडिट? करने का प्रयास किया है । उन्होंने हमारे इंश्योरेंस की रिस्क को दूर करने का काम किया है । हमारे लोगों को अच्छे बीज मिले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है । हमारे क्षेत्रों में जो न्यूट्रिएन्ट्स हैं, उनके क्षेत्र में उन्होंने काम किया है । उन्होंने पेस्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के साथ माइक्रो इर्रीगेशन को भी जोड़ने का काम किया है । इसके साथ-साथ सॉयल मैनेजमेंट और पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है ।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सोच है कि National Food Security and Nutrition Mission (NFSNM), National Mission on Edible Oils, Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), Sub-Mission on Seeds and Planting Materials (SMSP) के द्वारा हमारे क्षेत्रों में ?पर ड्रॉप, मोर क्रॉप? मिले । उनकी सोच है कि हमारे क्षेत्र का सिंचाई केन्द्र अच्छा बने, जिससे हमारे किसानों की उत्पादकता और आय अच्छी तरह से बढ़े ।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने राजस्थान में आकर सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू किया । जब उन्होंने इस काम को शुरू किया तो उससे पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था । यह काम उनके कर कमलों द्वारा हुआ और उनके विश्वास के कारण ही हमने यह काम करके दिखाया है । इस स्कीम में सॉयल हेल्थ और इसकी फर्टिलिटी को जानने का काम किया गया है । Twelve key soil parameters, such as micro-nutrients, essential soil indicators, pH, electrical conductivity, and organic carbon, इत्यादि को इसमें देखने का काम किया गया है । उन्होंने आज फोन के माध्यम से ही सॉयल हेल्थ कार्ड देने का काम किया है । इसकी जो टेस्टिंग हो रही है, इसके लिए उन्होंने ?विलेज लेवल टेस्टिंग लैब्स? बनाने का काम शुरू किया है, जिससे इसका लाभ सभी को मिले ।

महोदय, मेरे से पहले के वक्ता ने कहा कि हमारे क्षेत्र में मंडियों के लिए क्या काम किया गया है? क्या मुझे यह बात बोलने की जरूरत है कि मंडी के लिए e-NAM (National Agriculture Marketing) के द्वारा लगभग 1,389 मंडियों को जोड़ने का काम किया गया है? इससे 23 राज्यों, 4 केन्द्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ने का काम किया गया है । आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इसके माध्यम से हमारे 1 करोड़ 78 लाख फार्मर्स और ट्रेडर्स को जोड़ने का काम किया है । इसके साथ-साथ हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन्स को भी जोड़ने का काम किया गया है । इन सभी को देखते हुए कृषि क्षेत्र में हमारी मंडियों को और सुदृढ़ करने का काम आदरणीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी कर रहे हैं ।

महोदय, मुझसे पहले के वक्ता ने पूछा था कि हम अपने यहां के आवारा पशुओं के लिए क्या कर रहे हैं? आवारा पशुओं के लिए हम ?कैटल सेन्टर्स? की बात कर रहे हैं, जिससे वे किसानों के खेतों तक न पहुंचें ।

महोदय, हर किसान के घर में एक गौ माता होती है । इसके लिए हमने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया है । zero-budget, natural farming और हमारी परम्परागत खेती को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं । हम इसलिए इसकी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि आजकल कृषि के क्षेत्र में न्यूट्रिएन्ट्स की कमी के कारण बीमारियां होती हैं । इन्हें दूर करने के लिए National Mission of Natural Farming का काम शुरू किया गया है । इसका आउटले लगभग 2,481 करोड़ रुपये का है, जिसमें केन्द्र सरकार से 1,584 करोड़ रुपये आएगा और 897 करोड़ रुपये राज्यों से आएगा । इससे हमारे क्षेत्रों में chemical-free agro-ecological farming शुरू होगी, जिससे हमारे क्षेत्रों को बीमारियों से मुक्त करने का काम किया गया है । उन्होंने यह कोशिश की है कि हमारा इनपुट कॉस्ट कम लगे, बॉयो डायवर्सिटी हो और climate-resistant sector में काम किया जाए ।

महोदय, मैं झालावाड़-बारां संसदीय क्षेत्र से चुन कर आया हूँ, जो कि राजस्थान में है और हमारे माननीय स्पीकर साहब भी राजस्थान से आते हैं । इस क्षेत्र में गारलिक की खेती होती है । गारलिक की खेती में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी योगदान मिला है, जिसका नाम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है । किसानों को उभारने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यह स्कीम लागू की है । इसमें कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक चेन जोड़ने का काम किया गया है । हमारे इस क्षेत्र में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोशिश की है कि वर्ष 2016 से पहले जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना होती थी, वह पूरी तहसील की मानी जाती थी, उसको पंचायत से जोड़ने का काम किया है और इससे उसको भारत सरकार की वेदर बेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ने का काम किया गया है । Chairman Sir, I would like to mention that the outlay is Rs. 69,505.7 crore from 2021 to 2025-26, out of which Rs. 12,000 crore is for the farmers. यह हमारे किसानों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिया है । उसमें से 19.5 लाख करोड़ रुपये क्रॉप इंश्योरेंस के लिए दिए गए हैं । यह माननीय प्रधान मंत्री जी की वचनबद्धता है कि मोदी है तो मुमकिन है । कुछ वर्ष पहले कोविड बीमारी आई थी । उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि का काम शुरू किया । फरवरी, 2019 से डीबीटी के द्वारा तीन भागों में दो हजार रुपये किसानों के खातों में डाले जाते हैं । कांग्रेस के एक नेता बोलते थे कि राशि दिल्ली से जाती थी और उस राशि में से गांवों में कम पैसे मिलते थे । लेकिन आज माननीय मोदी

जी भेजते हैं तो किसानों के खाते में पूरी राशि एक निश्चित समय पर मिल जाती है। यह फाइनेंशियल सपोर्ट लोगों को डीबीटी के द्वारा मिल रहा है। यह माता और बहनों को मिल रहा है। जब माता-बहनों को मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत आ रही है।

आज यह देखने को मिल रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम आशा के द्वारा कोशिश की है कि it is a comprehensive initiative by the Government of India by providing remunerative prices to farmers and stabilising the price for essential commodities. माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15वें वित्त आयोग द्वारा 35 हजार करोड़ रुपये वर्ष 2025-26 तक के लिए दिए हैं। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की सराहना करनी चाहिए कि इतना अच्छा काम आपने किया है। आज हमारे नॉर्थ-ईस्ट के क्षेत्रों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू किया गया है। इसे इम्प्लिमेंट करने के लिए, स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए 31,500 प्रति हैक्टेयर तीन साल के लिए दिए गए हैं। इसमें 15,000 रुपये प्रति हैक्टेयर डीबीटी के माध्यम से दिए गए हैं। 4,500 रुपये प्रति हैक्टेयर वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए दिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो सर्टिफिकेशन होता है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा हम जोड़े जिससे हम लोग किसी भी क्षेत्र का समान सिर्फ यहां ही नहीं विदेशों में भी बेचें। हमारे पहले वक्ता बोल रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या हुआ है? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कृषि के क्षेत्र में एनुअल ग्रोथ वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2022-23 तक पांच परसेंट हुई है।

यह इसलिए हुआ है कि हमने इस क्षेत्र में इरिगेशन बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। इस क्षेत्र में हमने अपने लोगों को जोड़ने का काम किया है। यह ग्रोथ केवल वहीं नहीं हुआ है, बल्कि 6.5 परसेंट अलाई सेक्टर में भी हुआ है। यह ग्रोथ डेयरी, फिशरीज, एनिमल हसबैंडरी में भी हुआ है। 667 न्यू क्लाइमेट रेसिस्टेंस क्रॉप वेराइटीज का काम भी आईसीएआर के माध्यम से किया गया है। इसमें 3.5 परसेंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी काम किया गया है।

महोदय, मेरे से पहले के वक्ता बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में क्या काम किया गया है। वह एमएसपी के बारे में बोल रहे थे। सीएसपी ने कैलकुलेट किया और 1.5 परसेंट कॉस्ट आगे बढ़ाने का काम किया है। इसकी जो राशि है, हमें पूरा पता है कि हमारे

किसान भाइयों के लिए कई क्रॉप्स में काम किया गया है, चाहे रबी की क्रॉप हो, खरीफ की क्रॉप हो, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है ।? (व्यवधान)

महोदय, मैं पाँच मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा । हमने अपने कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के साथ-साथ लोगों को जोड़ने का भी काम किया है । आज हमारी कृषि को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ने की आवश्यकता है । हमने इसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के द्वारा जोड़ने का काम किया है । इसमें चाहे एग्री स्टॉक हो, कृषि डिजीजन सपोर्ट सिस्टम हो, हमारे नेशनवाइज सॉयल रिसोर्स मैपिंग हो, राज्यों को भी जोड़ने के साथ ही हमने लोगों को भी जोड़ने का काम किया है ।

महोदय, इस क्षेत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 22,600 करोड़ रुपये की राशि दी है । एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए, एफएम किसान के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए और आईसीएआर को बढ़ाने के लिए भी हमने काम किया है । हमने कोशिश की है कि हमारा माल केवल देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जाए । उदाहरण के लिए मैं कीवी के बारे में कह सकता है ।

महोदय, जहां से आप आते हैं, वह कीवी का प्रोडक्शन होता है और आज वह विदेशों में भी जा रहा है । आज हमारे किसान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में बजट एलोकेशन बढ़ाया गया है ।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री दुष्यंत सिंह : महोदय, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू अच्छा किया गया है । टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है । आखिरी में, मैं कहूंगा कि हमारे हर खेत को पानी, हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए । मैं राजस्थान से आता हूँ । मेरे क्षेत्र में एक परसेंट पानी है । आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो मध्य प्रदेश में किया, माननीय मोदी जी ने पूरे देश में जो करके दिखाया है, उन दोनों से सीख लेकर हम कोशिश करेंगे कि हमारा किसान विकसित हो । हमारे किसान विकसित होकर आगे बढ़ें । इसी के साथ उनकी इनकम भी बढ़े । हमारी इनकम बढ़ने के साथ ही क्षेत्र का भी विकास हो । माननीय प्रधानमंत्री जी ने एफपीओ को भी जोड़ा है । चाहे दूध का उत्पादन हो, मछली का उत्पादन हो, इन सभी के माध्यम से किसानों की आय बढ़े । इसके लिए हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं ।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिंद ? जय भारत ।

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): I would like to draw the attention of the Government towards the persistent and alarming issues faced by the farmers of my constituency, Kishanganj & Purnea, Bihar. Agriculture is the backbone of our economy, and Kishanganj & Purnea predominantly agrarian, with thousands of families depending on farming for their livelihood. However, despite the hard work and dedication of our farmers, the agricultural sector in Kishanganj & Purnea continues to struggle due to multiple challenges that demand urgent intervention.

Farmers in Kishanganj & Purnea & in rest of Bihar are facing an acute shortage of fertilizers, particularly urea, DAP (Di-Ammonium Phosphate), and potash. This persistent crisis severely affects crop yields and compels farmers to purchase fertilizers at inflated prices in the black market. The shortage often coincides with peak sowing seasons, exacerbating financial stress on farmers. The inefficient supply chain, poor stocking at cooperative societies, and hoarding practices need to be addressed urgently. Additionally, many farmers in remote areas are unable to access fertilizers due to poor distribution networks. The Government must ensure a dedicated fertilizer supply chain with timely distribution to meet demand during crucial farming cycles.

Kishanganj is severely affected by frequent floods, especially during the monsoon season. The Mahananda, Kankai, and Mechi rivers often overflow, causing devastating floods that destroy standing crops, livestock, and stored grains. Alongside this, soil erosion remains a major challenge, where fertile topsoil is continuously washed away, reducing land productivity. This ongoing loss of cultivable land plunges farmers into deeper economic distress.

I strongly urge the Government to implement the following measures to address this:

Construction of permanent embankments in flood-prone areas.

Dredging of rivers to improve water flow and reduce the risk of overflows.

Strengthening soil conservation projects such as check dams, terracing, and plantation of erosion-resistant vegetation.

Despite being an agrarian region, my constituency, Kishanganj's dependency on rainfall for irrigation is alarmingly high. The absence of sufficient canal networks, check dams, and tube well systems drastically hampers crop productivity. This reliance on erratic rainfall leaves farmers vulnerable to drought conditions and dry spells.

I demand that the government allocate funds for:

The construction of irrigation canals to connect major rivers with farmlands.

Installation of solar-powered tube wells to ensure water access during dry periods.

Revival of traditional water harvesting systems to promote water conservation.

Farmers in Kishanganj & [Purnea](#), are yet to fully benefit from advancements in modern agricultural technology. The absence of mechanized equipment, combined with a lack of awareness about scientific farming methods, has stunted productivity.

I recommend the following measures:

Establishing agricultural training centers to educate farmers on modern techniques, crop diversification, and climate-resilient crops.

Providing subsidies for purchasing advanced machinery like seed drillers, rotavators, and combine harvesters.

Organizing awareness campaigns to inform farmers about organic farming methods and improved pest control practices.

Farmers in Kishanganj & Purnea, often struggle to secure fair prices for their produce. The absence of organized markets, cold storage facilities, and proper transportation infrastructure leads to significant post-harvest losses. This compels farmers to sell their produce at distress prices to middlemen.

To address this, I urge the government to:

Establish dedicated agricultural markets in strategic locations to provide farmers direct access to buyers.

Develop cold storage units to preserve perishable produce and reduce wastage.

Introduce transport subsidies to help farmers reach distant markets.

Kishanganj & Purnea lacks adequate cold storage facilities, which severely impacts the preservation of perishable crops like maize, vegetables, and fruits. The absence of cold storage units results in considerable post-harvest losses, reducing farmers' profits and discouraging them from diversifying their crops.

I strongly urge the Government to establish modern cold storage units in Kishanganj to ensure farmers can store their produce safely and sell them at better prices during off-seasons.

The Seemanchal region, including Kishanganj & Purnea, faces additional challenges due to its geographical and socio-economic conditions. The region's proximity to international borders often results in logistical delays

and reduced market access. Moreover, a significant portion of the agricultural workforce migrates to other states, resulting in severe labor shortages during peak seasons.

The Government must introduce region-specific policies that include:

Incentives for local laborers to engage in agriculture during crucial seasons

Special economic zones for agro-based industries to boost employment and market linkage.

Enhanced border trade mechanisms to improve the export potential of agricultural produce.

Kishanganj is a major tea, jute & maize-producing region, yet farmers face exploitation due to the absence of a guaranteed Minimum Support Price (MSP). Without MSP protection, farmers are often forced to sell their produce at unreasonably low prices to middlemen. This exploitation has contributed to rising indebtedness and distress migration.

I urge the Government to announce an MSP for maize, Tea & jute (enhanced) along with other key crops such as jute and pulses. This will provide farmers with financial security, encourage better cultivation practices, and ensure fair pricing for their hard work.

Farmers in Kishanganj & Purnea frequently suffer crop losses due to floods, droughts, and pest infestations. However, the existing crop insurance schemes have proven ineffective due to cumbersome claim procedures, delayed disbursements, and inadequate outreach to marginalized farmers.

I demand that the Government:

Streamline crop insurance claims to ensure quick disbursements.

Extend insurance coverage to all registered farmers and simplify the enrollment process.

Introduce a special relief package for Kishanganj farmers to compensate for previous crop losses.

Demands for Immediate Action:

Ensure uninterrupted supply of fertilizers by improving the distribution network and cracking down on black-market practices.

Expedite the construction of embankments, dredging of rivers, and implementation of soil erosion control projects.

Allocate funds for developing irrigation infrastructure, including check dams, borewells, and canal systems.

Establish agricultural training centers to educate farmers on modern techniques and soil conservation.

Develop cold storage units and improve transportation infrastructure to reduce post-harvest losses.

Launch region-specific schemes for Seemanchal farmers to improve credit access, promote organic farming, and facilitate better market linkage.

Introduce an MSP for maize, jute, tea and pulses to secure fair prices for farmers.

Revise the crop insurance framework to ensure faster claim settlements and improved accessibility.

Electrical connection for rural farmers for irrigation.

Introduce other cash crops farming for Seemanchal region.

agriculture in Kishangan, holds immense potential, but this potential is being wasted due to administrative neglect and infrastructural gaps. I urge the Government to treat this as a priority and take concrete steps to resolve these challenges. By empowering our farmers with the right resources, knowledge, and facilities, we can not only uplift Kishanganj & Purnea's agriculture but also contribute significantly to the nation's food security. Thank you.

DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL): Today I express my views with a sense of duty and concern for the well-being of millions of farmers across our great nation, especially those in the heartlands of South India and Telangana. Agriculture, as we know, is not just an economic activity; it is the very foundation of our society. It sustains the lives of more than 60% of our population, yet, year after year, we see its struggles ignored or undermined. This Government, through the 2025-26 national budget, claims to offer solutions, but as an Opposition MP, it is my solemn duty to critically assess whether these provisions are truly in the interest of our farmers or just another set of promises designed to placate the masses.

To borrow a well-known English proverb: "Actions speak louder than words." While the Government is quick to announce grandiose plans and figures, the real question is whether these allocations will translate into real, meaningful change for the farmers of India. As we examine the agricultural provisions of this year's budget, I invite this house to consider whether we are merely treading water, or if we are truly setting a course for reform that will uplift our agricultural sector and the farmers who form its backbone.

Let us begin with the simple fact: agriculture in India is in crisis. Our farmers are caught in a web of challenges - from erratic rainfall and declining soil fertility to the spiraling costs of inputs like seeds and

fertilizers. And yet, the 2025-26 budget barely scratches the surface of these deep-rooted issues.

The reality on the ground is grim. According to a report by the National Sample Survey Office (NSSO), nearly 50% of farmers are in debt, with many forced to take loans from informal sources at exorbitant interest rates. The situation in South India, particularly Telangana, is no different. The farmers of Telangana, who rely heavily on irrigation, have been left to deal with the failure of the government's promises on water management. While the government talks about large irrigation schemes, the ground reality is that many farmers still have unreliable access to water for their crops.

As the old adage goes, "You can't make a silk purse out of a sow's ear." The government cannot hope to resolve these deep structural problems simply by allocating more funds to the same failed schemes. What is needed is not just financial support, but systemic reforms that address the root causes of agricultural distress.

A key component of the budgetary provisions for agriculture is the allocation for subsidies, particularly for fertilizers. The government has earmarked ₹1.5 lakh crore for fertilizer subsidies, claiming this will ease the burden on farmers. But here, too, we see the government's shallow approach. While subsidies may provide temporary relief, they fail to address the underlying problems that farmers face.

The reality is that our agricultural system has become overly dependent on fertilizers and chemical inputs. This dependency is not sustainable. As another proverb wisely says, "Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach him to fish, and you feed him for a lifetime." Instead of simply increasing fertilizer subsidies, the government should be investing in long-term, sustainable farming practices that reduce the need for such

chemicals. The focus should be on organic farming, soil health management, and promoting water-efficient technologies that will help farmers in the long run.

Subsidies can no longer be the band-aid solution to an agriculture sector that requires genuine reforms. What we need is a comprehensive plan for agricultural transformation - one that empowers farmers with the tools they need to increase productivity and reduce their dependency on expensive inputs.

In South India, water scarcity remains one of the most pressing concerns for farmers. States like Telangana, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh have faced severe droughts in recent years, and the failure of irrigation systems only exacerbates the situation. The 2025-26 budget promises ₹50,000 crore for irrigation, but let us not be fooled by these numbers. We have seen this before - grand promises made, but no real impact on the ground.

Telangana's Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme, which was supposed to revolutionize water supply for the state's farmers, has been beset by delays and cost overruns. This project proved a futile effort as engineering lapses took the toll. Despite the state government's best efforts, the central government's support has been far from sufficient, and the reality is that many farmers still lack access to reliable water.

The English proverb "A stitch in time saves nine" comes to mind. This proverb emphasizes the importance of addressing problems before they spiral out of control. Telangana's water crisis has been a long-standing issue, yet the government's response has been slow and insufficient. What farmers in Telangana and other drought-prone areas need is reliable irrigation systems that function in both the short term and long

term. Simply throwing more money at the issue without addressing the systemic failures will not yield positive results.

This Government has often touted its welfare schemes, such as the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) and the Farmer Welfare Fund, as steps toward ensuring financial support for farmers. However, the reality is far less impressive. While ₹6,000 annually may seem like a substantial amount, it is merely a token sum that does little to address the systemic issues in agriculture.

Consider the condition of Telangana's farmers, many of whom are in severe debt. The government's schemes are often poorly implemented, and delays in disbursements are commonplace. As the proverb goes, "Don't count your chickens before they hatch." The government often makes claims about the success of its welfare schemes, but the actual outcomes are far less positive. Many farmers continue to wait for their due payments, and the bureaucratic inefficiencies that plague these schemes mean that the real benefits do not reach the intended recipients.

Furthermore, the government's claims that PM-KISAN and other schemes are transformative only reveal their ignorance of the deep structural inequalities that plague our agricultural system. These one-time payments are not enough to lift farmers out of poverty or address the systemic issues in agriculture.

Let us now focus on Telangana, where the promises of the central government ring hollow. Telangana's farmers face unique challenges, not least of which is water scarcity. The state government has worked tirelessly to improve water resources through initiatives like Mission Kakatiya and the Kaleshwaram Project, but the Central Government's support has been sporadic at best.

In this context, the 2025-26 budget's allocation for irrigation is not just insufficient - it is an affront to the hard work of Telangana's farmers. The central government's failure to address inter-state water disputes, provide timely financial support, or allocate adequate funds for irrigation projects directly impacts farmers' livelihoods.

As the proverb "The proof of the pudding is in the eating" reminds us, it is only through action and tangible results that we can measure the effectiveness of the government's policies. Telangana's farmers, despite their best efforts, continue to struggle due to the lack of substantial support from the central government. They deserve better.

In conclusion, I express my views not only as an Opposition MP but as a voice for the farmers of India - those who till the soil, who feed us, and who struggle every day against a system that has neglected them for far too long. The 2025-26 budget does little to address the urgent needs of our agricultural sector. It is time we recognized that true agricultural reform cannot come from mere token allocations or subsidies that only scratch the surface.

We need a government that takes bold, visionary steps to ensure the welfare of our farmers. This includes a comprehensive strategy for irrigation, long-term reforms in subsidies, a shift towards sustainable farming practices, and the urgent need for reliable credit systems for small and marginal farmers.

As we consider the budget and its impact on the agricultural sector, I leave you with the words of the famous proverb: "A penny saved is a penny earned." We cannot afford to waste any more time or resources on inadequate measures. The time for meaningful reform is now. Let us work toward a future where the prosperity of our farmers is not an

afterthought, but the very foundation of our nation's well-being. Thank you.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I on behalf of my party support the demand for grants of ₹1,37,756.55 crore for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare for the year 2025-26. This budget reflects the unwavering commitment of the Government of India under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi towards making agriculture a robust engine of India's growth. The increase in budgetary allocation from ₹11,915.22 crore in 2008-09 to over ₹1.37 lakh crore in 2025-26 is not just financial arithmetic - it is a testament to this Government's resolve to transform rural India.

Over the past two decades, India's foodgrain production has risen remarkably from 204.6 million tonnes in 2004-05 to an estimated 332.3 million tonnes in 2023-24. Alongside, Minimum Support Prices (MSP) for paddy and wheat have grown substantially, with the MSP for paddy increasing from ₹850 per quintal in 2008-09 to ₹2,300 per quintal in 2023-24, and wheat rising from ₹1,080 to ₹2,425 per quintal in the same period. The total MSP payment made to farmers for paddy and wheat has surged threefold in the last decade, ensuring better returns and farmer security.

Farmer-centric schemes such as PM-KISAN, under which ₹3.46 lakh crore has been disbursed directly into farmers' accounts, and PMFBY, which has enabled ₹1.65 lakh crore in crop insurance claims, have provided a vital safety net to millions of farmers. In addition, initiatives like e-NAM have digitally linked over 1,400 mandis, enhancing market access and price transparency. The Agricultural Infrastructure Fund (AIF) has further sanctioned ₹52,738 crore to support over 87,500 projects, strengthening post-harvest and storage systems across the country.

India's agriculture is not only self-reliant today but is contributing significantly to global food security. Food exports now constitute 11.7% of India's total exports, with seafood exports registering a 29.7% rise between FY20 and FY24. Allied sectors have emerged as crucial drivers of agriculture, adding diversity and value to the sector.

The Economic Survey confirms that India's agriculture sector has demonstrated resilience, registering an average growth rate of 5% between FY17 and FY23. The Gross Value Added (GVA) from agriculture, forestry, and fishing has shown steady momentum, rising from a modest 1.2% in 2014-15 to 2.1% in 2023-24. Furthermore, the Gross Cropped Area has increased from 120.2 million hectares in 2004-05 to 132.1 million hectares in 2023-24, reflecting increased cultivation and better resource utilization.

Under the Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana, 100 agri-districts with low productivity and below-average credit flow are being developed to benefit 1.7 crore farmers through targeted skilling, infrastructure, and agri-technology.

The newly announced National Mission on High Yielding Seeds will enhance the availability of improved varieties, while the 6-year Mission for Aatmanirbharta in Pulses will boost domestic production of tur, urad, and masoor. These efforts are expected to reduce import dependency and ensure price stability.

In terms of financial inclusion, the enhancement of the KCC loan limit from ₹3 lakh to ₹5 lakh is a welcome move and will particularly benefit small and marginal farmers who form the backbone of Indian agriculture. Additionally, the comprehensive programme for vegetables and fruits is a crucial step to reduce post-harvest losses and ensure remunerative prices to horticulture farmers.

I would like to place on record the commendable efforts of the State of Odisha, which has emerged as a rising star in Indian agriculture. Odisha's irrigation infrastructure is being transformed through 94 new irrigation projects with an investment of ₹8,420 crore.

These projects will boost agricultural productivity and ensure better water availability across the state. Odisha has also seen an impressive rise in women cultivators - nearly 87% growth in the past five years - marking a silent revolution in gender inclusion in agriculture.

Moreover, the state is actively contributing to India's food basket and has benefited from Union schemes such as PM-KISAN and PMFBY, effectively reaching the grassroots. Odisha's model in sustainable agriculture and fisheries, with a focus on technology and inclusivity, serves as an inspiration for other states.

With increased investment in agricultural R&D, enhanced use of digital technologies, and farmer-centric reforms, this Government has made agriculture a truly aspirational sector. The integration of agriculture with the Public Distribution System, through full e-KYC compliance, and the strengthening of food processing under the PLI scheme, further adds value across the value chain.

In conclusion, I once again support the demand for grants for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. With ₹1.37 lakh crore in allocation, we are not just funding a ministry-we are investing in the dignity, prosperity, and future of India's farmers. I urge the House to pass this demand unanimously as a step toward building a prosperous, resilient, and globally competitive agriculture ecosystem. Jai Hind. Jai Kisan.

श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी (बीरभूम) : सर, जन्म से लेकर मरने तक हमारे जिंदगी में बहुत से फेजेज आते हैं । हर एज में हम लोगों की पसंद और नापसंद बदल जाती है,

रिश्ते बदल जाते हैं, मोहब्बत बदल जाती है, दोस्ती बदल जाते हैं, प्रोयोरिटी बदल जाती है । लेकिन, जन्म से लेकर मरने तक एक चीज नहीं बदलती है, वह है भूख । हमारी भूख को किसान लोग मिटाते हैं । हमारे किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है, इसे जानना बहुत जरूरी है ।

सर, दो-चार ऐसी स्टेट्स हैं, जहां कुछ किसानों के पास पक्का घर है, ट्रैक्टर है, लेकिन देश के बाकी किसानों के पास न तो घर है और न ही ट्रैक्टर है । उनके पास सिर्फ गरीबी है । Trust me!

The Economic Survey claims that the output in agriculture and farmers' income has increased, but record shows that it is still below the decade-back production. As regards farmers' income, either there is no change or there is fall in real income.

Allocation for agriculture under Demand No. 1 has been reduced by three per cent. So, here comes the crucial question. Nearly 48 per cent of country's employment, 65 per cent of the population and 18.2 per cent of the GDP depends only on agriculture.

Why is there a cut of three per cent in the allocation? How can merely three per cent allocation of the total budget do justice to such a massive dependency?

सर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता है? उसके बाप-दादा किसान हैं, तो वे उसे समझाएंगे कि यह महान काम है । बेटा बाप से यह नहीं पूछेगा कि अगर आपको पता है कि यह महान काम है तो सरकार को क्यों नहीं पता है? जो महानता सरकार को दिखानी है, वह क्यों नहीं दिखाती? सालों की मेहनत का टुमैटो, पोटैटो, ट्रक-ट्रक भरकर जब रास्ते में फेंकते हैं तब महानता कहाँ जाती है?

Last year, the Government claimed that there was a record output of food grains but, actually, soon they banned the export of wheat and

paddy, and public on the street had to buy the food grains at ever increased prices.

The total budget allocation for natural farming over the last three years has been Rs. 746.19 crore only. There is a mention of natural farming in the Budget but on the contrary, it is more inclined towards unnatural substances. *The Economic Survey* notes that the expected growth in the agricultural sector is 3.8 per cent. Interestingly, the State of Indian Agriculture 2015-16, a report by the Ministry of Agriculture informs that, a decade back, India had an annual average growth rate of five per cent in the agricultural sector.

Sir, are the lives and contributions of sharecroppers counted important? If my State of West Bengal can include sharecroppers under West Bengal Krishak Bandhu Scheme, what stops Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana to do the same? प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इसे इंकलूड करने में क्या प्रॉब्लम है? It remains a mystery as well as a pathetic decision.

Sir, we need to be serious about the distress of farmers. Perhaps, due to such poor understanding of farmer's problems, in this Budget, PMFBY, the crop insurance scheme has got a cruel cut of 23 per cent. PMFBY charges premium on the enrolled farmers. On the other hand, in West Bengal, the State-run Bangla Sashya Bima Scheme is a fully State Government funded scheme under which, farmers need not pay any premium. एनुअली 6,000 करोड़ रुपये स्टेट के लिए खर्च होते हैं । इसमें 109 लाख नए फार्मर्स एनरोल हुए हैं, जिन्हें ममता बनर्जी की सरकार मदद दे रही है । अगर 18 से 60 वर्ष तक की आयु में कोई किसान मर जाता है, तो ममता बनर्जी उनके लिए दो लाख रुपये देती हैं । ममता बनर्जी जी की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसमें एक लखी भण्डार स्कीम है । दो-चार स्टेट्स ने उस स्कीम को फॉलो भी किया है । अगर यह स्कीम सेंटर

भी फॉलो करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई ईगो नहीं है, इसे लागू कर सकते हैं ।

Fertilizers are crucial for farmers, because it covers all the economic aspects, and the wisdom of the Government not only cuts fertilizer subsidy in the Budget but also remains insensitive to the supply of fertilizer. For example, West Bengal used to get a specific grade of NPK to the tune of 4.50 lakh million tonnes in 2021. The pathetic fact is that, in 2024-25, the quantity of supply of the same grade was reduced to 1.33 lakh million tonnes. The mentioned cut in supply by the Union Government thus compelled the farmers of West Bengal to buy high-priced phosphate and potash fertilizers.

जनवरी, 2025 में 1.07 लाख एम.टी. सप्लाई करने की बात थी । जनवरी चला गया, फरवरी चला गया और अब मार्च भी जाने वाला है, लेकिन अभी तक वहां पर नहीं मिला । अभी तक वेस्ट बंगाल में किसान के पास फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा है । बहुत से किसान हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भर से बार्डर में पड़े हुए थे । उनको डे बिफोर यस्टर्डे वहां से निकाल दिया गया । जो आंदोलन करते हैं, उनको पता है कि उन्हें हक मिले या न मिले, लाठी-डंडे की मार तो मिलेगी ।

फिर भी वे लोग रास्ते पर बैठे हैं, क्योंकि उनकी जिन्दगी का सवाल होता है । जिनके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर होती है, जब वह एसी रूम में बैठकर खाना खाते हैं, शायद कभी न कभी उस किसान की बात याद करते हैं, जो रास्ते में पड़ा है, जो फैमिली नहीं है । ? (व्यवधान) मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक ही बोलने वाली हूं । West Bengal leads in jute production in the country. Unfortunately, jute industry is facing challenges due to the policy of Government of India in decreasing the demand of jute bags and going for eco-friendly packaging material. The Budget has not produced relaxation to jute production and scheme for assured price to farmers. Lakhs of families are dependent on jute industry and stand as a perfect example of how the policy-making of the Union Government is apathetic with the farmers. West Bengal, India?

s largest jute-producing State, accounts for 70 of the country's 93 jute mills. The Union Government has increased the MSP to Rs.5,650 per quintal from Rs.5,335 but the fact is that due to low demand from purchasers including the Food Corporation of India, the price went as low as Rs.5,000 per quintal last year. The country's production of raw jute has dropped by over 29 per cent in the past decade.

टाइम कम है, हम लोग अपोजिशन में भी हैं । सरकार की गलती के बारे में बोलते हैं, झूठ क्या है, सच क्या है, उसके बारे में भी बोलती हूं, इसलिए टाइम और भी कम हो जाता है । यह भी पता है कि तारीफ करने और वाह वाही करने से टाइम ज्यादा मिल जाता है ।

मैं एक स्टोरी बता कर अपनी बात खत्म करना चाहती हूं । यह स्टोरी नहीं है, एक इंसिडेंट है । हम लोगों के देश की एक रियलिटी है । मैं एक जगह पर गई थी, जगह का नाम नहीं बता रही हूं क्योंकि लोग चीखने चिल्लाने लगेंगे । वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनको देखने से पता चल रहा था कि वे गरीब हैं । किसी के पास शर्ट नहीं है, किसी के पास पैट नहीं है, किसी के पास चप्पल नहीं है । घर को भी देखने से पता चल रहा था कि वे गरीब ही हैं । एक बच्चे के हाथ-पैर में खरोंच थी, स्क्रीन डिजीज जैसा कुछ था । मैंने बोला कि ये क्या हुआ, स्क्रीन डिजीज है, क्या तुम डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि नहीं । उनके लिए डॉक्टर बहुत दूर की बात है । शायद माँ हल्दी वगैरह कुछ लगा देती होगी । मैंने पूछा कि तुम नहाते नहीं हो क्योंकि बच्चे लोग नहाने से भागते हैं । जब मिट्टी में खेलते हैं तो शायद मिट्टी में खेलने से स्क्रीन डिजीज हुई होगी । मैंने फिर से पूछा कि नहाते नहीं हो तो वह बोला कि नहीं । मैंने कहा कि देखा न, इसीलिए ये होता है । मैंने पूछा कि क्यों नहीं नहाते हो उसने बोला कि नहाने के बाद ज्यादा भूख लगती है । सोचिए, अगर नहाएंगे तो ज्यादा भूख लगेगा और भूख लगेगी तो खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वे लोग नहीं नहाते हैं । मैंने बोला था कि जगह का नाम बोलने से चीखने चिल्लाने लगेंगे, यह देश की रियलिटी है । उस टाइम मैं सुन कर चुप हो गई, इसीलिए कि ये बोलने से चीखेंगे । मैं उस वक्त वह बात सुनने के बाद चुप रही, लेकिन मैं यह बात कहूंगी सरकार यह बात सुनने के बाद चुप न रहे, कुछ कहे, कुछ करे । चीखना नहीं, काम करना है । थैंक्यू सर ।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I would like to mention, that as we all know, Agriculture remains the backbone of our India's economy, providing livelihoods to about 70% of the Country's workforce. It is a sad state of affairs, that the agriculture sector that engages 70% of our population only constitutes 17% of our GDP.

While the Centre has introduced several initiatives to support farmers, there are areas where further improvements and focused interventions are necessary without which all the slogans that our Prime Minister has provided will remain on paper only.

I would like to point out a few major concerns.

The farming budget for 2025-26 has dropped to ₹1,37,757 crore, down 2.5% from last year's revised estimate. Three giant schemes namely PM-Kisan, Modified Interest Subvention Scheme, and Crop Insurance take up 77% of all the money. However, another major worry is the fact that, the Crop Insurance plan has been cut by 23%, leaving farmers more at risk when crops fail.

Agricultural growth remains very erratic and is projected at 3.8% for 2024-25, which is still below the overall economic growth rate of the country.

If the agriculture sector does not grow then Sir, we cannot expect the Economy to grow also.

The Farmers in our country still face many problems: small plots of land that are hard to farm efficiently, water systems that waste too much, and not enough modern equipment to help with the work.

Despite the Central Government's push for the electronic National Agriculture Market (e-NAM), only 1,361 mandis (markets) have been integrated into the system nationwide. This limited coverage means

thousands of farmers in India are still dependent on local traders, often receiving prices below market value.

The procurement situation shows significant gaps: while 43% of paddy and 25% of wheat were purchased at Minimum Support Price (MSP) in 2023-24, procurement of pulses, oilseeds and other crops remains extremely low. This creates particular challenges for farmers who grow diverse crops. Especially in my State of Kerala where there are cash crops the farmers are receiving very low prices for cardamom, rubber, pepper, cloves, tea, coffee etc.

In this regard, I request the Government, to extend MSP to all the cash crops mentioned above, Additionally, we also need a legally binding MSP framework to ensure farmers receive fair prices for their produce, providing much-needed stability to the agricultural sector in the state. The LDF government always claims that it is the champion of the farmers. They will fight against the farm laws and unfair policies of the Central Government. However, in Kottayam district, paddy was not lifted by the Government for more than 2 weeks. Usually this process is done in just 2 or 3 days. In Thiruvarpur paddy field of 9000 Padasekharam, The harvested paddy is spread all over the field. And it has been lying there for 17 days. Every day, the farmers have to manually turn the heaped-up paddy. Meantime, the mill owners kept up the pressure on the farmers, demanding a 'procurement discount'. They refused to lift the paddy without the discount. In the meantime twice it rained, The moisture content of the paddy stockpile increased, allowing the mill owners to demand a greater discount. Finally after 17 days, that too after two days of consecutive rains, the farmers were forced to relent and they were forced to let the millers take their paddy with a discount. The State Government , shamelessly abandoned the cause of the farmers and

openly sided with the mill owners. I request the Central Government to seriously consider the plight of the farmers in Kerala.

Post-harvest losses drain ₹1.5 lakh crore yearly from farmers' incomes, with fruits (₹29,545 crore) and vegetables (₹27,459 crore) suffering the most. Despite the "World's Largest Grain Storage Plan," India faces a critical shortage requiring 6.1 crore tonnes of cold storage but having only 3.9 crore tonnes available. The Government should take urgent measures to increase the storage capacity available.

While the PM-KISAN scheme retains an allocation of ₹63,500 crore in the union budget, there is no increase despite rising inflation and production costs. The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme currently provides ₹6,000 annually to farmers which has remained unchanged over the years. Given the rising cultivation costs, this amount is insufficient for small and marginal farmers. We suggest that the Ministry increase financial support to a significant amount under PM-KISAN. With these suggestions I conclude. Thank You Sir.

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद) : विश्वनेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानसेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने पहले दिन से ही किसानों के समृद्धि हेतु प्रतिबद्ध एवं उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए संवेदनशील रही है और उसके सुखद परिणाम भी दिखायी देते हैं जिससे किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है ।

केंद्रीय बजट 2025-26 में 'प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन' को एक बड़ा बढ़ावा मिला क्योंकि इसके आवंटन में 516 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । यह मिशन किसानों को भविष्य में कृषि को लाभकारी बनाने में क्रांतिकारी कदम होने वाला है ऐसा मुझे विश्वास है । इसका उद्देश्य 0.75 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती शुरू करना है, जिससे 10 मिलियन किसानों को लाभ मिलेगा, तथा रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है ।

घोषित नए मिशनों के अलावा जिन अन्य योजनाओं के आवंटन में वृद्धि हुई, उनमें दो केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं - कृषिओन्नति योजना, जिसका उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर लाभ बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है, जिसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जो कृषि-उद्यमिता, नवाचारों और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने सहित पूर्व और पश्चात की फसल बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, इसमें 41 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई ।

नमो ड्रोन दीदी योजना, जिसका उद्देश्य 2024-25 और 2025-2026 के बीच 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि उद्देश्य (तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन प्रदान करना है, का आवंटन 2024-25 के संशोधित अनुमान 250 करोड़ रुपये से बढ़कर 676.85 करोड़ रुपये हो गया ।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बहुप्रतीक्षित बजट भाषण में कृषि सुर्खियों में थी, जिसके दौरान उन्होंने देश को "दुनिया की खाद्य टोकरी" बनाने में किसानों की भूमिका को मान्यता देते हुए, इस क्षेत्र पर केंद्रित कम से कम नौ नए मिशन या कार्यक्रमों की घोषणा की । इसके लिए वो बधाई की हकदार हैं।

माननीय वित्तमंत्री सीतारमण ने कृषि को विकास का "पहला इंजन" बताया और अपने भाषण की शुरुआत इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करके की । इन घोषणाओं को लाखों लोगों की आजीविका से इस क्षेत्र के अटूट संबंध की स्वीकृति के रूप में देखा गया । वास्तव में, कृषि उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जिसने स्थिर वृद्धि प्रदर्शित की है, जिसने भारत के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

माननीय वित्तमंत्री सीतारमण ने नौ कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाये गये हैं ।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों में मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा । इस कार्यक्रम से 17 मिलियन किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है ।

'दालों में आत्मनिर्भरता के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ छह साल का मिशन, जिसमें तूर (कबूतर मटर), उड़द (काला चना) और मसूर (लाल मसूर) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा । इस योजना के तहत, नेफेड (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जैसी केंद्रीय एजेंसियां अगले चार वर्षों में इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण करने वाले और समझौते करने वाले किसानों से "जितनी पेशकश की जाएगी" उतनी दालें खरीदेंगी ।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में इसे लॉन्च किया जाएगा । मिशन को 2025-26 के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

कपास उत्पादकता के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक पांच वर्षीय मिशन, जो अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास किस्मों को बढ़ावा देते हुए कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा ।

उच्च उपज देने वाले बीजों पर जुलाई 2024 से जारी 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता, विकास और प्रसार को लक्षित करेगा । इसे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

बिहार में मखानाबोर्ड मखाना (फॉक्सनट) के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी । वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा, जिन्हें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में संगठित किया जाएगा ।

'ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम': यह पहल राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू की जाएगी ताकि कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में बेरोजगारी को दूर किया जा सके । यह ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा ।

मत्स्य पालन हेतु माननीय वित्तमंत्री सीतारमण ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा पेश करने की सरकार की योजना की घोषणा की, जिसमें अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

इस संबंध में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2025-26 के लिए 64 प्रतिशत की पर्याप्त बजटीय वृद्धि प्राप्त हुई ।

असम में यूरिया की आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 1.27 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा ।

महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गाव, गरीब किसान, कृषि पर माननीय मोदी साहेब का विशेष ध्यान सरकार के शुरुआती साल से ही रहा है । हमारे प्रधानसेवक आदरणीय मोदी साहेब चाहते हैं कि किसान और कृषि विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये इसलिए उस दिशा में सरकार कार्य कर रही अब कृषि एवं किसान अब अपने पुराने वैभव एवं आत्मविश्वास को प्राप्त कर रहे हैं इस संतोष के लिए मुझे मोदी सरकार पर गर्व है ।

श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व) : लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने शुरुआत से ही किसानों के समृद्धि हेतु प्रतिबद्ध एवं उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए संवेदनशील रही है और उसके सुखद परिणाम भी दिखायी देते हैं ।

केंद्रीय बजट 2025-26 में 'प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन' को एक बड़ा बढ़ावा मिला क्योंकि इसके आवंटन में 516 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई 2024-25 के संशोधित अनुमान (आरई) में 100 करोड़ रुपये से बजट 2025-26 में 616.01 करोड़ रुपये हो गया । केंद्र सरकार ने 25 नवंबर, 2024 को मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और देश भर में किसानों की रासायनिक इनपुट पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) शुरू किया था । यह मिशन किसानों को

भविष्य में कृषि को लाभकारी बनाने में क्रांतिकारी कदम होने वाला है ऐसा मुझे विश्वास है ।

एनएमएनएफ को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएंडएफडब्ल्यू), केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएंडएफडब्ल्यू) के तहत एक स्वतंत्र, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें तीन वर्षों की अवधि के लिए 2,481 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार से 1,584 करोड़ रुपये और राज्यों से 897 करोड़ रुपये) का परिव्यय था ।

इसका उद्देश्य 0.75 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती शुरू करना है, जिससे 10 मिलियन किसानों को लाभ मिलेगा, तथा रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है ।

घोषित नए मिशनों के अलावा जिन अन्य योजनाओं के आवंटन में वृद्धि हुई, उनमें दो केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं कृषिओन्नति योजना, जिसका उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर लाभ बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है, जिसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जो कृषि-उद्यमिता, नवाचारों और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने सहित पूर्व और पश्चात की फसल बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, इसमें 41 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई ।

नमो ड्रोन दीदी योजना, जिसका उद्देश्य 2024-25 और 2025-2026 के बीच 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि उद्देश्य (तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन प्रदान करना है, का आवंटन 2024-25 के संशोधित अनुमान 250 करोड़ रुपये से बढ़कर 676.85 करोड़ रुपये हो गया ।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बहुप्रतीक्षित बजट भाषण में कृषि सुर्खियों में थी, जिसके दौरान उन्होंने देश को "दुनिया की खाद्य टोकरी" बनाने में किसानों की भूमिका को मान्यता देते हुए, इस क्षेत्र पर केंद्रित कम से कम नौ नए मिशन या कार्यक्रमों की घोषणा की । इसके लिए वो बधाई की हकदार हैं।

माननीय वित्तमंत्री सीतारमण ने कृषि को विकास का "पहला इंजन" बताया और अपने भाषण की शुरुआत इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करके की, जो लंबे समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है । इन घोषणाओं को

लाखों लोगों की आजीविका से इस क्षेत्र के अटूट संबंध की स्वीकृति के रूप में देखा गया । वास्तव में, कृषि उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जिसने स्थिर वृद्धि प्रदर्शित की है, जिसने भारत के आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

माननीय वित्तमंत्री सीतारमण ने नौ कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे कृषि विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए बनाये गये हैं:

'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों में मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा । इस कार्यक्रम से 17 मिलियन किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है । हालाँकि, बजट दस्तावेज़ से यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि इस योजना के लिए कितना धन आवंटित किया जाएगा ।

'दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन' वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ छह साल का, जिसमें तूर (कबूतर मटर), उड़द (काला चना) और मसूर (लाल मसूर) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा । इस योजना के तहत, नेफेड (राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जैसी केंद्रीय एजेंसियां अगले चार वर्षों में इन एजेंसियों के साथ पंजीकरण करने वाले और समझौते करने वाले किसानों से "जितनी पेशकश की जाएगी" उतनी दालें खरीदेंगी ।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में इसे लॉन्च किया जाएगा । मिशन को 2025-26 के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

कपास उत्पादकता के लिए मिशन: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक पांच वर्षीय मिशन, जो अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास किस्मों को बढ़ावा देते हुए कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा ।

उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन: यह मिशन जुलाई 2024 से जारी 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीज किस्मों की

व्यावसायिक उपलब्धता, विकास और प्रसार को लक्षित करेगा। इसे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बिहार में मखानाबोर्ड: मखाना (फॉक्सनट) के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 100

करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा, जिन्हें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में संगठित किया जाएगा।

'ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम: यह पहल राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू की जाएगी ताकि कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में बेरोजगारी को दूर किया जा सके। यह ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा

सीतारमण ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा पेश करने की सरकार की योजना की घोषणा की, जिसमें अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस संबंध में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2025-26 के लिए 64 प्रतिशत की पर्याप्त बजटीय वृद्धि प्राप्त हुई।

यूरिया की आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 1.27 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कृषि और किसान विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और कृषि एवं किसान जो पिछली सरकारों के द्वारा अपेक्षित ध्यान न देने के कारण दुर्दशा की ओर चले गए थे अब पुनः गौरव प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिमा) : बिहार भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण हेतु विभिन्न

योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना है।

बिहार की जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और भरपूर जल संसाधन इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, दालें, गन्ना, आलू और सब्जियों की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त, बागवानी और डेयरी उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहे हैं।

बिहार में कृषि की स्थिति इस प्रकार है:- छोटे जोत वाले किसान बिहार में ज्यादातर किसान छोटे एवं सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। सिंचाई सुविधा - गंगा, कोसी, गंडक और सोन जैसी नदियों के बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए अब भी संघर्ष करना पड़ता है। उच्च श्रमशक्ति-बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या अधिक है, लेकिन उनका कुशलता स्तर कम है। कृषि विविधीकरण - किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ नकदी फसलें और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

बिहार सरकार की प्रमुख कृषि कल्याण योजनाएँ इस प्रकार हैं:-

मुख्यमंत्री कृषि इनपुट अनुदान योजना

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
प्रति हेक्टेयर ₹13,500 तक का अनुदान दिया जाता है।

जल-जीवन-हरियाली योजना

जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह योजना लागू की गई है। किसानों को जल संचयन तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

यह योजना फसल बीमा का एक नया रूप है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सीधे मुआवजा दिया जाता है।

जैविक खेती प्रोत्साहन योजना

किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए सब्सिडी और तकनीकी सहायता दी जाती है ।

इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कृषि उत्पादों का मूल्य अधिक होता है ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

केंद्र सरकार कार की इस योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता राशि दी जाती है ।

बिहार में लाखों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है ।

कृषि में नवाचार और नई तकनीकों का उपयोग

बिहार सरकार किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है ।

ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर तकनीक जल की बचत करने और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए ।

कृषि यंत्रीकरण - ट्रैक्टर, थ्रेसर, पंप सेट आदि पर सब्सिडी दी जा रही है ।

डिजिटल कृषि - किसानों को मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से मौसम, बीज, खाद, और बाजार के बारे में जानकारी दी जा रही है ।

बिहार में कृषि चुनौतियाँ और उनके समाधान इस प्रकार हैं:-

चुनौतियाँ

बाढ़ और सूखा - बिहार का बड़ा भाग हर साल बाढ़ और सूखे से प्रभावित होता है ।

भूमि की कमी - अधिक जनसंख्या के कारण भूमि जोत छोटी होती जा रही है ।

बिचौलियों की समस्या- किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता ।

प्रसंस्करण उद्योग की कमी फसलों के उचित भंडारण और मूल्य संवर्धन की कमी है ।

समाधान

जल प्रबंधन पर ध्यान वर्षा जल संचयन और नहर प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता ।

कृषि सहकारिता - छोटे किसानों को संगठित कर सहकारी खेती को बढ़ावा देना ।

सीधे बाजार से जोड़ना- किसानों को ई-नाम (e-NAM) और कृषि बाजारों से जोड़ना ।

कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा - फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधा विकसित करना ।

बिहार में कृषि कल्याण हेतु सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनसे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है । हालाँकि, अभी भी कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं । इन समस्याओं के समाधान के लिए जल प्रबंधन, कृषि यंत्रीकरण, डिजिटल तकनीक और सहकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है । यदि सही नीतियों और संसाधनों का सही उपयोग किया जाए, तो बिहार का कृषि क्षेत्र और भी समृद्ध हो सकता है ।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2025 के बजट में बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं । इन घोषणाओं का उद्देश्य राज्य के कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है । निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया गया है:

बिहार में मखाना (Foxnut) उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है । यह बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देगा । इससे किसानों को संगठित किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा ।

यद्यपि मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि बोर्ड की नीतियाँ और कार्यक्रम जमीनी स्तर पर प्रभावी हों । इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि अन्य फसलों के किसानों को भी समान समर्थन मिले ।

मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी ।

इस परियोजना की सफलता निर्भर करेगी इसके समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन पर । पिछले अनुभवों से पता चलता है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ अक्सर देरी और लागत वृद्धि का सामना करती हैं । इसलिए, परियोजना की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा ।

बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना की जाएगी, जो खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता को बढ़ावा देगा ।

संस्थान की स्थापना से कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन में सहायता मिलेगी, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय किसानों और युवाओं को

इस संस्थान से सीधे लाभ मिले । इसके लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईआईटी पटना के बुनियादी ढाँचे का विस्तार, जिसमें छात्रावास सुविधाएँ शामिल हैं, की योजना बनाई गई है ।

आईआईटी पटना का विस्तार शिक्षा और शोध के क्षेत्र में लाभकारी होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस विस्तार का सीधा लाभराज्य के कृषि और ग्रामीण विकास को मिले । इसके लिए कृषि अनुसंधान और नवाचार पर विशेष ध्यान देना होगा ।

बजट 2025 में बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाएँ स्वागत योग्य हैं, लेकिन उनकी सफलता उनके प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी पर निर्भर करेगी । यह आवश्यक है कि इन योजनाओं का लाभ सभी किसानों तक पहुँचे और राज्य के समग्र कृषि विकास में योगदान दे ।

बिहार सरकार किसानों, पशुपालकों और कृषि समुदाय के अन्य सदस्यों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चला रही है । इन पहलों का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, पशुपालन को प्रोत्साहित करना और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है । निम्नलिखित प्रमुख योजनाएँ और उनके लाभ इस प्रकार हैं:

पशु शेड योजना 2025 के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों और पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए शेड निर्माण हेतु ₹75,000 से ₹1,60,000 तक की वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है । यह सहायता गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पालन करने वालों के लिए उपलब्ध है ।

योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड सख्त हैं, जिससे सभी इच्छुक पशुपालक इसका लाभ नहीं ले पाते ।

राज्य के सभी 534 प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की गई है, जिससे पशुपालकों को डोर-स्टेप पशु चिकित्सा सेवाएँ मिल सकें ।

दूरस्थ क्षेत्रों में इन सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक चुनौती है ।

पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार पशु बीमा पर 75% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे पशुधन की अप्रत्याशित हानि की स्थिति में उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके ।

बीमा प्रक्रिया की जटिलता और जागरूकता की कमी के कारण कई पशुपालक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते ।

मेथी और धनिया की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रति हेक्टेयर लगभग ₹30,000 तक की यूनिट लागत सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे मसाला उत्पादन में वृद्धि हो सके ।

यह सब्सिडी केवल मेथी और धनिया की खेती तक सीमित है; अन्य मसाला फसलों के लिए ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं ।

अरहर, मूंग, उड़द जैसी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके ।

MSP पर खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता की कमी के कारण कई किसान इसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते ।

सभी अनुमंडलों और प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की योजना है, जिससे किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी ।

इन सुविधाओं का समय पर निर्माण और संचालन सुनिश्चित करना आवश्यक है; अन्यथा, किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा ।

बिहार सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों के लिए कई लाभकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, लेकिन इनका प्रभावी कार्यान्वयन और सभी लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम, सरल प्रक्रिया और निगरानी तंत्र की आवश्यकता है, ताकि कृषि समुदाय के सभी सदस्य इन योजनाओं का पूर्ण लाभ उठा सकें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

योग्यता और शर्तें:

छोटे और सीमांत किसान इस योजना के पात्र हैं।

किसानों के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।

आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी और बड़े किसान इस योजना के लाभ से वंचित रहते हैं।

आलोचनाएँ और सीमाएँ

₹6,000 प्रति वर्ष की राशि बहुत कम है और महंगाई के दौर में इससे किसानों को कोई बड़ा आर्थिक संबल नहीं मिल पाता।

केवल छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया गया है, जबकि बड़े किसानों को भी समर्थन की आवश्यकता होती है।

कई बार तकनीकी कारणों से या दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता।

जो किसान कृषि भूमि के मालिक नहीं हैं, लेकिन खेती करते हैं, उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलता।

यह योजना केवल नकद सहायता प्रदान करती है, जबकि किसानों को सिंचाई, बीज, खाद और बाजार तक पहुँच जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है।

PM-KISAN योजना किसानों के लिए एक अच्छी पहल है, लेकिन इसकी राशि अपर्याप्त है और कई किसानों तक इसका लाभ सही तरीके से नहीं पहुँच रहा । इसे और प्रभावी बनाने के लिए भुगतान प्रक्रिया में सुधार, योजना का विस्तार और सहायता राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता है ।

बिहार में किसानों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार, समाज और निजी क्षेत्र को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है । निम्नलिखित प्रमुख उपाय अपनाए जा सकते हैं:

नहरों और तालाबों का पुनरुद्धार बिहार में गंडक, कोसी और गंगा जैसी नदियाँ हैं, लेकिन सिंचाई के लिए अभी भी अधिकतर किसान वर्षा पर निर्भर हैं । बेहतर नहर प्रणाली और जल संरक्षण परियोजनाओं की जरूरत है ।

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा कम पानी में अधिक उत्पादन के लिए इन आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाना आवश्यक है ।

केवल पारंपरिक फसलों (धान, गेहूं) पर निर्भर रहने के बजाय, सब्जी, मसाले (मेथी, धनिया), फल (लीची, आम) और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना ।

कृषि के साथ-साथ दूध उत्पादन और मछली पालन जैसी वैकल्पिक आय स्रोतों को बढ़ावा देना ।

रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती अपनाने से उत्पादों की बाजार में अधिक कीमत मिल सकती है ।

बिहार में किसानों को MSP का पूरा लाभ नहीं मिल पाता । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले ।

बिहार में बड़े पैमाने पर आलू, टमाटर और मखाना जैसे उत्पाद होते हैं । कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित करने से किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं ।

किसानों को ऑनलाइन कृषि बाजार (e-NAM) से जोड़ने से उन्हें देशभर में बेहतर कीमत मिल सकती है ।

किसानों को नई तकनीकों, उन्नत बीजों और प्राकृतिक खेती के तरीकों की जानकारी देने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिए ।

मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन के माध्यम से किसानों को मौसम, बाजार मूल्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए ।

किसानों को उचित ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाए और संकटग्रस्त किसानों के कर्ज माफ किए जाएँ ।

बिहार में बाढ़ और सूखे की समस्या रहती है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं । ऐसे में फसल बीमा को सरल और पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसानों को समय पर मुआवजा मिले ।

गाँवों से बाजार तक अच्छी सड़कें बनानी चाहिए ताकि किसान अपनी उपज आसानी से बेच सकें ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 24 घंटे बिजली और पर्याप्त जल आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए ।

महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार और कृषि में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना ।

खेती में ड्रोन, सौर ऊर्जा, ऑर्गेनिक फार्मिंग और अन्य तकनीकों को अपनाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए ।

बिहार में किसानों का जीवन सुधारने के लिए कृषि अवसंरचना, आधुनिक तकनीकों, सिंचाई व्यवस्था, उचित विपणन और वित्तीय सहायता पर ध्यान देने की जरूरत है । सरकार के साथ-साथ निजी कंपनियों और किसानों की भागीदारी से कृषि को लाभदायक बनाया जा सकता है, जिससे किसानों का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे ।

किसान को भगवान का दर्जा मिलना चाहिए । बिहार में छोटे और बंटे हुए खेत- 91% किसान लघु किसान हैं, जिससे आधुनिक खेती करना मुश्किल होता है । समाधान के रूप में, सहकारी खेती और भूमि समेकन को बढ़ावा दिया जा सकता है ।

? बार-बार आने वाली बाढ़ - बिहार के उत्तरी भाग का 76% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, जिससे हर साल किसानों को भारी नुकसान होता है । इसका समाधान मजबूत तटबंध और जल निकासी प्रणाली में सुधार करना है ।

?अकाल की समस्या - दक्षिण बिहार के कई जिलों में वर्षा की अनिश्चितता के कारण सूखा पड़ता है । इसका समाधान सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना और जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना है ।

?सब्जि में देरी और भ्रष्टाचार किसानों को समय पर खाद, बीज और बिजली की सब्जि नहीं मिलती, जिससे वे वित्तीय संकट में आ जाते हैं । समाधान के लिए सब्जि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) किया जाना चाहिए ।

?कर्ज माफी और ऋण की समस्या ? किसान साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं, और सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी स्थायी समाधान नहीं है । कम ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का लाभ और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता है ।

? सिंचाई की कमी - बिहार के सिर्फ 61% खेतों में सिंचाई की सुविधा है । समाधान के रूप में, नहरों का विस्तार, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा सकता है ।

?बिहार की उपजाऊ मिट्टी का सही उपयोग नहीं -बिहार की मिट्टी गंगा के जलोढ़ मैदान की वजह से अत्यधिक उपजाऊ है, लेकिन इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जाता । जैविक खेती और नकदी फसलों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

?खेती में आधुनिक मशीनों की कमी ? बिहार में केवल 35% किसान आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग कर पाते हैं । समाधान के लिए कृषि उपकरण किराए पर देने की सुविधाएं और सरकारी अनुदान जरूरी हैं ।

?बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलना - किसान बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का सही लाभ नहीं मिलता । एफपीओ (FPO) को बढ़ावा देकर और MSP को सख्ती से लागू करके इसका समाधान किया जा सकता है ।

?नकदी फसलों की कम खेती - बिहार में गन्ना, मक्का, केला और मखाना की जबरदस्त संभावना है, लेकिन संगठित उत्पादन की कमी है । सरकार को अनुबंध खेती

(Contract Farming) और नकदी फसलों के लिए सब्सिडी देनी चाहिए ।

भंडारण सुविधाओं की कमी - राज्य में 30-40% फल-सब्जियां खराब हो जाती हैं । इसका समाधान कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक गोदामों की स्थापना है ।

?खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अभाव ? बिहार में लीची, केला, मक्का और मखाना जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, लेकिन इन्हें प्रोसेस करने के लिए उद्योग नहीं हैं । इससे किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता । सरकार को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में निवेश बढ़ाना चाहिए ।

?बिहार की सर्वश्रेष्ठ फसलें - मक्का और मखाना

?मक्का ? बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है । कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के मक्का की सबसे ज्यादा मांग है । मक्का आधारित उद्योगों (कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

?मखाना - बिहार भारत के 80% मखाने का उत्पादन करता है । कटिहा, सहरसा, सुपौला और पूर्णिया में उच्च गुणवत्ता का मखाना उगाया जाता है । इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देना चाहिए ।

? कृषि में आधुनिक तकनीक की कमी - किसान पुरानी पद्धतियों पर निर्भर हैं, जिससे उत्पादन कम होता है । डिजिटल ट्रेनिंग और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जरूरी हैं ।

? कृषि ऋण की अनुपलब्धता - बैंक से कर्ज लेने में किसान कठिनाइयों का सामना करते हैं और साहूकारों पर निर्भर रहते हैं । किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को अधिक सुलभ बनाना चाहिए ।

? फसल बीमारियों और कीटों का हमला ? धान और गेहूं की फसलों पर कीट और बीमारियों का हमला होता है । सरकार को सस्ते दामों पर जैविक

और रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध कराने चाहिए ।

? जलवायु परिवर्तन का असर - अनियमित बारिश और बढ़ते तापमान से कृषि प्रभावित हो रही है । जलवायु-रोधी फसलों और मिश्रित खेती को बढ़ावा देना चाहिए ।

?खराब परिवहन सुविधा - गांवों तक उचित सड़कें नहीं होने के कारण किसान अपनी फसल बाजार तक नहीं पहुंचा पाते । ग्रामीण सड़कों के विकास में निवेश किया जाना चाहिए ।

?बिचौलियों की लूट - किसान अपनी उपज का सिर्फ 40%-50% पैसा ही कमा पाते हैं और बाकी मुनाफा बिचौलियों को चला जाता है । ई-नाम (e-NAM) ऑनलाइन मार्केट और किसान बाजार जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना जरूरी है ।

?फसल बीमा की समस्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई किसान (PMFBY) का लाभ नहीं ले पाते, या बीमा राशि समय पर नहीं मिलती । यह जरूरी है कि बीमा भुगतान में पारदर्शिता लाई जाए ।

?भूजल स्तर में गिरावट ? अधिक बोरवेल और जल दोहन के कारण भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है । ड्रिप इरिगेशन और वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया जाना चाहिए ।

? फसल विविधता की कमी - किसान सिर्फ धान और गेहूं उगाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है । दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

?सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं

कई बार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), MSP और KCC जैसी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिलता । इसके लिए रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाना चाहिए ।

? अनुसंधान एवं विकास (R&D) की कमी - बिहार में कृषि नवाचार केंद्रों की जरूरत है । सरकार को नए कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए ।

? मजदूरों की कमी और पलायन - बिहार से लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई और पंजाब चले जाते हैं, जिससे खेती के लिए श्रमिक नहीं मिलते । इसके समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ।

? सभी प्रखण्डों में, एक कोल्डस्टोन की स्थापना एशिया की सबसे बंद बड़ी माडी गुलावना । पुर्णियाँ को आधुनिकरण किया जाये ।

MSP को लागू किया जाए । कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ।

?खाद्य बीज को कालाबाजारियों से बचाया जाए, किसानों के फसल को बिचौलिया और दलालों से बचाया जाए ।

किसानों को बिजली मुफ्त दिया जाए ।

?किसानों को सिंचाई मुफ्त किया जाए किसानों के तरक्की के लिए सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए ।

?पंजाब में 700 से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया जाए ।

?पूर्णियां में एग्रीकल्चर महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था की जाए ।

?बेगुसराय में जो सिमांचल, कोशी, मिथनाचल अंग प्रदेश के किसानों के मक्का किसानों के लिए ?मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केन्द्र बिहार में स्थापित कर दिया जाए ।

?बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) की स्थापना पूर्णियां सिमांचल में किया जाए । मखाना एवं मक्का का दस फैक्ट्री खोला जाए । मखाना का बाजार को सिमांचल में बढ़ावा दिया जाए ।

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): Sir, I am proud to be a fifth-generation farmer. I, on my behalf and on behalf of my Party, rise to oppose Demand No 1 and Demand No. 2 pertaining to the Ministry of Agriculture.

Due to paucity of time, I will try to put my objections in a nutshell. Many have lost their lives in the year 2020, braving the hot sun and the cold at the border of Delhi. I expected something from this Government to be done. The Government also has made promises. I oppose this Demand because the Grant given to this Ministry is not meant to fix the legally guaranteed Minimum Support Price for crops, which has been the dream of 70 crore agrarian population of this country. As recommended by the much-respected National Commission for Farmers, the formula of C2 plus 50 per cent for all crops, is missing. The second foremost objection is this. This does not speak a word about the waiver of loan for

almost 18 crore farmers who are debt-trapped in this poor agrarian economy. Also, what about the much-awaited comprehensive insurance scheme? The scheme which we have now does not even compensate the cost of the seeds, leave alone the other inputs to the agriculture operation.

More than 200 people have died. This Government has made several promises to end the strike. None of them has been fulfilled, not even attempted to be fulfilled. Even the Standing Committee on Agriculture, which is supposed to be the mini-Parliament, where the ruling Treasury Benches MPs and the Opposition MPs are there, have unanimously given a report that this MSP had to be given to end the lakhs and lakhs of farmers' suicide in this country, the menace which has been continuing for almost ten years. Sir, 1,11,000 farmers have ended their life because of misery and the debt trap that they have been undergoing. The Committee gave a report with regard to waiver of loan. More than that, the famous Dr. M. S. Swaminathan's Committee, National Commission for Farmers, which had given a holistic approach to give a boost to this economy, agriculture economy, has been put in cold storage. Farmers are not given proper cold storages. Rather, this Government is putting all the Committee reports, including the Standing Committee report into cold storages because the rural voters have not voted for this regime. Is that their fault? Sir, whereas if you look at the corporate loans that have been waived, how this regime is pro-corporate is evidenced by an answer to a Question by none other than the hon. Finance Minister.

Sir, in 2022-23, Rs. 2,16,324 crore have been written off. In 2023-24, Rs. 1,70,270 crore and in 2014-15, Rs. 58,786 crore have been written off. In 2018-19, almost 2,36,265 crore have been written off for a very small group of corporates in this country, which is deplorable. If you look

at the amount of the public money that has been written off, it was almost Rs. 16,35,000 crore for the corporate sector, whereas 70 crore of this country's population belongs to the farming community. What we eat like rice, roti, is the result of blood and sweat of our farmers. Their long-pending demand has not been taken up. Look at the contrast. After the assumption of our Dravidian model of Government in Tamil Nadu, our dynamic leader, hon. Chief Minister Shri M. K. Stalin, has waived farmers' loans to the tune of nearly Rs. 12,110 crore, benefiting 16.5 lakh farmers.

15.00 hrs

He almost disbursed crop loans to the tune of Rs.54,800 crore, half of your Budget, to almost 67.81 lakh farmers of the State. The interest subvention is zero per cent. Compared to the Centre, it is three per cent where the farmers have to sell out. At the same time, in order to meet the short-term agriculture loan also, crop loan to the tune of Rs.17,000 crore will be provided this year alone in the State of Tamil Nadu. The capital loan for livestock is almost Rs.7,000 crore to 12.24 lakh farmers who have been advanced with the monumental livestock loan. With all these measures, now Tamil Nadu stands first in the poverty alleviation programme among all the States compared to the other States in the country because we have a separate budget for agriculture, which no other State has got. Therefore, this year alone, we have given about two lakh free pump sets, which no other State has done. I am raising all these issues because the Central Government may take a cue and follow the Dravidian Model. That would benefit the 60-crore farmer population.

The Finance Minister in the Budget speech had categorically said that a key driver for growth and Viskit Bharat, the first engine of growth, is the agriculture sector. What you have allotted is a hypocrisy. Out of

an enormous budget of Rs.56.75 lakh crore, you have allotted a pittance of Rs.1.77 lakh crore, which is almost 2.07 per cent compared to the revised estimate of 2014-15. Your Viksit Bharat scheme would derail. The first engine would derail if you look at the agrarian economy in this fashion. Therefore, what you utter that this is the first engine of growth for attaining Viksit Bharat in 2047 is meaningless. Even the Fertilizer Department had reduced the allocation from Rs.1.83 lakh to 1.56 lakh crore. Almost Rs.26,500 crore is missing, which will have a very bad impact on the fertilizer subsidy. In agriculture, what is needed is capital investment, which is absolutely neglected by this Government. If you take the statistics from 2020-21, it is completely coming down from 4.83 per cent to three per cent this year. If there is no capital expenditure, how do you think the Finance Minister or the Agriculture Minister depicts that agriculture is the first engine of growth for obtaining Viksit Bharat? For a country of 70 crore farmers, if this is the allocation, it is deplorable.

This House is well aware of the fact that India was dependent on PL 480 for importing wheat from the United States of America. Thanks to the Green Revolution brought by our forefathers, especially Dr. M.S. Swaminathan and Dr. C. Subramaniam who hail from our State. This Government is trying to reverse the trend that was set earlier where we absolutely stopped importing wheat from the United States of America. Now, a very alarming situation is there that the Government would allow duty-free import of American agriculture and dairy products. Even the Commerce Minister has gone on record saying in the Press that they are going to allow, and they have given a nod to duty-free import of American foodgrains and dairy products. The President of the United States, Trump has gone on record that India has agreed to the conditions

imposed by the United States of America. Mexico, China and even the European countries are resisting this. We have become spineless.

Sir, this will absolutely give a death knell to our farmers. There will be a huge dumping when we allow duty free imports. There is going to be a massive dumping. Therefore, the Government and the hon. Prime Minister should revisit it because this will completely wipe out the first engine of the growth to achieve the Viksit Bharat.

Sir, agriculture is a State subject. Therefore, this Government should allow the State to frame its policies, and a centralised policy and planning should not be thrust upon because farming differs from size to size, State to State, and climate to climate. This is the diverse position of the agrarian farming. We do not understand it, and, therefore, the problem exists. It should be given up at one go.

Sir, now, I come to insurance coverage.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, hon. Member.

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI: Sir, I am the only Member who will speak from my Party.

HON. CHAIRPERSON: You have already taken 10 minutes. Please conclude.

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI: Sir, please give me some more time. This is a State subject.

Sir, even the insurance coverage allocation to agriculture has been reduced in the General Budget. Almost Rs. 3,000 crore has been decreased from the earlier year. In Tamil Nadu, there are 14 lakh farmers holding an area of 34 lakh acres. They have registered in the crop insurance scheme. The State's contribution of Rs. 220 crore has been

paid completely. But the Centre has given a pittance amount of Rs. 70 crore and almost Rs. 140 crore have been pending for months together. This is one demand.

Another demand is this. To strengthen the agriculture infrastructure, we have been demanding this. The cap on the interest subvention is only Rs. 2 crore. What we want is that the cap should be increased to Rs. 20 crore so that larger investments would be there and the private parties would be investing more on agriculture to strengthen our infrastructure.

Sir, another PM's flagship scheme is PMKSY. It is called the Command Area Development and Water Management for irrigated areas. About 27 projects are pending to cover an area of 83,125 hectares with an outlay of Rs. 587 crore. That has been pending since 2018-19. This is the way the Government of India is dealing with the problems of agriculture.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, hon. Member. Please conclude.

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI : Sir, eNAM is very important. The hon. Minister is there. In our State, 157 markets have now been integrated with the eNAM and another 57 to be integrated with it. The problem is that the farmers, who have registered themselves with eNAM, are facing enormous problems because of the server issue. At gate entry itself, the commodities do not appear, and, therefore, they have to wait in a long queue, and the payment becomes a major issue wherever law and order problem is there.

We have been writing to them. Earlier, the eNAM payment was 80 per cent in our State, which has come down to 50 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, Shri Daggumalla Prasada Rao.

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI: Sir, please give me one more minute. ?
(Interruptions) We have been betrayed by the Government of India.

SHRI VIJAYAKUMAR ALIAS VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): I would like to express my views on the Demands and Grants for Agriculture and Farmers' Welfare for the year 2025-26, As we all know, agriculture is the backbone of our great nation. It sustains the livelihood of millions of our citizens, especially in rural areas, and is a key driver of economic growth. It is, therefore, our sacred duty to ensure that our farmers have the necessary tools, resources, and support to thrive.

While we acknowledge the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare's continued efforts in supporting our agricultural sector, we must also recognize the challenges that persist, particularly in our rural heartlands. Farmers across the country continue to face numerous challenges such as the vagaries of climate change, soil degradation, increasing water scarcity, and fluctuating market prices. These issues have only worsened in recent years, and there is an urgent need for focused interventions at both the national and state levels.

The previous year saw the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare being allocated Rs.1,38,564 crore, which accounted for 5% of the central government's total budget. While this allocation is commendable, we must acknowledge that it falls short in addressing the ever-growing needs of the agricultural community, especially with the increasing unpredictability in weather patterns, rising input costs, and infrastructural deficiencies that hinder farmers' productivity.

Kanniyakumari, located at the southernmost tip of India, is blessed with fertile land and a temperate climate ideal for various agricultural activities. The district is primarily dependent on agriculture, with crops like clove, rubber, coconut, banana, and tapioca being extensively grown.

However, despite these advantages, the farmers of Kanniyakumari continue to face numerous challenges that threaten their livelihoods and the sustainable growth of the region's agricultural sector. Some of these persistent challenges include:

Farmers in Kanniyakumari, especially those cultivating crops like clove, face immense difficulties due to inadequate post-harvest processing facilities. The absence of cold storage units and processing centres has led to Significant wastage and low prices for the produce.

Despite the region's potential, the irrigation infrastructure in Kanniyakumari remains underdeveloped. The Neyyar Idathukarai channel, which plays a vital role in floodwater management and irrigation, has not received the necessary investment to be modernized.

Like many parts of the country, Kanniyakumari too is witnessing erratic rainfall patterns and unseasonal weather events, which severely affect the crop yields. Farmers lack adequate training and resources to adapt to climate-resilient practices, thus exacerbating their hardships.

The absence of organized markets and proper linkages between farmers and consumers has led to the exploitation of farmers, with middlemen dictating the prices of produce.

Hon'ble Speaker Sir, the farmers of Kanniyakumari have been waiting for urgent intervention and support from both the state and central governments for many years. There have been several long-pending demands that need to be addressed with utmost priority:

Recently, Kanniyakumari was honoured with the Geo Tag for clove production, a recognition that highlights the uniqueness of this region's clove cultivation, However, despite this significant achievement, the clove

farmers continue to face numerous challenges that hinder their growth and potential.

The clove industry is still underdeveloped in the region, with farmers lacking access to advanced agricultural practices, modern equipment, and proper processing facilities. The absence of a dedicated support system and market linkages has meant that our clove farmers are often unable to capitalize on the full potential of their produce.

Therefore, I request the Hon'ble Minister to allocate Rs.500 crore to develop a Special Scheme for Clove and Spice Production in Kanniyakumari. This scheme should include:

- Training for farmers on advanced agricultural techniques, organic farming, pest control, and post-harvest handling.

- Setting up processing units for cloves and other spices to add value to the produce, enhance employment opportunities, and generate local income.

- Market linkages to help farmers access both national and international markets at fair prices.

Such a scheme will not only uplift the farmers of Kanniyakumari but also position the region as a leader in spice production, particularly cloves, which are in demand worldwide.

The Neyyar Idathukarai Channel, which is responsible for carrying floodwater to agricultural lands, plays a crucial role in floodwater management, irrigation, and preventing soil erosion in Kanniyakumari. However, this channel is in dire need of modernization and restoration. The current state of the channel leads to waterlogging and inefficient

water distribution, which ultimately hampers agriculture, especially during the dry season.

The farmers of Kanniyakumari have long demanded the restoration and development of this channel to improve irrigation facilities and flood control mechanisms. Given its importance for the agricultural productivity of the entire district, I urge the Hon'ble Minister to allocate Rs.500 crore for the development and modernization of the Neyyar Idathukarai channel, which will ensure efficient water management, increased irrigation, and better flood control for the agricultural lands in the region.

Farmers in Kanniyakumari face immense difficulties in accessing markets due to the lack of proper rural road infrastructure. The roads are either poorly maintained or do not connect directly to key market centres, leading to increased transportation costs and post-harvest losses. Furthermore, the absence of cold storage units and warehousing facilities in the region means that perishable goods, such as fruits and vegetables, often go to waste before they can be sold at markets.

I request the Hon'ble Minister to allocate Rs.71,000 crore for the development of rural infrastructure, including:

- Improvement of rural roads and connectivity to ensure that farmers can easily transport their goods to markets.

- Setting up cold storage units and processing centres to minimize post-harvest losses and enhance the value of agricultural produce.

- Establishment of modern warehouses for better storage and marketing facilities for perishable and non-perishable agricultural produce.

These investments will enhance market access, reduce wastage, and improve the incomes of farmers across Kanniyakumari.

Farmers in Kanniyakumari are particularly vulnerable to the impacts of climate change, with erratic weather patterns leading to both droughts and floods, affecting the yield of crops. The shift in weather patterns has made it difficult for farmers to rely on traditional farming methods.

There is an urgent need for the adoption of climate-resilient agricultural practices to safeguard the livelihoods of our farmers. This includes introducing drought-resistant crop varieties, improving water conservation techniques, and providing training on rainwater harvesting, soil conservation, and pest management.

I request the Hon'ble Minister to allocate \$300 crore to fund schemes that promote climate-resilient practices in Kanniyakumari and the state of Tamil Nadu. These schemes should:

- Encourage the adoption of sustainable and climate-resilient farming techniques such as agroforestry, organic farming, and conservation tillage.

- Provide subsidies for water-efficient irrigation systems, such as drip irrigation, to reduce water wastage and improve crop productivity.

- Support the development of drought-resistant crop varieties and improve the overall adaptability of agriculture to climate change.

In Kanniyakumari, as in other parts of Tamil Nadu, farmers continue to face financial distress due to crop failures, lack of access to affordable credit, and rising input costs. The long-standing issue of debt burden among farmers needs to be addressed immediately.

I request the Hon'ble Minister to introduce a loan waiver scheme to support distressed farmers and allocate Rs.3,000 crore for this purpose. Additionally, farmers should be provided easy access to credit with low

interest rates to help them invest in modern farming techniques and mitigate the risks of crop failures.

Let me now turn my attention to the specific issues faced by the farmers of my constituency, Kanniyakumari, and the farmers of Tamil Nadu as a whole. As a representative of this region, I am deeply committed to ensuring that our agricultural sector is provided with the resources it needs for sustained growth and prosperity.

Tamil Nadu seeks 23,000 crore for direct financial assistance and loan waivers for farmers who are struggling with debt, particularly those in distress after consecutive crop failures due to unpredictable weather patterns. Many farmers are caught in a cycle of debt, and this scheme will provide much-needed relief, allowing them to start afresh without the burden of unpaid loans.

These measures are necessary to ensure that the farmers of Tamil Nadu are equipped to face the changing climatic conditions and global market shifts.

In addition to these state-specific demands, [I urge the Hon'ble Minister to consider the following national initiatives, which will significantly benefit farmers across the country:

An allocation of Rs.8,079 crore for strengthening agricultural research and education is essential. We need to invest in developing climate-resilient crops, pest-resistant varieties, and sustainable farming practices. Our research institutes, like the Tamil Nadu Agricultural University (TNAU), must be adequately funded to carry out cutting-edge research to ensure the long-term sustainability of our agricultural practices.

It is crucial to provide an interest subsidy of Rs.713,000 crore to make credit more affordable and accessible for our farmers, especially those in remote areas. The availability of low-interest loans will help farmers invest in modern technology, better seeds, and more efficient irrigation systems, leading to improved productivity and farm income.

A continued commitment of 210,000 crore is needed to provide crop insurance, especially in disaster-prone areas like Kanniyakumari, to shield farmers from the financial impact of natural calamities. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) should be expanded and streamlined to ensure that farmers receive timely compensation, which will help them recover from crop losses and continue farming.

Let me now turn to the agriculture budget of the state of Tamil Nadu for the year 2025-26, which is an essential component of the overall development agenda. Tamil Nadu, as one of the leading agricultural states in India, has taken significant steps to support farmers and the agricultural sector. Below are the key schemes and allocations included in the Tamil Nadu State Agriculture Budget:

Farmer Welfare Fund: Aimed at providing financial aid to farmers in distress, especially in case of crop failure or unexpected circumstances. The allocation for this fund is 71,500 crore.

Crop Insurance Scheme (Tamil Nadu): This includes the National Agriculture Insurance Scheme (NAIS) and the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). This scheme provides protection to farmers against crop losses due to natural calamities. The allocation is Rs.800 crore.

Input Subsidy Scheme: Financial assistance for purchasing fertilizers, seeds, and agricultural equipment, especially for small and marginal

farmers. The allocation for this scheme is 21,200 crore.

Micro-Irrigation Scheme: Subsidies for adopting micro-irrigation systems like drip and sprinkler irrigation, especially in water-scarce regions. The allocation for this scheme is 2,500 crore.

Farm Pond Construction Scheme: Financial aid for farmers to construct farm ponds for water conservation and irrigation purposes. The allocation for this scheme is Rs.500 crore.

Restoration of Tanks and Channels: For maintaining and restoring the traditional irrigation systems, particularly for small farmers in rural areas. The allocation is Rs.1,000 crore.

Organic Farming Promotion Scheme: Assistance for transitioning conventional farms to organic farming, along with certifications for organic products. The allocation is Rs.400 crore.

Climate-Resilient Agricultural Practices Scheme: Encouraging farmers to adopt climate-resilient crops and practices, including rainwater harvesting and soil conservation. The allocation for this scheme is 300 crore.

Agri-Infrastructure Development Scheme: Enhancing agricultural infrastructure like cold storage units, processing units, and transportation to prevent post-harvest losses. The allocation for this scheme is 2,000 crore.

TNAU Strengthening: Funding for research on crop varieties resistant to diseases, pests, and climatic changes. The allocation for this scheme is Rs.400 crore.

Development of New Crop Varieties: Research in developing new varieties of crops that can withstand drought, pests, and diseases. The

allocation is Rs.300 crore.

Subsidy for Agricultural Equipment: Assistance for purchasing modern agricultural tools, machinery, and equipment, particularly for small farmers. The allocation is 7600 crore.

Subsidy for Fertilizers and Pesticides: Providing subsidies for fertilizers, pesticides, and other inputs required to improve productivity. The allocation is =1,000 crore.

Rural Roads and Connectivity Scheme: Enhancing transportation to markets, reducing the post-harvest loss, and ensuring timely delivery of inputs to farms. The allocation for this scheme is 71,500 crore.

Cold Storage and Warehousing Scheme: Setting up modern cold storage units and warehouses for the storage of perishable agricultural products. The allocation is 7700 crore.

The future of our country depends on the prosperity of our farmers. The agricultural sector needs focused attention, innovative solutions, and timely interventions to secure the livelihood of farmers and to boost productivity. I humbly request the Hon'ble Minister to consider the demands and grants presented for the year 2025-26, with particular attention to the specific needs of Kanniyakumari and Tamil Nadu.

The allocations and schemes I have outlined are aimed at creating an inclusive, sustainable, and prosperous future for farmers. It is our collective responsibility to ensure that agriculture remains a thriving sector that contributes significantly to the nation's growth and the well-being of our farmers.

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) :

जब देश पर आर्थिक और युद्ध संकट का तलवार झूल रहा था तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था "जय जवान जय किसान"

उनके महान मंत्र के ऊपर निर्भर होते हुए एक नया मंत्र का आगाज़ हुआ है

जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान

बहुत अच्छा विचार है लेकिन सोच और कोशिश में एक अंतर होता है

मैंने बजट को जब करीब से देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट को सिर्फ आरएस 11,253 करोड़ मिलता है, जो कि पूरे बजट का 0.21% है

इसके ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र में आरएस 30 करोड़ का बजट कट हुआ है इसका बहुत बुरा असर के.वी.के. में हो रहा है

जनवरी 2025 में के.वी.के. के कर्मचारियों को नोटिफिकेशन आया है कि उनका ईपीएफ और ट्रैवल अलाउंसेस रद्द कर दिया गया है

This has become a major roadblock for many innovative projects like making the soil health and salinity better.

ऑयलसीड्स और पल्सेस के लिए जो सीड का फंडिंग है वो भी डिलेड है सर

पैसा आईसीएआर से इतना डिलेड है कि वो साइंटिस्ट्स के पास सोइंग के बाद पहुँचता है

जब हम अनुसंधान में ध्यान नहीं देते तो इन्नोवेशन बंद हो जाती है

And that has scary outcomes such as higher cost of inputs.

आज आप एक किसान के पास जाएंगे तो वो अपनी हालातों पे निराशा दिखाएगा

और क्यों न दिखाए वो?

खाद्य यानी फर्टिलाइजर उसका प्राइस आज आउट ऑफ़ कंट्रोल होता जा रहा है

उसके ऊपर सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी को पिंग-पोंग के तरह उसे कर रही है

पिछले साल बजट में 13% रिडक्शन किया और फिर साल भर सब्सिडीज वापस लाती रही

पार्लियामेंट में आप दिखाते हैं कि डेली लेबर वेग 328.18 है, लेकिन फिर आप ही की सिचुएशन असेसमेंट सर्वे दिखाता है कि ये वृद्धि आईएनएडेक्टेड है

पानी की बात करें तो भी दिक्कत

Per Drop More Crop के फंड डिलेज के चलते आरएस626 करोड़ की सब्सिडी महाराष्ट्र में पहुँचने से डिलेड है

इससे सांगली में करीब 50% बेनिफिशियरीज अफेक्टेड हैं

जलवायु का भीषण परिवर्तन आज एक कृषक के लिए बुरे सपने जैसा समान है

सरकार की पीएमएफबी में उसमें डिलेस नज़र आती है

Many companies in Sangli who implement PMFBY do not conduct loss assessments in 10 days.

इससे जिन्हें बेनिफिट मिलना था उनको वो बहुत देर से मिलती है

बीजेपी के पहले महीने में पीएम किसान पे बड़ा जोर दिया गया था लेकिन इंप्लीमेंटेशन गैप कुछ ज्यादा ही हैं

या तो फंड्स गलत हाथों में पहुँचता है जैसे कि कैग रिपोर्टेड 67,871 इनएलिजिबल beneficiaries getting benefit in 2021

या फिर बेनिफिट ही मिस हो जाता है जैसे 2023 में, मोरे थन 96,000 महाराष्ट्रीयन किसानों को फंड्स नहीं मिले ड्यू तो नॉन-लिंग्किंग ऑफ़ आधार विथ एकाउंट्स

एक कृषक अपने हक की लड़ाई कितनी बार और कितने जगहों पे करेगा?

मैं सरकार को ये बात साफ तरीके से बोलूंगा, कि ये सब आज का युवा ध्यान से देख है

And this is leading to yet another crisis: The Agro Brain Drain.

A report suggests that only 1.2% young rural population aspires to be a farmer.

जब इतनी तकलीफें उठाना पड़ेगा? भला कोई कृषक क्यों बने?

सर मैं सांगली से आता हूँ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आधी से ज्यादा आबादी की रोटी हमारी मिट्टी से आती है

हमारे सपने, हमारा संसार का केंद्र बिंदु हमारे ज़मीन है सर

और इन मुश्किलों के कारण जब मैं देखता हूँ कि लोग ग्रेप्स, ऑरेंज, सोयाबीन, कॉटन और ना जाने कितने प्रोडक्ट्स का हार्वेस्ट छोड़ के चले जाते हैं

तो मेरा दिल टूट जाता है

And Dr MS Swaminathan had rightly said: If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right.

Sir let us make it right, there is still time and the government aspires to be Atmanirbhar.

To avoid above laggards I recommend prioritizing Annual Action Plans along with scheme convergences-

We must encourage MGNREGA with horticultural or irrigation facilities.

The turmeric program under National Horticultural Mission should be clubbed with the processing plant scheme under the Spices Board to boost exports.

PMFME components that enable processing units should be integrated to boost grape and pomegranate exports.

Coupled with arresting RKVY fund cuts, whose trends are 4,530 crore in 2022-23 to 1,729.11 crore in 2024-25, affecting agricultural innovation and modernization.

Only then will we make it right and truly give back to the fields which feed us. Thank you.

श्री आदित्य यादव (बदायूं) : 'एक जमाना था जब किसानों तक अलग-अलग योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बहुत दिक्कत और परेशानी होती थी, क्योंकि हमारे पास विश्वसनीय डाटा होते नहीं थे । लेकिन फिर डिजिटल कृषि क्रांति भारत में हुई है और डिजिटल कृषि मिशन बनाया गया है ।'

क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे की ये कैसी क्रांति है जिसने महाराष्ट्र के 43 साल के किसान कैलास नागरे को खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया । उनका डेटा तो आपके पास होगा उन्हें तो सरकार ने युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया था ।

ये कैसी क्रांति है जिसने मध्यप्रदेश जहाँ आपने लंबे वक्त तक शासन किया वहा मंदसौर में किसानों के साथ हुई घटना के बाद बने जेके जैन आयोग को अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा । क्योंकि किसानों पर गोलियाँ चलाने का सच आपकी तथाकथित क्रांति पर कालिख पोत देता ।*

प्रश्न ये है...

खेती खुदकुशी की वजह क्यों बन गई?

- * आत्महत्या का आँकड़ा*: एनसीआरबी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में कुल 53,478 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या की, यानी औसतन प्रतिदिन 29 मामले । कर्ज, फसल नुकसान और बाजार की अनिश्चितता इसके प्रमुख कारण हैं । क्या मंत्रालय के पास इसका कोई ठोस जवाब है?

-** महाराष्ट्र में आरटीआई एक्टिविस्ट जीतेंद्र घाटगे ने एक आरटीआई लगाई पता चला की 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 के बीच किसानों की आत्महत्या के कुल आंकड़े 1046 है । इस हिसाब से देखें तो करीब हर महीने औसत 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं ।

डायरेक्टोरेट ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड स्टॅटिस्टिक्स (देस) की रिपोर्ट एग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स अत अ ग्लांस 2023 कहती है की कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो देश के जीडीपी में लगभग 15% का योगदान देती है और 50% से अधिक कार्यबल

को रोजगार प्रदान करती है। यह डेटा कृषि के महत्व को दर्शाता है, विश्व बैंक के अनुसार, 2020 में यह आंकड़ा 16.5% था, यानी कृषि से लोग भाग रहे हैं। देस, जो कृषि मंत्रालय के तहत एक सरकारी निकाय है, उसमें जो बताया गया उसे भी ये सरकार नहीं देखती। आप सोचिए जीडीपी में कम योगदान के बावजूद, कृषि सबसे बड़ा नियोक्ता बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार इस पर निर्भर हैं। यह असमानता कृषि में कम उत्पादकता को दर्शाती है, जो छोटी जोत, पुरानी तकनीक और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे कारकों से प्रभावित है।

यह डेटा एक महत्वपूर्ण चुनौती को उजागर करता है: कृषि आधे कार्यबल को रोजगार देती है, लेकिन इसकी उत्पादकता अन्य क्षेत्रों से पीछे है। लेकिन फिर भी हमारी सम्मानित वित्त मंत्री जी बजट में कम से कम नौ नए मिशन या कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि

* कृषि "विकास का पहला इंजन" है

इस सरकार को इंजन शब्द से बहुत स्नेह है।

प्रश्न ये है की आपने विकास के पहले इंजन का बजट घटा क्यों है?

वर्ष 2025-26 के बजट में कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले साल के संशोधित अनुमान से 3,905 करोड़ कम है। क्यों?

ऐसे कैसे चलेगा इंजन?

और सबसे अहम सरकार ने 'एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड' जैसे कदम उठाये जो स्वागतयोग्य हैं, लेकिन इनके लिए स्पष्ट रोडमैप और पर्याप्त फंडिंग नहीं दी। हास्यास्पद ये है

* एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड' (आफ) को 2023-24 के बजट में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य ग्रामीण युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्टअप्स को वित्तीय (5-25 लाख रुपये) और तकनीकी सहायता देना है, ताकि स्मार्ट खेती और किसानों की आय बढ़े। लेकिन मार्च 2024 तक, पूरे देश में सिर्फ 31 करोड़ रुपये किसानों को मिले।

क्या इसका भी हाल भी एग्रीकल्चर इन्फ्रास्वर फंड जैसा होगा। जिसके बजट में आपने साल 22- 23 में भरी कटौती की और ये 500 सीआर से 150 सीआर कर दिया गया।

अब ब्राज़ील का उदाहरण लें ।

- * ब्राजील* ब्राजील का 2024-25 प्लानो साफ़ा यानी ब्राजील का एक वार्षिक कृषि नीति कार्यक्रम, जिसे वहां का कृषि और पशुपालन मंत्रालय संचालित करता है । यह छोटे, मध्यम, और बड़े किसानों को वित्तीय सहायता देता है इसमें 475.5 अरब रियाल (लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये) खर्च हुए जो भारत के बजट से कहीं अधिक है । यहाँ र&ड और बुनियादी ढांचे पर जोर है, हालाँकि सब्सिडी कम है । जीडीपी का 5.5% कृषि से आता है ।

लेकिन हम यहाँ 2025-26 में कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपये देकर क्रांति की बात करते हैं, जो जीडीपी का 0.4% से कम है ।

अब बताइए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर कहाँ से करेगा? जब इंजन में ईंधन नहीं है ।

ईंधन क्यों नहीं है?

आय दोगुनी करने का जुमला देने वाली सरकार का सच ये है की वर्ष 2024-25 में कृषि कल्याण के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये दिए मगर असफल और निकम्मी सरकार उसमे भी 13 फीसदी खर्च नहीं कर पाई ।

यानी लगभग 20,000 करोड़ खर्च नहीं हो पाए ।

मतलब देश में किसान खुदकुशी कर रहा है और आप पैसा खर्च नहीं कर पा रहे ।

इस सरकार के निकम्मेपन का पुराना इतिहास है ।

कैसे?

कुछ योजनाओं का हाल देख लीजिए ।

सरकार ने तकनीकी नवाचार, किसानों की आय सुरक्षा, और 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि तकनीकों और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करने का दावा किया है ।

सच्चाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीकेएस) जैसे संस्थानों के बजट आवंटन और उपयोग में कमी को लेकर गंभीर

सवाल हैं। क्योंकि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डरे) के तहत आईसीएआर और उससे जुड़े संस्थानों को मिलने वाला बजट भारत में कृषि र&ड का मुख्य आधार है। सरकार ने बार-बार दावा किया है कि वह किसानों की आय दोगुनी करने और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बजट आंकड़े और उसका उपयोग एक अलग कहानी बयान करते हैं।

हाल के वर्षों का बजट आवंटन

- *2021-22*: डरे/आईसीएआर को 8,514 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। संशोधित अनुमान (रिवाइज्ड एस्टिमेट्स - री) में यह घटकर 8,077 करोड़ रुपये हो गया, और वास्तविक व्यय (एक्चुअल एक्सपेंडिचर) 7,933 करोड़ रुपये रहा। यानी करीब 581 करोड़ रुपये (6.8%) का सरेंडर हुआ।

- *2022-23*: आवंटन 8,737 करोड़ रुपये था, रे में 8,514 करोड़ रुपये और वास्तविक व्यय 8,287 करोड़ रुपये। यहाँ 450 करोड़ रुपये (5.1%) उपयोग नहीं हुए।

- *2023-24*: बजट आवंटन 9,504 करोड़ रुपये था, लेकिन रे में यह 9,134 करोड़ रुपये तक सीमित रहा। इसमें भी आपने सरेंडर किया।

- *2024-25*: बजट में 9,941 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, यहाँ भी वही हाल।

सरकार ने एक और मज़ाक़ किया* 2024-25*: 731 केवीकेएस के लिए 234.89 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो प्रति के वी के औसतन 32 लाख रुपये से भी कम है। यह राशि बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, और तकनीकी प्रदर्शन के लिए अपर्याप्त है। और भद्दा मजाक़ है।

इस सरकार का (सरेंडर रेशों) देखिए यानी आवंटित राशि का उपयोग न हो पाने वाला हिस्सा,

-*2021-22*: 6.8% (581 करोड़ रुपये)

-*2022-23*: 5.1% (450 करोड़ रुपये)

- *2020-21*: कोविड-19 के कारण 7.2% तक सरेंडर हुआ था।

- औसतन, पिछले पांच वर्षों में 5-7% बजट सरेंडर हुआ, जो कि 400-600 करोड़ रुपये सालाना के बराबर है ।

यह सरेंडर तब और चिंताजनक हो जाता है जब इसे केवीकेएस और अन्य र&ड योजनाओं के संदर्भ में देखा जाए । 12वें पांचवर्षीय योजना (2012-17) में केवीकेएस के लिए 5,700 करोड़ रुपये मांगे गए थे, लेकिन केवल 3,900 करोड़ रुपये ही स्वीकृत हुए । इस कमी का असर आज तक दिखता है । और कृषि मंत्री क्रांति की बात करते हैं । यही है आपकी क्रांति?

सरेंडर रेश्यो दर्शाता है कि आइ कार और केवीकेएस के पास या तो कार्यान्वयन की क्षमता नहीं है या योजनाएं जमीनी जरूरतों से मेल नहीं खातीं । उदाहरण के लिए, कई केवीकेएस में प्रयोगशालाएं, प्रदर्शन फार्म, और प्रशिक्षण सुविधाएं पुरानी या अपर्याप्त हैं ।

अब ऐसे में आप 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी योजनाओं का ढोल पीट रहे हैं । इसके लिए आईसीएआर से तकनीकी सहायता और र&ड की जरूरत है । इस सरकार ने 2023 में बायर और अमेज़न जैसी कंपनियों के साथ माउस साइन किए, लेकिन स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त निवेश नहीं किया जा रहा ।

एक और हास्यास्पद बात केवीकेएस का लक्ष्य "लैब टू लैंड" है, लेकिन एक अध्ययन (नीलर्ड, 2022) के अनुसार, केवल 40% किसानों ने केवीकेएस से तकनीक को तुरंत अपनाया, और 80% ने फसल पैटर्न में बदलाव किया । यह प्रभाव सीमित है क्योंकि संसाधन और जागरूकता की कमी बनी हुई है ।

आईसीएआर और केवीकेएस के बजट में मामूली वृद्धि और लगातार सरेंडर नवाचार और आय सुरक्षा के लक्ष्यों को कमजोर करते हैं । 5-7% का सरेंडर अनुपात, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, और नीतिगत असंगति यह दर्शाती है कि कृषि र&ड को प्राथमिकता नहीं दी जा रही ।

* ये सरेंडर सरकार है

कृषि मंत्री की क्रांति का एक और नमूना देखिए

एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को हुई थी ।

- 2015 से 2025 तक 10 सालों में लगभग आरएस 2,500-3,000 करोड़ का अनुमानित आवंटन हुआ ।

... बजट सरेंडर**:

- रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2015-16 में आरएस 568 करोड़ में से करीब 40% (लगभग आरएस 227 करोड़) खर्च नहीं हुआ ।

- 2016-17 में आरएस 100 करोड़ में से 20-25% सरेंडर हुआ ।

- हाल के वर्षों में (2022-25), औसतन 15-20% बजट हर साल उपयोग नहीं हो पाया, जो कि आरएस 50-70 करोड़ सालाना के आसपास बैठता है ।

- कई राज्यों ने फंड को अन्य योजनाओं में डायवर्ट किया ।

एसएचसी योजना एक अच्छा पीआर कदम है, लेकिन इसका ज़मीनी असर सीमित है । बजट सरेंडर इस बात का सबूत है कि सरकार ने इसे लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई । अगर मिट्टी जांच लैब, किसान शिक्षा, और सिफारिशों के पालन पर ध्यान दिया जाता, तो यह वाकई क्रांतिकारी हो सकती थी ।

इसी तरह

* पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015-16 से अब तक 45 लाख 92 हजार किसानों को लाभ मिलने का दावा है सरकार का ।

* प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)* की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी, जिसका मकसद "हर खेत को पानी" और "प्रति बूंद अधिक फसल" सुनिश्चित करना था । अच्छी सोच थी लेकिन 2015-20 (पहला चरण)**: योजना के लिए 5 साल में आरएस 50,000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन स्वीकृत हुआ,

2021-26 (विस्तार)**: दिसंबर 2021 में कैबिनेट ने इसे 2026 तक बढ़ाया, जिसमें कुल 193,068 करोड़ का आवंटन किया गया ।

लेकिन

?? बजट सरेंडर...

-* 2015-20*: इस अवधि में कई घटकों (जैसे "पर ड्रॉप मोरे क्रॉप") में बजट का 20-50% हिस्सा खर्च नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, 2021-22 में आरएस 4,000 करोड़ के मूल आवंटन से आधा सरेंडर हुआ।

कुल अनुमान**: 2015 से 2025 तक करीब आरएस 10,000-15,000 करोड़ का बजट सरेंडर हुआ, खासकर एक्सीलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) में और भी दशा खराब है।

आप क्रांति की बात करते हैं लेकिन पीएमकेएसवाई 2016 में शुरू हुए 99 प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स में से कई अभी तक पूरे नहीं हुए। जल-गहन फसलों (जैसे गन्ना) को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बढ़ावा मिला, जो योजना के उद्देश्य के खिलाफ है। बुनियादी ढांचे (जैसे नहरें, ट्यूबवेल) में सुधार के बिना, योजना का असर आधा-अधूरा रहा।

पीएमकेएसवाई कागज पर एक क्रांतिकारी योजना थी, लेकिन इसकी ज़मीनी सच्चाई निराशाजनक है। बजट सरेंडर और अधूरे प्रोजेक्ट्स से पता चलता है कि यह योजना नौकरशाही और संसाधन प्रबंधन की कमियों का शिकार हुई।

(बदायूं में गुन्नौर, सहसवान के भुड़ जैसे इलाके सिंचाई के लिए जूझ रहे हैं। भूजल कम हो रहा है।)

एक और गेम चेंजर योजना है आपकी।

####** पीएम किसान सम्मान निधि योजना:

** इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सालाना आरएस 6,000 (तीन किस्तों में आरएस 2,000) की आय सहायता देना था। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए पहुंचती है।

आपने 2019 से 2025 तक करीब आरएस 4.5-5 लाख करोड़ का आवंटन किया। लेकिन 2019-25 तक आरएस 40,000-50,000 करोड़ का बजट सरेंडर हुआ, जो मुख्य रूप से शुरुआती वर्षों में पात्रता सत्यापन और आधार लिंकिंग की देरी के कारण था।

?? ज़मीनी सच्चाई: ये है की पीएम-किसान का लक्ष्य 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देना था, लेकिन आधार सत्यापन, बैंक खाता लिंकिंग, और डेटाबेस अपडेट में देरी से फंड सरेंडर किया आपने ।

दूसरा 6,000 सालाना (९500/माह) छोटे किसानों की जरूरतों के लिए नाकाफी है । लागत बढ़ने और मुद्रास्फीति के सामने यह राशि कमजोर पड़ती है । यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में नाकाफी है (2024 में ग्रामीण खपत वृद्धि केवल 4%) । अब आपको हर महीने 6 हज़ार देने चाइये ।

ऐसे ही प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है ।

... प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबी)**: 4 करोड़ किसानों को कवर करने का लक्ष्य है, लेकिन 2025 के बजट में इसका आवंटन 15,864 करोड़ से घटाकर 12,242 करोड़ कर दिया गया । अब इसकी सच्चाई देखिए आपने फरवरी 2016 को ये योजना शुरू की, यह योजना "एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम" के आधार पर चलती है । और आपने इसमें

2016-25 तक करीब आरएस 1.3-1.4 लाख करोड़ आवंटित किया । लेकिन भारत के किसानों का दुर्भाग्य देखिए और सरकार का निकम्मापन देखिए ।

- *2016-17*: आरएस 1,521 करोड़ (27%) खर्च नहीं हुआ ।

- *2017-18*: आरएस 200 करोड़ (2%) सरेंडर ।

- *2018-19*: आरएस 1,100 करोड़ (8%) उपयोग नहीं हुआ ।

2020-21: आरएस 1,195 करोड़ (7%) सरेंडर ।

- *2021-22*: 1,000 करोड़ (6%) बचा ।

यानी 2016-25 तक आरएस 10,000-15,000 करोड़ सरेंडर हुआ,

पीएमएफबी का दावा है कि यह किसानों को जोखिम से बचाती है, लेकिन इसकी हकीकत कई खामियों से भरी है । 2016-23 तक किसानों से 531,139 करोड़ प्रीमियम लिया, लेकिन दावे आरएस 1.55 लाख करोड़ दिए गए । सरकार और किसानों का योगदान मिलाकर बीमा कंपनियों को आरएस 40,000-50,000 करोड़ का लाभ हुआ ।

यह योजना किसानों से ज्यादा निजी कंपनियों के लिए फायदेमंद लगती । दूसरा बटाईदार और भूमिहीन किसान बाहर । स्थानीय जोखिम (जैसे जंगली जानवर) शामिल नहीं । प्रीमियम दरें (2% खरीफ, 1.5% रबी) छोटे किसानों के लिए भी बोझ हैं ।

ऐसे ही

- राष्ट्रीय कृषि योजना के लिए निर्धारित 7,553 करोड़ के मुकाबले 6,000 करोड़ ही खर्च हो पाए ।

- कृषोन्नति योजना में भी 7,447 करोड़ के बजट को संशोधित कर 7,106 करोड़ कर दिया गया है ।

अब आते हैं कर्ज पर । जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा किसान खुदकुशी करते हैं । सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है. लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज सब्सिडी के लिए के बजट में सिर्फ 22,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के बराबर है. अगर सब्सिडी में वृद्धि नहीं की जाती, तो यह सवाल उठता है कि क्या किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों की संख्या बढ़ने पर ब्याज दर बढ़ सकती है क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या बढ़कर 7.75 करोड़ तक पहुंच गई है । और दूसरा बड़ा सवाल जो पहले से प्रति किसान आरएस 74,121 का औसत कर्ज है उसका क्या होगा? ये एनएसएसओ 2021 का डेटा है ।

सब्सिडी

खाद्य सब्सिडी बजट अनुमान से कम रही है । मौजूदा वर्ष का बजट अनुमान 2,05,250 करोड़ रुपये था जबकि संशोधित अनुमान 1,97,420 करोड़ का है । ये तब है जब उर्वरक सब्सिडी के नाम पर अरबों रुपये की हेराफेरी की खबरें हैं । कंपनियाँ सब्सिडी लेती हैं, लेकिन किसानों तक सस्ता उर्वरक नहीं पहुँचता । 2022 में कैग की रिपोर्ट ने इस ओर इशारा किया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई । 2024 के रबी सीजन में डीएपी और यूरिया की कमी ने किसानों को परेशान किया । कालाबाजारी आम बात है, और कीमतें आसमान छू रही हैं ।

- * मंडियों का हाल*:

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईनाम) योजना, जिसे 14 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने शुरू किया था, का उद्देश्य देश भर के किसानों को एक एकीकृत ऑनलाइन मंच प्रदान करना है ताकि वे अपनी उपज को पारदर्शी तरीके से बेहतर कीमत पर बेच सकें।

हकीकत ये है कि पंजीकृत किसानों की संख्या भले ही 1.76 करोड़ से अधिक है, लेकिन सक्रिय रूप से इसका उपयोग करने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है। कई मंडियों में पारंपरिक तरीके से ही व्यापार हो रहा है, और इनाम का उपयोग नाममात्र का है।

*** मंडियों में बुनियादी ढांचे की कमी***: इनाम के लिए मंडियों में गुणवत्ता परीक्षण (असे लैब्स), वेयरहाउसिंग, और डिजिटल भुगतान सुविधाओं की जरूरत होती है, जो कई स्थानों पर अपर्याप्त हैं।

गुणवत्ता परीक्षण के लिए उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे खरीदार उपज की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं करते। छोटे किसान मंडी के बाहर व्यापार करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत नकदी की जरूरत होती है, और इनाम पर भुगतान में देरी की शिकायतें आम हैं। हालांकि 3,320 एफपीओ पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर सक्रिय नहीं हैं या उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। 2022-23 तक इनाम पर कुल व्यापार मूल्य लगभग 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, लेकिन यह भारत के कुल कृषि व्यापार का एक छोटा हिस्सा है। और 1,361 मंडियों में से केवल 50-60% ही पूरी तरह डिजिटल रूप से सक्रिय हैं। बाकी में आंशिक या नाममात्र उपयोग हो रहा है। इसलिए इस का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार और राज्य इन चुनौतियों को कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से दूर कर पाते हैं।

(उझानी का संदर्भ दे सकते हैं)

सवाल इतना है कि जब सरकार आवंटित बजट ही नहीं खर्च कर पाएगी तो किसानों को कृषि क्षेत्र के भारी-भरकम बजट आवंटन से कोई राहत कैसे मिल पाएगी?

एंड विथ *रिकमेंडेशंस*:

Enhance Transparency: Establish independent committees to probe scams, ensuring swift action against guilty parties.

***Improve Implementation*:** Strengthen ground-level monitoring of schemes like PM-KISAN and PMFBY, addressing data and infrastructure gaps.

***Legal Guarantee for MSP*:** Make Minimum Support Price (MSP) a legal right to ensure fair prices for farmers.

***Technology Support*:** Extend drone, AI, and smart farming to small and marginal farmers, with training and subsidies to bridge the digital divide.

2025-26 budget, with its reductions, must be revisited to prioritize farmer welfare. We cannot afford to ignore the plight of our farmers, who are the backbone of our nation. It's time for introspection and action, lest future generations hold us accountable.

श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी (सिवान) : मैं अपने क्षेत्र सीवान के किसानों के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ । हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और इस राष्ट्र की आत्मा हमारे अन्नदाता किसान हैं ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को सशक्त करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं, जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है ।

सीवान जिले के किसान मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, गन्ना और दलहनों की खेती करते हैं, लेकिन आज भी उन्हें सिंचाई, उचित मूल्य, भंडारण और विपणन जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है ।

सीवान में सिंचाई की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है । हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सीवान जिले को प्राथमिकता दी जाए और अधिक नहरों और ट्यूबवेलों का निर्माण कराया जाए । इसके साथ ही हर खेत को पानी योजना का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को निर्बाध जल आपूर्ति मिल सके ।

हमारे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी उपज बेचने के लिए संघर्ष करते हैं । मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करके यह सुनिश्चित किया है कि एमएसपी उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक हो । लेकिन हम मांग करते हैं कि सीवान में नए कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) और सरकारी खरीद केंद्र खोले जाएं, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके ।

सीवान के किसान अक्सर बाढ़ और सूखे की मार झेलते हैं । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत अधिक किसानों को कवर किया जाए और दावों के निपटारे की प्रक्रिया को सरल व त्वरित बनाया जाए ।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋण की सीमा 5 लाख रुपये की गई है, जिससे किसान उन्नत तकनीकों में निवेश कर सकते हैं । हम मांग करते हैं कि सीवान के अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ा जाए और स्थानीय बैंकों में इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं ।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । हम चाहते हैं कि इस योजना के तहत सीवान में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस बनाए जाएं, जिससे किसानों को अपनी फसल के उचित भंडारण की सुविधा मिल सके ।

मोदी सरकार के प्रयासों से भारत का खाद्यान्न उत्पादन 332 मिलियन टन तक पहुंच गया है और कृषि निर्यात 48.15 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है । हम चाहते हैं कि सीवान के किसानों को भी वैश्विक बाजार तक पहुंच मिले और उनके उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए ।

मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं । मैं इस सरकार से निवेदन करती हूं कि सीवान जिले को कृषि योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए और किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए ।

जय जवान, जय किसान । जय बिहार । जय हिन्द ।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): मुझे वर्ष 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मेरा देश कृषि प्रधान देश है । मैं सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, एवं माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपके द्वारा कृषि सहित किसान भाईयों के चहुंमुखी विकास के साथ देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 1 लाख 27 हजार 290 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जिसमें बिहार सहित देश के करोड़ों अन्नदाताओं के हित में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना सहित अनेकों योजनाएँ लागू कर एतिहासिक काम किया गया है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने सार्थक नीति एवं नीयत का परिचय देते हुए कृषि एवं किसान भाईयों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशील, सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए प्रथम इंजन का स्वरूप देकर सम्मानित किया है, यह वाकई में सराहनीय कदम है । मुझे गर्व हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी एवं सार्थक योजनाओं के द्वारा हमारा भारत कृषि प्रधान के साथ-साथ अन्य सभी क्षेत्रों में भी अग्रणी होगा ।

मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल बिहार के सीमावर्ती अति पिछड़ा नेपाल से सटा हुआ कोशी-मिथला का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है । माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा बिहार के किसान भाईयों के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना का विशेष अवसर देकर सम्मानित किया गया है, जिसमें किसान उत्पादक संगठन के द्वारा मखाना किसान भाईयों को संगठित कर उनके पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा कि उन्हें सभी संगत सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके ।

आंकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेकर सरकार राज्यों की भागीदारी से "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" का शुभारंभ करेगी । इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदण्डों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा । इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है । सरकार के द्वारा किसानों के प्रवास को रोकने तथा कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम अवसर हेतु कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यों की भागीदारी के साथ 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल कर एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय "ग्रामीण सम्पन्नता और

अनुकूलन निर्माण" कार्यक्रम चलाया जाएगा । सरकार खाद्य तेलों एवं दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन" के साथ तुअर, उड़द, और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6-वर्षीय "दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन" प्रारंभ करेगी, जिसके लिए केन्द्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी ।

सरकार के द्वारा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सब्जियाँ और फलों के पोषक संबंधी गुणवत्ता की जानकारी हेतु व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ कर लगातार जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से सब्जियाँ, फलों और श्रीअन्न का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है, साथ ही किसानों के आय के स्तरों में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है । राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का उद्देश्य अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किसमों को वाणिज्यिक स्तर पर होगा है । उपलब्ध कराना है । भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है । समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60 हजार करोड़ रुपये का है । सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाएगी । सरकार के द्वारा कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने हेतु पंच वर्षीय "कपास उत्पादकता मिशन" की घोषणा की गई है, जिससे कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा ।

किसान क्रेडिट कार्डों (के०सी०सी०) से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है । सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी । यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रीय पड़े तीन यूरिया संयंत्रों में उत्पादन पुनः प्रारंभ किया है । नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा । किसान भाईयों के आर्थिक हित एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जिससे पैसों के लेन-देन में सहूलियत प्राप्त हो सके, उसके लिए सरकार के द्वारा 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के

विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण आर्थिकव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा तथा भारतीय डाक को विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा । इससे विश्वकर्माओं, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा बड़े कारोबारी संगठनों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, साथ ही सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए एनसीडीसी के ऋण कार्यों के लिए सहायता प्रदान करेगी ।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल सहित बिहार के सभी किसान भाईयों के हित से संबंधित मुख्य अतिआवश्यक मांगों के लिए आग्रह करता हूँ । वर्ष 2008 के प्रलयकारी बाढ़ की तबाही के बाद कोसी क्षेत्र के किसान भाईयों ने बहुत ही कष्ट सहन कर मखाना के साथ मक्का एवं जूट की खेती करना शुरू किया । कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं उसका उपर वाला है । भगवान की कृपा एवं उनके कड़ी मेहनत के बाद मखाना के साथ मक्का एवं जूट की बहुत ही अच्छी पैदावार होने लगी है, जिससे किसान भाई अपना जिविकोपार्जन के साथ अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला रहे हैं ।

मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के साथ बिहार के सीमावर्ती कोसी एवं मिथला क्षेत्र में देश के कोने-कोने से मखाना के साथ मक्का एवं जूट की खरिदारी हेतु व्यापारियों का आना-जाना लगा रहता है, जिसके लिए बड़े स्तर पर व्यापार केन्द्र अतिआवश्यक एवं अपेक्षित है, जिसमें चौड़ी सड़क, रेलवे का कंटेनर डिपो, देश के सभी महानगरों के साथ रेल कनेक्टिविटी, भारी वाहन पार्किंग, उच्च क्षमता का भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, राष्ट्रीयकृत बैंक, भोजनालय, शौचालय के साथ अतिथि गृह का निर्माण हो जिससे किसानों एवं व्यापारियों के लिए मुलभूत सुविधाएँ प्राप्त हो सके । मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल एवं बिहार के कोसी-मिथला वासियों के लिए एक केन्द्रीय कृषि अनुसंधान महाविद्यालय की स्थापना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक एवं अपेक्षित है जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण संबंधित सभी विषयों का पठन-पाठन हो सके । आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में केन्द्रीय कृषि अनुसंधान महाविद्यालय की स्थापना की जाय । बिहार के सीमावर्ती कोशी मिथिला क्षेत्र में यूरिया उत्पादक संयंत्र की स्थापना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक एवं अपेक्षित है । आग्रह है कि यूरिया उत्पादक संयंत्र की स्थापना किया जाए, जिससे बिहार के समस्त किसान भाईयों को इसका लाभ मिल सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : मुझे वर्ष, 2025-26 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद ।

मा. वित्तमंत्री जी ने इस वित्तीय वर्ष में मंत्रालय को कुल एक लाख सैंतीस हजार सात सौ सत्तावन करोड़ रू. का आबंटन किया है । वैसे यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ढाई प्रतिशत कम है, किन्तु यह मंत्रालय के लिए काफी बड़ी राशि है । जिससे किसानों और देश में कृषि को आगे बढ़ाने में काफी सफल भूमिका निभाने का काम करेगा । मा. वित्तमंत्री जी अन्नदाता के व्यापक हितों का हमेशा ध्यान रखती हैं । देश में कृषि के विकास और उत्पादकता को यह बजट गति प्रदान करेगा । प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना प्रारम्भ हो रही है । इससे देश में जहाँ भी कुछ कमी रह गई है वैसे 100 जिलों को चयन कर करीब (1.7) एक करोड़ सत्तर लाख करोड़ किसानों को मदद देने का काम करेगा । दूसरा ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण योजना के तहत युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार और व्यवसायों का सृजन करना, सीमान्त और छोटे किसानों के लिए उत्पादकता में सुधार और भण्डारण का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है । जो किसानों के लिए लाभप्रद होगा । इसके साथ-साथ देश को दलहन के लिए आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक मिशन के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम, खाद्य तेल यानि कि तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाने के लिए किसानों को राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन के द्वारा लाभ देना और अगले चार वर्षों तक किसानों के पास तूर, उड़द और मसूर के कुल उत्पादित भण्डार को सरकारी एजेन्सीज द्वारा खरीदने का प्रावधान काफी सराहनीय योजना है ।

किसानों को लाभ देने के लिए सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम योजना चलाने के प्रस्ताव से अब किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है । इसी प्रकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उच्च पैदावार वाले बीज को मिशन के तहत काम करना भी काफी लाभदायक योजना है । किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य उत्पादन में किसानों को सहायता करना और डेयरी फार्म के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने

के लिए सरकार के प्रयास से निःसंदेह किसानों की आय जल्द ही दोगुनी हो जायेगी । देश के किसान हमारे अन्नदाता खुश रहेंगे तो देश विकसित और खुशहाल होगा ।

अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने 2016 में एक कमेटी का गठन किया था । उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी जानकारी किसानों को मिलनी चाहिए ।

बिहार के किसानों की मासिक आय लगभग 7500 रू. है । इसी प्रकार पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखण्ड राज्यों में किसानों की औसतन आय लगभग 1033 रू. से काफी कम है । अतः सरकार को इन राज्यों के किसानों के लिए कुछ विशेष योजना चलाने की आवश्यकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत करीब सात करोड़ सत्तर लाख किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के ऊपर जो पुराने ब्याज की राशि काफी समय से बकाया है, उसे माफ करने की कोई योजना सरकार को चलानी चाहिए ।

देश में किसानों के लिए खाद/फर्टिलाइजर अति महत्वपूर्ण है । क्योंकि इससे किसानों के पैदावार जुड़े हुए हैं । समय पर खाद की कमी के कारण किसानों को ब्लैक से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है । क्या कारण है कि ब्लैक मार्केट में खाद तो उपलब्ध रहता है, परन्तु सहकारिता द्वारा किसानों को नहीं मिल पाता है । मेरे राज्य बिहार से नेपाल सटा है, वहाँ खाद की काफी तस्करी होती है । जिसके कारण बिहार के लिए उपलब्ध खाद किसानों को मंहगे दामों पर खरीदना पड़ता है । इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है ।

अब यूरिया खाद नैनो यूरिया के रूप में मिल रहा है । मेरे राज्य के किसान नैनो की उपयोगिता के लिए तैयार नहीं है । उसकी उतनी उत्पादक क्षमता नहीं है । किसानों को नैनो यूरिया पर भरोसा नहीं हो रहा है । बिहार के किसानों के पास छोटी-छोटी खेती के रकवे हैं, जिसमें नैनो यूरिया का उपयोग संभव भी नहीं है । इस आशंका को दूर करने के लिए किसानों में जागरूकता लाने के बजाए खाद उत्पादक कम्पनी द्वारा किसानों को नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है । इसकी जाँच होनी चाहिए । किसानों को मजबूर करना उचित नहीं है ।

मैं मा. कृषि मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि देश में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता काफी कम है । किसानों के उत्पाद खराब और बर्बाद हो जाते हैं । इसके लिए भण्डारण पर ध्यान देने की जरूरत है । मैंने देखा है कि नागपुर में ऐसे-ऐसे कोल्ड स्टोरेज हैं, जहाँ किसानों के सभी उत्पाद फल और सब्जी रखे जाते हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र, नालंदा में आलू का उत्पादन काफी अधिक होता है । उत्तरी बिहार में भी आलू अच्छा होता है । अतः बिहार के इन जिलों में भी उसी तरह से कोल्ड स्टोरेज खोलने की एक विशेष योजना तैयार करनी चाहिए । मैं नालंदा में आलू अनुसंधान केन्द्र खोलने की माँग करता हूँ, क्योंकि नालंदा में आलू की बम्पर पैदावार होती है ।

सरकार को ट्रैक्टर की खरीद पर अधिक सब्सिडी देनी चाहिए । इससे किसानों और युवा किसानों को लाभ मिलेगा । वे इससे माल ढुलाई करके कुछ कमाई कर लेते हैं । यह किसानों की आय बढ़ाने का काम करेगा ।

अब तो देश में बिजली पूरी मात्रा में मिल रहा है । बिजली सस्ती भी हो गई है । इसलिए मेरा आग्रह है कि देश में किसानों के लिए बिजली फ्री कर देनी चाहिए ।

उत्तरी बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ से किसानों को काफी क्षति होती है । पूरे वर्ष वे मेहनत करते हैं । फसल लगाते हैं, किन्तु बाढ़ से सब बर्बाद हो जाता है । मेरी माँग है कि बिहार सरकार को साथ लेकर केन्द्र सरकार नेपाल सरकार से वार्ताकर इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए जल्द कदम उठाये।

मैं मा. वित्तमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किया है । आशा है, उत्तरी बिहार मखाना उत्पादक जिलों के किसानों को इससे लाभ मिलेगा । उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

बिहार राज्य का खाद्यान्न उत्पादन में विशेषकर धान और गेहूँ में देश में उतनी ही भागीदारी है, जितनी अन्य 3-4 राज्यों की है । अतः बिहार के किसानों की निम्न मासिक आय बढ़ाने के लिए सरकार को विशेष योजना चलानी चाहिए । बिहार सरकार वहाँ किसानों को उत्पादित धान और मसूर खरीद करने की गारन्टी देती है । इसके लिए राज्य को केन्द्र सरकार आर्थिक मदद देने का काम करे । बिहार में भूजल स्तर देश के औसत स्तर से काफी कम है । इसके लिए भी सरकार नदी जोड़ो परियोजना के अन्तर्गत भूजल स्तर को बढ़ाने और पानी की समस्या के समाधान के लिए जल्द विचार करे ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन मक्का अनुसंधान केन्द्र, बेगूसराय को स्थानांतरित करने की खबर आयी है । यह एक गंभीर विषय है । कृपया सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं ले, जिससे कि बिहार राज्य का अहित हो ।

बिहार में छोटे और मझोले किसान हैं । वहाँ खेती के रकबे छोटे-छोटे हैं । इसलिए वहाँ के किसानों की आवश्यकता के अनुरूप ही नीति निर्धारित किया जाये । बिहार के आम, लीची के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी वहाँ के किसानों को लाभ देने की आवश्यकता है । हमेशा किसी न किसी मौसम के खराबी के कारण इन फलों के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ता है । इसके लिए भी सरकार को सहायता देनी चाहिए । मा.मंत्री जी ने सदन में प्रश्न के जवाब में कहा है कि छोटे-छोटे किसानों को भी अब उनके फसल के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी । वहाँ के पंचायत के माध्यम से इसकी नीति का प्रचार-प्रसार होना चाहिए कि किसान इसके लिए कहाँ जाये । किसान कॉल सेन्टर प्रभावी नहीं है । यह मात्र घोषणा ही है, कोई काम नहीं करता है ।

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र योजना (एसीएबीसी योजना) को बिहार में सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है । नाबार्ड की पहुंच सुदूर ग्रामीण इलाके तक है । अतः इस योजना का पूरा लाभ ग्रामीण किसानों को पहुंचाने की आवश्यकता है ।

बिहार की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत है । यह बहुत बड़ी बात है । बिहार में अच्छी मिट्टी खेती के लिए उपलब्ध है । पर्याप्त वर्षा होती रहती है । भूजल में कमी है, फिर भी बिहार में किसानों का अच्छा उत्पादन नहीं हो पा रहा है । यही कारण है कि बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर है । ग्रामीण गरीबी, कम पोषण और श्रमिकों का पलायन राज्य के अन्य राज्यों में हो रहा है । इसके लिए राज्य सरकार अपनी उपलब्ध राजस्व क्षमता से विकास के सभी उपाय करती आ रही है । केन्द्र सरकार से अगर विशेष मदद बिहार को मिल जाता है, तो राज्य में कृषि के विकास को बढ़ावा देने में अमृत का काम करेगा ।

आशा है कि मा.कृषि मंत्री जी बिहार राज्य के प्रति उदारता दिखाने का काम करेंगे । मैं अपनी पार्टी जेडीयू की तरफ से अनुदानों की माँगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की 3 लाख करोड़ की ऐतिहासिक अनुदान मांग का पूर्ण समर्थन करता हूँ। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे देश के अन्नदाताओं के सम्मान, सशक्तिकरण और समृद्धि के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारत का कृषि क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प को साकार करने का माध्यम है जिसमें किसान को केंद्र में रखा गया है।

पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वह ऐतिहासिक है। 2008-09 में कृषि मंत्रालय का बजट 11,915 करोड़ रुपये था जो 2025-26 में बढ़कर 1,27,290 करोड़ रुपये हो गया है। यह बजट वृद्धि केवल वित्तीय प्रावधान नहीं बल्कि किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक दूरदर्शी नीति का प्रतिबिंब है। खाद्यान्न उत्पादन 2004-05 में जहाँ 204.6 मिलियन टन था, वह अब 2023-24 में 332.3 मिलियन टन तक पहुँच चुका है। इसी प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। धान का MSP 2850 से बढ़कर 2,300 रुपये और गेहूँ का 1,080 से 2,425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

पीएम-किसान योजना के माध्यम से 3.46 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में पहुँचे हैं, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.65 लाख करोड़ रुपये के दावे निपटाए गए हैं। ई-नाम योजना के तहत 1,400 से अधिक मंडियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 52,738 करोड़ रुपये की राशि 87,500 रुपये से अधिक परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे फसल के बाद के प्रबंधन में क्रांतिकारी सुधार आया है।

अब मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। मैं इस मंच से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी की विशेष धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य की कृषि नीति को जमीनी हकीकत से जोड़ा और किसान केंद्रित किया। उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है और उन्हें वर्ल्ड एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि महाराष्ट्र की कृषि नीति और उसके क्रियान्वयन में उत्कृष्टता है।

श्री एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में:

- * प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई ।
- * एक रुपये में खरीफ पिक बीमा योजना के तहत 1.70 करोड़ किसानों को 5.469 करोड़ रुपये की नुकसान भरपाई दी गई ।
- * नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के अंतर्गत 92 लाख किसानों को 7,134 करोड़ रुपये की सहायता मिली ।
- * प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1.16 करोड़ किसानों को 31,511 करोड़ रुपये लाभ मिला ।
- * कपास और सोयाबीन उत्पादक किसानों को 4,194 करोड़ रुपये और प्याज उत्पादकों को 851 करोड़ रुपये का आर्थिक सहयोग दिया गया ।
- * महात्मा फुले किसान कर्ज माफी योजना 2019 के तहत 14.38 लाख किसानों को 5,217 करोड़ रुपये की राहत दी गई ।
- * 145 सिंचाई परियोजनाओं को 2.19 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई, जिससे 22 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी ।
- * 5,000 गांवों में 'जलयुक्त शिवार अभियान पुनः शुरू किया गया, जिसमें 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।
- * मुख्यमंत्री बलिराजा विद्युत सब्सिडी योजना के अंतर्गत 44 लाख कृषि पंपों को मुफ्त बिजली दी जा रही है जिसमें 14,761 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया ।
- * किसानों को सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराने हेतु 15,000 करोड़ रुपये की योजना से 8.5 लाख किसानों को लाभ हुआ है ।
- * सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अंतर्गत 16,000 मेगावॉट विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है ।
- * मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के लिए नदी जोड़ परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है जिससे इन क्षेत्रों में जल उपलब्धता में सुधार होगा ।

* इस सबके साथ-साथ मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि महाराष्ट्र को एक मजबूत और कृषि-समर्थ राज्य के रूप में स्थापित करने में डिप्टी सीएम श्री एकनाथ शिंदे जी की भूमिका प्रशंसनीय रही है । मैं यह भी विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि श्री देवेंद्र फडणवीस और श्री अजित पवार जी के साथ मिलकर उनकी त्रिस्तरीय नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत महाराष्ट्र नई ऊँचाइयों को छुएगा ।

अतः मैं, मैं कुछ सुझाव सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ ।

*कृषि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए R&D और AI आधारित तकनीकी पर जोर दिया जाए ।

* जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में 100% माइक्रो इरिगेशन कवरेज का लक्ष्य रखा जाए ।

* किसान सहकारी समितियों को वित्तीय और तकनीकी रूप से मजबूत किया जाए ।

*जैविक और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि पर्यावरण की रक्षा के साथ किसानों की आय भी बढ़े ।

* ग्रामीण भंडारण, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल कनेक्टिविटी पर केंद्रित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जाए ।

यह बजट और नीति केवल योजना दस्तावेज़ नहीं, बल्कि भारत के किसानों के भविष्य में किया गया निवेश है । यही वह रास्ता है जिससे भारत की कृषि एक वैश्विक शक्ति बनेगी । धन्यवाद ।

DR. SHIVAJI BANDAPPA KALGE (LATUR): Thank you for giving me the opportunity to express my views on Demands for Grants (DFG) for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare.

It pains me to see the situation of our farmers who form the backbone of our country. Despite tall promises and grand announcements, this Government has once again failed to address the real concerns of our *Annadattas*, who toil day and night to feed the nation.

Despite the NDA government's claims of prioritizing farmers and agriculture under Prime Minister Narendra Modi, the Union Budget once again exposed its fake promises. There was not even a token mention of implementing the Swaminathan Committee report on agricultural pricing, nor any concrete step toward making the Minimum Support Price (MSP) legally binding.

For years the poor farmers have been demanding these crucial reforms, but the Government has consistently ignored their plight, offering nothing but empty rhetoric. This clearly shows how much "committed" the Government is towards farmers. This is also a prime example of how the Modi Government is more interested in headline management than in genuinely addressing the agrarian crisis.

This year's budget has completely abandoned Indian agriculture. The economic survey paints a very rosy picture, but if you look closely, you will understand that it is nothing but just another set of lies which the Government is feeding the innocent people. The growth rate of crop yields has plummeted, falling below even the previous decade. The farmers, who feed the nation, their real incomes are sinking while the prices of fertilizer, pesticides, and seed prices have skyrocketed. This Government has reduced Indian farmers to mere election slogans while delivering nothing but empty promises and disastrous policies. If this is not an outright betrayal of India's farmers, then what this is.

This Government extended the financial protection to employees earning up to Rs. 12.75 lakh annually, in contrast, the farmers who barely earn Rs. 1 lakh have been completely neglected. This discrimination underscores the Government's misplaced priorities, favoring salaried sections. Moreover, the Union Budget was nothing more than just making old announcements which has little to no real benefit for farmers. Many

of the so-called 'new' schemes were previously declared, but failed to make any tangible impact.

Despite grand rhetoric about supporting farmers, the Modi Government has once again proven that its policies cater to corporates and the privileged, while India's food providers continue to suffer under mounting debt, price uncertainty, and economic hardship.

There have been budget cuts for the Department of Agriculture and Farmers Welfare, despite Government's tall claims of supporting farmers. The Centre has slashed Rs. 3,905.05 crore from the Department's allocation compared to the revised estimates of 2024-25. For this financial year, the budget stands at Rs. 1,27,290.16 crore, which is significantly lower than last year's revised estimate of Rs. 1,31,195.21 crore.

What is particularly alarming is the Centre's massive cut to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), a Scheme the Government is very proud of. This year, funding for PMFBY has been slashed by Rs. 3,621.73 crore, despite the Government's claims that more states are participating. In the last revised budget, the Scheme was allocated Rs. 15,864 crore, but in this Budget, it has been reduced to a mere Rs. 12,242.27 crore. This is a clear hypocritical behaviour of the Government. While on one hand it promises farmers security, however on the other hand, it systematically slashes down the budget for vital support schemes. These budget cuts reflect a deliberate attempt to undermine farmers' welfare, raising serious concerns about the Centre's true commitment to the agricultural sector.

Today we have been in an era where you order food and it gets delivered in eight minutes, where technology has transformed every aspect of our lives, from artificial intelligence revolutionizing industries to automation

enhancing efficiency in every sector. The world is rapidly adopting smart solutions like self-driving cars, AI-powered healthcare, blockchain-based financial transactions, and precision farming that optimizes agricultural yield. The Government has been talking about it indefinitely but I want to ask what steps have the Government taken in this respect? The budget also failed to mention about equipping farmers to cultivate high-value cash crops.

This Budget has once again exposed the Modi Government's apathy and betrayal of our farmers. The continued neglect of their demands clearly shows that this Government is more interested in optics than real action. This Budget is not just a missed opportunity but an attack on the dignity and survival of Indian farmers. The Government's empty rhetoric stands exposed, and the nation must ask: For whom does this Government truly govern, India's farmers or its privileged elites?

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : मुझे Demands for Grants, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare 2025-26 पर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए धन्यवाद । जैसाकि हम सभी जानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में रहती है । कृषि का योगदान अभूतपूर्व है । ग्रामीण व्यवस्था रीढ़ की हड्डी है । सर हमारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनेन योजनाएँ किसान कल्याण के लिए लागू की हैं जिनका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी प्रतिफल और किसानों को आप सहायता प्रदान करना है ।

सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि वर्ष 2019 में शुरू की गई थी जिसमें किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं । अब तक 3.75 लाख करोड़ रूपये प्रदान किए जा चुके हैं और यह राशि सीधे 11 करोड़ किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई है । निश्चित ही

6000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। इस योजना का लाभ देश भर के किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान केन्द्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाया गया है, जिससे निचौलियों की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है।

कृषि के विकास से हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था पांचवें स्थान पर है, जल्द ही वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर होगी। एक विकसित राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि हमारी प्रति व्यक्ति आच में आठ गुना वृद्धि हो, आठ गुना वृद्धि तभी लाई जा सकती है जरूर इस देश की लड़ी आबादी और किसान इसमें भाग लें।

प्राचीन भारत में एक समय था जब गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे। अन्न का भंडार भी प्रचुर मात्रा में था। वर्तमान में भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 10-11 साल पहले कृषि उत्पादन लगभग 265 मिलियन टन था, जो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से अधिक हो गया है। बागवानी उत्पादन 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है। हाल के वर्षों में किए गए प्रयासों से देश में दालों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन घरेलू खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा अभी भी आयात पर निर्भर है।

यह हर्ष की बात है कि अपने देश में ने चना और मूंग के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है लेकिन अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन में तेजी लाने की जरूरत है। बागवानी, डेयरी और मत्स्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं और बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। मखाना बोर्ड की स्थापना से निश्चित ही मखाने की खेती को बढ़ावा मिलेगा और उत्पादन भी अधिक होगा। बिहार देश-विदेश में मखाने के लिए जाना चाहता जाता है।

7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पावधि ऋण की सुविधा के लिए प्रकरण राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। Indian Council of Agricultural Research के निरंतर, प्रयास से पिछले साल 109 किस्में बीजों की तैयार की गई है धान की ऐसी किस्म भी तैयार की है, जिसमें 20% कम पानी लगेगा।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है औ देश विश्व की एक अनूठी खाद्य टोकरी में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है । सरकार द्वारा कृषि में सुधार के कारण ही आज देश विश्व में सबसे बड़ा दूध और मसालों का उत्पादन करने वाला देश बन गया है । सबसे बड़ा millet उत्पादन करने वाला देश बन गया है ।

सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं । गांवों में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है । किसान उत्पाद संघ - FPO और PACS जैसे सहकारी संगठनों का प्रसार किया जा रहा है । सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू किया है । अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की supply chain को सशक्त कर रही है । पीएम किसान. सम्मान निधि के तहत किसानों को अपने छोटे खर्च पूरे करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है । पीएम किसान समृद्धि केन्द्रों के माध्यम से किसानों की विभिन्न जरूरतों को एक ही जगह पूरा किया जा रहा है ।

अभी भी बहुत सी समस्याएं बनी हुई हैं । बहुत से किसान भाई-बहन गरीबी में जीवन-यापन कर रहे हैं कृषि को लाभदायक उद्यम बनाने के साथ-साथ, 21 वीं सदी ने कृषि के समक्ष तीन अन्य बड़ी चुनौतियां हैं- खाद्य और पोषण सुरक्षा को बनाए रखना, संसाधनों का Sustainable use, तथा जलवायु परिवर्तन । Secondary Agriculture से जुड़ी गतिविधियां इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती हैं ।

किसान राष्ट्र की जीवनधारा और 'अन्नदाता' के रूप में सम्मानित, भारत की समृद्धि की नींव है । उन अथक परिश्रम देश का पेट भरता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कायम रखता है और हर घर की ताकत सुनिश्चित करता है किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, NDA की सरकार ने उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान का समर्थन और सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए कई पहल शुरू की हैं ।

भारत का कृषि क्षेत्र, देश की लगभग आधी जनसंख्या को रोजगार देता है देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला और राष्ट्र-निर्माण का प्रमुख चालक बना हुआ है । हमारी सरकार के अनेक पहल और योजनाओं किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के Sustainable Development के प्रति अटूट प्रतिवद्धता का प्रमाण हैं । पीएम-किसान, पीएम एफबीवाई और नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से, सरकार न केवल

वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि किसानों के लिए उत्पादकता और बाजार पहुंच भी बढ़ाती है ।

अंत में इस Demands for Grants को Support करता हूं ।

SHRI RAVINDRA VASANTRAO CHAVAN (NANDED): Respected Sir, I want to put forward the concerns of the oil seed farmers in my region. For the last three-and-a-half years due to the suspension of future contracts in oil seeds, the farmers have no visibility of prices. They are forced to sell their produce in distress. However, at one point of time by using commodity derivatives through their FPO they used to hedge their price risk using Soyabean Futures on NCDEX. After the suspension of Soyabean futures contract in November 2021, the farmers are rendered helpless. In the absence of benchmark pricing, farmers are not aware of the future prices of their produce at the harvesting and only depend on the mandi traders limiting the farmers bargaining power. Multiple independent research reports (IIM Udaipur, IIT Bombay, BIMTECH, IIM Ahmedabad etc.) and our economic survey 2024-25 has recommended that the suspended commodity derivatives (Soyabean, Ref Soyoil, CPO, Chana, Moong, Mustard seed, Wheat) should be revoked to give the commodity market participants market driven tools to hedge their price risk helping them with efficient price discovery. These research reports have clearly mentioned that in the absence of fair benchmark price discovery, the price dispersion between various mandis has increased and also commodity derivatives don't cause inflation ? they are rather tools to manage price volatility in the spot markets.

As far as NCDEX is concerned it is the largest domestic commodity exchange regulated by SEBI. NCDEX is owned by strong financial institutions like NABARD (National Bank of Agriculture and Rural Development), NSE (National Stock Exchange), LIC (Life Insurance

Corporation of India) etc. As a demutualized platform, its core function is to provide efficient tools for price risk management and effective price discovery. They have been working with FPOs/farmers to empower and educate them about these market driven tools since 2016. Currently there are 655 FPOs and millions of farmers associated with them.

Farmers from my constituency have not received remunerative price of MSP (Minimum Support Price) in soybean. This year the production of Soyabean is approximately 125000 lakh MT and the Government through its nodal procurement agencies like NAFED, FCI etc. has been able to procure only one-fifth of the total production. This clearly means that for the rest four-fifths of the quantity, the farmers have not received MSP but a market price which is 18 per cent below MSP (MSP Soyabean- Rs.4892/quintal and market price Rs. 4100/quintal). They are also not aware of future prices of soybean due to the suspension. Now, what should my farmers do in coming month of July when the kharif sowing season starts? Generally, they sow the crop of soybean by considering the future price of NCDEX in the harvesting period (September/October). Farmers might shift to other crops as there is now an absence of future prices and losses incurred during current season. The 'mission oil seeds' by the Government to increase the production of oil seeds in the country will not be achieved without the future prices being known to the farmers and market participants.

Why is the Government unable to take a decision on revocation empowering our farmers, when these tools have been empowering our farmers?

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): I just as a representative of the people of Davanagere, would like to raise of millions of farmers across this great

nation ? farmers who toil day and night to feed the country, yet struggle to feed their own families.

The Government often speaks of ?Sabka Saath, Sabka Vikas?. But I ask today ? whose *Vikas* are we really talking about? Is it the development of the farmers whose incomes have remained stagnant for years? Is it the progress of the families who have lost their loved ones to mounting debts? Or, is it the growth of a sector that registered a mere 1.3 per cent growth in 2023-24, far below the national average of three per cent over the past two decades?

About ?Broken Promises and Rising Hardships?, in the previous term, the Prime Minister promised to double the farmers' incomes by 2022. But where is that promise today? Farmers' incomes did not double, but food inflation did. Rising input costs, stagnant prices, and climate uncertainties have pushed our farmers to the brink. The reality is that if we adjust for inflation, real income has barely increased, leaving farmers in a perpetual cycle of distress.

With incomes barely growing and the cost of food, fuel, and fertilizers skyrocketing, our farmers are now just one drought away from a debt trap.

About the ?Crisis of Farmer Suicides?, the numbers paint a grim picture ? farmer suicides continue to haunt rural India. Why? It is because of crippling debts caused by: crop losses due to erratic weather: Over 50 per cent of agricultural land is still rain-fed; lack of fair prices because many crops are not covered under MSP. Even if they are, two major crops, paddy and wheat, are cornering them; failure of crop insurance schemes, which do not reach enough farmers. Also, the current Government has made a 23 per cent cut in the insurance scheme. What kind of farmers' development is this?; only 10 per cent of farmers have

crop insurance, and claims are often delayed; and institutional credit has increased but 63 per cent of small farmers remain highly indebted.

The Government claims that the number of suicides is reducing. But is it that because the crisis is improving or because hopelessness has forced farmers to abandon their lands entirely?

Now, I come to low investment in Agricultural Investment and Research. Adding to this crisis is the alarming low investment in agricultural research of mere eighth per cent of total Agricultural Budget. Research and innovation in farming have taken a backseat, and, without scientific advancements, we cannot expect to improve productivity. If India truly wants to support its farmers, it must increase investment in agricultural research to boost productivity.

Now, I come to the Crisis in Davanagere. Coming to my own constituency ? Davangere, known as the ?Rice Bowl of Karnataka?, is facing severe distress. Low procurement is leaving farmers with unsold produce. Why has the Central Government capped the procurement after encouraging Paddy with an MSP? Irregular rainfall and frequent droughts have worsened the situation. Low insurance claims and delays in delivering.

Now, I come to Call to Action. The hands that feed this nation deserve dignity, security, and prosperity. We need a comprehensive MSP policy covering more crops, especially millets which can be grown with little water yet nutrition rich. We also need better access to crop insurance and financial relief in times of distress, and increase in allocation of funds. We also need a higher investment in agricultural research up to 20 per cent of Agri budget to ensure long-term productivity.

This is not just about farmers; this is about food security, rural livelihoods, and the backbone of our nation. We cannot afford to fail them any longer.

Jai Jawan, Jai Kisan!

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भंडारा-गोंदिया) : मैं कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर स्थायी समिति की आठवीं रिपोर्ट से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहता हूँ, जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह रिपोर्ट सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली में गंभीर कमियों को उजागर करती है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को 2025-26 के लिए 10,466.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कुल केंद्रीय बजट का मात्र 0.21% है। यह आवंटन पिछले वर्षों की तुलना में लगातार कम होता जा रहा है। 2020-21 में यह 0.27% था, जो अब घटकर 0.21% रह गया है। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार सेवाओं के लिए पर्याप्त धन की कमी से किसानों को नई तकनीकों और जानकारी तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। क्या यह सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है? क्या किसानों के हित सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं?

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित 6.50 करोड़ रुपये में से केवल 2.05 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए यानी 54% घन अभी भी अप्रयुक्त है। सरकार अधिक धन की मांग करती है, लेकिन जो धन पहले से आवंटित है, उसे खर्च करने में भी नाकाम है। यह सरकार की अक्षमता को दर्शाता है।

देश के 121 जिलों में आज भी एक भी KVK नहीं है। जहां KVK हैं, वहां भी बुनियादी ढांचे और कुशल कर्मचारियों की कमी है। 731 KVKs में 3,499 पद खाली हैं, जो कुल पदों का 29.92% है। क्या यह सरकार की गंभीरता को दर्शाता है? KVKs किसानों और अनुसंधान के बीच की कड़ी है, लेकिन इनकी उपेक्षा से किसानों को नई तकनीकों और जानकारी तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है।

NICRA (नेशनल इनोवेशन्स इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर) को 2025-26 में 229.09 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए नई तकनीकों का विकास जरूरी है, लेकिन धन की कमी से यह काम प्रभावित हो रहा है। क्या सरकार किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए गंभीर है?

बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है, लेकिन मखाना की कटाई और प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त मशीनरी और उपकरण उपलब्ध नहीं है। दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान संस्थान की स्थिति भी चिंताजनक है। क्या बिना संसाधन और मानव शक्ति के इस संस्थान को प्रभावी ढंग से चलाना संभव है?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ICAR के विभिन्न संस्थानों में वैज्ञानिक, प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। कुल 23,378 पदों में से 8,182 पद खाली हैं। यह स्थिति संस्थानों के कामकाज को प्रभावित कर रही है। सरकार को इन रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

अंत में, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वह कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग को पर्याप्त धन आवंटित करे, KVKs को मजबूत करे, और किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए नई तकनीकों के विकास पर ध्यान दे। किसानों के हितों की उपेक्षा करके हम देश की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं।

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं पांच महत्वपूर्ण सुझाव इस सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ:

Konkan Mango Board की स्थापना की जाए ताकि हापुस आम के उत्पादन, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और निर्यात को संस्थागत ढांचा और बाज़ार मिल सके।

Climate Resilient Agriculture के लिए विशेष पैकेज घोषित किया जाए, विशेषकर सूखा प्रभावित जिलों के लिए जिसमें drip irrigation और solar powered irrigation को प्रोत्साहित किया जाए।

Rural Agricultural Logistics Hubs की स्थापना की जाए, जिसमें FPOs और किसान मंडलों को जोड़कर cold storage, warehousing और primary processing units विकसित किए जाएँ।

Agri Export Facilitation Mission शुरू किया जाए ताकि किसान अपने उत्पाद सीधे global markets तक पहुँचा सकें, जिससे foreign exchange भी आए और किसान की आमदनी भी बढ़े ।

Natural Farming और AI-enabled Precision Farming को बढ़ावा देने के लिए नवाचार अनुदान (Innovation Grant) की व्यवस्था की जाए, जिससे युवा किसान sustainable खेती में रुचि लें और modern tools का प्रयोग करें ।

Seeds", और "Mission for Cotton Productivity" जैसी योजनाएं long-term food security और farmer prosperity का रोडमैप प्रस्तुत करती हैं ।

Fisheries, Horticulture, Vegetables and Fruits के लिए भी comprehensive national-level योजनाएँ लाई जा रही हैं । विशेष रूप से Andaman & Nicobar और Lakshadweep Islands में मछली पालन की अपार संभावनाओं को sustainable तरीके से विकसित करने का विजन सराहनीय है ।

Growth Rate की बात करें तो, FY 17 से FY 23 तक कृषि क्षेत्र ने औसतन 5% की विकास दर दर्ज की है और पिछले दशक में agricultural income में 5.23% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है । वहीं allied sectors जैसे डेयरी, मछली पालन, और पशुपालन - अब कृषि वृद्धि के प्रमुख प्रेरक बन चुके हैं ।

भारत के food exports, जो देश के कुल निर्यात का 11.7% हैं, और seafood exports में FY20 से FY24 तक 29.70% की वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि agriculture अब आत्मनिर्भरता से global competitiveness की ओर बढ़ चुका है ।

किसान-केंद्रित योजनाओं की बात करें तो. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत ₹3.46 लाख करोड़ सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत ₹1.65 लाख करोड़ के दावे निपटाए गए हैं, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिली है । e-NAM के माध्यम से देश की 1,400 से अधिक मंडियों को डिजिटली जोड़ा गया है, जिससे बाजार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है ।

Agricultural Infrastructure Fund (AIF) के अंतर्गत ₹52,738 करोड़ से अधिक की राशि 87,500 से अधिक प्रोजेक्ट्स को दी गई है, जिससे post-harvest

management, cold storage और agri-logistics में जबरदस्त सुधार आया है। इसी प्रकार, Kisan Credit Card (KCC) के अंतर्गत ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर देना, किसानों को institutional credit तक आसान पहुंच दिलाता है।

सरकार ने कृषि में value addition को प्रोत्साहित करने के लिए PLI Scheme for Food Processing को लागू किया, जिसके तहत ₹8,910 करोड़ का निवेश हुआ और ₹1,084 करोड़ से अधिक की इंसेंटिव्स जारी की गईं। साथ ही, पोषणयुक्त अनाज (Shree Anna), pulses, oilseeds और cotton जैसी फसलों को MSP के जरिए बेहतर समर्थन दिया गया है।

नीतिगत दृष्टि से, सरकार ने agriculture को विकास का पहला इंजन माना है। "Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana" के तहत 100 जिलों को चिन्हित कर उन्हें कृषि विकास के मॉडल ज़िले बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, "Mission for Aatmanirbharta in Pulses", "National Mission on High Yielding.

मैं कृषि मंत्रालय की ₹1.37 लाख करोड़ की अनुदान मांगों का दृढ़ता से समर्थन करता हूँ। यह बजट महज़ एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे देश के अन्नदाताओं? किसानों के भविष्य को समर्पित एक दूरदर्शी और साहसी पहल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार लगातार यह सिद्ध कर रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था का पहला और सबसे मजबूत इंजन agriculture ही है।

वर्ष 2008-09 में जहां कृषि बजट ₹11.915 करोड़ था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर ₹1,27,290 करोड़ हो गया है। यह 10 गुना से अधिक वृद्धि केवल संसाधनों की बात नहीं करती, यह दर्शाती है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन में नवाचार लाने और rural economy को मजबूती देने के लिए कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है।

उत्पादन और समर्थन मूल्य की बात करें तो भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2004-05 में 204.6 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में अनुमानित 332.3 मिलियन टन तक पहुँच चुका है। इसके साथ ही, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है-धान के लिए ₹850 से बढ़ाकर ₹2,300 प्रति किंटल और गेहूं

के लिए ₹1,080 से ₹2,425 प्रति किंटल । MSP का कुल भुगतान भी 2004-13 के ₹4.40 लाख करोड़ से बढ़कर 2014-24 में ₹12.51 लाख करोड़ हो चुका है ।

SHRI BALWANT BASWANT WANKHADE (AMRAVATI): Thank you and the party leadership for giving me this opportunity to express my views on demands for grants under the control of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. As a member representing Amravati Lok Sabha constituency, while participating in this important discussion today, I felt the need to reflect deeply on the agricultural policies of our country. India is an agrarian country, where more than 60% of the population is dependent on agriculture. However, the situation of our farmers does not seem to have improved. The Indian agriculture sector is facing many challenges due to rising suicides, crisis of low productivity, erratic market prices, vagaries of nature and inadequate government support.

I will not only consider supporting the government's demands for grants, but also review the agricultural policies of the government as a responsible member. If we do not take concrete steps for sustainable agricultural development in the future, there will be far-reaching consequences for farmers and the economy as a whole.

India is an agrarian country where about 46 per cent of the workforce contributes to agriculture and it contributes about 18 per cent to its Gross Domestic Product (GDP). The Union Finance Minister rightly called it the "first growth engine". But the provision made in this year's budget is not consistent with this important recognition.

? The government has announced the Pradhan Mantri Krishi Dhan Yojana, which aims to benefit 1.7 crore low crop farmers in 100 districts. However, the budget of the Department of Agriculture and Farmers Welfare has been cut by ₹3,905.05 crore. The much-lauded Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), which provides insurance to protect

farmers against crop losses, has also seen significant budget cuts. This is a worrying trend, especially for a country that depends on the strength of its farmers.

? Maharashtra leads the way with the highest enrollment in the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, as farmers here grapple with the effects of climate change like frequent droughts every year.

? There has also been a cut in the budget of the fertilizer department, which may affect the fertilizer subsidy. These cuts will directly impact smallholder farmers, who are already struggling with high costs and volatile market conditions.

? Cotton was historically called "white gold" in Maharashtra, but today its luster is fading. Cotton farmers in Maharashtra have been demanding technological improvements and increased budgetary allocations for some time now as a solution to the problem of declining productivity. But Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman has allocated only Rs. 500 crore for the National Cotton Technology Mission in the budget for the financial year 2025-26. This paltry allocation is woefully inadequate to address the declining productivity problem plaguing cotton farmers for the past decade.

The issue of farmers' suicide and indebtedness is highly serious. I want to talk about the condition of farmers in Vidarbha and Marathwada parts of Maharashtra. In the last few years, the rate of farmer suicides has increased tremendously here.

Over 49 thousand farmers have committed suicide in last 24 years A shocking fact has been pointed out that in 24 years in the state, as many as 49 thousand farmers have become victims of Asmani and Sultani crises. Most of these 21,120 farmer suicides occurred in West Vidarbha,

under which 12,512 farmers died in Marathwada. Although the agriculture department has 35 schemes to improve the living standards of the farmers, there is no certainty that the needy farmers will benefit from the lottery system of 'DBT'. Last year, 1,051 farmers died in five districts of Amravati division, 104 in Wardha district of Nagpur division and 948 in Chhatrapati Sambhajnagar division. Of these, 981 cases are eligible for government assistance, 414 are ineligible, and 711 cases are pending. These figures are indicative of the failure of our agricultural policy.

The Government should go beyond mere rhetoric and implement immediate loan waivers, reasonable Minimum Support Price (MSP) guarantees and effective crop insurance payments so that farmers do not feel helpless and neglected in this tough battle for their livelihood.

Major causes of farmer suicides:

Crisis of Smallholders: 80-85% of our country's farmers are marginal land holders, owning only 2 acres or less. In such a situation, they do not have access to modern technology and facilities required for large-scale farming.

Increased risk due to erratic and inadequate rainfall: Due to climate change, erratic rainfall, drought, hail storming and heavy rains are causing massive agricultural losses in many states including Maharashtra.

Uncontrollable Debt Burden: According to a National Sample Survey Office (NSSO) report, 52% of India's farmers are indebted. Borrowing from moneylenders puts farmers in more trouble than borrowing from banks as interest rates are very high.

No Guarantee of Crops: Farmers do not get fair value for their labour. The minimum support price (MSP) announced by the government is always below the market price, resulting in losses to the farmers. For this I make the following demands to the government:

A separate fund of special financial assistance should be created for farmers in Maharashtra, which will be used for emergency measures to prevent suicide.

An interest-free loan scheme should be introduced so that small farmers can be freed from the clutches of moneylenders.

A crop insurance scheme should be implemented as an alternative to loan waiver, and restrictions on insurance companies should be reduced. It should be designed so that the farmers will get more benefit.

Today, farmers are the backbone of the country's nutrition security. The Government has to take more concrete measures for its protection. Agricultural development is not just a matter of slogans, but an area of real action.

Therefore, I request that by revising these subsidy demands, priority should be given to schemes that are truly transformative for the country's farmers.

"Jai Jawan, Jai Kisan, and Jai Science!"

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): I would like to express my views to speak in this august house today on the demand for Grants on Agriculture & Farmers' Welfare for the year 2025-26. An amount of Rs.1,37,757 crores has been allocated to the Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare during the financial year 2025-26. Hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman has described agriculture in her budget speech as 'First engine of growth'. In an estimate the agriculture

sector provides employment to 46 per cent of labour force in the country while contributing 16 per cent to the total value added. The Government is determined to increase the production of pulses, oilseeds, Dairy & fisheries in order to meet domestic demand and to some extent reduce dependency on imports. The Government has set the target of production of pulses to 30 million ton by the year 2030. The ambitious goal of increasing agriculture export to 80 billion dollar by the year 2030 from the current export of 50 billion dollar would definitely improve the rural economy.

The Government is working on Long Term plan of investment for inter linking of rivers to provide irrigation facility round the year, climate adaptive technologies, soil health management for a robust & sustainable agriculture to boost rural economy.

The Pradhan Mantri Dhan Dhaanya Krishi Yojana is likely to benefit 1.7 crore farmers in 100 districts with a low crop production. The PM Kisan Samman Nidhi the direct cash transfer of Rs.6000/ per farmer to their bank account for investment on farming. The Loan limit under Modified Interest Subvention Scheme (MISS) has increased from Rs.3 lakh to Rs.5 lakh for loan through Kisan Credit Cards (KCC) that facilitate short term loans to 7.7 crore farmers, fishermen & Dairy farmers of the country.

The Government has also announced a 6 year Long Mission for Aatmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad, and Masoor varieties of pulses.

Hinjili of my constituency is famous for vegetable production but there is no storage facility at present, as a result of which vegetable perish easily and farmers are selling at low prices at local market. More precisely the district of Ganjam is famous for cashew production. As

there is no proper upgraded processing unit the cashew farmers faces problem to sell for good price at local market.

The Government may take pragmatic steps to open cold storage chains, encourage orchard farming and cash crop cultivation, easy availability of loans & revision of minimum support price of Agri products for uplifting farmer's economic condition.

एडवोकेट प्रिया सरोज **(मछलीशहर)** : मैं उस अन्नदाता की बात रखना चाहती हूँ, जिनके खेत सूखे हैं, आँखों में आँसू हैं, और सरकार के वादों में सिर्फ झूठ का ढोल बज रहा है ।

खेत सूखे खड़े हैं, पर वादों की बारिश जारी है,

किसान के चूल्हे बुझ गए, मगर महलों में रौशनी सारी है ।?

गाँधी जी ने कहा था, 'भारत की आत्मा गांवों में बसती है । लेकिन अफसोस, आज इस देश के गांव, ये धरती के बेटे, आत्मा नहीं, अब बस संघर्ष का मैदान बन चुके हैं ।

भारत ने 21वीं सदी में बहुत प्रगति की, चाँद पर पहुँच गए, अंतरिक्ष में तिरंगा फहरा दिया, मगर किसान के आँगन में अब भी अंधेरे हैं ।

ये कैसी तरक्की है, जहाँ किसान की थाली खाली है?

ये कैसा विकास है, जहाँ किसान की झोली खाली है?

देश की 70% आबादी अब भी कृषि से जुड़ी है । किसान इस देश का पेट भरता है, लेकिन खुद कर्ज में डूबा है । देश के किसान धरती पर हल चलाते हैं, और आसमान की ओर देख कर बारिश माँगते हैं ।

सरकार कहती है, 'हम किसानों के साथ हैं?' । अगर सरकार साथ होती तो फिर 2022 में 11,290 किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? ये आँकड़ा नहीं, 11,000 चूल्हों का बुझना है । ये 11,000 परिवारों का टूटना है, और यह सब उस सरकार के राज में हो रहा है, जो 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देती है । लेकिन सच तो ये है, सबका साथ नहीं, बस अपने 'खास दोस्तों' का विकास ।

सरकार ने 3 काले कृषि कानून लाए ? किसानों को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर किया, ठंड में मरने दिया । लेकिन, सरकार ने चुनाव से पहले अचानक कानून वापस लिए ? क्यों? क्योंकि आपको किसानों की नहीं, सिर्फ वोटों की चिंता थी ।

बीजेपी को सत्ता में 11 साल हो गए । दुनिया के बड़े नेता 11 साल में अपनी छाप छोड़ देते हैं । लेकिन इस सरकार का क्या किया? 11 साल में किसानों के लिए क्या किया? पहले तो हर बात का ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ते थे ।

अगर 11 साल बाद भी आप अपनी नाकामियों के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, तो अब कोई पिछली सरकार नहीं बची, जिसे आप दोष दे सकें । अब जनता आपसे जवाब चाहती है । 11 साल बहुत होते हैं । इतने समय में दुनिया के बड़े-बड़े नेता इतिहास बना देते हैं, लेकिन आप अब भी बहाने बना रहे हैं । अब बहाने खत्म, हिसाब दो, किसानों को जवाब दो ।

अगर यह अवसर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मिला होता, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी होती । किसानों, महिलाओं, युवाओं और पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दी होती ।

आज आपकी नाकामी देखकर मुझे एक फिल्म का प्रसिद्ध डायलॉग याद आता है ? ?तुमसे ना हो पाएगा? । और सच मानिए, आपकी 11 साल की नाकामी देखकर यही कहना बनता भी है ।

Government that it is concerned about the farmers' condition in the country but it takes no action, whatsoever, to curtail their problems. Actions speak louder than words.

Government had the opportunity to showcase how much farmers mean to it, yet it has repeatedly proven that only the ultra-rich matter to it. There is no comprehensive loan waiver scheme for farmers, even though a parliamentary committee has recommended it.

What kind of governance is this, where a corporate loan is waived off overnight, but a farmer must beg for compensation after every

drought and flood?

मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से चुनकर आई हूँ, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण यहाँ की कमजोर कृषि व्यवस्था है। पूर्वांचल गेहूँ उत्पादन में प्रदेश में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन आज भी यहाँ के ज्यादातर किसान सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं।

इस क्षेत्र में न तो अच्छी मंडियों की व्यवस्था है और न ही खाद और बीज की सही आपूर्ति। बिचौलियों का बोलबाला है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है। खाद और बीज की कालाबाजारी भी आम बात हो गई है, जिससे किसानों को महंगे दामों पर खरीदारी करनी पड़ती है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस क्षेत्र में बेहतर मंडी व्यवस्था, सिंचाई के साधनों और खाद-बीज की उचित आपूर्ति की व्यवस्था की जाए, ताकि बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी जैसे जिलों के किसान अपनी सब्जियों और फसलों का सही दाम पा सकें। इसके साथ ही, किसानों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके, जिससे यह क्षेत्र भी कृषि के लिए एक मजबूत केंद्र बन सके।

Silence in this House becomes the loudest supporter of injustice. When a farmer hangs himself from a tree, the weight is not just on the rope, but on the conscience of this very House. Today I want to remind this House: ?When the farmer's spine bends, the nation's backbone weakens.?

मैं उत्तर प्रदेश, भारत के सबसे बड़े राज्य से आती हूँ, जहाँ की 66% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। जहाँ देश का 21% अनाज, करीब 11% फल और करीब 15% सब्जियाँ पैदा होती हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश, आज किसानों की आत्महत्या में 40% बढ़ोतरी देख रहा है। क्यों? क्योंकि, सरकार ?मन की बात? करने में व्यस्त है, लेकिन किसान के ?दिल की बात? सुनने का वक्त नहीं।

आपके नेता विदेशों में भाषण दे सकते हैं, लेकिन किसान की झोपड़ी में घुसने का वक्त नहीं।

आपका पूरा प्रचार तंत्र हवाई जहाज, बुलेट ट्रेन, डिजिटल इंडिया पर खर्च करता है, लेकिन खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं। लाखों टन अनाज उगाने वाले किसान के घर में रोटी क्यों नहीं? करीब 15% सब्जियाँ देने वाले यूपी के किसान खुद भूखे क्यों हैं? सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय आत्महत्या के लिए छोड़ दिया।

सरकार कहती है, 'जय जवान, जय किसान'। लेकिन जवान सीमा पर जान दे रहा है, और किसान खेत में। आज देश का किसान पूछ रहा है, 'क्या मेरी फसल से बड़ा कोई चुनावी मुद्दा है??' 'क्या मेरी जान से बड़ी कोई चुनावी जीत है??'

सरकार की नीतियाँ किसानों को राहत नहीं दे रही, बल्कि उन्हें और ज्यादा असुरक्षित कर रही हैं।

मेरी सरकार से मेरी माँग है कि:

किसानों को कानूनी MSP का हक मिले।

ऑनलाइन मंडी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए

सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया जाए,

बिचौलियों के शिकंजे से किसान को मुक्त किया जाए,

कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा मिले।

किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और सस्ता कर्ज मिले।

और किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए उन्हें आर्थिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा भी देनी होगी।

This budget has exposed the Centre's inability to comprehend the real issues plaguing the agricultural sector.

इस बार का बजट फिर से किसानों के लिए निराशाजनक रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। उचित दर पर खाद, बीज

और पानी भी नहीं मिल रहा है । कृषि उपकरणों को सस्ता करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन की मांग भी अनसुनी रह गई ।

I urge this Government to not just stand by few corporates who hoard profits, but to stand by the farmers who harvest hope. Because the day the farmer stops sowing seeds, this nation will stop growing dreams.

जब तक किसान की थाली भरी नहीं होगी, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा । जिस दिन किसान के हालात बदलेंगे, उस दिन भारत सच्चे मायने में विकसित होगा ।

अंत में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी --

?कहाँ ले जाओगे किसान के हक का दाना,

इस धरती को भी एक दिन है सबको छोड़ जाना ।?

SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE (DINDORI): I want to make following demands for the farmers who produce onions, grapes, sugarcane, soybean, vegetables and other crops in my Dinodori Lok Sabha constituency.

Onion Farmers-

- Minimum Support Price (MSP)- It costs an onion farmer approximately Rs. 1,500 to produce 1 quintal of onion. But, since the price of onion is continuously decreasing, a minimum support price should be announced.
- Rates planning and export policy- By removing restrictions on onion exports, export fees should be totally removed and the farmers should get remunerative price.
- Grant For Storage facility - Farmers should get subsidy for storing goods for themselves.
- The 'GST' on onion sales should be removed- The GST on goods required for production of onion or sale of onion produce should be

cancelled.

Grapes Farmers-

- Reducing production costs-

Fertilizers and pesticides are required to produce grapes. Even when the prices are very high of fertilizers and pesticides, GST is being charged. So the GST should be reduced.

- Encouragement to plant a new varieties of grapes -

Bring new varieties of grapes from abroad and make it available to the farmers at a low price.

- Export Facility - Remove the obstacles in grape exports and encourage for selling the produce in foreign market.

- Processing Sector promotion - For increasing the production of wine juice, dryfruits from grapes special grants should be given.

- Agricultural insurance plan- Grape growers should be protected from heavy rainfall, severe cold, hail storm and vagaries of weather.

Direct markets- ENAM or other digital platforms should be used for grapes sale.

Sugarcane Farmers-

-Reduce production costs - Grants should be given to fertilizers and irrigation equipments required for sugarcane production. GST should be waved off.

-Subsidy For Ethanol production- Ethanol Production should be given more subsidy and the sugar factories should be encouraged to produce it.

-Sugar sales policy-

Customers should be given sugar at low rates through ration cards and sell the remaining sugar stock in open market. So, the factories will be saved and the FRP can be given. Kindly look into this matter.

India is an agricultural country and the global recession in the world has hit many countries the farmers in the agriculture sector saved our country. The agricultural sector is providing employment to the people of the country.

Due to agriculture, our country is on the path of prosperity and progress. But the farmer is facing many problems. More than ten farmers are committing suicide daily, this is very unfortunate. Agriculture and farmers should prosper. The policies of the government should be in the favour of farmers.

- Production cost is increasing due to inflation. But farmer is not sure about the price he will get for his crop. Government should look into this matter.
- There should be a provision of rate fixation while deciding the export policy for onion, grapes, soybeans, cereals, cotton etc.
- By using the revenue of agriculture department and modern technology, the policy should be determined to take into account the number of crops and how much it needs.
- Dams and canals should be constructed to cover cultivation areas under the water.
- Farmers should be provided with seeds, fertilizers, pesticides, and technological upgradation at affordable prices.

- To increase irrigation coverage, drip irrigation scheme should be promoted.
- The number of various agricultural laboratories and agricultural colleges should be increased. Latest AI technology should be used for it.
- Organic farming should be encouraged for poison -free crops.
- Agriculture supporting and agricultural processing industries should be promoted.
- The entire outstanding loan of the farmers should be waived off. And fresh loan should be provided at cheaper interest rates.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): I feel it an honour for this opportunity to express my views on the Demands of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Before I start, I thank my leader, Shri Pawan Kalyan, who has given me this opportunity to represent Machlipatnam.

We are happy and, I am sure, hon. Minister is also happy for getting allocation of Rs. 1.37 lakh crore for 2025-26 - an increase of four per cent over the BE of 2024-25. This Budget helps the Government to double farmers' income and take up other welfare measures for farmers. As a representative from AP, I am particularly happy to see that this Budget addresses the concerns of our Annadatas through various schemes and programmes.

As we know almost 60 per cent of our population is dependent on agriculture and its related activities. Despite the initiatives taken by our Government, there are so many issues that yet need to be address. I would like to mention here and congratulate ICAR - Indian Council for Agriculture Research that has developed 109 high-yielding, climate-

resilient, and bio-fortified varieties of crops. What makes this achievement special, Sir, is that these varieties are not only high-yielding but also pest-resistant reducing ? a major factor in crop loss. Moreover, these are naturally bio-fortified meaning they already contain essential micronutrients and macronutrients, eliminating the need for separate fortification.

With these scientific advancements, we are not just ensuring food security but also nutrition security, while promoting sustainable agriculture and enhancing farmers' income. Here, I would like to request the Government that these initiatives may please be promoted among the farmers. A team of Agriculture Ministry should visit every district of the country. Farmers are not getting good quality seed and fertilizers. That is needed to be assured. Farmers' full grown crops get destroyed either because of untimely rains or drought during summers. Although it is not fully in one's hand but technical guidance to farmers can help the farmers to grow crops accordingly. The Government should guide them and support them. Accordingly, insurance support to farmers in case of crop loss shall be extended at the earliest without any delay.

A very important factor is financial support; Although there are multiple Government schemes but bankers are not supporting them positively. This needs to be assured. There are many loopholes in the system and that need to be addressed.

One important issue which I have raised on multiple occasions in Parliament is supporting our tenant farmers. There is no clear definition for tenant Farmers in the country because of which they are suffering a lot. The allocation under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme has been increased to Rs. 63,500 crore. I thank the hon. PM for releasing 19th Installment of PM-KISAN recently and so far the

Government of India spent more than Rs. 3.6 lakh crores. But the point is PM-KISAN Samman Nidhi and other schemes help only agriculture landowners and not tenant farmers who constitute 17.3 per cent as per NSO's latest figures and AP has highest (42.4 per cent) followed by Odisha (39 per cent) and West Bengal (29.5 per cent).

Secondly, GOI is giving PM-KISAN Samman Nidhi to only 9.5 crore farmers against the original estimated Rs.14.5 crore in 2019. It means, five crore left out farmers are tenant farmers and more than two crore tenant farmers are from AP alone. So, I appeal to the hon. Agriculture Minister and also hon. FM and PM to consider extending PM-KISAN Samman Nidhi to these five crore left out tenant farmers.

Thirdly, no doubt, Government of India is giving credit and insurance under KCC, PMFBY, RWBCIS. But, there are still challenges. Some of them are relating to documentation under KCC and enrollment is contingent on State-specific land record documentation which excludes a large number of tenant farmers. So, I appeal to the hon. Agriculture Minister to have some holistic, comprehensive and concrete approach for the benefit of tenant farmers

The second point I wish to make is relating to Agriculture Infrastructure Fund which has got Rs. 900 crore which is 50 per cent more for 2025-26. This has really helped in post-harvest management infrastructure across the country. Sir, AIF aims to disburse Rs. one lakh crore between 2020-21 and 2025-26. But, so far only Rs. 58,000 crore have been sanctioned in the first about five years and there is only one year left. So, I suggest for consideration of the hon. Minister to pay more focus on this scheme since it directly benefit the farmers. With 50 per cent increase, I am sure, it will really help in creating more and better infrastructure in the country in the coming years. The Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) is

another scheme which has got Rs. 8,500 crore, an increase of 12.5 per cent from BE 2024-25 and 42 per cent from RE 2024-25. Similarly, Krishionnati Yojana has received Rs.8,000 crore, an increase of 7.5 per cent from BE 2024-25. These investments will create the backbone for a modern agricultural ecosystem, benefiting farmers all over the country.

NAMO Drone Didi scheme has received Rs.676.85 crore. The increase of 170 per cent from RE 2024-25 is truly encouraging. The objective to empower 15,000 Women SHGs with drone technology. Government of India has so far given about 100 Drones to AP which is very less. Sir, Government of AP has recently unveiled Drone Policy 4.0 which will help a lot in creating not only ecosystem but also making Drones available for Drone Didis. So, I suggest the hon. Minister to take advantage of this and provide more and more Drones to SHGs in AP.

AP is the leader in natural farming and the Ministry getting Rs. 616 crore for National Mission on Natural Farming. It reflects as to how this Government is serious on natural farming. So, this Government is giving everything possible to push natural or organic farming. But, all I appeal to the hon. Minister is to further encourage States like AP, HP, Gujarat, Kerala, Sikkim, etc., which are leaders in natural farming to become growth engines of agriculture.

My JanaSena Party welcomes new initiatives to deal with sectoral challenges. Rs. 1,000 crore has been allocated for new Mission for Pulses and it will definitely boost domestic production and reduce imports. Taking advantage of this, I wish to submit that Government of AP started giving tur dal through PDS to poor. It is also planning to provide Millets, etc., through PDS. So, I appeal to the hon. Minister to help the State in this regard which helps to achieve twin objectives of

providing nutritious food to poor and also bringing down import of pulses thereby save foreign exchange.

It is good that you are giving Makhana Board in Bihar. We have no problem. But, there have been demands to set up Turmeric Board in Andhra Pradesh. But, there is no mention about this in the Budget or there is no move by the Ministry on this for the last many years. So, I appeal to the hon. Minister to consider this positively.

I am pleased to highlight the tremendous potential to build upon our Government's visionary BhoomiHeen Kisan initiative. The hon. Prime Minister's foresight has already led to remarkable progress, with Rs. 41,487.61 lakh successfully disbursed to 116,112 Joint Liability Groups in Andhra Pradesh during 2021-22. It is a testament to our commitment to inclusive agricultural growth. To further amplify this success, I propose that we should enhance our data collection on tenant farmers, which would enable our Government to extend the benefits of our flagship schemes even more effectively.

The strengthening of Joint Liability Groups and strategic adjustments to priority sector lending sub-targets would perfectly complement the Government's farmer-first approach, particularly benefiting states like Andhra Pradesh where tenant farming is prevalent. These refinements would advance our shared vision of ensuring that every farmer, regardless of land ownership status, participates in our nation's agricultural prosperity under the visionary leadership of our Prime Minister.

Lastly, although linkage of rivers is not directly concerning the Department of Agriculture and Farmers Welfare, it is a key factor. Your Department should coordinate with the Ministry of Jal Shakti and facilitate our Farmers for irrigation activities.

With these submissions and hoping that the hon. Minister will look into the issues I have raised seriously, I support the Demands of the Ministry. Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Just days before the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture, Maharashtra was shaken by the tragic suicide of Kailash Arjun Nagre, a young, award-winning farmer from Buldhana district. Mr. Nagare was not an ordinary farmer—he was celebrated for his progressive practices, recognized for his model farming techniques, and held up as a success story. Yet, behind the accolades lay mounting debts, price uncertainties, and systemic neglect that ultimately claimed his life. His story is not an aberration; it mirrors the daily struggles of millions of farmers across India, who find themselves trapped in a cycle of rising input costs, unstable incomes, and broken promises.

In the Budget speech, the hon. Finance Minister declared agriculture to be the "first engine of growth" for the Indian economy and expressed hope that India would become the food basket of the world. Yet, as we examine the fine print of this Budget, it becomes painfully clear that the Government continues to ignore the basic, long-standing demands of the farming community. Farmers have been pleading, year after year, for a legal guarantee to MSP, a comprehensive farm loan waiver, a universal pension scheme, and protection from hikes in electricity tariffs. Instead, what we see are incremental allocations and headline schemes, without addressing these structural issues at the heart of agrarian distress. The disconnect between the Government's proclamations and the ground realities in villages like Kailash Nagre's could not be more stark.

India's agricultural sector is in the grip of a persistent and multifaceted crisis, exacerbated by policy stagnation and inadequate structural

reforms. While agriculture continues to employ 46 per cent of India's labour force, its contribution to the national Gross Value Added (GVA) languishes at just 16 per cent. Despite multiple Government schemes, the sector's growth has remained erratic, averaging only 3 per cent annually, while the overall economy has grown at 7 per cent per year. This widening gap reflects systemic neglect in addressing core issues like low productivity, over-dependence on monsoons, and fragmented landholdings. The crops sub-sector, which forms the backbone of Indian agriculture, has grown at a mere 2.1 per cent annually between 2011-12 and 2022-23, even as allied sectors saw healthier growth. Yet, Government policy continues to focus disproportionately on flagship schemes like PM-KISAN transfers, offering a meagre 2500 per month, rather than investing in comprehensive rural infrastructure or structural reforms.

Compounding the problem, agricultural productivity in India remains significantly lower than global standards. For example, in 2022-23, the average yield for paddy in India was 4,229 kg/hectare, well below the world's highest of 7,080 kg/hectare, and for wheat, India's yield stood at 3,537 kg/hectare, a stark contrast to the global high of 8,590 kg/hectare. This crisis is compounded by Government-driven policy distortions and chronic underinvestment in critical areas. For instance, 86 per cent of India's farmers cultivate on holdings smaller than two hectares, yet the Government's institutional credit and mechanization policies largely fail to reach these smallholders. The average monthly income of an agricultural household touched Rs 10,218 by 2019, but a staggering 40 per cent of this low income came from wage labour, not agriculture itself. This income, in combination with very high rates of indebtedness, makes it difficult for farmers to survive.

According to a study by the OECD on the world's 54 major agriculture economies, only Indian farmers have continued to cultivate losses, year after year, ever since the study began in the year 2000. Crop losses in other countries were covered with subsidy support. While farmers in only two other countries, Vietnam and Argentina, also incurred losses, these were covered by Government subsidies, meaning only India's farmers face a crisis of this nature.

The budget allocation for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare for FY26 stands at Rs 1.37 lakh crore, a slight decrease from the revised estimates of Rs 1.41 lakh crore in FY25. This reduction translates to just 2.7 per cent of the total budget expenditure. Such a decrease indicates that the Government has failed to recognise the urgency tackling the deeper issues plaguing the agricultural sector.

The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has faced some of the largest cuts. The Centre has claimed that more States have joined this scheme, yet in the last revised estimates, the scheme received Rs. 15,864 crore while in this budget, the allocation is Rs. 12,242 crore—a reduction of Rs. 3621 crores.

The fertilizer subsidy has also been reduced from Rs 1.83 lakh crore in FY25 to Rs. 1.56 lakh crore for FY26. According to NABARD, input costs have risen by over Rs 4,000 per acre in Maharashtra over the last two years alone. In combination with the fact that the Government continues to levy GST on fertilizer, despite farmers' fervent requests that it receive an exemption, and that India imports around 80 per cent of its natural gas for urea production, making the cost of fertilizers vulnerable to fluctuations in global gas prices, this reduction in the subsidy could further jeopardize farmers' razor thin profit margins.

The Parliamentary Standing Advisory Committee on Agriculture has for a hike in PM-KISAN from the existing Rs. 6,000 to Rs. 12,000 per year, reinforcing farmers' long-standing demands that PM-Kisan payouts be indexed to inflation, but we have little reason to hope for these recommendations to be implemented, as the budgetary support for the scheme remains stagnant at Rs. 63,500 crores.

The Government has allocated Rs. 7100 crore to establish Makhana Board in Bihar to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. Given that a National Research Centre for Makhana has existed under the ICAR Research Complex for Eastern Region (ICAR-RCER) in Darbhanga, Bihar since 2002, one must wonder whether such a performative gesture that pulls valuable resources away from critical schemes is fiscally prudent in a time of crisis such as this.

Another looming threat that has not been addressed adequately in the Budget is the potential impact of increasing US tariffs on Indian agricultural exports. President Trump recently signed a Presidential Memorandum proposing the imposition of reciprocal tariffs to counter foreign trade barriers on US goods, and has made it clear that India will not be exempt from these reciprocal tariffs. There is currently a large gap between India and America's tariffs on each other's products, particularly in the agricultural sector.

India's simple average agricultural tariff stands at 39 per cent, and the trade-weighted average is 65 per cent, while the US maintains a simple average agricultural tariff of 5 per cent and a trade-weighted rate of 4 per cent.

According to a recent report by the Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), the imposition of reciprocal tariffs on Indian agricultural produce could have a range of impacts. Key

exports such as frozen shrimp, basmati rice, and natural honey could become significantly less competitive in the American market. Targeted tariff hikes on specific products, such as dairy and processed foods, could severely impact India's value-added agricultural exports. Additionally, the US could impose stricter sanitary and phytosanitary (SPS) regulations or licensing requirements, increasing compliance costs and delaying shipments for Indian exporters.

These developments would leave our farmers, many of whom are already under great financial strain and heavily dependent on exports, vulnerable to slipping into a crisis. Yet, there is no mention in the Budget about a contingency framework to cushion our exporters against such shocks?no special incentives for diversification, no increase in corpus of the Price Stabilization Fund to offset global price crashes, and no push for new Free Trade Agreements with alternative markets.

One of the most pressing demands echoing from every mandi, village, and farm across Maharashtra and much of India is the call for a legal guarantee to Minimum Support Price (MSP). The Government must recognize that announcements of MSP rates without statutory backing have little meaning when procurement mechanisms are weak, market prices fluctuate far below MSP, and farmers remain at the mercy of middlemen and volatile markets. This is especially true for soyabean, onion, and cotton, which are critical to Maharashtra's agrarian economy.

In the 2023-24 crop year, soyabean was cultivated on over 40 lakh hectares in Maharashtra, making the State the largest soyabean producer in India. Yet, market prices for soyabean have routinely crashed below MSP, sometimes by as much as 8500-700 per quintal, particularly during peak harvest season, due to lack of effective procurement and glut conditions. In the absence of a legal MSP guarantee, farmers are

forced to engage in distress sales, with no credible alternative buyer ensuring a fair price.

Similarly, onion farmers in Nashik and Ahmednagar, year after year, face brutal price crashes. In 2023, onion prices fell to as low as \$4-6 per kg at farmgate, even as retail consumers paid 725-30 per kg. Without an MSP safety net or structured market intervention, thousands of onion farmers have been pushed into debt traps. The Market Intervention Scheme (MIS), which could have cushioned such shocks, has been grossly underutilized and inconsistently applied, as evident from negligible allocations in this year's Budget.

Cotton is the lifeline of millions, yet official procurement at MSP covers barely 25-30 per cent of total production. Last year, Maharashtra's cotton prices plunged by 12 per cent, triggered by global price dips and lack of procurement infrastructure. The much-publicized Cotton Technology Mission has received a token allocation of *500 crore this year, but it is grossly insufficient to address the crisis of scale facing cotton cultivators in the absence of legal status of MSP, leaving cotton farmers vulnerable to exploitation by traders and international market fluctuations.

The Government's announcements to fix MSP at 1.5 times the cost of production have not translated into guaranteed incomes, simply because there is no statutory compulsion for the market or Government agencies to procure all eligible produce. A legal guarantee of MSP would assure farmers of a minimum monthly income, particularly for crops which are prone to price volatility. For millions of small and marginal farmers across India, this would be a matter of survival, not merely a change in policy.

A critical issue that has received little attention in this year's Budget is the Government's erratic approach to agricultural exports. Time and again, sudden export bans and restrictions are imposed without a transparent,

data-driven policy framework. While ensuring adequate domestic reserves is undoubtedly essential for food security, it is equally important to allow exports after reserve thresholds are secured, especially to safeguard farmers' incomes and India's credibility as a global supplier. We need only look at the recent experience of farmers in Maharashtra to understand the grave consequences of this ad-hoc approach.

In 2022-23, Maharashtra's onion farmers suffered tremendously due to abrupt export bans. Despite a bumper harvest, the Government imposed a ban on onion exports to control retail inflation. This led to a massive glut in the local markets, crashing wholesale prices to as low as ₹4-6 per kg, while farmers' input costs had soared due to rising fertilizer, labour, and transportation expenses. Farmers were forced into distress sales, unable to recover even their basic costs. The Government's intervention to procure a fraction of the produce was too little, too late.

The sugar sector has faced similar uncertainty. In 2023, restrictions on sugar exports citing stockpiling concerns were imposed despite record production levels. Many sugar mills dependent on export revenues and struggled to clear pending payments to sugarcane farmers. Mills had signed contracts in anticipation of export opportunities, only to have them rendered void overnight, damaging both farmer earnings and India's standing in global trade.

I strongly urge the Government to move away from this reactionary export policy. If we truly want to make India the "food basket of the world," our farmers must have access to global markets, not just as a privilege, but as a right-after safeguarding domestic needs.

Countries that have succeeded in transforming their agricultural sectors have done so by investing heavily in research, mechanization, extension, and innovation ecosystems. India cannot hope to double farmers'

incomes or ensure food security without placing agricultural R&D at the heart of its policy strategy, particularly as we confront challenges of stagnant yields, erratic weather patterns, pest outbreaks, and the growing threat of climate change.

Yet, year after year, the Government's interventions in this regard are confined to token announcements with inadequate funding. For 2025-26, the Department of Agricultural Research and Education has been allocated only Rs 10,466 crore, a mere 3.1 per cent increase over last year. Shockingly, this accounts for only 7.6 per cent of the total budget of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, despite research and extension being the backbone of long-term agricultural growth. Moreover, allocations for frontline institutions like Krishi Vigyan Kendras, tasked with last-mile delivery of scientific advice to farmers, have been reduced—from Rs 234 crore last year to Rs 204 crore this year.

Without investment in developing region-specific, climate-resilient, pest-resistant crop varieties and efficient agronomic practices, we are condemning our farmers to low incomes and vulnerability. Maharashtra, facing recurrent droughts, pest attacks like pink bollworm on cotton, and soil degradation, needs urgent research-driven solutions. Yet, there is no special push to strengthen agro-climatic research in such high-risk zones.

While Maharashtra's farmers grapple with rising debts, unpredictable incomes, and systemic neglect, shocking reports of corruption within the State's Agriculture Department have added insult to injury. Just days before this Budget was presented, anti-corruption activists brought to light a staggering 788 crore scam allegedly perpetrated under the leadership of Maharashtra's Agriculture Minister.

It has come to light that the department procured several lakh bottles of nano urea and nano DAP fertilizers at inflated prices without conducting any proper tendering process. The procurement price per bottle stood at Rs 92 and Rs 269 respectively, against open market rates of Rs 220 and Rs 590-a blatant overpricing that defrauded public funds.

What makes this scam especially heinous is not merely the financial malpractice but its direct impact on farmers. In a State where farmers are driven to suicide under crushing debt burdens, siphoning off crores meant for essential agricultural inputs is not just corruption - it is a betrayal. Every rupee misappropriated is a rupee denied to a farmer struggling to afford fertilizers, seeds, or basic irrigation.

Unfortunately, this is not an isolated incident. Just as disheartening is the recent exposure of a massive 85000 crore scam under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)-a scheme specifically designed to offer security to farmers against crop loss.

This scam came to light on 19 December 2024, when a sitting BJP MLA from Maharashtra raised serious allegations of widespread fraud in the implementation of PMFBY. According to the MLA, in villages like Ramapur Thanda, Udgir, crop insurance claims were made for over 4,000 hectares, despite the village not possessing even a fraction of that cultivable land. Such blatant inflation of claims exposes how corrupt networks have manipulated data to siphon off funds intended for genuine beneficiaries.

Following this revelation, on 21 December 2024, the Chief Minister publicly admitted to what he termed a "new Beed Pattern" scam and assured that an investigation would be conducted.

Shockingly, the Agriculture Minister, in a statement made on 21 January 2025, confirmed the validity of the BJP MLA's claims and admitted that irregularities and fraud had indeed occurred-but conveniently blamed them not on Government officials, but on private Common Service Centres (CSCs).

However, the scale of the scam, as highlighted by the same MLA on 22 January 2025, is far beyond what the Government appears willing to acknowledge. He asserted that the fraud may total a staggering 25000 crores, revealing glaring loopholes in monitoring and oversight. He cited the example of a single farmer allegedly obtaining crop insurance in eight different districts ? a logistical impossibility, laying bare the depth of the administrative failure.

This scam is not merely a case of financial impropriety-it is an outright betrayal of Maharashtra's farmers, who pin their hopes on crop insurance during years of drought, pest attacks, or unseasonal rains. Instead of providing relief, the scheme has been hijacked by profiteers exploiting systemic weaknesses, leaving genuine farmers to face delays, rejections, and harassment when they file legitimate claims.

A sitting MLA has alleged that Maharashtra's recently-resigned Minister of Food, Civil Supplies & Consumer Protection, during his earlier term as Minister of Agriculture, orchestrated a scam in which 5141 farmers were lured to deposit Rs 8 lakhs each with the promise of a Rs 36 lakh subsidy for a sugarcane harvester, In reality, however, harvester machine subsidies were to be provided only to 141 farmers for 141 machines. Thousands of farmers were thus duped of several crores of rupees.

These incidents exemplify how governance failures, lack of transparency, and absence of robust accountability mechanisms continue to deepen the agrarian crisis. They raise grave concerns about whether the funds

allocated in this Budget-whether for fertilizers, crop insurance, or research-will genuinely reach farmers or be lost to similar malpractices.

The Government must institute independent inquiries into these irregularities, bring those responsible to justice, and implement stringent reforms to ensure procurement and distribution processes in the agriculture sector are transparent, accountable, and corruption-free and implement robust reforms to close loopholes in PMFBYs administration. Otherwise, no policy or budget allocation, however well-intentioned, will truly serve the interests of India's farmers.

While the nation grapples with these crises, there is a silent revolution unfolding in Baramati-one that offers a beacon of hope for the future of Indian agriculture. Baramati has become a model for how cutting-edge technology, when harnessed responsibly, can empower farmers, boost productivity, and make agriculture climate-resilient.

Over the last few years, Baramati has pioneered the integration of Artificial Intelligence in farming practices, in collaboration with Microsoft's FarmVibes.AI platform. This initiative-one of the first of its kind in India-has been rolled out in partnership with the Baramati Agro cluster, Oxford University researchers, and local Farmer Producer Organisations (FPOs).

Through AI-driven tools, farmers in Baramati are now able to access real-time insights on optimal sowing times, weather patterns, pest outbreaks, and irrigation schedules. Satellite imagery, sensor data, and predictive models are being deployed to guide small and marginal farmers in making informed decisions that directly improve their yields and reduce input costs.

Take the case of sugarcane farmers in Baramati-traditionally vulnerable to erratic weather and pest infestations. Using AI models, they now receive customized advisories on when to apply fertilizers, how to manage water efficiently, and how to prevent pest attacks like the early shoot borer. Preliminary data shows that such interventions have resulted in a yield increase of up to 30 per cent and input cost reductions of nearly 15 per cent.

What is more heartening is that this technological transformation is not limited to large landowners. Over 3,000 small and marginal farmers-many cultivating on less than two hectares-have benefitted from training sessions, mobile-based advisories, and access to AI-generated insights, ensuring that the digital divide does not exclude those who need support the most.

Baramati's experience proves that if we invest in farmer-centric innovation, guided by transparency and community participation, we can unlock the true potential of Indian agriculture. I urge this Government to study the Baramati model, scale such interventions nationwide, and allocate dedicated funds for integrating AI and emerging technologies into the broader agricultural strategy-especially for climate-vulnerable and resource-poor regions.

SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR): I would like to raise issues of the agriculture sector which is the backbone of the Indian economy. India has a large number of agriculture and agro-based industries. But, the situation of farmers is very miserable. If the country's economy survives, the economy will be strengthened. But, during the last 10 years, the condition of farmers has become pathetic, because no MSP has been given to agriculture produces.

I would like to demand that farmers should be given a guaranteed price. Due to discontinuation of cotton purchase by CCI, cotton is lying in the houses of many farmers. My request is that till the last farmers' cotton is sold, the cotton buying centers should be kept open. Along with that, I request you to increase the number of cotton buying centers. In my Lok Sabha constituency Chandrapur and Yavatmal districts, the rate of farmer suicides is very high. So, I am demand that the Union government should take necessary measures to prevent farmer suicides. Similarly, loans should be made available for agriculture-based industries for the benefit of farmers.

Government of Maharashtra had promised loan waiver. But, still the farmers have not got the loanwaiver So, I request you to waive off the loans of the farmers of Maharashtra through the central government. Sir, crops insured through Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. But, unfortunately, the farmers are not getting the crop insurance money even after a year. I request you to order the concerned companies to pay the crop insurance amount immediately.

As many villages in my Lok Sabha constituency are covered with forest, wild animals are causing huge damage to farmers' crops. So, I request you to include the damage caused by wild animals in the crop insurance scheme. Due to the lack of space for the farmers to store their crops, the crops are often damaged due to natural calamities. So, I would like to request the government that the government should start the warehousing scheme in every village.

Many farmers are provided with substandard seeds and pesticides required for agriculture. Strict action should be taken against companies selling such duplicate seeds. I demand that land rights should be

transferred to the farmers who are cultivating the government lands for generations together in many villages in my Lok Sabha constituency.

I request the Government to provide large amount of funds to promote agriculture based industries to enrich the lives of farmers. Lastly, I would like to request that the government should take a positive approach regarding all the demands and consider it sympathetically.

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): Agriculture employs nearly half of the India population. Yet, the Modi Government has slashed the Agriculture Ministry's budget share from 4.69 per cent in 2020-21 to just 2.72 per cent in 2025- 26. Since 2018-19, agricultural growth has stagnated at an average of 18 per cent exposing the failure of the Government policies. The average farm household earns just Rs. 13,661 per month, while 55 per cent are trapped in debt. In the last 10 years till 2022, more than one lakh farmers have committed suicide. Yet the Government has not disclosed the full data. Farm labourers, often from SC and ST community and other disadvantaged groups face low wages, lack of social security, proper working conditions but are not adequately represented in policies.

There was no mention of Swaminathan Report in the Finance Minister's speech as well as there was no mention of legal guarantee of MSP to the farmers. It still remains a fact that under the PMFBY the private insurance companies benefit from the same and not the farmers. Most of the Government schemes focus on the land owning farmers, not on the tenant farmers, the landless labourers, the women who toil on the lands. This should be reconsidered at the earliest.

श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : वर्तमान में किसान कई गंभीर मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जिनमें फसलों का उचित मूल्य ना मिलना, बढ़ता कर्ज, बदलते जलवायु के कारण फसलें बर्बाद होना और कृषि कानूनों में बदलाव शामिल है । इससे किसान बर्दहाल है ।

इस समय बसंत कालीन फसलों की बुआई चल रही है । फसलों की बुआई के लिए खाद, बीज एवं सिचाई के लिए बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है । फसलों की लागत बढ़ रही है, उपज का बाजिव मूल्य नहीं मिल रहा है । किसान हताशा, निराश, परेशान एवं आत्महत्या के लिए मजबूर है । हाईवे और इंडस्ट्री के चक्कर में किसानों की जमीनों को नीलाम, उनका अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी फैल रही है और किसान मजदूर बनता जा रहा है और देश लेबर कंट्री की तरफ बढ़ रहा है ।

किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिलने के कारण KCC जमा करना मुश्किल हो रहा है । आवारा जानवरों की संख्या बढ़ने के कारण किसानों की फसल भी नष्ट हो रही है और दुर्घटनाएँ भी बढ़ रही हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्र है । पिछले 7 वर्षों में मात्र 55 रूपया गन्ने का दाम बढ़ाया गया है, जो नाकाफी है । वर्तमान में इसका रेट 370 है, इसे बढ़ाकर कम-से-कम 450 रूपया किया जाये ।

किसानों की दयनीय हालत को देखते हुये उनका कर्ज माफ किया जाए । कृषि यंत्रों पर जो जी.एस.टी. लगाया गया है, उसे खत्म किया जाये ।

इस वर्ष 2025-26 के लिए केन्द्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रूपया निर्धारित किया है, जो आज के मंहगाई के दौर में बहुत कम है । गेहूं मूल्य कम से कम 3,000 रूपया किया जाये तथा घटतोली पर रोक लागई जाये । वहीं देश में खाद्य तेलों और दालों की भारी कमी है । इसके लिए हम विदेशों से आयात पर निर्भर रहते हैं । इन दोनों खाद्यानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए । सरसों का समर्थन मूल्य 5,950/-, मसूर का 6,700 और चने का 5,650/- रूपया प्रति कुंटल है, जो किसानों के लिए बहुत कम है । इन फसलों को उगाने के लिए खाद, बीज, रोग नाशक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवा बाजार में मंहंगी आती है । किसान को आपके द्वारा निर्धारित मूल्य लागत के अनुपात में काफी कम है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 को मिलेट वर्ष के रूप में मनाया । पूरे प्रदेश में किसानों को बीज वितरण कर बुआई के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन फसल तैयार होने पर किसानों को बाजार में बेचने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे मिलेट किसान अपने उत्पाद को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं । मान्यवर, मेरे लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद में आलू, मटर, टमाटर और आम के प्रोसेसिंग प्लांट लगाये

जायें, जिससे कि किसानों को अपनी फसल का वाजिब दाम मिल सकें, उसकी खपत हो सके और क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें ।

मेरा निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाये । किसान आंदोलन में करीब 700 किसान शहीद हुये थे, लेकिन अब तक किसी को कोई मुआवजा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं मिला है । मैं सरकार से मांग करती हूँ कि शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा एवं रोजगार देने का कष्ट करें ।

SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): I would like to present my views on the Demand for Grants for Agriculture and Farmers? Welfare for the financial year 2025-26. Agriculture, the backbone of this country, continues to be neglected by the Union Government, which offers lofty rhetoric but fails to back it with tangible support. The budget allocation for the Ministry of Agriculture and Farmers? Welfare stands at Rs. 1,37,757 crore, a 2.5 per cent decrease from the revised estimates of 2024-25. While the Government claims to be prioritizing farmers, this cut exposes the stark reality of its commitment. Farmers are the most vulnerable section of our economy, facing unpredictable weather conditions, rising input costs, and fluctuating market prices. Instead of supporting them with increased investments, this Government has chosen to reduce its spending, making it clear that agriculture is not its priority.

Tamil Nadu has taken a proactive approach to protect farmers despite facing discriminatory fiscal policies by the Centre. The State has consistently invested in irrigation, crop diversification, and farmer welfare programmes. While Tamil Nadu contributed 9.21 per cent to India's GDP, its share in tax devolution has been a mere 4.08 per cent, a blatant injustice to a State that has long been a leader in agricultural and industrial development. Our hon. Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, has spearheaded key initiatives such as the Tamil Nadu Mission for Sustainable Agriculture, smart irrigation projects, and a State-level

procurement mechanism to support small and marginal farmers. However, the Union Government has failed to extend its share of support in these schemes, forcing Tamil Nadu to bear the entire burden. This consistent neglect by the Centre has left Tamil Nadu to fend for itself, placing additional pressure on State resources.

The PM-KISAN allocation remains stagnant at Rs. 63,500 crore, despite inflationary pressures and increased cost of inputs. Further, the allocation for the Crop Insurance Scheme has been slashed by 23 per cent, showing the Union Government's blatant disregard for farmer security. Tamil Nadu has suffered particularly in MSP procurement. The procurement of pulses, millets, and oilseeds under PM-AASHA is insufficient, leading to low farm incomes and distress sales. The Centre's Mission for 'Self-Reliance' in pulses does not include any firm commitments on higher MSPs, direct procurement, or State-level interventions, making it another hollow announcement. The failure to ensure proper procurement mechanisms has left farmers struggling to secure fair prices for their produce. The State's efforts to support small and marginal farmers through its procurement schemes should have been complemented by the Centre, but instead, Tamil Nadu is forced to shoulder this burden alone.

The Union Government continues to make grand announcements with little substance. The newly introduced PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana claims to support 100 low-productivity districts with Rs. 100 crore allocated for high-yield seed development. However, given India's vast agricultural sector, this is a mere pittance. Additionally, the failure to adequately increase the Kisan Credit Card (KCC) credit limit in real terms has left small farmers struggling for working capital. Agricultural growth in India remains volatile. In 2023-24, the sector contributed only 16 per cent to GDP while employing 46 per cent of the labour force. The overall

economic growth has far outpaced agricultural growth, widening rural distress and income inequality. The Government claims that agriculture is one of its four engines of growth, yet its budgetary allocation does not reflect this commitment. If agriculture is truly a priority, why are farmers being left behind with inadequate support and declining incomes?

Tamil Nadu, being a water-stressed State, has repeatedly requested increased allocations for interlinking rivers, micro-irrigation, and groundwater recharge projects. The Centre's neglect in addressing the Cauvery water dispute and failure to support critical irrigation projects have left our farmers at the mercy of unpredictable monsoons. The Rs. 500 crore allocation for horticulture is too little to effectively implement sustainable agriculture measures. The failure to invest in irrigation infrastructure has exacerbated water shortages and increased dependency on erratic rainfall, further endangering food security. Tamil Nadu has demanded an enhanced MSP for paddy, millets, and pulses, increased procurement under decentralized procurement schemes, and greater funds under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY). However, the Centre has chosen to ignore these concerns. The State's ambitious Agricultural Infrastructure Development Programme has received no Central support despite repeated requests. Farmers in Tamil Nadu are struggling to sustain themselves due to high input costs, poor market linkages, and a lack of investment in post-harvest infrastructure. Without adequate financial support from the Centre, the State Government is doing everything in its power to protect farmers, but this should not be a one-sided effort.

While the Government boasts of high GDP growth, farmers' income remains stagnant. The average monthly farm household income has increased by just 59 per cent in the last decade, whereas industrial and service-sector wages have risen far more rapidly. The Centre's over-

reliance on corporate agribusiness and contract farming policies is pushing small farmers into economic peril. The allocation to agricultural research and education has seen only a marginal increase of 3.1 per cent, which is inadequate given the challenges posed by climate change, pest outbreaks, and falling soil fertility. The much-hyped National Mission on High-Yield Seeds has been allocated a mere Rs. 100 crore, showing that the Government lacks any serious vision for agricultural transformation. Research and innovation are crucial for improving productivity and sustainability in agriculture, yet the Union Government has once again failed to prioritize this essential sector. Tamil Nadu has long been a leader in agricultural research and innovation, yet it receives little recognition or support from the Centre for its efforts.

Tamil Nadu has led the way in farmer welfare despite being continuously denied its rightful share of tax devolution and Central funds. The Union Government's neglect, inequitable policies, and budgetary cuts have pushed farmers further into distress. There must be an increase in MSP for pulses, millets, and oilseeds to ensure fair remuneration. Full restoration of funds under PM-Fasal Bima Yojana is needed to cover climate risks. Fair tax devolution to Tamil Nadu is required to address the unjust revenue-sharing formula. Increased investment in irrigation, climate resilience, and sustainable farming is essential. Without these corrective measures, India's farmers will continue to face economic hardships.

The Government must act now before the agricultural sector plunges into deeper crisis. Tamil Nadu's model of farmer-centric policies, sustainability, and technological advancement should be recognized and supported by the Union Government. Instead of neglecting the State, the Centre should learn from Tamil Nadu's success and work collaboratively

to improve agricultural productivity, ensure food security, and enhance farmer incomes across the country.

Thank you.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (KAZIRANGA): I hereby support the Demands on Grants for the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare of 2025-26.

Under the dynamic leadership of Shri Narendra Modiji as Prime Minister of our country, the Ministry of Agriculture fulfils the demands of the farmers which are called "Annadata" for our country. As all are aware that under the dynamic leadership of Shri Narendra Modiji the following schemes are introduced and executed, namely, PM KISHAN, PM-KMY, PM-FBY, MISS, AIF, formation and promotion of new 10,000 FPOS, National Bee Keeping and Honey Mission NBHM, MIS PSS, Namo-Drone DIDI under Rashtriya Krishi Vikas Yojana lots of works are done for the Agriculture sector. Introduction and execution of Soil Health Card, Rainfed Area Development, Per Drop More Crop, Micro Irrigation Fund, Paramparagat Krishi Vikas Yojana, Sub-Mission on Agriculture Mechanization, Crop Residue Management, Agro-forestry, National Food Security Mission under Krishonnati Yojana, Sub-Mission on Seed and Planting Material, National Mission on Edible Oils, Mission for Integrated Development of Horticulture, National Bamboo Mission, Integrated Scheme for Agriculture Marketing, Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region, Sub-Mission on Agriculture Extension, Digital Agriculture.

These Schemes will change the scenario of Agriculture Sector in a large scale.

The vision of Assam agriculture is that of a vibrant sector which is an engine of growth for the state economy, provides food and nutritional

security, supports the farmers for socio-economic uplift to have a comfortable life, minimizing environmental degeneration and helps the state in the path towards food self-sufficiency and poverty eradication.

Sustainable agricultural development in Assam is crucial for food security, economic growth, and environmental protection, requiring strategies like promoting organic farming, improving infrastructure, and supporting local farmers.

A thriving agricultural sector can drive economic growth by creating jobs, generating income, and boosting rural livelihoods. Sustainable agriculture helps preserve natural resources like soil, water, and biodiversity, which are essential for a healthy ecosystem. Assam faces challenges like traditional farming practices, limited access to technology, and infrastructure gaps, which hinder agricultural progress.

Agriculture is the principal occupation of majority (60%) of the rural population in the state in terms of employment and livelihood. Agriculture sector continues to providing employment of more than 50 per cent of the total workforce and support more than 75 per cent population of the state directly or indirectly.

Key Strategies for Sustainable Agricultural Development in Assam:

Promote Sustainable Farming Practices:

Organic Farming: Encourage farmers to adopt organic practices to reduce reliance on synthetic chemicals and improve soil health.

Water Conservation: Implement water-efficient irrigation techniques and promote rainwater harvesting to address water scarcity.

Crop Diversification: Encourage farmers to diversify their crops to reduce vulnerability to climate change and market fluctuations.

Soil Health Management: Promote practices that improve soil fertility and reduce erosion, such as crop rotation and cover cropping.

Improve Infrastructure:

- **Storage and Processing Facilities:** Invest in cold storage and food processing facilities to reduce post-harvest losses and enhance value addition.
- **Transportation Networks:** Improve Road and rail infrastructure to facilitate the efficient movement of agricultural produce to markets.
- **Energy Solutions:** Provide access to reliable and affordable energy sources for irrigation and other agricultural activities.

Support Local Farmers:

Extension Services: Provide farmers with access to training and extension services on sustainable farming practices.

Credit and Finance: Ensure access to affordable credit and financial services for farmers to invest in sustainable technologies and practices.

Market Access: Facilitate access to markets for farmers' produce, both local and international.

Policy and Regulatory Framework:

- **Develop Clear Policies:** Establish clear policies and regulations that support sustainable agricultural development.
- **Incentivize Sustainable Practices:** Provide incentives for farmers to adopt sustainable practices, such as subsidies for organic inputs or tax breaks for sustainable farming.
- **Promote Research and Development:** Invest in research and development to identify and promote sustainable technologies and

practices that are suitable for Assam's context.

Horticulture:

Assam produces a wide range of horticultural crops including fruits, vegetables, flowers, spices, nuts, tubers, medicinal and aromatic plants. The climatic condition and diverse landscape of the state have helped to develop diverse ecological habitats such as forests, grasslands, wetlands etc. which harbour and sustain wide ranging floral and faunal species in the state. The state has tremendous scope to promote horticulture sector that can help ensure food and nutritional security, as well as enhance employment opportunities via cultivation and post-harvest management and value addition of horticulture produces.

Horticulture crops occupy about 15 percent of gross cropped area of the State with an annual production of more than 67 lakhs metric tonnes of various horticultural produces. The state has now emphasized on the commercialization of the sector as a priority basis. The emphasis of the state is now on raising productivity of various commercially potential crops through use of better technology, management, and provision of planting materials to the farmers. Moreover, emphasis is also placed on pre and post-harvest treatment, proper harvest techniques, setting up of collection centres with grading facilities, transport facilities and marketing facilities.

Assam and other north-eastern states are always following organic farming. Like more specialized schemes required for the welfare of the farmers of north-eastern region especially for Assam farmers. As our Prime Minister and our Government change the scenario of North Eastern States.

I hereby request Hon'ble Agriculture Minister to promote the below mentioned crops to give a special attention and instruct his Ministry to

take special initiative.

Joha Rice Joha rice, aromatic rice cultivated in the Northeastern region of India is effective in lowering the blood glucose and preventing diabetes onset and hence is an effective nutraceutical of choice in diabetes management.

Joha is a short-grain winter paddy known for its significant aroma and noteworthy taste. The traditional claims are that the consumers of Joha rice have low incidence of diabetes and cardiovascular diseases, but these needed scientific validation.

Bora Saul Rice

Bora Saul is a variety of glutinous rice found in Assam, India. It has an important role in festivals of Assam. During traditional occasions like Bihu, this variety of rice is eaten with served with doi (curd), gur (jaggery) and cream.

Assam Lemon

Assam lemon is one of the most important crops of Assam and other parts of N.E. region. Fruit is widely used for culinary, beverages, industrial and medicinal uses.

Assam Potato

Assam small Potato is one of the important cash crops grown in the Brahmaputra Valley Zone of Assam. It is only available in Assam and North-eastern states.

Bhut Jolokia

Bhut Jolokia, also called the Ghost Pepper, is one of the hottest chillis in the world. People who love super spicy stuff love it to bits. It is only available in the north-eastern states and it is also a medicinal plant.

Moran Ginger

Moran Ginger is one of the variety Ginger which is medicinal one and it is only available in Moran, Assam.

Carombulla

This indigenous fruit of Assam is very popular for its medicinal value and an ideal fruit for various value addition and with medicinal properties.

Special schemes should be implemented for NER other than PM-Kisan Samman Nidhi.

Agricultural technologies change every day and it is more pertinent in view of the climate change effects. Therefore, a strategy for developing human resources is necessary to achieve desired goals.

Young people should encourage to enter in agricultural business. Due to Industrialization and urbanization the cultivated areas are reducing every year. Attractive specialized schemes should encourage and attract young people for enter into agricultural business. Single windows schemes should implemented for north-eastern states.

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग पर विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो देश के कुल जीडीपी में लगभग 18% का योगदान देती है और देश की लगभग आधी आबादी को रोजगार प्रदान करती है । इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में केवल सामान्य वृद्धि हुई । इसके विपरीत, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार (2009-2014) ने पांच वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए मात्र आरएस1,21,082 करोड़ का बजटीय आवंटन किया था, जबकि मोदी सरकार ने केवल एक वर्ष (2025-26) में ही आरएस2.35 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन किया है । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, मोदी सरकार ने कृषि को सर्वोच्च

प्राथमिकता दी है और इसके विकास के लिए अभूतपूर्व वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन सुनिश्चित किया है ।

हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियों और ठोस वित्तीय समर्थन के माध्यम से, देश की रीढ़ यानी के हमारे अन्नदाताओं को निरंतर सशक्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है ।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए रिकॉर्ड आरएस2.35 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है । इस महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान में फसल पालन के लिए आरएस1,53,683 करोड़, कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए आरएस43,913 करोड़, 'अन्य कृषि कार्यक्रमों' के लिए आरएस3,504 करोड़, और राज्य सरकारों को अनुदान सहायता के लिए आरएस20,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

यू.पी.ए सरकार के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्याओं को उपेक्षा और असंवेदनशीलता के साथ देखा गया, जबकि प्रशासन केवल देश की संपत्तियों को लूटने में व्यस्त रहा । इसके विपरीत, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) जैसी ऐतिहासिक योजनाओं को लागू किया है । यह परिवर्तनकारी योजना देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति वर्ष आरएस6,000 की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

24 फरवरी 2025 तक इस योजना के तहत आरएस3.7 लाख करोड़ वितरित किए जा चुके हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना बन गई है । इसके अलावा, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवंटन बढ़ाकर आरएस63,500 करोड़ कर दिया है, जो कि 2024-25 के बजट में निर्धारित आरएस60,000 करोड़ की तुलना में 5.8% अधिक है ।

स्वामीनाथन आयोग ने सुझाव दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक निर्धारित कर देना चाहिए, ताकि किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाया जा सके । लेकिन, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए सरकार ने इस महत्वपूर्ण सुझाव को लागू करने से इनकार कर दिया और इसे "अप्रभावी" भी बताया । जिसके परिणामस्वरूप, लाखों किसान, विशेष रूप से

छोटे और सीमांत किसान, खुले बाजार में अपनी फसल को काफी कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर हो गए, इससे उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग के सुझावों को लागू किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) हमेशा उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक हो।

वर्ष 2013-14 में यू.पी.ए सरकार के अंतर्गत, खाद्यान्न उत्पादन मात्र 264 मिलियन टन था, जबकि बागवानी उत्पादन 281 मिलियन टन रहा। एनडीए सरकार के अंतर्गत 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 332 मिलियन टन हो गया, जो 25.8% की वृद्धि को दर्शाता है, और बागवानी उत्पादन 353 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिसमें 25.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा, यूपीए शासन के अंतर्गत 2013-14 में जहाँ यह मात्र \$22.70 बिलियन था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर \$48.15 बिलियन हो गया, जो 112% की असाधारण वृद्धि को दर्शाता है। इस अप्रत्याशित प्रगति ने किसानों के जीवन को बदल दिया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि, आजीविका में सुधार और वैश्विक बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हुई है।

हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ व्यापक जोखिम कवरेज सुनिश्चित करके किसानों की वित्तीय सुरक्षा को लगातार प्राथमिकता दी है। वर्ष 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबी) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के लिए कुल आरएस69,515 करोड़ का बड़ा आवंटन किया गया है, जिससे किसानों को अप्रत्याशित नुकसान से बचाया जा सके। इस योजना की शुरुआत से अब तक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबी) के अंतर्गत आरएस1.75 लाख करोड़ से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है, जिससे 23.22 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। इस सशक्त समर्थन ने न केवल किसानों के लिए इनपुट लागत का बोझ कम किया है, बल्कि उन्हें अपनी फसलों में आत्मविश्वास के साथ निवेश करने, उत्पादकता बढ़ाने और अपनी आजीविका को सुरक्षित करने में भी सक्षम बनाया है।

पिछले एक दशक में, भारत ने खाद्यान्न खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिससे किसानों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच धान की खरीद 6900 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) तक पहुंच गई, जो इससे पूर्व

2004-05 से 2013-14 के दशक में 4590 लाख मीट्रिक टन थी । इसी तरह, गेंहू की खरीद में भी भारी वृद्धि हुई, जो 2004-05 से 2013-14 के दौरान 2140 एलएमटी थी, वह 2014-23 में बढ़कर 3072 एलएमटी हो गई । यह वृद्धि सक्रिय योजना और कुशल कार्यान्वयन का परिणाम है ।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत 21 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे फसल कटाई के बाद के प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को मजबूत करने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान किया जा सके । 27 दिसंबर 2024 तक, ए.आई.एफ (एआईएफ) के अंतर्गत 87,548 परियोजनाओं के लिए आरएस52,738 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से आरएस39,959 करोड़ योजनागत लाभों के अंतर्गत कवर किए गए हैं । इन स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में कुल आरएस86,798 करोड़ का निवेश आकर्षित किया गया है, जिससे कृषि अवसंरचना के आधुनिकीकरण और किसानों की उत्पादकता में व्यापक सुधार हो रहा है ।

श्री अनन्त नायक (क्योंझर) : मुझे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद ।

हमारी इस सरकार में, हम कृषि और किसान कल्याण को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं । यह क्षेत्र देश की रीढ़ है । खेत, किसान और कृषि पद्धति को मजबूत करना आज तक हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है ।

इस प्राथमिकता वाले मंत्रालय को बजट आवंटन से देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, गरीबों, किसानों सहित हमारे लाखों युवाओं एवं महिलाओं के उत्थान में किस प्रकार मदद मिलेगी, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है ।

हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है । हम कृषि और किसान कल्याण गतिविधियों के सुधार के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे सच्चे किसान हितैषी - हर किसी का प्रिय माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के नेतृत्व में हमने अपने बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है ।

कृषि बजट आवंटन 2008-09 में आरएस 11,915 करोड़ की मामूली राशि से बढ़कर 2025-26 में आरएस 1,27,290 करोड़ हो गया है। कृषि और किसान कल्याण के लिए आवंटन में भारी उछाल [2008-09 के बजट से 11 गुना अधिक]। इस क्षेत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कृषि मंत्रालय के पास विकास के अपार अवसर हैं। हमारी सरकार समग्र सरकारी दृष्टिकोण (व्होल ऑफ़ द गवर्नमेंट एप्रोच) अपनाती है। इसमें चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता है।

हमारी सरकार ने इस अवसर को देखा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के संकल्प के साथ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों - चाहे वे कृषि की दृष्टि से समृद्ध हों या नहीं के साथ पर्याप्त और समय पर समन्वय द्वारा सबका विश्वास सुनिश्चित करने का प्रयास करने के लिए तैयार है।

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख ड्राइवर बना हुआ है। मैं इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को बजट आवंटन से अपेक्षित कुछ महान प्रयासों को उजागर करना चाहता हूँ।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि और किसान कल्याण पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना 100 जिलों में राज्यों के साथ साझेदारी में मौजूदा योजनाओं और कृषि विकास से संबंधित विशेष उपायों को एकीकृत करेगी।

सरकार की प्रतिबद्धता उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर फसल सघनता बढ़ाने, सामुदायिक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने और किसानों को आवश्यक कृषि इनपुट के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की रही है।

मुझे उम्मीद है कि बढ़े हुए आवंटन के साथ, मंत्रालय सभी गतिविधियों को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, कुछ अन्य प्राथमिकता वाले हस्तक्षेपों में सिंचाई, मृदा (सॉइल) स्वास्थ्य प्रबंधन और जैविक खेती

और कृषि वानिकी जैसी टिकाऊ खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने में अधिक निवेश शामिल है ।

बजट आवंटन से किसानों के लिए प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार संपर्क तक बेहतर पहुंच को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपना सकेंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ सकेंगे ।

आवंटन से पीएम किसान सम्मान निधि (पीएमकिसान) योजना को भी मजबूती मिलेगी और कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स जैसे किसान केंद्रित बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा । यह वास्तव में कृषि-बुनियादी ढांचे में एक आधुनिक क्रांति लाएगा ।

मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री को टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर अधिक ध्यान देने और उर्वरक उपयोग में दक्षता लाने के लिए भी बधाई देता हूं । अब इसका उद्देश्य यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और मिट्टी के क्षरण को रोकना है । यह कदम जैविक खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है । इससे कृषि क्षेत्र को जैव उर्वरक और सटीक खेती जैसे अभिनव समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) जो सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और जल-उपयोग दक्षता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, का उद्देश्य सिंचाई कवरेज का विस्तार करना, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना और जल संरक्षण प्रथाओं में सुधार करना है । 2025-26 में 8,260 करोड़ रुपये के बजट आवंटन से जल प्रबंधन में सुधार होगा, मानसून पर निर्भरता कम होगी और वर्षा आधारित और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार होगा ।

अब समय आ गया है कि कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को समझा जाए और रेखांकित किया जाए तथा बुनियादी ढांचे, आधुनिकीकरण, पता लगाने की क्षमता, उत्पादन, उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर किया जाए ।

केंद्र सरकार के अटूट समर्थन से, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के दो मजबूत स्तंभ बनने के लिए तैयार हैं । बजट 25-26 देश के दृष्टिकोण को मजबूत करता है, यह

सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण भारत में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दें ।

अब मैं इस अवसर पर आपके समक्ष केंद्रीय कृषि मंत्रालय और ओडिशा सरकार के संबंधित कृषि विभाग के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता के बारे में कुछ बिंदु रखना चाहता हूं ।

डबल इंजन सरकार के शासन में, ओडिशा अपने कृषि और किसान कल्याण क्षेत्र में विकास के मामले में अन्य विकसित राज्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है ।

हमारे ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री के सक्षम नेतृत्व में, समृद्ध और आधुनिक कृषि के साथ एक स्वर्णिम ओडिशा हमारा ड्रीम को साकार करना है । हम पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक पद्धतियों के साथ संरक्षित और एकीकृत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं ।

मुझे उम्मीद है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न योजनाबद्ध अतिवृत्तियों में वित्तीय प्रतिबद्धताएं और आवंटन ओडिशा की कृषि के मुद्दों और चुनौतियों को दूर

करने में प्रभावी होंगे, जैसे कि जलवायु संवेदनशीलता लचीली फसलों (क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप्स) का कवरेज बढ़ाना और उन्हें अपनाना, मिट्टी के एरोजन, लवणता और जलभराव जैसी समस्याओं का समाधान करना और कृषि में युवाओं की स्वीकार्यता बढ़ाना और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर श्रमिकों के पलायन को रोकना ।

मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि ओडिशा - मेरा राज्य कृषि मंत्रालय के इस शानदार ढंग से तैयार किए गए योजनाबद्ध हस्तक्षेपों का लाभ उठाएगा और पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक कृषि तकनीक सुनिश्चित करके और राज्य की समग्र उत्पादकता में सुधार करके कृषि कठिनाइयों को दूर करेगा ।

मैं अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं तथा इस अवसर पर आशा करता हूं कि माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओडिशा के मित्र, एवं मार्गदर्शक बनेंगे तथा 2036 तक 'विकसित ओडिशा' के साथ-साथ 'विकसित कृषि राज्य' का गौरवशाली दर्जा प्राप्त करने के राज्य के प्रयास में अपना सहयोग प्रदान करेंगे ।

एक बार फिर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संबंध में अनुदान की मांग पर कुछ बिंदु व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

जय किसान !

जय जगन्नाथ !

जय हिंद!

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): I thank you for giving me the opportunity to express my views on the Demand for Grants for the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare for 2025-26.

On behalf of my leader and the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, I extend my appreciation to our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji, and hon. Agriculture & Farmers Welfare Minister for their unwavering commitment to the development of the agricultural sector. Their initiatives have been instrumental in enhancing farm productivity, improving rural livelihoods, and ensuring the welfare of our farmers.

Agriculture remains the backbone of our country, and within this, horticulture plays a crucial role in economic development. Among various horticultural crops, coconut holds immense potential, particularly in coastal states. Andhra Pradesh, blessed with the second-longest coastline in the country, provides an ideal climate for coconut cultivation. The high demand for coconut and its derived products in both domestic and international markets makes it a highly lucrative crop.

However, despite having the highest coconut productivity in India at about 16,000 nuts per hectare, Andhra Pradesh lags behind in total production due to its limited cultivation area of approximately 1.07 lakh hectares. This clearly indicates a significant opportunity to scale up

coconut production with increased focus and financial allocation to the Coconut Development Board.

A region that stands out in coconut cultivation is the Dr. B.R. Ambedkar Konaseema district of my constituency, which accounts for 50 per cent of Andhra Pradesh's total coconut production. The region's unique agro-climatic conditions make it an ideal hub for coconut cultivation and value addition industries. However, despite this potential, coconut farmers in the district face multiple challenges, including monoculture-related soil depletion, pest infestations, and climate-induced stress. Many farmers are moving away from coconut cultivation due to increased input costs and lower returns, which is exacerbated by low wholesale prices and inadequate quality control measures. Therefore, it is imperative that the government not only provides financial support but also implements structured interventions to address these challenges.

To strengthen the coconut sector, I urge for the better implementation of key schemes under the Coconut Development Board. The production and distribution of quality planting material must be expedited through DSP Farms, Regional Coconut Nurseries, and Nucleus Coconut Seed Gardens. Expanding the area under coconut cultivation, particularly in high-potential regions like Konaseema, should be prioritized. Integrated farming techniques should be promoted, including the adoption of demonstration plots and organic manure units to improve soil fertility and sustainability. The replanting and rejuvenation of aging coconut gardens must be financially supported to ensure the long-term viability of the sector.

Value addition and marketing remain critical for improving farmers' incomes. The Technology Mission on Coconut must be leveraged to facilitate research and innovation in coconut processing. Strengthening

market intelligence services, export promotion, and establishing quality testing laboratories will enable better market access and improved pricing for farmers.

There is also an urgent need to enhance publicity, extension services, and skill development initiatives so that farmers are aware of best practices and emerging technologies in coconut farming. The current publication of the Indian Coconut Journal in Telugu only biannually is insufficient. Given the high literacy rate in Konaseema, more frequent dissemination of technical information in the local language will be instrumental in educating farmers on sustainable practices.

Insurance coverage is another area that needs urgent attention. The Coconut Palm Insurance Scheme and Kera Suraksha Insurance Scheme should be expanded to cover more farmers, ensuring financial security against climate risks and pest infestations. Additionally, infrastructural development, better administration, and efficient project management under the Coconut Development Board should be strengthened for effective execution of these initiatives.

Furthermore, diversification of coconut-based products must be encouraged to make farming more profitable. High-value products such as activated charcoal, coconut sugar, virgin coconut oil, and coir-based goods have a growing demand in the global market. Special incentives and subsidies should be introduced to establish processing units in coconut-rich districts like Konaseema. The use of modern technology, such as drone-based pesticide application and pest surveillance using Unmanned Aerial Vehicles, can help mitigate crop losses and improve productivity. Intercropping with crops such as black pepper, cocoa, turmeric, and vegetables should be promoted to enhance soil health and generate additional income for farmers.

To fully realize the potential of the coconut sector, localized production centres for biological control agents must be established to combat pest infestations effectively. Regular district-level awareness programs should be conducted in collaboration with the Horticulture Board and the Coconut Development Board to educate farmers on best practices and emerging threats. Training programs can be organized through agricultural universities to equip extension officers with region-specific knowledge, who can then disseminate this information at the grassroots level.

Coconut farming is an integral part of our agricultural landscape, and with the right policies and targeted financial allocations, Andhra Pradesh, particularly Konaseema, can emerge as a leader in coconut production and processing. I urge the hon. Minister and the Government to increase the budgetary allocation to the Coconut Development Board and ensure effective implementation of the existing schemes. By doing so, we can safeguard the livelihoods of thousands of farmers, boost exports, and enhance India's global standing in the coconut industry.

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : हमारे देश में कृषि सबसे अधिक महत्व का क्षेत्र है । हाड तोड़ मेहनत करने वाले अन्नदाताओं का क्षेत्र है । और यह रेखांकित करना आवश्यक है कि यह सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र भी है ।

किसान सम्मन निधि द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा समर्थन अन्नदाता को दिया है । इससे इस क्षेत्र को ताकत मिली है, वरना विगत यूपीए की सरकार के दौरान किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या करते थे । इस किसान प्रेम के लिए मैं प्रधानमंत्री जी व कृषि मंत्री जी का अभिनंदन करना हूं ।

बजट में जिस बात को और रेखांकित किया गया है, उसमें युवा, किसान, महिला और गरीब को चार प्रमुख वर्ग बताया गया है । इस प्रकार का आधुनिक वर्गीकरण किसानों को बहुत बड़ी ताकत देता है । एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करता है । नीतिगत समर्थक भी मिलता है । मिल रहा है । हाथ बीमा इसमें एक है ।

सर्वज्ञात है कि 55 वर्षों तक जिनकी केंद्र में सरकार रही है, उनके द्वारा किसानों को दी गई गंभीर व्यथा का समाधान मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत कराता है। मुझे लगता है इसमें मान्यवर कृषि मंत्री जी का एक लंबा अनुभव है। अच्छी समझ है और किसानों के समस्याओं का निवारण के लिए समर्पण है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले वाली सरकारें लालमिर्च व समिर्न हरी मिर्च में अंतर भी नहीं जानते थे।

केंद्र सरकार द्वारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन चलाया है। यह पुरे भारत के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। एवं ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत तरीके से कार्य करने वाली खेती को समर्थन है। वह महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आज आवश्यकता आदिवासी क्षेत्र में उद्यानिकी और वानिकी मिशन को आधिकारिक समर्थन देने की आवश्यकता है। यह बढ़ती आबादी के रोजगार के लिए वहां से पलायन को बहुत हद तक रोकेगा। किसान आज अपना उत्पाद निपति करने की स्थिति में आ रहे हैं।

कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि माननीय मोदी जी के कालखंड में सिंचाई सकल कवरेज का क्षेत्र और सिंचाई सघनता दोनों बढ़ी है। यह जल के उत्तम उपयोग व कृषि के बढ़ते उत्पादन का संकेत है।

बजट में दाल उत्पादन को प्राथमिकता देना व दाल को बढ़ाने का उद्यम अच्छा है। अन्य बातों के साथ यह भी किसान जगत का उत्साह बढ़ता है। यह समावेशी एवं तेज गति से प्रकृति के अनुरूप कार्य करने का उत्साहवर्धक रास्ता है।

सरकार द्वारा नदी जोड़ो योजना का बहुस्तरीय लाभ कृषि व किसानों को मिलता हुआ दिखता है।

आज बढ़ती हुई आप के कारण किसानों के बेटे अच्छा अध्ययन रहे हैं और किसान परिवार की महिला को स्वास्थ्य सुधार रहा है। वे बहुविध प्रगतिरत हैं। इस प्रकार यह नारी शक्ति वंदन भी है।

एक अन्य कार्य उच्च पैदावार वाले बीजों को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन प्रस्तावित किया है जो खेती को और ज्यादा फारवर्ड लिंकेज देगा और धीरे-धीरे, कृषि उत्पादन बढ़ने से सकल आय बढ़ेगी और ग्रामीण गरीबी दूर होगी। सरकार ने MSP जी उल्लेखनीय मात्रा में बाई है।

बजट में प्रस्तुत सरकार का यह भी अच्छा दृष्टिकोण है कि देश के 10 व्यापक क्षेत्र में कृषि विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करने की बात भी एक है, जो बहुत हद तक किसानों को समर्थन करता है। इसका एक अन्य सबूत है चार शक्तिशाली ग्रोथ इंजन में कृषि को एक बताया गया है जिसके तहत पीएम धन्य धान्य कृषि योजना के माध्यम से समर्थन दिया गया है। इससे करीब एक करोड़ 70 लाख किसानलाभान्वित होंगे व उनको समर्थन मिलेगा।

जट 2025-26 में सब्जी और फलों को लेकर एक व्यापक कार्यक्रम भी अखिल भारतीय स्तर पर प्रस्तावित करना किसानों की आय बढ़ाने और सकल लोक स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए बढ़िया कहा जा सकता है। साथ ही कपास उत्पादकता मिशन एक ऐसा सार्थक कार्य है जो लाखों किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

एक अन्य कदम भी किसानों को समर्थन देने वाला है जिसमें अल्पकालीन ऋण लेने की सुविधा वाला किसान क्रेडिट कार्ड 7 करोड़ 70 लाख किसानों को लाभ देता है। अभी तक इसमें 3 लाख की क्रेडिट सीमा थी जिसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। यह कदम किसानों की लिक्विडिटी को बढ़ाएगा। इन प्रगतिशील प्रस्तावित रीति के कारण मे बजट के अनुदान मांग का समर्थन करता हूँ।

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : धन्यवाद आपने मुझे 1 लाख 37 हजार करोड़ के कृषि बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। यह सिर्फ एक बजट नहीं, बल्कि किसानों की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और उनके उज्ज्वल भविष्य का रोडमैप है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने भारतीय कृषि को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।

साथ ही, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य के किसानों के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएँ लागू की गई हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि किसान का बेटा ही किसानों की तकलीफ समझ सकता है, जबकि महलों में रहने वाले लोगों को किसानों की कोई चिंता नहीं होती।

इंडी अलायंस की सरकारें किसानों को कर्ज में डुबोकर चुनावी घोषणाओं का झूठा खेल खेलती रहीं। राहुल गांधी जैसे लोग, जो कैमरे ऑन होते ही खेती करने का नाटक करते हैं, उन्हें एमएसपी का फॉर्मूला तक नहीं पता।

रील वाले किसान को रियल किसान की कोई परवाह नहीं है, उन्हें रबी और खरीफ के बीच का अंतर नहीं मालूम, लेकिन एमएसपी दोगुनी करने की बातें करते हैं। जिन्होंने खेत में आज तक हल भी नहीं चलाया, वो फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करते हैं और यह वही कांग्रेस है जिसने 1986 में बिहार में, 1988 मेरठ में, 1995 हरियाणा में और 1998 मध्य प्रदेश में किसानों को गोली मार कर उनकी हत्या करने का पाप किया है।

कांग्रेस पहले किसानों को कर्ज में डालकर उनको आत्महत्या करने पर मजबूर करती है और जब वो किसान अपने हक के लिए लड़ाई करता है तो उसको गोली मारती है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है और इसी हाथ से इन्होंने देश के गरीब और किसान का गला घोटा है।

इनका असली मकसद किसानों को भड़काना है, लेकिन हमने किसानों को सशक्त बनाया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन हमने किसानों को सम्मान और आत्मनिर्भरता दी है।

आज भारत कृषि उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 2008-09 में कृषि बजट मात्र आरएस 11,915 करोड़ था, जो 2025-26 में आरएस 1,27,290 करोड़ हो गया है। 2004-05 में खाद्यान्न उत्पादन 204.6 मिलियन टन था, जो 2023-24 में बढ़कर 332.3 मिलियन टन हो गया।

एमएसपी में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है- धान का एमएसपी 2008-09 में आरएस 850 था, जो 2023-24 में आरएस 2,300 हो गया, और गेहूं का एमएसपी आरएस 1,080 से बढ़कर आरएस 2,425 हो गया। मोदी सरकार ने किसानों को सीधे भुगतान के माध्यम से आरएस 12.51 लाख करोड़ का एमएसपी दिया, जो यूपीए सरकार के 10 सालों में दिए गए आरएस 4.40 लाख करोड़ से तीन गुना ज्यादा है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम सिर्फ वादे नहीं करते, उन्हें पूरा भी करते हैं।

हमारी सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं। पीएम-किसान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को आरएस 3.46 लाख करोड़ का

सीधा लाभ मिला है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आरएस 1.65 लाख करोड़ के दावों का भुगतान किया गया है । ई-नाम (ए-नम) के माध्यम से 1,400 से अधिक मंडियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज के सही दाम मिल रहे हैं । कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत आरएस 52,738 करोड़ की सहायता देकर 87,500 से अधिक कृषि परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं ।

महाराष्ट्र में भी किसानों के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं । एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के किसानों को 'वर्ल्ड एग्रीकल्चर अवार्ड' से सम्मानित किया गया । राज्य में आरएस 15,000 करोड़ से अधिक आपदा राहत सहायता दी गई, एक रुपये में खरीफ फसल बीमा योजना लागू की गई, और 1.7 करोड़ किसानों को आरएस 5,469 करोड़ की मदद दी गई ।

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना के तहत 92 लाख किसानों को आरएस 7,134 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1.16 करोड़ किसानों को आरएस 31,511 करोड़ मिले । कपास और सोयाबीन उत्पादकों को आरएस 4,194 करोड़ की सहायता, प्याज उत्पादकों को आरएस 850 करोड़ का मुआवजा और महात्मा फुले कर्जमाफी योजना के तहत 14.38 लाख किसानों को आरएस 5,217 करोड़ की राहत मिली ।

आज इंडी अलायंस किसानों के हितैषी होने का दिखावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने किसानों की जमीन छीनी, उन्हें कर्जदार बनाया और फिर कर्जमाफी के नाम पर धोखा दिया । आज हम किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, न कि चुनावी घोषणाओं से उनका अपमान कर रहे हैं ।

हमारा संकल्प है कि 2027 तक किसानों की आय दोगुनी हो, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया जाए और सौर ऊर्जा आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाए । हमारा लक्ष्य है कि एमएसपी को और मजबूत किया जाए, कृषि स्टोरेज और सप्लाय चेन को सशक्त बनाया जाए और किसानों को ग्लोबल मार्केट तक पहुँच दी जाए ।

हमारी सरकार का संकल्प साफ है-किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आय दोगुनी करना और उन्हें उस सम्मान तक पहुँचाना, जिसके वे सच्चे हक़दार हैं ।

आज हमारी सरकार की योजनाओं से एमएसपी पर सबसे अधिक खरीद हो रही है, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सस्ता ऋण मिल रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसानों के खाते में जा रहा है और फसल बीमा योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिल रही है ।

हमने सिंचाई से लेकर मार्केटिंग तक, हर क्षेत्र में सुधार किए हैं ताकि किसान को उसकी मेहनत का पूरा दाम मिले । आज किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य भी मिल रहा है और तकनीक का लाभ भी । हमारी सरकार ने किसानों के लिए डिजिटल मंडियों (ए-नम) का विस्तार किया, जिससे बिचौलियों का खेल खत्म हुआ और किसान को सीधा लाभ मिला ।

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से लाखों नए वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाए गए ताकि फसल की बर्बादी कम हो और किसानों को मजबूरी में कम दाम पर अपनी उपज न बेचनी पड़े ।

हमने वह करके दिखाया है, जो पिछली सरकारें दशकों तक नहीं कर सकीं । महाराष्ट्र में हमारी सरकार किसानों के लिए जो कर रही है, वह पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है । 'एक रुपये में पिक बीमा योजना', नल से जल, मुफ्त सौर ऊर्जा पंप और लाखों किसानों को कर्जमुक्त करना-यह दिखाता है कि जब सरकार किसानों के हित में काम करती है, तो बदलाव कैसे आता है ।

हमारा सपना है कि देश का हर किसान सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और कभी किसी पर निर्भर न रहे । हमारा विजन सिर्फ कृषि सुधार नहीं है, बल्कि एक "कृषि क्रांति" लाने का है । एक ऐसी क्रांति जो किसान को सिर्फ खेतों तक सीमित न रखे, बल्कि उसे व्यापार, उद्योग और टेक्नोलॉजी से जोड़कर उसकी आय को नए स्तर तक पहुँचाए ।

हमने किसानों का सम्मान लौटाया है, उनकी मेहनत को पहचान दिलाई है और उनकी आँखों में नए सपने जगाए हैं । यही हमारा मिशन है, यही हमारा संकल्प है ।

अंत में चार पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा-

इंडी अलायन्स वालों ने बस छल किया,

भारत के अन्नदाता को कर्ज का दलदल दिया ।

हमने दिया उनको हक़ और सम्मान,

आज देश में है खुशहाली और आत्मनिर्भर है मेरा किसान ।

श्री रमेश अवस्थी (कानपुर) : हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने भारत के कृषि क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी क्रांति की शुरुआत की है । इस सरकार ने न केवल किसानों को गरीबी से उबारने का कार्य किया है, बल्कि करोड़ों लोगों के मन में आशा और प्रगति की भावना भी प्रज्वलित की है । किसानों के उत्थान के प्रति इस सरकार की अटूट प्रतिबद्धता ने अभूतपूर्व और मापनीय उपलब्धियाँ दी हैं ।

- आज मुझे अत्यंत गर्व के साथ इस सदन में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 2025-26 के लिए अनुदान की मांगें प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है । हमारी सरकार किसानों के कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है । कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं है, यह हमारी परंपरा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है । रणनीतिक नीतियों और बढ़ते बजटीय प्रावधानों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारतीय कृषि सतत रूप से आगे बढ़े आधुनिक बने और राष्ट्र की समृद्धि महत्वपूर्ण योगदान दे ।
- हमारी सरकार ने 2025-26 के बजट में कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए रु 1,27,290 करोड़ और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के लिए रु 10,466.39 करोड़ का प्रावधान किया है । ये आंकड़े हमारी सरकार की किसानों को वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नति और बेहतर अवसंरचना उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण हैं ।
- हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू कर चुकी है और उनका निरंतर विस्तार कर रही है, ताकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा, आय में वृद्धि और आधुनिक कृषि पद्धतियों का लाभ मिल सके ।
- सबसे पहले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसे रु63,500 करोड़ का आवंटन मिला है । यह योजना देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ताकि वे अपनी भूमि, बीज और खेती में आवश्यक निवेश कर सकें ।

- दूसरी प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबी), जिसके लिए रु12,242.27 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना किसानों को जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और बाजार अस्थिरता के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें भयमुक्त होकर कृषि करने का आत्मविश्वास देती है।
- तीसरी महत्वपूर्ण योजना है संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के तहत ऋण सीमा को रु3 लाख से बढ़ाकर रु5 लाख कर दिया गया है। जिससे को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के माध्यम से लाभमिल रहा है। इस प्रकार, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों को रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण समय पर और सुलभ रूप में प्राप्त हो, ताकि वे अपनी कृषि आवश्यकताओं को बिना किसी कठिनाई के पूरा कर सकें।
- इसके अलावा, हमारी सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओएस) के गठन पर जोर दिया है। यह पहल छोटे और सीमांत किसानों को एकजुट कर सामूहिक सौदेबाजी, बेहतर बाजार पहुंच और उचित मूल्य दिलाने में सहायता कर रही है।
- कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के लिए रु 900 करोड़ के बढ़े हुए आवंटन के साथ हम कटाई के बाद के प्रबंधन, भंडारण और ग्रामीण कृषि विपणन अवसंरचना को सुदृढ़ बना रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत को अधिक लाभ मिल सके।
- भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण को गति देने के लिए सरकार ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा में भी निवेश को मजबूत किया है। सरकार ने कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने के लिए 708 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे उच्च उत्पादकता वाली फसलों का विकास, टिकाऊ खेती की पद्धतियों और सटीक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान पर रु 965.46 करोड़ का निवेश किया गया है, ताकि हमारी कृषि अनुसंधान प्रणाली वैश्विक प्रगति के साथ कदम से कदम मिला सके।
- मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकास के लिए रु 192.81 करोड़, बागबानी विज्ञान के लिए रु 318.91 करोड़ और पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए रु

504.04 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार की कृषि विविधीकरण और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- सरकार ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए रु 229.09 करोड़ और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए रु 616.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये कार्यक्रम जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जल संरक्षण को बढ़ावा देते हैं और कृषि की दीर्घकालिक स्थायित्व एवं पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं।
- हमारी सरकार का किसान-प्रथम दृष्टिकोण केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे किसानों को सम्मान और सशक्तिकरण देने का भी प्रयास है। कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के लिए रु 204.23 करोड़ का आवंटन सुनिश्चित करता है कि किसानों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) के लिए रु 75 करोड़ का आवंटन ?मीठी क्रान्ति? को सशक्त कर रहा है और देशभर में हजारों मधुमक्खी पालकों को लाभ पहुँचा रहा है।
- माननीय सभापति महोदय, यह बजट किसानों की आय को दोगुना करने और भारत को कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का साक्षात् प्रमाण है। वित्तीय सहायता, बीमा, बाजार पहुंच, तकनीकी प्रगति और टिकाऊ खेती के साथ एक समग्र रणनीति के माध्यम से हम भारतीय कृषि को अधिक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और समृद्ध बना रहे हैं।
- आइए हम सब मिलकर इस बजट का समर्थन करें, जो केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे अन्नदाताओं के प्रति हमारी वचनबद्धता है - एक ऐसा वादा कि वे कभी अपनी प्रगति और समृद्धि की राह में अकेले नहीं होंगे। जय जवान, जय किसान !

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): India's agriculture sector is the backbone of the nation, directly and indirectly supporting nearly half of the population. Despite contributing approximately 18 per cent of the GDP, its vast potential remains largely untapped. With 328 million hectares of land, which is 4 percent of the world's total area. India possesses 11.2 per cent of the world's arable land the second largest after the United States. The country receives an average annual rainfall

of 1,170 mm, comparable to the global average, yet faces severe water scarcity, holding only 4 per cent of the world's freshwater resources while sustaining 17.8 per cent of the global population.

India ranks among the top agricultural producers, achieving record food grain production of 330.5 million metric tonnes in 2022-2023 and horticultural output exceeding 355 million metric tonnes. Agri-exports also surged to 53 billion USD in FY2022-2023 including rice, spices, fresh fruits and processed foods. However, productivity in key crops remains below global benchmarks, highlighting the sector's unexploited potential. For instance, India's average rice yields stands at 4.0 tonnes per hectare, whereas China achieves 7.1 tonnes and the global average is 4.8 tonnes. Similarly, wheat productivity in India is 3.5 tonnes per hectare, far behind China's 5.7 tonnes. The disparity is even more pronounced in soybean yields, with India producing only 1.2 tonnes per hectare compared to the U.S. average of 3.0 tonnes. Despite possessing more arable land i.e. 156 million hectares and higher annual rainfall of 1,170 mm than China's 120 million hectares and 645mm rainfall, India's agricultural GDP is merely 500 billion USD, just one-third of China's 1.5 trillion USD. This stark contrast underscores the urgent need for structural reforms, advanced agronomic practices and widespread technological adoption to enhance India's agricultural output and global competitiveness.

Under Prime Minister Modi's leadership, initiatives like Direct Benefit Transfer (DBT) and support through FPOS have strengthened agriculture. However, small and marginal farmers, who are 85 per cent of the farming population, often remain excluded due to lack of awareness, accessibility and resources. There are several challenges hindering agricultural growth. Uneven access to cutting-edge agricultural technology is a major contribution to low productivity and farmer distress. With 15

crore farmers spread across 6.5 lakh villages the current extension services are grossly inadequate. While new technologies such as drones, bio-stimulants and drip irrigation promise improved efficiency, awareness and affordability remain key barriers especially for small and marginal farmers.

Budget 2025-2026 has rightly, prioritized structural, medium to long-term issues in the farm sector. These reforms can ensure that the farm sector remains a key engine to growth, raising average farm income progressively while entrenching food and nutrition security. The Prime Minister's Dhan-Dhanya Krishi Yojana aims at addressing structural impediments encountered in 100 districts, which are to be selected in terms of low farm productivity, post-harvest losses, inadequate access to irrigation and credit, lack of crop diversification.

While India faces persistent deficits in pulses, in vegetables it is the supply chain inefficiency, large post-harvest losses, and the rising impact of extreme weather events that have led to both high inflation and large price volatility. Recognizing the nature and dimension of this challenge, the Government has announced a six-year Mission for Atmanirbharta in Pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. A critical component of this mission will be that two Central agencies - NAFED and NCCF will provide procurement assurance for these three pulses during next four years.

It is gratifying to note that credit intensity of agriculture i.e. annual disbursement of farm credit, both short term and long term, as a percent of annual Farm GDP, has increased from less than 30 per cent in 2010-2021 to more than 53 per cent now. Over time, with the rising cost of cultivation, however, there was a need for raising the scale of finance made available to the farming community, particularly, small and

marginal farmers. In December 2024, the RBI announced an increase in the limit for collateral free agricultural loan from Rs. 1.6 lakh per borrower to Rs. 2 lakh. The Budget has, enhanced the loan limit under the MISS (Modified Interest Subvention Scheme) to Rs. 5 lakh from Rs. 3 lakh for loans taken through KCC. These measures could be expected to help achieve near 100 per cent institutional coverage of Farm Credit.

With an aim to create digital identities for 11 crore farmers by 2027, the Agricultural Ministry is creating Farmers' Registry in FY2025-2026 and doubling its allocation to Rs. 10,000 crore. Six crore farmers will be covered in FY 2024-2025, three crore in FY 2025-2026 and two crore farmers in FY 2026-2027. The Government has set a target of creating six crore farmer IDs by March end this year.

In 2025-2026, Rs. 1,37,757 crore has been allocated which is 2.7 per cent of the Union Budget. Out of the total allocation to the Ministry, 92 per cent is estimated to be spent by Department of Agriculture and Farmers' Welfare while the remaining is estimated to be spent by the Department of Agricultural Research and Education. 77 per cent of the budget of Department of Agriculture and Farmers Welfare goes to three major schemes i.e. (1) Kisan Samman Nidhi, which is direct cash transfer of Rs. 6,000 per year per farmer family; (2) Modified Interest Subvention Scheme and (3) Crop Insurance Scheme.

In 2006, the National Commission on Farmer's chaired by Dr. M. S. Swaminathan noted that fragmented and scattered operational holdings are a major challenge to agricultural productivity. The Committee on Doubling Farmers Income (DFI) noted that land fragmentation is also associated with the division of land sharing the parcels among inheritors. One of the solutions recommended by the DFI Committee has been to aggregate farmers and promote land pooling to target fragmentation of

land holdings. Structure such as Farmer Producer Organisations (FPO)s and Self-Help Groups (SHGs) offer farmers the agriculture value chain. Collectivisation leads to higher collective output, increased land productivity and higher bargaining power for each farmer-member.

Availability of certified seeds is another important factor in ensuring optimum production for crops. There is need to access quality seeds.

As in India, about half of the agricultural area under crops is completely dependent on rainfall, there is a need for proper irrigation facility. 69 per cent of the total paddy and 96 per cent of total wheat in the country is cultivated using irrigation techniques. However, the irrigation efficiency for the majority of major sources of irrigation remains very poor. Most of the land under irrigation is irrigated using flood irrigation reducing water efficiency.

Access to affordable credit is important for enhancing agricultural productivity by making available the right inputs to farmers. Access to institutional credit to farmers has improved in the last ten years growing at an annual average rate of 14 per cent. In 2023-2024, institutional loans worth Rs. 24.8 lakh crore were extended to the agriculture sector. However, indebtedness continues to be high amount marginal and small farmers. The prevalence of agricultural credit from non-institutional sources remains high among marginal farmers. A Working Group was set up by the RBI to review the state of agricultural credit in the country. It noted that the interest subvention scheme was introduced with the aim of boosting crop-related investment credit in the sector. But, the share of short-term credit paid under the scheme at sub-vented interest rates has increased.

The Ministry incurs the second largest expenditure on Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). Crop insurance offers farmers security

against crop losses cause due to natural disasters, extreme weather events and non-preventable risks. PMFBY was launched in 2016 with the objective to provide affordable crop insurance to farmer. As on January 2025, total area of 4,803 lakh hectare has been insured under the scheme with the sum insured being Rs. 19.5 lakh crore. About 68 crore farmers have been insured under the scheme so far. In 2025-2026, the Government has allocated Rs. 12,242 crore for the Crop Insurance Scheme. This is 23 per cent lower than the revised estimate for 2024-2025 and the lowest allocation since 2018-2019. In addition, the amount of insurance claims paid to farmers has also been declining. This is not a good sign. Now there is a need for rethinking on crop insurance scheme that is prevalent today in the country and make it attractive and famers' friendly.

Remunerative pricing for agricultural produce is a crying need of the hour. The Government fixes MSP for 22 mandated agricultural crops as the basis of the recommendations of Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP). The MSP set by the Government for the financial year 2024-25 for paddy is Rs. 23 per kg and Rs. 24.25 per kg for wheat. Dr. Swaminathan Commission had recommended setting the MSP for crops at least 50 percent higher than the weighted average of the production cost. Adapting this recommendation, the Government in the Union Budget of 2018-2019 had announced that MSP for crops will be fixed at 1.5 times the production cost.

In her speech, the Finance Minister has announced a new Mission for procurement of pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. The scheme has been allocated Rs. 1,000 crore for the year 2025-2026. A very important decision was taken by the Government recently. The Government launched the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme in 2019. The scheme aims to provide income support of

Rs. 6,000 per year to all cultivable land- holding families. The transfer is made in three equal installments directly in the Aadhaar seeded bank accounts of eligible farmers. I may draw the attention of the Government that other than the landholding farmer families, there are large number of landless and tenant farmers. They also should be included in the scheme and provided with income support.

I would also like to draw the attention of the Government that high GST rates - 18 per cent on drones and 12 per cent on drip irrigation systems-increase financial strain on farmers. While fertilizer subsidies provide some relief, agricultural friendly tax reforms and long-term policy frameworks are essential to ensure the widespread adoption of modern technologies. Weak agricultural R&D and lack of indigenous innovation remains severely underfunded. Despite allocating Rs. 1 lakh crore R&D budget, there is little visible impact as most innovations are still driven by multi-national corporation (MNCs). Additionally, urea smuggling to Bangladesh and industrial diversion have worsened domestic shortages. Despite the presence of fertilizer subsidy scheme, weak enforcement and corruption have fuelled the parallel black market for agro-inputs.

There is need to carry forward the legacy of Lal Bahadur Shastri, whose leadership was pivotal in India's agricultural Revolution through his 'Green Revolution'. During a time of crisis, Shastriji's vision of self-reliance - from fasting to conserve Food to promoting wheat cultivation laid the foundation for India's food security. His leadership during the 1965 Indo-Pak war, when he coined the iconic slogan "Jai Jawan, Jai Kisan" reflects his deep commitment to both national security and farmers' welfare. Today, as a result of the Green Revolution, India not only feeds its population but is global exporter of agricultural products worth over Rs. 50 billion annually. Former PM Atal Bihari Vajpayee "Jai Vigyan" in 2002 underscored the role of science in national progress. In

2019, Prime Minister Modi reinforced this vision with "Jai Anusandhan" emphasizing research and innovation. However, true agricultural transformation remains incomplete with stronger R&D investments and effective grassroots implementation. While nations like Israel allocated up to 5 per cent of GDP to R&D, India's 0.6 per cent investment severely limits agricultural advancements. AI-driven precision farming, smart irrigation and sustainable inputs hold the key to unlocking India's agricultural potential. By prioritizing innovation, skill-based education and efficient agri-input utilization, India can triple its agricultural GDP-secure global leadership and fulfil its vision of becoming the world's top economy by 2047.

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : कृषि हमारे देश की रीढ़ है, और हमारे किसानों की मेहनत देश की समृद्धि का आधार है। भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित लगभग 11 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं। हमारे देश में कृषि उत्पादन में हर साल 2.3% की वृद्धि हो रही है, और 2022-23 में, कृषि क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 20% था। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 296 मिलियन टन तक पहुंचा।

यह सब कुछ हमें बताता है कि कृषि क्षेत्र के निरंतर विकास और सुधार की आवश्यकता है, ताकि हम अपने किसानों को उनके कड़ी मेहनत का उचित मूल्य दे सकें और देश की कृषि उत्पादन क्षमता को और बढ़ा सकें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। इन दोनों नेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पण के कारण हमारे किसानों के लिए न केवल नीतिगत सुधार किए गए हैं, बल्कि किसानों की समस्याओं का हल भी निकाला गया है। मोदी जी और शिवराज जी ने अपने नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है, जिससे किसानों की खुशहाली और देश की समृद्धि को नई ऊँचाइयाँ मिली हैं।

भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 17-18% है, और यह देश की लगभग 58% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है । ये आंकड़े दिखाते हैं कि कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है । यह हमारे किसानों की मेहनत का ही परिणाम है कि हमारे पास हर साल इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है ।

कृषि क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनका उद्देश्य न केवल खेती को समृद्ध बनाना है, बल्कि हमारे किसानों को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करना है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कृषि क्षेत्र में बदलाव की एक नई लहर देखने को मिली है । यह सरकार केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविकता में किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है ।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, किसानों की स्थिति बेहद खराब थी । कृषि संकट के कारण किसानों की आत्महत्या की घटनाएं आम हो गई थीं । कांग्रेस ने किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई, उनका परिणाम कभी भी धरातल पर नहीं दिखा । इसके विपरीत, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में न केवल नीतिगत सुधार किए गए, बल्कि किसानों की समस्याओं को समझते हुए योजनाओं को लागू किया गया, जो निम्न हैं:-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में इस योजना की शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है । कांग्रेस के समय, किसानों को कोई स्थायी आर्थिक मदद नहीं मिल पाई थी । मोदी सरकार ने इस योजना से करीब 11 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया है ।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): मोदी सरकार ने किसानों को सस्ते और सुलभ ऋण देने के लिए Kcc योजना का विस्तार किया । कांग्रेस के समय, किसानों को कर्ज के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, और कई बार उन्हें उच्च ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था । मोदी सरकार ने इसे सशक्त किया और किसानों की वित्तीय स्थिति को सुधारने का काम किया ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): कांग्रेस सरकार के समय, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या फसल खराबी से कोई सुरक्षा नहीं मिलती थी । मोदी सरकार ने

फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को सुरक्षा प्रदान की, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी आर्थिक राहत मिली ।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM): प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म e-NAM की शुरुआत की, जिसके जरिए किसानों को सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिला । कांग्रेस के समय, किसानों को बिचौलियों के हाथों में अपनी उपज बेचनी पड़ती थी, जिससे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता था ।

स्वामित्व योजना: कांग्रेस के कार्यकाल में, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों की स्थिति बहुत कमजोर थी । मोदी सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया, जिससे उन्हें ऋण प्राप्त करने में आसानी हुई और उनके आर्थिक समृद्धि के रास्ते खोले गए ।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF): मोदी सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष के जरिए कृषि क्षेत्र में भारी निवेश किया, जिससे कृषि उत्पादों के भंडारण, परिवहन और विपणन में सुधार हुआ । कांग्रेस के समय यह केवल एक सपना था, लेकिन अब यह वास्तविकता बन चुका है ।

अब मैं अपनी संसदीय क्षेत्र बालाघाट-सिवनी के कृषि क्षेत्र की विशेषताएँ और आवश्यकताओं के बारे में बात करना चाहती हूँ: कृषि अवसंरचना और सौर ऊर्जा का विकल्प: बालाघाट-सिवनी क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ता है । इस समस्या के समाधान के लिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि किसानों को सौर ऊर्जा (Solar Energy) पर आधारित ट्यूबवेल पंप मुहैया कराए जाएं । इससे उन्हें बिजली संकट से राहत मिलेगी और उनकी फसलों की सिंचाई सुचारू रूप से हो सकेगी । इसके साथ ही, सोलर पंप लेने की प्रक्रिया को किसानों के लिए सरल और सुलभ बनाया जाए, ताकि वे इस तकनीकी समाधान का आसानी से लाभ उठा सकें ।

कृषि मंडियों में सुधार: बालाघाट-सिवनी में कृषि उत्पादों के लिए बेहतर विपणन और मूल्य निर्धारण की व्यवस्था की आवश्यकता है । यहां की मंडियाँ पुराने और अव्यवस्थित तरीके से चलती हैं, जिससे किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं मिलता । मैं

सरकार से आग्रह करती हूँ कि इस क्षेत्र में ई-नाम जैसी डिजिटल मंडियाँ स्थापित की जाएं, ताकि किसानों को अच्छे बाजार और बेहतर कीमत मिल सके ।

कृषि तकनीकी प्रशिक्षण: बालाघाट-सिवनी के किसान पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं, और नई तकनीकी विधियों का उपयोग करने में पीछे रहते हैं । मोदी सरकार के द्वारा कृषि तकनीकी प्रशिक्षण के कई अवसर दिए गए हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र के किसानों को भी नए कृषि उपकरणों और तकनीकी विधियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए । इससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी और वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे ।

कृषि ऋण और वित्तीय सहायता: बालाघाट-सिवनी के किसान कभी-कभी ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं । मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूँ कि इस क्षेत्र में विशेष कृषि ऋण योजनाएं लागू की जाएं ताकि किसानों को सस्ते और सुलभ ऋण मिल सकें । यह उनके लिए फसलों की लागत कम करने और उनके उत्पादन को बढ़ाने में मददगार होगा ।

कृषि बीमा और आपदा प्रबंधन: बालाघाट-सिवनी में अक्सर प्राकृतिक आपदाएँ जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जिससे किसान प्रभावित होते हैं । इस क्षेत्र के किसानों को मोदी सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक लाभ मिलने की आवश्यकता है । मैं यह भी अनुरोध करती हूँ कि इस क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के तहत अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि किसान प्राकृतिक आपदाओं से बच सकें ।

बालाघाट-सिवनी का कृषि क्षेत्र हमेशा से ही समृद्ध और उत्पादक रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि यहां के किसानों को और बेहतर अवसर प्रदान किए जाएं । मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, उनका असर अब हमारे क्षेत्र में भी दिखना चाहिए । मैं विश्वास करती हूँ कि यदि इस क्षेत्र के कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो यह क्षेत्र न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कृषि में आत्मनिर्भरता का आदर्श प्रस्तुत कर सकता है ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि क्षेत्र को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, वे सचमुच एक प्रेरणा देने वाले कदम हैं । प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुधार और

नीतिगत बदलाव लाए गए हैं, जिससे हमारे किसान सशक्त हो रहे हैं। साथ ही, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने हमारे किसानों के जीवन में बदलाव लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन योजनाओं का और विस्तार करें, ताकि हमारे किसान और ग्रामीण समाज अधिक समृद्ध हो सकें।

श्री दुलू महतो (धनबाद) : हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में कृषि केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और हमारे किसानों का जीवन कृषि पर निर्भर करता है।

हालांकि, आज भी भारतीय कृषि कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, असमान वर्षा, आधुनिक तकनीकों की कमी और कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए उपयुक्त संसाधनों का अभाव प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों को उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, ताकि वे उन्नत कृषि पद्धतियों को अपना सकें और अपनी उपज में वृद्धि कर सकें। हालांकि, कृषि क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव भी हुए हैं, जैसे जैविक खेती, स्मार्ट फार्मिंग, और नई तकनीकों का उपयोग, लेकिन इनका पूरा लाभ अभी तक किसानों तक नहीं पहुँच पाया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें किसानों को सही तकनीकी ज्ञान और कृषि में नवाचार की ओर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को अवगत करवाना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद के चंदनक्यारी और निरसा विधानसभा क्षेत्रों में हजारों किसान अपनी मेहनत और लगन से कृषि कार्य कर रहे हैं।

इन क्षेत्रों में कृषि के विकास और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस केंद्र के माध्यम से न केवल किसानों को उन्नत खेती की तकनीकों का लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान में भी मदद मिलेगी।

चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र बोकारो जिले में स्थित है, जबकि निरसा विधानसभा क्षेत्र धनबाद जिले में आता है, और दोनों मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अतः इन

दोनों क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना से न केवल इन क्षेत्रों के किसानों को लाभ होगा, बल्कि आसपास के जिलों के किसान भी इसका लाभ उठा सकेंगे ।

इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियों, नवीनतम शोध, और जलवायु आधारित खेती के उपायों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी । इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार आएगा ।

सरकार से सविनय अनुरोध है कि कृपया चंदनक्यारी और निरसा विधानसभा क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करें । इस केंद्र के माध्यम से किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे और उन्हें कृषि में अधिक लाभ होगा ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय कृषि मंत्री जी मेरी इस मांग को स्वीकार करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के किसान नई दिशा में प्रगति कर सकेंगे और कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव आएगा ।

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Hon. Speaker Sir, I rise to wholeheartedly support the Demand for Grants 2025-2026 for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. Agriculture is the backbone of our nation, providing livelihood to nearly 46 per cent of our workforce while contributing 16 per cent to the GDP. The Government's unwavering commitment to farmers is evident in this year's allocation of Rs. 1,37,757 crore, which constitutes 2.7 per cent of the Union Budget. This allocation not only strengthens the farmer-centric schemes but also ensures India's progress towards self-reliance in food production, higher incomes for farmers, and sustainable agricultural practices.

A Decade of Transformative Agricultural Progress. Over the past ten years, India's agriculture sector has witnessed unprecedented reforms, record investments, and landmark policy decisions that have empowered farmers, improved productivity, and ensured food security. Let us recall the situation before 2014, when farmers were left struggling due to poor

MSP implementation, lack of financial assistance, rising input costs, and no structured support system.

Doubling Farmers' Income ? A Commitment Fulfilled

In 2016, the Committee on Doubling Farmers' Income (Dr. Ashok Dalwai) was constituted, leading to policy interventions such as crop diversification, higher investments in agri-infrastructure, and promoting value addition.

The average monthly income per agricultural household increased by 59 per cent, from Rs. 6,426 in 2013-2014 to Rs.10,218 in 2018-2019.

Implementation of the Swaminathan Report ? A Historic Step.

For decades, farmers demanded the implementation of M.S. Swaminathan Commission's recommendations, especially the MSP at 1.5 times the cost of production. While previous governments ignored these recommendations, our government fulfilled this promise in 2018, ensuring farmers receive fair and remunerative prices.

The Minimum Support Price (MSP) mechanism was strengthened, with Rs. 1.07 lakh crore spent on procurement of pulses, oilseeds, and copra under PM-AASHA since 2018-2019.

Record wheat and rice procurement ? In 2023-24, 43 per cent of paddy and 25 per cent of wheat production was procured at MSP.

Direct Benefit Transfers ? Farmers Empowered.

PM-Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) was launched in 2019, providing Rs. 6,000 per year to farmers directly in their bank accounts.

As of August 2024, Rs. 3.24 lakh crore has been transferred to 12.85 crore farmers, bringing financial security and stability.

And now the Government has released its 19th instalment.

Revolutionizing Farm Credit and Insurance.

Modified Interest Subvention Scheme (MISS) increased the Kisan Credit Card loan limit from Rs. 3 lakh to Rs. 5 lakh, with Rs. 22,600 crore allocated for 2025-2026.

PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) ? Rs. 19.5 lakh crore worth of crops have been insured under this scheme, covering 68 crore farmer applications.

Advancing Agri-Tech and Research.

The National Mission on High Yielding Seeds was launched, with an allocation of Rs. 100 crore, ensuring commercial availability of climate-resilient and pest-resistant seed varieties.

Investment in Agricultural Research has steadily increased by 3.1 per cent in 2025-2026, reaching Rs. 10,466 crore.

The key highlights of Budget 2025-2026 for Agriculture are as follows. This year's Budget continues the momentum with new initiatives:

PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana ? Targeting 1.7 crore farmers in 100 low-productivity districts to boost production.

Aatmanirbhar Bharat in Pulses ? Rs. 1,000 crore allocation to reduce import dependency on Tur, Urad, and Masoor.

Horticulture Boost ? Rs. 500 crore allocated to ensure better supply chains, processing, and price realization for fruits and vegetables.

Fertilizer Self-Sufficiency ? A new Urea plant in Assam with a capacity of 12.7 lakh tonnes to reduce import dependence.

Connecting with Farmers ? Real Impact on the Ground. Farmers today do not just cultivate crops; they are entrepreneurs, innovators, and contributors to India's economic strength. The Government's focus on:

Ensuring higher incomes through fair MSP and PM-KISAN.

Protecting crops and livelihoods with PM Fasal Bima Yojana.

Strengthening irrigation under PM Krishi Sinchayee Yojana (94 lakh hectares covered).

Improving market access through e-NAM (1.7 crore farmers registered).

These steps are transforming rural India and securing a prosperous future for every farmer.

A Vote for Farmers? Welfare and National Progress. This Demand for Grants is not just about financial allocation; it is a reflection of our Government's vision, commitment, and action for the farmers of India. In 10 years, agriculture has gone from crisis to confidence.

This Budget empowers every farmer, fuels India's self-reliance in food production, and drives the vision of Viksit Bharat.

I urge all Members of the to support this Demand for Grants and stand with our Annadatas, who feed the nation and fuel the economy.

(ends)

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 2025-26 के अनुदान की मांगों का पुरजोर समर्थन करती हूँ। सबसे पहले, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने किसानों के कल्याण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं, जिससे किसानों को सहायता, बुनियादी ढांचा, और प्रोत्साहन मिल रहा है।

मोदी जी के नेतृत्व में, भारत में एक ऐतिहासिक कृषि क्रांति आई है, जो न केवल उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि, उनके जीवनयापन की सुरक्षा और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर भी जोर देती है। सरकार किसानों को तकनीक, वित्तीय सहायता और स्थायी कृषि उपायों से सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

महाराष्ट्र सरकार की पहल और मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस जी का योगदान। महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस जी और राज्य के कृषि मंत्री की सराहना करती हूँ, जिन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया है।

महाराष्ट्र सरकार की ?महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना? हजारों किसानों को राहत देने में सहायक रही है। इससे लाखों किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं। इसके साथ ही ?नमामि गंगे कृषि सिंचाई योजना? के तहत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, जिससे किसानों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े।

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ?स्मार्ट प्रोजेक्ट योजना? किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए एक सराहनीय पहल है। इससे महाराष्ट्र के किसान ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और कृषि यंत्रीकरण जैसी नई तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ?हॉर्टिकल्चर क्लस्टर विकास योजना? के माध्यम से किसानों को भंडारण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की सुविधाएँ दी जा रही हैं, जिससे उनकी उपज को बेहतर दाम मिल रहे हैं।

महाराष्ट्र के लिए विशेष ध्यान। महाराष्ट्र कृषि क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। मैं इस बात की सराहना करती हूँ कि इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों, विशेष रूप से जलगाँव और आसपास के क्षेत्रों के लिए कई योजनाएँ शामिल की गई हैं। कृषि अवसंरचना निधि- महाराष्ट्र को 8,460 करोड़ रुपये मिले हैं, जिसमें से 1,233 करोड़ रुपये पहले ही भंडारण, सिंचाई और कृषि विपणन सुधारों के लिए वितरित किए जा चुके हैं। बागवानी

विकास कार्यक्रम - 500 करोड़ रुपये का प्रावधान केले, अंगूर और अनार किसानों के लिए किया गया है, जिससे वे अपनी उपज का अच्छा दाम प्राप्त कर सकें ।

सिंचाई और जल संरक्षण- ?पर ड्रॉप मोर क्रॉप? योजना को महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त जिलों में विस्तारित किया जा रहा है । कपास किसानों के लिए समर्थन- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से विदर्भ और खानदेश के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा । गन्ना किसानों की सहायता - 700 करोड़ रुपये का प्रावधान चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और किसानों को सीधी सहायता देने के लिए किया गया है । जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा - 300 करोड़ रुपये का प्रावधान सतत कृषि पद्धतियों और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है । किसान उत्पादक संगठन (एफपीओज़) को मजबूत करना - 10,000 से अधिक एफपीओ को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसान अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें ।

कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान - इन सफलताओं के बावजूद कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं । मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए -

ई-नाम (ई-नैम) का विस्तार ताकि महाराष्ट्र के किसान राष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुँच प्राप्त कर सकें । जलवायु प्रतिरोधी फसलों और सटीक खेती को बढ़ावा देना ताकि अनिश्चित मौसम का असर कम हो । ग्रामीण सड़कों और परिवहन ढांचे में सुधार ताकि फसलों को बाजार तक पहुँचाने में आसानी हो । कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार जिससे अधिक कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और डिजिटल परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें । कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान की जाए ।

कृषि क्षेत्र हमारे देश की रीढ़ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में यह स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है । 2025-26 के बजट में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए किया गया प्रावधान किसानों की आय दोगुनी करने और भारत को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए कार्य भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस जी और राज्य सरकार की योजनाएँ महाराष्ट्र के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही हैं । यह केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, आधुनिक तकनीकों को अपना रहा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहा है ।

सरकार की 'किसान प्रथम' नीति यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी किसान पीछे न छूटे, हर ग्रामीण परिवार सशक्त बने और कृषि को एक लाभकारी एवं टिकाऊ व्यवसाय बनाया जाए । मैं अनुदान की माँगों का पूरा समर्थन करती हूँ और सभी माननीय सदस्यों से अपील करती हूँ कि हम सब मिलकर अपने अन्नदाताओं का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करें ।

जय जवान । जय किसान । जय महाराष्ट्र । जय हिंद ।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (**हातकणंगले**) : मुझे कृषि मंत्रालय की अनुपूरक मांगों 2025-2026 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया ।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को सत्ता पर काबिज हुए 10 साल हो गए हैं । पूरे जीवन में प्रधानमंत्री जी का संकल्प आम आदमी की तकलीफ को दूर करना रहा है और 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी का फोकस आजादी के बाद से पिछली सरकारों द्वारा कृषि के क्षेत्र में हुई दुर्गति को सुधारना रहा । जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । यह न केवल देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है । मैंने गांव में जन्म लिया और गांव में ही पला-बढ़ा । इसलिए गांव की जो मूलभूत समस्या है उसको मैंने नज़दीक से देखा है, महसूस किया है और उसकी पीड़ा को समझता हूँ । हमारे गांव में पहले से दो प्रकार की खेती थी । एक परंपरागत खेती थी और एक अनुसंधान, विज्ञान के आधार पर होने वाली आधुनिक खेती थी । किसान उत्पादन करता था, लेकिन उत्पादन का लाभ इसलिए नहीं मिल पाता था, क्योंकि संसाधन नहीं थे, रास्ते नहीं थे । इस कारण वह अपने उत्पाद को बाजार तक नहीं पहुंचा पाता था । बिचौलियों के माध्यम से किसान ठगा जाता था । जब किसान को अपने उत्पादन से आय नहीं होती थी, तब निश्चित रूप से वह अपनी गरीबी को भोगने के लिए बाध्य था ।

पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस की सरकारों में जो किसान बेहाल था, गरीब था, मजबूर था, जो गांव बिल्कुल उजड़े हुए दिखाई देते थे, वे आज हमारे प्रधान मंत्री जी की नीतियों के कारण, जो नीतियां वर्ष 2014 से शुरू हुई हैं और जो आज के बजट में दिखाई दे रही हैं, इन 10 सालों में देश के गांवों की तस्वीर बदल गई है और किसान तथा गरीब की तकदीर बदल गई है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है।

कृषि को समर्पित इस बजट को देखकर मेरे मन में यह विश्वास हो गया है कि पिछले 60 वर्षों में विकास की दौड़ में पीछे रह गए हमारे गांव, गरीब और किसान को प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता और नीयत के बल पर हम वर्ष 2025 तक एक श्रेष्ठ भारत और किसान की आय को दोगुना करने के साथ उनको विकास की धारा में जोड़ने में सफल हुए हैं। तमाम आर्थिक प्रगति, तरक्की और चन्द्रमा तक चन्द्रयान ले जाने में सफल होने के बाद भी हमारी पहचान कृषि प्रधान देश की है। हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अर्थतंत्र की बुनियाद है। किसान ही देश के अन्नदाता हैं, परंतु बुआई, कटाई से लेकर अपनी फसल और सब्जी को बाजार तक पहुंचाने में किसानों को काफी दिक्कतें आती हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं और कुछ मौसम की मार किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य नहीं दे पाती है। हम सब लोग जानते हैं कि कृषि मुख्य रूप से लागत, उत्पादन और लाभकारी मूल्य के साथ मौसम पर भी निर्भर करती है। इसलिए महोदय सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

आजादी के 60 वर्षों तक अन्नदाता के कुशल क्षेम का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया। योजनाएं बनीं, लेकिन वे जमीन पर साकार नहीं हुईं। पहले भी लाभकारी मूल्य निश्चित किए जाते थे, सरकारें घोषणाएं करती थीं, लेकिन क्रय केन्द्र समय से नहीं खुलते थे, क्रय समय से नहीं होता था। किसान अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में बिचौलियों के माध्यम से अन्न बेच देता था। वही बिचौलिए क्रय केन्द्रों पर जाकर सरकारी मूल्य पर लेते थे और किसान ठगा जाता था। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारी केन्द्र सरकार ने अपनी नीतियों को जमीन पर उतारकर जहां लाभकारी मूल्य निश्चित किया है, वहीं उत्पादन खलिहान में आने से पहले ही कृषि केन्द्र या क्रय केन्द्र खोले जा रहे हैं। क्रय केन्द्रों के माध्यम से खरीद भी हो रही है और लाभकारी मूल्य उनके खातों में पहुंच रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में सारी योजनाओं की घोषणा करने के

बाद पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गाँधी जी ने पूरे देश के सामने कहा था कि हम जो गरीबों को देना चाहते हैं, किसानों को देना चाहते हैं, उसका 85 प्रतिशत रास्ते में रह जाता है, केवल 15 प्रतिशत पहुंचता है, लेकिन वे उसका समाधान नहीं कर पाए थे, लेकिन आज मुझे बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, तब से 100 रुपये दिल्ली से भेजे जाते हैं तो पूरे-पूरे 100 रुपये किसानों के खाते में जमा हो जाते हैं इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है ।

मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही जन-धन योजना में मार्च 2025 तक 55.2 करोड़ से अधिक लोग जो कृषि पर आधारित थे, कृषि मजदूर थे, खेत और खलिहानों में काम करने वाले थे, बड़ी संख्या में उसमें सम्मिलित थे, आज किसान की खरीद हो, चाहे उसको मिलने वाली सब्सिडी हो, चाहे गरीब को मिलने वाली सुविधाएं हों, वे सीधे उनके खाते में जा रही हैं । इसलिए, आज की मोदी सरकार अपनी योजनाओं को साकार करने में सफल हुई है । कृषि का विकास बिना गांव के विकास के संभव नहीं है और गांव का जो मूलभूत स्वरूप है, उसका विकास बिना कृषि के संभव नहीं है । कृषि क्षेत्र के विकास पर हमारी सरकार वर्ष 2014 से ही कार्य कर रही है । गांव के विकास को ही धुरी बना कर बाकी सारी कृषि योजनाएं तैयार की गई हैं । इस बजट में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विकास को गति देते हुए सरकार ने 2025-2026 के 127290.16 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया है कर दिया है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ ।

वर्ष 2014 से 2025 तक की अवधि में किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदीजी ने अनगिनत कदम उठाए गए हैं, जैसे 25 से अधिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, किसानों की लागत में कमी लाना । पिछली सरकारों में इसी देश का किसान यूरिया खरीदने के लिए लाइन में खड़ा होता था, लाठियां भी बरसती थीं और फिर भी ब्लैक मार्केट में यूरिया महंगे दामों पर लेनी पड़ती थी, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री की नीतियों से नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग किया गया । अब यूरिया की कोई कमी नहीं है । आज यूरिया सरल सुलभ है, सस्ता है, समय से मिल रहा है, बिना लाइन के मिल रहा है । इससे किसान खुशहाल है ।

'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना' और 'प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना' से किसानों को जमीनी स्तर पर बहुत लाभ पहुंचा है । उसी तरह फरवरी 2025 तक, इस

योजना के अंतर्गत स्थापना के बाद से 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का वितरण सीधे किसानों के खाते में वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना छोटे और सीमांत किसानों की त्रासदी यह है कि उनके पास बुढ़ापे के लिए बिलकुल भी बचत नहीं हो पाती है। जब तक उनके शरीर में शक्ति है, परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं और पारिश्रमिक पाते हैं। उससे उनकी रोटि चलती है। लेकिन जब 60 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं और शरीर शीर्ण हो जाता है, वे काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, श्रम नहीं कर सकते हैं तो रोटि के लिए मोहताज हो जाते हैं। ऐसे किसानों के लिए सरकार ने किसान पेंशन योजना लागू की है। साथ ही किसानों को बुढ़ापे में पेंशन दी जाए, इसको सुनिश्चित किया। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को तीन हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम का टारगेट पहले तीन वर्ष के दौरान पांच करोड़ लाभार्थियों को इसके अंतर्गत लाना है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी स्कीम है, जिसमें शामिल होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष की है। यह पेंशन योजना केवल खेती करने वालों के लिए ही नहीं, अपितु कृषि पर आधारित जो मजदूर हैं, जिनकी रोजी कृषि के माध्यम से चलती है, अब उनके लिए भी लागू की जाएगी, इसके लिए उनको बधाई।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के अंतर्गत 2025 तक देशभर के 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है, जिसमें 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल हैं। इसमें 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पीएम-किसान योजना ने देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

ऐसे किसान जो सीमांत हैं, लघु हैं, डेढ़ एकड़, दो एकड़, ढाई एकड़ जोतने वाले हैं, जब फसल का समय आता था, तो निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं पूंजी के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, पानी चलाने के लिए किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ता था, सूद देना पड़ता था। उत्पादन का लाभ पाने के बाद वह पैसा उसी सूद और कर्ज में चला जाता था, फिर किसान खाली हाथ हो जाता था, लेकिन यह 6 हजार रुपये की पूंजी उनको मोहताज नहीं करेगी कि किसी से कर्ज मांगें। किसान इन रुपयों से बीज खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे और छोटे किसानों के लिए यह पूंजी पर्याप्त होगी और

उससे जब लाभ होगा तो पूरा का पूरा लाभ उनको होगा और कुछ लोग कहते हैं कि दोगुना लाभ कैसे होगा? इसी में से दोगुना लाभ होगा । पूंजी सरकार की, उत्पादन का लाभ किसान को, उसको लाभ निश्चित होगा । हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है और किसानों के लिए ई-नाम जैसी योजनाओं को लागू किया गया है । आज देश के किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता के संकट से मुक्ति मिल गयी है । हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । हम उनकी आय बढ़ाने, उनकी लागत कम करने और उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ।

महाराष्ट्र राज्य के कृषि परिदृश्य पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं । महाराष्ट्र राज्य भारत के प्रमुख कृषि राज्यों में से एक है, जो कपास, गन्ना, सोयाबीन और अंगूर जैसी फसलों का प्रमुख उत्पादक है । हालांकि, राज्य को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अनियमित वर्षा, सूखा और अत्यधिक गर्मी के कारण फसलों की हो रही हानि की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है । महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या है, जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है उस तरफ भी सरकार ध्यान देंगी ऐसा मुझे विश्वास है । साथ ही महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ।

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The Budget 2025-26 paves the way for a "Viksit Bharat - Developed India" The main focus of this Budget has been tax reforms, agriculture, tourism, and strengthening infrastructure, development rural and mountain regions.

The Budget not only continues with the highest Capital Expenditure (CapEx) ever but also takes radical steps towards energizing domestic demands. Our Government is transforming the agricultural sector fundamentally. This year, our Government has allocated a record Rs.1.37 lakh crore for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare.

This year, our Government, under the leadership of PM Modi ji and Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chouhan ji, is prioritizing several key initiatives. The PM Dhan Dhanya Krishi Yojana aims to target 100 districts with low productivity and transform them into high productivity areas. Additionally, the National Mission on High Yielding Seeds will ensure the commercial availability of more than 100 seed varieties. To support farmers, the Enhanced Credit Limit under the Kisan Credit Card will increase the loan limit to Rs.5 lakh, providing working capital to 7.7 crore farmers. There will also be a focus on horticulture through a comprehensive program for the promotion, efficient supply, and processing of fruits and vegetables.

Furthermore, a new Mission on Aatmanirbharta in Pulses will ensure self-sufficiency in this essential crop. To bolster these efforts, a new urea plant will be established in Assam with an annual capacity of 12.7 lakh tonnes.

Enhanced Formal Credits ? Under the leadership of PM Modi ji, the financial security of people in our nation, especially in rural regions, has increased manifold. In the financial year 2013-14, formal institutional credit for farmers was at 64 per cent, while non-institutional credit stood at 36 per cent. Over the past 10 years, this has shifted significantly, with formal institutional credit rising to 75 per cent and non-institutional credit decreasing to 25 per cent. Today, more and more farmers are connecting with the formal financial sector, thanks to the JAM (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) Trinity initiated by PM Modi ji. As a result, fewer farmers are being exploited by money lenders, which is a testament to the inclusive policies of our Government.

The Government, under the leadership of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, is providing a platform for exporting products from

interior regions like Darjeeling to the world market. Our Darjeeling hills, Terai, and Dooars region possess immense potential to become an export hub for horticultural products, including tea, orange, pineapple, strawberry, cardamom, ginger, bananas, potatoes, and a remarkable range of flowers.

However, the lack of support from the West Bengal Government towards agriculture in our region has left our export potential untapped. I am taking this opportunity to highlight the urgent needs of farmers in my Darjeeling Lok Sabha constituency.

The development of irrigation facilities in West Bengal is crucial, as the region's agriculture heavily relies on natural rains and available water sources. The North Bengal districts of Darjeeling, Kalimpong, Alipurduars, and Jalpaiguri face an acute water deficit for agricultural purposes, making their entire agricultural system dependent on rainwater. This lack of irrigation facilities leads to significant crop losses for farmers, particularly between September and April, when drought-like conditions prevail.

Therefore, I urge the Central Government to allocate funding for these four districts to conserve existing water-shade areas, develop agricultural irrigation infrastructure, and implement modern irrigation practices such as drip irrigation as well as the renewal of traditional springs and water bodies.

The establishment of a Centre of Excellence for Horticulture and Floriculture in Kalimpong is crucial, as the Darjeeling hills, Terai, and Dooars regions are hubs of horticulture and floriculture in West Bengal. Yet nothing has been done to provide fruit growers with improved technology, knowledge and skills regarding modern fruit farming. A Centre of Excellence for Horticulture and Floriculture would enable these

growers to cultivate better varieties of fruits, such as Mandari Orange, Plum, Pears, Pineapple, Litchi, and Passion Fruit, as well as flowers like Gladioli, Orchids, Cacti, Amaryllis, Anthuriums, and Roses, ultimately enhancing their productivity. I had previously requested the establishment of this Centre, and I was informed that the proposal has been forwarded to the State Government for inclusion in the Annual Action Plan (AAP). However, I am still awaiting a response from the Ministry regarding this matter.

The inclusion of tea workers under the Kisan Samman Nidhi would be a significant step towards recognizing their contributions and providing them with financial support. Even though the tea garden workers do not get paid proper or do not get any facilities, they are counted as "industrial workers". Hence, they are deprived of many Central and State Govt Schemes, like Kisan Samman Nidhi Yojana. The tea workers do not have right to land, so they cannot avail benefits of PM Awas Yojana. I urge the Government that the tea workers should be included in the Kisan Samman Nidhi Yojana. They too are farmers

Revival of potato seed farms is another long pending demand of the people of my constituency. Prior to the 1990s, Darjeeling used to be a hub of potatoes not only in India, but internationally. There were multiple potato seed farms that grew, conserved and experimented with potato seeds from all across the world. Over 1200 varieties of potatoes, including both original and hybrid, were kept in seed form in these seed farms and exported internationally.

Tragically after 1990s, the Government of West Bengal completely abdicated their responsibilities and these potato seed farms were left fallow. These seed farms can be revived, not only for potatoes but also for other fruits and vegetables.

Then, the Government should decide a Minimum Support Price for ginger and cardamom crops. In the mountain regions, farming is very difficult and due to geographic conditions two of the major crops from Darjeeling and Kalimpong are cardamom and ginger. Yet these two crops do not get Minimum Support Price. Providing MSP support to these two crops will help the farmers from the region to regain their confidence and also encourage youths to continue growing these crops in their traditional farms.

Support to Mandarin Orange and Iskus Farmers is the need of the hour. In Darjeeling and Kalimpong region, we produce the best Mandarin Orange and Iskus, also known as Chayote or squash. In 2023, the Central Government had helped in exporting our oranges to Bahrain. However, in the past few years, the production of Mandarin Oranges has declined by near 80 per cent. Despite such a massive fall, there is not enough focus on finding sustainable solutions to support the orange farmers.

Similarly, Iskus/ Chayote is the best food for diabetic patients. However, not much has been done to promote this versatile vegetable that can cater to every taste bud. I am requesting the Ministry to kindly take active steps to provide support to Mandarin Orange farmers from our region. I also request the Ministry to examine the export potential of Iskus and take necessary action towards their promotion and international sale.

Support to pineapple farmers ? Phansidewa, Naxalbari, Khoribari and nearby places in Darjeeling Terai produce some of the best pineapples in India. In North Bengal, pineapple farming is done in 20000 hectors and supports the livelihood of close to 10 lakh individuals directly or indirectly. In Phansidewa block alone, close to 60,000 individuals are

dependent on pineapple farming for their subsistence. Despite this, the West Bengal Government has failed to provide any support to the pineapple farmers.

I, therefore, request the Ministry to kindly extend support to the pineapple farmers for finding national and international markets through the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMC).

The effective implementation of eNAM, along with enhanced digital marketing initiatives, is crucial for achieving better outcomes. Majority of the farmers in West Bengal are yet to derive the benefits of eNam and Digital Marketing Initiatives started by the Government of India. Lakhs of computers, hardware and requisite manpower are severely lacking in the Kisan Mandis of West Bengal.

The development of international marketing avenues is essential for expanding business reach and enhancing global presence. Darjeeling is the only district in India that shares border with four countries, namely, Nepal, Bhutan, China and Bangladesh. It is also the gateway to North East India and South East Asian countries.

Being an important agricultural zone, that produces the world's famous Darjeeling tea and oranges, Kalimpong flowers, Phansidewa Pineapples - agri-export from here has a huge potential to grow. However, due to the lack of proper marketing initiatives, and support to farmers to develop value chain, the farmers here continue to be deprived of the benefits of markets that are readily available internationally. Focus on developing proper marketing avenues for farm produce from this region will help the farmers augment their income and improve their living standards.

The establishment of the Krishi Vigyan Kendra in Darjeeling aims to enhance agricultural practices and support local farmers. The district of Darjeeling despite being an agricultural district is deprived of a Krishi Vigyan Kendra (KVK). While assurances regarding the establishment of a KVK have been given in the past, it is yet to manifest. I, therefore, request for KVK Darjeeling to be established without any further delay.

Similar subsidies as are given to the North East Region should be given to my region. The North Bengal districts of Darjeeling, Kalimpong, Alipurduar and Jalpaiguri are geographically contingent to the North East region. The farmers, livestock rearers, and fishermen from these districts face similar problems as those from the North East States. There is lack of infrastructure, transportation, connectivity, modern means of farming etc. Therefore, there is a strong case of these districts to be brought under the same tax and subsidies/ grants regime as the rest of North East states. This will go a long way in ensuring conservation of farm-based livelihood system. It will also ensure great investment in agriculture sector in the north Bengal region.

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा) : मैं इस सदन के माध्यम से देश के अन्नदाताओं को नमन करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। हमारे देश का किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की रीढ़ है, और उनकी तरक्की के बिना भारत की तरक्की की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

आज यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम स्वरूप, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) जैसी ऐतिहासिक योजना लागू की गई, जिसने किसानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया है।

यदि हम पीछे मुड़कर देखें, तो पूर्ववर्ती सरकारों ने किसानों की समस्याओं को केवल आंकड़ों और घोषणाओं तक सीमित रखा। किसानों की आत्महत्याएँ होती रहीं, उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिला, और वे कर्ज के बोझ तले दबते चले गए।

किसानों विकास के लिए बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ ।

इसके विपरीत, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं । PM-KISAN योजना इसी संकल्प का सशक्त प्रमाण है ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत सरकार देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । इस योजना के अंतर्गत अब तक ₹3.7 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में सीधे भेजी जा चुकी है ।

यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना बन चुकी है और छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर रही है । यह सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है ।

एनडीए सरकार की किसान-हितैषी सोच को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए PM-KISAN योजना का बजट ₹63,500 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जो कि 2024-25 के ₹60,000 करोड़ से 5.8% अधिक है । यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए कितनी समर्पित है ।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने केवल वित्तीय सहायता तक सीमित न रहते हुए, कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं:

साँइल हेल्थ कार्ड योजना - किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी देकर उपज बढ़ाने में सहायता की जा रही है ।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - "हर खेत को पानी" के संकल्प के तहत किसानों को सिंचाई की सुविधाएँ दी जा रही हैं ।

किसान उत्पादक संगठन (FPOs) ? किसानों को संगठित कर उन्हें बाज़ार में अधिक लाभ दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है ।

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डिजिटल क्रांति लाई जा रही है । कृषि को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर डिजिटल क्रांति लाई जा रही है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देने के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है ।

आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि ऊर्जादाता और समृद्धिदाता भी बन रहा है । PM-KISAN जैसी योजनाएँ किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं ।

हमारा स्पष्ट संकल्प है कि देश का हर किसान खुशहाल हो, उसकी मेहनत का पूरा सम्मान हो, और कृषि क्षेत्र भारत की आर्थिक रीढ़ बना रहे । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतः समर्पित है और इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा में गंगा नदी के समीप खेती करने वाले किसानों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ । इसके अलावा, फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को समय पर मुआवजा न मिलने की समस्या का समाधान किया जाए ।

एवं राज्य सरकार को गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करे किसानों की आय में वृद्धि हो सके किसान आत्म निर्भर हो सके । जय जवान, जय किसान!

श्री खगेन मुर्मु (मालदाहा उत्तर) : मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी दूरदर्शी नीतियों ने देश के किसानों की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार किया है । मैं हमारे आदरणीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए ऐतिहासिक बजट आवंटन इस सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का प्रमाण है ।

मालदाहा उत्तर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां मखाना, आम, आलू धान, गेहूं, सरसों, मक्का, जैसी महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन उचित सुविधाओं के अभाव में

हमारे किसान इन फसलों का सम्पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मैं इस पावन सदन के माध्यम से निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत करता हूँ।

मालदा में मखाना की खेती तेजी से बढ़ रही है, लेकिन किसानों को प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और मूल्य संवर्धन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः "राष्ट्रीय मखाना मिशन" के तहत मालदा को शामिल किया जाए और इसके लिए विशेष अनुदान दिया जाए।

मालदा का आम और लीची पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन भंडारण की समुचित व्यवस्था न होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः मालदा उत्तर में "मालदा आम एवं लीची कोल्ड स्टोरेज पार्क" की स्थापना की जाए, जिससे किसानों को फसल के उचित दाम मिल सकें।

मालदा में आलू उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है, लेकिन बाजार में कीमतों की अस्थिरता के कारण किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है। अतः "आलू मूल्य स्थिरीकरण कोष" की स्थापना की जाए और आलू से जुड़े प्रोसेसिंग यूनिट (चिप्स, पाउडर, स्टार्च) के लिए विशेष योजना लाई जाए।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मालदा के अधिक किसानों को जोड़ा जाए और उनके बैंक खातों में समय पर महायता राशि भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मालदा के कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए "मालदा एग्री-एक्सपोर्ट हब" की स्थापना की जाए, जिससे स्थानीय किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जा सके।

मालदा उत्तर के किसानों को जल संकट से बचाने के लिए "मालदा माइक्रो-इर्रिगेशन योजना" लाई जाए, जिससे ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा सके।

मोदी सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाओं ने किसानों को सशक्त बनाया है। मैं

पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ और सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरी इन मांगों को गंभीरता में लिया जाए।

"जय किसान, जय बंगाल !"

भारत माता की जय ।

SHRI YADUVEER WADIYAR (MYSORE): I support the Demand for Grants for the Agriculture Ministry. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, numerous initiatives have been launched with the goal of modernising agriculture, improving productivity, ensuring fair prices for farmers, and promoting sustainability.

Our agricultural sector is a pillar of our economy and our society. The demand for grants for agriculture for the year 2025-26 is not just about numbers; it is about securing a future where our farmers are empowered, resilient, and prosperous. It is about ensuring that the land that has sustained us for generations continues to thrive for future generations.

The need for investment in agriculture has never been more pressing. If the vision of our Prime Minister, that of Viksit Bharat, i.e. the complete economic development of India, is to be fully realised, there is a need to ensure that our farmers are supported, our ecosystems are protected, and our agricultural industry remains competitive in a rapidly changing global economy. The demand for grants for agriculture for 2025-26 is a crucial step toward achieving these goals.

My colleagues have highlighted the many benefits that the Prime Minister's policies and schemes have ensured for Indians, given the limited time, I would like to speak to policies that particularly benefit my state of Karnataka.

As far as climate resilience and water management is concerned, our country, particularly my State of Karnataka, and my constituency has

faced severe climate challenges over the years. Erratic rainfall, droughts, and floods have significantly impacted the agricultural production in our state. To address these challenges, it is essential that we invest in climate-resilient farming practices, including better water management systems, rainwater harvesting, and the adoption of drought-resistant crops.

The demand for grants includes funding for the implementation of efficient irrigation systems like drip and sprinkler irrigation, which will ensure that our farmers are not solely dependent on the unpredictable monsoon. My State of Karnataka also has vast potential for rainwater harvesting. and it is time we enhance our efforts in this area, ensuring sustainable water use for agriculture.

As far as infrastructure development and rural connectivity is concerned, the development of rural infrastructure is another critical area of focus. Farmers need access to better roads, storage facilities, and cold chains to prevent post-harvest losses and improve market linkages. The demand for grants will support the construction of rural roads and the development of integrated market systems where farmers can sell their produce directly to consumers. eliminating intermediaries and ensuring fair prices.

Additionally, the establishment of more warehouses, cold storage units, and value-added processing units will help farmers store their crops during surplus seasons and sell them at better prices during periods of demand.

As far as technology and innovation in agriculture is concerned, in today's rapidly evolving world, technology is key to ensure that agriculture is adapting to changing circumstances. We must prioritise the adoption of smart farming practices, such as precision agriculture, use of

drones for crop monitoring, and the incorporation of AI-driven solutions to monitor soil health and predict crop yields.

To empower our farmers, we need to increase funding for agricultural research and extension services, which will help farmers access knowledge on the best practices, pest control, and disease management. Providing grants for setting up agricultural technology centres will allow us to extend these innovations to our farmers, improving productivity and sustainability

As far as financial support for farmers is concerned, our farmers face significant financial challenges due to high input costs, fluctuating market prices, and climate-induced risks. We must ensure that our farmers have access to affordable credit and insurance to safeguard them from such vulnerabilities. The demand for grants will include funds for extending subsidies on agricultural loans, promoting crop insurance schemes, and providing grants for organic farming initiatives, which offer high returns and reduce dependency on chemicals.

Some of the landmark schemes given by the Modi-led Governments need to be highlighted as they have been the engines that have powered the revolution in the agrarian sector.

As far as Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) is concerned, one of the most significant steps taken by the Government to support our farmers is the launch of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme. This initiative provides direct financial assistance of Rs. 6,000 per year to small and marginal farmers. It aims to ease the financial burden on farmers, especially in times of distress, ensuring they have access to working capital for their farming activities. By providing this support directly to the bank accounts of farmers, PM-

KISAN has played a pivotal role in ensuring that farmers receive timely financial aid.

As far as PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) is concerned, agriculture is highly dependent on weather conditions, and crop failure due to natural calamities has been a recurring challenge. In response, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was introduced to protect farmers against such risks. This crop insurance scheme provides affordable insurance coverage, offering financial protection to farmers in the event of crop loss. With a record number of farmers enrolled, the scheme has proven to be a safety net for millions of farmers, helping them recover from the shocks of unpredictable weather patterns.

As far as Soil Health Management and National Mission on Sustainable Agriculture is concerned, the Modi Government has placed a strong emphasis on the sustainability of agriculture. Under the National Mission on Sustainable Agriculture (NMSA), initiatives have been undertaken to promote organic farming, water-efficient practices, and integrated nutrient management. Through Soil Health Management, the Government has encouraged farmers to use organic and balanced fertilisers, ensuring that soil health is maintained and agricultural productivity remains sustainable.

India, and in particular, my State of Karnataka has many diverse agro-climatic zones, from dry land farming areas to irrigated regions, all of which require tailored approaches to ensure sustainable agricultural practices. The demand for grants will prioritise soil health management through organic farming, agroforestry, and sustainable land-use practices.

Investing in soil health will reduce the dependency on chemical fertilisers, ensuring that our soil remains fertile for generations to come. Moreover,

promoting organic farming through grants will not only protect the environment but also help farmers access premium markets for organic produce.

Lastly, I would like to, with your permissions, add a few specific demands to the agriculture ministry with regards to my constituency.

Sir, Mysore district is famous for growing tobacco, but the tobacco farmers are not recognised under Fasal Bhima Yojana. I request the ministry to provide them this privilege, so that they are given the benefits that other farmers are given.

Secondly, given the fact that tobacco is a sin good, I would like to ask that the Ministry have a specific plan to start research or pilot projects towards providing alternate crops or alternate livelihood for those farmers who are farming crops such as tobacco, which are used for the production of sin goods.

Lastly, I would like to thank the Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, on this occasion, for removing the GST on black pepper for the agriculturist. It has benefited many farmers in the region of Kodagu and in Karnataka. This shows the tremendous concern our Government and the Prime Minister have for our farmers.

Agriculture is the backbone of our country's economy, with a significant population of our country dependent on it for their livelihood. The Demand for Grants for 25-26 ensures that there is a bright future for our agricultural sector.

I urge all Members of this House to support the Demand for Grants, as this is an investment in our agricultural future and the well-being of millions of farmers across the State.

Thank you.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): Thank you for giving me this opportunity to express my views on the Demands for Grants presented by our hon. Agriculture and Farmers Welfare Minister, Shri Shivraj Singh Chouhan ji. Before delving into the details, I must first commend this government for its unwavering commitment to our nation's agriculture sector. Under the visionary leadership of our Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we have witnessed remarkable achievements in agricultural productivity and sustainability. I take immense pride in being part of an administration that has spearheaded transformative reforms to drive growth in this vital sector of our nation.

Agriculture is the backbone of our economy. According to the Economic Survey, the agriculture sector contributes approximately 16 per cent of the country's GDP for FY24 at current prices and supports about 46.1 per cent of the population. Guided by the principles of "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas," this Government has undertaken many initiatives to empower our 'Annadatas, enhance food security, and modernize the agricultural sector of our nation. Over the years, our foodgrain production has seen remarkable growth, rising from 252 million tonnes in 2014-15 to an estimated 332.3 million tonnes in 2023-24. To support our farmers financial needs, this government launched the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme to provide direct income support to farmers. So far, over Rs.3.46 lakh crore has been disbursed to more than 11 crore farmers, empowering them with financial stability without any middlemen involved. In my constituency, 1.77 lakh farmers have benefited, with a total amount of Rs.859.43 crore disbursed to support their agricultural needs.

To further support our farmers, the National Mission on Oilseeds is being implemented to increase domestic production and reduce import dependence. Additionally, in a push towards sustainable farming, this

government actively promotes Natural Farming and ensures farmers have access to affordable fertilizers. The e-NAM initiative has integrated 1,410 mandis across the nation, registering 1.79 crore farmers and 2.63 lakh traders. As of December 2024, trade worth an impressive Rs. 4.01 lakh crore has been facilitated which has boosted market access and the incomes of our farmers. The promotional efforts for millets have increased production while institutional credit expansion and agricultural research and development investments continue to transform the sector.

As emphasized by our hon. Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji, agriculture is first engine of India's development journey. This commitment can be seen in the sixfold increase in the Union agriculture budget, which has grown from Rs. 21,933.50 crore in 2013-14 to Rs. 1,37,757 crore in 2025-26. This just goes to show this Government's determination to empower our farmers and enhance the agricultural sector.

A commendable step in this direction is the introduction of the Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana, which will focus on uplifting 1.7 crore farmers across 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below-average credit access. Furthering the vision for self-reliance in the agricultural sector, the launch of the National Mission on High-Yielding Seeds will ensure access to high-yielding, pest-resistant, and climate-resilient seed varieties. Moreover, the establishment of a second National Gene Bank with 10 lakh germplasm lines will provide critical conservation support for future food security.

The Mission for Cotton Productivity is another commendable initiative that will enhance sustainability, promote extra-long staple cotton varieties, increase cotton farmers' incomes, and ensure a steady supply of quality cotton for the nation's traditional textile sector. Moreover, the

increase of loan limits from Rs. 3 lakhs to Rs. 5 lakhs under the Modified Interest Subvention Scheme, the establishment of a Makhana Board in Bihar, the setting up of a 12.7 lakh metric ton Urea Plant in Assam, and the introduction of a framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and High Seas are all strategic initiatives that will strengthen India's agricultural foundation and ensure long-term growth for our farmers.

Over the past decade, the remarkable transformation of our agriculture sector is undeniable and stands as clear evidence of our nation's sustained progress. From soil health cards and the financial inclusion of farmers to the use of drones for pesticide and fertilizer spraying, every initiative introduced has been aimed at boosting agricultural resilience. Building on this strong foundation, this Government has laid out comprehensive and future-ready initiatives to boost agricultural productivity and uplift the lives of our *Annadata*s. With a clear focus on modernization, improved credit access, and the empowerment of women in agriculture, along with digital integration and climate-resilient practices, we are on the way to a self-reliant agricultural economy, bringing us closer to the vision of a Viksit Bharat.

With that, I support the Demands for Grants for Agriculture and Farmers Welfare. Thank you!

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): Thank you for giving me the opportunity to support the Demand for Grants for the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

Agriculture is the lifeline of our nation, sustaining nearly 58 per cent of India's population and contributing significantly to our economy. It is the hard work of our farmers that feeds the country, drives rural employment, and ensures food security for 1.4 billion Indians. This

government, under the visionary leadership of Prime Minister, Sri Narendra Modi Ji, has worked tirelessly to strengthen India's agricultural sector, ensuring farmers receive the dignity, respect, and prosperity they deserve.

In this budget, our government has allocated Rs.1,37,757 crore to the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, which is 2.7 per cent of the Union Budget. Before 2014, Indian agriculture faced multiple challenges. There was no integrated vision for the sector. Farmers struggled with inconsistent policies on subsidies, procurement, and pricing. Only 42 per cent of the total cultivated land was under irrigation, leaving the rest dependent on unpredictable monsoons. Farmers relied on informal moneylenders due to restricted access to institutional credit, pushing them into cycles of debt. Middlemen-controlled mandis led to unfair pricing and exploitation of small farmers. Crop loss due to weather shocks or pest infestations often pushed farmers into financial ruin. Lack of access to modern techniques and scientific advancements limited productivity and income growth.

The Modi Government has implemented several flagship schemes to revolutionise Indian agriculture, empowering farmers with financial stability, modern technology, better infrastructure, and increased productivity. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme was launched in 2019 to provide direct income support to small and marginal farmers. Over 11.8 crore farmers across India receive an annual benefit of 26,000 in three instalments. In Karnataka, 55 lakh farmers have benefited, receiving direct transfers into their bank accounts, ensuring financial security and timely investment in inputs. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was launched in 2016. This crop insurance scheme protects farmers from yield losses due to natural disasters. Over 42 crore farmers have been insured since inception, and claims worth Rs.1.4 lakh crore

have been paid. In Karnataka, in 2022-23 alone, 16.3 lakh farmers in the State availed crop insurance, with claims exceeding Rs.3,500 crore. Soil Health Card Scheme was introduced in 2015 to promote balanced fertiliser use and soil conservation. Over 23 crore Soil Health Cards have been distributed, improving soil productivity. In Karnataka, more than 1.5 crore farmers have received soil health cards, leading to a 20-30 per cent reduction in chemical fertilizer usage and higher yields. Kisan Credit Card loans provide easy credit to farmers at four per cent interest with government support. Over eight crore farmers have received Rs.24 lakh crore in loans. In Karnataka, 42 lakh farmers have availed credit under this scheme, significantly reducing reliance on informal lenders. E-National Agriculture Market was launched in 2016. E-NAM integrates wholesale mandis across the country into a single online market. Over 1,361 mandis in 23 States have been linked, enabling 1.75 crore farmers to sell their produce transparently. In Karnataka, 65 major mandis, including those in Mangalore, Hassan, and Chikkamagaluru, are connected to e-NAM, ensuring fair pricing for farmers.

The Government has introduced several new initiatives to enhance agricultural productivity and farmers' income. PM Dhan Dhaanya Krishi Yojana aims to benefit 1.7 crore farmers in districts with low productivity, improving irrigation, credit access, and cropping intensity. National Mission on High Yielding Seeds has been allocated Rs.100 crore. This mission will focus on developing climate-resilient and pest-resistant seeds. By increased KCC Loan Limit, farmers can now avail up to Rs.25 lakh under the Kisan Credit Card, up from the previous limit of Rs.3 lakh.

The coastal region of Dakshina Kannada is a vital agricultural hub, where thousands of farmers depend on their land for sustenance and livelihood. However, they face distinct challenges that threaten their productivity and income, requiring targeted intervention and urgent support. Areca nut is

a major cash crop in Dakshina Kannada, supporting over 2 lakh farmers. However, the spread of Yellow Leaf Disease (YLD) and other issues threatens productivity and farmer incomes. A dedicated research centre in Karnataka will help develop disease-resistant varieties and improved cultivation techniques and give way for Indian led research based on local data and conditions. Many areca nut farmers rely solely on one crop, increasing vulnerability to market fluctuations and disease outbreaks. Recent visits from the Central Coffee Research Institute have confirmed the potential of coffee as a viable crop in the region, especially in areas with favourable climatic conditions. However, institutional support is lacking compared to neighboring regions like Chikkamagaluru and Kodagu, which have received strong backing from the government and the Coffee Board. While farmers have taken the initiative through various collaborations, they are still in need of technical guidance, subsidies, and access to quality saplings. Research studies have also suggested that coffee could be integrated with existing areca nut plantations, offering a sustainable inter-crop option. The Government should introduce incentives, technical training, and financial support for coffee plantation expansion in Dakshina Kannada. There should be increased allocation of PM-KISAN funds and enhanced subsidy schemes for small and marginal farmers in coastal Karnataka. Expand insurance coverage under PMFBY to cover cash crops like areca nut and coconut.

The future of Indian agriculture is bright under the leadership of Sri Narendra Modi ji. From income support to crop insurance, irrigation projects to digital marketplaces, and scientific advancements to credit expansion, every step taken in the last ten years has been farmer-centric. The 2025-26 Budget takes this commitment further, ensuring that agriculture remains profitable, sustainable, and resilient. However, we must also address regional needs. I urge the Government to support the

farmers of Dakshina Kannada with financial and technical assistance. The Government should establish the Areca Nut Research Centre to tackle Yellow Leaf Disease. It should promote coffee cultivation to help diversify and stabilize farm incomes. By standing with our farmers today, we secure the food security, economic stability, and prosperity of our nation tomorrow. Jai Jawan, Jai Kisan! Thank you.

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): Thank you for giving me an opportunity to express my views on the supplementary demand for grants for the Ministry of Agriculture.

Our farmers are working tirelessly to feed our nation. They are the backbone of our economy, and it is our duty to ensure that they receive the necessary support from us to survive and thrive so that our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji's dream of Viksit Bharat can be achieved.

Supplementary demand for grants provides additional funds to various programs aimed at promoting agricultural growth, improving farmer welfare, and enhancing food security.

The increased allocation towards the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), which provides insurance coverage to farmers against crop losses. The allocation towards the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) is also worth appreciation. The scheme provides financial assistance to small and marginal farmers, helping them to meet their agricultural expenses and improve their livelihoods.

Focus on organic farming and agricultural research is also commendable. This will help to promote sustainable agriculture practices, improve crop productivity, and enhance farmer. Issues of

agricultural debt, water scarcity, and climate change require immediate attention and action.

This year's budget for agriculture is Rs. 1.37 lakh crore, a four percent increase from the previous year. The agriculture sector has been given preference by our hon. Prime Minister as well as our Agriculture Minister as the four basis for development is the GYAN, Garib Yuva *Annadata* aur *Nari* where our our Annadatas are given preference and have been given importance for the first time where they are considered basic for our growth of our country. Different sectors have been given importance such as fertiliser subsidies - 1.84 trillion has been allocated for fertiliser subsidies where 1.9 has been specially allocated for for urea subsidies.

Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana aims to cover 100 districts with low productivity and moderate crop intensity which has never been done in so many years.

National mission on high yielding seeds- aiming to improve the quality and availability of high yielding pest resistant and climate resilient seeds.

I come from the constituency of Kalahandi in Odisha once known worldwide for the famine, my grandfather in law maharaja PK Deo got the Indravati dam made and then my father in-law late Bikram Keshari Deo made the ret project and added more to the irrigation while my husband Arka Keshari Deo started many mega lift irrigation projects and today thanks to our hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji and our honourable Agriculture Minister and their schemes, today Kalahandi is the second highest paddy producing district of Odisha. With our new double engine Sarkar we are surely aiming to become the number one paddy producing district in Odisha for which our people have a lot of hope and expectations from our government, the only government that

works for people and not self. There are some demands for my constituency of Kalahandi for my districts of Kalahandi and Nuapada.

Please look into the execution of the seven numbers of irrigation projects on Udanti and lower Indra reservoir that will provide water to 2500 hectares of land.

The Kamal irrigation project or Moter irrigation project which will benefit 7500 hectare.

Utter Roul irrigation project over the river Uttei and Roul and will irrigate 6000 hectares of land

Lower Udanti irrigation project over Udanti, will irrigate 12000 hectare.

Upper Udanti barrage which will irrigate 10000 hectares of land

Upper Jonk project at Nuapada which will benefit 9200 he carafes of land.

I would also request that as we have seen with our last government of Odisha the hurdles and problems faced by our farmers during collection season and no help was given to them by the earlier government in Odisha which only exploited for last 25 years we are hoping support and help of our government, the Odisha government will be able to help the farmers by making Mandis more farmer friendly and making sure most Mandi's get covered as rains spoil the paddy which leads to huge problems.

Hoping that our irrigation sector is properly looked after by our government has it will help agriculture department and increase production and help the farmers improve their livelihood.

To conclude I totally support the supplementary demand for grants for the Ministry of Agriculture. I must show our gratitude to the

government which has only one main aim to promote agricultural growth, improve farmer welfare, and enhance security. Our Odisha government needs your blessings, support and cooperation to enhance and increase farmers income, hoping that our dream will be fulfilled by our new double engine Sarkar. our honourable prime minister has always given importance to Odisha and the hopes of people of Odisha is very high from our government.

(ends)

MS. BANSURI SWARAJ (NEW DELHI): Hon. Speaker Sir, I rise today to strongly support the Demands for Grants for the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and to commend the dynamic leadership of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the Government of India for their relentless focus on empowering our farmers, ensuring food security, and transforming Indian agriculture into a more sustainable, resilient, and technologically-advanced sector.

Agriculture is the backbone of our nation, employing nearly 46 per cent of our workforce and sustaining millions of lives. This year, the Government has allocated Rs. 1,37,757 crore to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. This allocation marks a significant step toward strengthening the welfare of farmers, enhancing agricultural productivity, and advancing our agricultural policies to meet both national and global challenges. The focus on a farmer-centric Budget demonstrates Modi Government's commitment to ensuring that India's agricultural ecosystem is not only efficient but also resilient in the face of emerging challenges.

A key highlight of this Budget is the continued success of the PM-Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), which provides Rs. 6,000 annually to over 12 crore farmers. With Rs. 63,500 crore allocated to PM-KISAN this year,

it ensures that farmers continue to receive timely financial assistance. Since its inception, this initiative has disbursed Rs. 3.24 lakh crore directly into the bank accounts of farmers, creating a positive impact on rural livelihoods and economic sustainability.

The Government has also substantially increased investments in agricultural growth programmes, with Rs. 8,500 crore allocated to the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), a 42 per cent increase from last year. Additionally, the Krishionnati Yojana has received Rs. 8,000 crore, furthering the cause of agricultural modernisation, research-driven innovations, and enhancing the overall productivity of our farms.

One of the cornerstones of our agricultural development is ensuring crop protection and risk management, and the Government has shown exceptional foresight in strengthening these areas. The PM Fasal Bima Yojana has been allocated Rs. 12,242 crore to protect crops from unpredictable weather patterns, ensuring that farmers receive timely compensation for their losses. With over 68 crore farmer applications insured, this scheme provides security to farmers across the country, safeguarding an area of 4,803 lakh hectares of crops.

The Modi Government is equally committed to ensuring that India achieves self-sufficiency in food production. The launch of the National Mission on High-Yielding Seeds with an allocation of Rs. 100 crore aims to develop more climate-resilient and pest-resistant seed varieties, improving the sustainability of farming practices. Furthermore, with Rs. 1,000 crore allocated to the Mission for Atmanirbharta in pulses, the Government is working towards reducing dependency on pulse imports and enhancing domestic production of crucial crops such as Tur, Urad, and Masoor. This will improve food security, stabilise prices, and increase farmers' incomes.

The importance of water in agriculture cannot be overstated, and this Government has been proactive in expanding irrigation and water conservation efforts. The Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) continues to receive robust funding, with the expanded micro-irrigation coverage benefiting over 48 lakh farmers. The Atal Bhujal Yojana has been allocated Rs. 8,500 crore this year to support ground water conservation in drought-prone areas, while the Per Drop More Crop initiative encourages efficient water use and reduces water wastage.

Our commitment to reducing post-harvest losses is evident in the Rs. 1,00,000 crore investment in the Agriculture Infrastructure Fund (AIF). This fund is being used to develop critical infrastructure such as warehouses, cold storage, and modern processing units. These investments will reduce wastage, ensure timely delivery to markets, and provide farmers with better pricing opportunities.

The Government has also recognised the importance of sustainable farming practices, and initiatives like the PM-PRANAM Scheme, are promoting balanced fertiliser use to reduce over-reliance on chemicals. Furthermore, the Soil Health Card Scheme, which has benefited 23.6 crore farmers, continues to provide guidance on soil fertility and crop-specific nutrient requirements, fostering long-term soil health.

The e-NAM platform has successfully linked 1,361 mandis, enabling farmers to directly connect with buyers, reducing middlemen and ensuring better price realisation. The Government has also committed Rs. 6,941 crore to the PM-AASHA scheme, which provides price support to oilseeds, pulses, and copra, ensuring that farmers get fair compensation for their produce.

However, we cannot ignore the increasing threat of climate change, which is having a profound impact on Indian agriculture. Unpredictable

weather patterns, rising temperatures, and extreme weather events are making farming increasingly challenging. In response, the Government must accelerate the adoption of climate-resilient agricultural practices, such as drought-resistant crops, precision farming, and efficient water management systems. It is critical that we support initiatives like the National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) and the promotion of organic and regenerative farming, which will help mitigate the adverse effects of climate change while creating new income opportunities for farmers.

As the Member of Parliament representing the vibrant New Delhi Constituency, I would also like to highlight the growing potential of urban farming and hydroponics in transforming our cities into more sustainable and self-sufficient environments. In a rapidly urbanising India, where space is limited, urban farming offers an innovative solution to boost local food production, reduce transportation costs, and minimise our environmental footprint.

New Delhi, with its population density and limited agricultural space, stands to benefit immensely from the integration of hydroponics and vertical farming systems. These methods use significantly less water compared to traditional farming and can produce high yields of vegetables and fruits in small spaces, such as rooftops and balconies. This not only contributes to urban food security but also promotes the efficient use of urban resources.

The Government has already begun recognising the importance of sustainable agriculture in cities. We must now accelerate the adoption of smart farming techniques such as hydroponics, aquaponics, and rooftop gardening. In New Delhi, we can create model projects in collaboration with local authorities, NGOs, and startups to establish hydroponics

systems in urban communities. These initiatives could also serve as learning centres for residents and farmers, encouraging the next generation to embrace modern farming methods.

By promoting urban farming and hydroponics, we can also create green spaces, enhance local biodiversity, and reduce the carbon footprint associated with the long-distance transportation of food. This is an important step toward building a more sustainable and resilient New Delhi, a city where every citizen has access to fresh and nutritious produce.

I urge the Government to consider further investments in promoting such urban agriculture initiatives, especially in metropolitan regions like New Delhi, where the population is rapidly growing and the need for innovative solutions to food security is becoming more pressing.

In conclusion, this Budget reflects Modi Government's steadfast commitment to securing the future of agriculture and the welfare of farmers. The allocations and schemes outlined are forward-thinking, comprehensive, and in line with the Prime Minister's vision of empowering farmers and modernising agriculture. I urge all Members to support the Demands for Grants for the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, as these investments will strengthen our rural economy, uplift the lives of millions of farmers, and ensure food security for our nation.

Jai Hind! Jai Bharat!

माननीय सभापति: श्री सी. पी. जोशी जी ।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, आज मैं देश के वर्ष 2025-26 के? (व्यवधान) ।

माननीय सभापति : आपको बोलने के लिए तीन मिनट का समय है, क्योंकि छः बजे गिलोटिन होना है और मंत्री जी को भी एक-सवा घंटा बोलना है ।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : मैं इसे टेबल कर देता हूँ । मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

माननीय सभापति : आप अपनी बात बोलिए ।

***m106 श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :** महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ । देश के वर्ष 2025-26 के बजट के ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्रालय अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद । साथ ही देश के प्रधानमंत्री जी व देश के वित्त मंत्री महोदया को भी धन्यवाद जिन्होंने देश के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रख कर इस बजट को देश के समक्ष प्रस्तुत किया है । विशेषकर किसानों का ध्यान बिन्दु गांव, गरीब व किसान पर केन्द्रित रहा है ।

हमारे देश की लगभग 60% आबादी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है । भाजपा के मूल चिंतन में ही कृषि और किसानों का कल्याण निहित है । जब भाजपा की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत जन संघ के माध्यम से शुरू हुई थी तब भी हमारा ध्येय वाक्य था- हर हाथ को काम और हर खेत को पानी ।

देश में जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं, उन प्रदेशों में कृषि सरकारों के मूल चिंतन में है अगर 90 के दशक के बाद के राज्य सरकारों का विकास दर और जीडीपी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो यह पता चलता है कि केवल भाजपा की राज्य सरकारें ही ऐसी हैं जहाँ निरंतर 10% से अधिक का कृषि विकास दर रहा है । भाजपा शासित राज्यों में कृषि विकास दर पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी है और राज्य के किसान खुशहाल हुए हैं जो यह बताने के लिए काफी है कि भाजपा कृषि विकास और किसानों के कल्याण के प्रति कितनी समर्पित है । - बीजेपी- पीएमजीएसवाई / फसल बीमा / केसीसी

कांग्रेस के शासनकाल में न तो कृषि के समुचित विकास पर ध्यान दिया गया, ना ही वैज्ञानिक पद्धति की कृषि योजनाओं को अमल में लाया और ना ही किसानों की भलाई के लिए ठोस कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई । कांग्रेस के शासन के समय फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की, कई यूरिया

कारखाने बंद हो गए, यूरिया का आयात करना पड़ा जिससे कालाबाजारी बढ़ी, पर इस समस्या के समाधान के लिए भी कोई उपाय नहीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में देश के गांवों और किसानों की क्षमता बढ़ी है ।

मोदी सरकार ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति) पर फोकस करके नीति निर्माण कर रही है । देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गरीब, युवा, किसान और नारी (ज्ञान) पर ध्यान का मंत्र दिया है ।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अनुसार किसान सशक्तिकरण सरकार के लिए प्राथमिकता है । इस पर अमल के जरिये ही देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है ।

हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है । हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ।

मोदी सरकार की प्राथमिकता एवं उपलब्धियां :

बीजेपी- पीएमजीएसवाई) फमल बीमा योजना) केसीसी / नदी जोड़ना - राजाभागीरथ

- > किसानों की आय बढ़ाना
- > खेती का खर्च कम करना
- > बीज से बाज़ार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएँ देना ।

किसान सम्मान निधि देश के 11 करोड़ किसान को डबल इंजन राजस्थान 6000+3000

बीते 6 वर्षों में रु 3.5 लाख करोड़ से अधिक की सम्मान राशि

UPA / NDA कृषि बजट बीते दस सालों में 5.26 गुना बढ़ोतरी ।

खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों की एमएसपी पर **50** फीसदी से भी अधिक वृद्धि

किसानों के लिए सस्ती दर पर **20** लाख करोड़ के ऋण की व्यवस्था

मोदी जी ने की किसान रेल की शुरुआत

स्वायल हेल्थ कार्ड - **23** करोड़ किसानों को

फसल बीमा योजना - **12** करोड़ किसानों को

मोदी जी ने मोटे अनाज, मिलेट्स, अन्न श्री को वैश्विक बनाया ।

पिछले साल इंटरनेशनल मिल्लेट्स ईयर घोषित होने से सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान के किसान को ।

राष्ट्रिय गोकुल मिशन

- बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट **3** से **5** लाख

फसल खराबा संसर में कानून बदला **50%** की जगह **33%** किया

- किसानों के लिए एक मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट हाउस ।
- किसानों को **270** रुपये प्रति बोरी के यूरिया ।
- पिछले **10** वर्षों में उर्वरकों पर दस लाख करोड़ से अधिक की सब्सिडी
- अनाज के एमएसपी पर पंद्रह लाख करोड़ रुपये खर्च ।
- नीम कोटेड यूरिया के पक्षधर है हमारे मोदी जी
- पीएम प्रणाम योजना से देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा ।

मोदीजी ने किसानों की आय के साधन बढ़ाए हैं

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, स्वीट रेवोल्यूशन (मधुमक्खी पालन),

इथेनॉल की खरीद तहत आय में बढ़ोतरी हुई है ।

दलहन और तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा

अबतक सबसे अधिक रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन

2016 से **2024** तक किसानों को फसल बीमा के रूप में **1.80** लाख करोड़

अधिक पैदावार वाले बीज की विकसित किस्मों की संख्या **1390** से बढ़कर **2900**

वैश्विक दूध उत्पादन में **25** फीसदी हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया में पहले स्थान ।

मुंहपका और खुरपका रोग के खिलाफ **100** करोड़ से ज्यादा टीकाकरण

किसानों को पशु एम्बुलेन्स की सौगात

पहली बार देश में ई-नाम प्लेटफॉर्म से **1400+** कृषि मंडियां जुड़ीं ।

ईच ड्रॉप मोर क्रॉप - माइक्रो इरिगेशन **42** लाख हेक्टेयर से **100** लाख हेक्टेयर ।

2.5 लाख कृषि समृद्धि केंद्रों से आधुनिक कृषि को बढ़ावा ।

नए कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए

हम राजनीति में सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं हैं बल्कि हमारा काम गाँवों, किसानों, गरीब, देश की समस्याओं का समाधान है ।

जिस कर्तव्यनिष्ठा से सैनिक सीमा पर कार्य करते हैं वैसी ही निष्ठा से भूमि पुत्र खेत में कार्य करते हैं ।

इन्द्र अपना कर्तव्य छोड़ेंगे तो उनकी उपयोगिता कम करेंगे । देवराज को यह बात दिल में उतर गयी । किसान से मिली सीख से उनसे तुरंत वर्षा की व कृषक की जुताई सफल हुई ।

जवान व किसान जितने देश से प्रतिबद्ध हैं उतनी ही प्रतिबद्धता देश के लिये हम सबको रखनी चाहिये ।

" छोडो राग की बातें, राग की बात पुरानी

नये दौर में लिखनी है, मिलकर नयी कहानी"

निरर्थक आलोचनाओं से बचे, यह देश हम सबका है, राजनीति चुनाव के समय करें चुनाव के बाद रचनात्मक व सुझाव दें स्वतंत्रता की शताब्दी 2047 तक हम सबको मिलकर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है ।

इसके साथ ही मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि

जैविक कॉटन की डिमांड, पूरे विश्व में हर साल तेज गति से बढ़ रही है । सरकार अगर टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड की तर्ज पर अगर जैविक कॉटन का बोर्ड स्थापित कर दे, तो इससे जैविक कॉटन की क्वालिटी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक नए आयाम साबित होंगे ।

कृषि उपज मंडी में काम करने वाले मजदूरों, हम्माल, ड्रॉगर्स, राइवर्स ईटीसी के कल्याण लिए सरकार अलग से, इंश्योरेंस, वित्तीय सहायता, पेंशन आदि की व्यवस्था अगर करती है तो, कृषि उपज से जुड़े इन मजदूरों को एक बड़ी राहत मिलेगी ।

चित्तौड़गढ़ जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र

नरेगा को कृषि में जोड़ना है ।

SHRI SUKANTA KUMAR PANIGRAHI (KANDHAMAL): It is with immense pride and responsibility that I rise today to discuss the transformative vision embodied in the Union Agriculture Budget 2025-26. This budget is not just a financial document; it is a roadmap for the future of India's agricultural sector, a sector that forms the backbone of our economy and the lifeline of our rural population.

The Union Agriculture Budget 2025-26 is unique in its approach, as it places agriculture at the core of India's economic development strategy. By positioning agriculture as the **“first engine of development”**, this budget acknowledges the sector's critical role in ensuring food security, promoting rural prosperity, and driving inclusive growth. It is a bold and forward-looking framework that addresses long-standing challenges while embracing innovation and sustainability.

Today, I will highlight the key features of this landmark budget, its transformative initiatives, and its potential to reshape India's agricultural landscape.

The allocation of Rs.1,37,757 crore to the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare reflects a strategic reorientation of our economic priorities. While this allocation represents a slight reduction compared to previous years, it is important to note that allied sectors such as fisheries, animal husbandry, and dairying have received a significant boost with a 37 per cent increase in funding to Rs.7,544 crore.

This strategic shift underscores the Government's recognition that agriculture is not an isolated sector but part of a broader ecosystem that includes allied activities. By diversifying income streams for farmers and reducing dependency on traditional crops, this budget lays the foundation for a more resilient and sustainable rural economy.

One of the standout initiatives in this budget is the Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana. This district-level program targets 100 districts with low agricultural productivity. It focuses on enhancing productivity through crop diversification, improving irrigation facilities, and strengthening post-harvest storage infrastructure.

By addressing local challenges with tailored solutions, this initiative represents a paradigm shift in agricultural policy. It moves away from a one-size-fits-all approach to a more nuanced strategy that leverages existing schemes while focusing on specific geographies. This initiative has the potential to uplift underperforming regions and bring them into the mainstream of agricultural development.

In this era of rapid technological advancement, digital transformation is no longer optional; it is imperative. The Union Budget 2025-26 introduces several digital initiatives aimed at modernizing Indian agriculture:

A **digital crop survey** will be conducted in 400 districts to gather real-time data on crop patterns and productivity.

The integration of **JanSamarth-based Kisan Credit Cards** will streamline credit delivery to farmers and improve financial inclusion in rural areas.

These initiatives promise to revolutionize agricultural planning by enabling data-driven decision-making. They will also empower farmers with better access to credit facilities and reduce delays in financial assistance.

India has long been dependent on imports for key pulses such as **tur, urad, and masoor**. To address this vulnerability, the budget introduces the Mission for Aatmanirbharta in Pulses of Rs.1,000 crore allocation with a procurement guarantee mechanism. This initiative aims to stabilize prices while ensuring self-sufficiency in pulse production. It aligns seamlessly with the broader vision of an **Atmanirbhar Bharat**, reducing import dependency and enhancing food security.

Another critical initiative is the National Mission on High Yielding Seeds having Rs.100 crore allocation, which focuses on developing climate-resilient seed varieties. By addressing yield gaps and promoting advanced seed technologies, this mission positions Indian agriculture to better withstand climate challenges while boosting productivity.

The Mission for Cotton Productivity seeks to enhance India's position as a global leader in premium cotton production. By adopting advanced technologies and improving quality standards, this initiative creates synergies between agriculture and industrial competitiveness, particularly in textiles a sector vital for exports.

One of the most innovative regional initiatives in this budget is the establishment of a Makhana Board in Bihar. Makhana (fox nut) is an important crop with immense nutritional value and export potential. The

board will focus on improving production techniques, processing infrastructure, and global marketing strategies for makhana

This initiative exemplifies how regional strengths can be leveraged for national growth. By promoting makhana as a superfood on global platforms, we not only boost farmers' incomes but also enhance India's reputation as an exporter of high-quality agricultural products.

The emphasis on sustainable fisheries development -- particularly in island territories -- demonstrates a commitment to utilizing marine resources responsibly. Fisheries are not only vital for nutritional security but also hold significant export potential.

A 37 per cent increase in allocations for animal husbandry and dairying reflects the Government's focus on diversification within agriculture. Livestock farming offers an alternative income stream for farmers while reducing dependency on traditional crops.

The Comprehensive Programme for Vegetables and Fruits aims to promote cluster-based production near consumption centres. By addressing post-harvest losses and transportation challenges, this initiative ensures better prices for farmers while meeting urban demand efficiently.

Enhanced Financial Support for Farmers

Recognizing rising input costs and the need for modern farming practices, this budget increases the loan limit under the Modified Interest Subvention Scheme from Rs.3 lakh to Rs.5 lakh per farmer. This move empowers farmers to invest in productivity-enhancing technologies such as mechanization and precision farming tools.

The budget emphasizes natural farming practices that reduce dependency on chemical inputs while ensuring environmental

sustainability. These efforts align with global trends toward eco-friendly agriculture.

Investments in warehousing, logistics, and processing aim to minimize post-harvest losses while improving market access for farmers – a critical step toward building resilience against climate-induced disruptions.

While this budget lays out an ambitious roadmap for agricultural transformation, its success hinges on effective implementation at every level – national, State, and local. Some key challenges include:

- Ensuring timely disbursement of funds to avoid delays in project execution.

- Raising awareness among farmers about new schemes through grassroots campaigns.

- Addressing policy bottlenecks that hinder market reforms.

- Building capacity among farmers to adopt advanced technologies introduced under various missions.

Collaboration between Central and State Governments will be crucial to overcoming these challenges and ensuring that benefits reach smallholders the backbone of Indian agriculture.

The Union Agriculture Budget 2025-26 represents a bold vision that combines traditional strengths with modern innovations to transform **Indian agriculture into a globally competitive sector**. By focusing on digital integration, climate resilience, regional specialization, allied sectors like animal husbandry and fisheries, financial inclusion through enhanced credit access, as sustainability measures like natural farming practices – this budget creates a comprehensive framework for growth.

It is not just about numbers or allocations; it is about empowering our farmers with tools they need to thrive in an ever-changing world –

whether through technology adoption of beer market linkages.

This budget calls upon all stakeholders ? farmers themselves; policymakers; researchers; private enterprises; cooperatives; State Governments ? to work collaboratively toward achieving higher productivity levels while ensuring rural prosperity remains at its heart.

Let us seize this opportunity together so we can transform aspirations into reality ? for our farmers today ? and generations yet unborn tomorrow!

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Thank you for allowing me to express my views on the Demands for Grants for Agriculture. At the outset I would like to remind the Union Government the heartbreaking images of thousands of farmers marching to Delhi?leaving behind their fields, their families, their livelihoods?simply to demand their rights. And how did this government respond? With tear gas, water cannons, and barricades, as if our farmers were enemies, not the backbone of our nation. The Prime Minister often says that farmers are one of the four ?castes? whose upliftment will drive India?s progress. But what he didn't tell us was that his idea of "upliftment" includes repression, neglect, and broken promises. Back in 2013, when farmers came to Delhi in protest, the UPA government sent a delegation of six cabinet ministers to meet them, listen to their demands, and set up committees to address their concerns. But today, under the BJP regime, farmers must die by suicide, fast unto death, or face state-sponsored brutality just to be heard. And still, their cries go unanswered. You make only tall claims; You boast about agricultural growth but the reality tells a different story.

Under UPA I, agriculture grew at 4.2% per year.

Under UPA II, it was 3.7% per year.

Under Modi 1.0, it dropped to 2.9%.

Under Modi 2.0, it is just 3.5%.

This is because we had focussed on Agriculture and supported the farmers but you are running a ?suit boot sarkar?.

The number speaks for itself. In the last 10 years, this government has written off Rs. 16.35 lakh crore in bad loans?Rs. 9 lakh crores for large industries alone. It?s the figure given by the Finance Minister to a question in this house.

Moreover, in 2019 they slashed corporate taxes by 1.6 Lakh crore per year, handing around Rs. 10 Lakh crores to big businesses over six years. When it comes to their crony friends, this government is generous beyond measure. But what about our farmers?

50% of agricultural households are in debt. Since this government came to power, over 1 lakh farmers have died by suicide. And yet, the Modi government refuses to waive farm loans. | ask this government?who is feeding this nation? Is it Ambani and Adani, or is it our farmers and labourers, who toil in the fields under the scorching sun and pouring rain?

Another group that the Prime Minister conveniently remembers when it suits him is women. But unsurprisingly, he has abandoned women farmers too. 80% of economically active women work in agriculture.

They make up 48% of self-employed farmers. Yet they own less than 15% of land. Why? Because this government refuses to recognize them as ?farmers.? Instead, they are labelled as "cultivators" or ?agricultural labourers,? cutting them off from benefits like crop insurance, subsidies, and institutional credit. The unemployment of women is highest in the country including farm sector.

If the PM is truly concerned about Nari Shakti, why has he failed every single woman working in our fields?

In 2016, this government promised to double farmers' income by 2022. But today, that promise has vanished—missing from the PM's so-called "guarantees."

However, do you know what has doubled. The number of Indian billionaires. Their total wealth has tripled. This is Modi's "New India"—where the rich get richer and the farmers get poorer. In November 2021, Hon'ble Prime Minister personally promised to agitating farmers for a legal guarantee of MSP. But now it's a forgotten promise. Because Farmers don't buy electoral bonds for BJP. I just want to ask a simple question: Every Industrial product has MSP on it. Why not an agricultural product? Despite all the noise about PM Fasal Bima Yojana, let's face reality. The real beneficiaries of this scheme are private insurance companies, not farmers. Farmers don't get compensation on time. It is a mystery that how the insurance law has drafted to benefit the insurance companies, not the farmers. No body knows how these insurance companies who gets paid and who doesn't and on what basis. Even its difficult for Hon Minister to understand! We four MPs together tried our best in DISHA committee meeting.

After centuries of British rule and devastating famines, the then Hon? PM Indira Gandhi Ji with her vision and courage along with the then Agriculture Minister C. Subramaniam, and Scientist Dr. M.S. Swaminathan ushered in the Green Revolution and ensure the food security. Indira Gandhi's vision and her team's hard work drove the Green Revolution, securing surplus grains. But | Caution you?neglecting farmers and agriculture risks our food security.

We need a Second Green Revolution?one that continue to ensure food security, raise farmers and farm labourers? incomes, and makes agriculture sustainable.

This means:

Expanding MSP to cover all major crops.

Strengthening irrigation and rural infrastructure.

Increasing financial assistance for FPOs?one in every Panchayat.

Recognizing women farmers and granting them equal rights. Making crop insurance transparent and farmer-centric. Encouraging diversification towards high-value crops. Before I conclude, I would like to remind the Hon'ble Agriculture Minister about two pending requests from my constituency to take immediate action. Establishment of cold storage facilities in Vedasandur, Karur, Kadavur, Manapparai, and Viralimalai. Action on the e-NAM proposal - Chinnadharapuram regulated market storage godown at Kuppam Village, K.Paramathi block. Our farmers are not asking for charity. They are asking for their fair share?fair prices, market and institutional support, modern technology, and financial security. This government must stop hiding behind slogans, theatrics, and corporate favouritism. It is time to walk the talk. It is time to deliver on the promises made to the farmers of this country. If this government does not act now, history will remember this Government?not for their tall claims, but for their betrayal of India?s farmers. Thank you.

SHRI DAGGUMALLA PRASADA RAO (CHITTOOR): I rise today to discuss the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture for 2025-26. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman, the Union Budget reaffirms its commitment to farmers? welfare. With a 3.89 per cent increase from the

previous year, it introduces new schemes to strengthen India's agricultural sector.

Today, I would like to talk about the three critical pillars of agriculture: 'Farmer', 'Finance', and 'Future'. These fundamental components shape the policies that will define the destiny of our agrarian economy.

I come to 'farmer'. The PM-KISAN scheme has been a gamechanger, with over Rs. 3.46 lakh crore disbursed to 11 crore farmers across the country in 18 instalments. In Andhra Pradesh alone, Rs. 836 crore has been transferred to more than 41 lakh farmers. However, there are two areas where we can further enhance this initiative. Over 50 per cent of the Andhra Pradesh's agricultural workforce comprises of tenant farmers. Recognizing them under PM-KISAN will ensure equitable benefits. The State Government, under Chief Minister Nara Chandrababu Naidu, has already promised it by recognising the tenant farmers through the Tenant Farmer Protection Act. And I urge the Centre to come up with a similar initiative.

The PM-KISAN was launched in 2019. The scheme provides Rs. 6,000 per year. Given the successful implementation over six years, I urge the Government to increase this amount to account for inflation and ensure greater financial security for our farmers.

Now, I come to the second pillar, that is, 'Finance'. A major achievement of this Government has been an exponential rise in institutional credit flow to agriculture from Rs. 8.5 lakh crore in 2014-15 to Rs. 25.48 lakh crore in 2023-24. This year's Union Budget has further reinforced this commitment by increasing the Kisan Credit Card loan limit from Rs. 3 lakh to Rs. 5 lakh.

However, a critical challenge remains for informal lending. Nearly 30-40 per cent of farmers still rely on private moneylenders due to stringent CIBIL score requirements for agricultural loans in some banks. This must be addressed. The farmers should not be denied access to formal credit based on credit scores. A foolproof implementation of relaxed credit norms will ensure more farmers benefit from institutional loans and break from high-interest informal borrowing.

The third pillar is future. As the global food demand surges, a quiet yet profound shift is underway. Two out of every five Indian farm workers have moved away from agriculture in the past three decades. How do we secure our agricultural future?

The answer lies in AgriTech. Encouraging AgriTech startups and implementing modern technology-driven solutions will enhance productivity, efficiency, and profitability for our farmers.

A visionary approach to revitalizing agriculture could follow the model of 'One Family, One Entrepreneur', introduced by our CM Nara Chandrababu Naidu in Andhra Pradesh. At the national level, this could be 'One Farming Family, One Agripreneur', ensuring entrepreneurial growth in rural households while securing India's agricultural future.

Now, I would like to highlight three critical initiatives in the Union Budget.

First is the Cotton Technology Mission. Second is the National Mission on High-Yielding Seeds.

These two will encourage agriculture in this country.

Further, I have one point that is related to Chittoor of Andhra Pradesh. It is about mangoes.

Andhra Pradesh is a significant mango-producing State in India with districts like Krishna, Chittoor and Godavari regions known for mango cultivation, particularly the Banganapalle variety, and there is a production of around 45-50 lakh tons annually.

Totapuri is grown in Chittoor district. Everywhere it is grown for domestic purpose. But in Chittoor district, it is produced for the pulp purpose. The mango farmers are facing problems now.

So, I would urge the Government to support mango farmers who are experiencing a crisis due to lack of remunerative prices for their produce as a result of the adverse climatic conditions for mango production. There is an urgent need to extend more support to the mango farmers and mango-based industries in Chittoor district.

Being a Member of Parliament in Lok Sabha, I have already given the representation to the hon. Agriculture Minister to set up a National Mango Board to solve all the issues relating to mango and it will give a Constitutional platform to address the much required initiatives for the sake of farmers.

I have one more issue. For export, there is a hurdle in the European countries. One of the hurdles is Ukraine war because of that we are not able to export the pulp. Another hurdle is European countries where they put more import duty on Indian products compared to other countries.

So, I urge the Ministry of Commerce to look into this matter.

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) : आज मैं भारत सरकार द्वारा 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में कृषि संबंधी अनुदानों और मांगों पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है । माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के विकास के लिए पहले इंजन के रूप में कृषि को मान्यता दी है । इस बजट में भारत सरकार ने कम उत्पादकता, कम फसलों की बुवाई और कम ऋण उपलब्धता

वाले देश के 100 जिलों में ? प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना? शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ । इससे उन जिलों में फसलों की उत्पादकता बढ़ने और ऋण की उपलब्धता बढ़ाने में किसानों को काफी मदद मिलेगी । मेरी यह मांग है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले को भी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में शामिल किया जाए ।

बिहार में माननीय मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है । बिहार सरकार ने अपना चौथा कृषि रोडमैप प्रस्तुत कर अपना विजन स्पष्ट किया है । इसके लिए मैं बिहार के मुख्य मंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को हृदय से बधाई देता हूँ ।

सभापति महोदय, मखाना बिहार का एक प्रमुख खाद्य उत्पाद है । मखाना के उत्पादन, विपणन, किसानों के प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा से बिहारवासियों को काफी खुशी हुई है । इससे बिहार के इस उत्पाद को देश-विदेश के कोने-कोने में पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी । माननीय प्रधान मंत्री जी अपने मॉरीशस दौरे पर इसके ब्रांड एंबेसडर के रूप में दिखाई दिए, जिसने बिहारवासियों का दिल जीत लिया है ।

राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन, मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहन और कपास उत्पादकता मिशन के जरिए भारत सरकार कृषि को एक नया मुकाम देने के लिए प्रयत्नशील है । सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को मिलने वाले ऋण की सीमा में वृद्धि कर महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जो कृषि सुधार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा । इस निर्णय के तहत कृषि, मत्स्य और डेयरी के प्रोत्साहन के लिए किसानों को ऋण की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक की गई है, लेकिन कुछ किसानों को केसीसी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वे आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने या बैंक की प्रक्रियाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं । इस प्रक्रिया को आसान कराने की मेरी सरकार से माँग होगी । केसीसी पर ब्याज दरें अन्य ऋण योजनाओं की तुलना में अधिक होती हैं, जिससे गरीब किसानों को अधिक खर्च करना पड़ता है । इसे भी कम करने का मेरा सुझाव होगा । केसीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया कुछ जटिल होती है, जिससे किसानों को परेशानी होती है । साथ ही किसानों को केसीसी के माध्यम से समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे वे

अपनी फसल की बुआई या अन्य कृषि गतिविधियों को समय पर शुरू नहीं कर पाते हैं। कुछ किसानों को केसीसी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, जिससे वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके लिए भी व्यापक जनजागरण अभियान चलाना होगा। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार और वित्तीय संस्थानों और किसानों को केसीसी के बारे में जागरूक करने, ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और ऋण की राशि को बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर गन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ चार चीनी मिलें हैं। मेरी सरकार से माँग होगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र बगहा में कृषि विज्ञान केंद्र और गन्ना अनुसंधान केंद्र खोलने की स्वीकृति दी जाए, ताकि इससे स्थानीय किसानों को उन्नत खेती करने में सहूलियत हो सके। थरुहट क्षेत्र का सुगंधित बासमती चावल और आनंदी चावल को भी प्रमोट किए जाने की जरूरत है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, आम आदि फसलों पर आधारित प्रसंस्करण यूनिट भी स्थापित करने का भी मेरा सरकार से अनुरोध होगा।

किसानों पर राष्ट्रीय आयोग, 2006 ने सुझाव दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की भारित लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 में उस सुझाव को मंजूर किया और सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी को भी बढ़ाया गया। मंत्रालय चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) भी तय करता है। मेरी माँग होगी कि फसल उत्पादन में किसानों की भारी लागत को देखते हुए समय समय पर गन्ना, धान और गेहूँ की एमएसपी में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहनी चाहिए। पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों में केवल वे किसान शामिल हैं, जिनके पास खेती योग्य भूमि है। इस योजना में कृषि मजदूरों को शामिल नहीं किया गया है, जो देश में कृषि श्रमिकों का 55 प्रतिशत हिस्सा है। खेतिहर मजदूरों के पास जमीन नहीं होती है और वे दूसरे की जमीन पर बटाईदारी पर खेती करते हैं। वे मजदूरी या फसल में हिस्से के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, भूजोत के टुकड़े-टुकड़े होने और खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ने से कृषि उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। भारत के कृषि क्षेत्र में सीमांत और छोटी भूजोतों की संख्या बहुत अधिक है। भूजोत के छोटे-छोटे टुकड़े होने के कारण

किसानों की फसल उत्पादन में अधिक लागत आती है। पूरे देश में चकबंदी कानून लागू कर इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। बिहार में इसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। बिहार सरकार ने नए प्रावधानों के साथ फिर से बाजार समिति व्यवस्था शुरू करने का विचार किया है, जो सराहनीय कदम है। बिहार में उचित बाजार नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें विपणन और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ? (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : सभापति जी, ये बिहार के बारे में अच्छी बातें रख रहे हैं।

श्री सुनील कुमार : सभापति महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में निजी चीनी मिल मालिकों की मोनोपोली से लोग परेशान हैं। उनके द्वारा पर्ची वितरण में धांधली और घटतौली की शिकायतें आम रहती हैं। आपके माध्यम से मेरी सरकार से माँग होगी कि भारत सरकार के उपक्रम एचपीसीएल की एक चीनी मिल यूनिट मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गंडक पार धनहा क्षेत्र में लगाई जाए, ताकि हमारे यहाँ के किसानों को निजी मिल मालिकों के शोषण से बचाया जा सके।

इसके साथ ही साथ, अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में गंडक नदी के उस पार केलों की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। वहाँ पर उनके लिए नई तकनीक से युक्त एंव बिक्री हेतु एक व्यवसायिक केंद्र केला के लिया बनाई जाए, जिससे वहाँ के किसान अपना केला विदेशो में बेच सकें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट पर अपना समर्थन देते हुए, अपनी पार्टी की तरफ से माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई देते हुए, अपनी समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

SHRI SANJAY HARIBHAU JADHAV (PARBHANI): Hon. Chairman Sir, I rise to participate in the discussion on Demands for Grants of the Ministry of Agriculture for the year 2025-26. I would like to draw Govt's attention towards various issues related to farmers' welfare. If we look at the farming expenses, total yield and the prices which farmers get, it is quite visible that it is a non-profitable and worthless business. Our Prime

Minister Narendra Modi ji promised that farmers income would be doubled. But, he could not do it. Now, Rs. 500 is given to farmers in the name of Kisan Samman Yojana but, not the remunerative prices for his agricultural produces. This is a very important issue. No bank is ready to provide loans to farmers due to low CIBIL score. Farmers cannot get education loan for their children. Many big industrialist, corporate houses and businessmen default the loans worth crores of rupees and this Govt. write off their loans happily. But, when it comes to farmers, this Govt. is not ready to take any responsibility.

I would like to draw Hon. Minister's attention towards an important issue. There were many cases of heavy downpour and cloudburst in the month of September in Maharashtra and Govt. had promises to provide Advance insurance bonus benefits of Rs. 335.90 crore, but that did not happen. Insurance companies are minting money through crop insurance business but, the farmers are still waiting for insurance benefits. This Govt. has ignored them completely. It is my request to you that you must support them in this hour of pain and distress.

Maharashtra is an agriculture dominated State and 3.25 lakh hectare of land is not cultivable as it is being utilized for industrial purposes. It is a need of the hour, to think about it. Hon. Chauhan ji, your Govt. has started this PM crop insurance Scheme, but there is a rampant corruption in this scheme and I can provide you all the proofs and evidences. In my district 11221 people have taken the benefits of this scheme through bogus insurance and Govt. has not taken action in this direction. Those who are eligible do not get the benefits but the so-called farmers are benefitting out of it. I have brought the complete list of these 11221 bogus beneficiaries and I would like to hand it over to you.

The Swaminathan Committee Report should be implemented immediately when BJP was not in power, they used to talk about this Report. It is now more than 11 years since Modi Govt. came to power but nothing has been done in this regard. Big businessmen have looted the public money in the name of corporate loans but this Govt. has no money to waive off poor farmers' loans. So, I request Prime Minister and Agriculture Minister to take steps in this connection. Hon. Ex-Prime Minister of India Man Mohan Singh ji declared a waiver for farmers' loan. Since then, nothing of this sort has been done. Therefore, I would like to request you to take an initiative in this direction. You will get blessings of poor and needy farmers.

वहाँ से क्या तू लाया बन्दे, यहाँ से क्या तू ले कर जाएगा ।
मुट्ठी बाँध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा ।
बालपन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा ।
बूढ़ापन में रोग सताये, खाट पड़ा पछताएगा ।
नाम हरि का जप ले बन्दे, फिर पीछे पछताएगा ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा ।

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे (शिरूर) : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले जी का अभिवादन करना चाहता हूँ ।

This is a right time to punish this government by using Mahatma Jyotiba Phule's long whip for the useless schemes run by the government.

सभापति जी, देश की दो-तिहाई आबादी खेती पर निर्भर है और खेती के लिए आबंटन मात्र 3.1 परसेंट है । मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हो या प्राइस सपोर्ट स्कीम हो, में आबंटन जीरो है । प्रधान मंत्र फसल बीमा योजना में कटौती 23 परसेंट है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने महाराष्ट्र में आकर किसानों को सोयाबीन के लिए 6,000 रुपये प्रति क्विंटल दाम देने की गारंटी दी थी लेकिन एमएसपी 4,800 रुपये दिया गया । एमएसपी पर जो खरीद हुई, वह मात्र 20 प्रतिशत है, बाकी 80 प्रतिशत किसानों को सोयाबीन

3500-4500 रुपये में बेचना पड़ा जबकि लागत का खर्च 7000 रुपये प्रति क्विंटल था । किसान की आय कैसे दुगुनी होगी? माननीय मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ?

सभापति जी, सरकार सोयाबीन के दाम बढ़ाने पर एडिबल ऑयल्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी लादने की बात कर रही है । **But, it is contrary and of no use.** क्योंकि इससे सोयाबीन के दाम नहीं बढ़ेंगे, इससे बढ़ेगी तो केवल महंगाई । सोयाबीन के दामों पर अगर कंट्रोल करना है तो मकई का डीडीडीएस और सोया डीओसी, जो 120 लाख टन देश में पड़ा है, इसे एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचना होगा । सरकार पर पोल्ट्री और पशु खाद्य इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा दवाब है कि सरकार सोया डीओसी एक्सपोर्ट नहीं कर रही है? मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम 15 से 20 लाख मीट्रिक टन सोया डीओसी एक्सपोर्ट किया जाए ।

महोदय, ऐसा ही एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा प्याज का है । जब प्याज को एमएसपी देने की बात आती है तो सरकार कहती है कि प्याज जीवनावश्यक वस्तु नहीं है लेकिन जैसे ही किसान को चार पैसे मिलने के अवसर का निर्माण होता है तो सरकार निर्यात पर पाबंदी लगा देती है, निर्यात शुल्क लाद देती है और कह देती है कि प्याज तो जीवनावश्यक वस्तु है । हमारे देश में कई समाज ऐसे हैं जो कभी-भी प्याज नहीं खाते हैं । हिंदुओं में चातुर्मास में चार महीने प्याज नहीं खाया जाता है तो फिर प्याज जीवनावश्यक वस्तु कैसे हुई?

अगर ग्राहक की औसतन कन्जम्पशन देखें तो पांच से छः किलो है, इस तरह से 60 रुपये किलो प्याज ग्राहक को खरीदना पड़ेगा तो मुश्किल से 300-350 रुपये खर्च होंगे जो कि आपके मोबाइल रिचार्ज से भी कम है । मेरी सरकार से मांग है कि प्याज पर हमेशा के लिए निर्यात पाबंदी हटाकर 20 परसेंट निर्यात शुल्क को अविलंब रद्द किया जाए और प्याज को एमएसपी के दायरे में लाकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल का दाम सुनिश्चित किया जाए ।

महोदय, इस बजट में बहुत-से मिशन की एनाउंसमेंट हुई, बहुत-से मिशन के बारे में कहा गया, **Government is misleading us and hiding the truth,** लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है । पल्सेस में आत्मनिर्भर होने की बात कही जाती है । किसान मार्च, अप्रैल और मई में चना बेचने के लिए मार्केट में आएगा, लेकिन सरकार ने 31 लाख मीट्रिक टन पीला मटर आयात किया है । पीला मटर खाने

के लिए नहीं होता है, बेसन में चने की जगह अडल्ट्रेशन में यूज होता है और चने के दाम गिरा देता है। आपने 31 मई तक पीले मटर के खुले आयात की परमिशन दे दी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पल्सेस में आत्मनिर्भर होना है और दूसरी तरफ 67 लाख मीट्रिक टन पल्सेस आयात कर चुके हैं। हम आत्मनिर्भर किसे करना चाहते हैं? क्या हम अपने देश के किसानों को या आस्ट्रेलिया, रूस, टर्की और म्यांमार के किसानों को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं?

ऐसा ही एक अहम मुद्दा है? मिशन ऑन वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन और स्टोरेज के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? आज मेरे नारायण गांव में किसान को टमाटर 4 से 5 रुपये किलो में बेचना पड़ता है और शहरों में ग्राहक 20 से 25 रुपये किलो में खरीदता है। इस मुनाफे पर कोई भी नियंत्रण क्यों नहीं है? इसका कारण बिचौलियों की श्रृंखला है। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

ऐसा ही एक अहम मुद्दा है? प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना बार-बार किसानों के लिए कम और बीमा कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। इस साल का प्रीमियम 10 हजार करोड़ रुपये है। बीमा कंपनियों को जो प्रीमियम मिला है, वह 10 हजार करोड़ रुपये का है और नुकसान एवं भरपाई का भुगतान मात्र 680 करोड़ रुपये है। यह 7 प्रतिशत से भी कम है। सभी नियम किसानों के लिए हैं। बीमा कंपनियां तो कोई नियम फॉलो ही नहीं करती है। इसका मतलब है कि योजना किसानों के लिए, पैसा सरकार का यानी टैक्सपेयर्स का और भला बीमा कंपनियों का हो रहा है। इसे मराठी में कहते हैं: - *we can say that poor farmers are paying for it but, insurance companies are getting benefitted out of it.*

एक और अहम मुद्दा है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों से ऋण माफी का वायदा किया था। सरकार के इस आश्वासन की वजह से किसान अब ऋण माफी की तरफ आस लगाये बैठे हैं और मार्च एन्ड होने की वजह से बैंक्स ने किसानों के पीछे ऋण वापसी की रट लगाई है। आज महाराष्ट्र में हर दिन सात किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कृषि प्रधान देश के लिए यह सम्मानजनक बात है?

अंत में मेरे दो ही मुद्दे हैं। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अमेरिका ने कहा है कि भारत को अपनी एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोलनी चाहिए।

इससे भारत के किसानों पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है । लेकिन सरकार ने अभी तक इसमें कोई स्पष्टता नहीं दी है । क्योंकि अमेरिका का किसान, जो सोयाबीन का उत्पादन करता है, वह 30 लाख किंटल पर-हेक्टेयर लेता है । लेकिन हमारे देश का किसान सिर्फ 10 लाख किंटल पर-हेक्टेयर लेता है । क्योंकि अमेरिका के किसान को जेनेटिकली मोडिफाइड जीएम वैरायटी लगाने का अधिकार है, हमारे किसान को नहीं है । सरकार जो एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करती है, वह जीएम वैरायटी का चलता है, लेकिन किसान जीएम वैरायटी की फसल नहीं लगा सकता । जहां अमेरिका अपने किसान को सक्षम कर रही है, वहीं हमारे विश्व गुरु देश का किसान अभी भी एमएसपी के लिए जूझ रहा है ।

सर, प्रधान मंत्री जी ने महाकुम्भ के बारे में वक्तव्य देते वक्त एक बहुत प्यारी बात कही । उन्होंने कहा कि नदी उत्सव मनाना चाहिए । लेकिन यह नदी उत्सव नदियों का खोलीकरण, रुंदीकरण और पुनर्जीवन होगा, तभी असली नदी उत्सव होगा । महाराष्ट्र में कैलाश नागरे जैसे एक युवा प्रगतिशील, किसान, खेतों के लिए पानी नहीं, अगर इसलिए खुदकुशी करता है तो क्या यह हमारी पॉलिसी पर तमाचा नहीं है? आज बहुत सारी चीजें खोदने की बात हो रही है, लेकिन डैमों में जो मिट्टी जमा हुई है, 30 से 40 प्रतिशत कैपेसिटी हर डैम की कम हुई है । शायद उत्तर भारत में इसका प्रमाण और ज्यादा होगा, लेकिन इसकी मिट्टी खोदने का कोई प्रावधान अब तक किया नहीं ।

अंत में इतना ही कहूंगा और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारे देश के किसान को पर्याप्त पानी, अच्छी क्वालिटी का बीज, उत्पाद का सही दाम और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए फ्री हैंड दीजिए । वह सरकार के दिन के कथित 17 रुपये सम्मान का मोहताज नहीं । अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि?

?मस्जिद के नीचे तुम मंदिर क्यों ढूंढते हो,
भविष्य की ओर देखो, तुम इतिहास पर क्यों लड़ते हो
वे लड़ाएंगे, भड़काएंगे, लेकिन राष्ट्रहित का रुख तू कर
किसानों के हित में हमेशा इंसानियत की बात तू कर ।?

धन्यवाद ।

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : सभापति महोदय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आपने चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको सबसे

पहले धन्यवाद देता हूँ । बिहार देश की कृषि परम्परा का केन्द्र रहा है । मैं अपनी लोक जनशक्ति पार्टी, मेरे लोक सभा क्षेत्र खगड़िया और हमारे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ । साथ ही साथ मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 1 लाख 37 हजार 756 करोड़ रुपये का बजट किसानों के लिए आवंटित करने का काम किया ।

जहां पहले किसान अपनी समस्या, अपनी पीड़ा के लिए विचलित रहते थे, जहां पहले उनको वह सम्मान नहीं मिलता था, जहां उस वक्त के प्रधानमंत्री खुद इस बात को कहते थे कि हम लोग केंद्र से 100 रुपए भेजते हैं, लेकिन लोगों की जेब में 15 रुपए पहुंचते हैं । वहीं अब हमारी एनडीए की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो किसानों के लिए 100 रुपए भेजे जाते हैं, वह शत-प्रतिशत किसानों के अकाउंट में जाते हैं । इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ । इसके साथ ही साथ, मैं सरकार में केन्द्रीय मंत्री एवं हमारे नेता चिराग पासवान जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई और उन्होंने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए और किसानों को उसका सही दर मिले, इसके लिए सकारात्मक रूप से अथक प्रयास किया । मैं इसके लिए भी उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ ।

माननीय सभापति महोदय, जब हम लोग किसानों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहाँ की 80 प्रतिशत आबादी किसानों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है । मेरे खगड़िया लोक सभा क्षेत्र में लगभग 3,85,000 टन प्रतिवर्ष मक्के का उत्पादन होता है, लगभग 50 हजार हेक्टेयर भूमि में मक्का की खेती होती है । मेरी कांस्टिट्यूएन्सी एशिया में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है । जिस तरह से, प्रधानमंत्री जी ने धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को शामिल किया है, उससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा । मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उन 100 जिलों में खगड़िया जिले को भी उसमें शामिल करने का काम करें क्योंकि हमारे जिले की एक बड़ी आबादी मक्का उत्पादन के क्षेत्र में काम करती है । एशिया का सबसे बड़ा मक्का उत्पादन का क्षेत्र, जो हमारी लोकसभा है, उस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

इसके साथ ही साथ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कृषि मंत्री जी का क्योंकि उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की, कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 वर्ष के मिशन की शुरुआत की और सबसे बड़ी बात, जो अभी कुछ देर पहले, विपक्ष के सांसद कह रहे थे कि किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें महंगे ब्याज दर पर सूदखोरों से पैसा लेना पड़ता है और वह कर्ज ब्याज देते- देते परेशान हो जाता है, लेकिन मूल नहीं दे पाता है । मैं अपने विपक्ष के उन बड़े भाई से कहना चाहता हूं कि यह एनडीए की सरकार में नहीं होता है । यह पहले की सरकारों में होता था कि सूदखोरों से किसान को पैसा लेना पड़ता था । अब तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों को 3 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने का काम किया और वह भी कम से कम ऋण- दर पर देने का काम किया ताकि न केवल किसान सम्मान से अपने काम को बढ़ा सकें, बल्कि इसके साथ ही साथ, अपने जीवन को किसी सूदखोर के चक्कर में लाए बिना, वह सम्मान के साथ अपनी किसानी कर सके और सम्मान के साथ जीवन जी सके । हम सभी लोग जिस पर निर्भर हैं, हमारे उन अन्नदाता किसानों के लिए हमारी सरकार ने यह काम किया है ।

जिस तरह से, वर्ष 2004-05 में, 204 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होता था, वह बढ़कर वर्ष 2023-24 में, 332.3 मिलियन टन हो गया है । धान का एमएसपी जहां पहले 2,300 रुपए प्रति किंटल था, गेहूं का 2,425 रुपए प्रति किंटल था, अब वह 2,425 रुपए प्रति किंटल कर दिया गया है । वर्ष 2014 से 2024 तक किसानों को लगभग 12.51 लाख करोड़ रुपए एमएसपी का भुगतान हमारी सरकार ने करने का काम किया है । जो लोग बार-बार इस बात को कहते हैं, हमारी सरकार को किसान विरोधी कहते हैं, मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूंगा कि

जब हुकूमत में थे वो,
मगर दिखा ना सके कोई कमाल,
आए थे वादों के साथ,
पर छोड़ गए सिर्फ सवाल,
जो खुद ही अंधेरे में भटकते रहे,
वो उजालों की बात क्या करेंगे,

जो खेतों की मिट्टी को समझ न सके,

वो किसानों की बात क्या करेंगे,

वो किसानों की बात क्या करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे केंद्र के कृषि मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, फिर से अपनी खगड़िया लोक सभा की जनता और अपने नेता चिराग पासवान जी का धन्यवाद देते हुए, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ ।

जय हिंद, जय भारत, जय हमारे देश के किसान भाई ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYUSH; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PRATAPRAO GANPATRAO JADHAV): *Hon?ble Chairman Sir, thank you. First of all, I would like to thank our Hon?ble Prime Minister Narendra Modi ji, Hon?ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitaraman, Hon?ble Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chauhan ji from the core of my heart for bringing this progressive, fulfilling and self-respectful budget for the entire farming community this year.*

सभापति जी, जब मैं यहां आया, तो मैंने हमारे सामने के बहुत सारे सदस्यों के भाषण को बहुत ही गौर से सुना । जो लोग यहां पर भाषण दे रहे थे, जब वे बोल रहे थे, तो उनकी भाषा और उनके उदाहरण सुनकर मुझे दिल में बहुत ही हंसी आ रही थी । जिन लोगों ने कभी खेती देखी नहीं, जो लोग कभी खेत में गए नहीं, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं, यह भी उन्हें मालूम नहीं, लेकिन पढ़कर बोलने की कला उनके पास है, इसलिए इतने भाषण वे लोग यहां देने लगे थे और किसानों की स्थिति कितनी गंभीर है, यह बता रहे थे ।

मेरी सभी माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर नम्र विनती है कि जो किसान हैं, वे हमारे अन्नदाता हैं । किसान अन्न उगाता है, इसीलिए, हम लोग जिंदा हैं । अभी एक सदस्य ने यह बोला कि किसान का बेटा किसानी करने को तैयार नहीं है । डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, वकील का बेटा वकील बन रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर

बन रहा है । अगर ऐसी ही स्थिति रही और अगर आगे आने वाली पीढ़ियों ने खेती करना छोड़ दिया, तो हम लोग क्या खाएंगे? अतः खेती के लिए यहां लोग जो भी नेगेटिव बोल रहे हैं, लोगों में इसके बारे में उनका मत खराब कर रहे हैं, उनसे विनती है कि कृपया किसानों के बारे में यहां पर इतना झूठ मत बोलिए ।

सभापति महोदय, मैंने देखा कि विपक्ष के कई लोग खुद का नाम बढ़ाने के लिए, राजकारण के लिए किसानों के मोर्चे निकालते हैं, आंदोलन करते हैं । ऐसा ही एक किस्सा मैंने पहले सुना, जब मैं नया-नया राजकारण में था । कांग्रेस के एक नेता ने किसानों के लिए, किसानों की समस्या को लेकर पूरा एक देशव्यापी मोर्चा निकाला था । दिन प्रतिदिन वह मोर्चा आगे चल रहा था, किसान लोग उनसे जुड़ रहे थे । एक गांव में उनका मुकाम था, जब वे सवेरे उठे, तो बोले कि चलो मंडी में जाकर आएं । किसानों की क्या हालत है, किसान कैसे अपनी फसल बेचते हैं । वे बाजार में घूमने लगे, दो-तीन कार्यकर्ता उनके साथ में थे । एक किसान वहां गुड़ बेचने आया था । हमारे महाराष्ट्र में जो गुड़ बनता है, उसकी भेली बनाई जाती है, जिसका वजन कम से कम 14-15 किलो होता है । वह किसान गुड़ की भेली बेच रहा था । हमारे विपक्ष के नेता ने जाकर पूछा भाई यह कौन सा फल है, क्या बेच रहे हो? वह किसान बोला कि मैं गुड़ बेच रहा हूं । विपक्ष के नेता ने कहा गुड़ का इतना बड़ा फल होता है? अगर फल इतना बड़ा है, तो पेड़ कितना बड़ा होगा?

फिर वे थोड़ा आगे गए । वहां कुछ किसान मिर्ची के बाजार में मिर्ची बेच रहे थे । एक किसान हरी मिर्च बेच रहा था और उसके बाजू में दूसरा किसान पकी हुई लाल मिर्च बेच रहा था । नेता को लगा कि चलो हम इसके भी दाम पूछ लेते हैं कि क्या भाव बेच रहा है । उसने हरी मिर्च बेचने वाले किसान से पूछा कि भाई साहब, यह मिर्च क्या भाव बेच रहे हो? किसान ने बोला कि दस रुपए के भाव से बेच रहा हूं । नेता बोले, ठीक है । फिर वे आगे गए, जहां एक किसान पकी हुई लाल मिर्च बेच रहा था । उससे नेता ने पूछा कि यह क्या है? किसान बोला कि यह भी मिर्च है । यह क्या भाव बिक रही है? किसान बोला कि मैं पचास रुपए किलो बेच रहा हूं । इस पर नेता ने बोला कि ये किसान लोग कितने नालायक हैं, अगर उनकी हरी मिर्च दस रुपए किलो बिकती है और लाल मिर्च पचास रुपए किलो बिकती है, तो फिर ये लोग लाल मिर्च ही क्यों नहीं लगाते हैं, हरी मिर्च क्यों लगा रहे हैं?

ऐसे-ऐसे नेता किसानों के लिए मोर्चे निकालते हैं ।? (व्यवधान) मेरा नाम बोलने का काम नहीं है, समझने वाले को इशारा काफी होता है ।? (व्यवधान)

महोदय, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों का भाषण सुन रहा था । वे कह रहे थे कि नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों की फसल के दाम दोगुने करने का वादा किया था । यह देखिए, मैं आपके सामने प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ कि वर्ष 2012-13 के बजट में हमारी फसलों का एमएसपी का क्या दाम था, आप जरा पीछे जाकर देखिए । वर्ष 2012-13 में सोयाबीन की एमएसपी 2 हजार रुपये प्रति किंटल थी, लेकिन आज उसी सोयाबीन की एमएसपी 4,892 रुपये प्रति किंटल है । इसमें लगभग 118 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है । तूर की एमएसपी वर्ष 2012-13 में 3 हजार रुपये हुआ करती थी । हमारे नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज तूर की एमएसपी 7,550 रुपये है । इसमें 151 प्रतिशत की वृद्धि गये 10 साल में हुई है ।

महोदय, सभी फसलों के दाम बढ़ाने के लिए मोदी जी ने निश्चित रूप से पिछले 10 सालों में प्रयास किए हैं । आज मैं किसानों की योजनाओं के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ही बताऊँगा कि आज जो हमारा किसान है, मैं महाराष्ट्र के बारे में बताऊँगा कि पिछले 2.5 साल में जब वहाँ पर हमारी शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी की सरकार थी, हमारी केन्द्र सरकार, मोदी जी किसान सम्मान निधि से 6 हजार रुपये किसानों के खाते में भेजते थे । हमारी महाराष्ट्र सरकार ने उसमें 6 हजार रुपये की नमो शेतकरी सम्मान योजना देकर किसानों की मदद करने का काम किया है ।? (व्यवधान)

महोदय, ज्यादातर कपास और सोयाबीन की फसल हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में होती है । पिछले साल इसके दाम कम होने की वजह से किसान लोग नाराज थे, तो हमारे महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 4100 करोड़ रुपये सोयाबीन और कपास के भाव फर्क में किसानों के खाते में भेज दिए थे ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे टिप्पणी मत कीजिए ।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : महोदय, जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वहाँ पर 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 50 प्रतिशत राज्य सरकार और दो प्रतिशत किसान को देना पड़ता था । महाराष्ट्र की हमारी पिछली सरकार द्वारा एक रुपये में फसल बीमा करने से, जो पहले 33 प्रतिशत किसान फसल बीमा करवाते थे, आज हमारे

महाराष्ट्र 95 प्रतिशत से ज्यादा किसान फसल का बीमा करवा रहे हैं । उसका मुआवजा भी उनको मिल रहा है ।? (व्यवधान)

महोदय, सभी यहाँ पर आकर खुद को किसानों का नेता कहते हैं ।

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप एक मिनट रूकिए । माननीय सदस्य, आप बैठिए । आपको मैंने अनुमति नहीं दी है । माननीय सदस्यगण, जब एक माननीय मंत्री बोल रहे हैं तो आप सुनने का धैर्य रखिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सुनिए । अमरा राम जी, कृपया सुनिए । कृपया, बैठ जाइए । अगर आप बोलने की ताकत दिखाते हैं तो आपमें सुनने की भी ताकत होनी चाहिए ।

? (व्यवधान)

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : आप जरा सुनिए कि आपके समय में क्या हुआ और अभी 10-11 साल में क्या हुआ है । मैं सुन रहा था, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी । यह बात बिल्कुल सही है । जो काम हमारे मोदी जी ने किए हैं, उसकी भरपाई हमारे किसानों ने सिर्फ एक चुनाव में नहीं, लगातार तीन चुनाव में की है ।

महोदय, महाराष्ट्र में भी लगातार तीन चुनावों में किसानों ने बड़ी तादाद में एनडीए के उम्मीदवारों को जिताया है । बिजली की सभी राज्यों में दिक्कत है । हमारे किसानों को रात में बिजली मिलती है, लेकिन हमारी महाराष्ट्र सरकार ने साढ़े सात हार्स पावर तक के बिजली पम्पों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं । एनडीआरएफ की मदद दो हेक्टेयर तक ही मिलती है लेकिन हमारी महाराष्ट्र सरकार ने वह सीमा तीन हेक्टेयर तक बढ़ा दी है । मैं यह बात इसलिए सदन में बोल रहा हूँ क्योंकि कई सदस्य बोल रहे थे, जहाँ उन्हीं की सरकार है लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, शिव सेना, राष्ट्रवादी की सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है, ये बातें जब वे सदस्य सुनेंगे तो अपने राज्य में जाकर बोलेंगे कि हमें भी यह करना चाहिए ।

सभापति जी, दो लाख रुपये कर्ज माफ करने की घोषणा महाराष्ट्र में यूपीए सरकार ने अपने समय में की थी । घोषणा उन्होंने की, लेकिन दो लाख रुपये कर्ज माफ करने का काम हमारे नेता एकनाथ शिंदे, मुख्य मंत्री के कार्यकाल में महाराष्ट्र सरकार ने की । ऐसे बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं और निश्चित रूप से मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की महायुति की सरकार हो, हमारे किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है । कुछ लोग किसानों के हमदर्द बनकर यहां किसानों पर भाषण देने के लिए आते हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी खेत में गए थे? क्या कभी आपने किसानों का हाल देखा कि किसान किसे बोला जाता है? जो हाथ में हल पकड़ता है, खेती करता है, उसे ही किसान पर बोलने का अधिकार है ।

माननीय सभापति : श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : जाधव जी, आपकी बात रिकार्ड में आ गई है । आप बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : चरणजीत सिंह चन्नी जी, आप बोलिए । केवल आपकी बात रिकार्ड में जाएगी ।

? (व्यवधान)

श्री चरणजीत सिंह चन्नी (जालंधर) : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । देश में 50 परसेंट से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं । इनमें ज्यादातर लोग खेत मजदूर हैं । किसानों के साथ कुल जितने मजदूर काम करते हैं, उसका लगभग 65 परसेंट लोग खेत मजदूर हैं । मेरा सबसे पहले ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट के नाम पर है । मैं चाहता हूं और मेरी रिक्वेस्ट तथा सुझाव है कि डिपार्टमेंट का नाम एग्रीकल्चर फार्मर एंड फार्म लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि जो

खेत मजदूर हैं, उन्हें सरकार की वेलफेयर स्कीम्स का फायदा मिले और यदि किसान का कर्ज माफ होता है तो खेत मजदूरों का भी कर्ज माफ हो । आप किसानों को जो सम्मान निधि देते हैं, वह छह हजार रुपये सालाना है, जो कि बहुत कम है । इसे बढ़ाकर 12 हजार सालाना किया जाना चाहिए और खेत मजदूरों को भी यह राशि मिलनी चाहिए ।

महोदय, शेयर ऑफ डिपार्टमेंट टोटल सेंटर प्लान है, वह पिछले पांच सालों से लगातार कम हो रहा है । वर्ष 2021-22 में 3.53 परसेंट था, वर्ष 2022-23 में 3.14 परसेंट रह गया, वर्ष 2023-24 में 2.57 परसेंट रह गया, वर्ष 2024-25 में 2.54 परसेंट रह गया और आज मात्र 2.51 परसेंट कर दिया है । हर साल आप यह खर्च कम कर रहे हैं ।

महोदय, इसके अलावा, शिड्युल्ड कास्ट सब-प्लान में जो पैसे हैं, वे यूज़ ही नहीं हो रहे हैं । आप हर साल बड़े-बड़े एलान कर देते हैं कि खेती में शिड्युल्ड कास्ट सब-प्लान में इतना खर्च होगा, लेकिन वह खर्च होता ही नहीं है । पिछले साल भी 21,551 करोड़ रुपये रखे गए और एक्चुअल्स 7,106 करोड़ रुपये दिए गए और वह भी खर्च नहीं हुए । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो पैसे दलित, गरीब लोगों के लिए हैं, वे उनके लिए खर्च हों । आप जो पैसे दलितों, गरीबों के लिए रखते हैं, उसे खर्च ही नहीं करते हैं, तो फिर गरीब, दलित, मजदूर कैसे ऊपर उठेगा?

सर, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि अनाज पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने के बारे में सोचें । अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कह ही दिया है कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लाएंगे । भारत सरकार की क्या तैयारी है? उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने यह मान लिया है कि हम अनाज पर इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करेंगे । यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे तो देश के अनाज का क्या होगा? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर जवाब देंगे ।

सर, क्रॉप रेसिड्यू के बारे में कहना चाहता हूं कि पराली के दिन जब आते हैं तो बड़ा रोड़ा पड़ता है । लोग धान काटते हैं तो वहां आग लगायी जाती है और इससे एनवायरनमेंट भी खराब होता है, लेकिन सरकार इसका इलाज नहीं कर रही है । यह हमारा प्रोपोजल है और हमारी स्टैण्डिंग कमेटी ने भी यह रिपोर्ट दी है कि किसानों को

एमएसपी के ऊपर 100 रुपये प्रति किंटल दिए जाएं । अगर आप उन्हें 100 रुपये प्रति किंटल देते हैं तो वे अपनी फसल को काटने के बाद जो पराली है, उसको उठाएंगे और फिर उसको उठाने की उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी और वे उसमें आग नहीं लगाएंगे ।

सर, चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं अब किसान आंदोलन के विषय पर आना चाहता हूं । यह सरकार किस तरीके से आज किसानों के आंदोलन को दबा रही है और किस तरीके से आज हमारी पंजाब की सरकार इनसे मिल कर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है? पहले यहां दिल्ली में एजिटेशन हुआ । उस एजिटेशन के दौरान वहां 750 किसान शहीद हो गए । सरकार ने उनको वहां से यह वादा करके उठाया कि हम एक कमेटी बनाकर आपको एमएसपी देंगे, आपकी डिमांड्स मानी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ । उन्होंने फिर एजिटेशन किया । वे दिल्ली आने लगे, तो सरकार ने हरियाणा में पूरा बंद कर दिया । रास्ता किसानों ने नहीं रोका, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है । इन्होंने वहां रास्ते बंद किए । वहां बैरिकेड्स सरकार ने लगाए हैं । वे किसान तो दिल्ली आना चाहते हैं । प्रधान मंत्री को, मंत्री साहेबान को किसानों की यूनियन्स से मिलने में क्या आपत्ति है? उन्हें यहां आने देते । यहां आप उन्हें एक अलग जगह दे सकते थे, लेकिन इन्होंने रास्ता रोका और इसके कारण किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि किसान एजिटेशन करते हैं, किसान रास्ता रोकते हैं और किसान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला रहे हैं, जबकि किसान तो अन्नदाता हैं । जब खाने की मजबूरी थी, जब देश में अन्न खत्म हो रहा था, उस समय भी किसानों ने देश को अन्न से भरपूर किया और आज भी वह ऐसा करता आ रहा है, लेकिन किसानों को ही क्यों मारा जा रहा है? उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, उनकी ? * जा रहा है । यहां से विश्वास देकर उठाया, फिर वे वहां बैठ गए ।

माननीय सभापति : ?* वाले शब्द को देख लीजिएगा ।

श्री चरनजीत सिंह चन्नी : सर, वहां उनके एक लीडर डल्लेवाल जी भूख हड़ताल पर बैठे थे । उनके पास दोनों सरकारें गयीं और कहा कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, बस आप अपने अनशन को खत्म करके हॉस्पिटल से सहायता ले लो । वे इनकी बातों को मान गए कि ठीक है, ये सुनने को तैयार हैं, मैं हॉस्पिटल से सहायता ले लेता हूं । उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने उनको बुलाया कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, इन्होंने दो मीटिंग्स की, चार मीटिंग्स की । इधर मीटिंग हो रही है और

उधर उनके आंदोलन को खत्म करने की और उनके आंदोलन को उठाने की तैयारी पुलिस द्वारा हो रही है । क्या यह विश्वास है? सरकार तो विश्वास से चलती है । अगर सरकार पर हमारे वोटर्स का विश्वास ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा? अगर आप किसानों को विश्वास में लेकर पीछे से उसकी ?* हैं तो फिर कैसे चलेगा? लोगों को कैसे विश्वास होगा? इन्होंने उनको बुलाकर उनसे बातचीत की । साथ ही, तैयारी भी कर ली और रात के अंधेरे में वहां हजारों पुलिस के लोगों को ले जाकर उन्हें वहां से उठा दिया ।

16.00 hrs

सर, ऐसे कैसे होगा? यह पंजाब के ही किसान के साथ नहीं, पूरे देश के किसानों के साथ गद्दारी है । ? (व्यवधान) सर, यह बीजेपी की नीति है । इन्होंने देश के किसान को बर्बाद करने की पूरी तैयारी की हुई है । ? (व्यवधान) यह इनकी राजनीति है कि किसान वर्सेज़ अदर्स कर के लड़ाई करवाई जाए । जैसे हिंदू वर्सेज़ अदर्स किया, जो कि अब इनका फेल हो रहा है । अब ये किसान वर्सेज़ अदर्स कर के किसानों को मार रहे हैं और दूसरों को दिखा रहे हैं कि किसान ऐसे कर रहे हैं । जबकि ये किसानों को मजबूर कर रहे हैं कि वे सड़कों पर आएँ । ये किसानों को मजबूर कर रहे हैं कि वे इनकी बात मानें । लेकिन किसान मांग क्या रहा है? एमएसपी मांग रहा है । क्यों नहीं देते? उसका राइट है । एमएसपी कोई खैरात नहीं है । एमएसपी की गारंटी देना ज़रूरी है । किसान का कर्ज़ा क्यों नहीं माफ हो रहा है? खेत मज़दूर का कर्ज़ा क्यों नहीं माफ हो रहा है । बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, अंबानी, अदाणी का हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपये माफ कर रहे हो, लेकिन किसानों का नहीं । क्यों? ? (व्यवधान)

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने वर्ष 2024-25 के बजट की कृषि अनुदानों की मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया है । यह बजट माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ष 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प को साकार करने वाला है । उस संकल्प में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि देश के गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण को ले कर उनका संकल्प है । आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कृषि क्षेत्र में इन चारों वर्गों की समृद्धि का रोडमैप तैयार करने का काम इस बजट के माध्यम से किया है । हम सब लोग जानते हैं कि यह आधारभूत सत्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है । इसलिए कृषि

आधारित सिस्टम में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, रोज़गार प्रदान करने के लिए कृषि महत्वपूर्ण साधन है । समग्र आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, इसने भारत के आर्थिक, सामाजिक, ताने-बाने को मज़बूत किया है । यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस भाव को माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचानते हुए अपने विभिन्न पहलुओं के आधार पर इस बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है । यह जब चर्चा होती है, अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा, जिन्होंने खेती देखी नहीं, जिन्होंने गांव देखा नहीं, जिन्होंने किसान और किसान की गरीबी को कभी अहसास नहीं किया, लेकिन देश का एक ऐसा प्रधान मंत्री, जब गरीब माँ का बेटा देश का प्रधान मंत्री बनता है, जिसने गरीबी को इस भारत के अंदर जिया और वे जब इसकी योजना बनाते हैं, तो उन गरीबों के जीवन को बदलने का संकल्प कैसे पूरा होगा, माननीय प्रधान मंत्री जी उसको निहित करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से करते है ।

सभापति जी, गरीबी के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का और भारत के परिदृश्य को बदलने के लिए इस बजट में माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो नेतृत्व और दिशा देने का काम किया है, मैं आज यहां पर कहना चाहता हूँ कि इस बजट में वह भावना निहित है, जो देश के अंदर महात्मा गांधी जी ने ग्राम विकास की परिकल्पना की है । इस बजट में वह भावना निहित है, लोग चर्चाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को, दलित, शोषित, पीड़ित के लिए कैसे हमें आगे ले जा कर उनके जीवन को बदलना है तो इस बजट के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की भावना को भी निहित किया है और पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को भी माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निहित किया है । वित्त मंत्री जी के माध्यम से इस बजट में उन सारी बातों को लाने का प्रयास करते हुए आज हमें गर्व है कि देश के अंदर माननीय प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग गरीबी हटाने का नारा देते रहे, यहां पर विपक्ष के मेरे मित्र हैं, जिन्होंने 55 वर्षों तक राज किया, कभी गरीबी हटी नहीं, केवल गरीबी हटाने का नारा देते रहे ।

वे केवल गरीबी की नारा देते रहे । आज भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं ।

महोदय, आज इस बजट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2008-09 में 11,915.22 करोड़ रुपये का बजट था । आज इस बजट में 1,22,528.77 करोड़ रुपये

का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दिया है । माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एमएसपी में 65 प्रतिशत की वृद्धि की है । अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि किसानों के विपणन के लिए अगर वह रिकॉर्ड देखने का काम करेंगे तो देश के अंदर हमारी सरकार ने सरकारी खरीदी में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है ।

महोदय, उर्वरक को लेकर कई प्रकार की बातें होती हैं । माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इस बजट में सब्सिडी में तीन गुने की वृद्धि हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की जो भाव है, वह कहते हैं ?

?माना कि अंधेरा घना है, दीया जलाना कहां मना है ।?

माननीय प्रधानमंत्री जी अपने इन भावों को कैसे जमीन पर उतारने का काम करते हैं । मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आकांक्षी जिले कौन हैं, कमजोर जिले कौन हैं, देश के अंदर आकांक्षी जिले स्थापित करके उन जिलों को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए सफलतम प्रयोग इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिलों के माध्यम से किया । इस बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । पीएम धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिले जो कृषि क्षेत्र के अंदर कमजोर जिले हैं, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है । इसलिए, ऐसे कमजोर जिले को घोषित करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस दिशा में अपना प्रयास बेहतर तरीके से इस बजट के माध्यम से किया है । आज 1.7 करोड़ किसानों को इसके माध्यम से लाभ पहुंचेगा ।

महोदय, प्रधानमंत्री किसान निधि के माध्यम से आज प्रतिवर्ष 6000 रुपये तीन किस्तों में देकर 11 करोड़ किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये वितरित किये गए हैं । मैं इस सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं । मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 6000 रुपये किसानों को दिये हैं । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लगभग अट्ठाइस लाख किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाया है । पहले एमएसपी के बारे में लोग चर्चा करते हैं । एमएसपी के अंदर भी 32 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । वर्ष 2008-09 में धान की एमएसपी 850 रुपये और गेहूं की एमएसपी 1080 रुपये थी । आज इस बजट के

माध्यम से धान की एमएसपी 2300 रुपये और गेहूं की एमएसपी 2425 रुपये करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है ।

महोदय, कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भी प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से इस फंड को आगे बढ़ाया जाए । इस दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 87,500 से अधिक परियोजनाओं के लिए 52,738 करोड़ रुपये की मंजूरी देने का काम किया है ।

आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं । दलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलहन मिशन की स्थापना की । इस बजट के माध्यम से मसूर, अरहर और उड़द जैसे दालों के बारे में इस बजट के माध्यम से विशेष प्रावधान किया गया है । इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । मध्य प्रदेश दलहन के क्षेत्र में भारत के अंदर एक नंबर पर उत्पादन करने वाला प्रदेश है । आगामी समय में दलहन उत्पादन के लिए जो दलहन का मिशन है, उस दिशा में मध्य प्रदेश के किसानों को भी बड़े पैमाने पर प्रगति करने का अवसर मिलेगा ।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब मध्य प्रदेश के अंदर देश का 25 प्रतिशत दलहन का उत्पादन होता है । इस दिशा में उर्वरक सब्सिडी में भी मध्य प्रदेश देश के अंदर सबसे आगे है । माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरिया उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी की है । 50 किलोग्राम डीएपी का बैग किसानों को 1350 रुपये मिलता था ।

इस साल उसकी कीमत 2,433 रुपये थी । डीएपी पर 1,043 रुपये की सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देने का किया है ।

एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इस बजट के माध्यम से उन्नत बीज मिशन, नमो ड्रोन दीदी और राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के माध्यम से, एग्री स्टार्ट अप के माध्यम से नौजवानों को अवसर देने का काम किया है । माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हमने देश के अंदर आईसीएआर के माध्यम से एग्रीकल्चर बीज के 25 हब स्थापित किए हैं, मिलेट का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ा है । इन प्रयासों से खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है, ऋण सुविधाओं में वृद्धि हुई है और

फसल बीमा बेहतर हुआ है । इसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र विकसित हुआ है और फल-फूल रहा है । दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और वैश्विक नेता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को कृषि उत्पादन और निर्यात में उच्च स्थान मिला है । माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार ।

माननीय सभापति : वैसे सभी को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक विकास दर वहां के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में हुई । यह जानकारी देश के लोगों के पास है ।

श्री के. राधाकृष्णन जी ।

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Thank you, Sir. Sir, I oppose the demands for grants of the Ministry of Agriculture and farmer?s welfare.

The reason why I oppose this is that there is nothing big in this budget that protect the interests of farmers and farm workers. The government has the responsibility to help the farmers in the country who constitute a major chunk of our population. The farmers and farm workers play a crucial role in the wealth creation of the country. Whether our governments are looking into their problems by keeping this fact in mind is to be examined. When we examine this, we can find that their life becomes difficult in every passing year. Many respected members who spoke here pointed out this reality that the life of farmers is going through hardships. Former Chief Minister of Punjab and MP who spoke just now has pointed out the farmer?s agitation and the difficulties they face. The hon?ble minister should examine whether we have given adequate provision in the budget by considering this aspect.

Sir, in 2024-25 budget the allocation was Rs. 1,20,775 crore and in the revised estimate this amount has gone up to Rs. 1,38,980 crore. But in this budget the total allocation is Rs. 1,24,341 crore. That means,

when we compare the last year's budget, the revised estimate, and the present budget allocation, we can see that the amount has decreased by around Rs. 14,000 crore. In the present scenario, whether we will be able to solve the problems of farmers with this amount needs examination. Sir we are neglecting the farmers and the agriculture sector. We must foresee the consequences and the disaster of such a negligence. When the economic slowdown happened throughout the world, we were able to withstand the same to an extent. How did we manage this? When the big powers like US had suffered due to crisis how did we tide over the situation? When we examine that we could see the importance of our agriculture sector. Over 52 per cent of our population is depending upon the agriculture for their livelihood. We have agriculture-based industry and agriculture-based economy. Just because of that agriculture-based economy we could withstand the big economic crisis. So, the main pillar that support our economy is the agriculture sector. Hence, we have to give adequate allocation to protect such an important sector, but sadly every year that allocation is going down, this is what we can see.

Sir, we cannot forget the agriculture while discussing about our economy. We should intervene to protect every important agriculture produce. For that, we should be able to provide timely help to the farmers. The main reason for the farmers moving away from the agriculture is the rising input cost and the non-availability of reasonable prices for their produce. So, we must have the mechanism to ensure the reasonable price for their produce. That is why the hon'ble members who had spoken here demanded the need for minimum support price. The state I represent, Kerala have been asking for many years about minimum support price. Many members have referred about Sri M.S. Swaminathan.

16.17 hrs

(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude now. You have taken more than five minutes. Just put your demand.

SHRI K. RADHAKRISHNAN : Till now we could not fix the MSP as per his recommendations. Farmers in Kerala are not getting enough price for their produce in accordance with the input cost, and that is the reason for the agriculture crisis in the state. So, to provide the minimum support price and to ensure that the famers get the same, Centre government should intervene in all possible way. Since the farmers who cultivate rubber, coconut, and paddy are in crisis centre government must give necessary assistance to them. Most of the time Kerala does not get the share from the centre. The state government have been demanding for quite some time to increase the minimum support price of rubber to Rs 200. The centre should accept this demand or else there will be a great crisis in agriculture sector. Sir, the centre must take a stand to help the states like Kerala. Recently there was a big natural calamity in the state and the damage was very heavy and there was crisis in the agriculture sector. The state government approached the centre for compensation on several occasions, but the centre is not helping. So, I demand the centre should give assistance to the state and to take steps to help whenever the natural calamity takes place.

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग की अनुदानों मांगों पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । समय बहुत कम है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । मैं माननीय मंत्री जी से सीधे सवाल कर रहा हूं, जिसका वह जवाब दें । बिहार में एक मक्का अनुसंधान केन्द्र की स्थापना 20 साल पहले तत्कालीन यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने की थी । इस अनुसंधान केन्द्र की स्थापना बेगुसराय में हुई थी, जिसके जरिए बिहार के 15 जिलों में मक्का उत्पादन करने वाले किसानों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आया ।

मक्का उत्पादन में, यील्ड के मामले में बिहार सबसे ज्यादा नम्बर वन स्थान पर पहुंच गया । वह इलाका, जो कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका है, जहां सबसे ज्यादा पलायन और गरीब है, वहां मक्का फसल ही सबसे बड़ा आधार है, जिसके उत्पादन के जरिए व्यापक पैमाने पर किसान के पास आमदनी आती है । वहां के किसानों का मांग थी कि हमारे उत्पादन पर एमएसपी गारंटी हो, एमएसपी पर खरीद हो और बाजार की व्यवस्था हो । लेकिन, भारत की सरकार ने सदन में एक सवाल के माध्यम से कहा कि मक्का अनुसंधान केंद्र को बेगुसराय से उठाकर शिमोगा, कर्नाटक ले जाया जाएगा । इस संबंध में सरकार का जवाब आया है । एनडीए में बिहार से 30 सांसद हैं । वे सदन के अंदर बजट में इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं । बिहार के लिए इससे बड़ा कोई दुखदायी विषय नहीं हो सकता है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब देते समय इस बात का जिक्र करें । अगर शिमोगा में मक्का अनुसंधान केंद्र की आवश्यकता है तो वहां एक नये संस्थान की स्थापना की जाए । बेगुसराय से उसको हटाने की क्या आवश्यकता है? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में जो ?पूसा? केंद्र है, वह किसी जमाने में बिहार में हुआ करता था । जब वह बिहार में था तो बिहार इस देश में गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान पर था । आजादी के समय 32 प्रतिशत गन्ने का उत्पादन बिहार में हो रहा था, लेकिन केंद्र ने ?पूसा? को समस्तीपुर से उठाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया । आज हम गन्ना उत्पादन में निचले स्तर पर पहुंच गए हैं । इतना ही नहीं दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी जिस मखाना की बात कर रहे थे, दरभंगा में मखाना के उत्पादन के लिए एक अनुसंधान केंद्र बना है । लेकिन, उस अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों की अनुपस्थिति के चलते वह मृतप्राय है ।

एक नये नारे भी गढ़े गए हैं कि हम मखाना बोर्ड बनाएंगे । मैं कहना चाहता हूं कि मखाना बोर्ड से पहले नारियल बोर्ड भी बना था, उसका क्या हुआ? बिहार में जूट बोर्ड भी बना था, उसका क्या हुआ? जब उन दोनों बोर्डों का प्रदर्शन नहीं हुआ, जिनको भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था तो मखाना बोर्ड का क्या होगा? मखाना बोर्ड की जगह बिहार में मंडी की स्थापना होनी चाहिए थी । एनडीए के साथी ने कहा था कि बिहार में बाजार समिति नहीं होने के चलते किसानों के उत्पाद औन-पौने भाव में बेचे जा रहे हैं । उसके लिए बिहार में मंडी कानून लागू होना चाहिए था । लेकिन, मंडी कानून का लागू नहीं होना और मंडियों के निर्माण के लिए जो निवेश की आवश्यकता है और किसानों

की आमदनी को दुगुना करने का जो सवाल है, वह मंडियों के निर्माण हुए बिना संभव नहीं है। मैं इन प्रमुख बातों पर चर्चा करना चाहते थे।

महोदय, दूसरा विषय एमएसपी को लेकर है। एमएसपी को लेकर लगातार मैं माननीय मंत्री जी का बयान इस सदन के अंदर सुनता रहता हूँ। जो यूपीए बनाम एनडीए के आंकड़े पेश होते हैं, मैं उन आंकड़ों की तरफ संकेत करना चाहता हूँ। आप उसको देख लीजिए। यूपीए में कांग्रेस की सरकार ने दस साल में वर्ष 2004 से वर्ष 2014 के बीच में गेहूँ और चावल का 137 फीसदी दाम बढ़ाने का काम किया। वहीं वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के बीच में एनडीए की सरकार ने केवल 69 परसेंट अनाज का दाम बढ़ाने का काम किया। जब आप एमएसपी पर दाम नहीं बढ़ाते हैं तो आप एमएसपी देकर भी क्या करेंगे? यह एक अंतर है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी की तरफ से इसलिए जवाब चाहिए, क्योंकि माननीय मंत्री जी लगातार कहते हैं कि हम डेढ़ गुना की गारंटी देते हैं।

महोदय, हम दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त कर देंगे। इस देश में कपास मिशन शुरू करने की बात हुई। इस देश में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीटी कॉटन को लाया गया। 20 साल में उसका दुष्परिणाम सबके सामने है कि आज कपास का उत्पादन घट रहा है। अब ये कपास मिशन चलाने की बात कर रहे हैं। जब जीएम सीड फेल हो चुका है तो ये पुनः जीएम सीड की तरफ जा रहे हैं। अब तो उससे भी खतरनाक तकनीकी, विदेशी तकनीकी, जो विश्व सम्प्रभुता को समाप्त करने के लिए जीई टेक्नोलॉजी लाने की बात इस देश में की जा रही है। यह देश के विश्व सम्प्रभुता को समाप्त कर देगा।

माननीय मंत्री जी तीनों सवालों का जवाब देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR): Hon. Chairperson Sir, I thank you for the opportunity given to me to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

This Government's slogans are very good, but practically, they are not up to the mark. There are five top slogans which the Government always talks about. Those are, 'सबका साथ, सबका विकास', 'अच्छे दिन आने

वाले हैं?, ?विकसित भारत?, ?आत्मनिर्भर भारत? और ?घर-घर रोजगार?, सरकार ये स्लोगन बोलती रहती है । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : That is why, you are here.

? (*Interruptions*)

श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी : महोदय, जो किसान हैं, भारत में जो प्रोफेशनलिज्म चलता है, इस देश के जो 60 प्रतिशत किसान हैं, उनके लाइविलीहुड के लिए आपका बजट कितना है? सिर्फ 3.8 प्रतिशत । वर्ष 2024-25 में 1.41 लाख करोड़ रुपये, वर्ष 2025-26 में 2.5 लाख करोड़ रुपये कम करके यानी 1.37 करोड़ रुपये खर्च किए हैं । यह दिखता है कि ?सबका साथ, सबका विकास? यही है । क्या आपको किसान नहीं दिखते हैं? क्या इस देश में किसान नहीं हैं? आप किसानों के लिए कुछ नहीं करते हैं? क्या आपको कॉर्पोरेट फ्रेंड्स ही दिखते हैं? आपने उनके तीन लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में आपने किसानों के लिए क्या किया है? आपने किसानों का कितने लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है? आप वह नहीं कर पाए हैं ।

यह जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके बारे में तो काफी चर्चा हुई है । आपके पास कभी किसानों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है । एमएसपी तो बिल्कुल लागू ही नहीं की है । स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें फुलफिल ही नहीं की हैं ।

As regards Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the flagship crop insurance scheme has seen a brutal cut of 22.9 per cent in this Budget, as compared to the last year. ?पीएम किसान सम्मान निधि? 6000 रुपये है । वह भी तीन बार में अर्थात् दो-दो हजार रुपये दिए जाते हैं । आज फर्टिलाइजर की कीमत क्या है? डीजल का क्या रेट है? The price of seeds has sky-rocketed. The Government of India should rethink if they really want to do something for the farmers.

The Budget is designed to favour the corporates.

HON. CHAIRPERSON: What is your suggestion?

SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY : Sir, I am coming to that. Since you have given me five minutes, I should tell you everything. मैं पहले नहीं बोलना चाहता हूं । आपने क्या-क्या किया है, मैं बाद में बताता हूं कि क्या-क्या करना है ।

Sir, please look at the facts. The increase in funds for agricultural research and education is pathetic, that is, Rs. 21 crore. It is a rise of merely 3.05 per cent. Climate change threatens crop yields. Makhana and Pulse Boards are empty gestures without real financial backing.

As regards e-NAM, that is, National Agriculture Market, the integration remains slow, leaving farmers at the mercy of middlemen. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana remains riddled with corruption.

Unlike this corporate-controlled Government, I can proudly say that our Congress Party has always stood with the farmers. It was the UPA Government in 2008, under the leadership of the then Prime Minister, Late Dr. Manmohan Singh ji, which gave a loan waiver of Rs. 60,000 crore. At the same time, when you look at the Government in Telangana, which had been formed last year, it has waived loans worth Rs. 21,000 crore in one stretch. Our Chief Minister, Shri Revanth Reddy ji has done this loan waiver which has benefitted about 25.35 lakh farmers.

During the first year of the Government, in 2024, the Congress Government in Telangana had spent Rs. 70,000 crore on farmers, which is nearly 20 plus percentage. Here, it is only 3.05 per cent increase but there, it is 20 plus percentage. So, please compare this. I am telling this to the people of this country and also to my colleagues on the other side. This is what we have done in Telangana.

Sir, just two days back, a Bill has been introduced in Telangana, through which Rs. 62,786 crore have been allocated to agriculture out of

the total budget of Rs. 3.04 lakh crore. This is again an increase of 20 plus percentage which the Congress Government has done in Telangana for the farmers. That includes even Rs. 12,000 for the farmers. Here, they are giving Rs. 6,000 in three instalments. But we are giving Rs. 12,000 at a stretch to the farmers, especially the labourers who are not having lands. I am talking about the labourers who are working in the farm lands and who do not have lands. So, this is what we are giving to the farmers under the Rythu Bharosa Scheme?

The other thing that we are doing is that we are giving Rs.500 as bonus to the farmers who are producing rice.(Interruptions) इस सिस्टम के साथ 25 लाख एकड़ से 40 लाख एकड़ तक तेलंगाना में खेती बढ़ गई है । Telangana Government is also purchasing rice from the farmers. (Interruptions)

There are two things, which I want to ask to the Government through you. Telangana is trying to promote oil palm cultivation under the National Mission on Edible Oils (NMEO-OP) launched in 2021-22. Our Agriculture Minister is in constant touch with the Government in this regard.

Another issue is with regard to the coconut production in Telangana. We are producing about 1.37 lakh nuts a year. But the coconuts are produced in only a few districts of Telangana.(Interruptions) Therefore, we request the Government to set up a Special Regional Office of Coconut Development Board in Telangana.(Interruptions)

Kindly give me one last minute to conclude.(Interruptions)

Sir, we want the Government to provide legally-guaranteed MSP for all crops, nationwide loan waivers for small and marginal farmers, massive investment in climate-resilient farming and irrigation projects,

and transparent insurance claims being processed under Prime Minister Fasal Bima Yojan with a strong grievance redressal mechanism. These are my requests to the Government. Thank you, Sir.

श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी (राजामुन्दरी) : सर, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर अपना वक्तव्य रखने का अवसर दिया । मैं बजटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अंडर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के समर्थन में खड़ी हुई हूँ ।

The strength and vitality of our farmers is closely linked to the growth and progress of our country. Today agriculture engages about 46 per cent of the workforce and its contribution to the GDP of our country is around 18 per cent. Despite this fact, the share of agriculture is progressively declining in our economy. But the importance of this sector goes beyond this indicator.

About three-quarters of Indian families depend on rural incomes, and a large section of the poor actually lives in rural areas. Over and above, the food security of our country is largely dependent on the agriculture sector. Therefore, realizing the potential, the relevance and the importance of the agricultural sector, innovation in farming practices and constant focus on high-yielding crops should be the focal point. It is also important to address the multifaceted challenges that this sector actually faces.

When we look back, in the past one decade since 2014, various issues that have been raised by my colleagues on the other side of the House have been continuously addressed time and again. There is an increase in the allocation of budget. This year the allocated budget is Rs.1,37,757 crore in comparison to Rs.1,22,528 crore in the previous budget. It clearly emphasizes our commitment to the fact that we would like to double the income of our farmers.

Credit availability is the first priority of the Government. It actually helps the farmers to increase the productivity to meet the changing market demands and also to brave the changing climatic conditions. Today, surveys have revealed that only about 30.3 per cent of the agrarian families have access to institutional credit. According to the latest report, which is normally done keeping the rural household in consideration, in 2019 it had come to the fore that over half of the farming families are caught in a quagmire of debt and each household has an outstanding debt of Rs.74,121. This debt burden normally leads to a vicious cycle of poverty and in extreme cases could even lead to farmer suicides. Here, the Kisan Credit Card (KCC) has actually transformed the availability of institutional loans for our farmers.

According to a 2024 report, we have 7.75 crore Kisan Credit Cards in the country and loan availed on these Kisan Credit Cards is around Rs.9.81 lakh crore. In the past one decade, an amount of around Rs.1.24 lakh crore has been released as interest subsidy on the Kisan Credit Cards.

The proportion of small and marginal farmers who have been availing institutional credit today has risen from 57 percent in 2014-15 to 76 percent in 2022-23. Therefore, we need to understand and realise that the increase in the available amount under the Kisan Credit Cards, which has been raised from Rs. 3 lakh to Rs. 5 lakh, is a transformational change and is going to support large sections of our farming society.

Today, India is home to 18 per cent of the world's land but houses only about four per cent of the global water resources. To top it all, climate change, due to global warming, is a reality and is here to stay. The dependency of the farming community or the over-reliance on monsoons has hampered our agricultural growth. According to the

reports of 2022-23, only 52 per cent of our cultivable land has access to irrigation facilities. It is estimated that due to global warming, about 15 per cent to 18 per cent of income would be reduced for families that possess land, while nearly 25 per cent of income would be reduced for those farming families that do not have land. Over-pumping of water has led to underwater depletion, and water logging has increased soil salinity. Heavy rains have caused soil erosion. Therefore, research and extension play a very important part, and we need to welcome the National Mission on Higher Yielding Seeds and the Gene Bank, which is going to house about 10 lakh germ plasms. It is a very welcome measure.

Under the National Mission for High Yielding Seeds, research will be conducted to develop seeds that are resilient to both pests and climatic conditions, and at the same time, would be able to withstand floods, droughts, or saline conditions in our country. Therefore, all of us across the board must welcome this measure. Regarding the Gene Bank, this would ensure that? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude.

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI : Sir, give me two minutes.

HON. CHAIRPERSON: One minute.

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI: Then I will have to lay this down on the Table.

HON. CHAIRPERSON: There are so many speakers. The Minister has to reply at 5 p.m.

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI: I will lay my speech on the Table, but I would like to raise a couple of concerns here, especially regarding the Krishna water distribution. The Bachawat Tribunal was constituted in 1969 to settle the water disputes between the three States

of Karnataka, Andhra Pradesh, and Maharashtra. About 811 TMC was apportioned to Andhra Pradesh, and later, after the bifurcation of the State, 512 TMC was allocated to Andhra Pradesh and 299 TMC was allocated to Telangana. This allocation was based on the command area as well as the existing utilization mechanisms. Today, to revisit the terms of reference and to suggest going back retrospectively to share the water would be doing injustice to Andhra Pradesh, so I request the Government to look into it.

Lastly, the word 'tariff' has never made it to the news as much as it has today after the President of the United States, Mr. Donald Trump, announced reciprocal tariffs. The products imported into the U.S. from countries with which it has a trade deficit would negatively impact every sector in our country. ? (*Interruptions*)

In January 2025, US Department of Agriculture in its paper had noted that India is confronting production challenges in agriculture due to climate change and in this situation, US could find a good market if exploited. Hence, we need to tread the soil with great caution.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Your point has been well taken.

DR. RAJ KUMAR CHABBEWAL (HOSHIARPUR): I thank you hon. Chairman, Sir for giving me the opportunity to speak on Demands for Grants under the control of Ministry of Agriculture for the year 2025-26.

Sir, I hail from Punjab. Punjab is an agricultural State.

Sir, Punjabis have been at the vanguard in sacrificing their lives for the sake of our country's independence during our freedom struggle. Punjabi farmers ushered in the Green Revolution. Before 1960s, India was not self-sufficient in production of foodgrains. In the last 5 decades,

the farmers of Punjab have contributed a lot in maintaining our food-security.

Hon. Chairman Sir, Punjab has only 3 per cent of our country's cultivable land which is 42 lakh hectares. However, Punjab produces 18 per cent wheat, 11 per cent rice, 4 per cent cotton of the total production in India. The market infrastructure of 'Mandis' is strongest in India. In 2023-24, 24 per cent rice was contributed and 50 per cent wheat was contributed in the Central pool by Punjab.

Hon. Chairman Sir, Punjab is stuck up in the production of wheat and rice. Today, Punjab and other such States need crop diversification. Punjab is taking a lot of measures. We have cleared the remaining amount of money of sugarcane farmers. More than Rs. 750 crores were given to such farmers. Similarly, Sir, Rs. 1500/- per acre was provided to farmers during the cultivation of paddy. For hybrid seeds of maize, our State Govt. provided Rs. 100/- per kg amount to the farmers. We also provided subsidy for farmers at the rate of Rs. 6000/- per hectare.

A far as SAP is concerned, Punjab's rate of SAP is above Rs. 400/-. So, I urge upon the Hon. Minister Sir that a big package should be granted to Punjab for crop-diversification. We need a package of at least 20,000/- crores.

If we talk about the Agricultural budget of 2025-26, Rs. 1,37,757 crores have been allocated. But, in 2024-25, it was Rs. 1,41,352 crore. So, the Budgetary amount this year has been reduced.

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए ।

DR. RAJ KUMAR CHABBEWAL: Subsidy has been reduced by 18%...

माननीय सभापति: आपकी बात आ गई है । आपके लिए तीन मिनट का समय था और आपको बोलते हुए चार मिनट हो चुके हैं ।

? (व्यवधान)

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Hon. Chairman Sir, Vanakkam. With no livelihood and only despair all around, as many as 10000 debt-ridden farmers commit suicide every year. During the last 10 years, approximately more than 1 lakh farmers had committed suicide in our country. This Union Government waived off the loans of the Corporate houses to the tune of Rs 15 lakh Crore. But the Government has not waived off farm loans which shows how our farmers are betrayed. The farmers of our country are agitating against this Union Government. Minimum Support Price, MSP for their agricultural produce is one of their pertinent demands and they want this MSP to be fixed and legalized. During the last 10 years the input cost along with the prices of seeds and fertilizers have gone upwards two to three times. But the prices of agricultural products have not gone up. Our farmers do not get remunerative prices for their produce. Fixing the right price for the agricultural produce is still a mirage. Prices of agricultural produce, fixed in such a way, should therefore be profitable and remunerative. This should be aimed at improving the livelihood of farmers. As recommended by Prof. Dr. M.S. Swaminathan, the prices guaranteed as such should be fixed on the basis of C2+50% formula. Minimum Support Price (MSP) fixed in such a way should be implemented 100 percent and a law should be legislated in this regard without any further delay. I condemn this Union Government for making strict guidelines as regards implementation of Crop Insurance Schemes thereby denying the benefits to farmers, at large. Every farmer pays premium for the crops and land separately and get into the cover of insurance schemes. But when the crops are damaged, the insurance claims are reviewed and settled only if the Taluk or Birga where the farmers live in fully affected. This is completely dishonest and injustice on the part of implementation. Crop

insurance schemes which are being implemented presently are not aimed to benefit the farmers. On the contrary, the corporate companies and insurance companies are earning so much of profit and filling their purse. Therefore, I make a fervent appeal to consider and review claims individually and settlements be made to each of the farmers separately. Insurance policies and related laws should therefore be amended in such a way by including the clauses relating to damages caused to crops by birds and wild animals as regards the settlement of claims. If the communal BJP government of the Union do not change their behaviour, they will end up in facing the ire of the people of Tamil Nadu. Let the voices of the farmers be raised against the Union Government which is continuously engaged in deceiving the farmers of our country. Thank you.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, given the paucity of time, I will come straight to the point.

हल जोत कर, खुन बहा कर, फिर भी अन्नदाता लाचार है ।
खेतों में सोना उगाने वाला, खुद भूख से बेजार है । ।
कभी बारिश की मार पड़ी, तो कभी सूखे ने रुलाया है ।
मोदी सरकार वादे करती रही, मगर किसने दर्द समझाया है?
कर्ज तले दबे हैं खेतों के राजा, हर दिन एक नई चुनौती है ।
फसल उगाने वाला खुद ही, जीवन से हारकर रोनी है । ।
हल की मूठ पकड़ने वाले, अब रस्सी पकड़ झूल रहे हैं ।
धरती मां के वे सपूत, सपनों संग ही धूल रहे । ।
बचाओ इन्हें, संभालो इन्हें, ये देश की शान हैं ।
किसानों की खुशहाली में ही, भारत की असली पहचान है । ।

माननीय सभापति : उलाका जी, आपने पूरी स्पीच पोएट्री में कह दी ।

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका : सर, अभी मैंने स्पीच शुरू भी नहीं की है । The total budget estimate is Rs. 1,37,000 crore; 2.7 per cent of the overall Budget. If you compare, it was 4.69 per cent in 2021, जोकि अब घट गया है । The agricultural growth has been stagnant at 3.6 per cent since 2018-19. The contribution to gross value addition is stuck at 18 per cent. इसलिए अभी किसान रास्ते पर, सड़क पर, हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लीगल गारंटी, लोन वेवर, जो भी उनका सम्मान है, उनको वह चाहिए । सर, यह चीज केवल एग्रीकल्चर बजट में नहीं देख रहे हैं । शिवराज चौहान जी यहां हैं । मैं यह रूरल डेवलपमेंट में भी देख रहा हूं । मनरेगा का जो बजट है, इस बार 22 per cent of the Budget will go into paying the liabilities of last year. 86 हजार करोड़ रुपए, जो बजट है, वह 22 प्रतिशत कम है । प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कहा गया कि पिछले पांच सालों में हम दो करोड़ घर देंगे । सर, उन दो करोड़ घरों में एक करोड़, 50 लाख वे घर हैं, जो पेंडिंग हैं । जो आवास प्लस योजना है, वर्ष 2018 की जो एसईसीसी लिस्ट है, उसमें डेढ़ करोड़ घर गए, तो केवल 50 लाख घर हैं, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलते हैं ।

सर, ये केवल किसान को नहीं, बल्कि सभी को धीरे-धीरे लूटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को फायदा पहुंचा पाएं और किसानों को नुकसान पहुंचा पाएं । मैं यह कह कर अपनी बातों को विराम देता हूं । धन्यवाद ।

श्री दिलीप शङ्कीया (दारंग-उदालगुड़ी) : सर, आज का दिन इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है । आज का दिन लोकतंत्र का विजय दिवस है । 24 जून, 1975 को इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लगाई थी और 19 महीने आपातकाल चला । देश के गणतंत्र का गला घोट दिया गया ।

हमारे बीच में जो लोकतंत्र सेनानी नहीं रहे, मैं आज लोकतंत्र विजय दिवस के अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जो सेनानी जिंदा हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं । सभापति जी, अब मैं विषय पर आता हूं । भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका जी ने कृषकों के लिए बहुत

अच्छा गीत गाया था । मैं इस गीत के द्वारा कृषकों के लिए श्रद्धा प्रकट करता हूं और गीत गाने की भी कोशिश करता हूं:

*?O mor dharitri aai, saronote diba thai

Khetiyokor nistar naai maati bine asohaai

Doya kora doyashila aai,

Rod borosun kaati kori,

Gham pelau soh kori,

Tomar bukur son sopaau

Aane niye karahi,

Maati aaru khetiyokor

Samondh aase jug jugor,

Krisok maatir milonor, diye ontoraai?

This means in English:

?Oh, my mother earth,

Let me rest at your feet

The farmers do not have a path to salvation

Without you, we all are helpless

Please have mercy on us,

Braving the sun and rain

I harvest gold,

While others snatch away the harvest

Soil and farmers,
Share a bond for ages,
In the union of farmer and soil,
This is the only barrier.? *

सभापति जी, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में कृषि, कृषकों के हित, कृषि क्षेत्र के विकास, कृषकों को न्याय दिलाने और कृषकों को उनके उत्पाद की डेढ़ गुना एमएसपी देने का प्रयास किया गया है । इसके बहुत-से परिणाम हमारे सामने हैं । मैं सबसे पहले अन्नदाता कृषकों को सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि पिछले 11 सालों में कृषि क्षेत्र ने देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान सुनिश्चित किया है । देश की जीडीपी में 18 परसेंट से अधिक का योगदान रहा है । हम सब जानते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का कार्यकाल वर्ष 2009-2014 तक रहा और इन पांच साल के कार्यकाल में कृषि का कुल बजट 21,082 करोड़ रुपये था जबकि माननीय मोदी जी के आने के बाद वर्ष 2025-26 में बजट 2 लाख 35 हजार करोड़ रुपए हो गया । ? (व्यवधान) कहां यूपीए सरकार का बजट लगभग 22 हजार करोड़ रुपये था और कहां माननीय मोदी के कार्यकाल में 2 लाख 35 हजार करोड़ रुपये बजट हो गया । ? (व्यवधान) सभापति जी, सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यूपीए सरकार के समय में किसानों की आत्महत्या की खबरें हर दिन मीडिया में और न्यूजपेपर्स में आती थीं और इससे हम लोग भी दुखी होते थे । ? (व्यवधान) लेकिन उन कृषकों को संवेदना देने के लिए, उनके पास कृषकों घर जाने के लिए समय नहीं था और न ही संवेदनाशीलता थी ।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त करें ।

माननीय कृषि मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया : महोदय, आज माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने कृषकों को सम्मान देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से कई योजनाएं चलाई हैं ।? (व्यवधान)

मैं अपने क्षेत्र की डिमांड रखकर अपनी बात समाप्त करता हूँ । असम सहित पूरा पूर्वोत्तर भारत ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल फार्मिंग के लिए जाना जाता है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी और भारत सरकार से विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि पूर्वोत्तर भारत को स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन बनाने का कष्ट करें ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय कृषि मंत्री जी, आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सब लोग अपनी स्पीच ले कर सकते हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: जो सदस्य नहीं बोल पाए हैं, आप सब सदस्यों से आग्रह है कि आप सब अपनी स्पीच ले कर सकते हैं क्योंकि छः बजे गिलोटीन है ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय कृषि मंत्री जी, आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : भारत देश की पहचान कृषि और ऋषि परम्परा से होती है । कृषि की पहचान दुनिया के लिए नयी हो सकती है लेकिन इसका उल्लेख त्रेता युग से मिलता है । उदाहरण स्वरूप राजा जनक जी स्वयं हल चलाने के लिए निकले और फलस्वरूप माता सीता जी की उत्पत्ति हुयी । संभवतः अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द का संधिविच्छेद करें तो इसका मूल सनातन परम्परा से जुड़ा प्रतीत होता है । ऋषि का अर्थ अर्थात् शोध करने वाला और वास्तव में कृषि भी एक प्रकार का शोध ही है इसी कारण किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र की हमारी मोदी सरकार सतत प्रयत्नशील है । सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उन्नत सिंचाई के साधन, Microdrip Irrigation मृदा परीक्षण करके Nitrogen Phosphorus, Nima इत्यादि की जांच करके आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करते हुए किसानों की अधिक पैदावार बढ़ाने की चिंता करते हुए सरकार हमेशा सक्रिय है । विपक्ष के सबसे बड़े माननीय नेताजी अपने भाषणों में कहते हैं कि ऐसी मशीन लगाऊँगा कि इस साइड से आलू डालो और उस साइड से सोना निकलेगा । एवं हरियाणा के किसानों को जलेबी की फैक्ट्री

लगाने की सलाह देते हैं और हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च की खेती करने की सलाह देते हैं ।

मैं एक कविता के माध्यम से मोदी सरकार के बारे में कहना चाहता हूं - गांव की गलियों में तब उम्मीदों के दीप जलते हैं, जब ब किसान के साथ, सरकार मिलकर चलती है । आज माननीय मोदी जी की सरकार किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है । जिससे किसानों के जीवन में अब नया सवेरा आया है । किसानों की योजनाएं सिर्फ कागजों में नहीं यथार्थ के धरातल पर उतर रही हैं और उसका परिणाम है कि देश के किसान समृद्ध हो रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं और कृषि के प्रति लोगों का झुकाव लगातार बढ़ रहा है । कृषि भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । किसान देश के भाग्य विधाता है परंतु आजादी के बाद से लगातार किसानों के साथ छल किया गया, धोखा दिया गया, उन्हें लूटा गया । आजादी के 50 वर्षों तक कांग्रेस एवं कांग्रेस सरकारों का एक ही काम रहा है, किसानों का शोषण, दमन एवं किसानों की योजनाएं सिर्फ कागजों पर रही हैं ।

50 साल तक देश के कवि गाते रहे हैं -

?भरता है तू पेट सभी का
फिर भी तू ही भूखा क्यों
तेरे ही बच्चों की फीकी,
होली और दिवाली क्यों ?
रोता हुआ दशहरा तेरा,
ऐ बीहड़ बेहाली क्यों ??

देश में जब जब गैर कांग्रेसी सरकार रही, तब तब किसानों के लिए सोचा गया और किया गया, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, अटल जी की सरकार हो । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने किसानों के दर्द को समझा और किसान हित में कई प्रभावी कदम उठाए गए जिससे किसानों की दशा और दिशा में भारी परिवर्तन आया है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक ही संकल्प लिया, अन्नदाता सुखी भवः, जिसके श्रम से खा रहा भोजन हिन्दुस्तान देश में पहली बार उन्हें मोदी ने दिया

सम्मान । मोदी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं । हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है । कृषि एवं किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । सरकार की योजनाओं से किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है । पिछले 10 सालों में संस्थागत ऋण प्रवाह तीन गुना बढ़ा है । 2014-15 में यह 8.5 लाख करोड़ रूपया था, जो साल 2023-24 में बढ़कर 24.48 लाख करोड़ रूपया हो गया है । अल्पकालीन कृषि ऋण दोगुना से अधिक हो गया है । 2014-15 में यह 06.04 लाख करोड़ रूपया था । जो बढ़कर 2023-24 में 15.07 लाख करोड़ रूपया हो गया है । मोदी सरकार ने कृषि बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है

पार्टी	वर्ष	बजट राशि विवरण
कांग्रेस	2008-09	11,915.22 करोड़ रूपये
कांग्रेस	2013-14	21,933.50 करोड़ रूपये
भाजपा	2024-25	1,22,528.77 करोड़ रूपये
भाजपा	2025-26	1,27,000 करोड़ रूपये का बजट पेश

खद्यान्न उत्पादन में वृद्धि -

पार्टी	वर्ष	कुल खद्यान्न उत्पादन
कांग्रेस	2004-05	204.6 मिलियन टन) (चौथा अग्रिम अनुमान)
भाजपा	2014-15	252 मिलियन टन
भाजपा	2023-24	332.3 मिलियन टन

प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रों में वृद्धि

पार्टी	वर्ष	प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि
कांग्रेस	2004-05	120.2 मिलियन हेक्टेयर
भाजपा	2014-15	124.3 मिलियन हेक्टेयर
भाजपा	2023-24	132.1 मिलियन हेक्टेयर

प्रमुख फसलों के उत्पादकता वृद्धि का चार्ट

फसल	वर्ष 2013-14	वर्ष 2023-24	अंतर	प्रतिशत
वृद्धि का	(किग्रा/हेक्टेयर में)	(किग्रा/हेक्टेयर में)	(किग्रा/हेक्टेयर में)	
चावल	2416	2882	466	
19.29				
गेंहू	3145	3559	414	13.16
मक्का	2676	3351	675	25.22
मोटा अनाज	1717	2945	1228	71.52
कुल दलहन	763	881	118	
15.47				
कुल खाद्यान्न	2120	2515	395	18.63
कुल तिलहन	1167	1314	147	
12.60				
गन्ना	70522	78953	8431	
11.96				
जूट	2639	2783	144	
5.46				

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान)

इस योजना ने तो छोटे एवं सीमांत किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है । पात्र सभी किसान को प्रति वर्ष 6000 रु., 2000 के तीन किस्तों में, कोई बिचौलिया नहीं, सीधे किसानों के खातों में । इस योजना ने किसानों को अब साहूकार एवं सेठों के चुंगल से मुक्ति दिला दी है । केसीसी ऋण सीमा बजट में 3 लाख बढ़ाकर 5

लाख मत्स्य पालन एवं पशु पालन को भी केसीसी योजना में शामिल पिछले 10 वर्षों में किसान क्रेडिट कार्डों पर 1.44 लाख करोड़ रुपये की ब्याज सबसीडी जारी की गई है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- पिछले 09 साल में 21.95 करोड़ किसान भाई-बहनों को लाभ मिल चुका है । इसके अतिरिक्त 1.72 लाख करोड़ के दावों का भुगतान किसानों को किया जा चुका है ।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना - 8 हजार 272 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला देश में स्थापित । (1068 स्टेटिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, 163 मोबाईल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, 6376 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला एवं 668 गांव स्तर की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है ।)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी, जल संसाधनों का फसल प्रबंधन, ड्रिप और स्ट्रीपलर के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई ।

परम्परागत कृषि विकास योजना - वर्ष 2024 तक 9268 एसपीओ का गठन और संवर्धन के लिए केन्द्रिय क्षेत्र की योजना के तहत संवर्धित किया है । जैविक खेती अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता ।

राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) - कृषि उत्पादनों के लिए एकीकृत ऑनलाईन मार्केट तैयार करना, देशभर के कृषि बाजारों को जोड़ना, किसानों को बेहतर दाम दिलाना, पारदर्शी व्यापार प्रक्रिया । अब तक 1410 मंडियों को एकीकृत किया गया है । 31 दिसम्बर 2024 तक 1,79 करोड़ किसान और 2.63 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत है ।

कृषि और अवसंरचना कोष - कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, 1 लाख करोड़ के कोष की स्थापना, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्रोससिंग यूनिट का विकास ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन - देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, विशेषकर गेहूं, दलहन, और मोटे अनाजों की पैदावार को बढ़ाने पर जोर, आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए किसानों को सहायता, बीज, उर्वरक और किटनाशकों पर अनुदान ।

जल संरक्षण - "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" योजना के तहत जल संरक्षण पर जोर ।

फसलों के एमएसपी में लगातार वृद्धि - किसानों की आय दुगुनी करने के लिए मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। फसलों के एमएसपी दर को लगातार बढ़ाया गया है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन - देसी नस्ल के पशुधन का संरक्षण एवं संवर्द्धन, दूध उत्पादन को बढ़ान एवं पशुपालन को आधुनिक तकनीक से जोड़ना।

मिलेट : भारत का सुपरफूड - आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2023-24 के बजट में की गई घोषणा का फल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में दिखने लगा है। पिछले 1 वर्ष में ही मिलेट उत्पादन में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 में 173.21 लाख टन। वर्ष 2023-24 (अंतिम अनुमान) में 175.72 लाख टन।

आई.सी.ए. आर. के सहयोग से 25 बीज हब स्थापित। देश भर में मिलेट के उन्नत किस्मों के उन्नत बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन - 2025-26 के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट के साथ शुरू किया जावेगा। इस मिशन से देश दालों के उत्पादन में आत्म निर्भर होगा।

कपास उत्पादकता मिशन - 2025-26 के लिए 500 करोड़ आबंटित किये गये हैं।

मखाना बोर्ड का गठन - 2025-26 में 100 करोड़ आबंटन। यह बोर्ड मखाना किसानों के लिए वरदान साबित होगा।

मत्स्य पालन - माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत मत्स्य पालन नील क्रांति के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): The ongoing farmers' protests have been fueled by a series of unfulfilled promises from the Government. Key demands include a legal guarantee for the Minimum Support Price (MSP) for crops, a debt waiver for farmers, and pensions for both farmers and farm laborers. Additionally, farmers are calling for no hikes in electricity tariffs, the withdrawal of police cases filed against them during protests, and justice for the victims of the 2021 Lakhimpur

Kheri violence. They seek the reinstatement of the Land Acquisition Act of 2013 and compensation for the families of farmers who lost their lives during the protests of 2020-21. As the agitation continues, another meeting is scheduled for May 4th. However, there is a prevailing sentiment that meetings alone may not lead to meaningful change, as the saying goes, 'If you don't want to do a thing, then form a committee.' It is crucial that these discussions do not end without addressing the farmers' legitimate concerns.

The MSP Policy Implementation is currently at a pivotal stage, raising the question of why a comprehensive white paper or status report on its progress has not been produced. A critical analysis of past experiences in implementation reveals several key points. Notably, the budget announcements for 2024 included six major initiatives, yet the outcomes of these announcements remain unclear. There is a pressing need to focus on technological integration, sustainable practices, and financial support to enhance agricultural productivity and improve farmers' welfare. Additionally, the necessity for an Action Taken Report (ATR) is evident to ensure accountability and track the effectiveness of these initiatives.

Now, I would like to touch upon certain issues pertaining to my State of Kerala. The issues concerning Kerala's coconut industry highlight the need for urgent attention and action. Historically, the procurement of raw coconut was a common practice, but this has ceased, necessitating its restoration to support local farmers. Additionally, the current coconut prices present an opportunity that must be made sustainable to ensure long-term viability. It is crucial to approach productivity with seriousness, as this will directly impact the economic stability of the sector. Furthermore, the PM-KISAN scheme, which offers a financial benefit of

Rs.6,000, should be significantly enhanced to provide better support for coconut farmers and stimulate growth in the industry.

My State of Kerala has been going through certain bitter experiences. In Kerala, the issue of human-wildlife conflict has become increasingly severe, with 460 fatalities reported over the past five years, as highlighted in data presented to the Rajya Sabha. This alarming statistic places Kerala among the worst-affected States in India regarding wildlife-related deaths. The conflicts primarily involve elephants, wild boars, leopards, and other wildlife, significantly impacting farmers and rural communities. These groups face not only crop damage but also threats to their lives, underscoring the urgent need for effective solutions to mitigate these conflicts.

In Kerala, the agricultural landscape is undergoing significant changes, particularly with the decline of traditional crops. While paddy remains a staple, other important crops such as cashews, pepper, rubber, pulses, ginger, and turmeric are experiencing reduced production levels. This shift is further compounded by some farmers moving away from cultivating traditional crops like millets, which play a crucial role in ensuring food security and promoting nutritional diversity. The transition away from these vital crops raises concerns about the future of agriculture in the region and its impact on food security and nutritional diversity.

Organic farming is increasingly recognized for its significance and relevance in today's agricultural landscape. However, this sector encounters several challenges that hinder its growth. Key issues include limited market access, which restricts farmers from reaching potential customers, high certification costs that can be prohibitive for many, and a general lack of awareness among both farmers and consumers about the

benefits and practices of organic farming. Addressing these challenges is crucial for the advancement of organic agriculture.

The transition to agro machineries presents several implementation hurdles that need to be addressed for successful adoption. One of the primary challenges is the high cost associated with acquiring these machines, which can be a significant barrier for many farmers. Additionally, the prevalence of small and scattered land holdings complicates the situation, as these machines are often more suitable for larger, consolidated areas. To overcome these challenges, it is essential to provide comprehensive training for farmers on the effective use of agro machineries, ensuring they can maximize their benefits. Furthermore, the lack of repair and servicing facilities poses a risk to the sustainability of these machines, as does the availability of spare parts. Addressing these issues will be crucial in facilitating the successful integration of agro machineries into farming practices.

The issues related to chemicals and fertilizers are critical and multifaceted, impacting various aspects of the environment and agriculture. Soil degradation is a significant concern, as it diminishes the land's productivity and health. Additionally, water pollution arises from the runoff of fertilizers, leading to contamination of water bodies and affecting aquatic life.

Air pollution is another consequence, often resulting from the release of volatile compounds during fertilizer application. Furthermore, the loss of biodiversity is alarming, as chemical use can disrupt ecosystems and threaten various species. Reduced soil fertility and crop quality are direct outcomes of excessive chemical use, which can lead to diminished agricultural yields. Moreover, the development of resistance in pests and diseases poses a challenge to sustainable farming practices.

Lastly, both water and food contamination are pressing issues that arise from the improper use of chemicals, ultimately affecting human health and safety. Addressing these interconnected issues is essential for promoting a sustainable agricultural future.

To build a coexistence policy that enhances employability in rural areas, it is essential to address several key challenges. These include low awareness and access to skill programs, the lack of modern curriculum in agricultural institutes, inadequate infrastructure, and limited credit availability for agri-entrepreneurs.

As agriculture in India transitions from subsistence to enterprise mode, there is significant potential for employment growth if we scale up skills, technology, and support systems. By enhancing employability, we can mitigate rural migration, increase incomes, and modernize Indian agriculture.

Shri M.S. Swaminathan aptly stated,

'If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right in the country.'

This sentiment echoes the vision of Lal Bahadur Shastri's '*Jai Jawan, Jai Kisan*,' emphasizing the importance of both farmers and soldiers in nation-building.

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : मैं वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । कृषि संबंधी अनुदान की मांगों पर चल रही चर्चा में अपनी बात रखने का आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका जबलपुर की देवतुल्य जनता की ओर से अभिनंदन करता हूँ ।

भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ ग्रामीण संस्कृति से समृद्ध देश भी है । खेती-किसानी और गाँव हमारे देश की आत्मा है । मेरा यह सौभाग्य है कि जबलपुर जैसे कृषि सम्पन्न क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं सदन में कर रहा हूँ । मैं इसलिए भी

अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मुझे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कुशल, निर्णायक और निर्भीक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा है। गत 2014 से अभी तक हुए कृषि क्षेत्र में हो रहे कायाकल्प से यह स्पष्ट हो गया है कि देश की कृषि और किसान हमारा स्वाभिमान है, हमारे स्वावलंबन का आधार भी है।

वर्ष 2013-14 में UPA शासन काल में कृषि मंत्रालय का वार्षिक बजट आवंटन जहां 27,663 करोड़ रुपए मात्र था, वहीं मोदी जी की सरकार ने इसे 5 गुना बढ़ाकर 1,37,756 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके लिए मोदी जी आज देश का हर किसान, हर गाँव आपका हृदय से अभिनंदन कर रहा है।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट में देश की कृषि को समृद्ध बनाने के लिए कृषि बजट बढ़ाने के साथ-साथ किसान और कृषि हितों का विशेष ध्यान रखा गया है, अनेकों लोक-कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को धरातल तक उतारने का कार्य मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

पीएम धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से कम उत्पादन वाले 100 जिलों को चिह्नित करके उनमें कैसे उत्पादन बढ़े, किसान कैसे खुशहाल हो, इस पर काम हो रहा है। पीएम किसान योजना के माध्यम से देश के 11 करोड़ जरूरतमन्द किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सरकार द्वारा 12,242 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता को व्यक्त करता है, जिसका लाभ चार करोड़ किसानों को मिल रहा है। 2013-14 में यूपीए सरकार के समय देश का कृषि निर्यात जहां 37.2 बिलियन USD था, वहीं आज यह 31% बढ़कर 48.77 बिलियन USD हो गया है। वर्ष 2013-14 में UPA सरकार के समय जब धान की MSP 1,310 रुपए प्रति क्विंटल थी वहीं आज 2,300 रुपए प्रति क्विंटल MSP किसानों को मिल रही है।

यूरिया उत्पादन में, दलहन के क्षेत्र में देश आज पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देश के 7.7 करोड़ किसान भाइयों को अल्पावधि ऋण की सुविधा निर्बाध रूप से मिल रही है। ब्याज छूट योजना के तहत अब ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का माननीय मोदी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। मखाना उत्पादन में अग्रणी राज्य बिहार में मखाना बोर्ड बनाकर सरकार द्वारा किसान कल्याण के क्षेत्र में नया आयाम गढ़ दिया गया है। विश्व

स्तरीय लॉजिस्टिक्स सेवा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने से देश के किसान भाई-बहन बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे ।

मैं पुनः बधाई देना चाहूँगा कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेत्रत्व में भारत सरकार द्वारा जो लोकहित के प्रावधान किए गए हैं, उनमें सर्वप्रथम है ?

आर्थिक मदद ? किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है ।

कम उत्पादकता वाले जिलों पर ध्यान ? बजट में देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है ।

कृषि क्षेत्र में निवेश ? बजट में कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और पहलों का भी प्रावधान किया गया है ।

पीएम धन धान्य कृषि योजना ? बजट में किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है ।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती ? राजस्थान जैसे प्रांत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो गौ-उत्पादों पर आधारित है ।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लचीलापन ? बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लचीलेपन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई है ।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए, सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में माननीया वित्त मंत्री जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वर्ण सहायता समूहों (SHG) को ड्रोन प्रदान करने के लिये 500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है ।

इसके साथ ही एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु समर्थन दिया । मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिवादन करता हूँ ।

दूसरा क्रांतिकारी कदम सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता नीति के माध्यम से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने का सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें सरकार ने

सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और सुव्यवस्थित सर्वांगीण विकास के लिये राष्ट्रीय सहयोग नीति की घोषणा की, जिससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति मिलेगी साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन होगा ।

इसलिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संबंधी अनुदान की मांगों में मांग संख्या-2 में उल्लिखित कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में बजट की और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है ।

जबलपुर में कृषि क्षेत्र को विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं । खासकर, मटर, धान, गेहूं और चने की खेती के लिए । यहाँ हम जबलपुर में जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे किसान चिया सीड्स की खेती करके आज अच्छा लाभ कमा रहे हैं ।

मटर की खेती ? जबलपुर में मटर की खेती काफी लोकप्रिय है और यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर मटर का उत्पादन करते हैं ।

सरकार के प्रयासों से जबलपुर जिले में बड़ी मात्रा में मटर का उत्पादन होता है । अतः जबलपुर में भारत सरकार द्वारा सफल का प्रोसेसिंग और प्रिक्वोरमेंट प्लांट लगाना चाहिए ।

धान की खेती ? जबलपुर में धान की खेती भी महत्वपूर्ण है और यहाँ सुगंधित धान की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

गेहूं और चना ? गेहूं और चना जबलपुर में प्रमुख फसलें होने के साथ-साथ मक्का, बाजरा आदि की भरपूर पैदावार होती है ।

जैविक खेती ? जबलपुर में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान अब जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं । हमारे यहाँ चिया सीड्स की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है साथ जबलपुर संभाग में ब्रीडर बीज की भी बहुतायत में उपलब्धता है ।

डेयरी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं ? जबलपुर संभाग में दुग्ध उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है । यहाँ के किसान और समग्र ग्रामीण पशुपालन को अपनी अतिरिक्त आय के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं, और यह भी माननीय मोदी जी की ही प्रेरणा का परिणाम ही है ।

अतः मेरा सरकार से निवेदन होगा कि जबलपुर में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वहाँ के किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, यहाँ डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाए ।

इसलिए, मेरा सरकार से निवेदन होगा, सरकार जबलपुर में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं जैसे कि चावल मिल, दाल मिल, आटा मिल, तेल मिल, बेकरी उद्योग, अचार उद्योग ।

सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव में अनुदान की मांगों पर चल रही महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात रखने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से देश की कृषि और किसान खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे ।

मैं पुनः वित्त विधेयक (बजट-2025-26) का समर्थन करता हूँ । उसमें निहित अनुदान की मांगों में जबलपुर की मांगों को सम्मिलित करने की कृपा करें ।

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि आज भी प्रमुख भूमिका में है । देश की आधी से अधिक आबादी कृषि और इसी से जुड़े उद्योग धंधों या गतिविधियों में लगी हुई है । उनकी जीविका का आधार कृषि ही है । देश में लगभग 6.50 लाख गांव हैं, जिसमें देश की कुल आबादी की 63% जनसंख्या निवास करती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि देश की तरक्की और गांव का विकास कृषि के बिना अधूरा है ।

मैं यहां भारत रत्न किसान मसीहा देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का कथन दोहराना चाहूंगा कि- देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है यह कथन आज भी सौ फ़ीसदी सच और प्रासंगिक है ।

आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गांव के विकास के लिए, कृषि, किसानों, मजदूरों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है । इन सभी के विकास के लिए प्रभावशाली योजनाएं बना रही है और उन योजनाओं को पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित कर रही है ।

हमारी सरकार ने 2025-26 के बजट में कृषि क्षेत्र में किसानों, मजदूरों और गांवों के विकास के लिए वर्तमान की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के अनुरूप पुरानी योजनाओं का विस्तार किया है तथा नई और सार्थक योजनाएं/नीतियां बनाई जा रही हैं।

इस बजट में कृषि क्षेत्र को जो आवंटन किया गया है, उससे फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि एवं विस्तार होगा। कृषि में डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कृषि ऋण के लिए मोबाइल एप तथा ऑनलाइन बैंकिंग का प्रावधान किया गया है जो कि वर्तमान की महती आवश्यकता है। इस बजट के माध्यम से ग्रामीण सहकारी बैंक और लघु वित्त बैंक को कृषि ऋण देने के लिए भागीदारी बढ़ाई जाएगी। छोटे एवं सीमांत किसानों तथा मजदूरों तक कृषि ऋण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। एग्रीकल्चर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसके माध्यम से (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के युग में किसानों को स्मार्ट फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारी सरकार के द्वारा कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग तक छोटे किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इस कदम से कृषि क्षेत्र नई क्रांति की ओर अग्रसर होगा। इस बजट के अंतर्गत संचालित योजनाओं से कृषि क्षेत्र में आ रही नई चुनौतियों का सामना करने हेतु किसानों को सक्षम बनाया जा रहा है।

ग्लोबल वार्मिंग आधुनिक समय की एक ऐसी गंभीर चुनौती है जिसका कृषि क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण वर्षा की निरंतरता में कमी भूजल स्तर में नित गिरावट आ रही है, जिससे कृषि क्षेत्र में सिंचाई की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। इस गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि सिंचाई योजना में 8260 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसके तहत महत्वाकांक्षी योजना हर खेत को पानी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम 50 से 70% की सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि सूखे इलाकों में भी खेती करना संभव हो सकेगा।

जैसा कि अवगत है कि मेरा संसदीय क्षेत्र बागपत निरंतर गिरते भूजल की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा मेरा संसदीय क्षेत्र गिरते भूजल स्तर की चुनौती का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा।

अतः इस संबंध में मेरी विनम्र मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बागपत में माइक्रो इरिगेशन फंड के द्वारा किसानों में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए ।

कुल मिलाकर 2025-26 का बजट कृषि क्षेत्र के विकास द्वारा ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगा । इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदुषी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति धन्यवाद व्यापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं ।

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे (शोलापुर) : लालबहादुर शास्त्रीजी ने 1965 में अपनी सेना और अपने देश के किसानों को प्रेरित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था । आज इस अमर नारे को, और देश के किसानों की मौजूदा हालात को. याद करते हुए मन पीड़ा से भर आता है. सारी अवाम का पेट भरने वाला किसान, आज देश कि अवाम और उसकी चुनी गई सरकार से गुहार लगा रहा है ।

सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान आंदोलन में करीब 700 किसानों की जान गई है । इसके बावजूद भी इस सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है । इन बलिदानों का हिसाब इस सरकार को आज नहीं तो कल जरूर देना पड़ेगा । पुंजीवादियों के खिलाफ किसानों की ये जंग आज भी जारी है ।

जीएसटी की मार, मेहेंगाई की मार, सही समय पर बीमा और कर्ज का भुगतान न मिलने, और उचित एमएसपी न मिलने के कारण, देश के किसानों की हालत खस्ता हो रही है । गांव का युवा किसान बेरोजगार हो रहा है । ऐसे ही चलता रहा तो इस कृषि प्रधान देश में किसान नामक परजाति विलुप्त हो जाएगी,

भारत को कृषि प्रधान देश बनाये रखने हेतू, और सर्वांगीण प्रगति हेतू किसानों को मजबूत बनाना अनिवार्य है ।

? Agricultural problem

Our country India is known as an agrarian country. But, in real sense the agricultural problems are still not solved.

Sugarcane:

Solapur district is known for its sugar factories. But, the farmer is not allowed to know how the recovery of sugarcane is done by the factory. As a result, showing less recovery, the farmer is getting less rate of sugarcane. At present some factories in Solapur district are charging Rs.3500 per ton as a declared rate. While some factories Rs.2700/- Per ton which is a low rate. There is a huge gap between Rs. 3500/ and Rs. 2700/- The rate per ton has such a variation in rate. Why is this? A single rate is expected from all the factories in the district when the recovery is similar. Weighing in sugarcane factory needs to be done online originally. Because, weight fraud has become a common practice. So, the government should make the weighing scale digital and fix the policy that the sugarcane recovery should be informed to the farmers too.

Even when the factories are making profit by doing various ancillary businesses such as power generation, ethanol, baggasse and molasses sales from the sugarcane factories, the farmers are given lower rates by showing the government that the factories are making losses.

Demand

Payment of sugarcane to the farmer should be made mandatory within 15 days once the sugarcane reaches the factory. This arrangement should be made to pay the amount to the farmers within 15 days after selling the goods.

Milk:

India's population is over 135 crores, but milk production is very less in comparison. But, due to adulterated milk availability in market, milk is not getting remunerative price. So, the government should impose strict restrictions on adulterated milk and stop the adulterated

milk in the market. And fair price should be given to the milk farmers. In the current market, cow's milk should be getting at least Rs. 40-45 and for buffalo milk, it should be Rs 70 to 75. per litre.

A policy should be made to provide Guaranteed prices for agricultural produces. Subsidy of milk is not provide on time. So, the rates should be increased. When the farmers bring the produces then the prices of the goods in the market decreases when the sugarcane gets ready to yield, sugar prices decrease in November, December and January. Also, when the agricultural produces such as jowar, wheat, rice etc get ready to harvest.

The prices drops in March and April. As a result, farmers do not get fair price for their goods. Traders buy and store the same goods. When farmers run out of produce, they sell their produce in the market at a higher price. So, this government should give guaranteed price for agricultural produces.

Fertilizers, pesticides, equipments and tools, irrigation material, drips, sprinklers, vehicles, (tractors and other similar vehicles) modern machinery, electric motors are inherently expensive due to government's GST. The policy has broken the back of the farmers. If farmers are to be truly emancipated, taxes like GST should be completely waived and all agricultural facilities should be provided to farmers at tax-free and subsidized rates without imposing any other taxes.

At present, the farmer through P.M. Kisan Yojana gets Rs. 2000 every four months from the central government. Also, Maharashtra government gives Rs. 2000 every four months under Nammo Samman Yojana. This amount is very less, even two sacks of fertilizers can be

bought. So, the central government should give additional Rs. 2000 per month and the state government should give Rs. 2000 per month.

The present government bans export of agricultural produce when the market price is good. And imports the same goods from abroad. (Eg, Onion, pulses, Sugar) Instead of doing this, the government should plan the import-export policy in order to get a remunerative price for the agricultural goods, considering the farmer and the farmer will get the right price for his goods. Also, an export policy should be fixed decided at a discounted rate so that the farmer can get direct prices for the goods without having to arrange an agent to send his goods from his farm to the international market.

Government announces many subsidy schemes for educated unemployed youth and farmers, but banks do not provide loans to farmers and unemployed youths and violate rules made by government. As a result, the schemes of government do not reach to the poor farmers and the unemployed youth. So, the government should intervene and make it mandatory for the banks to give loans to the farmers and the unemployed youth. Also, CIBIL condition should be condoned while giving loans to farmers.

Banks charge interest at the rate of 8% for home loans and 12% for agriculture ancillary businesses. Micro, Small, and Medium Schemes of the Central Government as well as NLM are run by Central Government. For that, bank regulations become problematic. Will the central government interfere in this? Also, the limit of 3 lakh for crop loan has been increased to 5 lakh. But, it is not being implemented. Farmers are not even getting the loan concession. What decision will the government take for it?

So, all the above problems should be considered sympathetically and action should be taken in this regard. Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana In Solapur district onion, millet, pigeon pea, maize, groundnut Bananas, pomegranates and grapes are considered as a crops and major fruits. After storm, wind, unseasonal rain, heavy rain, they are forced to give advance notice of loss within 72 hours, but after reporting the representatives of the insurance company do not come for inspection even after a month. So, the farmers face difficulty in cultivation of the next crop. Up to Rs 5000 is extorted and money is demanded from the farmer as the compensation for Kharif season 2024 to be paid by the end of February 2025. For Kharif season 2024 crops like millets. Tur, Maize, Onion, Groundnut are included. Even though the insurance expected to be paid by the end of February 2025, the farmers have not received the insurance by the end of March. Kharif season 2025 is starting in just two months, the farmer does not have money for cultivation and seeds. Therefore, it is necessary to accumulate crop insurance as soon as possible. Also, due to unseasonal rains in the month of May 2024, mango and pomegranate crops have been damaged, but compensation has not been received for this loss.

70 thousand metric tons of pomegranates are exported from Maharashtra every year. Out of this, 30 thousand metric tons of pomegranates used to be exported from Solapur alone. Recognizing this potential, the Central Government announced a Pomegranate Cluster worth 247.67 crores for Solapur in August 2023. Farmers were to be provided assistance under this scheme. But, the process of this scheme has been delayed at the government level for a year.

The Union Ministry of Agriculture has fixed the overall horticulture cluster for the country in 2021. 12 more were selected under the Group Development Scheme. Solapur was selected for pomegranate

production from Maharashtra. A program of about 4 years was fixed by the National Horticulture Board to develop the pomegranate cluster. From this project, the pomegranate orchards of 30,000 farmers on 20,000 hectares would get assistance. Now, with the withdrawal of the company appointed for it, the challenges faced by the farmers will continue to increase.

Due to natural calamities, the recognition of Solapur pomegranate in the global market due to geographical indication is on the verge of being wiped out. In the last 10 years, 12 thousand hectares of pomegranate orchards in the district have been destroyed. The Pomegranate Cluster Scheme is in shambles due to the neglect of the Central and State Governments. The company appointed by the government by paying Rs 247.67 crore for pomegranate cluster, has pulled out citing cost implications. New tenders have been floated for the selection of new company. But, the process is slow.

Wanted Export Center for Onion In Solapur district, onion is grown on 55 thousand hectares during kharif, late kharif and rabi seasons. Moreover, Solapur is a city situated on the border of Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka states. The Solapur Agricultural Produce Marketing Committee here receives an average of 50,000 quintals of onions from 500 trucks every day. It has a turnover of around 2 thousand crores every year. Even Lasalgaon, known as the largest onion market in Asia, has been overtaken by the Solapur Bazar Committee. Onions are imported from 3 states to Solapur Agricultural Produce Marketing Committee. But, there are no facilities for onion export in Solapur district. Onion from here is sold in the states of Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh. If an export center is set up in Solapur, the farmers here can benefit from it. Therefore, it is necessary for the central government to make an effort for it.

The Grape growing farmers, due to demonetization and covid-19 Currently, removing vineyards due to lack of remunerative market price around 5 lakhs per acre is spent on setting up a vineyard. But a crop loan of one lakh per acre has been given by the bank. If the government waives the crop loan of Rs 1 lakh, the grape farmer will get a relief.

Under the National Agricultural Development Scheme, Per Drop More Crop Drip scheme. subsidy of Rs. 16.5 crore Solapur district is pending with the central government and approximately 400 crores of subsidy of farmers of Maharashtra is still pending. The central government should make it available immediately.

Inclusion of sunflower and sorghum crops under kharif crop insurance (sorghum crop insurance Grop and Fruit insurance, Solapur) - In Mangalvedha Tehsil, sunflower is cultivated in maximum area during kharif season. Also, sorghum crop is also cultivated on a large scale for animal fodder, but no compensation is given to them if these crops are damaged due to the vagaries of nature. Also, as no crop protection has been provided for it, a large number of farmers are facing problems. Therefore, sunflower and jowar crops should be included under Kharif crop insurance and also included in the government's Rs 1 crop insurance scheme.

Mohol Tehsil has been excluded from drought fund. But, Narkhed mandal in Mohol tehsil of Solapur district is getting funds by declaring wet drought. But, the village of Khuneshwar in Sawleshwar mandal, had heavy rains. The farmers of this village have suffered huge losses. But, due to non-declaration of wet drought in Savleshwar Mandal, Khuneshwar village is not getting funds.*

देश के और मेरे राज्य के किसानों के कुछ मुद्दे आपके समक्ष रखना चाहती हूं. ऐसी इस सरकार का क्या कहना. आज देश की 70 फिसदी किसान पीड़ित है ।

पंडित नेहरुजी, इंदिराजी, लालबहादूर शास्त्रीजी, इतना ही नहीं जिनको ये सरकार अपना आदर्श मानती है वे अटल बिहारी बाजपेयी जी, ने भी किसानों के हित में अच्छे-अच्छे निर्णय लिए थे. पर अफसोस! आज कि ये सरकार पूंजीवाद के पिछे दौड रही है । आज सरकार क्या कर रही है?

पिछले 10 से ज्यादा सालों में मेरे महाराष्ट्र में 30 हजार से उपर किसानों ने आत्महत्या कि है. क्या सरकार को किसानों की आत्महत्याए नही दिख रही? क्या उनके परिजनों का शोकमग्न स्वर सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रहा? केंद्र में और महाराष्ट्र में भाजप की सरकार है. पिछले १० साल से किसानों की हालत बद से बत्तर होती जा रही है । महाराष्ट्र मे परिस्थिती इतनी चिंताजनक हे की महाराष्ट्र के कृषी मंत्री आरोपों के घेरे में है । अन्न और नागरी पुरवठा मंत्री को एक हत्या के मामले में इस्तिफा देना पड़ा । दूसरे अनेक मंत्रियों पर गंभीर किस्म के आरोप है । आए दिन सरकार में बैठे मंत्री हि मजहबी दंगे भड़काने का काम कर रहे है । भारत के सबसे प्रगतिशील राज्य, मेरे महाराष्ट्र को, इस सरकार ने, दीवालिया बनने कि कगार पे, ला कर खड़ा कर हे. मानो सरकार जनता के प्रति अपना दायित्व भूल चुकी है ।

अंत में कुछ पंक्तियों के साथ में अपने विचारों को समाप्त करती हूं :

?जो मिट्टी से उगले सोना, वो किसान आज बेहाल है ।

सरकार कुंभकर्ण कि नींद सो रही है, सब चंगा खुशहाल है ।

साहूकारो कि चाटूकारी मे लीन,

करती ऊनको वंदन है ।

खोखले वादों और जुमलों से, जनता को लगाती चंदन है ।

ये संस्कारि सरकार, धन और सत्ता के नशे में चूर है ।

वहीं भूमिपुत्र अन्नदाता, बुनियादी सुख साधनो से भी दूर है ।

मत छोड हौसला ऐ हलधर !

तेरा ऋणी हर भारतवासी जागेगा,

झूठ और नफ़रत की बुनियाद पर,

इनके अच्छे दिन आए है,

सत्य और प्यार के दम पर,

हमारा अब जमाना आएगा ।?

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : माननीय फ़ाइनेंस मिनिस्टर ने अपने सारगर्भित बजट उद्घोषण से हमारे राष्ट्र के दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को ही नहीं रेखांकित किया है बल्कि सभी नागरिकों के भीतर नयी आशा और संकल्प को जागृत किया है । मोदी जी के नेतृत्व में स्थिरता, प्रगति और विकास के नये आयाम के स्थापित होने की निरंतरता में विश्वास व्यक्त किया है । मोदीजी के नेतृत्व वाली सरकार का जनकल्याणीकारी बजट सभी क्षेत्रों में विकास इंजन को प्राथमिकता देने वाला अभूतपूर्व समावेशी बजट है । "यह समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है । गाँव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है । यह नयी ऊर्जा लेकर आया है ।"

यह बजट हमारे देश के अन्नदाताओं-हमारे किसानों के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो उनकी मेहनत को सम्मान देने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भरता, उत्पादकता और समृद्धि की ओर ले जाता है । मैं इसके प्रमुख पहलुओं को तथ्यों, आंकड़ों और पूर्व की कांग्रेस सरकार की नीतियों से तुलना के साथ आपके सामने रखूंगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हमारी सरकार किसानों के लिए कितनी गंभीर और दूरदर्शी है । पिछले 10 वर्षों में सरकार ने इस संदर्भ में क्रांतिकारी कार्य किए हैं । सरकार मानती है किसान अन्नदाता है, जीवनदाता है । यह विश्वास भी करती है कि किसान विकसित समाज का सर्वप्रथम अग्रसर रहा है । ऐसा माना जाता है कि "किसान के हल से खींची गई रेखा सभ्यता के पूर्व के समाज और विकसित समाज के बीच की रेखा है ।" गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था "God is where tiller is tilling the hard ground" सरकार की विभिन्न योजनाएँ इन्हीं मूल्यों और दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं । Therefore finance minister has rightly emphasized Agriculture as first Growth Engine.

सबसे पहले, बजट 2025 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । यह राशि बजट 2024-25 के 1.41 लाख करोड़ रुपये

से 10% अधिक है और पिछले पांच वर्षों में कृषि बजट में लगातार वृद्धि को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, 2019-20 में यह आंकड़ा 1.38 लाख करोड़ रुपये था, जो अब तक 12% से अधिक बढ़ चुका है। यह राशि सिर्फ एक संख्या नहीं है- यह उस माँ की राहत है, जो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकेगी; उस बूढ़े किसान की सांस है, जो अब कर्ज के बोझ से मुक्त होकर चैन की नींद सो सकेगा। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो कांग्रेस की यूपीए सरकार का 2013-14 का बजट याद आता है- महज 27,049 करोड़ रुपये। उस समय महंगाई 9.5% थी, और यह राशि हमारे किसानों की मेहनत को थप्पड़ मारने जैसी थी। क्या उस दौर में किसी ने उनके आंसुओं को देखा? नहीं, उन्हें सिर्फ सब्सिडी के झुनझुने थमाए गए, और उनकी तकदीर को अंधेरे में छोड़ दिया गया। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को केवल सब्सिडी का लालच दिया, लेकिन उनकी दीर्घकालिक समृद्धि के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में कृषि की भूमिका को ध्यान में रख कर बजट ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए धनराशि में रेकॉर्ड वृद्धि की है। और यह हमारी पार्टी के मूल्यों एवं दर्शन को दर्शाती है जैसा की रुरल इकॉनमी पर Swami Vivekananda का दर्शन था। "समग्र रूप से ग्रामीण विकास के लिए परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे ग्रामीण भारत में जीवन के गुणात्मक पहलुओं में निरंतर सुधार हों। इसलिए इससे आत्मनिर्भरता में वृद्धि और जीवन के उच्च मूल्यों की प्राप्ति होनी चाहिए"

बजट 2025 में 109 नई उच्च-उपज और जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को जारी करने की घोषणा की गई है, जो 32 विभिन्न क्षेत्र और बागवानी फसलों को कवर करती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसार, ये किस्में सूखा, बाढ़ और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं, जिससे किसानों की फसल जोखिम 20-25% तक कम होगी। इसके साथ ही, 1 करोड़ किसानों को अगले दो वर्षों में प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित होंगे। यह योजना न केवल पर्यावरण को संरक्षित करेगी, बल्कि रासायनिक उर्वरकों पर खर्च को 30-40% तक कम करेगी। कांग्रेस सरकार के समय ऐसी कोई पहल नहीं थी। 2004-14 के दौरान उर्वरक सब्सिडी में भारी वृद्धि हुई-2008-09 में यह 99,494 करोड़ रुपये तक पहुंच गई लेकिन इसका अधिकांश लाभ बड़े किसानों और उर्वरक कंपनियों को मिला, छोटे किसानों को नहीं। प्राकृतिक खेती या जलवायु अनुकूल नीतियों पर कोई

ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता घटती गई और आज भी कई क्षेत्रों में इसका असर दिखता है । इसके अलावा अनय उल्लेखनीय योजनाएँ हैं -

* प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना- कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम

राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाने वाला यह कार्यक्रम, कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा ।

* ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन का निर्माण

कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के माध्यम से कृषि में कम रोजगार को संबोधित करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ।

* चरण-1 में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा ।

* दलहनों में आत्मनिर्भरता

सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 वर्षीय "दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन" शुरू करेगी । नैफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से इन दालों की खरीद करेंगे । सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ।

मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी ।

अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, उच्च उपज वाले बीजों के लक्षित विकास और प्रसार और 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता को लक्षित करने के उद्देश्य से उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा ।

सरकार अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक रूपरेखा लाएगी ।

कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार की सुविधा प्रदान करने और अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई ।

संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी ।

असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा ।

इस बजट में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है, जिसके तहत 3 वर्षों में 6 करोड़ किसानों और उनकी 25 करोड़ एकड़ जमीन को डिजिटल रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा । इसके साथ ही, 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू होगा । यह कदम न केवल भूमि विवादों को कम करेगा, बल्कि किसानों को कर्ज, बीमा और बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करेगा । इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM), जो हमारी सरकार की देन है, आज 1.8 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार से जोड़ रही है । कांग्रेस सरकार के समय तकनीकी नवाचार की कमी थी । 2013 तक केवल 21 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा गया था, और e-NAM जैसी कोई योजना शुरू नहीं हुई । उनकी नीतियां मैनुअल और मध्यस्थ-केंद्रित थीं, जिसके कारण 2008-09 में मंडी व्यापार में किसानों को उनकी उपज का केवल 60-70% मूल्य मिलता था, बाकी बिचौलियों की जेब में जाता था । आज हमारी सरकार ने इस अंतर को पाट दिया है । आज हमारा बजट उस किसान को कहता है-अब तुम्हारी मेहनत का हर दाना तुम्हारा है ।

दालों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए बजट 2025 में उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करने का प्रावधान है । भारत, जो 2022-23 में 26 मिलियन टन दालों का उत्पादन करता था, अब 30 मिलियन टन तक पहुंचने की ओर अग्रसर है । तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की विशेष योजना शुरू की

गई है। इसके अलावा, झींगा मछली पालन के लिए NABARD के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में 2 लाख रोजगार सृजित होंगे। कांग्रेस सरकार के समय भारत खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर था। 2013-14 में 10.3 मिलियन टन खाद्य तेल आयात किया गया, जिसकी कीमत 60,000 करोड़ रुपये से अधिक थी। आत्मनिर्भरता की कोई योजना नहीं थी, और किसानों को न तो प्रोत्साहन मिला और न ही बाजार समर्थन। इसके विपरीत, हमारी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लागत का 1.5 गुना करने का वादा पूरा किया है-2024-25 में धान का MSP 2,183 रुपये प्रति क्विंटल है, जो 2013-14 के 1,310 रुपये से 66% अधिक है।

पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सीधी सहायता दी जा रही है, जिसका कुल खर्च अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। पीएम फसल बीमा योजना ने 4 करोड़ किसानों को जोड़ा है, और 2023 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है। यह कांग्रेस की 2008-09 की 70,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी से कहीं अधिक प्रभावी है, जो केवल 5.2 करोड़ किसानों तक पहुंची और उसका लाभ मुख्य रूप से बैंकों को मिला। हमारी योजना हर किसान तक पहुंचती है और उनकी जेब में सीधा पैसा डालती है।

"कृषि ही भारत की आत्मा है, और किसान उस आत्मा का संरक्षक।" यह बजट इस कथन को साकार करता है। हमारी सरकार ने किसानों को केवल आर्थिक सहायता नहीं दी, बल्कि उन्हें सम्मान, तकनीक और भविष्य की दिशा दी है। कांग्रेस की नीतियां अल्पकालिक राहत तक सीमित थीं- उनका ध्यान वोट बैंक पर था, न कि किसानों की आत्मनिर्भरता पर। हमारा लक्ष्य "सबका साथ, सबका विकास" है, और यह बजट उस संकल्प का प्रमाण है।

बजट 2025 किसानों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। यह उत्पादकता बढ़ाने, लागत घटाने, आय दोगुनी करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। मैं आग्रह करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से समर्थन दें, ताकि हम अपने अन्नदाताओं के लिए एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। "If

agriculture goes wrong, nothing else will have chance to go right" - M.S Swaminathan

अंतिम पंक्ति तक हर व्यक्ति को लाभ मिले, ऐसा सुनिश्चित किया है ।

'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ? सबका विश्वास ।

बीमारू प्रदेश मध्य प्रदेश को श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विकसित प्रदेश बनाया । विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे, माननीय डॉ. मोहन जी यादव । भारत को विकसित भारत और विश्व गुरु बनाएंगे माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ।

जय जवान, जय किसान । वंदे मातरम्, जय बलराम ।

भारत माता की जय, धरती माता की जय ।

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : महोदय, ट्रम्प के सता में आने के बाद, अमेरिका भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगा रहा है और भारत को सस्ते दामों पर अमेरिकी उत्पादों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है । मेक्सिको, कनाडा और अन्य देश इस टैरिफ नीति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बेशर्मी से अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे झुक रहे हैं । बीजेपी और मोदी सरकार क्या चाहती है? भारतीय किसान अपनी ज़मीन कॉरपोरेट्स को बेच दें और सब्सिडी वाले अमेरिकी उत्पाद खाएं? क्या यही आपका "मेक इन इंडिया" है? अमेरिकी कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर भारतीय कृषि और किसानों को बर्बाद करके मोदी ने साबित कर दिया कि वे पूरी तरह उनके साथ हैं ।

इस साल के बजट को ही देख लीजिए । कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 2025-26 के बजट में 1,37,757 करोड़ रुपये मिले हैं, जो कुल केंद्रीय बजट का मात्र 2.7 प्रतिशत है । यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से 2.5 प्रतिशत कम है ।

पीएम-किसान और ब्याज सब्सिडी योजना को पिछले साल की तरह ही बजट आवंटन मिला है, लेकिन फसल बीमा योजना का बजट पिछले साल की तुलना में 23 प्रतिशत कम कर दिया गया है, जो 2018-19 के बाद सबसे कम है ।

पीएम-किसान योजना में बंटाईदार किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल नहीं किया गया है ।

इसी तरह, वर्षों से मनरेगा को कृषि से जोड़ने की मांग उठ रही है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मनरेगा के कार्य दिवसों को 200 तक बढ़ाने और न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने के साथ इसे कृषि क्षेत्र से जोड़ना किसानों और ग्रामीण गरीबों के लिए फायदेमंद होगा।

बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के दौर में सरकार किसानों की सुरक्षा कैसे करेगी, जब नाबार्ड का कहना है कि केवल 10 प्रतिशत कृषि परिवारों के पास फसल बीमा है और मात्र 2 प्रतिशत के पास पशुधन बीमा है? क्या सरकार सिर्फ अपने कॉर्पोरेट दोस्तों का बीमा कराने में रुचि रखती है और किसानों की कोई चिंता नहीं?

2020 किसान आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने की मांग पर बजट में कोई चर्चा नहीं हुई, न ही सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के बीच लंबित मांगों की कोई बात हुई। सरकार ने फिर से किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी की मांग को नजरअंदाज कर दिया। मोदी सरकार किसानों के साथ विश्वासघात जारी रखे हुए है।

पिछले दस वर्षों में बैंकों ने कॉर्पोरेट्स के 16.35 लाख करोड़ रुपये के डूबे हुए कर्ज (NPA) को माफ कर दिया है। भारतीय कृषि गंभीर कर्ज संकट से गुजर रही है, फिर भी सरकार के पास अडानी-अंबानी के लिए पैसा है लेकिन किसानों के लिए नहीं।

आर्थिक सर्वेक्षण (2024-25) के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति में सब्जियों और दालों का योगदान 32.3 प्रतिशत है, फिर भी सरकार ने इन फसलों के लिए एमएसपी का विस्तार नहीं किया। जब सरकार अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को न्यूनतम लाभ की गारंटी दे सकती है, तो सब्जियों, दालों और मिलेट्स के लिए एमएसपी क्यों नहीं?

National Statistical Office's (NSO) के 77 वे दौर के सर्वेक्षण (जनवरी-दिसंबर 2019) के अनुसार, एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। चार सदस्यों के परिवार के लिए 10,000 रुपये प्रति माह क्या काफी है? किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर, सरकार उन्हें एक सम्मानजनक आय और उचित लाभ देने में भी विफल रही है।

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Our land has been blessed by Panchbhoota that makes it so divine.

It has been blessed with 15 Agroclimatic Zones that makes our land so divine & unique. I stand to raise not as the representative of people but as a daughter of a farmer & as voice for millions of unsung heroes who toil in the sun day and night, expect the unexpected, yet unshattered, hopeful & do not let our Country sleep with empty stomach. I express my gratitude towards our honourable PM Shri Narendra Modi Ji & the Union Ministry for the unwavering commitment & proactive policies in the agrisector. Our honourable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji goal of making India a 5 trillion economy & our CM Chandrababu Naidu garu's vision of Swarnandhra Pradesh 2047 can be achieved by developing global competition not only in Industrial or Service Sector but Agriculture Sector too. Though our Farmers receive free irrigation, electricity, low interest CREDIT, Subsidised urea, cash and loan waivers. Farmers still remain orphaned & global competition is achieved only when the farmers has economic equity & social recognition on par with other sectors.

I Whole heartedly welcome the Union Budget with 1,37,575 Lakh Crores allotted to Agriculture Sector 2.7% of 1,27,290 Cr (92%) being allotted for agriculture and farmers welfare & 10,466 Cr for (8%) for research & education. I appreciate the Agriculture Ministry for utilising its 90% of the Fund allotted from 2015 ? 16. And in Andhra Pradesh our honourable CM Shri Nara Chandrababu Naidu Garu we have highest priority for farmers welfare. Today total budget 43,402 has been allotted.

Farmer in order to compete & globally here are few inputs. First we need to reduce the Cost of Production as it is a Serious problem & I request the FM to reduce the cost of Insecticides, Pesticides, tractors and also reduce the GST to 5% for 10 Years. MNREGA that has been instrumental in generative employment and financial assistance to the Rural Labourers. I request there be a restructured made in MNGREGA where in Agricultural Labourers can work for 5 months where 50% is

given by farmers, 50% by MNREGA which will help farmers get agricultural labourers & also prevent seasonal migration.

With the technology improving day by day & appreciate the initiative taken by CG by introducing Drones however there are few limitations in controlling the pests & disease & should be further improved. When remote sensing technology is used in all the sectors why not use in agricultural sector in detection a natural calamity & extent of crop loss & paid in 30 days, Embryo technology for Dairy farmers where there is 90% accuracy in Sex Selection of the cattle which would further develop dairy farmers. Artificial Intelligence results is 50% made capable which is no use to the dairy farmers . Another major issue is the low price realisation by the farmers for e.g. Tomato being 33.5%, onion 36%, mango 40%. For e.g. 21.5 millions tons of mango is produced annually pulp processing is about 10 lakh tons & fruit export is 1 lakh tons.

When production value addition in other countries is almost 70% why cant we reach it, production is huge but processing is negligible. I request to have a MOU for all the crops other than cereal for production, processing, storage & exports & start mango board which would benefit farmers of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka & Uttar Pradesh.

There are about 2,69,833 graduates enrolled in Agricultural Sector like Agricultural Engineer, Biotechnology, Polytechnic need to provide employment to all. People are on the system in are sure there be improvement in Agrisector & future generation.

I come from Nandyal which is in Rayalaseema zone which was once called Rathnaleseem (land of gems) & had a glorious agricultural past. Farming is not just an occupation but it is the identity, legacy and the only means of survival. For the past few years it is experiencing severe crisis because of insufficient rainfall, scarcity or no rainfall, recurred drought &

insufficient irrigation system and brutally middle men, pathilconda market which is largest wholesale hub 1Rs/Kg. Dhan Dhanya Krishi Yojna where 100 Districts low procedure and modern crops intensity to initiate the scheme in our society, specially in Rayalaseema and Nandayal. Rayalaseema is a centre for pulses & can contribute in Atmanirbhar Bharat pulse programme. Due to dry climate mullet power foxtail reg. staple food special pil seeds. Reviving this would be a game changer. Establishment of Millets Research Institute & Processing Unit in Rayalseema. Support exports, Provide MSP. Establish Make in India Millets based food industry. Out of 26 Districts only 13 Districts have operating Krishi Vignan Kendras & request to establish in all Districts.

Completion of pending Irrigation Projects, interlinking of Godavari and Kaveri which would solve drought across the country.

Hamara Rashtriya Gaan me
Bharat bhagya vidhata hota
hai
Ye bhagya vidhata hamara
Kissan hai
Uppar se insaan, Ander se
Farishta
Or annadata hota
Ye anndata bharat bhagya
vidhata hota hai
Jai Jawan, Jai Kissan.

I would like to conclude by telling

Transformation of Indian Agriculture is not about policies but about people.

It is about a father in Rayalaseema hoping his child would inherit a prosperous farm

It is about a mother in Nandyal who wish to have better prices for her crop.

And about a young farmer who wants to embrace technology.

Blending Tradition and Technology

Policies and Practice

Vision and Action.

Jai Jawan Jai Kissan.

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : अगस्त 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपाई ने किसानों के लिए तीन लाख रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड जारी करके किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम किया । आज 27 साल बाद पुनः मोदी सरकार ने किसानों की सुध लेते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख से 5 लाख रुपये की है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता है । मुझे 2007 में इजराइल जाने का अवसर मिला था । मैं वहाँ के किसानों की आर्थिक बहुत अच्छी है । तब मैंने सोचा क्या भारत के किसानों की ऐसी स्थिति कब होगी, भारत में ये नियम कब लागू होगा ।

इजराइल के किसानों की उपज व्यापारी किसानों के खेत में आकर खेत से सीधी खरिद की जाती है । वहीं से सब्जी फल अन्य सभी उपज देश और विदेश में जाती है, जिससे किसान को मंडी व आडत व अन्य टैक्स से बच कर सही रेट मिलती है । मैं वहाँ से लौटने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी मनोदशा से अवगत करवाया था । इजराइल के किसानों की तरह भारत के किसानों को सीधे बाजार मिले तो भारत के किसान भी अपने फसल सब्जी फल का सीधा व्यापार कर पाएँगे । इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल 2020 में लाकर किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था । 17 सितम्बर, 2020 को लोकसभा और 20 सितम्बर, 2020 में राज्य सभा में बिल पास हो गया था । मगर जिन व्यापारियों

की मंडियो में बड़ी-बड़ी दुकानें थीं, उन्हीं दुकानदारों ने किसानों से मंडी टैक्स व दलाली वसूल कर उनका धन्धा चल रहा था ।

ऐसे व्यापारी नकली किसान बनकर किसान विरोधी व्यापारी रोडों पर उतरे व किसान विरोधी पार्टी कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया और कृषि सुधार बिल 2020 का भारी विरोध किया, जिससे किसानों के हितेषी बिल, 2020 को सरकार को वापस लेना पड़ा, जिससे भारत के किसानों को काफी नुकसान हुआ और आज भी मंडियो के दलालों से किसान लुटे जा रहे हैं । जिन पार्टियों ने किसान हितेषी बिल का विरोध करवाया गया है, उसके आने वाले समय भगवान भी माफ नहीं करेगा और किसानों की हाय लगेगी । अगर यह बिल रहता तो किसानों को निम्न फायदे होते जैसे :-

कृषि उपज मंडी समिति मंडी में बेचने या किसी अन्य विक्रेता या किसी अन्य विक्रेता को चुनने की आजादी होती ।

उपज बेचने के लिए कई विकल्प होते ।

प्रतियोगिता के माध्यम से किसानों को बेहतर कीमत मिलती ।

कोई फीस नहीं और कोई कमीशन नहीं देना पड़ता, जिससे किसान सीधे अपने खेत से अपनी उपज किसी को भी बेच सकता था

किसानों के अधिकार की रक्षा करने वाले कानूनी ढांचे का निर्माण होता ।

मंडी शुल्क और आडत आदि करों में कमी और बेहतर कीमत निर्धारित होती ।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी खेती लाभदायक हो जाती ।

महोदय, किसान अपने खेत में रात-दिन मेहनत कर तीन से चार महीना सब्जी को तैयार करता है । उसकी अनुमानित लागत 10 रुपये होती है, मगर वही सब्जी मंडियो से होते हुए मंडी टैक्स व आडत और हमाली जैसे कई टैक्स लगकर उस सब्जी से दाम 10 रुपये से बढ़कर 30 रुपये तक हो जाती है । माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा कृषि सुधार बिल 2020 को पुनः लाकर किसानों को मंडी के दलालों से बचाने का कष्ट करें ।

- उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन हेतु 100 करोड़ रुपये देकर किसानों का फायदा होगा ।

- धन धान्य कृषि योजना लोकर सौ जिलों में 1.75 करोड़ रुपये देकर किसानों का फायदा हो। मैं लोक सभा जालोर, सिरौही में वर्षा कम होने से डार्क जोन घोषित है। उसमें हमारे दोनों जिलों को शामिल कराएं।
- बागवानी बढ़ाने हेतु 500 करोड़ रुपये देकर सहायता की है।
- दलहन में आत्मनिर्भर के लिए 1000 करोड़ रुपये देकर किसानों की आय बढ़ाने का काम किया है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय व कृषि मंत्री महोदय व मोदी सरकार को किसानों की ओर से धन्यवाद देता हूँ।

डॉ. लता वानखेड़े (सागर) : आज इस गौरवशाली सदन में खड़े होकर मैं अपने हृदय की गहराइयों से हिन्दुस्तान के क्षितिज पर देदीप्यमान हस्ताक्षर, हमारे प्रेरणापुंज, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को नमन करती हूँ। जिनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और दूरदृष्टि के कारण भारत आज एक नए स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। सदियों से बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे अन्नदाता की सुध यदि किसी ने वास्तव में ली, तो वे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जिन्होंने "किसान क्रेडिट कार्ड" जैसी योजना शुरू करके कृषि क्षेत्र में एक सराहनीय पहल की थी। लेकिन आज़ादी के बाद आधी सदी तक जिस पार्टी ने इस देश पर शासन किया, उन्होंने किसानों और कृषि क्षेत्र की ज़रा भी परवाह नहीं की। उन्होंने केवल और केवल सत्ता का सुख स्वयं तक और अपने परिवार तक सीमित रखा। फाइव-स्टार संस्कृति में पले-बढ़े लोग क्या जानें कि किसान का संघर्ष क्या होता है। वे तो यह भी नहीं जानते कि आलू ज़मीन में होता है या पौधे पर लगता है।

आज हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिससे कृषि क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। हमारे किसान सशक्त हो रहे हैं, उनकी आय बढ़ रही है और वे नई तकनीकों को अपनाकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद कई दशकों तक कृषि क्षेत्र को वह पहचान और महत्व नहीं मिला, जो उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि पिछली सरकारों ने कृषि की प्रधानता केवल कागजों तक सीमित रखी। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता में रखा और किसानों की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। यह

मोदी जी के उस संकल्प का प्रतिबिंब है, जो उन्होंने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए लिया है। कुछ लोग आते हैं तो साँचे ढह जाते हैं और कुछ लोग आते हैं तो साँचे बदल जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश की तस्वीर बदलने का सराहनीय कार्य किया है।

मैं वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी और कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में कृषि मंत्रालय के लिए कुल आवंटन 1.27 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 1.17 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष की संशोधित अनुमानों की तुलना में यह 22 प्रतिशत अधिक है और बजट अनुदानों की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हमारे वित्त मंत्री और कृषि मंत्री जी ने किसानों के हित में 12,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह निर्णय हमारे अन्नदाताओं के जीवन को संवारने और उन्हें सशक्त बनाने वाला है। भारत में कृषि का इतिहास हजारों साल पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक कृषि हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार की किसान विरोधी नीतियों और संवेदनहीन रवैये के कारण हमारा देश कृषि क्षेत्र में निरंतर पिछड़ता गया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि को केवल नगदी फसलों तक सीमित कर दिया था, जिससे किसानों की स्थिति कमजोर हो गई थी। दुर्भाग्यवश आज़ादी के बाद भी दशकों तक कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया। हरित क्रांति जरूर हुई, लेकिन इसका लाभ भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिला। सिंचाई सुविधाओं में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल रही। कर्ज माफी के नाम पर घोटाले हुए, ईमानदार किसानों को फर्जी कर्जमाफी में फंसा दिया गया। 2014 से पहले सिंचाई योजनाएँ जर्जर थीं, योजनाएँ केवल कागजों तक ही सीमित रहीं। बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया था कि हम 100 रुपये भेजते हैं, लेकिन किसानों तक सिर्फ 10 रुपये ही पहुंचते हैं। आज मोदी सरकार में 100 प्रतिशत पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। कृषि निर्यात नीति असफल रही - कांग्रेस सरकार ने गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया,

जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाया । फसल बीमा योजना पूरी तरह विफल थी, किसानों को सही समय पर मुआवजा नहीं मिलता था ।

आज के परिदृश्य में यदि कृषि की बात करूँ तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के करोड़ों किसानों को सीधे 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनके खातों में भेजे जाते हैं । पहले की सरकारों में यह पैसा बिचौलियों की भेंट चढ़ जाता था । न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है । हमारी सरकार ने MSP लागत का 1.5 गुना तय कर किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई तेजी से की जा रही है । अब तक 1.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बीमा दावा किसानों को दिया गया है । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी के तहत 99 सिंचाई परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिससे लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है । नीम कोटेड यूरिया से खाद की कालाबाजारी समाप्त हुई है । पहले की सरकारों में यूरिया की किल्लत बनी रहती थी, लेकिन हमारी सरकार ने यूरिया की 100 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की है ।

E-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) - मंडियों को डिजिटल बनाया गया, जिससे किसान बिचौलियों से मुक्त होकर सीधे व्यापारियों को अपनी उपज बेच सकते हैं । ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिजिटल कृषि मिशन - हमारे प्रधानमंत्री जी की ड्रोन योजना के तहत सरकार 1,261 करोड़ रुपये खर्च करेगी । इस धनराशि से सरकार 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया कराएगी । महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने का विजन गाँवों की बेटियों को आत्मनिर्भर बना रहा है । केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना - प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इसकी आधारशिला रखी, जिससे पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र लाभान्वित होगा । नर्मदा घाटी परियोजना - दशकों तक कांग्रेस सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल रखा था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे किसानों की सिंचाई समस्याओं के समाधान हेतु प्राथमिकता दी है । खेती में आधुनिकता लाने के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंप और स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया । किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार किया गया, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो सके । इन सभी उपायों ने मिलकर भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और कृषि क्षेत्र को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया । आज भारत की कृषि पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है । किसान अब पारंपरिक खेती के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों को भी

अपना रहे हैं। भारत का कृषि निर्यात पहले से कहीं अधिक बढ़ रहा है। लेकिन सरकार यहां रुकने वाली नहीं है। भविष्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैविक और प्राकृतिक खेती, हरित ऊर्जा तथा वैश्विक बाजार से सीधा जुड़ाव हमारे किसानों की आय को और अधिक बढ़ाएगा।

मैं मध्यप्रदेश से आती हूँ। हमारा प्रदेश जिसे देश का हृदय कहा जाता है, कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। यहाँ लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में से एक है और कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है। मध्य प्रदेश गेहूं, सोयाबीन, चना, सरसों, मक्का और दालों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसे "सोयाबीन का कटोरा" भी कहा जाता है। यहाँ की उपजाऊ भूमि नर्मदा और चंबल जैसी नदियाँ तथा अनुकूल जलवायु कृषि के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। मध्य प्रदेश को "भारत का अन्न भंडार" भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो स्वयं किसान के बेटे हैं, माननीय डॉ. मोहन यादव जी ने 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें कृषि और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त 4,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता दी जा रही है। हमें केवल पारंपरिक योजनाओं तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि शोध, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाना होगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र सागर सहित मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और किसानों की यह दृढ़ मान्यता है कि "कृषि और ग्रामीण विकास प्रबंधन की सही और उचित शिक्षा, किसानों और ग्रामीणों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।" इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस सदन के माध्यम से सागर में एक अत्याधुनिक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की मांग करना चाहती हूँ। मैं सागर में एक ग्रामीण विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना की मांग करती हूँ। साथ ही मैं यह भी प्रस्तावित करती हूँ कि मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि महाविद्यालय खोला जाए,

इससे किसानों और उनके परिवारों को आधुनिक कृषि शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाया जा सके।

इसके अलावा मध्य प्रदेश में मौजूदा कृषि अनुसंधान केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों को अत्याधुनिक केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए । इन केंद्रों में स्मार्ट खेती, जलवायु अनुकूल कृषि, प्रिसिजन फार्मिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर, जैविक और प्राकृतिक खेती, बागवानी, आधुनिक सिंचाई प्रणाली, कृषि विपणन और आपदा श्रृंखला प्रबंधन जैसी नई तकनीकों पर शोध और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए । इससे किसानों को नवीनतम कृषि प्रणालियों की जानकारी मिलेगी, जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप खेती कर सकेंगे । आज जब पूरी दुनिया कृषि 4.0 की ओर बढ़ रही है, तब हमें अपने किसानों को केवल पारंपरिक कृषि तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाना होगा । हमें अपने किसानों को केवल पारंपरिक कृषि तक सीमित रखने के बजाय, उन्हें आधुनिक कृषि प्रबंधक और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में कार्य करना होगा । यदि प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय होगा और सभी अनुसंधान केंद्र अत्याधुनिक बनाए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश देश में कृषि शिक्षा और नवाचार का प्रमुख केंद्र बन सकता है ।

अनुदान की मांगों पर बोलते हुए, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अपील करती हूँ कि सागर में एक उन्नत कृषि अनुसंधान केंद्र और ग्रामीण विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाए । साथ ही, मैं सरकार के माध्यम से मांग करती हूँ कि सागर में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय खोला जाए । इसके साथ ही, सभी कृषि अनुसंधान केंद्रों को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । यह केवल एक नीति नहीं होगी, बल्कि यह एक आंदोलन होगा, एक क्रांति होगी, जो किसानों और ग्रामीण युवाओं को नई दिशा और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करेगी ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): It is with great honour that I stand before you today to acknowledge the commendable efforts of the Government of India in advancing the agricultural sector through the latest budget allocation. The Union Budget 2025-26 has seen a substantial increase of 3.89 per cent in the allocation for agriculture, reaffirming the Government's unwavering commitment to farmer welfare and rural prosperity. The achievements in food grain production, which

have risen from 204.6 million tonnes in 2004-05 to an estimated 332.3 million tonnes in 2023-24, are a testament to this commitment. Furthermore, the remarkable growth in horticulture production, reaching an all-time high of 355.25 million tonnes, and the surge in agricultural exports to Rs.4.2 lakh crore in FY23 highlights the robust strides taken in the sector.

The PM-KISAN scheme continues to be a cornerstone of farmer empowerment, with over Rs. 3.46 lakh crore disbursed to 11 crore farmers since its inception. In Andhra Pradesh alone, Rs. 836.36 crore has reached more than 41.22 lakh beneficiaries in the 18th instalment. Additionally, the steady increase in Minimum Support Price (MSP) for paddy, from Rs. 850 per quintal in 2008-09 to Rs. 2,300 per quintal in 2023-24, has reinforced price stability and income security for our farmers.

Andhra Pradesh has emerged as a frontrunner in sustainable and natural farming, setting an example for the rest of the country. Our commitment to Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming (APCNF) has gained international recognition. Delegations from countries such as the USA and Mexico visited my district, Palnadu, to study our pioneering models. The vision of our Chief Minister Nara Chandra Babu Naidu aligns seamlessly with the objectives of the Union Government, ensuring that our State remains a key player in sustainable agricultural practices.

The newly introduced budget schemes, such as the Cotton Technology Mission, the Mission for Pulses, and the National Mission on Hybrid Seeds, present immense opportunities for Andhra Pradesh. As the 8th largest cotton-producing State, Andhra Pradesh stands to gain significantly from the Cotton Technology Mission, enhancing traceability and ensuring higher returns for farmers. Similarly, the Mission for Pulses,

with a budget of Rs. 1,000 crore, will bolster our production capacity, helping us compete with leading States like Karnataka and Gujarat. Furthermore, the National Mission on Hybrid Seeds aligns with Andhra Pradesh's long-standing tradition of being a leader in seed production, enabling us to develop high-yielding and region-specific hybrid seeds for rice, millets, and pulses.

With increased support from the Union Government, Andhra Pradesh is poised to maximize the benefits of these schemes, further strengthening our agricultural backbone and contributing to the national goal of food security and economic growth.

While the Government's initiatives have laid a strong foundation, there remain key areas that require further attention. Firstly, the need for a comprehensive price support mechanism for horticulture crops such as red chilies is paramount. Andhra Pradesh's Palnadu district, which covers nearly 90 per cent of its horticultural area under red chili cultivation, has faced severe losses due to adverse weather conditions. Given the substantial financial burden on the State Government, we urge the Union Government to include red chilies under the Price Support Scheme (PSS) through NAFED, in alignment with PM-AASHA, ensuring remunerative prices for our farmers.

Secondly, Andhra Pradesh, despite being a leader in agricultural growth, hosts only three ICAR research institutes out of the 102 across India. None of the 11 Agricultural Technology Application Research Institutes (ATARIs) are located in the State. Given our commitment to sustainable farming and our contributions to the agricultural sector, we strongly advocate for the establishment of additional ICAR institutes in Andhra Pradesh. These institutions will serve as vital hubs for research,

innovation, and capacity building, further propelling our agricultural excellence.

Andhra Pradesh has demonstrated time and again its resilience, innovation, and commitment to sustainable growth. With continued support from the Union Government, we are confident that our farmers will thrive, our yields will multiply, and our rural economy will flourish. Together, let us work towards an agricultural revolution that not only uplifts Andhra Pradesh but also strengthens the entire nation's food security and economic stability. Thank you.

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसका लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। साथ ही, वित्त वर्ष 2025 26 में इस योजना के बजट में 23% की कटौती की गई है।

क्या फसलों पर जोखिम कम हो गया है? , क्या किसान 23% कम हो गए हैं? इस योजना का बजट बढ़ाया जाए और सभी किसानों को इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।

गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिससे किसानों को गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को जल्द से जल्द बकाया भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों की आय का मुख्य आधार है। एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, लेकिन उन्हें उचित सहायता नहीं मिल रही। बाढ़ प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए।

किसान कर्ज माफी योजना फिर से शुरू की जाए, जिससे कर्ज में डूबे किसानों को राहत मिल सके। किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि बढ़ाई जाए, ताकि दुर्घटना की स्थिति में किसानों और उनके परिवारों को पर्याप्त आर्थिक कृषि

उपकरणों छूट उपलब्ध कराई जाए, जिससे छोटे किसान भी आधुनिक उपकरणों का लाभ उठा सकें और उनकी उत्पादकता बढ़े । सिंचाई संसाधनों का विकास किया जाए, जिससे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके । सरकार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) के तहत किसानों को 6000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता दी जाती है । बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस राशि को 60,000 बढ़ाया जाए ।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के तहत मिलने वाली ब्याज छूट को बढ़ाकर किसानों को और राहत दी जाए । किसानों की फसल का उचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक वेयरहाउसिंग सिस्टम विकसित किया जाए, जिससे फसल की बर्बादी रुके और किसानों को सही मूल्य मिले ।

यूरिया सब्सिडी का बजट पिछले कुछ वर्षों में लगातार घटाया गया है, जबकि बढ़ती 507 और महंगाई को देखते हुए इसकी आवश्यकता अधिक है । इस कटाव को रोका जाए और यूरिया सब्सिडी बढ़ाई जाए । अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह लगातार घटती जा रही है, जो बेहद चिंता का विषय है । सरकार को कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे ।

किसानों का सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों से संभव होगा । इसलिए, सरकार को इन मुद्दों पर तत्कात्र ध्यान देना चाहिए । मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए ताकि किसानों को नुकसान न हो ।

विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए । मनरेगा में 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी सुनिश्चित की जाए । नकली बीज, कीटनाशक और खाद बेचने वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बने ।

मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए । संविधान की 5वीं अनुसूची लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट रोकी जाए ।

देश के 55.4 प्रतिशत किसान परिवार कर्ज में डूबे हैं, पश्चिम यूपी में भी हालात खराब हैं । हर किसान परिवार पर औसतन 21,231 रुपए का कर्ज है, जो चिंता का

विषय है । 18.81 करोड़ किसानों पर 32,35, 747 करोड़ रुपए का कर्ज है, स्थिति गंभीर है । किसानों के आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें छुपा रही है ।

***m138 श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) :**

"जिस धरती से अन्न उगे,
उसी धरती पे अन्नदाता रोए,
ये कैसा विकास है,
जो खेतों की जगह खबरों में बोए?"

मैं किसानों की उस चीत्कार को मैं उठा रहा हूं जो न सरकार की नीतियों में सुनी जाती है, न बजट के भाषणों में दिखाई देती है । 2025-26 का कृषि बजट किसानों के विकास का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक धोखा है, एक अपमान है, उन किसानों के लिए जो दिन-रात मेहनत करके इस देश को अन्न दे रहे हैं । सरकार कहती है- ये बजट किसानों का है । पर सच्चाई यह है कि यह बजट किसानों की पीठ में छुरा है ।

"किसान खून बहाए खेतों में,
और सरकार बहाए आँसू कैमरों में ।"

जब देश का किसान कर्ज, जलवायु परिवर्तन, और बढ़ती लागत से त्रस्त है, तब यह सरकार कृषि बजट में 2.5% की कटौती कर देती है ।

कृषि मंत्रालय को 21,37,757 करोड़ दिए गए हैं, जो पिछले वर्ष से कम हैं ।

फसल बीमा योजना (PMFBY) में 23% की कटौती कर दी गई है ।

उर्वरकों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सब्सिडी घटाई जा रही है. और यूरिया की बोरी का आकार छोटा कर दिया गया है ।

क्या यही है सरकार को "प्रो फार्मर" नीति?

"जिन हाथों ने देश को भोजन दिया,
आज वही हाथ मदद के लिए फैले हैं ।"

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान जिनकी मेहनत से देश को 40% गन्ना मिलता है, उनके ₹16,000 करोड़ बकाया है ।

आलू किसान जिन्हें ठंडा भंडारण, डीजल, खाद, और मज़दूरी की चढ़ती लागत ने तोड़ कर रख दिया है आज आत्महत्या की कगार पर खड़े हैं । मेरा सरकार से मेरा सवाल है कि जब शुगर मिलों को सब्सिडी दी जा सकती है, तो किसानों को क्यों नहीं? क्यों किसान का भुगतान महीनों तक लटका रहता है?

"जिसने खेतों में जीवन बोया,
सरकार ने उसी का सपना धोया ।"

अब बात करते हैं ऐतिहासिक किसान आंदोलन की । लाखों किसान महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे, और क्या माँग थी उनकी?

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो ।

MSP को कानूनी गारंटी मिले ।

सभी फसलों के लिए सार्वजनिक बीमा योजना हो ।

Singhu और Tikri बॉर्डर पर शहीद स्मारक बने ।

700 से अधिक मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले. और उन पर दर्ज सभी मुकदमे वापस हो ।

MGNREGA की मज़दूरी ₹700 प्रतिदिन हो. और 200 दिनों का न्यूनतम रोजगार सुनिश्चित किया जाए ।

कृषि उपकरण, बीज, और खाद पर GST घटाई जाए ।

पर सरकार ने इन माँगों का जवाब आँसू गैस, लाठियों और झूठे प्रचार से दिया ।

"शहीद हुए किसान, और सरकार ने उन्हें गद्दार बताया,

मूल्य माँगने पर, उन्हें आंदोलनजीवी कह कर डराया ।"

क्या यह वहीं भारत है, जहाँ किसानों को राष्ट्रद्रोही कहकर बदनाम किया जाता है ।

अब बात करते हैं उस तपते सत्य की, जिसे सरकार छुपाना चाहती है ।

किसान आत्महत्याएं ।

- 1 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ।
- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इस त्रासदी में सबसे ऊपर हैं ।
- कारण है: कर्ज, फसल बर्बाद, आवारा पशु, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का अभाव ।

लेकिन सरकार क्या करती है? बड़े उद्योगपतियों का 214.56 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ करती है. लेकिन गरीब किसान को बैंक नोटिस और ज़मीन जब्ती का सामना करना पड़ता है ।

"मुनाफ़ा कमाए अमीर, और मिटे किसान की तस्वीर,
ये कैसा न्यू इंडिया है, जहाँ मेहनत की कोई तासीर नहीं?"

और उस पर आवारा पशुओं का संकट- उत्तर प्रदेश, बिहार, और मध्य प्रदेश में हजारों गाये किसानों की फसलें तबाह कर रही हैं । किसान रातभर जाग कर खेतों की रखवाली कर रहे हैं । क्या अब किसान कृषक से चौकीदार बन गए हैं?

"जहाँ नदियाँ सूख रही हैं, जहाँ पानी खारा हो चला है,
वहाँ ये बजट केवलवादों का बहाव है ।"

जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं किसान- 15% तक फसल उत्पादन घट चुका है । 90% सिंचाई भूजल से हो रही है, जो अब समाप्ति की ओर है । परन्तु सरकार ने जल संरक्षण या सिंचाई परियोजनाओं पर कोई ठोस योजना नहीं दी ।

निष्कर्ष में यह बजट किसानों के लिए नहीं है । यह एक अपमान है । न MSP की कानूनी गारंटी, न कर्जमाफी, न आवारा पशु संकट का समाधान, न जलवायु संकट की तैयारी, न गन्ना किसानों को न्याय और न ही शहीद किसानों की स्मृति का सम्मान ।

सरकार झूठे विज्ञापन, फेक फोटो, और मीडिया मैनेजमेंट से असलियत छुपा रही है ।

"किसान की आँखों में आंसू हैं, पर टीवी पर मुस्कान,
सत्ता को भुला है कि भूखा पेट कभी वोट नहीं देता जान ।"

महोदय, अगर यह सरकार किसानों की नहीं है, तो उसे सत्ता छोड़ देना चाहिए और उस नेतृत्व को आने देना चाहिए, जो खेत, खलिहान और किसान के साथ खड़ा हो सकें ।

जय जवान, जय किसान ।

श्री अशोक कुमार यादव (मधुबनी) : मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ ।

एक अनुमान के अनुसार अभी भी भारत की आबादी का 65 प्रतिशत कृषि तथा उससे जुड़े हुए कार्यों पर आश्रित है । भारत की दो प्रमुख समस्याओं, गरीबी तथा बेरोजगारी का समाधान कृषि को समृद्ध बनाकर ही कर सकते हैं ।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कृषि एवं कृषकों की महत्ता को समझते हुए वर्ष 2014-2015 के बजट से ही कृषि एवं कृषि आधारित विषयों पर फोकस करते हुए पर्याप्त धनराशि का आबंटन किया है ।

कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए इस बजट में करीब 1.71 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2013-14 के बजट के आबंटन 21,933 करोड़ से करीब सात गुना ज्यादा है ।

उल्लेखनीय है कि खाद्यान उत्पादन जो वर्ष 2014-15 में 252 मिलियन टन था, वह वर्ष 2023-24 में 332.3 मिलियन टन हो गया । साथ ही उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्टेयर) में भी अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है । 2013-14 की तुलना में मोटे अनाज (श्रीअन्न) की उत्पादकता में करीब 71.52% की वृद्धि दर्ज की गई है । अन्य अनाजों की उत्पादकता में भी करीब 18% से 25% की वृद्धि दर्ज की गई ।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस साल के कृषि

बजट में बिहार तथा मिथलांचल के विकास के हेतु बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिसमें ये तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं मील का पत्थर साबित होंगी ।

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना प्रस्तावित है जिससे इसके उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाया जाएगा । इसके लिए 100 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है ।

पश्चिमी कोसी नहर योजना के लिए वित्तीय सहायता जिससे करीब 50,000 हेक्टर जमीन की सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी ।

बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमितता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम (NIFTEM) की स्थापना, जिससे इस क्षेत्र की फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ में काफी बढ़ोतरी होगी और इसके द्वारा यह किसानों की आय में भी वृद्धि होगी ।

यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एनडीए सरकार बिहार ने बरौनी में बंद पड़े खाद उत्पादन संयंत्रों को फिर से चालू किया । इस बजट में 12.7 लाख मैट्रिक टन का यूरिया संयंत्र असम के नामरूप में स्थापित करने की घोषणा की गई, जिसका लाभ बिहार को भी मिलेगा ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) जो वर्ष 2018 में शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक किसानों को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये की राशि प्रत्यक्ष रूप से डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई ।

अकेले बिहार में पीएम-किसान के अंतर्गत पिछली किस्तों के माध्यम से 25,497 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं जिससे राज्य के 86.56 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है । भागलपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 19वीं किस्त जारी की, जिससे लगभग 76.37 लाख किसानों को 1,591 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला, जिससे बिहार में लाभार्थियों को हस्तांतरित कुल लाभ राशि लगभग 27,088 करोड़ रुपये हो गई ।

पिछले 10 वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों पर 1.44 लाख करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है । यह वर्ष 2014-15 में 6,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 14,252 करोड़ रुपये हो गई ।

कृषि के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह 2014-15 से लगभग तीन गुना बढ़ गया है, जो 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अल्पावधि कृषि ऋण दोगुने से भी अधिक हो गया है, जो 2014-15 में 6.4 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 15.07 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

इफको नैनो यूरिया, दुनिया का पहला नैनो उर्वरक, फसल उपज बढ़ाने, लागत कम करने, पौधों के पोषण एवं मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में सहायक, पारंपरिक यूरिया से सस्ता, जिससे किसानों की आय में सुनिश्चित वृद्धि हो।

नमो ड्रॉन्स योजना - महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी) को उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाना। मुख्य विवरण, कुल फंडिंग- 1261 करोड़ रुपये। 14,500 महिलाओं एसएचजी को ड्रोन (किराए पर) उपलब्ध कराए जाएंगे। ड्रोन का उपयोग उर्वरक कीटनाशक छिड़काव एवं फसल की स्थिति एवं संभावित रोगों का शीघ्र पता लगाने में होगा। इसकी कार्यान्वयन अवधि 2024-2026 है।

फर्टिलाइजर सब्सिडी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फर्टिलाइजर सब्सिडी 2013-2014 में 71,000 करोड़ से बढ़ाकर 1.67 लाख करोड़ किया गया है, जो करीब ढाई गुना है।

कृषियांत्रिकीकरण उप-मिशन (एसएमएम) के तहत विभिन्न कृषि उपकरणों पर 40-50% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। छोटे एवं महिला किसानों के लिए यह प्रतिशत और भी अधिक हो सकता है।

पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए केवल 10-30% का अंशदान करना होगा, शेष राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

दिसंबर 2024 तक 6.1 लाख सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। 35 लाख कृषि पंप सोलराइज किए गए हैं। एमएसपी पर रिकार्ड खरीदी की जा रही है। एनडीए शासन (2014 से 2024) के दौरान, यूपीए शासन (2004 से 2014) की तुलना में धान की खरीद में लगभग 47% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, धान के लिए किसानों की कुल भुगतान में लगभग 177% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई।

एनडीए शासन के दौरान गेहूं की खरीद में यूपीए शासन की तुलना में लगभग 44% की वृद्धि हुई, जबकि किसानों को कुल भुगतान में लगभग 140% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने अरहर एवं बाजरा के एमएसपी में क्रमशः 59 एवं 77 प्रतिशत की वृद्धि उनके उत्पादन की लागत की तुलना में की है। इसी तरह मसूर और रेपसीड के एमएसपी में क्रमशः 89 प्रतिशत तथा 98 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की है।

कृषि विकास को बढ़ावा एवं ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना में कृषि जिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 100 जिलों को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। केसीसी के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

5 वर्षीय मिशन से कपास की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय उच्च पैदावर बीज मिशन के अंतर्गत पैदावार कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से सम्पन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार किया जाएगा।

दलहन में आत्मनिर्भरता के अंतर्गत तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन का आरंभ किया गया है तथा इसके लिए 1,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।

बागबानी विकास हेतु एक विस्तृत योजना बनाई गई है, जिसके लिए 2025-26 में 500 करोड़ का प्रावधान है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में संशोधित अनुदान 2024-25 में 1500 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी कर 8500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह कृषोन्नति योजना में करीब 900 करोड़ की बढ़ोत्तरी कर 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत 8500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो संशोधित अनुदान 2024-25 की तुलना में करीब 2500 करोड़ रुपये अधिक है।

कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2013-14 से 2023-24 तक कृषि निर्यात में करीब 115% की वृद्धि दर्ज की गई । मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में वर्ष 2014 के बाद 25 करोड़ से अधिक किसानों को यह कार्ड जारी किए गए, जिससे कृषि भूमि की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है । ई-नाम के तहत बिना बिचौलियों के उत्तम फसल सीधे मंडी में बेचने की सुविधा किसानों को मिल रही है, जिसमें 23 राज्यों एवं 4 केन्द्र शासित प्रदेशों की 1,466 मंडियां जुड़ी हुई । * 1.78 करोड़ से अधिक किसान, 2.64 लाख व्यापारी, और 4,389 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) इसमें जुड़े हुए हैं । नए नीतिगत सुधारों से किसानों को सीधा बाजार संपर्क मिला । इसके अंतर्गत 10,000 एफपीओ बनाये गये हैं ।

वर्ष 2023-24 में 1,200 स्टार्टअप्स को 130 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई । किसानों की आय के लिए विविध उपाय किए गए हैं । सौर पैनल बंजर भूमि पर स्थापित किए जा रहे हैं । दुग्ध उत्पादन में 2014-15 की तुलना में 55% वृद्धि हुई है । इथेनॉल खरीद 450 करोड़ लीटर तक बढ़ी । इथेनॉल उत्पादन में आमतौर पर गन्ना, मक्का या गेहूं जैसे जैव ईंधन जैसे कृषि उत्पादों का प्रयोग होता है जिससे कृषकों की आमदनी में इजाफा होता है ।

उपज में सुधार हुआ है । पारंपरिक किस्मों की उपज जो पहले लगभग 1.4-1.9 टन/हेक्टेयर थी, अब नई किस्मों से 3.0-3.5 टन/हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो रही है । 2022 की मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने से ब्रांडिंग में सुधार हुआ और निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं । हालांकि अभी भी निर्यात में केवल लगभग 1% हिस्सा है ।

मोर ड्राप पर क्रॉप के तहत 2017 में 42 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024 में 100 लाख हेक्टेयर (135% वृद्धि) और वार्षिक भूमिगत जल रिचार्ज में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर वृद्धि । उच्च उपज वाले बीजों की संख्या 1,390 से बढ़कर 2,900 कर दी गई है । जलवायु-प्रतिरोधी बीजों में 228% की वृद्धि हुई है । जीरो बजट, नेचुरल फॉर्मिंग जैसी प्रथाएँ, जिसका लक्ष्य आने वाले 2 वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर एवं 1 करोड़ किसानों (15,000 क्लस्टर्स) को कवर करना है । 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत 25 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और मिट्टी की सेहत में क्रांतिकारी सुधार होगा ।

प्रिसीजन फॉर्मिंग, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, आईओडी सेंसर एवं बिग डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से खेती को स्मार्ट एवं कुशल बनाने का प्रयास हो रहा है । 71 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इनफ्रॉस्ट्रक्चर फंड स्थापित किया गया है । दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजन में 9,750 एमटी क्षमता वाले गोदाम बनाए गए हैं, जिससे संरक्षित भंडारण सुनिश्चित हुआ । इसी तरह इस साल का बजट भी कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसान कल्याण सुनिश्चित करने और समग्र राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है ।

केंद्रीय बजट 2025-26 कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वित्तीय आवंटन बढ़ाकर, प्रमुख फसलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर, अनुसंधान और नवाचार में निवेश करके और बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर, सरकार का लक्ष्य किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना और राष्ट्र के समग्र विकास को आगे बढ़ाना है । इन पहलों से कृषि को अधिक टिकाऊ, लाभदायक और लचीला क्षेत्र बनाने की उम्मीद है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा ।

महोदय, मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों का पूरजोर समर्थन करता हूँ ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : तमाम योजनाओं और दावों के बाद भी देश का किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और आत्महत्या करने पर मजबूर हैं ।

मैं कृषि मंत्री जी से पहला अनुरोध करता हूँ कि सदन में किसी भी माननीय सदस्य का किसान के हित में कोई सुझाव आता है तो आप उनका अध्ययन करके उन सुझावों को किसानों के हित में लागू करें, तभी ऐसी चर्चा की सार्थकता सही मायनों में सफल होगी । क्योंकि आरोप-प्रत्यारोप से हम किसान का भला नहीं कर सकते हैं ।

जहां तक किसान कर्ज माफ़ी का सवाल है, आज देश के कुल कृषि बजट से 20 गुना ज्यादा देश के किसानों पर कृषि कर्ज बकाया है । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के किसानों पर 1,74,798 करोड़ रुपये व देश के किसानों पर 33,52,646 करोड़ रुपये का कर्जा बकाया है । आप जब धन्ना सेठों का राईट ऑफ़ के नाम पर लाखों करोड़ का कर्जा माफ़ कर देते हो, तो मेरी मांग है कि राजस्थान सहित देश के सभी किसानों की कर्जमाफी की जाए ।

देश में किसान आंदोलन चला और 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी । आपने काले कानूनों को वापिस, ठोस आश्वासन के बावजूद आप वादों को भूल गए । देश का किसान एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की मांग कर रहा है । इस संबंध में आपसे जब पूछा जाता है तो आप जुलाई 2022 में गठित समिति का ज़िक्र कर देते हैं, लेकिन MSP को कानून के दायरे में कब लाओगे, यह नहीं बताते हैं। मेरी मांग है कि MSP को कानूनी दायरे में लाया जाए ।

सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की थी, जिससे उन्हें खेती-बाड़ी और अन्य जरूरतों के लिए आसानी से कर्ज मिल सके । लेकिन, इस योजना का लाभ देने के बजाय कुछ भ्रष्ट बैंक अधिकारी और तहसील के कर्मचारी तथा दलालों की एक चैन किसानों से अवैध कमाई का जरिया बना चुके हैं । मैं सरकार ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि जब कोई किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेने जाता है, तो बैंक उनसे सर्व रिपोर्ट नामक एक कानूनी दस्तावेज की मांग करता है । यह रिपोर्ट यह साबित करने के लिए होती है कि किसान की ज़मीन पर कोई और कर्ज या कानूनी विवाद नहीं है । लेकिन यह रिपोर्ट मात्र ₹200-₹500 में आसानी से बन सकती है । फिर भी किसानों से इसके नामपर ₹5,000 से ₹10,000 तक वसूला जाता है । मेरी मांग है कि तहसील या ग्राम स्तर पर में सर्व रिपोर्ट को ऑनलाइन और फिक्स रेट पर उपलब्ध कराया जाए । बैंक, तहसील तथा अन्य बिचौलियों की सांठगांठ खत्म करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र बनाया जाए । किसानों को सीधे शिकायत करने का मौका मिले और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो ।

मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे राजस्थान के संदर्भ में सूखा घोषणा की अवधि सूखे के प्रभाव के अनुसार आगामी वर्ष के माह जुलाई तक अथवा मानसून आने तक जो भी पहले हो बढ़ाए जाने के लिए आप किसानों के हित में सूखा संहिता 2016 में संशोधन करें ।

कीट/रोगों द्वारा 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराब होने पर सहायता दी जाए । माननीय कृषि मंत्री जी राजस्थान में रबी, खरीफ व जायद में बोयी जाने वाली फसलों में कीट या रोग द्वारा 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराब होने पर किसानों को कृषि आदान-अनुदान सहायता प्रदान करने के संबंध में राजस्थान सरकार

द्वारा आपसे मार्गदर्शन मांगा गया है, जो लंबित है, आप ऐसे प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करें ।

किसानों को लंबित क्लेम मिलें । कृषि मंत्री जी, मेरे नागौर व डीडवाना - कुचामन जिले सहित राजस्थान के सभी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का क्लेम बकाया है । कम्पनियां झूठी आपत्ति लगा देती हैं । मामला जिला स्तर से राज्य स्तर की समितियों के मध्य फंस जाता है । मेरी मांग है कि किसानों को जल्द से जल्द लंबित क्लेम दिलवाया जाए ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है । आपने किसानों के साथ हो रखी धोखाधड़ी को रोकने के बजाय खड़ी फसल में हुए नुकसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में होने वाले व्यक्तिगत नुकसान के प्रावधान को हटाया गया है, जो कि सरासर गलत है। पश्चिमी राजस्थान में इसबगोल, जीरा सहित कई फसलें प्रमुखता से बोई जाती हैं । इसके पकने की अवस्था पर बे-मौसम बारिश या ओलावृष्टि होने पर यह कांच की तरह शत प्रतिशत नष्ट हो जाती है । इस फसल की पकाव की अवस्था पर अगर 2mm बारिश हो जाए तो भी किसान का बहुत नुकसान हो जाता है । सरकार ने इस तरह की व्यक्तिगत आपदा को कवरेज में सम्मिलित नहीं किया है । सरकार से अनुरोध है कि खड़ी फसल को पकाव की अवस्था पर अगर बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि हो जाए तो ऐसी स्थिति को फसल बीमा योजना के दायरे में आपदा में सम्मिलित करते हुए किसान को उसका हक दिलाने की कृपा करें । बेमौसम बारिश किसी सम्पूर्ण पटवार हल्के में नहीं होकर छोटे-छोटे पेचेज में भी हो सकती है ।

कृषि और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें- माननीय कृषि मंत्री जी, डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने किसानों के हित में जो सिफारिशें की, उन सिफारिशों में कितनी आपने लागू कर दी और कौन कौन सी सिफारिशें लागू करना शेष है? आप जब जवाब दे तो यह जरूर बताएं ।

संविदा खेती के क्षेत्र में डिग्री कोर्स का अभाव - देश से संविदा खेती जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, उसका बखान आपने जोर शोर से किया, लेकिन 27 जुलाई, 2021 को जब मैंने इस सदन में पूछा तो तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का

देश में कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स नहीं है । आप बताओ कि उस बात को चार वर्षों हो गए, क्या आपने किसी संस्था में यह डिग्री या डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है अथवा नहीं ।

नागौर में स्वीकृत हो कृषि विश्वविद्यालय- मैं आपके माध्यम से स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी द्वारा राजस्थान में शुष्क कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही लेकिन तत्कालीन राजस्थान की BJP सरकार ने उस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव गैर शुष्क क्षेत्र के लिए भेज दिया इसलिए वो घोषणा पूर्ण नहीं हो पाई, मेरी मांग है कि मेरे नागौर में केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, नागौर शुष्क विश्वविद्यालय के सारे मापदंड पूरे करता है ।सिफारिश जो कृषि मंत्रालय से गृह मंत्रालय को करवानी है ।

माननीय कृषि मंत्री जी, मेरे राजस्थान राज्य के संदर्भ में कृषि आदान- अनुदान की अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 हैक्टेयर तक करने व होर्टीकल्चर एवं क्रीश क्रोप के लिए कृषि आदान -अनुदान में वृद्धि के लिए आप गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे क्योंकि यह आपदा के नियमों में संशोधन से जुड़ा विषय है- कृषि अनुसन्धान और शिक्षा के लिए बजट को बढ़ाया जाए । नागौर में मुंग पर अनुसन्धान हेतु राष्ट्रीय स्तर का केंद्र स्वीकृत किया जाये । नागौर व डीडवाना - कुचामन जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत किये जाये । आपने बाजरे को एमएसपी के दायरे में ले रखा है लेकिन हमारे राजस्थान में सरकार बाजरे को एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही है, इसलिए बाजरे की एमएसपी पर खरीद शुरू की जाये । फार्म पोंड, पोली हाउस के लिए केंद्र सरकार राजस्थान के किसानों हेतु अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाएभारत में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों के संदर्भ में कृषि रिसर्च पर अधिक ध्यान, बजट और बहस की जरूरत है. जबकि कृषि में शोध और नवाचार का महत्व बढ़ रहा है.

बजट आवंटन में केवल मामूली वृद्धि देखने को मिल रही है. कृषि के भविष्य की चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, घटती जोत, बढ़ती जनसंख्या और खेती की लागत में वृद्धि शामिल है. इन समस्याओं से निपटने के लिए कृषि में अनुसंधान का विस्तार और सुधार जरूरी है. देश में बढ़ती जनसंख्या और घटती खेती की जोत, उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने की चुनौती, खेती में बढ़ती लागत और लाभदायक घटने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि रिसर्च जरूरी है. जलवायु परिवर्तन और कम होते प्राकृतिक संसाधन, भूमिगत जल, मिट्टी की उर्वरता

में कमी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि शोध की जरूरत है। जबकि, सरकार ने कृषि शोध और शिक्षा के बजट में पिछले साल की तुलना में मात्र 6 परसेंट की बढ़ोतरी की है। पिछले साल 2023-24 में 9876.60 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो इस साल 2024-25 में 9941.09 करोड़ रुपये किया गया है। इसके बजट का ज्यादा हिस्सा 70 से 80 फीसदी सैलरी और अन्य कार्यों पर खर्च होता है जिससे रिसर्च कार्य के लिए बहुत कम बचते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवंटन किए गये कृषि रिसर्च के बजट से भविष्य की चुनौतियों के सभी रिसर्च संभव हो सकते हैं क्या?, वही दूसरा कृषि रिसर्च और अन्य कृषि नवाचारों के लिए आवंटित बजट पूरी तरह से उपयोग हो और इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए। इस प्रकार, कृषि अनुसंधान में अधिक निवेश से देश की कृषि उत्पादकता और किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद) : मुझे वर्ष 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए कोटिश: धन्यवाद।

हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यहां कृषि कार्य करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति सदैव दैनीय ही रहती थी। मैं भी एक किसान हूं और जाति से भी किसान हूं। मुझे एक किसान का दर्द जितना मालूम है, उतना शायद ही किसी को मालूम हो।

2014 के बाद देश के किसान भाइयों को ध्यान में रखकर ही योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही साकार की हैं।

पहले तो योजनाएं बनती थी परंतु धरातल पर नहीं दिखती थीं माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों के कल्याण के लिए उनके जीवकोपार्जन के लिए जो योजनाएं बनी वह धरातल पर भी दिखती हैं और साकार भी हुई है देश का लगभग 95 प्रतिशत गांव आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लाभान्वित है देश के 99 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच गई है सहकारी प्रथा से किसानों को मुक्ति मिल गई है अब हमारे किसान भाई किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं अपनी छोटी-छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी सूदखोर के पास नहीं जाना पड़ता है कृषि उत्पादन में विगत 10 वर्षों में आशा तीत वृद्धि हुई है किसानों की आय बढ़ाने के सकारात्मक कदम उठाए गए हैं

विगत 10 वर्षों में है किसानों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संचालन की इस बजट में घोषणा भी हुई है महोदय जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMRBY) और (RWBCI), संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS), एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना (AIF), 10000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आए संरक्षण अभियान (PM-आशा), कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर), पर ड्राप मोर क्रॉप (PDMC), कृषि विस्तार यूपी मिशन, कृषि मशीनीकरण उप मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, डिजिटल कृषि मिशन, एकीकृत कृषि मिशन योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), सॉइल हेल्थ कार्ड ।

ऐसी ही कई योजनाएं चलाकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य किया है मोदी सरकार ने इतना ही नहीं, इस बजट में देश की यशस्वी वित्त मंत्री हम किसानों के लिए मां लक्ष्मी स्वरूपा आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 9 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का प्रस्ताव रखा है, जो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र की वृद्धि और उत्पादकता को बढ़ाने में केंद्रित है ।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना- ऐसे राज्यों के साथ मिलकर देश के ऐसे 100 कम उपज वाले जिलों में लागू किया जाएगा जहां फसलों की उपज मानक औसत से कम है । इस योजना से देश के लगभग पौने दो करोड़ किसान भाइयों को लाभ मिलेगा । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में आवंटित राशि भी स्पष्ट करने की कृपा करें ।

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन - 6 सालों का यह मिशन 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ आरंभ होगा इसका मुख्य फोकस अरहर और मसूर दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना होगा नेफेड और NCCF इसकी सहायक एजेंसियां होंगी ।

सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम - इस बजट में इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को उत्पादन आपूर्ति

चैन प्रसंस्करण के द्वारा लाभकारी दाम दिलाना होगा । कपास उत्पादन मिशन । उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन । राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना । ग्रामीण समृद्धि और सुदृढता कार्यक्रम । मत्स्य पालन क्षेत्र । असम में यूरिया संयंत्र आदि कार्यक्रमों की घोषणा इस बजट में की गई है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी एवं देश के सदस्य प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र आलू और मक्का के उत्पादन में देश में ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है परंतु आजादी के इतने वर्षों बाद भी आलू उत्पादक किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है जबकि आलू सब्जियों का राजा कहा जाता है और इतना विनम्र स्वभाव का होता है यह सभी सब्जियों से घुल मिल जाता है आलू सब्जियों के अलावा इसके पाउडर से तमाम तरीके की नमकीन बनती है ग्रेवी ने भी पूरे विश्व में प्रयोग होता है और वोडका के निर्माण में भी प्रयोग होता है परंतु आलू का यहां अत्यधिक उत्पादन होता है वहां आलू रिसर्च सेंटर नहीं है इसलिए पुन निवेदन है कि आलू उत्पादक किसानों के आर्थिक स्थिति के सुचारु हेतु जिस प्रकार बिहार के मखाना उत्पादक किसानों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु मखाना बोर्ड बनाया गया है, आसाम बंगाल के किसानों के लिए चाय बोर्ड बना है, उसी प्रकार राष्ट्रीय आलू बोर्ड की स्थापना कराई जाए ।

फर्रुखाबाद जनपद में आलू की उन्नत किस्म के संवर्धन के लिए आलू रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाए मक्का रिसर्च सेंटर भी खोला जाए मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक युवा कृषि वैज्ञानिक ने टिस्यू कल्चर पर आधारित एक प्रयोगशाला स्थापित की है, जिससे उसने कई उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन किया है ऐसे होनहार कृषि वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना भी लाई जाए ।

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Thank you for having allowed me to express my views on demand for grants for agriculture 2025-26. I remember a quote by legendary M A Swaminathan that says, 'If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right?'. For any country, the degree of economic progress is measured in terms of the progress that is made in agriculture. Our country started focusing more on this sector only after 2014, till then it was largely neglected. In

2025-26, Rs 1,37,757 crore has been allocated to the Ministry which is 2.7 percent of the Union Budget 2025-26. This is an increase of Rs 18934 crores from the actuals of 2023-24. Out of the total allocation to the Ministry, 92% is estimated to be spent by the Department of Agriculture and Farmers' Welfare while the remaining is estimated to be spent by the Department of Agricultural Research and Education. An increase of 3.1 percent has been given for agriculture research and education. The Department of Agriculture and Farmers' Welfare spends 77% of its budget on three major schemes: PM-Kisan Samman Nidhi (direct cash transfer of Rs 6,000 per year per farmer family), Modified Interest Subvention Scheme, and Crop Insurance Scheme. The actuals under PM KISAN for 2023-24 was Rs 61441 crores which is now increased to Rs 63500/crores under the Union Budget 2025-26.

This year's budget launched PM DHAN DHAANYA KRISHI YOJANA. We are very thankful for this. The scheme is being launched in partnership with states and estimates to cover 1.7 crore farmers. The scheme will target 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit access. I request Chikkaballapur district to be brought under this scheme.

Another unique feature of this year's Budget is National Mission on High Yielding Seeds: This mission focuses on: (i) ensuring commercial availability of more than 100 seed varieties, (ii) development and propagation of climate and pest resilient high yielding seeds, and (iii) strengthening research on high yielding seed varieties. Rs 100 crore has been allocated for 2025-26 under the mission.

My only request is to ensure that more research is done for production of drought resistant seeds. This will support food security in our country.

The enhanced limit under Kisan Credit Card is welcome. Today Loan limit under the Modified Interest Subvention Scheme will be increased from three lakh rupees to five lakh rupees.

A comprehensive programme for the promotion of production, efficient supply, processing, and remunerative prices for fruits and vegetables will be launched. The programme has been allocated Rs 500 crore for 2025-26. It will target formation and participation of Farmer Producer Organisations and Cooperatives across states. While various government initiatives such as Venture Capital Assistance (VCA), Equity Grant and Credit Guarantee Fund Scheme (EGCGS), NABARD Credit Guarantee, and the Agriculture Infrastructure Fund have played a pivotal role in supporting FPOs, these schemes primarily focus on governance, capacity building, and infrastructure development. However, a direct business fund for FPOs is still lacking, which limits their ability to scale operations and gain a substantial market share. This is something innovative that the government can do. There is also a greater need for promotion of floriculture in the country. My district Chikkaballapur can be the centre of floriculture in the country. My humble request to the Minister through you sir, is to help us make Chikkaballapur the centre of global floriculture industry. A new Mission for Aatmanirbharta in Pulses will be launched for a period of six years in this year's Budget. The Mission will aim at achieving self-sufficiency in pulses production through procurement of Tur, Urad, and Masoor. An allocation of Rs 1,000 crore has been made for this scheme for 2025-26. I request the Government's support for farmers of Karnataka under this Mission.

The agriculture ministry has so many unique features. Since 2015-16, the Ministry has utilised 90% of its allocated budget on an average. This performance has ensured that our farmers are adequately compensated

for production. My request to the opposition is to stop politicisation of agriculture. This is my sincere request.

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): Thank you very much for giving me an opportunity to express my views in the discussion on the demands for grants for the year 2025-26 for the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. I also thank our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, for giving me this opportunity to raise the issues of farmers on the floor of the House today.

As we all are aware, agriculture is the first engine for India's development journey and our Government is giving top priority for our farmers and sincerely working for their welfare according to their needs from time to time and has taken a number of steps from time to time and due to which our farmers are very much happy in the country.

The second thing is establishment of National Mission on High Yielding Seeds which is a welcome measure to increase the productivity of the items which the farmers produce.

The third thing is establishment of second gene bank with 10 lakh germplasm lines is a most welcome measure. It is to be noted here that almost three decades after the first National Gene Bank was set up in India, the establishment of a second such bank comprising a million germplasm lines will definitely achieve desired results for future food and nutritional security and provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources which is the need of the hour.

The fourth thing is Kisan Credit Card loan limit to be raised from Rs. 3 lakh to Rs. 5 lakh. I am happy to say that the move is aimed at providing support to the 7.7 crore farmers, fishers, and dairy producers who are beneficiaries of this program who are small and marginal farmers of our

country. I am also happy to note that under the new interest subsidy program, farmers can now borrow money of up to 75 lakh which may help them to raise their income levels also. This great move will help the applicants who have to be tenant farmers, owner-cultivators, sharecroppers, or members of joint liability or self-help organizations engaged in farming or other producer activities like fishing or animal husbandry.

Loans amounting to Rs. 72 lakh or less will in future not require collateral. The RBI has taken one of those steps in favour of making credit easy for farmers and this is a milestone of our Government.

The fifth thing is five- year mission for cotton productivity after careful consideration and to address the challenges of stagnant cotton productivity, the Government has announced a five-year Cotton Mission to increase cotton productivity especially extra-long staple varieties. Moreover, Science & Technology support will be provided to farmers under this Mission and the cotton farming will be more beneficial from this Mission.

Overall, one can say confidently that a slew of measures to spur Agricultural Growth and Productivity, thereby benefitting our Annadata have been taken to give desired results and to face the challenges in farming.

The sixth thing which I am happy to see that the Government's decision to establish a Makhana Board in Bihar, which will improve production, processing, value addition, and marketing of makhana as well as support the people engaged in these activities to be organized into Farmer Producer Organizations (FPOs) which will also provide handholding and training support to makhana farmers and also work to ensure they receive the benefits of all relevant Government schemes.

I am also confident that the Government will achieve the growth rate of more than five per cent in agriculture and in turn, it will benefit the farmers of our country particularly small and marginal farmers.

With these few words, conclude and support the same.

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): On behalf of the backbone of our country-our farmers demand amplify the urgent demand for agriculture to be placed at the core of our national agenda. Agriculture is not merely an occupation; it is the lifeline of India, sustaining over half our population, feeding 140 crore citizens, and driving our economy. Yet, the plight of our farmers-nationally and particularly in states like Tamil Nadu- reveals a story of neglect, despair, and broken promises.

Our Leader of Opposition, Shri Rahul Gandhi, has been a steadfast voice for farmers across India. He has consistently demanded a legal guarantee for Minimum Support Price (MSP) based on the Swaminathan Commission's C2+50 per cent formula, ensuring farmers receive a fair return for their toil.

He has called for comprehensive farm loan waivers to break the cycle of debt that has claimed countless lives. He has urged compensation and jobs for the kin of farmers who died during the protests against the repealed farm laws over 700 brave souls whose sacrifices this Government refuses to acknowledge. Just last month, in February 2025, Shri Gandhi reiterated these demands, accusing the Modi Government of laying "nails in the path of farmers" and betraying them for a decade. The Congress stands resolute behind these demands, and I echo them today in this august House.

But let me bring the focus to Tamil Nadu, where our farmers face unique and pressing grievances. The Cauvery water dispute remains an open

wound. Despite legal rulings, the failure to secure Tamil Nadu's rightful share of water from Karnataka has left our delta farmers especially in Thanjavur, Tiruvarur, and Nagapattinam-struggling to irrigate their fields. The Mettur Dam, a lifeline for the region, often runs dry due to delayed releases, pushing farmers into distress. In 2024 alone, samba paddy cultivation suffered as water shortages coincided with untimely rains, a double blow worsened by climate change.

Moreover, Tamil Nadu farmers have long demanded the establishment of a Cauvery Management Board with teeth-something promised but never delivered. The Central Government's apathy has emboldened vested interests, leaving our farmers to protest in vain. In Madurai and Trichy, they have raised their voices against corrupt procurement centres, where they are forced to pay illegal handling charges of Rs. 40 - Rs. 60 per bag. They demand CCTV surveillance and accountability, yet the response is silence. Add to this the steep fall in turmeric prices in Erode-down to Rs. 6,000 per quintal and the lack of subsidized fodder seeds during droughts, and you see a state of abandonment.

The crisis is national too. Rising input costs-fertilizers, seeds, fuel-have made farming unviable. Erratic weather devastates crops, yet crop insurance fails to deliver. MSP, promised for 23 crops, remains a mirage for most. As colleague Raja noted, it barely reaches 21 crops in practice. Farmers from Punjab to Tamil Nadu have marched Khanauri, Shambhu, Jantar Mantar-only to face barricades, tear gas, and now, eviction threats. This is not governance; it is oppression.

The Congress demands action. First, a legal MSP guarantee, as Shri Rahul Gandhi has championed, rooted in the Swaminathan formula. Second, a nationwide farm loan waiver to end the debt trap. Third, compensation and jobs for families of martyred farmers, as justice

delayed is justice denied. Fourth, a permanent commission to oversee these reforms. Fifth, massive investment in climate-resilient agriculture-irrigation, seed technology, extension services- -so farmers are not left to battle nature alone. For Tamil Nadu specifically, we demand the immediate constitution of a functional Cauvery Management Board, timely water releases, and fair procurement systems free of corruption.

The BJP claims Jai Jawan, Jai Kisan, but where is the 'jai' for our kisans? Budgets favour photo ops over fields; policies favour corporates over cultivators. Shri Rahul Gandhi has warned that those who betray farmers cannot be trusted. The Congress will not stand for this injustice. We will fight for every farmer's dignity, from the Cauvery delta to the Gangetic plains.

I urge this House to rise above politics and unite for agriculture. Let us honour the hands that feed us-nationally and in Tamil Nadu. Let their voices shape our laws and budgets. The time for promises is over-the time for action is now.

श्री नीरज मौर्य (आंवला) :

मैं उस इंसान की आवाज उठा रहा हूँ,

जिसके बिना ये देश दो वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता

भारत का किसान, जो धरती से अन्न उगाता है, लेकिन खुद भूखा सो जाता है ।

गाँधी जी कहते थे - "भारत की आत्मा गांवों में बसती है ।

लेकिन अफसोस, आज गांवों में सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और कर्ज का बोझ बसता है ।

हमने चाँद पर तिरंगा फहरा दिया,

मगर किसान के आँगन में अब भी अंधेरा है ।

ये कैसा 'अमृतकाल' है,

जहाँ किसान का बच्चा स्कूल छोड़ रहा है और किसान खुद खेत छोड़ रहा है?

देश में एक ओर उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो रहा है,

तो दूसरी ओर किसान महज 13,000 रुपये महीने की आमदनी में जीवन गुजार रहा है । किसान जो हर रोज धरती को सींचता है,

वो खुद आसमान की ओर देख कर बादलों से भीख माँग रहा है ।

सवाल यह है कि ये किसान कब तक सिर्फ 'जय जवान, जय किसान' के नारे पर जिंदा रहेगा?

इस बार का बजट देख लीजिए -

देश का पेट भरने वाले किसान पर बजट का मात्र 2.8% खर्च ।

और जब किसान सड़कों पर उतरता है, तो उसे 'आंदोलनजीवी' कहा जाता है ।

सरकार बताये -

क्या देश के अन्नदाता को दो वक्त की रोटी भी अब आंदोलन से मिलेगी?

आज खेती मुनाफे क्का नहीं, घाटे का धंधा बन गई है ।

क्योंकि डीजल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगे, लेकिन MSP वही पुरानी ।

ये कैसा 'डबल इंजन' है,

जहाँ किसान की लागत दोगुनी हो गई,

पर आमदनी आधी रह गई?

आप कहते हैं, किसान मजबूत होगा,

लेकिन मंडी में किसान अपनी मेहनत की फसल औने-पौने दाम में बेच रहा है ।

बिचौलियों की जेबें भर रही हैं और किसान का खून सूख रहा है ।

कृषि कानून लाकर किसानों की आवाज को दबाने का जो प्रयास हुआ,

वो इस सरकार की किसानों के प्रति असली सोच दिखाता है ।

प्रधानमंत्री जी जिस पूर्वाचल से आते हैं,

वहाँ किसान आज भी बारिश का इंतजार कर रहा है ।

आज भी आधे से ज्यादा खेत सिर्फ मानसून पर निर्भर हैं ।

सवाल:

क्या सिंचाई के नाम पर सिर्फ घोषणाएँ ही होती रहेंगी?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हाल देख लीजिए -

किसान को मुआवजा नहीं मिलता, मगर बीमा कंपनियों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है । क्या ये योजना किसानों की है या कॉरपोरेट घरानों की?

हर दिन किसान कर्ज में डूब कर जान दे रहा है ।

2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की ।

ये आंकड़ा नहीं, 11,000 घरों की टूटती दुनिया है ।

किसान पूछ रहा है -

क्या मेरी मौत से भी सस्ती कोई चीज़ है इस देश में?

क्या मेरी मेहनत सिर्फ चुनावी रैली में तालियाँ बटोरने के लिए है?

क्या मेरे हिस्से का पानी, बिजली और दाम सिर्फ घोषणाओं में रहेंगे?

आज इस सरकार से किसान सिर्फ सवाल नहीं, समाधान मांग रहा है:

MSP की कानूनी गारंटी दीजिए ।

स्ती सिंचाई और बिजली सुनिश्चित कीजिए ।

ऑनलाइन मंडी और भंडारण की सुविधा दीजिए ।

कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाइए ।

किसानों को कृषि तकनीक और सस्ता कर्ज दीजिए ।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को फास्ट ट्रैक मुआवजा दीजिए ।

अगर भारत का किसान रो रहा है, तो ये देश कभी 'विकसित भारत' नहीं बन पाएगा । आज ये किसान कह रहा है ?

"अब मैं सिर्फ अन्नदाता नहीं, बदलावदाता भी बनूँगा ।"

खेत उजड़े हैं, किसान तन्हा है,

नेताओं के वादों का बस दिखावा है ।

अन्नदाता का पेट खाली है साहब, और सत्ता में बैठों का पेट हमेशा भरा है ।

अब ये किसान वोट नहीं, इंसाफ माँग रहा है ।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : हमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रांधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान अपने बात रखने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

देश का अन्नदाता किसान, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वह दिन-रात मेहनत करके देश का पेट भरता है साथ ही ग्रामीण विकास और राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । बावजूद इसके आज देश का किसान बहुत परेशान है, किसानों की माली हालत खराब है कर्ज में दबा किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर है । देश के करीब 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं । देश के करीब 82% प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं ।

भारत की लगभग 55 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर निर्भर करती है । देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 18.2 प्रतिशत है और कुल रोजगार में 42 प्रतिशत का योगदान देता है । बावजूद इसके मौजूदा बजट में कृषि मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट का मात्र 2.7% प्रतिशत राशि ही आवंटित की गई है ।

सरकार का वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य था । आज 2025 चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है की नाबार्ड की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कृषि पर निर्भर रहने वाले किसानों की औसत आय प्रतिदिन 150 रुपए से भी कम हैं ।

ऐसे में आज की बढ़ती हुई महंगाई में किसान क्या खाएगा और क्या बोएगा । वह कैसे बीज, खाद, कृषि उपकरण, दवा और सिंचाई आदि की व्यवस्था करेगा । आज किसान कर्ज तले दबा हुआ है । ऐसा लगता है कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बजाय, किसानों को ही समाप्त करने पर तुली हुई है । महंगाई की मार झेल रहे किसानों के साथ सरकार छलावा कर रही है । कृषि में बढ़ती लागत और भगवान भरोसे पैदावार की वजह से युवा किसानों का कृषि से मोह भंग हो रहा है । वह शहरों की तरफ पलायन कर रहा है

मैं जिस संसदीय क्षेत्र से चुन कर आता हूं, उसमें दो जिले आते हैं श्रावस्ती और बलरामपुर । ये दोनों जिले हर मायने में बहुत ही पिछड़े हैं और उत्तर प्रदेश के कुल 8 अति पिछड़े आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं । अभी भी यहां के किसान ज्यादातर कच्चे मकानों व झोपड़पट्टी में रहते हैं । यहाँ राप्ती नदी में लगभग हर साल बाढ़ आती है, जिस कारण किसानों की हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो जाती है । किसानों को उनकी फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है । भूमिहीन किसान एवं कृषि पर आधारित मजदूरों के लिए उनकी जीविका के साधन की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए । फसलों की सही और उचित मूल्यों का निर्धारण की जाए । विशेष राहत पैकेज की व्यवस्था की जाए । जो महिलाएं पशुपालन और दूध उत्पादन का काम करती हैं, उनको सशक्त बनाने की जरूरत है । स्थानीय स्तर पर कृषि बाजार की उपलब्धता के साथ साथ किसान अपनी सब्जियों फलों को डायरेक्ट विदेशों में एक्सपोर्ट कर सके, इसकी पर्याप्त व्यवस्था और इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण करने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि किसानों का बकाया लोन माफ किया जाए । MSP गारंटी कानून लागू किया जाए । डीएपी खाद की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए । कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर आदि उपकरणों पर लगने वाले टैक्स पर 100% की छूट दी जानी चाहिए । फसलों की सिंचाई हेतु फ्री बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए । साथ ही लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने के साथ-साथ बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए । किसानों की आय को बढ़ाया जाए । किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर करीब 15000 प्रतिवर्ष की जानी चाहिए । प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु उचित मुआवजा देने के लिए विशेष राहत पैकेज की

व्यवस्था की जानी चाहिए । स्थानीय स्तर पर फसलों के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : मुझे कृषि मंत्रालय की वर्ष 2025-2026 की अनुपूरक मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद ।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को सत्ता पर काबिज हुए 10 साल हो गए हैं । पूरे जीवन में प्रधानमंत्री जी का संकल्प आम आदमी की तकलीफ को दूर करना रहा है और 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी का फोकस आजादी के बाद से पिछली सरकारों द्वारा कृषि के क्षेत्र में हुई दुर्गति को सुधारना रहा ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । यह न केवल देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है ।

हमारे केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई है । इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित खरीफ फसलों, बागवानी एवं फलों की खेती के लिए प्रीमियम दरों पर कोई भी निजी बीमा एजेंसी कार्य करने को इच्छुक नहीं है ।

इस कारण से हमारे क्षेत्र के किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है । महोदय किसानों के उत्थान और सशक्तीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन एवं विस्तार करने की आवश्यकता है ।

दादरा और नागर हवेली एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां अधिकांश किसान कृषि पर निर्भर हैं । लेकिन, कृषि से उनकी आय सीमित है । साथ ही, हमारे क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जिससे किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं । हालांकि कृषि मंत्रालय द्वारा कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वे अभी तक हमारे क्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई हैं । उन्हें तत्काल लागू करने का मैं अनुरोध करती हूँ । सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वे अभी तक हमारे क्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई हैं । उन्हें तत्काल लागू करने का अनुरोध करती हूँ ।

सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सोलर पंप एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की सुविधा किसानों को दी जाए, जिससे उन्हें सिंचाई की समस्या से राहत मिले । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सोलर पंप, ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिस्टम की सुविधा किसानों को दी जाए । वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) और जल संरक्षण परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए, ताकि सूखे की स्थिति में किसान प्रभावित न हों ।

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाने की आवश्यकता है । खाद एवं बीज पर सब्सिडी, किसानों को उन्नत किस्मों के बीज एवं खाद सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए जाएं । उन्नत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोपाई मशीन एवं अन्य उन्नत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की आवश्यकता है । सरकार उस तरफ भी ध्यान देगी, मुझे विश्वास है ।

किसानों को अच्छी किस्मों के फलदार पौधे एवं मोटे अनाज के उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएं । कृषि प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती, जल संरक्षण, एवं कृषि विपणन से संबंधित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । इस तरफ भी सरकार ध्यान देगी, मुझे पूरा विश्वास है ।

मैं आदिवासी बाहुल्य प्रदेश से आती हूँ, इसलिए आदिवासी किसानों को उनके कृषि उत्पादन एवं विपणन क्षमता को बढ़ाने हेतु विशेष सहायता दी जानी चाहिए । मोटे अनाज (रागी) की खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है । हमारे क्षेत्र में रागी की खेती बड़े पैमाने पर होती है, अतः इसके लिए विशेष सरकारी सहायता, विपणन सुविधाएं एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित किया जाएगा तो किसानों को लाभ मिल सकेगा । मोटे अनाजों के लिए विशेष प्रसंस्करण इकाइयां (Processing Units) स्थापित की जाएं, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके ।

किसानों के लिए सस्ते कृषि लोन एवं वित्तीय सहायता, किसानों को PM Kisan Samman Nidhi जैसी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक दिलाने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए जिसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी । इससे किसानों को लाभ मिलेगा ।

सस्ते ब्याज दरों पर कृषि ऋण (Kisan Credit Card KCC) एवं फसल उत्पादन हेतु कार्यशील पूंजी लोन की सुविधा को आसान बनाया जाए । आदिवासी किसानों के लिए विशेष सब्सिडी और वित्तीय सहायता पैकेज की व्यवस्था की जाए । उन्नत कृषि तकनीकों एवं वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण, मिट्टी परीक्षण (Soil Testing) की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसान अपनी मिट्टी के अनुसार उचित फसल का चयन कर सकें ।

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नियमित प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन हो, जिसमें किसानों को उन्नत बीज, जैविक खेती, मिश्रित खेती और अधिक उत्पादन वाली फसलों की जानकारी दी जाए । रागी और अन्य मोटे अनाजों की खेती के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि इनके उत्पादन और विपणन में वृद्धि हो ।

दादरा और नगर हवेली के किसान ग्रीन हाउस खेती के लिए भी प्रशिक्षण, सुविधाएं, सब्सिडी और जागरुकता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं । इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि दादरा नगर हवेली में ग्रीन हाउस खेती को बढ़ावा देने में मदद करे जिससे कि यहाँ के किसानों के फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो और वह किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सके । हमारा क्षेत्र कृषि पर अत्यधिक निर्भर होते हुए भी केंद्र सरकार की योजनाओं से पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पा रहा है । अतः हमारे किसानों के हित में उपरोक्त योजनाओं को दादरा और नगर हवेली में शीघ्र लागू करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने की कृपा करें । इससे हमारे आदिवासी किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी ।

सरकार के सहयोग के लिए मैं समस्त दादरा नगर हवेली वासियों के तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ ।

DR. C. N. MANJUNATH (BANGALORE RURAL) : Central Silk Board (CSB) is a statutory body created by an Act of Parliament, namely, The Central Silk Board Act, 1948 for the development of sericulture across the country. CSB through its Research & Development is catering to the needs of the sector working in co-ordination with Sericulture Departments of different States.

The Board of CSB has a total strength of 39 members, headed by a Chairperson appointed by Government of India, comprising Members of Parliament, officers of central and state governments and industry representatives as its other members. The Board is the highest body of CSB which deliberates and suggests policy interventions for the development of sericulture industry apart from considering other proposals required for the smooth functioning of CSB.

The position of Chairperson, CSB is lying vacant since August, 2019 and there is an urgent need to fill this vacancy. The presence of a dynamic Chairperson augurs well for the smooth and effective functioning of CSB.

Regarding strategy for utilization of Silk Waste, the fibrous waste which gets generated during the process of reeling and weaving is classified as silk waste which is used as raw material for production of value-added products like spun silk yarn, noil silk yarn, silk sheets etc. Currently, the domestic silk waste production is around 6000 MT. India once had its own capacity to utilise silk waste locally, but, as on date, only few spun silk mills are functioning. Silk waste is being exported in large quantities to China and value-added products are coming back to India. Reportedly, there are unfair trade practices in export of silk waste in the form of under invoicing and export of cocoons suitable for reeling as silk waste.

With a measure to support value addition locally, there is a need to support establishment of few spun silk mills along with imposing strict vigilance on export of silk waste to counter unfair trade practices.

Regarding according permission to the private agencies for augmenting the production of basic seed (P1), for accomplishing the envisaged target of production of 2800 lakhs of bivoltine commercial silkworm seed by 2030, around 51 lakhs of P1 basic seed is required. Currently, the production of P1 Disease Free Laying (DFLs) is carried out by the P1

grainages of National Silkworm Seed Organization (NSSO) and other State Government sericulture departments. However, the current in-built capacity of NSSO and state government P1 grainages together is hardly 20 lakhs of P1 basic seed.

Although the NSSO and a few State Governments are currently putting forth their commendable efforts to meet the demand for P1 DFLs, their limitations and the ever-increasing demand necessitate the participation of the private sector in P1 DFLs production. By leveraging the resources, expertise, and efficiency of the private sector, they can enhance the overall availability and accessibility of P1 DFLs to the commercial silkworm seed producers of both the Government and private agencies. Additionally, this approach would alleviate the burden on NSSO, allowing them to focus on upstream multiplication (P4 to P2) levels, while adhering meticulously to the procedures established by Japan International Cooperation Agency (JICA). In view of the above, permission may be accorded to any non-governmental agency which possess experience and expertise to handle basic seed and also enforcing stringent norms under the supervision of NSSO. Such an agency must ensure the maintenance of all the quality standards and willing to sell P1 DFLs on par with the government rates.

Regarding scheme for improving the soil health, Soil Organic Carbon (SOC) is a critical component of soil health and plays a vital role in the production of quality mulberry leaf. Its importance includes: Nutrient supply, Soil structure improvement, Water retention, Microbial activity, Buffering capacity and Climate resilience. Recent study indicates that SOC of mulberry gardens in Karnataka has depleted to 0.4 per cent very much below the optimum level of 1.0 per cent. Higher level of SOC in the mulberry gardens of Japan (1.8 per cent) and China (1.9 per cent) are producing good quality mulberry leaves and in turn resulting in superior

quality cocoons and raw silk. In order to overcome this, it is necessary to introduce some schemes to help farmers to improve their soil status

Regarding establishment of Silk Museum & Silk Tourism Corridor, with a production of around 38500 MT of raw silk per annum, India is the second largest producer of silk in the world. Indian Sericulture has a rich history of more than 200 years, being known for its exquisite craftsmanship and unique designs made using handlooms. Silk is an integral part of Indian culture and has a special place, especially amongst womenfolk. Karnataka is a pioneering State in sericulture with around 40 per cent of country's raw silk production coming from the State. Sericulture has a strong presence in the southern part of the State. The GI registered brand Mysore Silk given to sarees produced by Karnataka Silk Industries Corporation is quite popular. There is a scope and need for creating an infrastructure to showcase the rich history of Indian silk through establishment of a state-of-the-art Silk Museum. The proposed facility can also have place for carrying out different activities of silk value chain for visitors to see and an infrastructure for artisans to sell their products. The ideal location for creation of such an infrastructure can be in Bengaluru Mysore corridor, which is known for its big presence in sericulture. Also, few Silk Corridors / Silk Routes can be considered for creation in famous silk weaving clusters across the country clubbing them with tourist destinations present in and around.

Regarding formation of National Task Force, the formation of a national-level Task Force for monitoring sericulture is crucial to align the sector with India's Vision 2030 and 2047, focusing on sustainable growth and enhancing silk production productivity and quality. The sericulture sector involves multiple stakeholders, including farmers, Central agency, State agencies, scientists, private players, and policymakers. A Task Force will ensure better coordination among these entities, fostering synergies and

avoiding duplications in efforts to promote innovation, new technologies, and improved cultivation practices, to meet national goals. The Task Force can also help India tap into global knowledge by fostering Partnerships and collaborations, such as introducing Israeli agriculture technologies or promoting research into sustainable sericulture practices. It can guide efforts to customize international best practices to India's unique conditions. It would promote innovation, especially in Seri-Tech and smart farming, support climate resilience, and foster global collaborations, such as adopting Israeli agriculture technologies. Additionally, the Task Force would enhance India's export competitiveness by improving quality standards and pre-cocoon and post-cocoon practices, making sericulture a key driver of economic growth by 2030 and 2047.

Regarding establishment of Cold Storages for preservation of bivoltine eggs, to achieve a quantum leap in the production of internationally gradable bivoltine raw silk and make India self-sufficient, the key requirement is the large-scale production of high-quality, disease-free bivoltine silkworm seeds (eggs). Considering the envisaged target of production of 20,000 MT of gradable bivoltine raw silk in the country by 2030, the requirement of bivoltine commercial seed would be 2800 lakhs on a very conservative consideration against the current estimated production of 800 lakhs. That means the production has to be increased by 250%. While both State and Central Governments are engaged in seed production, they are unable to fully meet the domestic demand owing to manpower crunch and other reasons. Therefore, encouraging the private entrepreneurs for taking up large-scale bivoltine silkworm seed production is the need of hour. However, existing private players face challenges in scaling up due to the lack of adequate cold storage facilities, which are critical for preserving silkworm seeds for four to six

months, as recommended by best practices. To address this, there is an urgent need to establish four high-capacity cold storage units in strategically located areas in the southern region of the country. These facilities will ensure the preservation and availability of quality seeds year-round, facilitating consistent raw silk production and helping India become import-free in bivoltine silk.

Regarding establishment of cocoon markets under PPP model and introducing quality linked pricing system, although, the existing Government cocoon markets are facilitating the farmers with instant sale of their produce and realization of money on the very same day, auction system followed in those markets for fixing the rate does not reflect the cocoon quality in true sense and leads to unpredictable pricing. To encourage higher quality cocoon production, as followed in all the advanced countries like China, it is essential to introduce scientific quality linked pricing system (based on Renditta) in all the markets which will ensure, fair and transparent pricing and also minimizes market fluctuations. During the year 2015 the Government of Karnataka had constituted a 'Technical Committee to study the cocoon marketing system in Karnataka, the committee in its report, recommended implementation of cocoon quality testing and grading process for both crossbred and bivoltine cocoons and also provided testing guidelines in the form of a protocol. That 'Technical Committee' recommended a protocol to assess the quality from one kg of cocoons sample which is randomly taken from the cocoon lot arriving in the market, considering Defective Cocoons, Cocoon Weight, Shel Weight, Cocoon Shell Ratio and Estimated Renditta. Based on these quality parameters cocoon lots are graded as Grade-A, B and C and the cocoon rates could be fixed. Such a system could be introduced at every cocoon market involving a third party for cocoon assessment, under PPP model.

Regarding designation of Special Sericulture Zones, rapid urbanization and industrialization are threatening traditional mulberry cultivation areas, essential for silk production. For instance, Bangalore Rural district of Karnataka had an appreciable mulberry area of 22,682 hectares in 1997-98, which has declined to a bare 5,052 hectares during 2023-24. To address this, it is crucial to declare Special Sericulture Zones (SSZs), which would protect key agricultural land from being repurposed for non-agricultural activities. This approach will help safeguard the livelihoods of rural families dependent on sericulture, ensure a stable domestic supply of raw silk, and reduce dependency on imports. Additionally, preserving mulberry cultivation supports ecological balance and allows for the integration of modern technologies like IoT and Seri-Tech, fostering innovation and sustainable practices in the silk industry. Establishing SSZs is a strategic step towards securing silk production and promoting rural development.

Further, it is essential to declare Special Sericulture Zones (SSZs) and legally protect them from being repurposed for non-agricultural activities. Enforcing specific laws to ensure these zones are used exclusively for mulberry cultivation will preserve vital agricultural land, safeguard rural livelihoods, and secure the future of domestic silk production. This protection will also promote environmental sustainability, encourage innovation through technologies like IoT and Seri-Tech, and support the continued growth of the silk industry. Establishing and legally enforcing SZs is a critical step towards maintaining the balance between development and sericulture, ensuring the industry's long-term viability.

Regarding manpower crunch and need for filling up of the vacancies, retirement of scientists and other technical staff has created a large vacuum at Central Silk Board, KSSRDI, Thalaghatpura and DoS Karnataka. Central Silk Board's staff strength was reduced to 1897

during 2021-22 compared to 3275 during 2012-13. Every year more than 250 staff are retiring leading to restructuring of the existing units and resorting to multi-tasking. Similarly, against the sanctioned strength of 4299 posts, DoS Karnataka has only 1191 posts filled thus the vacancy is 3108 posts (72 per cent). At KSSRDI, Thalaghatpura against the scientists' sanctioned strength of 54 now it has only 14 scientists

Regarding leasing of unused infrastructure by DoS Karnataka, a substantial infrastructure, including Basic Seed Farms (BSFs), grainages and Cold Storages was established in the earlier years utilizing the funds provided by World Bank and other agencies. However, due to manpower shortage and other challenges, much of the infrastructure has become defunct and remains underutilized or totally unutilized. To revitalize these assets, they can be leased out to NGOs or other individuals through SAI, exclusively for undertaking sericulture related developmental activities.

Regarding coordination between CSB and State Sericulture Departments (DoSs), success of any program depends on the concerted efforts of all the agencies involved and their active participation. Progress of sericulture in any state and in turn in the country depends solely on the coordinated efforts of both Central Silk Board and respective DoSs. In the past there used be monthly bivoltine coordination committee meetings jointly held by DoS Karnataka and Central Silk Board which has ceased long back and that's why the bivoltine implementation programme is not running smoothly and the stakeholders are facing lot of problems. For successful implementation of bivoltine program, monthly bivoltine coordination committee meetings to be compulsorily attended by both State and CSB officers/ scientists, have to be revived with immediate effect

Regarding strengthening R and D, establishment of by-product laboratory, strengthening R&D in sericulture is crucial for enhanced productivity and sustainability, value addition through by-products and ensuring the industry's global competitiveness, through the following core ideas establishing an exclusive by-product institute under a Public-Private Partnership (PPP) model: A dedicated institute focused on developing innovative uses for silk byproducts from mulberry leaves, mulberry fruits, mulberry roots, pupae, moths, silkworm excreta, sericin, fibrion and silk fibre waste can significantly boost value addition. Through a PPP model, the government can provide infrastructure support, while private players bring in cutting-edge technologies and commercialization of strategies.

Collaborative Research Initiatives: Encourage collaborations between research institutions, universities, and industry leaders to work on high-impact research. This includes improving cocoon and silk yield, pest resistance in host plants, and water efficiency, while also exploring sustainable by-product processing methods that create economic value from sericulture waste.

Advanced Technological Integration: Introduce modern technologies like biotechnology, nanotechnology, and artificial intelligence in silk R&D. These can enhance cocoon and silk quality, optimize resource use, and create innovative byproducts like high-performance textile materials.

Innovation Hubs for Start-ups: Create innovation hubs within the by-product institute that foster start-ups and entrepreneurs focusing on silk processing and waste management. This could include incubators supported by industry mentorship and funding for start-ups developing silk-based eco-friendly products, medical products and cosmetics.

Policy Support and Incentives: Provide policy frameworks that encourage private sector investment in silk R&D under the PPP model. This could involve tax incentives for research initiatives, subsidies for R&D infrastructure development, and grants for innovations that enhance silk by-product utilization, ensuring the economic viability of the sector.

Regarding extending support to Soil to Silk Company, for the first time in India a Soil to Silk Company has been established at Bangalore having members of SAI as its advisors and shareholders. Intention is to strengthen the silk industry mobilizing its experienced manpower. It has planned few prolific projects like; Exposure of College Students to Sericulture Activities through seri-tourism, taking up the production of PI basic seed production to supplement the efforts of CSB and DoS. It also has many other developmental activities on its agenda. In the initial stages it requires financial, logical support and hand holding support from both CSB and DoS.

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान): महोदय, यह तरीका उचित नहीं है ।? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ । मैं उन सभी माननीय सदस्यों को भी, लगभग 22 माननीय सदस्य बोले हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ । ? (व्यवधान) उन सब ने अपने विचार व्यक्त किए हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो सकारात्मक सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं, उन पर पूरी गंभीरता से विचार होगा ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों, आप अपनी-अपनी स्पीच को ले-कर दीजिए ।

माननीय कृषि मंत्री जी ।

? (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : जो सकारात्मक सुझाव दिए हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक, मैं कृषि मंत्री के नाते सदन को आश्वस्त करता हूँ कि गंभीरता से विचार करेंगे ।? (व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं सोच रहा था कि प्रतिपक्ष के मित्र भी सार्थक चर्चा करेंगे ।

लोकतंत्र में संवाद, लोकतंत्र में बहस और लोकतंत्र में चर्चा सही अर्थों में लोकतंत्र के प्राण हैं ।? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह तो ठीक नहीं है । मैंने सभी माननीय सदस्यों को ध्यान से सुना है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृषि मंत्री जी, आप अपनी बात कहें ।

? (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : सभापति जी, इस टोका-टोकी में तो ठीक से बात ही नहीं कर पायेंगे ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृषि मंत्री जी, आप बोलिये । आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी । आप अपनी बात कहें।

? (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : महोदय, ?निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय ।? आलोचना का सदैव स्वागत है, लेकिन क्या आलोचना के लिए केवल आलोचना की जाएगी? ? (व्यवधान) क्या आलोचना में कोई तथ्य नहीं होंगे और क्या अपनी बात कहकर सरकार की बात नहीं सुनना चाहेंगे? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष का यह व्यवहार ठीक नहीं है ।? (व्यवधान) मैं एक-एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूं और हमारा यह अधिकार भी है ।? (व्यवधान) यहां कई तरह के आरोप लगाए गए हैं । ऐसे में तो बोल ही नहीं पायेंगे ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृषि मंत्री जी, आपको बोलना होगा ।

? (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : महोदय, मुझे बोलने में मजा नहीं आ रहा है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय कृषि मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए । आप बोलिये । आप हमें एड्रेस कीजिए और सारे सवालों का जवाब दीजिए । आप उधर मत देखिये ।

? (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : महोदय, मुझे इस टोका-टोकी में बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं साफ दिल का इंसान हूँ ।? (व्यवधान) मैं जो कहता हूँ, दिल से कहता हूँ और अंतरात्मा से कहता हूँ ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : हनुमान बेनिवाल जी, आप जानते हैं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं और आप वरिष्ठ सदस्य हैं । आप पहली बार चुनकर नहीं आये हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : गिलोटिन का टाइम 6 बजे है और वह समय बदलता नहीं है । वह 6 बजे मुकर्रर है। सभी दलों के सदस्य बोल चुके हैं । समाजवादी पार्टी के भी सदस्य बोल चुके हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह तरीका ठीक नहीं है । सदन ऐसे नहीं चलता है । क्या आपका सदन में यह तरीका सही है?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय कृषि मंत्री, आप बोलिये ।

? (व्यवधान)

-

17.00 hrs

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि ये मेरे उत्तर को सुनने से घबरा रहे हैं, इसलिए ये मुझे नहीं बोलने देना चाहते हैं । मैं कांग्रेस सहित सभी प्रतिपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि इनका किसान कल्याण का लक्ष्य कभी नहीं रहा ।

17.0^{1/2} hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ । कृषि मंत्रालय संभालने के बाद? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए । ऐसे नहीं चलता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए । मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ।

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : सर, हमें दो मिनट बोलने का समय दीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए । इस तरह से डिबेट नहीं करते हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभी को पर्याप्त मौका और पर्याप्त समय मिलता है । हमारे पास पर्याप्त समय भी था और पर्याप्त मौका भी था ।

? (व्यवधान)

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल: सर, हमें बोलने का मौका ही नहीं मिला ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप बैठिए । डिबेट नहीं करते हैं । आप व्यवस्था को समझें । हम समय बढ़ा सकते थे, हम आपका आग्रह भी स्वीकार करते, लेकिन तीन दिन पहले ही आज 6 बजे गिलोटिन की प्रक्रिया निर्धारित हो चुकी है । जब गिलोटीन की व्यवस्था निर्धारित हो जाती है, तो फिर समय नहीं बढ़ाया जाता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको मंडे को मौका दूँगा । मैं आप सबको शून्यकाल के दौरान बोलने का मौका दूँगा ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बजट पर ही अपनी बात बोल लीजिएगा ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए । अगर आप व्यवस्था के तहत सुनिए ।

आपके दल के पास 17 मिनट का समय था, लेकिन आपको 26 मिनट का समय दिया गया ।

? (व्यवधान)

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल: हमें इस विषय पर एक मिनट भी बोलने का समय नहीं मिला ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : समय दल को मिलता है, सदस्य को नहीं मिलता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय शिवराज जी, आप बोलिए ।

17.03 hrs

*At this stage, Shri Naresh Chandra, Uttam Patel
and some other hon. Members left the House.*

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता था कि विपक्ष कोई सार्थक चर्चा करेगा और उनको किसानों की चिंता होगी । लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी बहस सुनी और खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वह भी मरी हुई । हम पर आरोप लगाये गये । आरोपों का भी स्वागत है और आलोचनाओं का भी स्वागत है । लेकिन क्या आलोचना केवल आलोचना के लिए ही की जाएगी? क्या आलोचना में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाएगा? महोदय, यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की जमीनें छीनना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं । यह भी कहा गया कि हम लाठियाँ बरसाना चाहते हैं, किसानों को ज़बरदस्ती उठाना चाहते हैं ।

महोदय, पंजाब के किसान संगठनों से चर्चा करने के लिए एक बार नहीं, बल्कि तीन बार तीन-तीन मंत्री गए । हमने विनम्रतापूर्वक चर्चा की । कई तथ्यों पर बात हुई और अगली चर्चा की तिथि भी तय हुई । लेकिन मेरे परम मित्र जय प्रकाश जी कह रहे थे, उसके बाद एक और साथी बोले कि वे तो गए ही इसलिए थे कि वे जाएं और आ जाएं, तो पकड़कर ले जाएं ।

अब आपकी और उनकी दोस्ती है, हमारे दोस्त नहीं थे क्या कभी? लोक सभा चुनाव तक आपके गले में बहियां कौन डालते थे, मेरे मित्र? ? (व्यवधान) आप और वे साथ-साथ थे और आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसानों की बात कर रहे हैं? मैंने कृषि मंत्रालय संभालने के बाद, लाल किले की प्राचीर से दिए गए सारे प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने । ? (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता था कि किसानों और खेती के बारे में किस प्रधानमंत्री जी ने क्या-क्या बातें कही हैं? ? (व्यवधान) मुझे जानकार आश्चर्य हुआ, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन किसानों के मामले में वर्ष 1949 से लेकर वर्ष 1963 तक वे केवल तीन बार बोले, बाकी वर्षों में कभी किसान का नाम ही नहीं लिया । ? (व्यवधान) स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ? (व्यवधान) किसान की चर्चा होती, तो लाल किले की प्राचीर से नाम लेते । ? (व्यवधान) लेकिन, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में छः बार, वर्ष 2015 में 23 बार, वर्ष 2016 में 31 बार, वर्ष 2017 में 20 बार, वर्ष 2018 में 17 बार, वर्ष 2019 में 17 बार और वर्ष 2020 में किसान, किसान, किसान, किसान का नाम लिया । ? (व्यवधान) किसान का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है, भारतीय जनता पार्टी के खून में है । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लाठियों की बात कर रहे हैं । ? (व्यवधान) मैं यह बताना चाहता हूं । ? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लाठी-गोली की बात कर रहे हैं, तो सुन लें, बिहार में वर्ष 1986 में कांग्रेस की सरकार थी । ? (व्यवधान) एक आंदोलन के दौरान किसानों पर गोलीबारी हुई, 23 किसानों की मृत्यु हो गई । ? (व्यवधान)

नई दिल्ली में वर्ष 1988 में कांग्रेस की सरकार थी । ? (व्यवधान) 31 अक्टूबर, 1988 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, अपनी मांगों को लेकर किसान जनपथ पर धरना दे रहे थे । ? (व्यवधान) कार्यक्रम खराब न हो जाए, इसलिए लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई, दो किसानों ने अपनी जान गंवा दी । ? (व्यवधान) ये हमसे बात करते हैं? ? (व्यवधान) उत्तर प्रदेश, साल 1988, मेरठ, श्री एन. डी. तिवारी जी मुख्यमंत्री थे । ? (व्यवधान) गोलीबारी हुई, पांच किसान, मैं पूरी सूची दे सकता हूं । ? (व्यवधान) इसलिए, ऐसे तथ्य रखने का प्रयास न करें । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है । ? (व्यवधान) महोदय, किसान अन्नदाता है और अन्नदाता जीवनदाता होता है । ? (व्यवधान) मैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को प्रोटैक्ट करता हूँ, किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है । ? (व्यवधान) उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे । ? (व्यवधान) मैं तथ्य बताता हूँ, आप बजट की बात कर रहे थे । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह बजट रखा हुआ है । ? (व्यवधान) दस साल, वर्ष 2004 से वर्ष 2014 का बजट देख लीजिए । ? (व्यवधान) बजट में वर्ष 2004-05 में कितना प्रावधान था? 4,767 करोड़ रुपए, फिर, 6,531 करोड़ रुपए । ? (व्यवधान) कुलमिलाकर, दस सालों में कांग्रेस ने जो दस बजट प्रस्तुत किए थे, उनमें 1,51,277 करोड़ रुपए का कुल बजट का प्रावधान था । ? (व्यवधान) यह एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । ? (व्यवधान) मुझे कहते हुए गर्व है, आपने 1,51,277 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि हमने 10,00,756 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था । ? (व्यवधान) यह तो केवल कृषि का बजट है । ? (व्यवधान) एलाइड सैक्टर को और देख लीजिए । ? (व्यवधान) ये मेरे पास प्रमाणित आंकड़े हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सबको सुना है । ? (व्यवधान) अब जवाब देने का अधिकार तो मेरा है । ? (व्यवधान) इसलिए, आप कृपया करके सुन लें । ? (व्यवधान) डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बैंड्री में आपने दस सालों में 15,544 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि हमने 43,425 करोड़ रुपए खर्च किए । ? (व्यवधान)

महोदय, मेरे पास आंकड़े हैं । यहाँ परसेंटेज की बात हो रही थी । आप धैर्यपूर्वक सच सुनिए । वर्ष 2013-14 में आपने बजट प्रस्तुत किया था, उसमें केवल 1.66 परसेंट कृषि पर प्रावधान आपने किया था । आप हमारी बात करते हैं, हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और ।

महोदय, यह नहीं चलेगा । मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और बाकी फिशरीज, अगर ये सारे बजट मिला लें तो कांग्रेस, यूपीए की सरकार से कई गुना ज्यादा राशि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने खर्च करने का काम किया है । हमारी प्रतिबद्धता है । ? (व्यवधान)

महोदय, हमारी प्रतिबद्धता है ।? (व्यवधान) हमारी प्रतिबद्धता है ।? (व्यवधान) अब आप सुन तो लें ।? (व्यवधान)

महोदय, अगर लीडर विजनरी हो, जनसेवा और देश की सेवा लक्ष्य हो और उस लक्ष्य की पूर्ति का संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करने के लिए रोडमैप बनाया जाए और उस रोडमैप पर दिन और रात परिश्रम करके चला जाए तो चमत्कार होता है और यह चमत्कार नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है ।

महोदय, अगर आप उत्पादन में देखेंगे तो मैं ?मोदी सूत्र? आपको बताता हूँ । यह आज का भारत है । यह नया भारत है । एक जमाना था, तब हम अमेरिका का पीएल-480 जैसा गेहूँ खाने को विवश थे, लेकिन आज अन्न के भण्डार भरे हुए हैं और 80 करोड़ भारतवासियों को, यूरोप की कुल आबादी 50 करोड़ है, अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, यूरोप और अमेरिका दोनों को मिलाकर 80 करोड़ की आबादी होती है, अकेले 80 करोड़ को नरेन्द्र मोदी जी फ्री में गेहूँ और चावल दे रहे हैं ।? (व्यवधान) मैं किसानों को प्रणाम करता हूँ ।? (व्यवधान) मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ ।? (व्यवधान)

महोदय, लगातार उत्पादन बढ़ रहा है ।? (व्यवधान) आप प्रोडक्शन देख लीजिए ।? (व्यवधान) ये मोदी जी की नीतियाँ हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ हैं ।? (व्यवधान)

महोदय, वर्ष 2013-14 में फूडग्रेन का प्रोडक्शन 265.05 मिलियन टन था, यह अब बढ़कर 330.92 मिलियन टन हो गया है ।? (व्यवधान) हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन 277 मिलियन टन से बढ़कर 362.08 मिलियन टन हो गया है । आप गेहूँ को देख लीजिए, आप चावल देख लीजिए, आप ज्वार देख लीजिए । अन्न का उत्पादन, फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है और केवल उत्पादन ही नहीं, उत्पादकता भी बढ़ रही है । जब वर्ष 2013-14 तक यूपीए की सरकार थी, उस समय गेहूँ का उत्पादन 2,416 किलो प्रति हेक्टेयर होता था, अब वह बढ़कर 2,859 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है । मेरे पास एक-एक आंकड़ा है कि उत्पादन बढ़ा है ।? (व्यवधान) उत्पादन बढ़ भी रहा है ।? (व्यवधान)

महोदय, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोची, समझी रणनीति है, ?मोदी सूत्र? है । अगर किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाना है और हमारे

प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा किसान अन्नदाता है, उनका विकास ही देश का विकास है । प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की समृद्धि से ही गाँव की समृद्धि होगी और गाँव की समृद्धि से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और जब किसान मजबूत होगा तो भारत समृद्ध होगा । उसी किसान को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने का काम हो रहा है । उत्पादन बढ़ाने के एक नहीं अनेक प्रयास किए गए हैं । बीज की नई किस्में जारी की गई हैं । पिछले 10 सालों में बीजों की 2,900 नई किस्में जारी की गई हैं । ये बीज जलवायु अनुकूल हैं । ये बीज रोग-प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं । इनमें से कई बीज बायोफोर्टिफाइड हैं ।

महोदय, केवल ये बीज ही नहीं, अभी जल शक्ति विभाग के बजट पर यहाँ चर्चा हो रही थी, नरेन्द्र मोदी जी का विजन है, उन्होंने तय किया कि पानी के बिना खेती में उत्पादन नहीं बढ़ेगा, रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून ।

महोदय, सिंचाई की व्यवस्था, रीवर लिंगिंग प्रोग्राम] अटल जी के नदी जोड़ों के संकल्प को पूरा करने का काम भी यदि किसी ने किया है तो नरेन्द्र मोदी जी ने किया है । पानी का बेहतर उपयोग कैसे होना चाहिए इसके लिए ?पर ड्रॉप, मोर क्रॉप? की कल्पना भी भारत में पहले नहीं हुई । यह कल्पना भी किसी ने की तो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की और एक-एक बूंद से अधिक उत्पादन तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी । इतना ही नहीं, जब तक यूपीए, प्रतिपक्ष की सरकार थी, वह कभी किसान और खेती की गहराई में नहीं गई । किसानों को पता ही नहीं होता था कि वे जिस खेत में खेती कर रहे हैं, उस मिट्टी में कौन-से पोषक तत्व हैं और कौन-से पोषक नहीं हैं । यह तो तब पता होता जब दिल में गहराई से किसानों की हालत ठीक करने की तड़प होती है । जिन्होंने कभी खेत नहीं देखे, खेत की गलियां नहीं देखीं, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखीं, खेत की पगडंडियां नहीं देखीं, जिन्हें पता ही नहीं है कि मिर्ची ऊपर की तरफ लगती है या नीचे की तरफ लगती है, ऐसे लोग आज किसानों की बात कर रहे थे ।

अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने तय किया कि हर किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण कराया जाएगा और सोइल हेल्थ कार्ड योजना बनाई । वर्ष 2022-23 में 42 हजार सोइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए । वर्ष 2023-24 में 40 लाख जारी किए गए । वर्ष 2024-25 में 36 लाख जारी किए गए, आपने तो यह तक नहीं बताया कि मिट्टी में क्या

है? आदमी में पहले से यदि कैल्शियम है और उसे कैल्शियम की रोज गोली खिला दो, तो क्या उसका स्वास्थ्य ठीक होगा? आज प्रधान मंत्री जी ने तय किया तो उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने का काम हो रहा है। यह बात भी हो रही थी कि कृषि में निवेश के लिए पैसा कहाँ है? मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पर क्रेडिट वर्ष 2014-15 तक केवल 8,45,000 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2023-24 में 25,49,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह निवेश खेती में किया गया। पहले जो अल्पकालिक ऋण 6.35 लाख करोड़ रुपये का था, वह बढ़कर 15.08 लाख करोड़ हो गया। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि छोटे और सीमांत किसानों की ऋण खातों में भागीदारी 58 परसेंट थी, जो बढ़कर 76.45 परसेंट हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि किसानों का उत्पादन बढ़ाना है तो कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ेगी। बंगाल की माननीय सदस्या कह रही थीं कि किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है। किसान के पास कृषि यंत्र नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के अंतर्गत कृषि यंत्रों की व्यवस्था छोटे किसानों के लिए भी सब्सिडी पर हो जाए, इसका प्रबंध किया गया और 18,16,221 छोटी-बड़ी मशीनें किसानों को प्रदान करने का काम हुआ है। मैक्नाइजेशन के काम में भी प्रधान मंत्री जी ने लगातार चिंता की है और उत्पादन की लागत घटाने का काम भी हुआ है।

महोदय, हमारे यहां खेती की जोत के आकार छोटे-छोटे हैं। लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं। उनके पास निवेश के उतने पैसे नहीं होते थे। कांग्रेस ने भी अपने वर्ष 2009 के घोषणा पत्र में कई तरह के वायदे किए थे कि प्रत्यक्ष सहायता दी जाएगी और इसका अनुमान लगाएंगे। ये अनुमान लगाते रहे और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना बना दी। बड़ी बात हो रही थी कि 60 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए जाएंगे। 60 साल के शासन में 60 हजार करोड़ रुपये की बात की गई, लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में सीधे पहुंचाए गए।

अध्यक्ष जी, एक सम्माननीय प्रधान मंत्री हुए थे, जो कहते थे कि मैं क्या करूँ। मैं एक रुपया भेजता हूँ तो केवल 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं लेकिन मोदी जी मजबूर प्रधान मंत्री नहीं हैं, मजबूत प्रधान मंत्री हैं। वे एक रुपया खाते में डालते हैं, तो एक रुपया ही पहुंचता है। यदि वे छह हजार रुपये डालते हैं तो छह हजार रुपये ही पहुंचते हैं और वह भी डीबीटी के माध्यम से ऐसे पहुंचते हैं कि इधर क्लिक किया और उधर पैसे पहुंच गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बिहार के हमारे मित्र बैठे हैं। अभी भागलपुर में, गिरिराज जी भी मंच पर थे, हम लोग मंच पर बैठे थे, प्रधानमंत्री जी ने एक क्लिक किया और वहां किसान ने मोबाइल दिखा कर कह कि ?आ गया, आ गया, आ गया।? यह चमत्कार हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिन्दगी बदलने का काम किया है। केवल इतना ही नहीं, हमने उत्पादन की लागत घटाने के लिए कदम उठाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी की बात करना चाहता हूं। पहले फर्टिलाइज़र पर कितनी सब्सिडी मिलती थी? वे इसके बारे में बहुत बातें कह रहे थे कि खाद महंगा हो गया है, खाद की कीमत बढ़ गयी है। वर्ष 2013-14 तक फर्टिलाइज़र की कुल सब्सिडी 71,280 करोड़ रुपये थी। आपकी सरकार में यह 71,280 करोड़ रुपये थी और जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो यह उर्वरक सब्सिडी बढ़ते-बढ़ते वर्ष 2022-23 तक 2,54,799 करोड़ रुपये हो गयी।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वे खाद की कीमत के बारे में बात कर रहे थे, वे धैर्यपूर्वक सुन लें, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2010-11 में डीएपी की बैग 507 रुपये में मिलती थी। उस समय यूपीए की सरकार थी। वर्ष 2011 में इन्होंने इसे बढ़ाकर 827.46 रुपये प्रति बोरी कर दी। इसे उन्होंने बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया, यूपीए की सरकार ने बढ़ाया।? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे देश के किसान सुन लें, यह यूपीए की ही सरकार थी, जिसने वर्ष 2012-13 में बढ़ाकर डीएपी की बोरी की कीमत 1315 रुपये कर दी। खाद की कीमत किसने बढ़ायी? क्या खाद की कीमत हमने बढ़ायी?? (व्यवधान) आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने तय किया कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में चाहे खाद की कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं, पर हमारे किसानों के लिए खाद की कीमत नहीं बढ़ेगी। मंत्रिमंडल के हमारे अनेक मित्र यहां बैठे हैं, हमने बस एक बार नहीं, बल्कि तीन-तीन बार स्पेशल पैकेज किसानों को दिए। हमने तय किया कि हम किसानों को डीएपी की एक बोरी को 1350 रुपये में ही देंगे और किसानों को एक नया पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा।? (व्यवधान) यह किसने किया?

आप बढ़ाते थे । पर, हमने तय किया कि इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी ।? (व्यवधान) ये, हर साल कीमत बढ़ाने वाले, ये हमसे बात कर रहे हैं ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 1350 रुपये प्रति बैग डीएपी दे रहे हैं और 266 रुपये में अगर यूरिया का एक बैग किसानों को कोई दे रहा है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार दे रही है । हमने इसमें एक पैसा भी बढ़ने नहीं दिया । इसलिए उर्वरक पर लगातार सब्सिडी बढ़ती चली गयी । जैसा मैंने कहा कि 2,54,000 करोड़ रुपये तक एक साल में सब्सिडी देने का काम किया है और यह मोदी जी का वचन है, कमिटमेंट है कि हम किसानों को किसी भी कीमत पर महंगी खाद नहीं खरीदने देंगे । हमने उत्पादन की लागत घटाने के लिए कदम उठाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना बनी । किसानों के लिए यह योजना बुढ़ापे का सहारा बन रही है, ताकि बुढ़ापे में उन्हें हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिल सके । 10,000 किसान उत्पादक संगठन बने और उन एफ.पी.ओज़. में से कई एफ.पी.ओज़. बेहतर काम कर रहे हैं । समय के अभाव में मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा ।

महोदय, हमने ई-एन.ए.एम. जैसे कृषि बाजार की व्यवस्था की, ताकि एक स्थान पर बैठे-बैठे किसान यह पता कर ले कि दूसरे शहरों में चीज़ों के दाम कितने हैं और वह ऑनलाइन ही अपना व्यापार कर सके और ठीक दाम और लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की बात हो रही थी । मैं इस पर भी चर्चा करना चाहता हूँ । कांग्रेस पार्टी किस मुँह से ?50 प्रतिशत प्रॉफिट? की बात करती है? जब स्वामीनाथन आयोग ने यह बात कही तो मेरे पास इनका कैबिनेट नोट है ।

महोदय, इन्होंने एफिडेविट दिया और यह कहा कि किसी भी कीमत पर 50 पर्सेंट लागत पर मुनाफा जोड़ कर एमएसपी नहीं दी जा सकती है । उस समय के एक-एक नहीं, तीन-तीन मंत्रियों ने - कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय श्रीमान शरद पवार जी, के.वी. थॉमस जी, हरेक के जवाब सदन में हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 में यूपीए की सरकार की कैबिनेट में यह कहा जाता है, काउंटर प्रोडक्टिविटी का हवाला देते हुए,

स्वामिनाथन आयोग की इस प्रमुख सिफारिश को खारिज कर दिया जाता है और तर्क दिया कि यह बाजार को विकृत कर देगा । ? (व्यवधान) बाजार को विकृत को देगा? किसान को पैसा मिलेगा तो बाज़ार विकृत हो जाएगा? आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि लागत पर 50 पर्सेंट मुनाफा दे कर, वर्ष 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह चमत्कार किया कि लागत पर 50 पर्सेंट मुनाफा घोषित कर के ही एमएसपी दी जाएगी । ? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यूपीए का और कांग्रेस का सच उजागर करना चाहता हूँ । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, एक मिनट आपको रोकता हूँ ।

जय प्रकाश जी, यह सदन है । आपने अपना भाषण बोल लिया न? हर विषय पर बोलना ठीक नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आपका गलत तरीका है । बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सच है वह मैं कहूंगा । विनम्रता के साथ कहूंगा, लेकिन दृढ़तापूर्वक कहूंगा । आज मैं इस सच को उजागर करना चाहता हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी, धान पर एमएसपी ए2 प्लस एफएल लागत थी 961 रुपये, और इन्होंने एमएसपी 1310 रुपये घोषित की, केवल 36 पर्सेंट मुनाफा मिला । ज्वार पर केवल 18 पर्सेंट, रागी पर केवल 12 पर्सेंट, मूंग पर केवल 19 पर्सेंट दिया । लेकिन यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो कम से कम 50 पर्सेंट लागत पर जोड़ कर लाभकारी मूल्य देने का काम करती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीदी की बात भी ये देख लें । खरीदी पर अभी काफी बात हुई कि किसने कितना खरीदा, ये आंकड़े गवाह हैं । महोदय, मैं एक-एक फसल की एमएसपी पढ़ कर आपका समय नहीं लेना चाहता । लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यह मेरे पास सरकारी खरीद के कागज़ हैं । ये लोग कहते हैं कि एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही है, खरीदी नहीं हो रही है, खरीदी नहीं हो रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, धान, वर्ष 2004-2014 तक खरीदी गई केवल 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन और हमने खरीदी 75 करोड़ 74 लाख मीट्रिक टन । यह मोदी सरकार ने खरीदने का काम

किया । गेहूं ? इन्होंने खरीदे 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन और हमने खरीदे 30 करोड़ 57 लाख मीट्रिक टन। दलहन की बात की जा रही थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 6 लाख 29 हजार मीट्रिक टन वर्ष 2004 से 2014 तक खरीदी की गई और मुझे बताते हुए गर्व है कि एक करोड़ 72 लाख मीट्रिक टन अगर दलहन खरीदा तो इस सरकार ने खरीदने का काम किया है । इन्होंने तिलहन 47 लाख मीट्रिक टन खरीदा, हमने एक करोड़ 21 लाख मीट्रिक टन खरीदा । वाणिज्यिक फसलें आपने 45 मीट्रिक टन खरीदीं, हमने 63 लाख 81 हजार मीट्रिक टन खरीदी । अगर ओवरऑल देखें तो 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन इन्होंने खरीदी । 110 करोड़ 46 लाख मीट्रिक टन मोदी जी की सरकार ने खरीदने का चमत्कार किया है । इसको अगर रुपयों में परिवर्तित करें तो दस सालों में आपने धान की चार लाख 44 हजार करोड़ की खरीदी की । हमने 14 लाख आठ हजार करोड़ रुपये की खरीदी की । महोदय, इन्होंने गेहूं दो लाख 56 हजार रुपये का खरीदा, हमने पांच लाख 65 हजार करोड़ रुपये का खरीदा । इन्होंने 1900 करोड़ रुपये का दलहन खरीदा, हमने 93 हजार करोड़ रुपये का खरीदा । इन्होंने नौ हजार करोड़ रुपये का तिलहन खरीदा, हमने 62 हजार करोड़ रुपये का खरीदा । माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ें गवाह हैं कि ओवरऑल सात लाख 41 हजार करोड़ रुपये की खरीदी इनके दस सालों में हुई । लेकिन हमने 22 लाख 38 हजार करोड़ रुपये की खरीदी कर के दिखाई है । इतना कौन खरीदता है?

अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर भी अगर ठीक दाम देने का और खरीदने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया ।

केवल इतना ही नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी किसान को ठीक दाम मिले, इसके लिए हमने पीएम आशा योजना बनायी । पीएम आशा योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि जो अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की फसलें हैं, पहले तिलहन की कितनी फसलें खरीदी जाती थी? अभी महाराष्ट्र की बात हो रही थी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में पहली बार अगर किसी ने 19 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन खरीदने का चमत्कार किया है तो इस सरकार ने किया है । हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल महाराष्ट्र में नहीं दिया, बल्कि हमने कर्नाटक में भी खरीदा है । कर्नाटक में भी सोयाबीन खरीदा गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर 18 लाख मीट्रिक टन मूंगफली खरीदी गई है तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने खरीदी है । ? (व्यवधान) चाहे कोई भी राज्य हो, हमने उनके साथ भेदभाव नहीं किया । अगर कर्नाटक ने कहा कि खरीदी की समय सीमा हमारे लिए बढ़ाए तो हमने कर्नाटक के लिए भी बढ़ाई है । अगर महाराष्ट्र ने कहा तो महाराष्ट्र के लिए भी बढ़ाई है । ? (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से आश्चस्त करना चाहता हूं कि किसानों को लाभकारी मूल्य और एमएसपी देने में मोदी जी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको सुनना चाहिए । मैं जो कहता हूं, सच ही कहता हूं और सच के सिवाये कुछ नहीं कहता हूं । मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं कि इनको खरीदा गया । इसके बाद आप प्याज की बात कर रहे थे । मैं यह कह रहा हूं कि पूरे देश में पहली बार 20 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदने का काम मोदी सरकार ने किया है । पहले क्या इनकी सरकार में इतनी खरीदी की गई थी ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, टमाटर, प्याज और आलू जैसी चीजें जो जल्दी खराब होती हैं, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहता हूं । हमने बाजार हस्तक्षेप योजना बनायी । पीएम आशा योजना के तहत यह तय किया कि अगर इन फसलों के बाजार भाव 10 प्रतिशत से ज्यादा गिर जाते हैं तो हम बाजार में हस्तक्षेप करेंगे और जो कुल उत्पादन है, उसका 25 परसेंट खरीदने का तत्काल फैसला करेंगे । उसमें जो घाटा होगा, राज्य और केंद्र 50-50 परसेंट के आधार पर उसको सहन करने का काम करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आलू, प्याज और टमाटर की बात करना चाहूंगा । राज्य कृषि का विषय है । इसे हम राज्यों के माध्यम से ही खरीदते हैं । राज्य सरकार हमको लिखती है और अनुमति मांगती है तो केंद्र सरकार उनको अनुमति देती है । ठीक दाम की अनुमति देने में हम कोई कोताही नहीं करेंगे । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी टमाटर की खेती करता हूं । मेरे मित्र, भाव पूछने की बात मुझसे मत कीजिए । मैं खालिस किसान हूं । ? (व्यवधान) अभी आंध्र प्रदेश में हरी मिर्च का दाम कम हो गया । वहां के मुख्यमंत्री जी आए । हमने उनसे चर्चा की और फिर यह तय किया कि 11,781 रुपये प्रति किंटल पर मिर्च खरीदने का काम किया जाएगा । इससे बाजार भी स्थिर हुआ । 12,000 रुपये प्रति किंटल के ऊपर दाम

चला गया । मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी जरूरत पड़ती है, हम फैसला करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक और फैसला किया । अभी एक बात आई थी । उस पर मैं गंभीरता पूर्वक चर्चा करना चाहता हूँ । अगर आप वास्तव में किसानों का हित चाहते हैं तो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ । हम कई बार देखते हैं कि किसानों को अपने गांवों में, अपने आसपास के शहर में दाम ठीक नहीं मिलते हैं, लेकिन वही उत्पादन बड़े शहरों में चला जाता है तो सामान महंगा बिकता है ।

बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत एक नई योजना अभी-अभी बनाई, जिसमें हमने तय किया कि अगर किसान नैफेड या राज्य की एजेंसी के माध्यम से अपने ऐसे उत्पादन को मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में ले जाना चाहेगा, तो परिवहन के लिए जो लागत आएगी, वह पूरी की पूरी केन्द्र सरकार वहन करने का काम करेगी । हमने मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को इसकी मंजूरी देने का काम भी किया है । यह फैसला अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने किया है । ?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, यह फेयर नहीं है । इनको पूरी बात सुननी चाहिए । मैं भी चिन्तित हूँ कि गांव में जो फसल की कीमत मिलती है और आपने भी कहा है कि जो उपभोक्ता को मिलती है, उस कीमत में अंतर कम होना चाहिए, किसान को ठीक दाम मिलना चाहिए, उपभोक्ता को भी कुछ सस्ता मिलना चाहिए और बीच में जो बिचौलिए हैं, उनको कम करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस काम में हम निरन्तर लगे हुए हैं । अगर आप भी कोई सकारात्मक सुझाव देंगे तो उन सुझावों पर भी विचार करके, यदि वह लागू करने के लायक होगा, तो निश्चित रूप से विचार करके हम उस पर फैसला करने का काम करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों किसान के कुछ उत्पादनों के दाम घटे । जैसे सोयाबीन के दाम घटे, तो सरकार ने उसके लिए तत्काल फैसला किया । मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बधाई देना चाहूंगा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी ने फैसला किया कि जो खाद्य तेल है, उसका आयात जीरो पर्सेंट ड्यूटी पर होता था, उसको बढ़ाकर 20 पर्सेंट और इफेक्टिवली 27.5 पर्सेंट कर दिया गया, ताकि हम अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने का काम कर पाएं । इतना ही नहीं, अमित जी की अध्यक्षता में जो कमेटी है, उसने फैसला किया कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन खोला जाए और 40

पर्सेंट से घटाकर 20 पर्सेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी की जाए, ताकि प्याज के उत्पादक किसानों को ठीक दाम मिल सकें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी । हमने उस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को भी हर प्रकार के चावल के ऊपर से हटाने का काम किया, ताकि चावल के रेट भी हमारे किसानों को ठीक निर्यात होने के कारण मिल सकें । मसूर जो दलहनों में आती है और कई राज्यों में होती है, अभी वह जीरो पर्सेंट इम्पोर्ट ड्यूटी पर आती थी, हमने फैसला किया कि उस पर 11 पर्सेंट इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि मसूर के दाम कम न हों ।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सदन और सदन के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुअर हो, मसूर हो, उड़द हो, किसान जितनी भी दालें पैदा करेगा, वह उसका रजिस्ट्रेशन करवाए, हम उसकी सौ पर्सेंट खरीदी करेंगे, एक दाना नहीं छोड़ेंगे । हम सौ पर्सेंट खरीदी करने का काम करेंगे, ताकि किसान को दलहन के रेट्स भी ठीक मिल सकें, इसलिए हमने यह फैसला किया है । किसानों के पक्ष में हमने सदैव आयात और निर्यात नीति बनाने का फैसला और नीति बदलने का काम किया है ।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण काम, जिसके बारे में यहां चर्चा भी हो रही थी कि किसानों को अगर नुकसान हो जाए तो वह बर्बाद और तबाह हो जाता है । एक साल अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो वह तीन सालों तक पनपता नहीं है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का बड़ा फैसला किया । यहां से बात उठाई जा रही थी कि यह फसल बीमा योजना कब बनी? मैं अंतर बताना चाहता हूं । मेरे प्रतिपक्ष के मित्रों और पूरे देश को अन्तर बताना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना पहले भी थी । पहले कैसी फसल बीमा योजना थी? जब आपकी सरकारी थी, तब फसल बीमा योजना की इकाई ब्लॉक होती थी । ब्लॉक का इकाई होने का मतलब क्या होता है? ब्लॉक इकाई होने का मतलब यह था कि पांच गांवों में फसल खराब हो गई तो हम क्लेम नहीं देंगे । अगर दस गांवों में फसल खराब हो गई, तो क्लेम नहीं दिया जाएगा । जब पूरे ब्लॉक में फसल खराब हो जाएगी, तभी हम क्लेम देंगे । इसका मतलब यह है कि अगर एक गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए, दस गांवों के किसानों की

फसल खराब हो जाए तो वह भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी फसल खराब कर दो, तभी मुझे बीमा का क्लेम मिलेगा ।

ऐसी आपकी योजना थी । हमने इसमें परिवर्तन किया और यह तय कर दिया कि फसल बीमा योजना की इकाई ब्लॉक नहीं होगी, गांव होगा, ग्राम पंचायत होगा । अगर एक भी गांव में फसल खराब होगी तो हम क्लेम देंगे, यह मोदी सरकार का फैसला है ।

जब इनके समय यूपीए की सरकार थी तो केवल बैंकों के जो ऋण होते थे, केवल उनका बीमा होता था, उनके लिए अनिवार्य था, बीमा कराना ही पड़ेगा, प्रीमियम काट लिया जाता था । मोदी जी ने फैसला किया कि यह योजना स्वैच्छिक होगी, कराना है तो कराओ नहीं कराना है तो मत कराओ । ऋणी के लिए भी होगी और गैर-ऋणी के लिए भी होगी ।

हमने इसमें और परिवर्तन किए । पहले स्थानीय आपदा का इसमें कोई प्रावधान नहीं था । स्थानीय आपदा में एक किसान की फसल खराब हो जाए, कोई क्लेम का प्रावधान नहीं था । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीय आपदा का प्रावधान कर तय कर दिया कि एक भी किसान की अगर फसल खराब होगी तो क्षतिपूर्ति की जाएगी, उसको क्लेम दिया जाएगा ।

इनके समय नुकसान का आकलन, नुकसान की गणना परंपरागत तरीके से की जाती थी, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होती थी । अगर लोग गड़बड़ करना चाहते हैं तो गड़बड़ करते थे । हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया, सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेन्सिंग के माध्यम से फसलों के नुकसान का आकलन प्रारंभ किया ताकि तकनीक का इस्तेमाल हो ताकि किसी किसान के साथ अन्याय न हो । इन्हीं परिवर्तनों का प्रभाव है कि 2004 से 2014 तक आवेदन केवल 22 लाख 71 हजार आए थे, उस समय ऋणी आवेदन केवल 271 लाख थे, लेकिन अब 5978 लाख है । गैर ऋणी आवेदन उस समय केवल 120 लाख आते थे, पिछले साल 216 लाख आए । कुल किसान आवेदन उस समय 2391 लाख, अब 8564 लाख आए हैं । सकल बीमित राशि उस समय 4,14,525 करोड़ जो अब बढ़कर 21,82,209 करोड़ हो गई । 2004 से 2013 तक किसानों ने 11,354 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में जमा किया, उसके बदले 37 हजार करोड़ रुपये मिले । जब हमारी सरकार आई, 14 साल में एनडीए की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में 41 हजार 593 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा हुआ

और किसानों को 23357 लाख करोड़ रुपये मिले, पांच सौ प्रतिशत ज्यादा मिला । मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि फसल बीमा योजना लोगों की जिन्दगी बदलने का माध्यम बन गई है ।

महाराष्ट्र के मित्रों ने कहा कि फसल बीमा योजना में गड़बड़ी हुई है, ऐसे लगभग 2 लाख आवेदन निरस्त किए गए हैं । ये आवेदन फर्जी पाए गए थे । मैं फिर से आश्चस्त करना चाहता हूं, मेरे सांसद मित्र ने कहा था कि नाम सहित सूची देंगे । वह सूची हमें दें, अगर कहीं गड़बड़ हुई होगी, गड़बड़ करने वाली बीमा कंपनी हो या कोई और हो, किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों के निपटान में विलंब होता था । कई बार बीमा कंपनियां देर करती थीं, कई बार विलंब इसलिए होता था कि राज्य अपना अंशदान ठीक से नहीं देता था ।

समय पर नहीं देता था, इसलिए हमने एक फैसला किया कि राज्य अपना अंश दे या न दे, देर भले ही लगे, लेकिन हम केंद्र सरकार का अंश तुरंत जारी करके उतने पैसे सीधे किसान के खाते में डाल देंगे और सभी औपचारिकताएं अगर पूरी हो गई होंगी और बीमा कंपनी क्लेम देने में अगर देर करेगी, तो 12 परसेंट ब्याज बीमा कंपनी को किसान को देने का काम करना पड़ेगा, ताकि, विलंब भी अगर कहीं हो, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका खामियाजा किसान को न भुगतना पड़े ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही अभी बात हुई थी । हमारे एक सांसद मित्र ने कहा था कि कई बार वेयरहाउस न होने के कारण, कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण, राइपनिंग चेंबर न होने के कारण किसान की फसलें खराब हो जाती हैं और कटाई के बाद का नुकसान बहुत होता है । यह मोदी विज़न ही है, जिसने एक लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि - एग्रीकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) तय की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 30.11.2024 तक एआईएफ के तहत 85,314 परियोजनाओं के लिए 51,783 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है । ? (व्यवधान) इन स्वीकृत परियोजनाओं से लगभग 85,208 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है और एआईएफ के तहत प्रमुख स्वीकृत परियोजनाओं में 22,627 कस्टम हाइरिंग सेंटर, 17,699 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 14,201 गोदाम, 3,282

छांटने और ग्रेडिंग की इकाइयां, 2,044 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं और लगभग 25,461 अन्य प्रकार की बाढ़ की फसल प्रबंधन परियोजनाएं बनाई गई हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका फायदा किसान को मिलेगा । लेकिन, केवल इतना ही नहीं, लैब से लैंड तक और विज्ञान से किसान तक कैसे सीधे, हमारे जितने भी अलग-अलग शोध होते हैं, उनका लाभ मिले । हमने आधुनिक कृषि चौपाल की पहल की है । हर महीने में एक बार किसान और वैज्ञानिक बैठेंगे और वह डीडी किसान के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा कि वैज्ञानिकों ने कौन-कौन से नए बीजों की किस्में इजाद की हैं या अलग-अलग कौन से नए शोध किए हैं, ताकि उनका लाभ तत्काल किसान को मिल सके, ताकि हम लैब-टू-लैंड जोड़ने का काम कर सकें, किसान और विज्ञान को जोड़ने का काम कर सकें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल कृषि मिशन मोदी जी के विज्ञान का प्रतीक है । समय की सीमा है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं । लेकिन, डिजिटल क्रांति का लाभ उठाने के लिए और डिजिटल क्रांति का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने इस मिशन की शुरुआत की है । इस मिशन के अंतर्गत सभी किसानों को एक डिजिटल किसान पहचान पत्र दिया जाएगा । किसान की पहचान, किसान आईडी अब अलग से बनेगी । इसका लाभ और सेवाएं किसानों तक पहुंचाने के लिए, स्वयं की डिजिटल रूप से पहचान वह प्रमाणित कर पाएगा और बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा । उन्हें अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी । पहले फसल ऋण प्राप्त करने के लिए कागजी कार्यवाही में ही महीनों निकल जाते थे, अब आधे घंटे के बाद, किसान रजिस्ट्री बनने के बाद वह फसल का ऋण प्राप्त कर सकते हैं । बिना किसी कागज के, फार्मर आईडी बताकर अपनी बोई गई फसल का ब्यौरा साझा कर सकते हैं, जिससे एफसीआई आसानी से उनकी फसल खरीद सकती है । एक नहीं, बल्कि अनेक लाभ इस डिजिटल कृषि मिशन के कारण किसानों को होंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय की सीमा के कारण मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । अभी एक मित्र ने बेगुसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र के लिए यह कहा कि वह बदला जा रहा है । भद्र फैलाने में तो कुछ प्रतिपक्षी मित्र मास्टर हैं । मैं कहना चाहता हूं कि बेगुसराय में मक्का का जो अनुसंधान केंद्र है, वह बेगुसराय, बिहार में ही रहेगा ।

वह नहीं बदला जाएगा । कर्नाटक के लिए हम अलग से संस्थान खोलने का काम करेंगे । यह मोदी सरकार है और ?मोदी है, तो मुमकिन है? ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम छीनते नहीं हैं, बल्कि नया कारखाना खोलने का काम करते हैं । इस नए बजट में जो सबसे बड़ी बात है, प्राकृतिक खेती के मिशन को स्वीकृत किया गया है । मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह केवल आज के बारे में नहीं सोचते हैं, कल के बारे में भी सोचते हैं, वे आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में भी सोचते हैं । आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती कैसे उपयोगी बन पाएगी, वह इसका भी विचार करते हैं । इसलिए जो प्राकृतिक खेती मिशन है, जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर की खेती होगी । यह संभव है, अगर सही ढंग से प्राकृतिक खेती की जाए, तो उत्पादन घटेगा नहीं, बल्कि कई मामलों में उत्पादन बढ़ सकता है । मोदी जी की यह पहल धरती को केमिकल फर्टिलाइजर के प्रभाव से बचाएगी । आज धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तथा आज हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, उसे बचाने की पहल की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट मोदी विजन है, इसलिए ?पीएम धन-धान्य कृषि योजना? बनी है । हम देश के अनेक राज्यों में देखते हैं कि बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जहां उत्पादन कम है । जब हम राज्यों को देखते हैं, तो कुछ राज्यों के कुछ जिलों में उत्पादन बहुत कम है । इसीलिए उत्पादकता, सिंचाई, क्रेडिट एक्सेस और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए हम ?पीएम धन-धान्य कृषि योजना? के तहत 100 एस्पिरेशनल कृषि जिलों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे । 1,07,00,000 किसानों को उसका लाभ मिलेगा । बिहार के लोगों ने बात उठाई थी, तो निश्चित तौर पर बिहार को भी उसका लाभ मिलेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी अनेक पहलें हैं । दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन है । फलों और सब्जियों के लिए व्यापक कार्यक्रम, राष्ट्रीय उच्च उपज, बीज मिशन, कपास उत्पादकता मिशन इत्यादि घोषणाएं इस बजट में की गई हैं । समय की सीमा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भारत की कृषि की जो विकास दर है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में वह लगभग पांच प्रतिशत के आस-पास है । उसके लिए मैं राजीव रंजन सिंह जी को बधाई दूंगा, क्योंकि वह मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं । सहकारिता के क्षेत्र में आज बेहतर काम हो रहे हैं, उसके

लिए मैं गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को बधाई दूंगा । आज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की ग्रोथ पांच प्रतिशत है, जो विश्व में अपने आपमें चमत्कार है । पहले दो-तीन प्रतिशत से ज्यादा ग्रोथ नहीं होती थी । यह मोदी जी के मिशन और उनके विजन का ही परिणाम है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने कहा है कि मुझे 1755 बजे अपना भाषण समाप्त करना होगा । मैं सदन को फिर से अवगत कराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है । मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण हमारे लिए सर्वप्रथम है । हम मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की सेवा करेंगे, क्योंकि किसान खेती की आत्मा है, वह जीवनदाता है, वह अन्नदाता है । हम तीसरे कार्यकाल में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे । माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है । एक विजन दिया है और विकसित भारत बनाने के लिए समृद्ध खेती ही हमारा लक्ष्य है । इसी विजन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत केवल भारत के लिए नहीं है । आज हम अपना पेट तो भरते ही हैं, लेकिन भारत आज पूरी दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत आज विश्व बंधु है । भारत ने तो आज नहीं, बल्कि हजारों साल पहले कहा था कि ?जियो और जीने दो? । यह हम ही हैं, जिनके ऋषि-मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था कि

?अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्,

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्? ।

यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी सोच छोटे दिलवालों की होती है । जो विशाल हृदय के होते हैं, वे तो कहते हैं कि सारी दुनिया ही एक परिवार है । भारत सारी दुनिया को परिवार मानने वाला है । भारत का लक्ष्य है कि हम कृषि सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक तो बनाएं ही, लेकिन हम भारत को दुनिया का फूड बास्केट भी बनाएं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आज लगभग 50,000 करोड़ रुपये का बासमती चावल निर्यात कर रहे हैं। चाहे अमेरिका हो या कनाडा हो, भारत के बासमती के चावल के बिना उनका काम नहीं चलता है। आज पूरे देश और दुनिया में एमपी व्हीट की गूंज सुनाई देती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने इस समय जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं। भारत के खाद्य तेलों के आयात पर अत्यधिक निर्भरता है, जैसे कीमतों में उतार-चढ़ाव और विदेशी मुद्रा आउटफ्लो होता है। इस निर्भरता को कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उपयुक्त कृषि जलवायु क्षेत्रों में तिलहन की खेती का हम विस्तार करेंगे, उच्च उपज जलवायु अनुकूल बीज की किस्मों को बढ़ावा देंगे, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद सुनिश्चित करेंगे। दलहनों के लिए भी इसी तरह से लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं। 6 साल का दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है, जिसमें हमने तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया है। नेफेड और एनसीसीएएफ द्वारा उच्च खरीद और किसानों को स्थिर मूल्य प्रदान करने की हमारी गारंटी है। प्रोटीन सामग्री और सूखा प्रतिरोध बढ़ाने के लिए अनुसंधान संचालित बीजों का विकास किया जाएगा तथा दलहन उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही हम खेती में वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को अपनाने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मौसम पैटर्न और मिट्टी का क्षरण किसानों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हम इस पर पहले से ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उच्च जलवायु अनुकूल फसलें, जो सूखा, बाढ़ और तापमान में उतार-चढ़ाव का सामना कर सकती हैं, उनकी किस्में तैयार करने का प्रयास करेंगे। उच्च उपज कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों के लिए आईसीएआर के नेतृत्व वाला अनुसंधान कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए एआई, रिमोट सेंसिंग, एलओटी का उपयोग करके हम सटीक खेती, तकनीकी बेहतर संसाधनों के उपयोग और कम लागत के साथ उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कृषि मशीनीकरण का विस्तार भी हमारा लक्ष्य है। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। अब हम निम्नलिखित को बढ़ावा दे रहे हैं ? ?नमो ड्रोन दीदी? के माध्यम से छिड़काव और निगरानी के लिए ड्रोन, पानी के उपयोग को अनुकूलित करने

के लिए, वह न कम हो न ज्यादा हो, उसमें स्वचालित सिंचाई प्रणाली । हमारा लक्ष्य कृषि निर्यात को बढ़ाना है और भारत को विश्व खाद्य बास्केट बनाना । भारत पहले से ही चावल, चीनी और मसालों के शीर्ष वैश्विक निर्यातकों में से है, लेकिन हमें अपने कृषि निर्यात का विस्तार करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है । देरी को कम करने और निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, उस क्षेत्र में भी सरकार काम करेगी । अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता का अनुपालन हो, इसके लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम हमने चलाया हुआ है । उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पाद, डेयरी और मत्स्य पालन, जैविक और जीआई टैग कृषि उत्पाद पर हम ध्यान दे रहे हैं । बाजार का विविधीकरण करके फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, मसालों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, रेशम पालन के साथ-साथ कृषि वानिकी पर भी लगातार ध्यान देने का काम कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए हम उत्पादन, भूमि उपयोग और ऋण पहुंच पर जो क्षेत्रीय असंतुलन बना है, उसको दूर करने के लिए कम उत्पादकता और सीमित सिंचाई और विविधीकरण की कमी से जो क्षेत्र पीड़ित हैं, उनमें अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए एक नई रणनीति बनाई है । संतुलित कृषि विकास के लिए हमारी रणनीति में शामिल है और उसमें नंबर एक कृषि ग्रामीण विकास जल संसाधन और वित्त मंत्रालय क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेपों को डिजाइन करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं । क्रेडिट एक्सेस और भूमि उपयोग के लिए स्थानीयकृत योजना हमने बनाई है । छोटे और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड को हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं । हम मिट्टी की उपयुक्तता और पानी की उपलब्धता के आधार पर फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं । हम किसानों के समूहों को मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं । इसके साथ ही मैं विनम्रता और दृढ़तापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ।

18.00 hrs

भारत आज विश्वबंधु है, लेकिन कल विश्व गुरु बनेगा । मैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा । स्वामी विवेकानंद जी ने 100 साल पहले कहा था :-

?सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, लेकिन जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वे सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर खड़ी हो रही है और विश्वगुरु के पद पर आसीन हो रही है ।?

एक नरेन्द्र ने 100 साल पहले कहा था और दूसरे नरेन्द्र के नेतृत्व में यह होगा, यह होगा, यह होगा । भारत विकसित भारत बनेगा और कृषि का उसमें विशेष रूप से योगदान होगा । किसान समृद्ध होंगे और कृषि क्षेत्र आगे बढ़ेगा ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही आइटम नम्बर 27 की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधाकर सिंह, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, प्रो. वर्षा एकनाथ गाड़कवाड़, श्री लालजी वर्मा, श्री राजीव राय, श्री दुरई वाइको, श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, श्री राजकुमार रोट, श्री अमरा राम, एडवोकेट चन्द्र शेखर, श्री राजेश रंजन ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं ।

अब मैं उन सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के सामने मतदान हेतु रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2025-2026 की अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

?कि कार्य-सूची के दूसरे स्तंभ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2 के सामने प्रविष्ट मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान पर किए जाने वाले खर्चों को चुकाने के निमित्त, आवश्यक धनराशियों को पूरा करने के लिए, संबंधित धनराशियां, जो कार्य-सूची के तीसरे स्तंभ में दिखाई गई राजस्व रेखा

और पूंजी लेखा की रकमों से अधिक न हों, भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को प्रदान की जाएं ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप न का अर्थ जानते हैं? क्या आप किसानों को अनुदान नहीं देना चाहते हैं? आप थोड़े बहुत तो विद्वान बनिए ।

? (व्यवधान)
